राजनीतिक और सांगठनिक समीक्षा

फरवरी, 2007

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

यहां भाकपा (माओवादी) की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस में एकमत से पारित किया गया था। इसमें नक्सलबाड़ी के सशस्त्र किसान संघर्ष का उभार से लेकर कांग्रेस के समय यानी जनवरी-फरवरी 2007 तक की समीक्षा दी गयी। इस दौरान जनयुद्ध का विकास का संपूर्ण चित्रण इसमें दिया गया है।

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1 (i)	पूर्ववर्ती एमसीसीआई की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा-रिपोर्ट	5
(ii)	पार्टी इतिहास के कुछेक पहलू	107
2	पूर्ववर्ती सीपीआई (एमएल) [पीडब्ल्यू] की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा	123
3	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा	264

पूर्ववर्ती भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसीआई) की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा-रिपोर्ट

भूमिका

आज अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति क्रांति के लिए बहुत-ही अनुकूल है। ऐसी स्थिति में क्रांति की आत्मगत तैयारियों (subjective preparation) को ठोस बनाना जरूरी है। सांगठनिक रिपोर्ट के जरिए इस काम को ही आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है।

पर सांगठनिक समीक्षा के पहले इसी बीच राजनीतिक सवाल पर हमने क्या स्टैण्ड लिया इसके बारे में खूब संक्षेप में दो-चार बात कहना लाजिमी है।

यह बात सभी को मालूम है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के दिशा-निर्देशन के आलोक में अपनी राजनीतिक और सैनिक लाइन की अग्रगति की प्रक्रिया से जुड़े रहकर हमने समय-दर-समय अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्षेत्रों में होनेवाले कतिपय परिवर्तनों पर गंभीर और पैनी दृष्टि रखी । उसके मुताबिक उन परिवर्तनों का सही विश्लेषण करते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टैण्ड लिए जैसे:- 1976 में महान माओ की मृत्यु के तुरंत बाद 'चार गुट (gang of four)' का हौवा खड़ाकर माओ के नेतृत्वाधीन सी.पी.सी. के चार महत्वपूर्ण कामरेडों को चरम तानाशाहीपूर्ण तरीके से गिरफ्तार करने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर तेङ-हुआ गुट या तेङ संशोधनवाद का कब्जा हो जाने और 'तीन दुनिया के सिद्धांत' के नाम पर वर्ग संघर्ष को खारिज करने वाले एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत को सामने लाने, महान समाजवादी चीन देश को एक पूंजीवादी देश में अध:पतित कर दिये जाने के कारण हमने चीनी पार्टी को एक संशोधनवादी पूंजीवादी पार्टी और चीन देश को एक पूंजीवादी देश कहा है। उधर सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद का संकट उत्तरोत्तर गंभीर होने के चलते जब उसने अपना समाजवादी मुखौटा नोचकर फेंक दिया तो हमने उसे सामाजिक साम्राज्यवाद के बदले केवल साम्राज्यवाद कहा और उसे दुर्बल महाशक्ति कहा। बाद में खासकर, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान और इराक पर हमले के वक्त हमने यह देखा कि

दुर्बल महाशक्ति भी जो कुछ भूमिका निभा सकती है, उसकी भी कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, तब 2002 के नवम्बर में हमने दुर्बल महाशक्ति जैसे विश्लेषण को वापस लिया और उसे आणविक हथियारों से लैस एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद कहना ज्यादा प्रासंगिक समझा।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुख्य-मुख्य अन्तर्विरोधों के अंदर चौथे अन्तर्विरोध यानी, समाजवादी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था के बीच के अंतर्विरोध को, जो अभी (साम्राज्यवादी व्यवस्था के साथ समाजवादी शक्ति के बीच के एक अंतरविरोध के रूप में उसके रहने पर भी) दो विपरीत व्यवस्था के बीच के बुनियादी अंतरविरोध के रूप में अस्तित्व में नहीं है, हमने हटा दिया है और 1917 से यानी, रूसी क्रांति की सफलता के बाद से 1976 में महान माओ की मृत्यु तक उस अन्तर्विरोध का अस्तित्व था– इसका उल्लेख करने के साथ ही साथ हमने यह भी स्पष्ट किया है कि फिर अगर किसी देश में क्रांति हो तो तुरन्त वह अन्तर्विरोध बुनियादी अन्तर्विरोध के रूप में अस्तित्वमान हो जायेगा।

युग के बारे में हम आरंभ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस में पारित "वर्तमान युग साम्राज्यवाद के अन्तिम पतन तथा समाजवाद के विश्वव्यापी विजय का युग है" प्रस्थापना को ही एक रणनीतिक महत्व रखनेवाले सिद्धांत के रूप में मानते आ रहे हैं। इस युग को हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का युग भी कहते आ रहे हैं। इस विषय पर पुरानी सी. पी. आई. (एम-एल) का स्टैण्ड भी यही रहा है। फिलहाल क्रांतिकारी एकता के बृहत स्वार्थ को देखते हुए हमने इस युग को साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति का युग कहना तय किया है। साथ ही कहा है कि यह युग कई चरण व स्तर में विभाजित है तथा दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थिति में आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में एक भारी व विशाल परिवर्तन हुआ है। हालांकि, हम अभी भी 9वीं कांग्रेस के उक्त विश्लेषण को एक सही रणनीतिक अवधारणा के बतौर मानना उचित समझते हैं।

जनवरी, 2000 में हमने वर्ग संघर्ष के मौजूदा स्तर को और उन्नत करने के लिए माओ विचारधारा का नाम लेकर माओ विचारधारा का विरोध करने वाले अत्याधुनिक संशोधनवाद के साथ सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचना जरूरी समझा। उसी समझ के तहत ही हमने अपने विचारधारात्मक मार्गदर्शक व दिशा-निर्देशक सिद्धांत के रूप में पहले से इस्तेमाल किये जानेवाले शब्द "मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा" के बदले "मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद" कहने का निर्णय लिया। इसके जरिए ही एक तरफ

अत्याधुनिक संशोधनवाद सी. पी. आई. (एम–एल) लिबरेशन आदि के साथ स्पष्ट विभाजन–रेखा खींचना, तो दूसरी तरफ, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी सच्चे माओवादियों के साथ गोलबन्द होना संभव है, हमने इस प्रासंगिकता को समझा है । ऐसे भी हमारा संगठन बिल्कुल आरंभ से ही हमारे संस्थापक व नेता कामरेड कन्हाई चटर्जी के इस विश्लेषण को बहुत ही महत्व के साथ मानते आ रहा है कि ''माओ विचारधारा'' और ''माओवाद'' के बीच सारवस्तु में कोई फर्क नहीं है या कोई चीन की दीवार नहीं है तथा ''विचारधारा'' और ''वाद'' दोनों समानार्थक शब्द हैं एवं अन्तर्वस्तु में दोनों एक ही हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ही हम अब ''माओवाद'' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । अनुभव ने हमें दिखाया है कि ऐसा करके ही हम क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष के मौजूदा स्तर को और उन्नत करने में समर्थ हुए हैं।

इस प्रकार समयानुकूल कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ–साथ हमने सैद्धांतिक और राजनीतिक रूप से मजबूत और सुव्यवस्थित पार्टी बनाने हेतु वैचारिक और सांगठनिक मामलों में संशोधनवाद के साथ सुस्पष्ट विभाजन–रेखा खींचते हुए भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में संघर्ष जारी रखा । लम्बे संघर्षों और जद्दोजहद के जरिए पार्टी के भीतर और बाहर के अवसरवादियों को परास्त करते हुए सन् 2000 से राजनीतिक और सैनिक लाइन के गुणात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में सच्चे माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के साथ एकता स्थापित करने में हम कामयाब होने लगे । राष्ट्रीय क्षेत्र में माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने का सवाल पर सन् 2003 के आरंभ से ही गुणात्मक छलांग के नमूने दृष्टिगोचर होने लगे । 2003 की जनवरी में आर. सी. सी. आई. एम. और आर. सी. सी. एम. के साथ एम. सी. सी. की एकता तथा फरवरी में सी. पी. आई. (एम–एल) (पीपुल्स वार) के साथ एकता के सवाल पर बहुतेरे मुख्य बिन्दुओं का हल हो जाना, 22 अप्रील को PLGA की स्थापना, मई माह में सी. पी. आई. (एम–एल) (सेकेण्ड सी. सी.) और एम. सी. सी. आई. के बीच एकता, सितम्बर में आर. सी. सी. आई.(एम–एल–एम) के साथ एकता आदि उक्त नमूनों की वास्तविक मिसालें हैं । उसके बाद आरंभ हुई चिरप्रतीक्षित जनफौज व आधार क्षेत्र की अवधारणा को साकार रूप देने की दिशा में चुने हुए छापामार जोन (रणनीतिक क्षेत्र) को आधार क्षेत्र बनाने की तथा पी. एल. जी. ए. को पी. एल. ए. में विकसित करने की दिशा में एवं क्रांतिकारी किसान कमिटी को अन्यान्य क्रांतिकारी शक्तियों से मिलाकर क्रांतिकारी जन कमिटी के रूप में गठित करने और सही प्रक्रिया व पद्धति का अनुसरण करते हुए

एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने की दिशा में पहल।

बुनियादी लाइन पर अडिग रहते हुए तथा उसे व्यवहार में लागू करते हुए संघर्ष व संगठन का विकास और विस्तार करने का हमारे संगठन का एक लम्बा इतिहास है। इसके अलावे हमारे संगठन के विकास और विस्तार के दौर में हुए लम्बे उतार-चढ़ाव, कमजोर और मजबूत पक्ष, क्षतियों और उपलब्धियों, आलोचनाओं-आत्मालोचनाओं आदि पर अनेकों दस्तावेज समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं। वे महत्वपूर्ण दस्तावेज [खासकर, रणनीति व कार्यनीति संबंधी, सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी लड़ाई तथा फौज व आधार क्षेत्र का निर्माण संबंधी, चुनाव के बारे में दृष्टिकोण संबंधी, राष्ट्रीयसत्ता (nationality) की समस्या और कम्युनिस्टों का कर्तव्य संबंधी, मास लाइन (जन लाइन) संबंधी दस्तावेज] आज भी मौजूद हैं। इसलिए आज हमारी इस राजनीतिक और सांगठनिक समीक्षा-रिपोर्ट का मूल उद्देश्य है– लाइन को व्यावहारिक तौर पर आगे बढ़ाने के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर क्रांति की आत्मगत तैयारियों को और भी ठोस बनाना तथा साथ ही साथ उक्त अनुभवों की रोशनी में हमारे रोजमर्रे के क्रांतिकारी व्यवहार से ओत-प्रोत रूप से जुड़ीं आज की मूल समस्याओं और सम्भावनाओं को उजागर करना ताकि दोनों धाराओं के मिलन यानी एम. सी. सी. आई. और सी. पी. आई. (एम-एल) (पी. डब्लू.) के मिलन के पश्चात एक एकीकृत पार्टी के अंदर भी इसपर एकरूपता कायम करते हुए समस्याओं को हल करने के दौर से संभावनाओं को वास्तव में साकार करने में तेजी लाई जा सके तथा इस तरह आगे के प्रवाह को वेगवान बनाया जा सके।

* * *

जन फौज-आधार क्षेत्र बनाने की हमारी अवधारणा और कामकाज की शुरूआत तथा उसका विकास व विस्तार

सभी को मालूम है कि कामरेड कन्हाई चटर्जी के कुशल नेतृत्व में संचालित हमारे संगठन का इतिहास 1964 के सी.पी.एम. पार्टी की संशोधनवादी 7वीं कांग्रेस के ठीक बाद से ही जुड़ा हुआ है। बाद में, 'चिन्ता' और 'दक्षिण देश' ग्रुप के रूप में कुछ दिन काम करने के पश्चात अंततः 1969 के 20 अक्टूबर को कामरेड के.सी., कामरेड अमूल्य सेन और कामरेड चन्द्रशेखर दास इन तीन संस्थापकों के नेतृत्व में माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (M.C.C) के नाम से हमारे संगठन को ठोस रूप दिया गया। एम.सी.सी. के गठन के कुछ समय पहले से ही यानी, 1969 की मई से ही कामरेड के.सी. द्वारा लिखित 'रणनीति व कार्यनीति' संबंधी एक बुनियादी दस्तावेज हमारे संगठन का बुनियादी राजनीतिक आधार बना। 'संशोधनवादियों के साथ सभी क्षेत्रों में एक साफ विभाजन-रेखा खींचना बहुत ही जरूरी है'– कामरेड के.सी. की इस बात का व्यावहारिक रूप सर्वप्रथम इस बुनियादी दस्तावेज के जरिए ही ठोस रूप से सामने आया। बाद में, इस रणनीति व कार्यनीति संबंधी दस्तावेज के अनुसार भारतीय क्रांति के व्यावहारिक कामकाजों को यानी जनफौज व आधार क्षेत्र के निर्माण के कामकाजों को आगे बढ़ाने हेतु कामरेड के.सी. का एक और बहुमूल्य लेख (1970 में प्रकाशित) 'सशस्त्र कृषि क्रांति में कूद पड़ें, फौज व आधार क्षेत्र निर्माण के काम को तेज करें' हमारे व्यावहारिक कामकाज की दिशा के रूप में स्थापित हुआ। हमारे संगठन में इस दस्तावेज को (दक्षिण देश और लाल पताका विशेष अंक–1) एक और बुनियादी दस्तावेज के बतौर माना जाता है और जहां ही व्यावहारिक कामकाज का सवाल है, उसी दस्तावेज का अनुसरण किया जाता है। इस दस्तावेज का सबसे ज्यादा महत्व इस सवाल पर है कि अगर सचमुच में भारतीय क्रांति को आगे बढ़ाना है तो स्वयंस्फूर्त ढंग से जहां-तहां काम करना नहीं, बल्कि ऐसे कुछ इलाकों (जिसको रणनीतिक इलाका कहा जाता है) को फौज व आधार क्षेत्र निर्माण करने हेतु सर्वाधिक अनुकूल इलाके के रूप में चुन कर काम करना अत्यावश्यक है। इस दृष्टिकोण से जहां तक हमारे संगठन का कामकाज चल रहा है उसके अंदर (i) असम-त्रिपुरा इलाके को प्रथम और (ii) तत्कालीन बिहार व पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से को लेकर स्पेशल एरिया के विशाल इलाके को द्वितीय रणनीतिक क्षेत्र के बतौर निर्धारित किया गया था।

भारत में नये-पुराने संशोधनवादियों के संसदवादी विचारों व लाइन के साथ साफ विभाजन रेखा खींचने के सवाल पर कामरेड के.सी. के एक और महत्वपूर्ण लेख यानी, "संसदीय राजनीति तथा आत्मसमर्पणवाद के खिलाफ संघर्ष को जोरदार करें, कृषि क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध के झंडे को ऊंचा उठाए रखें" शीर्षक लेख (लाल पताका-12) हमारे लिए तथा तमाम क्रांतिकारियों के लिए एक अमूल्य संपदा है। यह लेख चुनाव के बारे में हमारे दृष्टिकोण संबंधी बुनियादी व आधारभूत लाइन को रेखांकित करता है। इस लाइन के आधार पर हमारा पूरा संगठन एकदम शुरू से ही संसदवादी मार्ग को खारिज करना और संसदीय चुनाव का बॉयकाट करना तथा चुनाव का बॉयकाट के सवाल को न केवल कार्यनीतिगत दृष्टिकोण से देखना, बल्कि इसे रणनीति के बराबर महत्व देने का दृष्टिकोण अपनाना- इस दिशा से लैस हुआ है और आज भी उस लाइन पर डटे रहकर सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तथा कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध को क्रमशः और व्यापक व तीव्र बनाते जा रहा है। अनुभव ने हमें सिखाया है कि इस लाइन पर अडिग रहकर ही हम भारतीय क्रांति को उसकी विजय की मंजिल तक आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं।

अतः कहा जा सकता है कि संशोधनवादियों से लाइनगत रूप से स्पष्ट विभाजन-रेखा खींच लेने के साथ-साथ जनफौज व आधार क्षेत्र का निर्माण हमारे सभी कामकाज का मुख्य केन्द्र-बिन्दु बन गया । इधर, पहले ही 'रणनीति व कार्यनीति' संबंधी दस्तावेज के जरिए यह भी तय हो गया कि हमारा देश 1947 के बाद से ही नव औपनिवेशिक किस्म की एक अर्ध औपेनिवेशिक-अर्ध सामंती व्यवस्था वाले देश में रूपान्तरित हो चुका है अर्थात्, यहाँ साम्राज्यवाद व सामंतवाद मौजूद है और किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता और लेशमात्र भी जनवाद नहीं है । साम्राज्यवाद और उसके गुर्गे सामंतवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना ही भारतीय क्रांति की वर्तमान मंजिल का मूल लक्ष्य है । यह क्रांति सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में की जानेवाली एक राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति है, जिसे नवजनवादी क्रांति कहा जाता है । कृषि क्रांति नवजनवादी क्रांति की बुनियाद या धुरी है । देहाती इलाके क्रांति के मुख्य केन्द्र हैं । साथ ही साथ शहरों के कामकाज को भी विशेष महत्व देना अनिवार्य है । हमारा दुश्मन अपेक्षाकृत बड़ा और शक्तिशाली है तथा जनता या क्रांतिकारी शक्तियाँ कमजोर हैं । लेकिन यह बरतरी और कमतरी स्थायी नहीं है । धीरे-धीरे शत्रु की बरतरी कमतरी में और जनता या क्रांतिकारी शक्तियों की कमतरी बरतरी में विकसित होगी । स्वभावतः हमारा युद्ध तुरन्त-फुरन्त विजय हासिल करनेवाला नहीं, बल्कि दीर्घकालीन चरित्रवाला युद्ध है । कृषि

क्रांतिकारी छापामार युद्ध इस युद्ध की रणनीतिक विशेषता है, जो आरंभ से अंत तक जारी रहेगी। आरंभ में क्रांतिकारी शक्तियाँ कमजोर और रणनीतिक आत्मरक्षा की स्थिति में रहेंगी। फिर क्रमिक रूप से वे बढ़कर दुश्मन से बराबरी की स्थिति में होंगी और अन्त में शत्रु से अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तिशाली और रणनीतिक आक्रमण के दौर में पहुँच जाएंगी। छापामार युद्ध यहाँ की एक बुनियादी विशेषता है जो आरंभ से आखिरी तक रहेगा। लेकिन निर्णायक युद्ध के लिए नियमित और चलायमान युद्ध भी जरूरी होगा। यहाँ मोर्चाबद्ध लड़ाई की परिस्थिति बहुत बाद में और बहुत कम समय के लिए ही आएगी।

इन सारी रणनीतिगत अवधारणाओं के आलोक में कृषि क्रांति, जनफौज और आधार क्षेत्र के परस्पर संबंधों का अध्ययन और उनके समाधान से संबंधित एम. सी. सी. की अवधारणा तथा उसकी सैनिक लाइन से संबंधित अवधारणा को ही कामरेड के.सी. ने फौज व आधार क्षेत्र के निर्माण संबंधी दस्तावेज के जरिए ठोस रूप दिया।

इस दस्तावेज में यह स्पष्ट किया गया था कि ''कृषि क्रांति के बिना जनफौज का निर्माण संभव नहीं है। फिर जनफौज के बिना आधार क्षेत्र कायम नहीं हो सकता। साथ ही आधार क्षेत्र के बिना जनफौज को टिकाकर रखना भी संभव नहीं है और फिर जनफौज व आधार क्षेत्र के बिना कृषि क्रांति को भी मंजिल तक पहुँचाना संभव नहीं हो सकता।''

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्रांति का प्रश्न कृषि प्रधान अर्ध औपनिवेशिक-अर्ध सामंती असमान विकासवाले देश में एक ऐसा मूल प्रश्न है, जिसे नजरअन्दाज करके कोई भी क्रांति या परिवर्तन की बात बेबुनियाद हो जायगी, जबकि इस प्रश्न का हल ही सभी क्रांतियों और परिवर्तनों का आधार तैयार करेगा। इसके बिना चाहे साम्राज्यवाद से मुक्ति का मामला हो या सामंती भूस्वामी व दलाल नौकरशाह पूंजीपति के वर्ग शोषण से मुक्ति का मामला अथवा राष्ट्रीयताओं की मुक्ति का मामला हो, किसी भी मसले का हल संभव नहीं है।

कृषि क्रांति का प्रश्न सिर्फ किसानों का प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न देश की समूची जनता का प्रश्न है। इस प्रश्न का हल मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसान मैत्री के बिना संभव नहीं हो सकता। ऐसे एक देश में सर्वहारा वर्ग और उसकी अगुआई करनेवाली कम्युनिस्ट पार्टी का पहला कर्तव्य मजदूर-किसान मैत्री के आधार को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना है। इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सुनिर्धारित योजनाबद्ध तरीके से चुने हुए इलाके [रणनीतिगत इलाके (strategic area)] में कामकाज शुरू करना

तथा विकसित करना होगा ।

हमारे संगठन ने इसी सोच को साकार करने के लिए ''श्रेष्ठ क्रांतिकारियों गांव चलो'' का नारा बुलन्द किया था तथा शहर से पेशेवर क्रांतिकारियों के सर्वश्रेष्ठ अंश के एक बड़े भाग को देहातों में भेजना आरंभ किया था ।

देहात में हमारे कामकाज की शुरूआत कोलकाता के नजदीक चौबीस परगना जिले में स्थित डिही–सोनारपुर इलाके से ही हुई । सोनारपुर में कुछ जुझारू लड़ाई का निर्माण भी किया गया। हालांकि, ये सारी लड़ाइयां ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ सकीं । पर इस लड़ाई के जरिए देहात के कामकाज के बारे में हमें कुछ सकारात्मक अनुभव हासिल हुआ। इन अनुभवों को संश्लेषित कर ग्रामीण इलाकों में कामकाज के कतिपय ठोस दिशा–निर्देशनों का निर्धारण कर उनके अनुसार पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना, मिदनापुर, मालदह, बर्दवान सहित असम–त्रिपुरा के गहन जंगल–पहाड़ों के दुर्गम इलाकों तथा तत्कालीन बिहार के धनबाद, हजारीबाग, गया एवं यू. पी. के गोरखपुर में भी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कामकाज के लिए कार्यकर्ता भेजे गये थे ।

गांवों में कृषि–क्रांतिकारी आन्दोलन तथा कृषि–क्रांतिकारी छापामार संघर्ष का निर्माण करना, उसे क्रमशः विकसित करना और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पार्टी, जनफौज और क्रांतिकारी किसान कमिटी का निर्माण करने के उपादानों को विकसित करना ही हमारा लक्ष्य था । यह काम परम्परागत रूप से चली आ रही अवसरवादी, संशोधनवादी व संसदवादी धारा के आन्दोलनों व संघर्षों के विपरीत क्रांतिकारी सिद्धांत व राजनीति से लैस व जागरूक तथा सत्ता दखल के लक्ष्य से गठित सशस्त्र संगठनों के बिना कतई संभव नहीं था । इसके लिए पहले कृषि क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करना जरूरी था । इसे किये बिना कृषि क्रांतिकारी संघर्ष के लिए किसान जन समुदाय को जागरूक करना भी संभव नहीं था । फिर क्रांतिकारी संघर्ष की भट्ठी में तपकर परीक्षित हुए लोगों के बिना ऐसा सुदृढ़ और सुव्यवस्थित पार्टी संगठन भी नहीं बन सकता था जो आन्दोलनों और क्रांतिकारी संघर्षों का निरंतर संचालन व विकास करने में समर्थ हो ।

अतएव उपरोक्त प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने प्रचार, संघर्ष व संगठन के आपसी संबंधों को एकसूत्र में पिरोकर सुव्यवस्थित किया । तत्कालीन परिस्थिति में गांवों में भेजे गये चन्द कामरेडों (जो शहर के कामकाज के दौरान कमोबेश परीक्षित थे) को प्रथमतः यही दिशा–निर्देश दिया गया था कि किस तरह जनता को छापामार (गुरिल्ला) युद्ध में शामिल किया जा सकता है– इस सवाल को ध्यान में रखते हुए वे गांवों में जाकर किसानों

के साथ खासकर, भूमिहीन व गरीब किसानों के साथ एकात्म होकर वहाँ की बुनियादी समस्याओं से रूबरू हों, तात्कालिक और बुनियादी समस्याओं को सूत्रबद्ध कर क्रांतिकारी किसान संघर्ष का कार्यक्रम तैयार करें और प्रचलित हथियारों से जनता और खुद को लैस करें, उसी के आधार पर क्रांतिकारी राजनीति से जनसमुदाय को जागरूक करने की योजना बनाएँ, उनको शुरू से ही गुप्त ढंग से उठना-बैठना सहित सभी कामकाज के लिए अभ्यस्त कराएं, उसके जरिए स्थानीय तौर पर उभर कर आये सबसे सक्रिय व अगुआ हिस्से को चलायमान सशस्त्र प्रचारक व संगठक के रूप में अथवा पार्टी की रीढ़ के रूप में संगठित करने के साथ-साथ क्रांतिकारी किसान कमिटी के नाम से संगठित करें तथा उसके ही नेतृत्व में मूलतः गुप्त, गैरकानूनी व हथियारबंद तौर-तरीके से क्रांतिकारी किसान आन्दोलन और सशस्त्र प्रतिरोध संघर्ष शुरू करें। इसके लिए निम्नलिखित दो बुनियादी नारों सहित अन्य कुछ नारों को जोरदार ढंग से बुलन्द करने को कहा गया था :

दो बुनियादी नारे :

★ (i) सही किसानों के हाथों में जमीन चाहिए और (ii) क्रांतिकारी किसान कमिटी के हाथों में राजनीतिक हुकूमत चाहिए।

अन्य कुछ नारे :

★ गांव-गांव और इलाके-इलाके में क्रांतिकारी किसान कमिटी और आत्मरक्षा व जनमिलिशिया दल और छापामार दस्ते का निर्माण करो।

★ अगर जनता के हाथों में हुकूमत नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है।

आरंभ में इन्हीं नारों के आधार पर जनसमुदाय को क्रांतिकारी राजनीति से जागरूक करते हुए कुछ हद तक सचेतन और प्रत्यक्ष आन्दोलन व क्रांतिकारी किसान संघर्ष में भागीदारी के जरिए परीक्षित लोगों को लेकर गांव-गांव व इलाके-इलाके में सत्ता कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ने हेतु एक संक्रमणकालीन संगठन के बतौर क्रांतिकारी किसान कमिटियाँ गठित करना एवं गांव-गांव व इलाके-इलाके में आत्मरक्षा दल, जनमिलिशिया दल और छापामार दस्ता बनाना ही हमारा प्राथमिक कार्यभार था।

उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार नये सिरे से पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना जिले के और कुछ थाना इलाके में तथा वर्दवान जिला के कांकसा-बुदबुद-आउसग्राम इलाके में हमारे क्रांतिकारी कामकाज को आगे बढ़ाया जाने लगा। कुछ दिनों के अंदर ही क्रांतिकारी किसान संघर्ष का निर्माण हुआ और कुछ नया-नया अनुभव हासिल होने लगा। खासकर, चौबीस परगना के डिही-सोनारपुर इलाके की लड़ाई से शिक्षा लेकर उसे लागू

करने के क्रम में कांकसा–बुदबुद–आउसग्राम इलाके की लड़ाई में एक नया उभार पैदा हुआ और वह पहले की अपेक्षा एक विकसित स्तर के रूप में सामने आया। एम.सी.सी. के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारी किसान संघर्ष तत्कालीन समय में यानी, 1973 से 1976 के काल में (जब आपातकालीन स्थिति का समय था) भारत के क्रांतिकारी किसान संघर्ष पर जब जबरदस्त घेराव–दमन व प्रहार चल रहा है, उस स्थिति में दुश्मन के तमाम आक्रमणों का डटकर सामना करते हुए कांकसा में कृषि क्रांति के झंडे को बुलंद रखने की घटना भारत के क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास में गौरवोज्ज्वल अध्याय के रूप में निश्चित ही चिन्हित रहेगी। जहां तक हमारा अनुभव प्राप्त करने का सवाल है, हम कृषि क्रांति के वास्तविक कामकाज से संबंधित कई बुनियादी विषयों के बारे में [जैसे–जन–लाइन व वर्ग–लाइन को दृढ़तापूर्वक लागू करने का महत्व, भूमिहीन व गरीब किसानों से योग्य कैडर निर्माण करते हुए उन्हें नेतृत्व के स्तर तक विकसित व स्थापित करने का महत्व, पार्टी के विभिन्न स्तरों सहित क्रांतिकारी किसान कमिटियों का गठन व उनकी गतिविधि चलाने का महत्व, फौजी संगठन के निम्नतर रूप से यानी, आत्मरक्षा दल से क्रमशः नियमित गुरिल्ला स्कवाड निर्माण करने का महत्व व तौर–तरीका, विभिन्न क्रांतिकारी जन–संगठनों का निर्माण करने का महत्व आदि के बारे में] बहुत ही सकारात्मक व गहरा अनुभव हासिल करने में समर्थ हुए हैं।

हालांकि दुश्मन के प्रचण्ड आक्रमण के सामने और इलाके के अंदर जितनी राजनीतिक व सांगठनिक (या आत्मगत) तैयारी की जरूरत थी उतनी और गुरिल्ला युद्ध के दाव–पेंच लागू करने हेतु जितना विस्तृत इलाके की जरूरत थी उतना नहीं कर पाने के कारण कांकसा की लड़ाई पीछे हटने को मजबूर हुई। फिर भी, कांकसा की लड़ाई से प्राप्त अनुभव हमारे लिए एक ऐसा आधार बना जिसके बल पर हम बिहार–झारखंड–बंगाल स्पेशल एरिया में कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष को आज के स्तर तक उन्नत करने में सक्षम हुए हैं। इसीलिए हम एम.सी.सी. के नेतृत्व में जारी सशस्त्र संघर्ष के लम्बे दौर के अंदर कांकसा के अनुभव को अपने लिए दूसरी आधारशिला मानते हैं।

इस अनुभव को सार्विक तौर पर और समृद्ध बनाते हुए तथा जिस लाइन और कार्य–पद्धति का हम अनुसरण करते आ रहे थे उसे और दृढ़तापूर्वक अनुसरण करने के दौर से आगे बढ़ते हुए ही संघर्षरत इलाके का विस्तार करने, कृषि–क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए गहन जनाधार विकसित करने, मूलतः भूमिहीन व गरीब किसानों के बीच से स्थानीय नेतृत्व को विकसित करते हुए सेल और एरिया से आरंभ कर ऊपरी स्तर तक पार्टी–संगठनों का संगठनात्मक ढाँचा तैयार करने, आत्मरक्षा दल तथा जन–मिलिशिया दल

से स्थानीय नियमित गुरिल्ला दस्ता और उसके बाद प्लाटून, कम्पनी आदि में फौजी संगठन को विकसित करने एवं पी. एल. जी. ए. के निर्माण की घोषणा करने तथा उसे पी. एल. ए. में विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होने के साथ-साथ क्रांतिकारी किसान कमिटी के स्वरूप को भी गांवों से शुरूकर एरिया व जिला सीमांत और प्रमंडल व राज्य स्तर तक विकसित करते हुए आज की परिस्थिति में छापामार आधार क्षेत्र का निर्माण करने की प्रक्रिया के दौर से इसका क्रांतिकारी राजनीति से लैस, अनुशासनबद्ध व हथियारबंद जनता और उनकी क्रांतिकारी कमिटियों यानी क्रांतिकारी जन कमिटी के रूप में गुणात्मक विकास करने की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। साफ जाहिर है कि मौजूदा समय में बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया सहित अन्य सभी इलाके उपरोक्त प्रक्रिया-पद्धति का दृढ़तापूर्वक लागू करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं।

पार्टी-संगठन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के बारे में

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के सिद्धांत और व्यवहार के दौर से यानी, इसी नीति और शैली से पार्टी संगठन का निर्माण हमारे संगठन के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यभार था। लाइन तो पहले ही तय हो गई पर बाकी रहा व्यवहार का सवाल, जिसे हल करने हेतु विभिन्न स्थानों में कामरेड भेजे गये। व्यवहार का मामला ही एक ऐसा मामला होता है जो यह तय करता है कि सिद्धांत के प्रति कौन कितना समर्पित है अथवा सिद्धांत भी कितना सही है। आज भारतीय क्रांति के लिए सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते से आगे बढ़कर जनफौज व आधार क्षेत्र के गठन-कार्य को पूरा करना और वर्तमान अर्धऔपनिवेशिक-अर्धसामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर नवजनवादी क्रांति सम्पन्न करना ही क्रांति के वर्तमान स्तर का लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए तीन जादूई हथियारों- पार्टी, फौज और संयुक्त मोर्चा का गठन उस लक्ष्य की दिशा में निर्धारित मार्ग पर चलकर ही संभव है। क्रांति के तात्कालिक और आखिरी लक्ष्य के लिए निर्धारित मार्ग पर चले बिना क्रांति के उपादानों का संपोषण, संकेन्द्रण, संप्रसारण और विकास कतई संभव नहीं होता। यह हमारे लम्बे कामकाज के अनुभवों से सुस्पष्ट हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि हमारी राजनीतिक और सैनिक लाइन जो आज से 36 साल पहले निर्धारित की गयी थी, आज भी सही और प्रासंगिक है जिस पर आगे बढ़कर हमने अपने लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप में हासिल किया है और कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट हुआ है कि कथनी में क्रांति की लम्बी-लम्बी बातें करने और सही सिद्धांत को सिर्फ

कथनी में मान लेने के बावजूद व्यवहार में उसे लागू करना यानी, कथनी और करनी में तालमेल बैठाना उतना आसान काम नहीं है। इसलिए सबों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता । अतएव क्रांतिकारी सिद्धांत पर अडिग रहने और उसे व्यवहार में लागू करने के दौर से ही सही क्रांतिकारिता की पहचान बनती है ।

सबों को मालूम है कि कामरेड कन्हाई चटर्जी, कामरेड अमूल्य सेन और कामरेड चन्द्रशेखर दास हमारे संगठन के संस्थापक, नेता व शिक्षक थे और कामरेड कन्हाई चटर्जी ही संगठन के महासचिव थे तथा सिद्धांत, राजनीतिक व सांगठनिक लाइन एवं व्यावहारिक कामकाज में दिशा-निर्देश देते थे। प्रसंगवश हम यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि 1969 में एम. सी. सी. की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद (यानी, नवम्बर 1969 में) इसके संस्थापकों, नेताओं व शिक्षकों में से एक का. चन्द्रशेखर दास की हत्या पं. बंगाल में सी. पी. आई. के गुण्डों ने कर दी । अब का. कन्हाई चटर्जी और का. अमूल्य सेन रह गए। 1978 में दोनों ने सलाह-मशविरा करके बिहार-बंगाल स्पेशल एरिया, पश्चिम बंगाल, असम-त्रिपुरा आदि प्रांतों में कामकाज के दौर से उस वक्त तक के परीक्षित-निरीक्षित लोगों को लेकर सी. सी. को नये सिरे से पुनर्गठित और शक्तिशाली किया। 1981 के मार्च और 1982 की जुलाई में क्रमशः का. अमूल्य सेन और कन्हाई चटर्जी का देहावसान हो गया। उसके बाद उनके द्वारा गठित सी. सी. सैद्धांतिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दिशा-निर्देश करती रही ।

संक्षेप में कहा जाए तो जनफौज व आधार क्षेत्र का निर्माण करने की अवधारणा के आधार पर कामकाज की शुरूआत करने और उसे विकसित करने की अबतक की हमारी यही धारा रही है ।

अब हम पार्टी को मजबूत करने के उपायों के बारे में अवगत करायेंगे ।

रणनीतिक लाइन को कार्यरूप देने के दृष्टिकोण से ही सांगठनिक लाइन व सांगठनिक ढांचे का निर्माण करना जरूरी है

इस बात का पहले ही हमने उल्लेख किया है कि सशस्त्र कृषि-क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए ही हमारे देश की वर्तमान स्तर की क्रांति– नई जनवादी क्रांति सफल होगी। इसके लिए फौज व आधार क्षेत्र निर्माण करने के काम को ही हमने अभी-अभी का बुनियादी, प्रधान, केन्द्रीय कर्तव्य के बतौर तय किया।

सवाल है कि उपरोक्त कार्यभारों को सम्पन्न करने हेतु पार्टी का ढांचा किस प्रकार का होगा? क्या यह रूसी मॉडल के पार्टी ढांचे [जो बगावत की रणनीति के अनुरूप होता है] के अनुरूप होगा अथवा चीनी मॉडल के अनुरूप ? हमारे विवेचन से भारत जैसे देशों में चीनी मॉडल के अनुसार ही पार्टी ढांचा होना चाहिए। इसका मतलब, यहां पार्टी का सांगठनिक ढांचा, मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप (जिला, प्रांत आदि) नहीं, बल्कि युद्ध के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए और युद्ध की जरूरत तथा फौज व आधार क्षेत्र बनाने हेतु चुने हुए [या रणनीतिक क्षेत्र (Strategic Area)] इलाके के अनुरूप स्पेशल एरिया, स्पेशल जोन, जोन, सबजोन, एरिया आदि स्तर के पार्टी संगठनों के रूप में होना चाहिए।

इस दृष्टिकोण के अनुसार ही हम एकदम शुरूआती दौर से ही रणनीतिक क्षेत्र के लिए स्पेशल एरिया कमिटी सहित रीजनल, जोनल, सब जोनल, एरिया, सेल आदि सांगठनिक रूप अमल में लाए हैं। अनुभव हमें बताता है कि स्पेशल एरिया (अथवा स्पेशल जोन) के चिंतन के बिना फौज व आधार क्षेत्र निर्माण करने की बात केवल बात ही में रह जाएगी, कभी भी साकार नहीं हो पाएगी।

उपरोक्त अवधारणा के अनुसार ही 1989 और 1996 में क्रमशः प्रथम व द्वितीय केन्द्रीय सम्मेलन के जरिए जनवादी केन्द्रीयता के नियम के तहत हमारे उच्चतम कमिटी से लेकर सर्वनिम्न स्तर यानी, बुनियादी इकाई तक सिलसिलेवार ढंग से पार्टी ढांचा सजाया गया है। अभी हमारे संगठन की सर्वोच्च कमिटी है केन्द्रीय कमिटी । इसके नीचे क्रमशः स्पेशल एरिया, प्रादेशिक (राज्य), रीजनल [जिसमें तीन-चार जोनल कमिटियां अंतर्भुक्त हैं], जोनल, सबजोनल, एरिया कमिटियां हैं और बुनियादी इकाई (या सर्वनिम्न स्तर) के रूप में सेल है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन (CMC) सहित और कुछ विशेष विभागों की देख-रेख करने वाली कमिटियां मौजूद हैं और एक-एक विशाल इलाके के जिम्मा प्राप्त सी.सी. सदस्यों को लेकर केन्द्रीय रीजनल ब्यूरो गठित करने की योजना कुछ दिन पहले ही ली गई है।

पार्टी के आंतरिक संघर्ष के दौरान सही लाइन की जीत से पार्टी और आगे बढ़ती है

1969 के 20 अक्टूबर में एम.सी.सी. के नाम से हमारे संगठन का परिचय होने के बाद से हमारे संगठन के अंदर पहली बार 1974-75 में एक आंतरिक संघर्ष सम्पन्न हुआ था। यह आंतरिक संघर्ष जिस सवाल को केन्द्र कर सामने आया था, वह था– “अभी के समय में शहर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िये, यहां तक कि सुदूर

देहाती क्षेत्र में भी सशस्त्र संघर्ष चलाते जाने की नीति कितनी सही है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए; एम.सी.सी. की लाइन भी सी.एम. की लाइन जैसी 'वाम' भटकाववादी लाइन है", आदि,आदि।

स्वभावत: इन गलत और संशोधनवादी रूझानवाले चिंतन के विरूद्ध जोरदार राजनीतिक, वैचारिक व सैद्धांतिक संघर्ष हुए और अंत तक जब उक्त गलत लाइन का पूर्ण रूप से राजनीतिक भंडाफोड़ हुआ तो उस लाइन के प्रवक्ता के रूप में इने-गिने दो-चार व्यक्ति संग्राम के मैदान से भाग खड़े हुए और उन्होंने संगठन से खुद को अलग कर लिया । इस आंतरिक संघर्ष के नतीजा से हम कह सकते हैं कि लाइन के तौर पर संगठन के अंदर कोई विभाजन नहीं हुआ, बल्कि संशोधनवादी रूझान रखने वाले लोगों के अलग-थलग हो जाने से संगठन राजनीतिक रूप से पहले की अपेक्षा कुछ ठोस व मजबूत हुआ।

इसके बाद भी हमारे संगठन के अंदर कभी-कभी कुछ सवालों को लेकर वाद-विवाद होता रहा, पर आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, बातचीत और राजनीतिक शिक्षा के जरिए उन सभी वाद-विवादों का हल निकाल लिया गया और संगठन मजबूत बनता गया।

फिर 1999 की अगस्त सी.सी. बैठक से ही 'नेतृत्व के फोटो सजाने का क्रमबद्ध रूप क्या होगा और इसके मार्क्सवादी-लेनिनवादी तौर-तरीके क्या होंगे'- इसे केन्द्रित कर एक बहस सामने आई। यद्यपि कि सी.सी. बैठक के दौरान ही करीब 7 रोज बहस व तर्क-वितर्क के बाद लाइन का निर्धारण करने और उसे व्यवहार में ले जाने में जिनकी देन सबसे ज्यादा है उन्हीं की तस्वीर सबसे पहले आनी चाहिए ऐसा निचोड़ निकलने के जरिए उक्त सवाल का हल निकाल लिया गया और सभी सी.सी. सदस्यों के हस्ताक्षर के जरिए एक लिखित निर्णय (resolution) (यानी कामरेड के.सी. की तस्वीर पहले और उसके बाद कामरेड अमूल्य सेन व कामरेड चन्द्रशेखर दास की तस्वीरें रहेगी जैसा निर्णय) ग्रहण किया गया। पर बाद में उस निर्णय के खिलाफ 'बा' व 'भ' द्वारा गुप्त रूप से पार्टी के अंदर गुटबंदी चलाए जाने की घटना ने प्रमाण किया कि उक्त सवाल का जो हल निकाला गया था उसे वे मानने को तैयार नहीं हुए जिससे दो-लाइन का संघर्ष संचालन करना अनिवार्य हो पड़ा। फिर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर गद्दार तेङ गुट द्वारा माओ-विचारधारा के महत्व को बहुत ही छोटा कर दिखाने और माओ-विचारधारा को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विकसित स्तर के रूप में न दिखाने की करतूत तथा भारत में उसी के चेले लिबरेशन गुट द्वारा माओ विचारधारा के ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय महत्व को पूरे के पूरे नकारने की करतूत बहुत ही स्पष्ट तौर पर सामने आयी। उस समय से ही माओ-विचारधारा की गलत ढंग से व्याख्या करने वालों के साथ एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचने की जरूरत हमारी सी.सी. महसूस कर रही थी। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारी सी.सी. के अंदर कुछ वर्ष पहले

से और करीब 1997-98 से ही 'माओवाद' शब्द (term) को ही माओ-विचारधारा के बदले ग्रहण करना उचित है- ऐसा एक विचार बनता जा रहा था इसकी धारावाहिकता में ही इस बनते हुए विचार को एक ठोस रूप देने हेतु 2000 की जनवरी सी.सी. बैठक में करीब 6 रोज विचार-विमर्श व बहस के दौरान माओ-विचार के विश्लेषण में संशोधनवाद के सर्वाधुनिक रूप के साथ एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए 'माओवाद' शब्द को ही ग्रहण करना सबसे वैज्ञानिक, सही और उचित होगा- ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय सी.सी. द्वारा ग्रहण किया गया। पर, बाद में देखा गया कि इस सवाल पर भी सी.सी. में भारी मतभेद मौजूद है और इसके लिए भी दो-लाइन का संघर्ष अनिवार्य हो पड़ा। साथ ही साथ कामरेड स्तालिन के संबंध में 'महान बहस' के दौरान माओ नेतृत्वाधीन सी.पी.सी. ने जो मूल्यांकन प्रस्तुत किया था, उसी को हमारे संस्थापक व शिक्षक नेताओं ने एवं सी.सी. के स्टैण्ड के रूप में ग्रहण किया। उनके हमसे बिछुड़ जाने के बाद भी उसी स्टैण्ड पर हमारी केन्द्रीय कमिटी खड़ी रही। पर, 'बा'-'भ' गुट स्तालिन के बारे में सी.पी.सी. का वह मूल्यांकन सही है या नहीं, इसपर पुनर्विचार करना चाहिए और नये सिरे से स्तालिन का मूल्यांकन करना चाहिए- यह मांग उठाने लगा और माओवाद का विरोध करने हेतु "जिस कारण से स्तालिनवाद नहीं कहा जाता है, उस कारण से माओवाद भी नहीं कहना चाहिए"- यह कुतर्क पेश करने लगा। काफी बातचीत के बाद भी जब 'बा'-'भ' गुट ने अपने रूप में बदलाव नहीं लाया तब इस विषय पर भी दो लाइन का संघर्ष अनिवार्य हो उठा।

बुनियादी तौर पर उक्त तीन विषयों को लेकर ही हमारे अंदर बहुत तीखा व जोरदार ढंग से दूसरी बार दो-लाइन का संघर्ष शुरू हुआ। बाद में, इन दो विषयों के साथ और दो मुद्दे भी युक्त हो गये । जैसे- (क) एकतरफा ढंग से PW के साथ आपसी झड़प बंद करने और उस पर अमल करने का ऐलान कितना सही है; और (ख) RIM में शामिल होना सही होगा या नहीं।

स्वभावत: 'माओवाद' शब्द को ग्रहण करने के सवाल को केन्द्र में रखते हुए बाकी तीन सवालों पर भी सही व गलत के अंदर एक साफ सीमा रेखा खींचने की जरूरत को देखते हुए 'बा'-'भ' अवसरवादी गुट के विरूद्ध तीव्र व तीखा वाद-विवाद यानी, दो-लाइन का संघर्ष सम्पन्न हुआ। इस दो-लाइन के संघर्ष का नतीजा यह निकला कि सही लाइन की जीत हुई और पश्चिम बंगाल में इने-गिने दो-चार अवसरवादी लोगों को छोड़कर बाकी सभी प्रान्तों के सभी सदस्य हमारे साथ रह गए तथा हम सार्विक रूप से आगे की ओर एक छलांग लगाने में समर्थ हुए। दूसरी तरफ विपरीत पक्ष यानी, 'बा'-'भ' गुट पीछे की ओर छलांग मारते हुए सशस्त्र संघर्ष के मैदान से भाग खड़े होनेवाले और सशस्त्र संघर्ष से कोई रिश्ता न रखनेवाले तथा सशस्त्र संघर्ष के बारे में केवल दुष्प्रचार करनेवाले कुछ

व्यक्तिों के बतौर अध:पतित हुए।

इस दो–लाइन के संघर्ष में जीत हासिल करने के बाद ही हमारी सी.सी. कई कार्यभारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में समर्थ हुई। मिसाल के लिए : (i) सर्वाधुनिक या अत्याधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने हेतु तथा जारी क्रांतिकारी व सशस्त्र वर्ग–संघर्ष को और उन्नत करने हेतु हमारे पथ–प्रदर्शक सैद्धांतिक हथियार को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के रूप में ग्रहण कर उसे और पैना बनाने में हम समर्थ हुए; (ii) राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच्चे माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हम समर्थ हुए; (iii) अपने देश में एम.सी. सी. के नेतृत्व में जारी सशस्त्र संघर्ष ठीक किस चरण में है इसका ठोस विश्लेषण करने में और इसके आधार पर फौज व आधार क्षेत्र बनाने हेतु कुछ ठोस योजना अपनाने में भी हम समर्थ हुए; (iv) हमारी अभी के स्तर की लड़ाई को हमने कृषि–क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध कहा है और उस स्तर के मुताबिक फौजी संगठन को जन मुक्ति छापामार फौज [People's Liberation Guerrilla Army (PLGA)] के रूप में गठित करने में सक्षम हुए हैं; (v) क्रां.कि. कमिटी को आगे बढ़ाते हुए कब क्रांतिकारी जन कमिटी का गठन करना है और किस प्रक्रिया–पद्धति के जरिए करना है आदि पर भी हम अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सक्षम हुए हैं और (vi) एक जादूई हथियार के बतौर संयुक्त मोर्चा के गठन करने की प्रक्रिया–पद्धति को भी आगे बढ़ाने हेतु हम एक कार्य–योजना अपनाने में समर्थ हुए हैं।

उपरोक्त उपलब्धियों को हासिल करने के कारण ही हमने बताया है कि हम आगे की ओर एक छलांग लगाने में सक्षम हुए हैं।

पार्टी संगठन को मजबूत बनाए बिना बुनियादी, प्रधान व फौरी कर्तव्य सहित किसी भी कर्तव्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं है

हम जानते हैं कि क्रांति करने हेतु एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। ऐसी एक पार्टी की जरूरत है जो क्रांतिकारी शैली व पद्धति के जरिए गठित होगी एवं मार्क्सवाद–लेनिनवाद व माओवाद पर आधारित होगी तथा साथ ही साथ अन्य कुछ गुणों से भी लैस होगी। ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। इस विषय पर पहले भी बहुत चर्चा हुई है और आज भी यह चर्चा जारी है। पार्टी स्थिति पर बहस करने हेतु हम केवल उक्त उसूल

संबंधी बातों को ही रटना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी सवालों पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करेंगे जो कि पार्टी को मजबूत करने के सामने समस्या के रूप में खड़े हैं। अतः व्यावहारिक जगह से पार्टी संबंधी बातचीत ही ज्यादा उपयोगी होगी।

वर्तमान समय में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं– फौज व आधार-क्षेत्र का निर्माण करना एवं कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध यानी, लोकयुद्ध का विस्तार करते हुए भारत की नई जनवादी क्रांति को क्रमशः उसकी सफलता की ओर आगे बढ़ाकर ले जाना।

क्या हमारी पार्टी-स्थिति इन कामों को आगे बढ़ाने खातिर उतना चुस्त-दुरूस्त हो पायी है? जवाब है, नहीं। बल्कि सच कहा जाए तो अभी-अभी कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष को तेज व उन्नत करना, ज्यादा संख्या में आत्मरक्षा दल, इलाकाई मिलिशिया स्कवाड तथा स्थानीय नियमित गुरिल्ला स्कवाड व प्लाटून, कम्पनी का निर्माण करना, एक प्रभावकारी संगठन यानी, हुकूमत कायम करने के लक्ष्य के भ्रूण वहनकारी संगठन के रूप में क्रांतिकारी किसान कमिटी को मजबूत बनाना तथा आगे बढ़कर जन सरकार के रूप में क्रांतिकारी जन कमिटी का गठन करना, व्यापक जनता को विभिन्न किस्म के जन-संगठनों के अंदर गोलबंद करते हुए विभिन्न मुद्दों को केन्द्रित कर विशाल-विशाल क्रांतिकारी जन आंदोलनों तथा जन प्रतिरोध आंदोलनों का निर्माण करना और संघर्षरत इलाके का लगातार विस्तार करना आदि कामों को चुस्त-दुरूस्त ढंग से कर पाने हेतु जितने मजबूत पार्टी संगठन की जरूरत है अभी-अभी उतना मजबूत हमारा पार्टी संगठन नहीं हो पाया है।

अतः पार्टी को मजबूत बनाने हेतु निरंतर प्रयास चलाना हमारा फौरी कर्तव्य है।

पेटी-बुर्जुआ विचारधारा तथा इसकी अभिव्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष संचालित करते हुए पार्टी को मजबूत बनावें

चूंकि भारत एक अर्ध औपनिवेशिक व अर्ध सामंतवादी देश है, इसलिए यहां व्यापक संख्या में निम्न पूंजीवादी (अथवा पेटी-बुर्जुआ) लोग मौजूद हैं। हमारी पार्टी में भी कमोबेश इनकी संख्या मौजूद है।

अतः कभी-कभी पेटी-बुर्जुआ विचारधारा की अभिव्यक्ति के रूप में राजनीति में 'वाम' व दक्षिण भटकाव और संगठन में संकीर्णतावाद की झलक दिखाई पड़ रही है।

पेटी बुर्जुआ जीवनधारा की पद्धति चिंतन में मनोगतवाद को जन्म देती है और एकांगीपन के चलते पेटी-बुर्जुवाओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में 'वाम' और दक्षिण के बीच

एक ढुलमुल स्टैण्ड का उदय होता है।

फिर जीवनधारा में सीमाबद्ध स्थिति और आम तौर पर पेटी–बुर्जुआ चिंतन–पद्धति के लिए एवं खासकर, पिछड़ा हुआ और असमान आर्थिक–राजनीतिक व विकेन्द्रित सामाजिक परिवेश तथा सीमित दायरे के अन्दर जीवन बिताने के फलस्वरूप संगठनात्मक जीवन में भी पेटी–बुर्जुआ लोगों का व्यक्तिवाद और संकीर्णतावाद में जकड़ जाना आदि जैसी आदतों के चलते पेटी–बुर्जुआ (या निम्न पूंजीपति) वर्ग के लोग आम जनता से अलग–थलग रह जाते हैं। यह रूझान जब पार्टी में प्रतिबिम्बित होता है, तब अक्सर नौकरशाही, पितृसत्तात्मक हुक्मवाद, व्यक्तिवाद, हीरोवाद, आधा अराजकतावाद, उदारतावाद, अतिजनवाद, अपने आदमी के प्रति पक्षतापूर्ण रवैया, गुटबंदी आदि मनोभाव पैदा होता है। इसके चलते एक ओर जनता के साथ पार्टी के रिश्ते में खाई बढ़ती है और दूसरी ओर, पार्टी की आंतरिक एकता बर्बाद होती है।

ये हैं पेटी–बुर्जुआ विचारधारा के तीन खतरनाक पहलू। विचारधारा में मनोगतवाद, राजनीति में 'वाम' और दक्षिण भटकाव एवं संगठन में संकीर्णतावाद ये सब कुछ ही कमोबेश हमारे संगठन के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं। निश्चित तौर पर ये सभी चीजें मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद विरोधी हैं एवं पेटी–बुर्जुआ विचारधारा की अभिव्यक्तियां हैं।

पार्टी और जनता के स्वार्थ में पार्टी के अंदर पेटी–बुर्जुआ विचारधारात्मक अवरोध ों को दूर हटाने के लिए तथा पार्टी को सर्वहारा विचारधारा से लैस करने हेतु शिक्षा की पद्धति को अमल में लाना बहुत ही जरूरी है।

पार्टी में जनवादी केन्द्रीयता और नेतृत्व की सही पद्धति को दृढ़तापूर्वक लागू रखें

कामरेड माओ–त्सेतुङ ने कहा, "जनता से लो और जनता को वापस लौटा दो"– यही होनी चाहिए एक सही राजनीतिक लाइन। इस लाइन को अगर सचमुच जनता से आना है और खासकर जनता के पास पहुंचा देना है तब केवल पार्टी और पार्टी के बाहर की जनता के साथ (वर्ग और जनता के बीच) घनिष्ट संबंध रहने से ही नहीं चलेगा, बल्कि सर्वोपरि पार्टी की नेतृत्वकारी संस्था और पार्टी सदस्यों के बीच [संगठनकर्ता (organiser) कैडर और आम कार्यकर्ता के बीच] भी घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; दूसरे अर्थों में, एक सही संगठनात्मक नीति अवश्य ही रहनी चाहिए।

हमें भी इस नीति को अवश्य ही अमल में लाना है। कठिन स्थिति के अंदर भी इस नियम को लागू करने में निपुण होना होगा।

सभी कामरेड जानते हैं कि हमारी पार्टी सशस्त्र संघर्षरत एक गुप्त पार्टी है। हम पर दुश्मन की 'घेराव व दमन' मुहिम सहित चौतरफा हमले जारी हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी यदि कठोर रूप से गुप्त पार्टी नहीं हो, तो दुश्मन के हर हमले का मुकाबला करते हुए सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। स्वभावतः ऐसी एक गुप्त पार्टी में जनवादी केन्द्रीयता के सारे नियमों को लागू कर पाना वास्तविक तौर पर कुछ मुश्किल-सा काम है। खासकर, दुश्मन के अत्यधिक हमले चलते रहने के कारण, जनवाद को विस्तृतरूप से लागू करने के मामले में कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। फिर भी अभी के समय में जहां तक संभव हो, वहां तक "जनता से लेकर जनता को लौटा देने" की नीति के साथ-साथ पार्टी और पार्टी के बाहर की जनता के साथ एवं नेतृत्वकारी संस्था और कैडर व आम कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रखने आदि जनवाद के नियमों को लागू करना ही होगा। खासकर, पार्टी के संविधान के मुताबिक तमाम पार्टी कमिटियों का सम्मेलन बुलाकर प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के जरिए ही पार्टी कमिटी का निर्माण करना होगा, कभी-कभी किसी विशेष मुद्दों पर वरिष्ठ कामरेडों को लेकर प्लेनम भी बुलाई जा सकती है। इसी तरह परिस्थिति के अनुसार जहां तक संभव हो, जनवाद को लागू रखने की कोशिश जारी रखनी होगी।

और, जहां तक केन्द्रीयता का सवाल है, यह केन्द्रीयता जनवाद पर आधारित केन्द्रीयता होगी। अनुभव बताता है कि यदि पार्टी की केन्द्रीय कमिटी से लेकर अन्यान्य नेतृत्वकारी संस्थाएं लड़ाई के मैदान से तथा उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई रहती हैं तब केन्द्रीयता और जनवाद के बीच का सही अंतरसंबंध सजीव ढंग से लागू हो सकता है, अन्यथा केन्द्रीयता के नाम पर नौकरशाही या फरमानशाही का तरीका अथवा जनवाद के नाम पर अव्यवस्थित या स्वयंस्फूर्त्त तौर-तरीका लागू हो जाएगा।

अतएव परिस्थिति के अनुसार पार्टी के अन्दर ठोस व सजीव रूप से जनवाद और केन्द्रीयता के बीच के सटीक संबंध को लागू रखने की हर चन्द कोशिश करनी होगी।

फिर, वास्तविक काम-काजों के साथ जुड़कर कामरेड माओ द्वारा निर्देशित नेतृत्व की पद्धति को अमल में लाने की कोशिश करनी होगी। नेतृत्व का काम केवल फरमान जारी करना ही नहीं है, बल्कि वास्तविक समस्याओं से जूझ रहे कामरेडों को उनकी समस्याओं का हल करने में मदद करना भी है।

अतएव नेतृत्व की सही पद्धति को अमल में लाते हुए पार्टी संगठन के अंदर

जनवादी केन्द्रीयता के सारे नियमों को सजीव रूप से लागू करना ही पार्टी को शक्तिशाली करने का एक प्रमुख उपाय है।

पार्टी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक स्तर को उन्नत किए बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती

सभी को मालूम है कि माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के नेतृत्व में कुछ प्रांतों में क्रांतिकारी कामकाज जारी है तथा तीन-चार प्रांतों में क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष जोरों पर है।

हमारी केन्द्रीय कमिटी और उसके तहत बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी, उत्तरी बिहार-यू.पी.-उत्तराखंड स्पेशल एरिया कमिटी, लोअर (lower) असम जोनल कमिटी, प. बंगाल प्रादेशिक कमिटी, पंजाब राज्य कमिटी, उड़ीसा राज्य सांगठनिक कमिटी आदि कमिटियां मूलतः क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष का नेतृत्व दे रही हैं। इसके अलावा यू.पी. व राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हमारी कुछ जोनल स्तर और एरिया स्तर की कमिटियां कार्यरत हैं।

सभी जगहों को लेकर अभी माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के अंतर्गत कुल मिलाकर करीब .... हजार पार्टी सदस्य कार्यरत हैं। इसमें 70 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमिहीन व गरीब किसान से, लगभग 15 प्रतिशत मध्यम किसान से, लगभग 2 प्रतिशत धनी किसान से, लगभग 5 प्रतिशत मजदूर वर्ग से और लगभग 8 प्रतिशत निम्न पूंजीपति (पेटी-बुर्जुआ) वर्ग से हैं। फिर हमारे पार्टी सदस्यों के एक बड़ा भाग ही है आदिवासी व दलित।

निश्चित तौर पर वर्ग लाइन के दृष्टिकोण से विचार करने से यह एक सकारात्मक पहलू है। इस पहलू को हमें अवश्य ही भविष्य में भी बरकरार रखना होगा क्योंकि वर्ग लाइन पर अडिग रहे बिना हम क्रांति में सफल नहीं हो सकते।

लेकिन हमारे सामने वास्तविक समस्या यह है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता भूमिहीन व गरीब किसान घर से आने के कारण तथा आदिवासी व दलित होने के कारण आम तौर पर अनपढ़ हैं। इसके चलते किताबों के अध्ययन के जरिए ज्ञान हासिल करना उनके लिए बहुत ही कठिन काम है, दूसरी ओर, पार्टी में बुद्धिजीवी पेशेवर साथियों की संख्या भी जरूरत की अपेक्षा कम है। इसकी वजह से व्यापक मजदूर-किसान कार्यकर्ताओं को मार्क्सवादी शिक्षा व पार्टी शिक्षा से शिक्षित करने का काम एक समस्या के बतौर खड़ा है। फिर संघर्ष के इलाके में लगातार 'घेराव व दमन' मुहिम जारी रहने की वजह से ज्यादा पार्टी क्लास का आयोजन करना भी कुछ मुश्किल सा नजर आ रहा है। इन तमाम कारणों

के चलते आम कार्यकर्ताओं का राजनीतिक स्तर वर्ग-संघर्ष की ठोस स्थिति के साथ तालमेल पूर्ण ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फलस्वरूप संघर्ष आगे बढ़ गया और संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी कुछ पीछे पड़ गई ऐसा लगता है। जल्द से जल्द इस खाई को पाट लेना जरूरी है और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक स्तर को उन्नत करके ही इस खाई को पाटा जा सकता है। अत: पार्टी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक मान को उन्नत करने हेतु कुछ ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। जैसे- (i) एक-एक प्रांत की मूल नेतृत्वकारी कमिटी द्वारा वहां की स्थिति के मुताबिक वरिष्ठ और आम कार्यकर्ताओं के बीच अलग-अलग पाठ्यक्रम तय करते हुए पार्टी स्कूल का आयोजन किया जाए; (ii) पार्टी स्कूल के संचालन के लिए पहले से ही विषयों का निर्धारण किया जाए और कौन साथी किस विषय पर क्लास लेंगे उसे भी तय किया जाय; (iii) पाठ्यसूची के अंदर मार्क्सवाद के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ आम कार्यकर्ताओं के लिए सा2ाारण भूगोल, इतिहास व विज्ञान के बारे में भी कुछ रहना चाहिए; (iv) एक-एक बार कम से कम कई रोज के लिए पार्टी स्कूल चलाना चाहिए। फिर केन्द्रीय कमिटी की देख-रेख में चुने हुए कामरेडों को लेकर विशेष पार्टी क्लास का आयोजन करना बहुत ही जरूरी है और (v) आज की परिस्थिति में चलायमान पार्टी क्लास का संचालन करने पर विशेष जोर देना होगा। चुने हुए कामरेडों के साथ इस उद्देश्य से पार्टी क्लास लेना चाहिए ताकि वे इस क्लास से जाने के बाद स्वयं दूसरे कामरेडों को लेकर क्लास ले सकें। केन्द्रीय कमिटी की देख-रेख में और एक किस्म के क्लास का आयोजन करना आज के समय में नितांत जरूरी हो गया है, वह है, ऑल इंडिया स्तर के जन संगठनों सहित तमाम जन संगठनों के वरिष्ठ साथियों को लेकर क्लास का आयोजन करना। इस क्लास में कुछ उन्नत विषयों और लाइन व कार्यशैली संबंधी बिन्दुओं पर बहस होनी चाहिए।

फिर समूची पार्टी के राजनीतिक स्तर को उन्नत करने हेतु उच्चतर कमिटी से लेकर उच्चतम कमिटी के कामरेडों को चाहिए कि वे अपने राजनीतिक स्तर को अधिकाधिक उन्नत करने हेतु विशेष ध्यान दें। केवल अनुभव पर ही निर्भर न रहकर आज की स्थिति में भ्रांति पैदा करने वाली विभिन्न सैद्धांतिक व राजनीतिक लाइन को नेस्तानाबूद करने हेतु महान शिक्षकों के प्रासंगिक लेखों का व्यक्तिगत व सामूहिक अध्ययन करें। इसके बिना आधुनिक संशोधनवादियों का सैद्धांतिक पैंतरों को परास्त कर क्रांतिकारी विचारधारा को हम फौलादी नहीं बना पायेंगे।

इन तमाम कामों को ठीक-ठीक कर पाने से अभी की स्थिति में पार्टी को कुछ हद तक मजबूत करना संभव है।

लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के मामले में हमारे अंदर कुछ खामियां

मौजूद हैं : पहला, कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने की समस्या गंभीर होने के बावजूद कुछ नेतृत्वकारी पार्टी कमिटियां इसके प्रति उतनी गंभीर नहीं हैं; दूसरा, कभी-कभार कुछ पार्टी क्लास चलने से भी उसकी धारावाहिकता नहीं रहती है; तीसरा, पार्टी के विभिन्न स्तरों में हो अथवा स्कवाड के अंदर, हर जगह ही हर समय जानकारी हासिल करने की दृष्टि से कुछ न कुछ विषयों को लेकर चर्चा करते रहने की शैली का अभाव।

अगर हम सचमुच पार्टी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक स्तर को उन्नत करना चाहते हैं, तो हमें इस विषय पर अवश्य ही गंभीर होना होगा तथा पार्टी के हर स्तर में और स्कवाड के अंदर जानकारी हासिल करने खातिर कुछ न कुछ चर्चा चलानी होगी और एक राजनीतिक वातावरण पैदा करना होगा एवं धारावाहिक रूप से पार्टी शिक्षा के लिए क्लास चलाते जाना होगा।

हमें याद रखना होगा कि आम कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक-राजनीतिक स्तर के उन्नत नहीं होने से संशोधनवाद के खिलाफ खासकर सी.पी.आई., सी.पी.एम. व लिबरेशन सहित दूसरी गलत लाइनों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष चलाने में हम अक्षम साबित होंगे एवं पार्टी में विभिन्न तरह के गलत रूझान और गलत कामकाज की शैली व पद्धति पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। हमें याद रखना होगा कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों पहलुओं की ओर से कुछ योग्य कैडर नहीं बना पाने से हम पार्टी, फौज, क्रा.कि. कमिटी, जन संगठन या संयुक्त मोर्चा आदि एक भी चीज को ठीक ढंग से गठन व संचालन नहीं कर पायेंगे। ताकि ऐसा न हो, इसकी गारंटी करने हेतु आम कार्यकर्ताओं के राजनीतिक स्तर को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस काम पर ढिलाई बरतना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा।

विभिन्न प्रांतों में हमारी पार्टी की स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय

विभिन्न प्रांतों में हमारी स्थिति निम्न प्रकार है :

(i) **बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी** – पहले बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया चुने हुए विभिन्न इलाकों में दूसरे नम्बर पर था। किन्तु जब पूर्वोत्तर की तत्कालीन संभावनाएं टल गईं तो यही इलाका प्रमुख बन गया। तत्कालीन बिहार (आज के झारखंड समेत) के एक हिस्से, खासकर गंगा नदी के दक्षिणी भाग को और पश्चिम बंगाल के कई जिलों– जैसे झारखंड से सटे हुए मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरूलिया के पश्चिमी छोर एवं बीरभूम व बर्दवान के एक छोटे से अंश को इस स्पेशल एरिया में शामिल किया

गया। स्पेशल एरिया के इस इलाके को कई भागों में विभाजित कर कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। चुने हुए इलाके की भौगोलिक बनावट गुरिल्ला लड़ाई के संचालन के दृष्टिकोण से काफी अनुकूल है। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भी है। लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। झारखंड इलाके को केन्द्र मानकर आधार क्षेत्र बनाने, उसके चारों ओर विशाल इलाका लेकर [जिसमें मध्य बिहार का विशाल मैदानी इलाका भी शामिल है] छापामार लड़ाई का इलाका तैयार करने तथा उसे विकसित करने की तत्कालीन अवधारणा के अनुसार ही इस स्पेशल एरिया का निर्धारण हुआ है। तत्कालीन परिस्थिति में हमारे नेताओं की अवधारणा और उनकी दूरदृष्टि की ठोस मिसाल है– सही इलाका चयन, ठीक ढंग से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और संशोधनवाद के साथ सुस्पष्ट रूप से विभाजन-रेखा खींचकर आन्दोलन व संघर्ष का निर्माण करने की शिक्षा से कार्यकर्ताओं को लैस करना आदि। प्रायः सभी इलाके में नियुक्त कार्यकर्ताओं ने संघर्ष-निर्माण की दिशा में स्वतंत्र पहल से कामकाज शुरू किया। हर इलाका उतार-चढ़ाव के विभिन्न दौर से गुजरा।

आखिरकार लम्बे समय तक कृषि-क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष को लगातार जारी रखने के क्रम में यहाँ ऊपर से नीचे तक, यानी स्पेशल एरिया कमिटी से शुरूकर नीचे की एरिया कमिटी व पार्टी सेल तक विभिन्न स्तर की कमिटियों यथा, सबजोनल कमिटियों, जोनल कमिटियों व रीजनल कमिटियों को गठित किया गया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने और आसपास के इलाकों में फैलने के क्रम में बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया सिर्फ इन राज्यों और पहले के चुने गये कुछ इलाकों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने इलाकागत रूप से झारखंड और दक्षिण बिहार के प्रायः तमाम जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में भी अच्छा संगठनात्मक आधार विकसित कर लिया है।

कुल मिलाकर एक छापामार क्षेत्र से होते हुए आधार इलाके का व जन सेना का निर्माण करने के हमारे बुनियादी, प्रधान व फौरी कार्य के मद्देनजर इस स्पेशल एरिया कमिटी के पूरे क्षेत्रों में हमारा कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध पहले तो सामंतों और उसकी निजी सेनाओं के हमलों को चकनाचूर करते हुए तथा उन्हें धराशायी करते हुए आगे बढ़ा। खासकर, कृषि-क्रांति की लाल आग में सामंतों की जात-पांत पर आधारित निजी सेना जैसे– ब्रह्मर्षि सेना, सनलाईट सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रण्ट, भूमिसेना आदि प्रतिक्रांतिकारी सेनाओं की कमर तोड़ने तथा उन्हें जला डालने की यानी, दलेलचक-बघौरा और बारा (बिहार) व खुखरा (झारखंड) जैसे प्रतिक्रांतिकारी अड्डे स्थलों पर क्रमशः मई 1987, फरवरी 1992 और मई 1992 में हजारों किसान जनता द्वारा जबरदस्त हमला करने की

शानदार कार्रवाई जारी क्रांतिकारी संघर्ष की एक विशेषता के बतौर उभर कर सामने आयी। साथ ही कुछ वर्ष पहले से ही सभी जाति के सामंतों की सम्मिलित सेना के रूप में गठित रणवीर सेना को चकनाचूर करने का संघर्ष तो अभी जोरदार ढंग से जारी है। खासकर, सेनारी (जो रणवीर सेना का अड्डा स्थल था) पर क्रांतिकारी जनता द्वारा जबरदस्त चोट पहुंचाना– उसी की ही एक शानदार मिसाल है।

फिर राज्य–मशीनरी के, उसकी पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के निरंतर जारी एक–पर–एक क्रूर व भारी–भरकम घेराव–दमन मुहिमों के खिलाफ लड़ते हुए तथा उन्हें नाकाम करते हुए ही हमें आज की ठोस उपलब्धियां हासिल हो पाई हैं। ऐसी स्थिति की पृष्ठभूमि में बिहार–झारखंड–बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी के चौथे सम्मेलन के बाद में आयोजित दूसरी बैठक के दौरान हमने संघर्ष ठीक किस स्तर पर है और उससे संबंधित तमाम पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार–विश्लेषण किया। इस विचार–विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि बिहार–झारखंड–बंगाल स्पेशल एरिया के अंतर्गत 80–85 प्रतिशत इलाका अभी छापामार इलाके के स्तर में पहुंच गया है और इस स्थिति में अगले महत्वपूर्ण कार्यभारों का भी तय किया। इन कार्यभारों का केन्द्रबिन्दु छापामार इलाके को कैसे आधार इलाके में जल्द से जल्द परिवर्तित किया जाए, यही रहा। कामरेड माओ द्वारा दर्शायी गयी छापामार युद्ध की पूरी रणनीति व कार्यनीति को खासकर, 'दुश्मन की घेरेबंदी के खिलाफ जवाबी घेरेबंदी' की नीति को हमने यहां की ठोस परिस्थिति में लागू किया है और कर रही हैं। वह हमारे लिए बेहद कारगर साबित हुई है और हो रही है।

यह बात निस्संदेह कही जा सकती है कि भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के अन्तर्गत तमाम स्तर की कमिटियों के अंदर बिहार–झारखंड–बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी के नेतृत्व में प्रचण्ड तात्पर्यपूर्ण बिहार–झारखंड का क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष यानी, कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष ही हमारे संगठन के नेतृत्व में जारी लड़ाई के अंदर सबसे अगुआ भूमिका निभा रहा है। दरअसल बिहार व झारखंड का आर्थिक–सामाजिक ढांचा तथा सामंती शोषण और उत्पीड़न की पृष्ठभूमि ही बिहार व झारखंड को वर्ग–संघर्ष के मैदान में सबसे अगुआ भूमिका निभाने खातिर ढकेल दी है। साथ ही कई साल पहले जब उत्तरी बिहार को एक विशेष इलाके के बतौर निर्मित करने का निर्णय लिया गया और 2–3 वर्ष पहले जब उत्तरी बिहार–उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड स्पेशल एरिया का विधिवत गठन हो गया तब से उस कमिटी के नेतृत्व में भी तीखा क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष हमारे संगठन के नेतृत्व में जारी लड़ाई का और एक प्रमुख स्थान बन गया है। सच कहा जाए तो लम्बे समय से बिहार में जमींदारों और उनकी निजी सेनाओं द्वारा दबे–कुचले गरीबों पर चले आ रहे एकतरफा आक्रमण के विरूद्ध बिहार व झारखंड की वीर किसान जनता और वीर कामरेडों

ने जवाबी जन-कार्रवाई का एक ऐसा सही रास्ता खोल दिया, जिसके जरिए एकतरफा आक्रमण का उचित मुकाबला संभव हुआ है। इस जवाबी जन-कार्रवाई की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया गया है। इसके साथ-साथ सामंतों के खिलाफ लड़ते हुए जोतदारों-जमींदारों की हजारों-हजार एकड़ (लगभग .... एकड़) जमीन जब्त करने जैसी भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं।

साथ ही अपनी स्वतंत्र पहल और स्वतंत्र कार्यक्रम के आधार पर तथा आदिवासी जनता सहित गैर-आदिवासी जनता के अंदर एम.सी.सी. की जड़ को मजबूत बनाकर कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ-साथ वर्ग संघर्ष की दिशा से लैस एवं झारखंड को लालखण्ड में बदल डालो के लक्ष्य पर आधारित राष्ट्रीयता आंदोलन को आगे बढ़ाना तथा इसमें हजारों-हजार आदिवासी जनता सहित गैर-आदिवासी जनता को भी शामिल कर पाना झारखंड के पूरे इलाके सहित बंगाल के मेदिनीपुर, बाँकुड़ा व पुरूलिया इलाके में जारी वर्ग-संघर्ष की खास विशेषता है।

बिहार-झारखंड-बंगाल के विशेष इलाके में नेतृत्वकारी पार्टी संस्था है बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी। इस कमिटी के नेतृत्व में लड़ाई का क्षेत्र क्रमागत विस्तार होकर बिहार से सटे यू.पी. एवं झारखंड से सटे हुए छत्तीसगढ़ में और कुछ हद तक उड़ीसा में फैल गया है।

फिलहाल बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी के अधीन दो रीजनल कमिटियाँ हैं । ये हैं-(1) बिहार-झारखंड-उत्तर प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमांत रीजनल कमिटी जिसे आम तौर पर बिहार रीजनल कमिटी कहा जाता है और (2) झारखंड-बिहार-बंगाल-उड़ीसा सीमांत रीजनल कमिटी जिसे आम तौर पर झारखण्ड रीजनल कमिटी कहा जाता है। फिर इन दोनों रीजनल कमिटियों के नीचे चार-चार जोनल कमिटियाँ हैं । बिहार रीजनल कमिटी के अंतर्गत हैं-

(क) उत्तरी जोनल कमिटी

(ख) दक्षिणी जोनल कमिटी

(ग) बिहार-यू.पी. सीमांत जोनल कमिटी
यानी, सोन-गंगा-विध्यांचल जोनल कमिटी

(घ) छत्तीसगढ़-झारखंड सीमांत जोनल कमिटी

और झारखंड रीजनल कमिटी के अंतर्गत हैं-

(क) उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमिटी

(ख) दक्षिणी छोटानागपुर जोनल कमिटी

(ग) बांका–जमुई–भागलपुर जोनल कमिटी

(घ) मेदिनीपुर–बाँकुड़ा–पूरूलिया जोनल कमिटी

हर जोनल कमिटी के नीचे पाँच से सात सबजोनल कमिटियाँ तथा प्रत्येक सबजोनल कमिटी के अधीन 3 से 6 एरिया कमिटियां कार्यरत हैं। इसके नीचे पार्टी सेल है। इस स्पेशल एरिया में लगभग .... पार्टी–सदस्य हैं, जिसमें 70 प्रतिशत से ऊपर भूमिहीन व गरीब किसान वर्ग से आए हुए सदस्य हैं और महिला पार्टी सदस्यों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है। जहां तक महिलाओं को हर तरह से आगे बढ़ाने का सवाल है, हमारे लिए महिला पार्टी सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु विशेष पहल लेने की आवश्यकता है।

लगभग.....लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और लगभग 8 करोड़ लोगों को नेतृत्व प्रदान करनेवाली यह S.A.C. आज की परिस्थिति में राजसत्ता के साथ मुख्य रूप से संघर्ष में उतरी है। ऐसे में और ज्यादा पार्टी–सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पेशेवर के साथ–साथ गैर–पेशेवरों को भी पार्टी–सदस्यता देने तथा गांव स्तर में और पेशागत स्तर में पार्टी कमिटियों का गठन करने पर हमें विशेष बल देना चाहिए। हालांकि तमाम नेतृत्वकारी कमिटियां पेशेवर कार्यकर्ताओं को लेकर अवश्य ही गठित करनी होगी– इस पॉलिसी पर अडिग रहने के सवाल पर हमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या इस S.A.C. के लिए यह है कि शहरों में पर्याप्त ढंग से पार्टी और संघर्ष–निर्माण के सवाल को मजबूती से नहीं पकड़ा गया है। ऐसा किये बिना हम आज की स्थिति में प्रतिक्रांति से लोहा लेने में सक्षम नहीं हो पायेंगे। अत: हमें अविलम्ब शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत पार्टी आधार बनाने के काम को आगे बढ़ाना होगा।

साथ ही संघर्ष के विस्तार और जरूरत को देखते हुए सी.सी. ने 2002 के अंत में ही निर्णय लिया था कि बिहार रीजन के छत्तीसगढ़–झारखंड सीमांत जोनल कमिटी के अंतर्गत इलाके को संघर्ष के एक अलग स्वयंसंपूर्ण इलाके के बतौर विकसित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सी.सी. की ओर से कुछ ठोस योजना भी ली गई है। इस योजना के अनुसार ही अभी इस जोन का कामकाज व संघर्ष आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी इस जोन को एक अलग स्पेशल जोन के रूप में गठित नहीं किया जा सका है

उत्तरी बिहार–उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड नामक और एक स्पेशल एरिया का गठन भारतीय क्रांति के विकास हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है

सबों को मालूम है कि हमने फौज व लाल आधार क्षेत्र निर्माण करने के दृष्टिकोण से एक स्पेशल एरिया के बतौर बिहार–बंगाल [जो अभी बिहार–झारखंड–बंगाल] स्पेशल एरिया को चुन लिया था। उस समय दक्षिण बिहार में ही ज्यादा कामकाज व संघर्ष आगे बढ़ा। बाद में 1983 से उत्तरी बिहार में भी कामकाज और संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना ली गई। उस योजना को साकार करने के क्रम में आज उत्तरी बिहार का पूर्वी, मध्य व पश्चिमी भाग कृषि–क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष के एक बड़ा इलाके के रूप में उभर आया है। हाल में सेकेण्ड सी.सी. के साथ विलय के बाद हमारी शक्ति में खासकर (उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में) अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब उत्तरी बिहार के पूर्वी हिस्सा का करीब–करीब पूरा क्षेत्र ही हमारे कामकाज के दायरे के अंदर आ गया।

विगत कई सालों से उत्तरी बिहार में खूंखार व बड़े–बड़े सामंत प्रभुओं के खिलाफ व्यापक व तीव्र कृषि–क्रांतिकारी संघर्ष अभी और तेज होता दिखाई पड़ रहा है। बड़े भूस्वामियों से हजारों एकड़ जमीन सहित अनेकों तालाब व सैकड़ो बगीचे आदि जप्त किये गये हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान फौजी संगठन के रूप में आत्मरक्षा दल, इलाकाई मिलिशिया दल और LRGS का गठन किया गया है और अभी फौजी फारमेशनों को प्लाटून के स्तर में उन्नत करने का निर्णय लिया गया है तथा इसी बीच एक प्लाटून का गठन किया गया है। उत्तर बिहार में भी खूंखार जमींदारों के घर पर हमला करते हुए उनके हथियार सहित सबकुछ जप्त करने के कार्यक्रम किये गए हैं इसके साथ ही साथ पुलिस जुल्म के खिलाफ विगत 2003 की 15 जुलाई को आयोजित तिरहुत–मिथला बंद अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है। साथ ही और कुछ महत्वपूर्ण रेड व एम्बुश जैसे कार्यक्रम अपनाए गये हैं। फिलहाल जुलाई, 2004 में सिमरहनी पुलिस कैंप पर रेड करते हुए तमाम हथियार आदि जप्त करने और सभी पुलिसवालों को आत्मसमर्पण करवाने जैसी उज्ज्वल लड़ाई हुई है। साथ ही क्रां.कि.क. के विभिन्न स्तरों का गठन किया गया है तथा महिला, छात्र–युवा, बुद्धिजीवी व सांस्कृतिक फ्रण्ट को मजबूत बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावे, उत्तरी बिहार की एक बुनियादी समस्या यानी बाढ़–सुखाड़ व जलजमाव की समस्या लेकर भी एक मंच टाइप का संगठन बनाया गया है और कुछ कार्यक्रम भी लिया जा रहा है।

फिर दूसरे केन्द्रीय सम्मेलन (1996) के समय से हमने भारत के अन्य कुछ क्षेत्रों में अपने कामकाज के विस्तार हेतु एक योजना अपनाई। उसी योजना के अनुसार हमने जब उत्तराखण्ड में काम शुरू किया तो उसके खास रणनीतिक महत्व की बात हमारे दिमाग में थी तथा शुरू से ही वहां हमने एक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य से काम करना शुरू किया। उत्तराखण्ड के कुछेक हिस्सों (खासकर कूमांयू क्षेत्र) में कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसी समय उत्तराखण्ड में कुछ सक्रिय कामरेड, जो लोग पहले सेन्ट्रल टीम के साथ जुड़े हुए थे, एम.सी.सी.आई. में शामिल हो गए। तब कुछ जिलों को चुनकर [जहां संघर्ष उठाने और उसे टिकाकर रखने की संभावना ज्यादा है] वहां कामकाज को आगे बढ़ाते हुए और फौज व आधारक्षेत्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघर्ष के निर्माण हेतु एक ठोस योजना अपनाई गई। उसी योजना के अनुसार कामकाज का विकास व विस्तार होने लगा और कुछ छोटे-मोटे संघर्ष का कार्यक्रम भी अपनाया गया। प्रचार, संग्राम व संगठन– इन तीनों प्रक्रिया के अंदर से गुजरते हुए आज कुछ पार्टी सेल से आरंभ कर एरिया, सबजोन और एक जोनल कमिटी का गठन हुआ। फिलहाल जून, 2004 में बहुत ही जोश खरोश के साथ उक्त जोनल कमिटी का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ। पार्टी के विभिन्न स्तरों के अलावा वहां एक नियमित गुरिल्ला स्कवाड यानी, LRGS का गठन किया गया। कुछ गांवों में और कुछ इलाके के आधार पर "वन, खनन और जमीन पर जनता का अधिकार तथा किसान कमेटियों के हाथों में सारी राजनीतिक हुकूमत" – के नारे को लेकर क्रांतिकारी किसान कमेटियों का भी गठन हुआ। इसके साथ-साथ छात्र-युवा संगठन और एक सांस्कृतिक संगठन भी मौजूद हैं तथा महिलाओं के बीच भी कामकाज जारी है। फिलहाल इलाके को और ठोस बनाने और पहले की अपेक्षा उन्नत स्तर की कुछ लड़ाई लड़ने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कामकाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच दमन की तीव्रता बढ़ी है, फलतः हमारी आत्मगत शक्तियों का कुछ नुकसान भी हुआ है।

इसी बीच, उत्तरी बिहार से ही उत्तरी बिहार के सटे हुए यू.पी. के इलाके में भी [यानी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया आदि] कामकाज और लड़ाई का विस्तार होने लगा। आगे बढ़कर लखिमपुर-खीरी इलाके का संपर्क भी मिलने लगा। उधर उत्तराखण्ड से भी पिलीभीत क्षेत्र में कुछ संपर्क मिले और कामकाज शुरू किया गया।

ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय कमिटी ने उत्तरी बिहार, उत्तरी यू.पी. और उत्तराखण्ड के कामकाज और लड़ाई की प्रगति तथा उक्त पूरे क्षेत्र में फौज व आधार इलाके के बनने की संभावना– इन सभी विषयों पर समीक्षा की और सर्वसम्मत रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची कि अब भारतीय क्रांति के समग्र स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्षेत्र को (यानी उत्तरी बिहार, उत्तरी यू.पी., उत्तराखण्ड क्षेत्र को) कामकाज के एक स्पेशल

एरिया के रूप में आगे बढ़ाना होगा। इस स्पेशल एरिया की विशेषताएं ये हैं : (i) ज्यादातर हिस्से में तीखा वर्ग विरोध मौजूद है, इसीलिए वर्ग–संघर्ष तेजी से फैल सकता है, (ii) यह इलाका विशाल आबादी से भरा हुआ एवं भारत की राजनीति में प्रभाव डालने वाला एक ऐसा इलाका है, जहां सशस्त्र क्रांति की लहर उठा पाने से भारत के मध्य व उत्तरे तथा कुछ हद तक पूर्वी हिस्से में भी इसका जबरदस्त असर होगा, (iii) यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है और नेपाल के उस हिस्से से सटा हुआ है जहां सी.पी.एन. (माओवादी) के नेतृत्व में घमासान लोकयुद्ध जारी है।

हालांकि 3-U स्पेशल एरिया के अंतर्गत पूरे क्षेत्र को अभी भी मिलाकर एकाकार नहीं किया जा सका है। इसीलिए इस पर ध्यान केन्द्रित करना और पूरे क्षेत्र को एक निश्चित समय सीमा के अंदर मिला देने के लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ प्रयास करना होगा।

इस स्पेशल एरिया की उत्तरी बिहार जोनल कमिटी के अंतर्गत के इलाके में कामकाज व लड़ाई के व्यापक विस्तार को देखते हुए उस क्षेत्र को [यानी, उ.बिहार के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर को पार करते हुए उससे सटे यू.पी. के कुछ इलाके तक को] तीन जोनल कमिटियों के इलाकों के रूप में बंटवारा कर उसके ऊपर स्तर की पार्टी कमिटी यानी, एक रीजनल कमिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अभी 3-U स्पेशल एरिया में निम्न पार्टी कमिटियां मौजूद हैं :

(i) उत्तरी बिहार जोनल कमिटी

(ii) उत्तराखण्ड जोनल कमिटी

(iii) पूर्वी–उत्तर यू.पी. सबजोनल कमिटी

पश्चिम बंगाल

हम पहले ही यह बता चुके हैं कि प. बंगाल के चौबीस परगना जिले के सोनारपुर थाने का डिही गांव का इलाका हमारे संगठन द्वारा ग्रामीण इलाके में कामकाज के आरंभ का पहला स्थान था। बाद में इस सोनारपुर लड़ाई से शिक्षा लेते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन सहित चौबीस परगना, हावड़ा–हुगली, मालदह, वीरभूम, बर्दवान के कांकसा–बुदबुद–आउसग्राम, मिदनापुर, बाँकुड़ा, पुरुलिया के कुछ इलाकों तथा मजदूरों के बीच कामकाज के लिए कोलकाता व हावड़ा–हुगली के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज को फैलाने की योजना बनी और पहल शुरू हुई।

हमारी अवधारणा कोलकाता सिटी कमिटी और हावड़ा-हुगली के औद्योगिक क्षेत्र की कमिटी के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाके में गुरिल्ला जोन का निर्माण करने की थी। इसमें चौबीस परगना जोन, हावड़ा-हुगली-मिदनापुर जोन, बर्दवान-वीरभूम-नदिया जोन आदि के रूप में इन इलाकों का विन्यास कर वहाँ क्रांतिकारी किसान आन्दोलन तथा छापामार संघर्ष के संचालन हेतु कामकाज शुरू किया गया। बाद में कामकाज को और विस्तार करते हुए दिनाजपुर, दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी- यानी, उत्तरी बंगाल को भी कामकाज के क्षेत्र के अंदर लाया गया।

कामकाज के विकास की प्रक्रिया में अगुआ हिस्से को लेकर विभिन्न जोनल सांगठनिक कमिटियों तथा पं. बंगाल राज्य सांगठनिक कमिटी का भी गठन हुआ।

1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी आपातकाल का दंश हमलोगों ने भी झेला। हालांकि 70-71 के बाद जब क्रांतिकारी लड़ाई पीछे हटने को मजबूर हुई उस समय और खासकर, आपातकाल के समय भारी राज्य आतंक के बावजूद कांकसा में सशस्त्र कृषि-क्रांति की मशाल जलती रही। इसके बाद 77 में जनता पार्टी का शासन आने और पश्चिम बंगाल में वाम-मोर्चा सरकार के गठन के बाद यानी, 1977-78 में चौबीस परगना के सुंदरवन इलाके में क्रांतिकारी किसान संघर्ष कुछ हद तक तेज हुआ। पर उसके बाद दुश्मन द्वारा घेराव व दमन मुहिम चलाये जाने के समय उसका उचित ढंग से मुकाबला न कर पाने के कारण उक्त लड़ाई भी और आगे नहीं बढ़ पायी। इस समय मात्र कुछ दिवसों का पालन करने और हल्का-फुलका कुछ कार्यक्रम लेने जैसे कामकाज ही होते रहे। इसके अनिवार्य परिणामस्वरूप, संग्राम न करने की मानसिकता, घिसेपिटे तौर-तरीके और यथास्थिति में फंस जाना आदि भी मुख्य समस्या के बतौर सामने आया।

इसके बाद का इतिहास है प. बंगाल प्रादेशिक कमिटी के तत्कालीन सचिव 'बा' द्वारा सशस्त्र कृषि-क्रांति का निर्माण करने हेतु दक्षिण देश- अंक 1 की यानी, एम.सी.सी. की बुनियादी लाइन को व्यवहार में नहीं ले जाने का इतिहास। अंत में, केन्द्रीय कमिटी के अंदर 'बा'-'भ' गुट का उदय और उस गुट को निकाल बाहर करने के बाद प. बंगाल की स्थिति में भी एक बदलाव आया।

2002 में 'बा' की प्रभावाधीन प. बंगाल प्रादेशिक कमिटी को भंग कर एक नई एडहॉक कमिटी का गठन हुआ। बाद में, जनवरी, 2003 में आर.सी.सी.एम. और मई, 2003 में सेकेण्ड सी.सी. के साथ एम.सी.सी.आई. की एकता स्थापित होने के पश्चात संगठन की शक्ति वृद्धि हुई और जुलाई, 2003 में पश्चिम बंगाल प्रादेशिक कमिटी का सम्मेलन भी सफल हुआ और एक नई प्रादेशिक कमिटी का चुनाव किया गया। इस नई

कमिटी की योजना के अनुसार अभी-अभी पश्चिम बंगाल में चार जोनल कमिटियां कार्यरत हैं। जैसे - (i) हावड़ा-हुगली-मेदिनीपुर जोनल कमिटी, (ii) वर्दवान-बीरभूम-नदिया-मुर्शिदाबाद जोनल कमिटी, (iii) उत्तरी बंगाल जोनल कमिटी और (iv) वृहत कोलकाता शहर कमिटी (जोनल कमिटी के बराबर दर्जा) आदि। इसके अलावा हावड़ा-हुगली औद्योगिक क्षेत्रीय पार्टी कमिटी भी मौजूद है। हर जोनल कमिटी के नीचे कुछ सबजोनल व एरिया कमिटी सहित कुछ पार्टी सेल हैं। अभी इन कमिटियों ने कुछ संघर्ष का कार्यक्रम भी ग्रहण किया है । इसके नेतृत्व में कुछ आत्मरक्षा दल, जनमिलिशिया तथा LRGS आदि का और क्रांतिकारी किसान कमिटी की गांव व इलाका स्तर की कमिटियों का गठन हुआ है तथा कुछ सफल एक्शन व प्रतिक्रियावादी दुश्मनों का सफाया आदि कार्यक्रम भी सफल हुए हैं । साथ-साथ जन-संगठनों के जरिए जन-आंदोलन के कार्यक्रमों को भी संचालित किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में प. बंगाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना अपनाई गई है, जैसे- जहां संभावना सबसे ज्यादा है, वहां अभी-अभी लड़ाई उठाने हेतु सबसे ज्यादा जोर देने का निर्णय लिया गया है तथा प. बंगाल में लड़ाई को टिकाकर रखने के लिए हमारा रणनीतिक क्षेत्र कहां पर होगा और इसके लिए क्या कार्यभार लेना होगा यह भी करीब तय किया गया है। फिर भी घिसेपिटे तौर-तरीके की सोच और कार्यपद्धति तथा यथास्थिति को तोड़ने की दृढ़ मानसिकता का अभाव अभी भी प. बंगाल के संगठन की मूल समस्या है।

असम-त्रिपुरा

भौगोलिक दृष्टिकोण से दुर्गम व आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ा और सामाजिक रूप से आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए बन्दूक उठाकर लड़ने में जिज्ञासु यह क्षेत्र साम्राज्यवाद-सामंतवाद विरोधी सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्ष को शुरू करने और उसे टिकाए रखने के लिए अत्यन्त अनुकूल है- इस अवधारणा के आधार पर हमारे संगठन ने एकदम शुरूआती दौर में अपने चुने हुए सभी रणनीतिक कार्यक्षेत्रों में इसे प्रथम स्थान दिया था । भारत के पूर्वोत्तर सभी राज्यों की एक विशेष सामाजिक विशिष्टता थी और बगल में लाल चीन की मौजूदगी ने भी उस इलाके को तत्कालीन परिस्थिति में प्रथम स्थान देने की प्रेरणा जतायी थी। उसी आधार पर तत्कालीन स्थिति के अनुसार हमने अपने चुने हुए श्रेष्ठ क्रांतिकारी अंश के एक हिस्से को यहाँ भेजा भी था । त्रिपुरा में हमारे तीन स्थानीय नेता शहादत भी दिए। किन्तु हमें तत्काल अनुकूल सफलता नहीं मिली । यों तो इसके कई कारण थे, परन्तु मुख्य कारण था- जनता के बीच में धैर्यपूर्वक काम करते

हुए उनके साथ एकात्म होने के तथा उनकी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर कुछ आंदोलन वगैरह निर्माण करने के पहले ही पुलिस व मिलिटरी की व्यापक 'घेराव व दमन' मुहिम का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमें अनुकूल सफलता तत्काल नहीं मिली।

जो भी हो, वहाँ सोच के मुताबिक कामकाज के विकास की संभावनाएं न देखकर वहाँ भेजे गये कार्यकर्ताओं के एक छोटे हिस्से को छोड़कर अधिकांश को वापस बुला लिया गया और उन्हें अन्यत्र कामों में भेजा गया।

अतीत के कामकाज की समीक्षा करते हुए तथा उससे शिक्षा लेते हुए केन्द्रीय कमिटी ने पुनः 1987 में वहाँ योजनाबद्ध ढंग से कामकाज शुरू किया। असम को तीन भागों- अपर असम, लोअर असम एवं बराक वैली- में बांटा गया और बराक वैली तथा कछार से सटे त्रिपुरा के इलाके को मिलाकर एक कार्यक्षेत्र बनाने के लिए सोचा गया। अतीत के अनुभवों से तथा अन्य इलाकों में राष्ट्रीयताओं के बीच में चल रहे कामकाज से शिक्षा लेकर असम की धरती पर उसे प्रयोग करने के फलस्वरूप नतीजा अच्छा निकलने लगा। खासकर, लोअर (निचली) असम के कई जिलों में संगठन की पकड़ मजबूत होने लगी। क्रमशः कुछ स्थानीय तरुण-तरुणी पेशेवर क्रांतिकारी बनकर संगठन में भाग लेने लगे। स्थानीय स्तर पर पार्टी कमिटियों, क्रांतिकारी किसान कमिटियों और आत्मरक्षा दलों, इलाकाई जनमिलिशिया दलों व स्थानीय नियमित छापामार दस्तों के बनने की शुरूआत हुई। बर्बर महाजनी शोषण और सामंती उत्पीड़न व वन विभाग के जुल्म के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के साथ राष्ट्रीयता की भाषा, शिक्षा, संस्कृति सहित समान अधिकार व समान मर्यादा के सवालों को भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और चोरी-डकैती, बलात्कार जैसे सामाजिक व्याधियों के खिलाफ भी संघर्ष शुरू हुआ। इसी संघर्ष के दौरान महाजन और गुण्डों के आक्रमण के कारण हमारे एक कामरेड मुकूल शहीद हुए। इसके बदले की कार्रवाई भी की गई। फलतः जनता का उत्साह और भी बढ़ा।

आज वहां सम्मेलन द्वारा गठित एक जोनल कमिटी और उसके अन्तर्गत दो सबजोनल कमिटियों और उसके नीचे चार एरिया कमिटियों के रूप में पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा मौजूद है। साथ ही फौजी संगठन के बतौर आत्मरक्षा दल व जन मिलिशिया दल के कुछ स्क्वाड सहित 2 स्थानीय नियमित गुरिल्ला स्कवाड [यानी 2 LRGS] भी मौजूद हैं। इसके अलावे गांव व इलाके के स्तर पर क्रा.कि.क. का और साथ-साथ जन-संगठन का भी कुछ संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, जैसे- महिला संगठन, छात्र-युवा संगठन, सांस्कृतिक संगठन और प्रतिरोध मंच किस्म के संगठन। हालांकि

जन-संगठन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होने की आवश्यकता है।

लड़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में हाल ही में यानी, पिछली जनवरी, 2004 को हमारे LRGS ने SDS को साथ में लेकर वन रक्षकों से 4 रायफलें और एक स्टेनगन छीन ली है। यह कार्रवाई असम के इतिहास में किसी माओवादी संगठन द्वारा राष्ट्रीयता के बीच से स्थानीय नेतृत्व को विकसित करते हुए उनके नेतृत्व में ऐसी लड़ाई को अंजाम देने जैसी एक खास महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आयी है। इस घटना से प्रभावित होकर उल्फा ने हमारे साथियों को अभिनन्दन भेजा है और आम दुश्मन के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का आग्रह भी प्रकट किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि खुद की स्वतंत्र पहल पर संघर्ष का निर्माण कर पाने से ही राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़ रही शक्तियों से पारस्परिक दोस्ताना संबंधों का विकास संभव है।

त्रिपुरा में कुछ दृढ़ समर्थकों व कुछ संपर्कों के अलावा हमारा कोई खास कामकाज नहीं है। जो भी हो, इन क्षेत्रों में कुछ प्रारंभिक सफलता हासिल होने पर भी लड़ाई को आगे बढ़ाना व टिकाकर रखना और गुरिल्ला जोन का निर्माण करना– आदि महत्वपूर्ण व जरूरी काम संपन्न करना अभी अगले कर्तव्य के रूप में बाकी रह गया है। इसलिए सही कार्य-पद्धति के जरिए ली गई योजना को निश्चित समय-सीमा के अंदर साकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अतः पार्टी, फौज, क्रांतिकारी किसान कमिटी और अन्य जन-संगठनों को मजबूत बनाने और साथ ही संघर्षरत इलाके का लगातार विस्तार करने पर सर्वाधिक बल देने की आवश्यकता है।

उड़ीसा

यह भारत के पिछड़े प्रान्तों में से एक है। इसका अधिकांश इलाका दुर्गम पहाड़ों-जंगलों से घिरा इलाका है। यह घोर गरीबी और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ कटक, जगतसिंहपुर आदि जिलों में हमारा कामकाज शुरू हुआ। वहाँ से कुछ पेशेवर साथी निकल कर आये। उनके माध्यम से नोवापाड़ा, बलांगिर आदि दुर्गम और पिछड़े इलाकों में कामकाज के लिए कार्यकर्ता भेजे गये। फिर सम्बलपुर, देवगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ आदि जिलों के कुछ इलाके में भी कामकाज की शुरूआत की गई है। सम्बलपुर-देवगढ़ इलाके में इसी बीच कुछ लड़ाई का कार्यक्रम जैसे वर्ग दुश्मन का सफाया करना और दुश्मन से बंदूक जब्त करना आदि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। इस प्रकार वहाँ मैदानी और दुर्गम दोनों इलाकों में कामकाज का प्रसार हुआ है। अभी वहाँ एक सांगठनिक स्टेट कमिटी कार्यरत है तथा उसके अधीन कुछ एरिया कमिटियाँ कार्य

कर रही हैं । कुछ जगह में गांव के स्तर पर कुछ क्रा.कि.कमिटी की इकाइयां मौजूद हैं और देवगढ़-सम्बलपुर क्षेत्र में एक LRGS का भी गठन किया गया है। इसके अलावा महिला, छात्र-युवक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवियों के बीच भी कामकाज के लिए जन संगठन यहाँ कार्यरत हैं । साथ ही साथ प्रतिरोध मंच जैसा एक संगठन भी यहां मौजूद है।

पंजाब

यह बात सबों को मालूम है कि साम्राज्यवाद और सामंती राजा-महाराजाओं व नवाबशाही के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चलाने की एक गौरवमयी परम्परा पंजाब में मौजूद है और इस कारण से आज भारत में जारी लोकयुद्ध के नक्शे में पंजाब एक अहम स्थान रखता है। खासकर, जब भारत के दलाल शासक वर्ग द्वारा पंजाब में हरित क्रांति (green revolution) की सफलता का शोर मचाया जा रहा है, तब वहां माओवादी पार्टी और क्रांतिकारी संघर्ष का विकास व विस्तार होना सचमुच ही भारत की क्रांति में बहुत ही प्रभाव डालने वाली घटना है।

सभी जानते हैं कि पंजाब में बहुत लम्बे समय से आर.सी.सी.आई.(एम-एल) काम करती आ रही थी। 1995 में यह दो हिस्सों में विभाजित हो गयी। एक का नाम आर.सी. सी. (एम) रखा गया और दूसरे का नाम आर.सी.सी.आई. (एम-एल-एम)। बाद में लगभग इन दोनों ने ही एमसीसी के साथ एकता कायम कर ली। खासकर, चार जिलों में इनका कुछ हद तक गहन कामकाज और करीब उतने ही जिलों में कमोबेश प्रभाव डालने लायक कामकाज जारी है। अब इस ग्रुप के साथ एम.सी.सी. का विलय होकर एम.सी.सी.आई. बनने के बाद वहां के अगुआ और पंजाब की आर्थिक-सामाजिक स्थिति के जानकार तथा पंजाब की विशेषता के अनुरूप आंदोलन के निर्माण व संचालन में कुछ हद तक अनुभवी कामरेडों को लेकर पंजाब राज्य कमिटी का गठन किया गया है। उसके अंतर्गत कुछ एरिया कमिटियों और कुछ पार्टी-सेलों के रूप में पार्टी का सांगठनिक ढांचा मौजूद है। इसके अलावा कुछ जिलों में आम किसान और खेतिहर मजदूरों के बीच पार्टी का अच्छा-खासा प्रभाव है और किसान-मजदूरों का मजबूत जन संगठन भी मौजूद है। खासकर, ... मंच नामक संगठन बहुत ही लोकप्रिय और प्रभाव रखने वाला एक जन संगठन है। साथ-साथ महिलाओं के बीच भी एक जन संगठन कार्यरत हैं। हालांकि शहर के मजदूरों के बीच काम करने का प्रयास जारी है पर अभी भी कल-कारखानों में मजदूर संगठन बनाया नहीं जा सका है और छात्रों के बीच भी काम काज की खास अग्रगति नहीं हो पायी है।

जहां तक पंजाब में हमारे लिए क्रांतिकारी संघर्ष का निर्माण व विस्तार करने का

सवाल है, तो "पंजाब में सशस्त्र क्रांति या सशस्त्र संघर्ष नहीं होगा, केवल कुछ जन आंदोलन होगा" और "जनआंदोलन व जनसंगठन खुद-ब-खुद सशस्त्र संग्राम में बदल जाएगा"– ऐसे चिंतन के विरूद्ध जोरदार संघर्ष करते हुए ही हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। हमारी समझ में पंजाब में पूंजीवाद के नाम पर जो कुछ भी विकास हुआ है, वह विकृत पूंजीवाद है और वहां आधा-सामंती आधार विभिन्न शक्लों में अभी भी मौजूद है तथा वास्तविक तौर पर किसानों की जमीन की समस्या का हल नहीं हो पाया है और किसान सचमुच ही जमीन चाहते हैं। हमारे विचार से पंजाब में विकृत (distorted) पूंजीवाद का कुछ हद तक विकास होने पर भी आधा-सामंती उत्पादन प्रणाली का प्रभाव व नियंत्रण बरकरार है।

अतः दीर्घकालीन लोकयुद्ध की रणनीति के तहत और पंजाब के विशिष्ट आर्थिक-राजनीतिक व सामाजिक पहलुओं के मद्देनजर पंजाब में भी सशस्त्र संग्राम का विकास व विस्तार कर पाना संभव है– इस विश्लेषण के अनुसार ही हम पंजाब के लिए भी एक कार्ययोजना ग्रहण की है। इस योजना के अनुसार पंजाब की विशिष्टता के अनुरूप जन आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रमों व उसके विभिन्न रूपों से शुरूकर कुछ विस्तृत क्षेत्र को लेकर सशस्त्र संघर्ष का इलाका तथा स्थानीय नियमित गुरिल्ला दस्ता (LRGS) का गठन कर सशस्त्र संघर्ष की गतिविधि को क्रमशः बढ़ाया जाएगा। इसे फौरी लक्ष्य के रूप में लेते हुए लड़ाई को टिकाकर रखने हेतु पंजाब के ....इलाके को एक रणनीतिक क्षेत्र (Strategic Area) के रूप में निर्मित करने का फैसला लिया गया है। इसी बीच कुछ हद तक गहन जन-आधार है और कुछ लड़ाई भी लड़ी गई है– ऐसे इलाके में एक LRGS का गठन किया गया है और उसकी संख्या भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

हमारे लिए वहां मुख्य समस्या है पेशेवर कार्यकर्ताओं की कमी। इसलिए पेशेवर मानसिकता व पेशेवर कार्यकर्ता बनाना– इस पर ही अभी हम सबसे ज्यादा जोर लगाए हुए हैं। इसीबीच इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलना शुरू हुआ है। कुछ साथी पेशेवर बन गए हैं और कुछ बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। अंत में हम समझते हैं कि ऑल इंडिया पार्टी द्वारा समूचे भारत के लिए अपनायी गई दीर्घकालीन लोकयुद्ध की रणनीति के तहत ही पंजाब में भी वहां की विशिष्ट स्थिति के अनुसार सशस्त्र संग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और समग्र के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, इसे तय करना होगा। व्यावहारिक रूप से इसको करके दिखाना भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के लिए एक चुनौती है जिसे हर क्रांतिकारी को स्वीकार कर लेना चाहिए।

दिल्ली

सर्वविदित है कि यह देश की राजधानी है और देशी–विदेशी शोषक–शासक वर्गों के और प्रायः नये–पुराने धनाढ्यों का केन्द्र भी है। यह देश की पुरातन और नूतन कलाकृति का भी केन्द्र है। जहाँ प्रतिक्रियावादियों का मजबूत और दुर्भेद्य किला रहे, वहाँ क्रांतिकारियों की निगाह का न पहुँचना उनके एकांगीपन को ही दर्शाएगा। इसलिए दुश्मन को जानो, खुद को जानो– इस द्वन्द्वात्मक नियम के अनुसार हमारे लिए दिल्ली को जानना और वहां क्रांतिकारी कामकाज को आगे बढ़ाना नितांत आवश्यक है ताकि, समय अनुकूल होने पर उस दुर्ग को भी भेदना संभव हो सके। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए जब केन्द्रीय स्तर पर पूरे देश में राजसत्ता कब्जा करने का सवाल है, तब बहुत महत्व के साथ और कठोर गुप्त तौर–तरीकों के जरिए वहां हमारे पार्टी संगठन को मजबूत करना बाकी सभी कामों को आगे बढ़ाने की बुनियादी शर्त है।

दिल्ली और उसके चारों ओर आज भी सामंती ठाट–बाट मौजूद है। मौजूद है जनता पर वीभत्स सामंती अत्याचार व शोषण। इस क्षेत्र में हुए बुर्जुआ विकास ने सामंती प्रभुत्व और परंपरा के साथ गूँथकर और भी वीभत्स रूप ले लिया है।

दिल्ली में हमारा कामकाज मजदूर वर्ग पर आधारित होकर ही चलाया जा रहा है। हालांकि मजदूर वर्ग के बीच हम बहुत ज्यादा पार्टी कामकाज का विस्तार कर पाए हों, ऐसी बात नहीं है, फिर भी मजदूरों के बीच कुछ पार्टी सेल मौजूद हैं। इसके साथ–साथ मजदूरों का ट्रेड–यूनियन संगठन भी है और कुछ कारखानों में मजदूरों के ट्रेड–यूनियन आंदोलन भी हम ही संचालित करते हैं। इसके अलावा युवा, बुद्धिजीवी व सांस्कृतिक फ्रण्ट में भी हमारा कुछ कामकाज जारी है। यहाँ एक शहर कमिटी (जो जोनल कमिटी के बराबर) है तथा कई जन संगठनों की स्टेट इकाइयाँ भी कार्यरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले एक सम्मेलन के जरिए दिल्ली शहर (या जोनल) कमिटी का गठन किया गया है। इसके अलावा पूरे दिल्ली स्तर पर एक युवा संगठन को भी सम्मेलन के जरिए गठित किया गया है।

यहाँ से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में भी कुछ कामकाज संचालित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश–राजस्थान का सीमा क्षेत्र

इस क्षेत्र में भी हमारी एक जोनल सांगठनिक कमिटी कार्यरत है जो फिलहाल बिल्कुल ही प्रारंभिक स्थिति में है। यहां हाल में तीन सबजोनल कमिटियां गठित करने और LRGS व क्रांतिकारी किसान कमिटियों का भी गठन करने का निर्णय लिया गया है।

यहां के हमारे कामकाज में चंबल के विशाल बीहड़ में फौज व आधारक्षेत्र के निर्माण की भारी संभावनाएं निहित हैं।

तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि

तमिलनाडु : हम पिछले पांच वर्षों से तमिलनाडु में कुछ सम्पर्कों के जरिए कामकाज को जारी रखे हुए हैं। खासकर पाडुकोट्टाई, आरंगतंगी, डिनडिगाल, मदुरै और धर्मपुरी जिलों में कामकाज का कुछ विस्तार हुआ है। छात्रों, किसानों व मजदूरों के बीच कुछ संपर्क मिले हैं और उनमें से पेशेवर कार्यकर्ता निकालने व जन मिलिशिया वाहिनी का गठन करने की कोशिशें जारी हैं। इस क्रम में हमने जिन तत्वों पर निर्भर किया है उनमें कुछ गलत तत्व भी रहे हैं जिन्होंने बाद में चलकर एकता के क्षेत्र में समस्याएं पैदा की हैं।

केरल : यहां हमने अपने कामकाज का विस्तार करने के साथ-साथ सीपीआई (एम-एल) (नक्सलबाड़ी) ग्रुप से आये कुछ लोगों को भी साथ में लिया। हमने उनके जरिए भी कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिशें की। पर उनके नेताओं में संकीर्णतावाद एवं अराजकतावाद के रुझानों के खिलाफ संघर्ष कर उन्हें सुधारने में हम सफल नहीं हो सके। बाद में इसका हमारी एकता पर भी कुछ-न-कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

कर्नाटक : पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सम्पर्क कायम किया है। बंगलोर के अगल-बगल के क्षेत्रों, गडाक, बेलगांव और उत्तर-पश्चिम कर्नाटक के कुछ इलाकों में किसानों व छात्र-नौजवानों के बीच हमारे कुछ सम्पर्क हैं।

महाराष्ट्र : पिछले पांच वर्षों के दौरान हम महाराष्ट्र के मुम्बई, न्यू मुम्बई, मराठवाड़ा और शोलापुर में सम्पर्कों का विस्तार कर आगे बढ़ रहे हैं। यहां किसानों, छात्रों व बुद्धिजीवियों के बीच संपर्कों का निर्माण व विस्तार करने के जरिए पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं।

हरियाणा : पिछले चार वर्षों से हम हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में संपर्क बनाये रखकर कामकाज जारी रखे हुए हैं। यहां किसानों, मजदूरों और छात्र-नौजवानों व बुद्धिजीवियों के बीच संपर्क है। यहां के फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत आदि जिलों में कामकाज का विस्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं।

शहर क कामकाज के बारे में

हम जानते हैं कि शहर शत्रु के मजबूत गढ़ हैं । ऐसा कहने से ही यह स्पष्ट होता

है कि हमारे शत्रुओं– साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीवाद का मजबूत अड्डा है शहर। शत्रु की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैनिक शक्ति का मूल केन्द्र शहर है। साथ-ही-साथ क्रांति के हिरावल-मजदूर वर्ग का वास भी वहीं है अर्थात्, शहरों में ही है। मजदूर वर्ग और उसका अग्रणी संगठन, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन या पार्टी अपनी आखिरी जीत सुनिश्चित करने यानी, सर्वहारा अधिनायकत्व को स्थापित कर वर्गहीन व शोषणविहीन समाज के निर्माण के लिए लड़ रही लड़ाई को सफल बनाने का लक्ष्य सिर्फ तभी पा सकती है जब वह भारत में नवजनवादी क्रांति को सम्पन्न करे और जनता के जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना तथा इसके लिए देहाती क्षेत्रों में सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध व दीर्घकालीन लोकयुद्ध को संचालित करे। इससे साफ हो जाता है कि देहातों में कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्ष संचालित करने अथवा दीर्घकालीन लोकयुद्ध का काम सिर्फ किसानों का ही नहीं है, बल्कि यह काम शहर के मजदूरों, छात्रों व बुद्धिजीवी आदि तमाम लोगों का है। यहीं से देहात को संघर्ष का केन्द्रबिन्दु बनाने का सवाल सामने आता है। इसका यह अर्थ नहीं कि शहर के कामकाज पर कम ध्यान दिया जाए। बल्कि उस काम को यथेष्ट महत्व देना ही हमारी घोषित नीति है। इस पर 1969 के हमारे मूल दस्तावेज– भारतीय क्रांति की रणनीति व कार्यनीति संबंधी दस्तावेज में इस प्रकार का दिशा-निर्देशन दिया गया है–''देहाती इलाकों में क्रांतिकारी युद्ध का निर्माण करना एवं जनफौज व देहाती लाल आधार क्षेत्र कायम करना सिर्फ किसानों का तथा ग्रामीण जनता का ही काम नहीं है। शहर के मजदूरों, छात्रों व युवकों सबों को इस काम में भाग लेना होगा, भाग लेना होगा संगठक के रूप में, भाग लेना होगा सैनिक के रूप में।'' शहर के मजदूर वर्गों और पार्टी का काम देहातों में रुपया-पैसा, हथियार, दवा, रसद तथा अन्य विभिन्न प्रकार की मदद पहुँचाने के साथ-साथ दुश्मन की ताकत के एक बड़े हिस्से को शहर में फंसाये रखने तथा दुश्मन पक्ष की फौजी कार्यवाही में बाधा डालने के उद्देश्य से लाल प्रतिरोध संघर्ष तथा क्रांतिकारी संघर्ष को जारी रखना है। दुश्मन के सैनिकों के वाहनों और उनकी यातायात व्यवस्था पर हर वक्त हमले करना और उसकी संपर्क व आपूर्ति-व्यवस्था को कमजोर करना, फौजी कैम्पों तथा सैन्य उत्पादन-केन्द्रों और आपूर्ति डिपो पर हमले करना आदि उनका एक आवश्यक काम है। ऐसा नहीं करने से दुश्मन अपनी समूची शक्ति का बड़ा हिस्सा देहात में भेज सकता है जो क्रांति के लिए नुकसानदायक होगा।

आज जब क्रांतिकारी संघर्ष लगातार तेज व उन्नत होता जा रहा है, तब शहर के कामकाज की आम लाइन के तहत ही संघर्षरत इलाके के तथा रणनीतिक क्षेत्र के अंदर के छोटे शहरों, कस्बों, खदानों, कोलियरियों, चाय बगीचों आदि क्षेत्रों में कामकाज को आगे बढ़ाने का महत्व काफी ज्यादा है। इसके लिए ठोस रूप से कुछ कार्ययोजना ग्रहण करना

बहुत ही जरूरी है। हमारे दस्तावेज (लाल पताका– अंक1) में भी इस महत्वपूर्ण काम के बारे में इस रूप में लिखा हुआ है कि, "......... गांवों की लड़ाई के साथ तालमेल रखकर प्रत्येक अंचल के अंतर्गत तथा आसपास के छोटे-छोटे शहरों व कस्बों में लाल प्रतिरोध संघर्ष (अभी हम इसको क्रांतिकारी संघर्ष व गुरिल्ला संघर्ष कहते हैं) का निर्माण करना होगा।" पर अपने आत्मगत उपादानों की कमी और संघर्षों के भीषण दबाव की स्थिति में इस पहलू पर हमें जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी, उतना ध्यान हम नहीं दे पाए हैं।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि छोटे-छोटे शहरों व कस्बों सहित बड़े औद्योगिक क्षेत्रों व शहरों में मजदूर वर्ग समेत तमाम निम्न पूंजीपति वर्गों– छात्र, नौजवान, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार व मेहनतकश महिलाएँ, वाहनचालक, खलासी, छोटे दुकानदार, दुकान कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आदि के बीच सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्ष व दीर्घकालीन लोकयुद्ध के महत्व व तात्पर्य को बताना होगा । इसके लिए उन्हें शहरों से संबंधित सभी वर्गों तथा विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आन्दोलन के लिए संगठित करने के साथ-साथ वहाँ पर पार्टी और छापामार दलों का गठन करने पर विशेष जोर देने की जरूरत है ताकि, जब देहात के कामकाज का समुचित विकास हो जाए और शक्ति एक निश्चित मंजिल में पहुँच जाए, तो पहले से ही संघर्षशील शक्ति के लिए शहर पर कब्जा करने में विशेष मुश्किल नहीं हो ।

हमारा यह एक काफी कमजोर पक्ष है कि शहर में कार्यों का उपयुक्त विकास करने के मामले में हम काफी पीछे हैं । इस स्थिति से उबर पाने हेतु यानी, शहर की कामकाज की दुर्बलता को दूर हटाकर पार्टी स्थिति को सबल बनाने हेतु दो-चार बिन्दुओं पर ध्यान देना जरूरी है:

(i) सबसे पहले हमें याद रखना है कि शहर दुश्मन के शक्तिशाली अड्डा स्थल हैं और शहर में साम्राज्यवाद और दलाल पूंजीपतियों का जबरदस्त शोषण, जुल्म व अत्याचार जारी है तथा तमाम किस्म की प्रतिक्रियावादी व संशोधनवादी पार्टियों के क्रिया-कलाप भी जारी हैं। अतः शहरों को वर्ग दुश्मन और दलाल पार्टियों के शोषण, जुल्म व दलाली के लिए खुली छूट नहीं देनी चाहिए, बल्कि शहर में क्रांतिकारी कामकाजों के विकास पर यथोचित महत्व देने की जरूरत है।

(ii) शहर में कामकाज चलाने के लिए सही लाइन क्या है इसके बारे में गहरी समझदारी हासिल करनी होगी। इसके अलावे कामरेड लेनिन का 'क्या करें' लेख एवं चीन में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंधी दस्तावेज और हमारे 'अर्थवाद के विरुद्ध और कुछ बातें' शीर्षक लेख को भी अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन के जरिए शहर में

मजदूर वर्ग के अंदर कामकाज करने के महत्व तथा कामकाज करने की शैली व पद्धति के बारे में सही-सही समझदारी हासिल करनी होगी।

(iii) राजनीतिक, सांगठनिक कार्यशैली व पद्धति के मामलों सहित तमाम मामलों में जाने पहचाने संशोधनवादियों व सरकारी नक्सलपंथियों के साथ एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचने की जरूरत को भलीभांति समझना होगा तथा वास्तविक कामकाजों के दौरान भी इस विभाजन रेखा को सुस्पष्ट करने की सृजनात्मक व गंभीर कोशिश करनी होगी।

(iv) शहर में जहां हमारा कामकाज जल्द से जल्द आगे बढ़ सकता है, ऐसे कुछ स्थानों को चुन लेने तथा उसके साथ-साथ कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए एक सही कैडर पॉलिसी सहित एक सुसंबद्ध योजना अपनाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

(v) शहरी इलाकों के कामकाज तथा संघर्ष के बारे में दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन एक बुनियादी उसूल का सवाल है। जब गांवों से शहरों को घेरा जाता है, तब दुश्मन के शक्तिशाली गढ़– शहर में 'बगावत' अथवा 'अंतिम' लड़ाई को संगठित करने का व्यर्थ प्रयास चलाकर वास्तव में क्रांतिकारी शक्ति का ही सर्वाधिक नुकसान करने की गलत नीति को अपनाने के बदले शहरी इलाकों की लड़ाई को देहाती इलाकों की लड़ाई के अधीन रखना चाहिए।

(vi) देहाती इलाकों को मुक्त कर गांवों से शहरों को घेरकर उचित समय पर शहरों को भी मुक्त किया जा सके इसके लिए पहले से ही तैयारियां करनी होंगी।

(vii) शहर के मजदूर वर्ग तथा पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम है : दुश्मन पक्ष अपनी पूरी शक्ति को अथवा प्रायः पूरी शक्ति को देहाती इलाकों में क्रांतिकारी शक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके, इस उद्देश्य से दुश्मन की शक्ति के एक बड़े भाग को शहरों में उलझाए रखने के लिए एवं दुश्मन के पक्ष के सैनिक कार्यकलापों में बाधा डालने के लिए विभिन्न रूपों के प्रतिरोध व क्रांतिकारी संघर्षों से शुरू करके विभिन्न पद्धति से जनता की लड़ाकू शक्तियों तथा सृजनशीलता को दुश्मन के खिलाफ संगठित व गतिशील करना। शत्रु के सैनिकों के यान-वाहन व यातायात व्यवस्था के ऊपर रोज-ब-रोज छापामार तरीके से हमले करना, दुश्मनों की संचार व आपूर्ति व्यवस्था को रोज-ब-रोज पंगु कर डालना, दुश्मनों के सामरिक कैंप, सामरिक उत्पादन केन्द्र तथा आपूर्ति डिपो पर मौका मिलते ही हमले करना इत्यादि बहुत तरह के काम ही क्रांतिकारी संघर्ष के अंतर्गत आते हैं।

(viii) जबतक गांवों से शहरों को घेर नहीं लिया जाता तबतक शहरों में हमारा खास काम नहीं, केवल बीच-बीच में दो-चार जुलूस, सेमिनार, सभा व सांस्कृतिक अनुष्ठान करना है– इस चिन्तन को पूर्ण रूप से त्याग देना होगा। इसके विपरीत, शहर में मजदूर वर्ग की समस्याओं के साथ-साथ तमाम मेहनतकश जनता की समस्याओं को लेकर यानी,

स्थानीय तौर पर छोटी लेकिन ज्वलंत समस्याओं को लेकर तथा आम समस्याओं के रूप में बेरोजगारी, महंगाई, सूदखोरी, नशाखोरी, कु-संस्कृति, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को लेकर पहले छोटे-छोटे और बाद में क्रमशः बड़े आंदोलनों का निर्माण करना होगा। इस जन-आंदोलन को प्रतिरोध आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। शहर में रेड-गार्ड आंदोलन हेतु शुरू से ही तैयारी का काम करना होगा और मूल धारा के तहत आवश्यकता अनुसार कहीं-कहीं गुरिल्ला एक्शन करने होंगे। पुलिस, गुण्डों व माफिया गिरोहों को चूर-चूर कर देने हेतु सदा सतर्क रहना होगा। चलना-फिरना, उठना-बैठना आदि मामलों में क्रांतिकारी शैली कठोरतापूर्वक लागू करनी होगी। फिर अन्य कामों के साथ-साथ हमारी घोषित नीति के तहत सात (7) स्कवाडों का निर्माण करना शहर कमिटी का एक महत्वपूर्ण काम है।

(ix) मजदूरों के धावड़ों में यानी झुग्गी-झोपड़ी में और मेहनतकशों के मुहल्ले में रहने का तरीका अपनाकर शहर के कामकाज को आगे बढ़ाना होगा। मजदूरों के पास जाना, मजदूरों के साथ खाना-पीना, मजदूरों के साथ रहना, मजदूर समस्याओं को समझना, मजदूर आंदोलन में हिस्सा लेना, मजदूरों को क्रांतिकारी राजनीति से लैस करना- इस तरह से मजदूरों तथा मेहनतकशों के साथ एकरूप होने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

(x) शहर में एक मजबूत पार्टी व पार्टी कमिटी व्यवस्था बनाने पर विशेष जोर देने के साथ-साथ विभिन्न फ्रण्टों पर खासकर, मजदूर फ्रण्ट एवं छात्र, युवा, बुद्धिजीवी व सांस्कृतिक तथा महिला फ्रण्टों पर विशेष बल देकर काम करना चाहिए।

हमें उम्मीद है कि ऐसा करने से शहर के मौजूदा दुर्बलता को दूर हटाकर पार्टी कामकाज की स्थिति को विकसित करना संभव होगा।

हमें याद रखना है कि तेज गति से शहर के कामकाज को आगे नहीं बढ़ा पाने से सार्विक रूप से गांव की लड़ाई धक्का खाएगी और पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगी, जो हमलोग कतई नहीं चाहते।

एक सही राजनीतिक लाइन के तहत ही एक सैनिक लाइन का निर्धारण करना जरूरी है

भारत में कृषि-क्रांतिकारी छापामार संघर्ष जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक संघर्ष की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के तौर पर सैनिक संघर्ष की भूमिका क्रमशः प्रधान होती जा रही है और होगी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए न केवल एक सही राजनीतिक लाइन की आवश्यकता है, बल्कि राजनीतिक लाइन के तहत ही एक सही सैनिक लाइन का निर्धारण करना भी आवश्यक है। हमारी सैनिक लाइन मूलतः दो मूल बिन्दुओं से ही अग्रसर हो सकती है; पहला, हमारी फौज केवल एक ही

किस्म की फौज हो सकती है और वह है, इसको ऐसे एक हथियार के रूप में उभरना होगा जो मजदूर वर्ग के सैद्धांतिक नेतृत्व के अधीन रहेगा और जनता के संघर्षों में अपने को नियुक्त करेगा तथा लाल आधार इलाके का निर्माण करेगा; दूसरा, हमारा युद्ध केवल एक ही किस्म का युद्ध हो सकता है, इसको ऐसा एक युद्ध होना होगा जिसमें हमको यह मान लेना होगा कि दुश्मन बड़ा व शक्तिशाली है और हम छोटे व कमजोर हैं। इसलिए इस युद्ध में हमें पूर्ण रूप से दुश्मन के दुर्बल पहलू के खिलाफ हमारे सबल पहलू का इस्तेमाल करना होगा तथा फौज का विकास, स्थायित्व, विस्तार और विजय हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से जनता की ताकत पर निर्भर करना होगा।

हमारे फौजी स्कवाडों को अवश्य ही हर विषय के बारे में केवल सैनिक दृष्टिकोण का विरोध करना होगा एवं फौज राजनीति को लेकर माथा-पच्ची नहीं करती है– इस चिंतन का भी विरोध करना होगा अथवा राजनीति ही फौज का संचालन करती है– इसे इंकार करते हुए जो घुमंतु विद्रोही का सिद्धांत मौजूद है उसका कड़ा विरोध करना होगा।

अभी-अभी के फौजी संगठन के बतौर PLGA का गठन एक तात्पर्यपूर्ण पहलू है

देशव्यापी पैमाने पर राजनीतिक सत्ता कायम करने हेतु ''अगर जनता के पास एक जनसेना नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है''– इस अवधारणा के आधार पर जनसेना और आधार क्षेत्र के निर्माण के काम को केन्द्रित करके हमारा तमाम क्रांतिकारी कामकाज शुरू से आज तक जारी है । इसमें अबतक हम PLGA के गठन में सफल हो पाये हैं और वर्तमान में निर्धारित कुछ इलाके को छापामार इलाके से आधार क्षेत्र बनाने के प्रयास में जुटे हैं ।

हमने कामकाज का आरंभ इस दिशा-निर्देशन से किया था–''कुछ हद तक एक-एक विस्तृत इलाके की आम जनता को जागरुक व संगठित करके लाल प्रतिरोध संघर्ष तथा सामंतवाद को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की लड़ाई शुरू करें । इस लड़ाई से गुजरते हुए ही एक ओर पार्टी व गुरिल्ला फौज (आत्मरक्षा दल, स्थानीय जनमिलिशिया व स्थानीय नियमित गुरिल्ला फौज) को क्रमिक रूप से दृढ़, सुव्यवस्थित और प्रसारित (strengthen, consolidate and expand) करें, साथ ही दूसरी ओर, संघर्ष के इलाके को भी क्रमिक रूप से सुदृढ़, सुव्यवस्थित व प्रसारित करें । कृषि क्रांति को और भी गहन बनावें तथा स्थानीय नियमित (गुरिल्ला) फौज को क्रमशः केन्द्रित (centralise) कर नियमित केन्द्रीय गुरिल्ला फौज तैयार करें ।'' –(लाल पताका-1)। इसके बाद की प्रक्रिया के रूप में और भी कहा गया है, "ये .... स्थानीय नियमित फौजें (मतलब स्थानीय

नियमित छापामार स्कवाड).... जब आकार की दृष्टि से बढ़ जाएंगी तथा संघर्ष ऊंचे स्तरों पर उठेंगे तब वे अलग-थलग रहकर दुश्मन के हमलों के सामने टिक नहीं पाएंगी और इस प्रकार की परिस्थिति में ..... जिन लोगों को एक केन्द्र में गोलबंद व संगठित करना संभव हो, उन्हें गोलबंद व संगठित करके ही केन्द्रीय नियमित छापामार फौज का गठन करना होगा....। केन्द्रीय नियमित छापामार फौज नियमित लाल फौज का ही प्रारंभिक रूप है।"(लाल पताका-1)। साथ ही और भी कहा गया है, "सामान्य तौर पर स्थायी आधार क्षेत्र एक ही छलांग से कायम नहीं हो सकता। किसी एक इलाके को कब्जे में लाना अथवा उसपर कब्जा कायम करना, दुश्मन की प्रभावकारी शक्ति को खत्म करने का ही नतीजा है। दृढ़ता के साथ संघर्ष के जरिए ही किसी एक इलाके में अस्थायी आधार क्षेत्र बनाया जा सकता है तथा कई बार की अदला-बदली के बाद ही एक अस्थायी आधार क्षेत्र को स्थायी आधार क्षेत्र में बदला जा सकता है।" (लाल पताका-1)।

हमने उपरोक्त दिशा-निर्देशन पर बिहार-झारखंड-बंगाल के एक विशाल इलाके में बिहार-झारखण्ड-बंगाल स्पेशल एरिया कमिटी के नेतृत्व में कई बड़े जोनों में कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष तथा सामंतवाद को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की लड़ाई संचालित की और इस लड़ाई के दौर से गुजरते हुए ही आत्मरक्षा दलों का स्कवाड, इलाकाई जन-मिलिशिया स्कवाड (बुनियादी शक्ति), स्थानीय नियमित छापामार स्कवाड व स्पेशल नियमित छापामार स्कवाड (मध्यवर्ती शक्ति) तथा प्लाटून और कम्पनी (मुख्य शक्ति) बनाने में हम सफल हुए। इस विकास के आधार पर बुनियादी, मध्यवर्ती व मुख्य- इन तीन प्रकार की शक्तियों को लेकर 2003 में जन मुक्ति छापामार सेना (PLGA) का गठन कर पाने में हम सक्षम हुए हैं और PLGA के गठन की घोषणा भी की गई है। साथ ही साथ लड़ाई के स्तर को हम छापामार इलाके के स्तर तक उन्नत करने में तथा छापामार इलाके से छापामार आधार इलाके की प्रक्रिया से गुजरते हुए आधार क्षेत्र निर्माण करने के स्तर तक पहुंचने हेतु कार्य-योजना अपनाने में सक्षम हुए हैं।

यह फौज खाद्य, अस्त्र-शस्त्र व अन्यान्य सामग्रियों की आपूर्ति भी कर रही है। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह फौज स्वतंत्र पहलकदमी पर दीर्घकालीन युद्ध संचालित करने की क्षमता रखती है। यह सेना विपन्नता से संघर्ष के क्रम में ही सम्पन्नता अर्जित कर रही है। कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है इस सेना का संघर्ष तथा संगठन और स्वयं को शस्त्रास्त्रों से सज्जित करने का सिलसिला। अतएव यह सेना विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने और टिके रहने की हिम्मत रखती है। यह सेना "युद्ध की बुनियादी आवश्यकता है दुश्मन को नष्ट करना, और अपने को सुरक्षित रखना उसकी दूसरी आवश्यकता है। अपने को सुरक्षित रखने का उद्देश्य दुश्मन को नष्ट करना है जबकि दुश्मन को नष्ट करना अपने को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है।" युद्ध के

बुनियादी उसूल संबंधी माओ की इस बात को हृदयंगम करते हुए दृढ़तापूर्वक लड़ाई का संचालन करती है। इस सेना का सबसे मजबूत आधार है क्रांतिकारी आदर्श और जनता के साथ एकरूपता तथा जनता के प्रति सेवा और समर्पण की भावना एवं इसके साथ-साथ छापामार युद्ध चलाने की कला। यह सेना कामरेड माओ के उन विचारों से अभिभूत है जो उन्होंने लाल सेना के लिए कहा था : "..... लाल सेना क्रांति के राजनीतिक कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक सशस्त्र संगठन है। खासतौर से इस समय, लाल सेना को निश्चय ही अपनी गतिविधियां सिर्फ लड़ने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। शत्रु के सैन्य बल को चकनाचूर करने के लिए लड़ने के अलावा उसे ऐसे महत्वपूर्ण काम भी संभाल लेने चाहिए जैसे आम जनता में प्रचार करना, उसे संगठित करना, उसे हथियारों से लैस करना तथा क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता कायम करने और कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन कायम करने में भी उसकी मदद करना। जब लाल सेना लड़ती है तो वह केवल लड़ने के लिए ही नहीं लड़ती, बल्कि आम जनता में प्रचार करने के लिए, आम जनता को संगठित करने के लिए, उसे हथियारबन्द करने के लिए और क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता कायम करने में उसकी मदद करने के लिए लड़ती है। ऐसे उद्देश्यों को छोड़कर लड़ना एकदम निरर्थक हो जाता है और लाल सेना के कायम रहने का कोई कारण नहीं रह जाता।" –(पार्टी के भीतर गलत विचारों को सुधारने के बारे में – माओ)।

आज जनमुक्ति छापामार फौज विधिवत घोषित हो चुकी है। सच्चाई यही है कि यह अकस्मात नहीं हुई। अनेकों छोटी-बड़ी लड़ाइयों के दौर से गुजरते हुए और जनता के बीच रहकर उन्हें जागरूक, संगठित और हथियारबन्द करने तथा लड़ाई में उन्हें शामिल करने एवं उनकी सभी समस्याओं के समाधान में उनके साथ रहकर उनका दिल जीतने जैसी परीक्षाओं से गुजरे हुए लोगों को लेकर यह गठित हुई है। दुश्मन के हर हमले का सामना करने और उसका मुंहतोड़ जवाब देकर उसे पीछे हटाने, इस तरह छोटी लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई, छोटे फारमेशनों से बड़े फारमेशन, पिछड़े व अनुन्नत हथियारों से शुरूकर कदम-ब-कदम दुश्मन से छीने गये आधुनिक व उन्नत हथियारों से खुद को लैस करने, कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्ष को कदम-ब-कदम निम्न स्तर से उच्चतर स्तर की ओर, छोटे दायरे से बड़े दायरे की ओर आगे ले जाने की कठिन, कष्टदायक व एक लम्बी प्रक्रिया के जरिए ही इसका उद्भव, विकास व विस्तार हुआ है और हो रहा है। यह महान राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ती जा रही है और अन्य सभी उपयोगी सामग्रियाँ भी यह स्वयं युद्ध के मैदान से ही अर्जित करती है।

पिछले कुछ वर्षों से फौजी लड़ाई के संचालन के जरिए हमारा अनुभवों के निचोड़ को खूब संक्षेप में इन बातों के जरिए रखा जा सकता है: (i) चाहे हम रक्षात्मक स्थिति में

हों, चाहे बराबरी की स्थिति में अथवा आक्रमणात्मक स्थिति में, हर स्थिति में आक्रमण का पहलू ही प्रधान पहलू है। हालांकि हर स्थिति में आक्रमण की कार्रवाइयों में मात्रागत अंतर जरूर रहेगा; (ii) प्रधान पहलू के रूप में आक्रमण का पहलू को ध्यान में रखकर ही हम युद्ध की योजना, पहल और सक्रियता को अपने हाथ में बरकरार रख सकते हैं तथा लचीले ढंग से सैन्य विन्यास करते हुए सक्रिय प्रतिरोध या जवाबी कार्रवाई का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं; और (iii) सही योजना, पूरी तैयारी और पूरी सक्रियता के बिना किसी भी लड़ाई में कतई नहीं जाना चाहिए और सही योजना, पूरी तैयारी और पूरी सक्रियता ही जीत की गारंटी करती है।

इसीबीच भारत के कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध के विकास-विस्तार में पी.एल.जी.ए. ने शानदार भूमिका निभाई है और निभा रही है। कामरेड माओ की इस बात को– "तुम अपने ढंग से लड़ते हो और हम अपने ढंग से लड़ते हैं; हम तभी लड़ते हैं जब हम जीत सकते हों तथा जहां जीतने की संभावना न हो वहां से अलग हट जाते हैं" बहुत ही सृजनात्मक ढंग से लागू करते हुए पी.एल.जी.ए. के कमाण्डरों व योद्धाओं ने एक-से-एक बहादूराना व शानदार रेडों व एम्बुशों को अंजाम दिया है तथा इस तरह छापामार युद्ध के उन्नत कला-कौशलों का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के एक-पर-एक घेराव-दमन मुहिमों को चकनाचूर करते हुए वे गुरिल्ला युद्ध को कदम-ब-कदम विकसित करते जा रहे हैं। इसी बीच इन्होंने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ (उत्तरी भाग), यू.पी. (पूर्वी भाग) और असम, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में सैनिक लड़ाई के रूप में रेड व एम्बुश की बहुत सी शानदार व शौर्यपूर्ण मिसालें पेश की हैं। खासकर, टेकारी व प्रेतशिला (गया-बिहार), भृगुरारी व माली (औरंगाबाद-बिहार), पहसौल बाजार (दरभंगा-बिहार), देवकुली धाम (शिवहर-बिहार), सिमरहनी (पश्चिमी चंपारण-बिहार), खोराडीह (मिर्जापुर-यू.पी.), मतारी, दुधमनिया, कतरास, बनियाडीह, बगोदर, नावाडीह, तीसरी, गोरहर, टुण्डी, तोपचांची, चन्द्रपुरा, डेम्बोटांड़, बड़ा जामदा (ये तमाम झारखंड के अंतर्गत), वन विभाग के दफ्तर (कामरूप-असम) आदि रेड और चुरचू, पलामू, सातगांवा, सारंडा (दिसम्बर, 2002), पलमा, टुण्डी आदि (ये तमाम झारखंड के अंतर्गत) एम्बुश शानदार लड़ाइयों की कुछ अच्छी मिसालें हैं। इसी की धारावाहिकता में विगत 7 अप्रील, 2004 को सारंडा में एक ऊंचे स्तर के एम्बुश की बहादूराना व शानदार लड़ाई को सफल बनाकर पी.एल.जी.ए. ने भारतवर्ष के विकासमान कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध के विकास-विस्तार के क्षेत्र में एक गुणात्मक छलांग का संकेत दिया है। उधर पी.डब्लू. के नेतृत्व में पी.जी.ए. द्वारा संचालित कोरापुट का ऐतिहासिक रेड भी इस क्षेत्र में एक शानदार छलांग का संकेत है। ऐसी कार्रवाइयों के जरिए ये दोनों छापामार फौजें एक सुव्यवस्थित व पूर्णविकसित पी.एल.ए.

के रूप में विकसित होने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ती जा रही हैं।

पी. एल. जी. ए. को शक्तिशाली और सुव्यवस्थित करने हेतु केन्द्रीय फौजी कमीशन, स्पेशल एरिया फौजी कमीशन तथा रीजनल फौजी कमीशन का गठन हुआ है जो संबंधित कमिटियों के सैनिक मामलों में विशेषज्ञों तथा उसके सचिव को लेकर गठित हुआ है। नीचे के सभी कमीशन, केन्द्रीय फौजी कमीशन के दिशा-निर्देशन में काम करेंगे। साथ ही साथ एरिया, सबजोनल और जोनल स्तर में कमान गठित होगी। अभी-अभी फौजी शक्ति के रूप में हमारे पास .... कम्पनियां, ... प्लाटून, ... SRGS, ...LRGS, इलाकाई जन मिलिशिया स्कवाड और .... SDS मौजूद हैं।

जन मुक्ति छापामार सेना (PLGA) के सामने अभी कठिन व बड़ी-बड़ी निम्नलिखित चुनौतियाँ मौजूद हैं

हमने शुरू से ही फौज और आधार इलाके का निर्माण करने के अपने बुनियादी, प्रधान एवं फौरी कर्तव्य के मद्देनजर योजनाबद्ध रूप से काम शुरू किया। हमने छोटे-बड़े संघर्षों के दौर से जन मिलिशिया से लेकर पेशेवर साथियों को लेकर गठित दस्ता संगठनों का निर्माण व संचालन भी किया। पर हम अच्छे-खासे समय तक इसी स्थिति में पड़े रहे। पीएलजीए की विधिवत घोषणा करने में हमसे विलम्ब हुआ और इस मामले में हमारी सीसी में ठीक समय पर पहल लेने की एक कमी रही। अभी हमारी नवगठित पीएलजीए के समक्ष निम्न चुनौतियां मौजूद हैं :

1. पी.एल.जी.ए. के गठन व विकास की पहली चुनौती है, इसे नई किस्म की एक सच्ची लाल सेना या जनमुक्ति सेना के भ्रूण के रूप में खड़ा करना यानी, कामरेड माओ के ऊपर उल्लेखित दिशा-निर्देश के आधार पर खड़ा करना। इसका मतलब होता है सबसे पहले पी.एल.जी.ए. को जनता व राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित और जनता की मुक्ति तथा नवजनवाद, समाजवाद व साम्यवाद के महान लक्ष्य के प्रति समर्पित एक सच्ची जनफौज के रूप में खड़ा करना। अतः हमें पी.एल.जी.ए. को सही माओवादी विचारधारा व राजनीति की बुनियाद पर खड़ा करने पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। इसके लिए फौजी फारमेशनों में पार्टी-शाखाओं के निर्माण और उनकी सतत् क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

2. शत्रु की सैनिक शक्ति की तुलना में इसकी संख्या काफी कम है। अभी सिर्फ इसका संगठनात्मक स्वरूप कुछ प्लाटूनों और कई कंपनियों तक ही निर्मित हुआ है जिसे कम से कम बटालियन तक कितने कम-से-कम समय में व्यवस्थित किया जा सकता है, उसे पूरा करने के लिए सोचना चाहिए।

3. इसकी बुनियादी शक्तियाँ बहुत ही सीमित मात्रा में संगठित और व्यवस्थित हैं और जो हैं उनका भी कोई लेखा-जोखा (यूनिटों की संख्या, हथियारों व गोला-बारूद का परिमाण आदि) नहीं है। इसे पूरी तन्मयता से यथाशीघ्र पूरा और व्यवस्थित करना होगा।

4. रोजमर्रे के काम में आनेवाली वस्तुओं और खाद्य पदार्थ, कपड़ा, वर्दी, जूता, छाता, बैग, टार्चबत्ती, साबुन, तेल, गोली, बारूद, हथियार आदि की सप्लाई की व्यवस्था मुख्य रूप से छापामार फौज को अपने आप ही कर लेनी होगी और इन तमाम वस्तुओं का प्रबंध लड़ाई करते समय दुश्मनों से ही करना होगा। इसके अलावा छापामार आधार क्षेत्रों में उत्पादन कार्य का संचालन करना होगा।

5. पी.एल.जी.ए. की तीनों शक्तियों का खासकर, बुनियादी शक्तियों का राजनीतिक और सैनिक प्रशिक्षण बहुत ही कम या न के बराबर है। इसकी समयानुकूल और नियमित व्यवस्था करनी होगी।

6. क्रांतिकारी किसान कमिटियों तथा क्रांतिकारी जन कमिटी के निर्माण के अन्य उपादानों को संगठित करने में इसे मदद करनी होगी।

7. युद्ध के स्तर को और उन्नत व शक्तिशाली बनाने के लिए अपने बड़े फारमेशन के जरिए दुश्मन की बड़ी शक्तियों पर हमला करने की कला विकसित करनी होगी।

8. छापामार क्षेत्र को और भी लहर की तरह फैलाना होगा और छापामार क्षेत्र को आधार क्षेत्र में बदलने हेतु छापामार इलाकों से दुश्मन की फौजी ताकतों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा।

9. हर हालत में पी.एल.जी.ए. पर पार्टी के नेतृत्व व नियंत्रण को मुकम्मिल करना होगा और उसे सुनिश्चित करना होगा। कामरेड माओ के इस कथन को हूबहू लागू करना होगा कि लाल सेना को पार्टी के नियंत्रण में बने रहना चाहिए, राजनीति को चाहिए कि वह बन्दूक को नियंत्रित करे और किसी भी हालत में बन्दूक को, राजनीतिक को नियंत्रित करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जानी चाहिए।

पी.एल.जी.ए. को उपरोक्त चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ बनाने के लिए सैनिक कमीशनों और संबंधित पार्टी कमिटियों की ओर से और खासकर, केन्द्रीय कमिटी की ओर से विशेष पहल लेने की जरूरत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी.एल.जी.ए. के विकास के क्षेत्र में समस्याएं हैं, किन्तु उसमें संभावनाएं भी प्रबल हैं।

एक अच्छी बात यह है कि हमारी केन्द्रीय कमिटी आरंभ से अब तक की हमारी सैनिक लाइन संबंधी अवधारणाओं और व्यवहार में हुए इतने लम्बे समय के विकास की समीक्षा करते हुए सैनिक लाइन संबंधी अपनी अवधारणा और फौजी मैनुअल को प्रकाशित कर पाई है। इस अवधारणा को तैयार करते वक्त हमने रूस व चीन के अनुभवों विशेषकर,

चीनी क्रांति व चीनी लाल फौज संबंधी अनुभवों से शिक्षा लेकर भारत की ठोस परिस्थिति में इसे लागू करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ नेपाल, पेरू, फिलिपींस और भारत की सी.पी.आई.(एम-एल) (पी.डब्लु.) के अनुभवों का भी हमने अध्ययन किया है और उन अनुभवों से जो कुछ सीखना हमने उचित समझा उसे ग्रहण किया है।

हमारा यह विकास 2000 तथा उसके बाद गलत विचारों के प्रतिनिधियों के खिलाफ लड़ते हुए लिये गये निर्णयों और उठाये गये कदमों की ठोस अभिव्यक्ति मानी जा सकती है । विकास के सारे उपादानों की पहले से मौजूदगी के बावजूद हम इसे नहीं कर पा रहे थे । अंत तक पार्टी विरोधी 'बा'-'भ' गुट को पराजित कर हमने यह कामयाबी हासिल की है ।

हालांकि इस विषय पर हमारे लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। इसलिए केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन को चाहिए कि वे इस बाकी कामों को पूरा करने हेतु भरपूर प्रयास करें।

दुश्मन द्वारा गठित ज्वाइंट ऑपरेशनल कमाण्ड के तहत जारी बर्बर 'घेराव व दमन' मुहिम को नाकाम करने हेतु उचित कार्यनीति अख्तियार करें

जाहिर है कि क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष यानी, कृषि-क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष को कुचल देने की नापाक मंशा से दुश्मन द्वारा 'घेराव व दमन' मुहिम चलायी जा रही है। चाहे झारखंड हो या बिहार, आंध्र हो या दण्डकारण्य, छत्तीसगढ़ हो या पश्चिम बंगाल, असम हो या यू.पी., कोई भी प्रान्त क्यों न हो, जहां भी क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष है वहीं दुश्मन द्वारा बर्बर अत्याचार जारी है। वस्तुतः बन्दूक और बन्दूक के बल पर ही वह अपना राज टिकाकर रखने में सचेष्ट है। आज दिन का उजाले जैसा साफ है कि सशस्त्र शक्ति या बन्दूक ही सबकुछ है बाकी जनवाद, स्वाधीनता व लोकतंत्र आदि बातें केवल ढकोसला और धोखा हैं।

झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम से लेकर आंध्र, दण्डकारण्य आदि के पटल पर नजर दौड़ाने से उपरोक्त बातें बहुत ही सच मालूम पड़ती हैं। यहां 'लोकतंत्र' और 'जनवाद' के पर्दा की आड़ में ही इज्जत, आजादी, जमीन सहित तमाम आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता पर बर्बर दमनात्मक अभियान

जारी है। यहां विगत कई सालों से विभिन्न नामों के ऑपरेशन के जरिए लगातार 'घेराव व दमन' मुहिम चलायी गई है और अभी भी एक के बाद एक नाम से यह दमनात्मक ऑपरेशन जारी है। इन तमाम ऑपरेशनों में सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., कमाण्डो फोर्स, एस.टी.एफ., ग्रेहाउन्डस आदि सशस्त्र बलों और विभिन्न राज्यों के सशस्त्र बलों को शामिल किया जाता है। इससे साफ है कि दुश्मन क्रमशः अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपने उन्नत व शक्तिशाली सशस्त्र बल पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गया है। इसके विपरीत यह भी साफ है कि क्रांतिकारी शक्तियां इससे टक्कर लेते हुए क्रमशः उन्नत होती जा रही हैं।

इन तमाम ऑपरेशनों का संचालन करने हेतु उनकी भाषा में उग्रवाद प्रभावित जिलों के हेड क्वार्टरों में भारी संख्या में अर्धसैनिक बल को रखा जाता है और साथ ही विभिन्न थानों में भी व्यापक संख्या में सशस्त्र बलों को भेजा जाता है। इसके बाद आई.जी., डी. आई.जी. की देख-रेख में और एस.पी., डी.एस.पी. के प्रत्यक्ष नेतृत्व में आधुनिक हथियारों से लैस सशस्त्र बल और कमाण्डो वाहिनी(फोर्स) रात में, दिन में जब कभी गांव घेर लेती है एवं व्यापक लोगों को खासकर नौजवानों को पकड़ लेती है। कभी-कभी एक गांव तो कभी-कभी एक साथ कई गांवों को घेर लिया जाता है। इसके बाद लोगों को मनमौजी तथा बिना वारंट से गिरफ्तार करना, मारपीट करना, मां-बहनों के साथ अश्लील आचार-आचरण करना, घर की सारी सामान लूट-पाट करना एवं फर्जी मुठभेड़ में व्यापक कार्यकर्ता व क्रांतिकारी जनता की हत्या करना आदि क्रूर व बर्बर अत्याचार चलाए जाते हैं।

बी.जे.पी. नेतृत्वाधीन एन.डी.ए. सरकार के शासन काल से ही अमेरिकी साम्राज्यवाद के निर्देशानुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की देख-रेख में झारखंड, बिहार, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व यू.पी. आदि नौ प्रान्तों के मुख्य सचिव व डी.जी.पी. (पुलिस प्रधान) और केन्द्रीय खुफिया विभागों के आला अफसरों को लेकर गठित ज्वाइंट ऑपरेशनल कमाण्ड के तहत केन्द्रीय योजना के अनुसार तमाम क्रांतिकारी संघर्षों पर व्यापक व क्रूर दमनात्मक अभियान चलाया जा रहा है जो अभी कांग्रेस नेतृत्वाधीन यू.पी.ए. सरकार के शासन काल में भी बेरोकटोक व जबरदस्त ढंग से जारी है।

केन्द्रीय सरकार सहित नौ प्रान्तों की राज्य सरकार– सभी के लिए 'नक्सलवाद' का उन्मूलन यानी क्रांतिकारी संघर्षों को कुचल डालना एकसूत्री कार्यक्रम बन गया है। इसलिए ये लोग अपने बीच विभिन्न प्रान्तों में नक्सलवादी आंदोलन का दमन करने के उपायों पर अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने और इन नौ प्रान्तों के बीच तथा

केन्द्र के साथ इनका और सजीव रिश्ता बनाये रखने और नक्सलवादियों के बारे में विभिन्न सूचनाओं का आदान-प्रदान करने खातिर उन्नत तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करने के बारे में सहमत हुए हैं। इस दमन अभियान की योजना को साकार रूप देने के लिए केन्द्र की तरफ से पूरा व्यय-भार वहन करने की घोषणा की गई है।

अब, दुश्मन ने जब एक के बाद एक 'घेरा डालने और दमन करने' की मुहिम को जारी रखा है, जब वह फर्जी मुठभेड़ के जरिए क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं व जनता की हत्या कर रहा है, तब इसका मुकाबला करने हेतु हमारा तरीका क्या होना चाहिए?

इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु अगर उपयुक्त तरीका यानी, कार्यनीति नहीं अपनायी गयी तो हम अपनी आत्मरक्षा करने और दुश्मन पर जवाबी हमला जारी रखने– इन दोनों कामों को तालमेलपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में अक्षम साबित होंगे।

भारी खून बहाकर जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उसके जरिए हम कह सकते हैं कि देहाती क्षेत्र में और खासकर मैदानी क्षेत्र में अगर कमोबेश विस्तृत क्षेत्र में कामकाज नहीं फैलाया गया और जनता की समस्याओं को केन्द्रित कर लड़ाई का निर्माण करते हुए कुछ हद तक गहन जन-आधार या जन-किलेबंदी नहीं बनायी गयी यानी, आम जनता को हथियारबंद नहीं किया गया एवं आवश्यक गोपनीयता की रक्षा करने तथा चलायमान रहने की और दिन-रात चौबीसों घंटे संतरी ड्यूटी देने की शैली व पद्धति अगर कठोर रूप से लागू नहीं रखी गयी, तो फिर सैनिक कला के दाव-पेंच [जैसे आगे बढ़ना, घात लगाकर हमला बोलना व रीट्रीट (पीछे हटना) करना, आदि-आदि तरीके] अपनाना, आत्मरक्षा करना तथा दुश्मन पर जवाबी आक्रमण जारी रखना– कुछ भी संभव नहीं है।

आज जब एक के बाद एक 'घेरा डालने व दमन करने' की मुहिम जारी है तब हमारे लिए उपयुक्त तरीके क्या होंगे ? उसके बारे में हमारे दस्तावेज लाल पताका-1 में कहा गया है, "जम कर काम करने के नाम पर कठमुल्ला तरीके से 'घेराबन्दी के इलाके' में ही अपनी समूची शक्ति को टिकाकर रखने अथवा इलाके को कब्जा में रखने की बेकार कोशिश करने के बजाय, अपनी शक्ति के एक बड़े भाग को और व्यापक जन-समुदाय में से जिनलोगों को ही संगठित व चलायमान बनाया जा सके उन्हीं को ही अति तेजी से चलायमान दस्तों के रूप में संगठित कर 'घेराव के इलाके' से बाहर चारों तरफ, कुछ हद तक विस्तृत इलाके भर में सुव्यवस्थित ढंग से बिखेर देना तथा इनकी मदद से एक तरफा 'घेराव के इलाके' के चारों तरफ छापामार इलाके को फैला देना, और दूसरी तरफ 'घेराव के इलाके' के भीतर से छापामार तरीके से हमला करने के साथ-साथ बाहर की ओर से भी और प्रधान रूप में बाहर की ओर से ही आक्रमण जारी रखना।"

विगत क्रांतिकारी लड़ाई के उतार–चढ़ाव के इतिहास के कटु अनुभवों से भी हमें यह शिक्षा मिली है कि कठमुल्ला तरीके से 'घेराव के इलाके' के अन्दर रह जाने का रूझान दरअसल आत्महनन करने के बराबर है। अतः हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए कि जमकर काम करने के नाम पर 'घेराबन्दी के इलाके' के अन्दर ही पूरी शक्ति को फंसाकर न रखा जाय, बल्कि पूरी शक्ति के एक छोटे से अंश को घेराव के इलाके के अंदर रखकर बाकी अंश को घेराव के इलाके से बाहर सुव्यवस्थित ढंग से बिखेर देना ही उचित काम होगा।

पिछले अनुभवों से यह बात हम जोर देकर कह सकते हैं कि अगर पहले से ही लड़ाईरत इलाके अथवा 'घेराबन्दी के इलाके' की चारों ओर कामकाज को फैला देने हेतु योजना नहीं रहेगी तथा कैडर नहीं दिया जाएगा तो अपनी शक्ति को बचाने और लड़ाई को भी विकसित करने की संभावना कम होती जाएगी।

दूसरी बात यह है कि 'घेराबन्दी के इलाके' के बाहर अपनी शक्ति के एक हिस्से को केवल अमूर्तरूप से बिखेर देने से ही नहीं होगा बल्कि PLGA को मजबूत बनाने का प्रयास जारी रखते हुए 'घेराव के इलाके' के बाहर व भीतर से आत्मरक्षा खातिर मुख्य रूप से बाहर से, दुश्मन पर जवाबी गुरिल्ला कार्रवाई चलाने हेतु विशेष बल देना होगा। वह काम नहीं कर पाने से 'घेराबन्दी के इलाके' के अन्दर की जनता की मानसिकता कुछ गिर सकती है। इसके अलावा जनता और स्कवाड की पहल को निष्क्रिय कर सकती है, ऐसी पद्धति अपनाने की हमारी सोच कभी भी नहीं होनी चाहिए बल्कि, हर समय पहल को बरकरार रखने तथा आगे बढ़ाने हेतु उचित पद्धति को अमल में लाने खातिर ही हमारी सोच होनी चाहिए।

अभी की स्थिति में हमारे उक्त दस्तावेज द्वारा निर्धारित कार्यदिशा, हमारी लड़ाई की अग्रगति के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, अगर हम उसे अमल में लाएं। अर्थात्, घेराबन्दी के इलाके के चारों तरफ पहले से ही कमोबेश कामकाज जारी रखना, घेराबन्दी के समय 'घेराव के इलाके' की चारों ओर शक्ति को अनुशासनबद्ध ढंग से बिखेर देना और ज्यादा संख्या में स्थानीय नियमित गुरिल्ला दल के दस्तों, प्लाटुनों व कम्पनियों का निर्माण करना और दुश्मन पर घेराव के इलाके के बाहर व भीतर से खासकर, बाहर से आक्रमण जारी रखना तथा फौज के जरिए इलाका विस्तार एवं संघर्ष व संगठन के विस्तार का काम को आगे बढ़ाते जाना– अभी की स्थिति में यही हमारी बुनियादी कार्यदिशा है। ऐसा करने से ही हम लहरों की तरह आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि, पार्टी के सजग प्रयास के बिना लहरों की तरह आगे बढ़ना कतई संभव नहीं है।

सैनिक दृष्टिकोण से हमारा काम है– दुश्मन द्वारा घेराव तो हमारे द्वारा पल्टा घेराव; दुश्मन द्वारा फिर घेराव तो हमारे द्वारा भी फिर पल्टा घेराव यानी, घेराव और पल्टा घेराव का काम ठीक–ठीक रूप से और कारगर रूप से आगे बढ़ाते जाना। इसमें दुश्मन द्वारा घेराव का पहला वृत तो हमारे द्वारा उस वृत को घेरकर और एक बड़ा वृत (परिवेष्टण)– इस रूप को भी लहरों की तरह आगे बढ़ना कहा जा सकता है। यहां पर हमारे द्वारा बड़ा वृत बनाने यानी, पल्टा घेरा डालने खातिर पहले से ही सोचकर इलाका–विस्तार हेतु चारों ओर कामकाज फैलाने की योजना का रहना भी आवश्यक है।

अत: उपरोक्त परिस्थिति की पृष्ठभूमि में दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम कर देने हेतु उचित कार्यनीति अख्तियार करना अभी के समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और यह उचित कार्यनीति, जैसे कि कामरेड माओ ने कहा है, "जब दुश्मन आगे बढ़ता है, तो हम पीछे हट जाते हैं; जब दुश्मन पड़ाव डालता है तो हम उसे हैरान–परेशान करते हैं; जब दुश्मन थक जाता है, तो हम उसपर धावा बोल देते हैं; जब दुश्मन पीछे हटता है, तो हम उसका पीछा करते हैं"– इसके अनुरूप होगी। इसी के अनुसार हम जिस तरीका पर सबसे ज्यादा बल देते आ रहे हैं वह है– 'घेराव व दमन' मुहिम चलाने हेतु हमारे इलाके के अंदर घुस आए दुश्मनों पर, जबकि वह कूच कर रहा हो, जबरदस्त एम्बुश के जरिए जवाबी हमला करो। अभी तक हमारी इस कार्यनीति का नतीजा अच्छा ही निकला है।

क्रांतिकारी किसान कमिटी

''अगर जनता के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है''– इस अवधारणा पर संशोधनवाद के साथ सुस्पष्ट विभाजन–रेखा खींचना हमारी प्राथमिकता रही है । क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार प्रारंभ से ही अगर इस बिन्दु से नहीं हो, तो अन्य संसदीय राजनीतिक दलों तथा संशोधनवादी पार्टियों या ग्रुपों के खिलाफ जनता को सचेत बनाना और उन्हें संगठित करना संभव नहीं है । क्रांतिकारी राजनीति से जागरूक, संगठित और हथियारबन्द जनता अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना कब और कैसे करेगी ? उसका संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा ? यह प्रश्न क्रांति के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर हमने गहराई से विचार किया । हमने यह समझा कि सत्ता हस्तांतरण के सवाल को मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंककर ही हल करना संभव है । एक ही समय में एक साथ दो सत्ता का अस्तित्व नहीं रह सकता, फिर एक ही झटके में मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंककर स्थायी जनसत्ता स्थापित नहीं हो सकती, बल्कि सत्ता की

छीनाझपटी का एक दौर चलेगा। पहले अस्थायी तौर पर कुछ-कुछ क्षेत्रों में जनसत्ता का अस्तित्व कायम होगा तथा धीरे-धीरे वह स्थायी जनसत्ता में तब्दील होगी। आधार क्षेत्र की अवधारणा भी वहीं से सामने आती है।

लेकिन उपरोक्त सोच तक स्थिर हो जाने से भी समस्या का हल अधूरा ही रह जाता है। तब सवाल सामने आता है कि क्या अस्थायी तौर पर ही सही, अर्थात् कुछ समय अथवा दिन के लिए ही सही, जब मौजूदा सत्ता को पूर्णरूप से हटा दिया जाएगा, उसके बाद ही क्या जनसत्ता का गठन करना होगा ? क्या एक सत्ता को उखाड़ दिया जाना और दूसरी सत्ता की स्थापना के बीच का समय सत्ताशून्य रहेगा, या क्या होगा ? इन सवालों पर गंभीर विचार-विमर्श करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब और जितने परिमाण में दुश्मन की सत्ता पर हम चोट करेंगे तब और उतने ही परिमाण में अपनी सत्ता लागू करेंगे। तब सत्ता के संचालन के लिए संगठन के तात्कालिक स्वरूप का प्रश्न सामने आया। क्या पार्टी संगठन स्वयं यह कार्य करेगा या क्या यह काम फौजी संगठन के जिम्मे होगा या जनता के सभी तरह के संगठन मिलकर शुरू से ही संयुक्त रूप से यह कार्य करेंगे ? स्वभावतः ये सारे अनगिनत प्रश्न उभरकर सामने आने लगे।

विभिन्न पहलुओं से विभिन्न सवालों को सामने रखकर सत्ता के स्वरूप और उसके संगठन के स्वरूप पर ठोस निष्कर्ष सामने आया। आखिरी विश्लेषण में क्रांति का सवाल सत्ता के सवाल से ओत-प्रोत रूप से जुड़ा है। क्रांति का सवाल उत्पादिका शक्ति और उत्पादन-संबंधों के बीच के अन्तर्विरोध और उसके हल से जुड़ा मामला होता है। उत्पादिका शक्ति में उत्पादन के साधन के साथ श्रम की निर्णायक भूमिका होती है। नवजनवादी उत्पादिका शक्ति के अन्तर्गत श्रम की भूमिका में मजदूर वर्ग और किसान वर्ग दो बुनियादी तत्व सामने आते हैं। उनकी एकता ही पिछड़े उत्पादन के साधनों को उन्नत उत्पादन के साधनों में तब्दील करने और समाज के समुचित विकास के योग्य उत्पादन के लायक उन्हें बनाने में सक्षम होगी तथा उत्पादन के साधनों और उत्पादन पर तथा वितरण के साधनों और वितरण-व्यवस्था पर उनकी मिल्कीयत कायम होने से ही नवजनवादी व्यवस्था स्थापित होगी। यह तबतक संभव नहीं है, जबतक कि उत्पादिका शक्तियों का राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कायम नहीं हो जाता। वर्तमान में कृषि क्रांति नवजनवादी क्रांति की धुरी है। कृषि क्रांति की मूल शक्ति है—किसान समुदाय, विशेषकर गरीब-भूमिहीन किसान अर्थात्, इस वर्ग के अग्रणी हिस्से को ही सत्ता दखल के लक्ष्य से किये जानेवाले संघर्ष की मूल जिम्मेवारी निभानी होगी। इस निष्कर्ष पर पहुँचकर किसान कमिटी के लिए दो नारे तय किये गये—"सही किसानों के हाथों में जमीन

चाहिए'' तथा ''क्रांतिकारी किसान कमिटी के हाथों में तमाम राजनीतिक हुकूमत चाहिए।'' इस नारे के आधार पर क्रांतिकारी किसान कमिटी के लिए दो काम की जिम्मेवारी सामने आयी–एक, भूमि–समस्या के हल के लिए किसान समुदाय को गोलबन्द करना तथा दूसरा, क्रांतिकारी किसान कमिटी द्वारा सत्ता दखल करने और उसका संचालन करने के लिए अपना कानून व हुकूमत कायम करना।

भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में किसान–आंदोलन के संबंध में एक संशोधनवादी धारणा शुरू से ही जड़ जमायी थी कि किसान आन्दोलन के साथ सत्ता पर कब्जा जमाने का कोई संबंध नहीं है और भूमि का सवाल तथा कुछ मामूली मांगें पेश करना ही किसान संघर्षों का केन्द्र–बिन्दु है। हमने इस संशोधनवादी धारणा के खिलाफ संघर्ष किया और भूमि के सवाल को राजनीतिक सत्ता के सवाल से जोड़ा तथा इस सत्ता के सवाल को क्रांतिकारी किसान संघर्ष का प्रधान एजेण्डा बना दिया। इसी के मद्देनजर क्रांतिकारी किसान कमिटी जैसे संगठन के रूप को हमने मुख्य रूप से सामने ला हाजिर किया। इस तरह हमने पुरानी सत्ता व कानून तथा उसकी राज्य–मशीनरी को कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्षों के जरिए ध्वस्त करते हुए क्रांतिकारी किसान कमिटी की सत्ता को निर्मित व कदम–ब–कदम मजबूत बनाते जाने के सवाल को मुख्य रूप से सामने ला हाजिर किया।

इस अवधारणा पर आरंभ में जब किसान कमिटी के गठन की प्रक्रिया शुरू होती थी, तो इस क्रम में मूलतः किसानों के बीच कामकाज के दौरान राजनीतिक प्रचार इस विषय को सामने रखकर ही होता था। इस दौरान हमने शुरू से ही माओवादी वर्ग–दिशा व जन–दिशा को लागू करने की गंभीर व सचेत कोशिशें कीं। हमने गरीब–भूमिहीन किसानों पर निर्भर किया, उनकी पहलकदमी का विकास करते हुए मध्यम किसानों से दृढ़ एकता कायम की, धनी किसानों के भी एक हिस्से को अपने पक्ष में मिला लिया और इस तरह शुरू से ही जोतदार–जमींदारों के खिलाफ गरीब–भूमिहीन किसानों के नेतृत्व में एक वर्गीय संयुक्त मोर्चा गठित करने का भरपूर प्रयास किया। धीरे–धीरे क्षेत्र में इस राजनीतिक बुनियाद पर खड़ा होकर ही पार्टी, फौजी संगठन और क्रांतिकारी किसान कमिटी के गठन की प्रक्रिया शुरू होकर आगे बढ़ी। इस संगठन का स्वरूप पार्टी की भाँति पूर्णतः गुप्त नहीं रहा। बल्कि यह मूलतः गुप्त संगठन के रूप में अस्तित्वमान हुआ। इसका संगठनात्मक ढाँचा और इसकी गठन–प्रक्रिया ऐसी गुप्त रीति–पद्धति से तैयार की जाने लगी जो दुश्मन की संवैधानिक धारा व कानून के साथ तालमेल करके नहीं चलती। इसके अलावा वह कृषि संघर्ष या अन्य तरह के सामाजिक संघर्षों में प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ जुड़ी रहती है। यह पार्टी और फौजी संगठनों के साथ और सत्ता कब्जा करने की लड़ाई के साथ बहुत करीब से जुड़ी रहती है तथा प्रत्यक्षतः उनके साथ मदद व

सहयोग का आदान-प्रदान करती है।

आज देश के विभिन्न भागों– बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया, उत्तर बिहार–उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड स्पेशल एरिया, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश–राजस्थान सीमा-क्षेत्र आदि के व्यापक गांवों में क्रांतिकारी किसान कमिटी का नाम और उसके दोनों प्यारे नारों ने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। व्यापक गांवों और इलाकों में इसका संगठन फैल चुका है। बिहार–झारखण्ड–बंगाल स्पेशल एरिया में तो गांव, एरिया (थाना-सीमांत), आंचलिक (जिला-सीमांत), प्रमण्डल (कमिशनरी) स्तर को पार करते हुए राज्य स्तर तक इसका गठन करने हेतु निर्णय लिया गया है। बाकी तमाम जगहों में इसे ऊपर से लेकर नीचे तक सुव्यवस्थित व सुगठित कर लेना और इनकी इकाइयों को सभी जगह सभी स्तरों में सक्रिय व गतिशील बनाना हमारे लिए फौरी तौर पर जरूरी हो गया है।

इसके नेतृत्व में हजारों हेक्टेयर जमीन दखल व वितरित हुई है तथा बगीचों, पेड़-पौधों, तालाबों आदि पर कब्जा हुआ है एवं कुआँ, तालाब, चेक-डैम व स्कूल आदि बनाने जैसे रचनात्मक कार्य किये गये हैं।

इसे उन्नत और व्यवस्थित करने के लिए सभी स्तर की पार्टी कमिटियों को निम्नलिखित समस्याओं पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें हल करना चाहिए:

1. इस संगठन का अपना संविधान व गठनतंत्र मौजूद है। अभी जरूरी है कि उसके अनुसार विभिन्न कमिटियों के स्तर में चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर कार्यशाला आयोजित की जाए। इसमें संगठन बनाने के लक्ष्य-उद्देश्य व तौर- तरीके बताये जाएं और यह प्रयास किया जाए कि एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विभिन्न स्तरों की कमिटियाँ गठित कर ली जाएं। इसे ऊपर और नीचे, दोनों स्तरों से ही शुरू किया जाए।

2. राज्य स्तर से इसका मुखपत्र निकालने पर विचार किया जाए।

3. इसके तत्वावधान में पिछड़े हुए हिस्से तथा मध्यम वर्ग के किसानों को भी अपने प्रभाव में लाने हेतु किसान आंदोलन मंच का गठन किया जाए तथा मालगुजारी, टैक्स, पटौनी, बिजली आदि की मनमानी दर के खिलाफ और अनाज के दामों का ठीक-ठीक निर्धारण, कृषि-औजारों को सही मूल्य पर उपलब्ध कराने, डब्लू. टी. ओ. द्वारा अपनाई जा रही प्रतिक्रियावादी पॉलिसी को नाकाम करने आदि मांगों पर आन्दोलन संगठित व संचालित किया जाए।

4. इसके नेतृत्व में भूमि के पुनर्वितरण, कृषि-उत्पादन, विकास व नियंत्रण,

क्रय-विक्रय, उत्पादन व सहकारिता आन्दोलन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सवालों पर आंदोलनों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संगठनों व नेताओं को प्रशिक्षित किया जाए।

क्रांतिकारी जन कमिटी

(Revolutionary People's Committee)

क्रांतिकारी जन कमिटी क्रांतिकारी जनसत्ता की स्थापना के संघर्ष की उस मंजिल में सामने आती है जब किसी क्षेत्र विशेष से मौजूदा सत्ता के प्रभुत्व को हम प्रायः समाप्त करने में सक्षम हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में पार्टी, सेना, क्रांतिकारी किसान कमिटी,और संयुक्त मोर्चा में साझीदार अन्य सभी वर्गों तथा अन्यान्य जनप्रतिनिधियों को लेकर सत्ता के संगठन के बतौर क्रांतिकारी जन कमिटी विकसित होगी।

छापामार आधार क्षेत्र के लिए चुने गये क्षेत्रों में अभी दुश्मन की सैनिक शक्ति को उखाड़ फेंकने हेतु कार्यवाहियाँ संचालित की जा रही हैं। उसके सुचिहिन्त दलाल प्रतिक्रियावादियों, जमींदारों और पुलिस बलों पर हमले संगठित हो रहे हैं। उसी प्रकार उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व व प्रभावों को भी उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी आर्थिक नीति को युद्ध को जारी रखने और जनता के जीवन स्तर को सुधारने के सवाल से जोड़ कर जनता के समक्ष पेश किया जाए और आर्थिक उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए तथा उसे बढ़ाया जाए। इसके लिए कृषि उत्पादन सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, बाजार सहकारी समिति, सहकारी बैंक, छोटे व मंझोले उद्योग जैसे– कपड़ा उद्योग, कृषि-औजार निर्माण उद्योग, जूता, छाता, साबुन, तेल आदि निर्माण के लिए उद्योग, प्रेस उद्योग, शस्त्रास्त्र निर्माण उद्योग, बारूद निर्माण उद्योग आदि का छोटे पैमाने पर निर्माण और उनकी खपत के लिए स्थानीय बाजार की आवश्यकता होगी। आधार क्षेत्र के बाहर और भीतर व्यापार भी चलाने होंगे तथा आयात-निर्यात करने होंगे। हालांकि दुश्मन ऐसे एक इलाके की सिर्फ सैनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी घेराबन्दी करेगा और दबाव बढ़ाएगा। हमें उसे चकनाचूर करना होगा। कौन करेगा इन सब कार्यभारों का संचालन ? इसके लिए जरूरत आ पड़ी है क्रांतिकारी जन कमिटी यानी, विभिन्न वर्गों के संयुक्त मोर्चे की कमिटी की, जो उस क्षेत्र में सरकारी तंत्र का संचालन करेगी। इसके लिए मजदूरों, किसानों और सेना के साथ-साथ विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर ऐसी एक संस्था बहाल होनी चाहिए जिसे हम क्रांतिकारी जन कमिटी कहेंगे।

आज हमारा यह दायित्व है कि चुने हुए क्षेत्रों में हमारी अवधारणा और हमारी नीति

से व्यापक जनसमुदाय को अवगत कराया जाए। साथ ही प्रत्येक गांव और पूरे इलाके में बसनेवाले नारी-पुरुष, बच्चों-बूढ़ों, जवानों तथा विभिन्न कामों से जुड़े सभी समुदायों एवं मजदूरों, किसानों, छात्र-नौजवानों, बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिककर्मियों सहित अन्यान्य मेहनतकश लोगों को उनके लिए आवश्यक और उपयुक्त संगठन में शामिल किया जाए। साथ ही उपरोक्त कार्यभार का युद्ध स्तर पर संचालन करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान, संगठन-निर्माण अभियान तथा उत्पादन व वितरण-व्यवस्था को नियंत्रित करने के अभियान एवं युद्ध को उन्नत रूप में विकसित करने के अभियान के जैसे सारे अभियान व्यापक रूप से चलाने होंगे। इसके लिए हर मामले के जानकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को व्यापक सहयोग के लिए सभी इलाकों से भेजने की आवश्यकता है।

क्रांतिकारी जन कमिटी या क्रांतिकारी जन परिषद छापामार आधारों या लाल इलाकों में सरकारी तंत्र का संचालन करनेवाली संस्था होगी जिसका विकास क्रमशः आगे के समय में जब साम्राज्यवाद-सामंतवाद को उखाड़ फेंककर नव जनवादी राष्ट्र बनेगा, तो नई जनवादी सरकार के रूप में होगा।

क्रांतिकारी किसान कमिटी से शुरू कर क्रांतिकारी जन कमिटी और उसका उच्चतम रूप नव जनवादी राष्ट्रीय सरकार एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। यही अवधारणा शुरू से अन्त तक सामने रखकर संशोधनवाद के साथ स्पष्ट विभाजन-रेखा खींचकर क्रांतिकारी संघर्ष का निर्माण व विकास करने में और उसकी सर्वोच्च मंजिल केन्द्रीय सत्ता के दखल तक उसे आगे बढ़ाने में हम सक्षम हो रहे हैं और होंगे।

किसान आन्दोलन मंच

किसान समुदाय का एक अच्छा-खासा तबका है, जो क्रांतिकारी किसान कमिटी का समर्थन तो करता है, किन्तु वह उसके सैद्धांतिक-राजनीतिक लक्ष्यों के साथ एकात्म होने में हिचक महसूस करता है, डरता है। वर्ग विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन-गरीब किसान क्रांति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग के ज्यादा हिस्से को छोड़कर बाकी कुछ खुशहाल मध्यम किसान और धनी किसान ढुलमुल चरित्र अपनाते हैं। ऐसे ढुलमुल दोस्त समस्या से ग्रसित रहने के बावजूद सत्ता दखल की लड़ाई में खुलकर भागीदार नहीं हो पाते। हमें इन तमाम वर्गों को जो ढुलमुल रूख अपनाते हैं, अपने पक्ष में खड़ा करना होगा। इसके लिए सी. सी. ने कई साल पहले कुछ मुद्दा केन्द्रित आन्दोलन के संचालन हेतु किसान आन्दोलन मंच जैसा संगठन बनाने का निर्णय लिया है। यह संगठन क्रांतिकारी किसान कमिटी के तत्वावधान में ही संचालित होगा। वह विभिन्न मुद्दों तथा कानूनी और खुली मांगों जैसे मालगुजारी में वृद्धि, टैक्स वृद्धि,

सिंचाई व बिजली की समुचित व्यवस्था की मांग पर और बिजली व सिंचाई की दर में वृद्धि के खिलाफ एवं फसल के दामों के निर्धारण व कृषि-उपकरणों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की मांगों तथा किसानों को दी जानेवाली सब्सिडी में कटौती, डब्लू. टी. ओ. आदि के खिलाफ आन्दोलन संचालित करेगा। फिलहाल कुछ जगहों में स्थानीय स्तरों पर इसका गठन हुआ है तथा यह कुछ कार्यक्रम भी ले रहा है। इसे और भी सुव्यवस्थित करना होगा।

लम्बे अरसे से चले आ रहे गांधीवाद और संशोधनवाद के साथ एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए ही दीर्घकालीन लोकयुद्ध की दिशा (orientation) से लैस जन-आंदोलन व जन-संगठनों को आगे बढ़ाएं

सर्वविदित है कि जन-आंदोलन व जन-संगठन के मामले में हमारी एक सुसम्बद्ध पॉलिसी मौजूद है। इस सुसम्बद्ध पॉलिसी के पीछे एक मजबूत राजनीतिक आधार भी मौजूद है। इस राजनीतिक आधार के बिना भारत जैसे अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती देश में जन-आंदोलन व जन-संगठन के लक्ष्य-उद्देश्य, दिशा एवं कार्यक्रम तय कर पाना नामुमकिन है। हमें अवश्य ही (क) बगावत की दिशा से लैस, (ख) पार्लियामेण्टरी (संसदवादी) दिशा से लैस, और (ग) सशस्त्र कृषि-क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध की दिशा से लैस– इन तीन किस्म की दिशा से लैस जन-आंदोलनों व जन-संगठनों के बीच सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचनी होगी एवं अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती देशों में सही दिशा की ओर जन-आंदोलन व जन-संगठन के कामकाजों का संचालन करने के लिए दीर्घकालीन लोकयुद्ध की दिशा से लैस जन-आंदोलन व जन-संगठन की विशेषता को ही चुन लेना और अमल में लाना होगा।

जन-आंदोलन व जन-संगठन के सवाल पर हमारे साथ नये-पुराने संशोधनवादियों का जो मतभेद मौजूद है, वह इस प्रश्न को लेकर नहीं है कि जन-आंदोलन व जन-संगठन करना है या नहीं। क्योंकि मार्क्सवाद का क, ख, ग जानने वाले लोग भी जानते हैं कि जन-आंदोलन व जन-संगठन का काम अवश्य ही करना है। पर इतना कहना ही काफी नहीं है क्योंकि इससे अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि किसलिए और किस दिशा से लैस जन-आंदोलन व जन-संगठन का संचालन करना है। अतएव, उपरोक्त तीनों दिशाओं के अंदर कौन-सी दिशा हमें ग्रहण करनी है इस बिन्दु पर ही बहस मौजूद है। भारत में लम्बे दिनों से चले आ रहे गांधीवाद व संशोधनवाद के जबरदस्त प्रभाव की बात याद रहने

से तथा केवल एम.एल.ए., एम.पी. व मंत्री बनने एवं केवल दो-चार पैसे मांग बढ़ाने खातिर चले आ रहे आंदोलनों (?) की बात याद रहने से उक्त बहस के बिन्दु पर साफ स्टैण्ड लिये बिना अपने को हम क्रांतिकारी पांत में शामिल नहीं कर सकते।

जन-आंदोलन व जन-संगठन के सवाल पर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां स्वाधीनता और जनवाद का अस्तित्व नहीं है, जहां मामूली मुद्दों पर जुलूस व जन-गोलबंदियों पर यानी, बोलने व सुनने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तथा व्यापक मार-पीट तथा गिरफ्तारियां की जा रही है, जहां शासक गुट चरम तानाशाही रूख अख्तियार किए हुए हैं, वहां जन-आंदोलन व जन-संगठन के कामकाज के तौर-तरीके, रूप व पद्धति पर गहराई से सोच-विचार किए बिना हम नहीं रह सकते। इस परिस्थिति के मद्देनजर ही जन-आंदोलन व जन-संगठन के सवाल पर हमारी कार्यवाही तय करनी चाहिए।

जन-आंदोलन व जन-संगठन के सवाल पर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समय में ही सोच केवल कानूनी, खुला व न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रचण्ड तानाशाही के वातावरण के अंदर जासूस और पुलिस की नजर से बच कर कुछ हद तक गुप्त तौर-तरीकों के जरिए जन-आंदोलन व जन-संगठन का संचालन होना चाहिए।

उपरोक्त तमाम बातों के निचोड़ के रूप में हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में युद्ध निर्माण करने के काम में मदद करना ही तमाम जन-आंदोलन व जन-संगठन का मुख्य उद्देश्य है।

पूंजीवादी देशों के साथ फर्क रेखा खींचते हुए अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती देशों में संग्राम व संगठन की दिशा व रूप आदि के सवाल पर कामरेड माओ ने कहा है, "..................... संघर्ष का मुख्य रूप युद्ध है और संगठन का मुख्य रूप फौज है। जन संगठन और जन संघर्ष जैसे दूसरे रूप भी बहुत महत्व के हैं और निश्चय ही अनिवार्य हैं तथा इन्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन, ये सब युद्ध की सेवा के लिए ही हैं। युद्ध छिड़ने से पहले सभी तरह के संगठन और संघर्ष युद्ध की तैयारी के लिए किए जाते हैं, ... युद्ध छिड़ जाने पर सभी तरह के संगठनों और संघर्षों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के साथ तालमेल कायम हो जाता है।" (युद्ध और रणनीति की समस्याएं- माओ)

कामरेड माओ के इस कथन से जन-आंदोलन व जन-संगठन के लक्ष्य व उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन, 'वाम' लाइन सुधारने के नाम पर जब दक्षिणपंथी अवसरवादी रूझान पनपने लगा, उस समय वे लोग अक्सर इस उद्धरण के "जन-संगठन और जन-संघर्ष जैसे दूसरे रूप भी बहुत महत्व के हैं और निश्चय ही अनिवार्य है तथा इन्हें

किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए" इस अंश पर ही बल दिया करते थे। इससे हमारा ऐतराज नहीं है। हमारा ऐतराज की वजह यह है कि कामरेड माओ ने जहां पर जन-आंदोलन व जन-संगठन के लक्ष्य-उद्‌देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से "ये सब युद्ध की सेवा के लिए ही है" कहा है उसपर बल नहीं दिया जाता है अथवा उसे एकदम नजरअंदाज किया जाता है। हमारे विचार से इस मूल बात को नजरअंदाज कर केवल "जन-आंदोलन व जन-संगठन अनिवार्य हैं"– यह बात रटना अवसरवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है।

अतः उक्त उद्धरण से यह साफ है कि युद्ध की सेवा के लिए ही तथा युद्ध छिड़ने से पहले उसकी तैयारी के लिए और युद्ध छिड़ जाने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के साथ तालमेल कायम करने के लिए ही जन-आंदोलन व जन-संगठन करना है।

चूंकि युद्ध निर्माण करना ही हमारा मूल मकसद है, इसलिए अभी-अभी युद्ध की सेवा करने के उद्‌देश्य से ही जन-आंदोलन व जन-संगठन का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण काम है। चूंकि हमारी लड़ाई छापामार इलाके से आधार इलाके का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ रही है, इसलिए संघर्षरत इलाकों में जन-आंदोलन व जन-संगठन को अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से और संघर्षरत इलाकों के बाहर अप्रत्यक्ष रूप से उक्त लड़ाई के साथ तालमेल कायम कर लेना होगा।

भारत की एक खास विशेषता यह है कि यहां पर सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र प्रतिक्रांति से लोहा ले रही है। मौजूदा स्थिति ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। ऐसी स्थिति में जन-आंदोलन और जन-संगठन के कामकाजों का संचालन करने के लिए कामरेड माओ ने जैसे कहा है, "हर पार्टी सदस्य को हथियार उठाकर मोर्चे पर जाने के लिए हर घड़ी तैयार रहना चाहिए"– (युद्ध और रणनीति की समस्याएं) वैसी ही नीति का अनुसरण करना होगा।

जन-आंदोलन और जन-संगठन के मामले में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कामरेड माओ के निम्नलिखित बातों के बारे में गहरी समझदारी हासिल करना तथा उसे भारत की विशेषता अनुसार अमल में लाना बहुत ही जरूरी है। कामरेड माओ ने कहा है, "................ अधिकांश हिस्सों में पार्टी का संगठनात्मक कार्य और जन-आंदोलन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से सशस्त्र संघर्षों से जुड़े हुए; सशस्त्र संघर्ष से अलग और स्वतंत्र न तो कोई पार्टी कार्य अथवा जन-आंदोलन होता है और न हो सकता है।" (युद्ध और रणनीति की समस्याएं)।

यद्यपि कि जन-आंदोलन और जन-संगठन के बारे में हमारी सोच और समझ बहुत दिनों से ही ऐसी बनी हुई है, फिर भी इस सोच और समझ के मुताबिक जन-आंदोलन

और जन-संगठन को व्यावहारिक रूप देने के सवाल पर हमारे अंदर बहुत सी खामियां मौजूद हैं।

योग्य कैडर और सही कार्यशैली व पद्धति का अभाव ही क्रांतिकारी जन-संगठनों के संचालन में मुख्य समस्या है

सर्वविदित है कि केन्द्रीय कमिटी के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जन-संगठन कार्यरत हैं। हालांकि हर प्रांत में जन-संगठनों का विकास एक ही तरह का नहीं है, फिर भी, हर जगह कुछ न कुछ जन-संगठन कार्यरत हैं। खासकर, मजदूर संगठन, महिला संगठन, सांस्कृतिक संगठन, बुद्धिजीवी संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन अपने कामकाज के द्वारा आम जनता के बीच मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन तमाम जन-संगठनों के बावजूद विभिन्न जन-संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित .... संघर्ष मंच तो व्यापक तौर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में उभर आया है।

हर जन-संगठन के अपने-अपने घोषणापत्रों पर आधारित कुछ कार्यक्रमों सहित विभिन्न मुद्दों पर हमारी रैली व आमसभा, फर्जी मुठभेड़ में कार्यकर्ताओं की हत्या करने तथा कानून की आड़ में फांसी की सजा सहित पुलिस जुल्म के विरूद्ध विक्षोभ-प्रदर्शन, राजनीतिक बंदियों की मुक्ति का सवाल, विभिन्न ऐतिहासिक दिवस, खासकर मई दिवस, महान रूसी नवम्बर क्रांति दिवस, साम्राज्यवाद विरोधी दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, 22 अप्रैल कामरेड लेनिन के जन्म दिवस आदि को केन्द्रित कर व्यापक आयोजन करना– जन-संगठनों द्वारा लिए गए कार्यक्रमों की एक विशेष धारा बन गई है।

इसके अलावा चुनाव के बहिष्कार सहित चुनाव विरोधी विभिन्न रूपों के कार्यक्रम तथा अन्य किसी-किसी मुद्दे पर इलाका बन्द अथवा राज्य स्तरीय बन्द– हमारे जन-संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विशेष तात्पर्यपूर्ण कार्यक्रम है। साथ ही न्यायपूर्ण किसान आंदोलन के खिलाफ कुत्सा, षड्यंत्र व पुलिसिया जुल्म के विरूद्ध एवं कुसंस्कृति के विरूद्ध जुलूस, विक्षोभ प्रदर्शन व सभा का आयोजन करना भी हमारे जन-संगठनों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

इन सबों के बावजूद विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), भूमंडलीकरण की नीति और कार्यक्रम के विरूद्ध तथा नई आर्थिक व औद्योगिक नीति और नई शिक्षा नीति के विरूद्ध व्यापक प्रचार व आंदोलन करना भी हमारे जन-संगठन का तात्पर्यपूर्ण पहलू है।

उपरोक्त सभी कुछ हमारा अच्छा पहलू है, सकारात्मक पहलू है। इस पहलू को आगे बढ़ाना और व्यापक व उन्नत करना हमारा कर्तव्य है।

पर साथ ही साथ जन-आंदोलन व जन-संगठन के सवाल पर कुछ खामियां भी हमारे अंदर मौजूद हैं। वे खामियां निम्न प्रकार की हैं :

(i) जन-संगठन व जन-आंदोलन को सुचारू और सृजनात्मक ढंग से संचालित कर सकते हैं– ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं का अभाव;

(ii) हर समय जन-आंदोलन का सिलसिला जारी रखने के लिए एक के बाद एक फौरी कार्यक्रमों का अभाव;

(iii) एक घोषणपत्र व संविधान के मुताबिक कमोबेश जन-संगठन के संगठनात्मक ढांचे को बरकरार रखने की योजना का अभाव; और

(iv) जन-संगठनों में कार्यरत पार्टी सदस्यों के संचालन के लिए जन-संगठन और पार्टी-संगठन के बीच की एक कड़ी के रूप में फ्रैक्शन कमिटी के कामकाज की दुर्बल स्थिति।

हमें अवश्य ही उपरोक्त खामियों को दूर हटाने हेतु अपने अंदर के गैर सर्वहारा विचारों की अभिव्यक्तियों के विरूद्ध संघर्ष चलाना होगा। जन-संगठन में कार्यरत कार्यकर्ताओं को याद रखना होगा कि भारत जैसे देश में जहां स्वतंत्रता व जनवाद नहीं है, जहां जनता की साधारण मांगों की लड़ाई को भी पुलिस-मिलिटरी के बूटों तले रौंदा जाता है, वहां सही लक्ष्य पर क्रांतिकारी जन-आंदोलनों व जन-संगठनों को आगे बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान देना होगा। इस विषय पर सृजनात्मक ढंग से सोचना होगा तथा संशोधनवादी, सुधारवादी व गांधीवादी जन-आंदोलनों व जन-संगठनों के साथ सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचनी होगी। सशस्त्र कृषि क्रांति व दीर्घकालीन लोकयुद्ध की दिशा से लैस तथा राजसत्ता कब्जा करने की दिशा से लैस जन-आंदोलन व जन-संगठन का निर्माण करना होगा।

विभिन्न जन संगठनों की स्थिति

मजदूर फ्रण्ट

हमारी अवधारणा के अनुरूप इस फ्रण्ट पर संघर्ष व संगठन के निर्माण में हम बहुत पीछे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है शहर में क्रांतिकारी कामकाज को आगे बढ़ाने के मामले में बरकरार हमारी कमजोरी। अगर हमने अपनी पार्टी की लाइन को, जिसमें शहर में पार्टी, रेडगार्ड और संयुक्त मोर्चा का गठन करने पर जितना महत्व देने की बात कही

गयी है, उतना महत्व दिया होता और आत्मसात किया होता तो इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को अपनी लाखों समस्याओं के बावजूद, आज की-सी स्थिति से तो जरूर आगे बढ़ाये होते।

हमारे कामकाज के क्षेत्र- बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में अनेकों बड़े-छोटे औद्योगिक शहर मौजूद हैं। वहाँ मजदूरों के समक्ष बन्द उद्योगों व नौकरी से छंटनी तथा अनेक तरह की कटौतियों के साथ-साथ हड़ताल जैसे न्यूनतम अधिकारों से वंचित करने व तरह-तरह के काले कानूनों में जकड़ने जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। खासकर, साम्राज्यवाद निर्देशित और उनके भारतीय दलाल शासक वर्गों द्वारा लागू की जा रही उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीतियां शहरी मजदूर वर्ग पर करारा व प्रत्यक्ष प्रहार कर रही हैं। नतीजतन उनमें साम्राज्यवाद और उनके पालतू गुर्गों के खिलाफ व्यापक आक्रोश भड़क उठा है जो विभिन्न मौकों पर संघर्ष के विभिन्न रूपों में प्रकट भी हो रहा है। ऐसे में शहरी मजदूरों के बीच इन्हें केन्द्रित कर मजबूत मजदूर आन्दोलन खड़ा करने व संगठन बनाने के आधार भी वहाँ मौजूद हैं। किन्तु हम वैसा कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह हमारी एक विशेष कमजोरी है, जिसे अविलम्ब दूर करने पर विचार करना चाहिए।

इन सब कमजोरियों के बावजूद जहां तक मजदूर फ्रण्ट में काम करने का सवाल है, झारखंड-बिहार में धनबाद, रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, गया, रोहतास, औरंगाबाद आदि जिलों में मजदूरों के बीच मजूदर ....नामक एक मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन संगठन कार्यरत है जो मजदूरों की दैनान्दिन की समस्याओं को लेकर आन्दोलन करते रहता है। बिहार-झारखंड में रेलवे मजदूरों के बीच भी हमारा कामकाज जारी है। खासकर, ... रेलवे वर्कशॉप और .... के रेल मजदूरों के बीच हमारा कामकाज और हमारे नेतृत्व में मजदूर आंदोलन एक अच्छा प्रभाव रखता है। इसके अलावा झारखंड-बिहार में मजदूर ......नामक एक राजनीतिक जन-संगठन भी है जो मजदूरों के राजनीतिक मुद्दे पर आंदोलन का संचालन करता है तथा साथ-ही-साथ शासक वर्ग की साम्राज्यवादपरस्त नीतियों जैसे निजीकरण, आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण की नीति, इन्हीं के तहत लागू की जा रही नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति व शिक्षा नीति का, मजदूर विरोधी दमनात्मक कानूनों का तथा उनके दमनकारी रवैये का भण्डाफोड़ और विरोध करता है।

पश्चिम बंगाल के विशाल औद्योगिक क्षेत्रों [कोलकाता, हावड़ा-हुगली, चौबीस परगना, दुर्गापुर, आसनसोल, आदि] में कुछ इंजीनियरिंग कल-कारखानों, जूट मिलों, चर्म उद्योगों में मजदूरों के बीच हमारा कामकाज जारी है तथा कुछ मजदूर आंदोलनों का भी

संचालन होता रहता है। इसके अलावा, कॉरपोरेशन कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, फार्मासिस्ट एसोसियेसन आदि में भी कमोबेश हमारा कामकाज है। हालांकि संशोधनवादियों के कब्जे से मजदूर आंदोलन को मुक्त करने हेतु हमारे लिए बहुत कुछ करना जरूरी है जिस पर पार्टी को विशेष ध्यान देना होगा।

दिल्ली में भी .... मजदूर .... नामक एक ट्रेड यूनियन हमारा है जो मजदूरों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के साथ ही साथ तालाबंदी, छंटनी आदि मजदूर समस्या को लेकर भी विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का संचालन करता है। साथ-ही-साथ दूसरों के साथ मिलकर भी मजदूर आंदोलन के सवाल पर हम कुछ संयुक्त कार्यक्रम चलाते हैं।

असम के कुछ चाय बगीचों में और तेल शोधनागार में कामकाज का प्रयास शुरू किया गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और ठाणे इलाके के कुछ कल-कारखानों में हमारा कुछ कामकाज जारी है।

इसी तरह पंजाब के लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के अंदर भी कामकाज चलाने हेतु हमारा प्रयास चल रहा है। इन सबों के अलावे झारखंड, बिहार और झारखण्ड से सटे बंगाल के प. मेदिनीपुर व बांकुड़ा-पुरूलिया इलाके में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में केन्दु पत्ता मजदूर .... नाम का एक जुझारू संगठन मौजूद है, जिसके नेतृत्व में करीब दो दशकों से केन्दु पत्ता मजदूरी वृद्धि आंदोलन चला आ रहा है। उन सभी इलाकों में भी इस संगठन का अच्छा प्रभाव मौजूद है।

मजदूर फ्रण्ट से .... और ....नाम की दो पत्रिकाएं भी हमारी तरफ से प्रकाशित होती हैं ।

सामग्रिक तौर पर विचार करने से हम कह सकते हैं कि शहर में मजदूरों के धावड़ों और कारखानों तथा गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच भी आधार बनाकर कामकाज करने के लिए हमें समर्पित और सुयोग्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहिए तथा वहाँ पार्टी और दस्ता तथा विभिन्न जन संगठनों के निर्माण के साथ-साथ मजदूरों का ट्रेड-यूनियन किस्म का संगठन और राजनीतिक जन-संगठन प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर पर गठित करना चाहिए ।

मजदूर पत्रिकाओं को धारावाहिक रूप से प्रकाशित करना चाहिए और उसमें मजदूरों के लिए सरल भाषा में लेख प्रकाशित करना चाहिए ।

मजदूर फ्रण्ट में हमारी कमजोरी को दूर हटाने के लिए हमें और जो करना है, वह है :

(i) संगठित और असंगठित– दोनों किस्म के मजदूरों के बीच ही काम करना होगा। पर, आम तौर पर असंगठित और ठेका मजदूरों तथा छोटे कारखानों के मजदूरों पर जोर देकर काम करने के साथ–साथ संगठित उद्योग के मजदूरों पर भी यथोचित महत्व देकर काम करना होगा। जरूरत के मुताबिक यूनियन का निर्माण करते हुए मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन आंदोलन का भी संचालन करना होगा।

(ii) कोयला मजदूर सहित अन्य खान मजदूरों एवं चाय मजदूरों तथा कपड़ा व जुट उद्योग के मजदूरों के बीच काम करने पर भी विशेष महत्व देना होगा।

(iii) यातायात व संचार, बिजली, इस्पात, ऑर्डिनेन्स आदि उद्योगों पर विशेष महत्व देकर काम करना होगा।

(iv) मजदूरों के बीच सिद्धांतकार, प्रचारक, आंदोलनकारी व संगठक के रूप में जाना होगा; अर्थवादी के रूप में अथवा स्वयंस्फूर्त आंदोलन का जयगान गाने के लिए नहीं।

(v) अगुआ मजदूरों के लिए अग्रणी राजनीतिक जन संगठन का निर्माण करने पर उचित महत्व देना होगा।

(vi) मजदूर समस्या सहित जन जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विशेष–विशेष मुद्दों को लेकर आंदोलन का निर्माण करना होगा। अपनी समस्या को लेकर आंदोलन निर्माण करने के साथ–साथ किसानों के साथ एकताबद्ध होने खातिर प्रयास चलाना होगा तथा मजदूर–किसान की मजबूत एकता बनानी होगी।

(vii) औद्योगिक क्षेत्र और शहर के नजदीक देहात इलाके को भी संगठित करना होगा एवं गांव से आए हुए मजदूरों के साथ यत्नपूर्वक बातचीत करनी होगी और उनके माध्यम से यहां भी संगठन बनाने की कोशिश करनी होगी।

(viii) अगुआ मजदूरों को किसानों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा, उनको राजनीति से लैस करते हुए उनके साथ घुलमिल जाना होगा।

मजदूर फ्रण्ट का फौरी कार्यक्रम

हमें याद रखना है कि आंदोलन के कुछ फौरी कार्यक्रम के बिना मजदूर फ्रण्ट को सक्रिय व गतिशील बनाना संभव नहीं है। इसलिए फौरी कार्यक्रमों के रूप में एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है जिसपर आधारित होकर एक–एक औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता को उसके साथ जोड़कर आंदोलन चलाने की कोशिश करनी चाहिए:–

(i) नई आर्थिक व औद्योगिक नीति के खिलाफ।

(ii) छंटनी, ले-ऑफ, तालाबंदी और बाध्यतामूलक सेवानिवृत्ति या विदाई नीति के खिलाफ तथा उचित मजदूरी सहित विभिन्न हक-अधिकारों के लिए।

(iii) मजदूरों के हित विरोधी तमाम पॉलिसियों के खिलाफ।

(iv) मजदूर आंदोलन को संकुचित करने खातिर लाए जा रहे विधेयकों(bill) के खिलाफ।

(v) समूचे काले कानूनों के खिलाफ।

(vi) औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण-प्रदूषण के खिलाफ।

(vii) मजदूर इलाके में व्यापक शराब भट्ठी तथा नशाखोरी व सूदखोरी के खिलाफ।

(viii) मजदूरों के जीवन में सुरक्षा की गारंटी के लिए तथा शिक्षा, इलाज और आवास के अधिकार के लिए।

(ix) ट्रेड-यूनियन में जनवाद तथा जनवादी पद्धति लागू करने के लिए।

(x) क्रांतिकारी किसान आंदोलन के समर्थन में तथा पुलिस जुल्म के विरूद्ध।

(xi) साम्प्रदायिकता व जात-पांत सहित तमाम फूटपरस्त नीतियों के विरूद्ध तथा दंगा भड़काने वाले साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध।

(xii) अभूतपूर्व महंगाई और चरम भ्रष्टाचार के खिलाफ।

(xiii) जन-जीवन और राष्ट्रीय-जीवन की मूल-मूल समस्याओं को केन्द्रित कर।

(xiv) विभिन्न राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी जन आंदोलनों के समर्थन में तथा उनपर हो रहे दमन के खिलाफ।

इन तमाम आंदोलनों के अंदर परिस्थिति के अनुरूप दो-चार कार्यक्रमों को चुन लेना होगा तथा एक प्रचार अभियान चलाना होगा। हस्तलिखित पोस्टर, दीवाल लेखन, पर्चा, नुक्कड़ सभा, जुलूस, कल-कारखाना, कोलियरी, बगीचा आदि में गेट मीटिंग, मजदूरों के धावड़े में ग्रुप मीटिंग आदि के जरिए प्रचार आंदोलन चलाना होगा तथा मजदूरों के लड़ाकू मिजाज और चिन्ता-चेतना के स्तर के मुताबिक आंदोलन का रूप देना होगा। जैसे- गेट के सामने खड़े होकर नारा लगाना, ऑफिस के सामने जमा होकर नारा लगाना, बड़े अफसरों व ऑफिस घेराव करना, विक्षोभ प्रदर्शन करना, रोज दिन थोड़ा समय के लिए काम बन्द कर देना, कभी-कभी अचानक हड़ताल करना, एक रोज के लिए सांकेतिक हड़ताल करना तथा इसके साथ-साथ सड़क जाम व सड़क पर रूकावटें खड़ी

करना एवं घेराव व हड़ताल आदि रूपों को भी परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करना होगा।

महिला फ्रण्ट

समाज का आधा भाग महिलाएँ हैं, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गैरबराबरी का शिकार रही हैं। फिर गुलामी में जकड़ी महिला समुदाय की यह दुर्दशा समाज में वर्गों के उदय, मातृसत्तात्मक युग के अन्त और पुरुषतांत्रिक पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना से आरंभ हुई, जो सामंती और पूंजीवादी समाज की मंजिल तक और अधिक जकड़नों में कसती चली गई। सामाजिक विकास के सारे सपने उसके और शोषित वर्ग समुदाय के लिए मृगमरीचिका बने रहे। आखिरकार इसकी गुत्थी सुलझी। महिला–मुक्ति का सवाल मार्क्सवाद पर आधारित सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के जरिए सर्वहारा अधिनायकत्व में समाजवाद की स्थापना और वर्गहीन व शोषणविहीन साम्यवादी समाज में विकास की अवधारणा से गुंथा हुआ है।

इन्हीं विचारों पर आधारित विश्व महिला समुदाय की मुक्ति का हिस्सा है भारतीय महिला समुदाय की मुक्ति। इस मुक्ति हेतु महिलाओं को साम्राज्यवाद–सामंतवाद विरोध ी जारी वर्ग संघर्ष में शामिल होना लाजिमी है। भारत में जारी सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध व दीर्घकालीन लोकयुद्ध में शामिल होकर ही महिलाएँ खुद की मुक्ति और पूरे शोषित वर्ग समुदाय की मुक्ति को सुनिश्चित करेंगी। इसलिए महिलाओं को पार्टी संगठनों के साथ–साथ संघर्ष व संगठन के सभी प्रधान और गौण रूपों में व्यापक रूप से शामिल करना अनिवार्य है। हमारे संगठन का, महिलाओं के बारे में ठोस दिशा–निर्देशन इसी रूप में रहा है। आम और खास दोनों तरह के संगठनों में महिलाओं को संगठित करना हमारी आरंभिक सोच है। चूँकि महिलाएँ समाज में वर्गों के विभाजन के आधार पर भी दो वर्गों में बंटी है और लिंग–भेद के आधार पर भी समाज में उनके साथ गैरबराबरी की समस्या मौजूद है, अतः उन्हें तमाम किस्म के वर्गीय संगठनों में शामिल करने के अलावा महिलाओं के विशेष संगठन का भी गठन करना आवश्यक है।

बावजूद इसके, हमारे संगठन में तुलनात्मक ढंग से उनकी बराबरी के अनुपात में काफी अन्तर है। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन इसमें एक कारण है पुरुष साथियों के भीतर 'महिला संगठन का काम केवल महिला साथियों का ही है' जैसे चिन्तन का अस्तित्व। इसके अलावा, दीर्घदिन से पुराने समाज में पले–पोसे होने के नाते पुरूषों में अभी भी मालिक के अधिकार की भावना मौजूद रहना तथा पितृसत्तात्मक विचार–आचार का मौजूद रहना भी एक और कारण है। साथ ही महिलाओं में निर्भरशील रहने की मानसिकता और दृढ़ता का अभाव भी एक कारण बना हुआ है। समाज में मेहनतकश महिलाओं को

उन तमाम सत्ताओं का निर्मम उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है जो शोषित वर्ग के पुरुष झेल रहे हैं, जैसे–राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, जाति–बिरादरियों की सत्ता आदि । पर महिलाएँ एक और सत्ता यानी पुरुष सत्ता से भी पीड़ित हैं। यही कारण है कि क्रांति में महिलाओं की शौर्यपूर्ण भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

झारखण्ड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड और दिल्ली आदि प्रायः सभी जगहों में ही प्रयास जारी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में संगठन में शामिल किया जाए । लेकिन तुलनामूलक ढंग से यह देखा जा रहा है कि जहाँ वर्ग संघर्ष जितना उन्नत स्तर में पहुँच रहा है वहाँ संगठनों में उनके शामिल होने का परिमाण बाकी जगहों की अपेक्षा ज्यादा है । बि–झा–बं एस. ए. सी. के अन्तर्गत दोनों रीजनल कमिटियों के विभिन्न इलाकों में महिलाएँ अच्छी संख्या में पेशेवर होकर काम कर रही हैं । इसमें से कुछ योग्य महिला कामरेड पार्टी के विभिन्न स्तर सहित फौजी संगठनों में प्लाटून कमाण्डर, एल.आर.जी.एस. कमाण्डर, सेक्शन कमाण्डर आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही क्रांतिकारी किसान कमिटी सहित अन्य अनेक जन–संगठनों में महिला कामरेड नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। पुलिसिया जुल्म का मुकाबला करने में भी इनहोंने शानदार व शौर्यपूर्ण भूमिका निभाई है तथा निभा रही है। हमारी पार्टी में एस. ए. सी., रीजनल कमिटी, कई जोनल व सबजोनल और एरिया कमिटियों तथा पी. एल. जी. ए. व किसान–संगठनों, मजदूर–संगठनों अथवा प्रतिरोध मंच जैसे संगठनों आदि की कमिटियों में महिला प्रतिनिधि देखी जा रही हैं । बि–झा–बं एस. ए.सी. के अंतर्गत पेशेवर महिलाओं की संख्या लगभग ...... है । इसके अलावा गैर पेशेवर सदस्यों की संख्या इससे कई गुना अधिक है ।

इस तरह उत्तरी बिहार–उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड नामक स्पेशल एरिया में भी अच्छी खासी संख्या में महिला पेशेवर कामरेड काम कर रही हैं। गैर पेशेवरों की संख्या भी इससे कई गुना ज्यादा है। इसके बाद, छत्तीसगढ़, असम, पंजाब, प. बंगाल, उड़ीसा व दिल्ली में भी कमोबेश पेशेवर व गैर पेशेवर महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसी प्रकार क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की जहाँ जैसी स्थिति है वैसे पेशेवर व गैर पेशेवर महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं । इसके चलते महिला संगठनों के गठन और उनके विकास–विस्तार की संभावनाएं भी अच्छी हैं- ऐसी बात कही जा सकती है।

हमारा महिला संगठन नारी–समस्या के विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी संगठन–शक्ति व सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार आंदोलन का संचालन कर रहा है। जैसे– नारियों के समान अधिकार व समान मर्यादा के लिए, जमीन सहित तमाम संपदा पर समान अधिकार के लिए, एक–ही काम के लिए पुरूषों के समान वेतन के लिए, तिलक–दहेज प्रथा और बहु–हत्या के खिलाफ, बलात्कार सहित विभिन्न प्रकार की बेइज्जती के खिलाफ, पुरूष

सत्ता से संबंधित जुल्म के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, सरकारी स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के खिलाफ आदि, आदि। इसके अलावा, पुलिसिया जुल्म-अत्याचार के विरुद्ध जोरदार प्रतिरोध सहित विभिन्न रूपों का आंदोलन निर्माण करना, पोटा सहित विभिन्न काले कानूनों के खिलाफ और जुलूस व आमसभा पर रोक लगाने के खिलाफ हमारा महिला संगठन लगातार संघर्ष करते आ रहा है। साथ ही साथ भारी जोश-खरोश के साथ एवं हजारों प्रतिबंध या रोक लगाने के बावजूद हमारे महिला संगठन द्वारा 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पालन करना एक विशेषता बन गई है। अन्य महान दिवसों (जैसे– मई दिवस, 7 नवम्बर रूसी क्रांति दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस आदि) का पालन करना भी हमारे महिला संगठन की एक विशिष्टता बन गई है।

अब महिला कार्यकर्ताओं को हर मामले में आगे बढ़ाने हेतु पार्टी के विभिन्न स्तरों में उनकी भागीदारी व अगुआ भूमिका सुनिश्चित कराने, विभिन्न समय में विभिन्न विषय पर वर्कशॉपों का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षित करने, आन्दोलन व युद्ध-कला संबंधी विशेष प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि में देने पर हमें जोर देना चाहिए।

हमारी एक कमजोरी यह है कि हम जैसे गांव इलाकों में महिलाओं के बीच कामकाज के कुछ नमूने तैयार करने में सक्षम हुए हैं, वैसा शहरों में नहीं कर पाये हैं। इसके चलते शहरों की मेहनतकश और बुद्धिजीवी महिलाओं की उल्लेखनीय संख्या को हम संगठन में नहीं ला पाये हैं। इसे अविलम्ब प्रयास से दूर करना चाहिए।

संगठन में पुरुष सत्ता की विभिन्न अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखना चाहिए।

हमारे विचार से सही दिशा पर आधारित होकर राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन का गठन करना आज की परिस्थिति में निहायत जरूरी हो गयी है। साथ ही महिला संगठन का एक मुखपत्र निकालने के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए और उसके उपादानों को विकसित करना चाहिए।

युवा फ्रण्ट

किसी भी समाज में युवा समुदाय पर, नौजवानों व नव-युवतियों के कंधों पर उस समाज का मुख्य भार होता है और वे खुशी से उसका वहन करते हैं। समाज के परिवर्तन यानी, सामाजिक क्रांति का भार भी उन्हीं के कन्धों पर है। समाज का प्रत्येक वर्ग ही अपनी युवा पीढ़ी पर भरोसा रखता है। यों तो पार्टी, पी.एल.जी.ए., के.के.सी., क्रांतिकारी जन कमिटी तथा किसी भी जनसंगठन में इनकी भूमिका को नजरअन्दाज करने की बात नहीं है, किन्तु इस समुदाय के खुद के एक स्वतंत्र संगठन की भी जरूरत है। इस जरूरत

को ध्यान में रखकर हमने प्राय: सभी प्रान्तों में स्वतंत्र युवा संगठन के लिए भी प्रयास जारी रखा है। देश का विशाल युवा समुदाय भारी बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। साम्राज्यवाद और उसके दलालों ने वैश्वीकरण की नीति के सहारे हमारे जैसे तमाम अर्धऔपनिवेशिक-अर्धसामंती देशों की जनता और खासकर, युवा वर्ग के स्वतंत्र रोजगार के तमाम साधनों को छीनकर उन्हें मुट्ठीभर बड़े कंपनियों के हाथों सौंप दिया है। भोजन की चटनी, अचार और पानी जैसी चीजों पर भी मुट्ठीभर लोगों ने कब्जा कर लिया है। युवा समुदाय के समक्ष दिशाहीन होकर अराजक स्थिति में जीने से बचने का एक ही उपाय है– मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की रोशनी में अपनी समस्या का स्वयं हल करने के लिए साम्राज्यवाद-सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़ना तथा मजदूर-किसानों के साथ एकरूप होना और अपनी सृजनात्मक क्षमता का संगठित उपयोग करके अपनी प्रतिभा को समाज के नव निर्माण के लिए समर्पित करना।

बिहार-झारखंड-बंगाल स्पेशल एरिया में हमारा एक युवा संगठन तथा उत्तरी बिहार, छत्तीसगढ़, प. बंगाल, उड़ीसा, असम और नई दिल्ली में भी हमारे युवा संगठन कार्यरत हैं। इनका एक अपना घोषणा पत्र, कार्यक्रम तथा संविधान भी है। लेकिन फिर भी इनका विकास उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्टेट कमिटियों तथा स्पेशल एरिया कमिटी की ओर से समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संगठन के बैनर तले हम ऐसे अनेक मुद्दे स्वतंत्र व संयुक्त कार्यक्रम के लिए ले सकते हैं जिनके जरिए आन्दोलन को व्यापक रूप दिया जा सके।

सी. सी. की ओर से इस समुदाय की क्रांतिकारी परंपरा को देखते हुए कार्यकर्ता-निर्माण के एक भारी स्रोत के रूप में इसे खड़ा करने हेतु इसपर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

छात्र फ्रण्ट

छात्र समुदाय को राष्ट्र का भावी कर्णधार माना जाता है। विश्व में जहाँ भी कोई परिवर्तन या क्रांतियाँ हुई हैं, छात्र समुदाय ने उसमें भारी भूमिका निभायी है। हमारे देश का इतिहास भी यही है। छात्र समाज का वह अंग है जो सीखने का भार वहन करता है। वह जो कुछ सीखता है समाज से और जो भी सीखता है समाज के लिए। समाज की प्रगति और परिवर्तन के लिए, जो कुछ समाज उसे सिखाता है, वह उस शिक्षा को समाज पर लागू करता है। वर्ग-विभाजित समाज में जारी वर्ग संघर्ष छात्र समुदाय को भी विभक्त कर उसे अपनी वर्गीय एकता को मजबूत कर विरोधी वर्ग के खिलाफ निर्मम वर्ग संघर्ष करते हुए वर्गहीन समाज के निर्माण का कार्यभार सौंपता है। आज समाज के उन सारे नौनिहालों को, जो उम्र के अनुसार छात्र होने के अधिकार से वंचित हैं या वंचित रह

जाते हैं, उनके इस अधिकार हेतु उन्हें संघर्ष करने के लिए संगठित करने के साथ-साथ क्रांति के लिए भी संगठित करने तथा उन छात्रों को जो छात्र होकर भी शिक्षा के समान अधिकार से वंचित हैं या रह जाते हैं, नव जनवादी क्रांति के एक अनिवार्य अंग के रूप में संगठित करने का जिम्मा क्रांतिकारी पार्टी के ऊपर है। छात्रों के कंधे पर यह भी भार है कि वे क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर समाज की प्रगति और परिवर्तन में बाधक मौजूदा अर्धऔपनिवेशिक-अर्धसामंती समाज और इसकी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाएं। साम्राज्यवाद-सामंतवादपरस्त मौजूदा समाज-व्यवस्था व उसकी शिक्षा प्रणाली की जगह नव जनवादी समाज-व्यवस्था तथा उसकी शिक्षा प्रणाली की स्थापना के दौर से समाज और उसके अंग नौनिहाल छात्र समुदाय की प्रगति, परिवर्तन और उच्चतम लक्ष्य की दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना ही आज छात्र समुदाय का विशेष कार्यभार है।

हमारा संगठन इस लक्ष्य व उद्देश्य को सामने रखकर छात्रों के बीच कामकाज करता आ रहा है। नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति तथा नई शिक्षा नीति के नाम पर दलाल भारतीय शासक वर्ग द्वारा गृहीत साम्राज्यवाद के आज के युग के अनुसार संशोधित व परिमार्जित नीतियों एवं पुरातन अभिजात वर्गीय शिक्षा नीति का विरोध करना हमारे छात्र संगठन के संघर्ष का मूल लक्ष्य है। इसके बिना नव जनवादी शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कतई संभव नहीं होगा।

हमारे कामकाज के प्रायः सभी इलाकों में छात्रों के बीच कामकाज है और स्वतंत्र छात्र संगठन भी है। कमोबेश छात्र समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर स्वतंत्र कार्यक्रम के आधार पर तथा समाज के अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अन्य सामाजिक मुद्दों पर हम संघर्ष करते आ रहे हैं। किन्तु इस महत्वपूर्ण समुदाय को और व्यापक व जोरदार ढंग से क्रांतिकारी आन्दोलन में उतारने हेतु जो प्रयास हमारी पार्टी को करना चाहिए, ठीक उस रूप में हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते छात्र आन्दोलन से जो प्रखर नेतृत्व व व्यवस्थित कार्यकर्ता समूह को तैयार होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसके बिना हम राष्ट्रव्यापी उभार पैदा करने की स्थिति में जाना अत्यन्त कठिन समझते हैं। अतएव यह कार्यभार अवश्य ही हमें और भी सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर A2 नाम से इसका एक संगठन है, जहां हमारे लिए और सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है।

बुद्धिजीवी फ्रण्ट

क्रांति में इस समुदाय के योगदान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समुदाय

काफी संवेदनशील होता है। किसी घटना की क्रिया-प्रतिक्रिया अन्य किसी वर्ग या समुदाय से कहीं ज्यादा जल्द इस समुदाय में होती है। यह अपनी भावनाओं को बहुत जल्द समाज में प्रभावकारी ढंग से रखने में सक्षम होता है। इसलिए आज जब क्रांतिकारी संघर्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तब मजदूर-किसानों को संगठित करने में, क्रांतिकारी किसान आंदोलन व क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलनों सहित अन्य जन-आंदोलनों का विकास करने में बुद्धिजीवी लोग एक बड़ी भूमिका का पालन कर सकते हैं। कामरेड माओ ने कहा, "बुद्धिजीवियों के शामिल हुए बिना क्रांति में विजय हासिल करना असंभव है" – (बुद्धिजीवियों को बड़ी तादाद में भर्ती करो)।

हमारे देश में साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल पूंजीपतियों के हित में काम करने वाले या कलम बेचू इने-गिने बुद्धिजीवियों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा बुद्धिजीवी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था का बदलाव चाहते हैं। हालांकि मजदूर-किसानों के साथ एकात्म होनेवाले ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या अभी जरूरत की तुलना में कम है। फिर भी यह हिस्सा क्रांति के विकास के दौर में उत्साह से आगे आता है, बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करता है और एक अच्छी भूमिका भी निभाता है। अतएव सर्वहारा वर्ग और उसकी पार्टी के लिए बुद्धिजीवियों, कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों आदि को काफी संख्या में पार्टी में लाने और उनकी वर्गीय कमजोरी को दूर हटाकर क्रांति में उनकी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। सर्वहारा वर्ग को क्रांति के कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु इस समुदाय की जितनी ज्यादा आवश्यकता है, उसे ध्यान में रखकर इस पर उतना ही बल देना चाहिए।

सांस्कृतिक फ्रण्ट

संस्कृति किसी भी समाज का दर्पण होती है। आज हमारे देश में अर्धऔपनिवेशिक-अर्धसामंती संस्कृति साम्राज्यवाद और उसके दलालों की सेवा में अनैतिकता की चरम अभिव्यक्ति के रूप में उजागर हो रही है। उसके विपरीत, नव जनवादी क्रांति के लक्ष्य के लिए लड़ रही तमाम क्रांतिकारी राजनीतिक शक्तियाँ एक नई सांस्कृतिक पहचान बिखेर रही हैं। नव जनवादी तथा क्रांतिकारी संस्कृति सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार युद्ध व दीर्घकालीन लोकयुद्ध के मैदान से जन्म लेकर फल-फूल और विकसित हो रही है। जिस प्रकार क्रांतिकारी युद्ध आम जनता का युद्ध होता है और आम जनता इस युद्ध का वाहक होती है, ठीक उसी प्रकार क्रांतिकारी संस्कृति भी आम जनता की संस्कृति होती है और आम जनता उसका वाहक होती है। संस्कृति समाज की अर्थनीति व राजनीति का प्रतिबिम्ब होती है, फिर संस्कृति अर्थनीति व राजनीति के

विकास में भी सहयोग करती है । आज क्रांतिकारी राजनीति द्वारा क्रांतिकारी संस्कृति का सृजन हो रहा है, फिर क्रांतिकारी संस्कृति क्रांतिकारी राजनीति के विकास में सहायता कर रही है । इसके लिए जैसे क्रांति को सभी क्षेत्रों में संगठित रूप देने और उसे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार नई संस्कृति को भी संगठित और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है । इस उद्देश्य से जैसे हम अपने कार्यक्षेत्र के प्राय: सभी इलाकों में विभिन्न किस्म के संघर्षों व संगठनों के निर्माण का कार्यभार ग्रहण कर उसे लागू करने में जुटे हैं, ठीक उसी प्रकार कला और संस्कृति को भी संगठित और व्यवस्थित रूप देकर आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं । इसके लिए झारखंड, बिहार में सांस्कृतिक संगठन कार्यरत है । झारखंड में इसके घटक के रूप में झारखंड ..... नामक सांस्कृतिक संगठन भी काफी लोकप्रिय है । इसके अलावा, उत्तरी बिहार, प. बंगाल, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यू.पी. आदि में भी सांस्कृतिक संगठन हैं तथा बाकी सभी जगहों में इसके उपादान मौजूद हैं । पार्टी को चाहिए कि वह सभी राज्यों में इसके संगठनात्मक ढाँचों को व्यवस्थित करे, विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर व गैर पेशेवर– ज्यादा संख्या में दोनों प्रकार की सांस्कृतिक टीम बनाये, उन्हें वर्कशॉप चलाकर प्रशिक्षित करे और जनता के बीच भेजे। झारखंड–बिहार सहित अन्य जगह का अनुभव यह बताता है कि यह संगठन जनसमुदाय की क्रांतिकारी चेतना के विकास में और उसमें लड़ाकू तेवर लाने में मदद करता है । पार्टी के फैलाव में भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है ।

इसका A1 नामक एक राष्ट्रीय संगठन है जो कई क्रांतिकारी सांस्कृतिक संगठनों का मंच है । इसमें भी हमारी अच्छी भागीदारी होती है । इसे और भी व्यवस्थित और सक्रिय बनाने की जरूरत है ।

किशोर–किशोरी वाहिनी

हम आरंभ से ही कम उम्र के बच्चे–बच्चियों के ऊपर खूब सतर्कतापूर्वक ध्यान देते आ रहे हैं । क्रांतिकारी संघर्ष में इन्हें शामिल करना और यत्नपूर्वक इनका लालन–पालन करना हम अपना एक कर्तव्य समझते हैं । ऐसा न करने से मौजूदा पीढ़ी को आनेवाली पीढ़ी से कट जाने का खतरा उठाना होगा । अनुभव यह बताता है कि प्यार से इस उम्र के बच्चे–बच्चियों का लालन–पालन करने और उन्हें क्रांतिकारी शिक्षा से शिक्षित करने से इनका क्रांतिकारीकरण बड़ी तेजी से होता है । ये अपने अधिकार व कर्तव्य–बोध को बहुत सहज और सरल ढंग से समझ लेते हैं और अपने कर्तव्य का किसी युवा–युवती से भी ज्यादा ईमानदारी से वहन करते हैं । सैन्य शिक्षा भी ये आसानी से प्राप्त कर लेते हैं । वर्गीय चेतना और शत्रु के प्रति वर्ग घृणा इनमें तेजी से उभरती है । जनता के बीच सहज ही ये प्यार के पात्र बन जाते हैं । इनका हृदय बड़ा सरल होता है । पार्टी में इन्हें पितृ और

मातृ स्नेह देनेवाला कुशल नेतृत्व मिलने से इनका विकास बहुत कम समय में और अच्छे ढंग से होता है। ये किशोर-किशोरियां सांस्कृतिक टीम में तथा अन्य कामों में रहकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और जब कुछ बड़े होते हैं, तो सैन्य प्रशिक्षण लेकर फौजी संगठन में शामिल होते हैं। फिर समय बीतने के साथ-साथ ये लोग पार्टी और PLGA की भी विभिन्न जिम्मेवारियां सम्हालते हैं।

हमारा अनुभव यह बताता है कि हमें इस पीढ़ी पर पूरे संगठन में यत्नपूर्वक ध्यान देकर इसका लालन-पालन करना चाहिए। भविष्य के कर्णधार के बतौर तैयार करने हेतु अभी से ही इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।

मोर्चा-संगठन

विभिन्न प्रान्तों में हमारे अपने विभिन्न जन संगठनों को लेकर गठित कई मोर्चा संगठन कार्यरत हैं जैसे- जन.... मंच, गण... मंच, जन.... मोर्चा, लोक..... मोर्चा, आदि। फिर 14 राज्यों के मोर्चा-संगठनों को लेकर गठित राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा संगठन S. R. भी मौजूद है। इस संगठन का एक घोषणापत्र व कार्यक्रम मौजूद है और यह संगठन आम जनता से चुनाव का बायकाट करने हेतु आह्वान करता है। साथ ही राज्य-आतंक के विभिन्न रूपों के विरूद्ध, फांसी की सजा के विरूद्ध, पोटा सहित तमाम काले कानूनों के विरूद्ध, डब्लू.टी.ओ. के विरूद्ध, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा छेड़े गये युद्ध के विरूद्ध यह संगठन जोरदार आवाज उठाता है। फिर राष्ट्रीय जीवन व जन-जीवन के विभिन्न मुद्दों को लेकर भी यह संगठन जहां तक संभव हो, आंदोलन का संचालन करता है। विभिन्न प्रान्तों में इसके अंतर्भुक्त संगठन भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कार्यक्रम करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो समूचे देश के पैमाने पर जुझारू जन-आंदोलन का निर्माण करने के बारे में यह संगठन कारगर भूमिका निभा सकता है। इसी प्रक्रिया के जरिए ऐसे कुछ उपादान मिल सकते हैं जिनके जरिए हमारे रणनीतिक कार्यक्षेत्रों में तथा इससे आगे बढ़कर देश के पैमाने पर भी रणनीतिक संयुक्त मोर्चा के भ्रूण के गठन में सहुलियत होगी। पर इस संगठन द्वारा जिस हद तक अपनी गतिविधि का संचालन करना चाहिए अभी भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। अत: इसे अविलम्ब पूरा करने हेतु केन्द्रीय कमिटी से विशेष प्रयत्न करना चाहिए और इसकी फ्रैक्शन कमिटी की नियमित बैठकें होनी चाहिए।

क्रांति के एक जादूई हथियार के रूप में संयुक्त मोर्चा के निर्माण पर विशेष बल दें

सभी को मालूम है कि क्रांति के तीन जादूई हथियारों में से एक है पार्टी के नेतृत्व

में तमाम क्रांतिकारी वर्गों तथा तमाम क्रांतिकारी दलों को लेकर निर्मित एक संयुक्त मोर्चा। चूंकि यह क्रांति का एक हथियार है, इसलिए सशस्त्र संघर्ष के दौरान और सशस्त्र संघर्ष संचालित करने के उद्देश्य से ही इस संयुक्त मोर्चे का गठन होना अत्यावश्यक है। इसमें संदेह की कोई गुंजाईश नहीं है कि भारत का सर्वहारा वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग का हिरावल दस्ता कम्युनिस्ट पार्टी ही होगी इस संयुक्त मोर्चे (या जनवादी मोर्चे) का नेता व संगठक। कम्युनिस्ट पार्टी के सैद्धांतिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा सैनिक नेतृत्व के बिना क्रांतिकारी मोर्चा तैयार नहीं हो सकेगा और क्रांति भी सफल नहीं हो सकेगी।

नव जनवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग का प्रधान मित्र है किसान जनता एवं विशेष रूप से भूमिहीन व गरीब किसान। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसान की मित्रता ही है साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी व्यापक संयुक्त मोर्चे की बुनियाद। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के बिना एवं मजदूर-किसानों की दृढ़ संग्रामी एकता के बिना तमाम क्रांतिकारी वर्गों तथा क्रांतिकारी दलों के व्यापक संयुक्त मोर्चे का गठन कतई संभव नहीं है।

आज जबकि देश के बहुत से क्षेत्रों में कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध क्रमशः और भी तेज होता जा रहा है या यों कहिए कि गुरिल्ला संघर्ष छापामार इलाके से आधार इलाके के गठन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, तब निश्चित रूप से ही संयुक्त मोर्चे के गठन की मजबूत बुनियाद के रूप में मजदूर वर्ग व किसान जनता (खासकर गरीब व भूमिहीन किसानों) की दृढ़ मैत्री स्थापित हो रही है। इस मजबूत बुनियाद के आधार पर ही मजदूर और भूमिहीन व गरीब किसान, मंझोले किसान व धनी किसान के एक अंश और पेटी-बुर्जुआ मंझोले वर्ग के विभिन्न अंशों को लेकर एक वर्गीय मोर्चे की गठन-प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। छोटे व मंझोले पूंजीपति भी इस मोर्चे में शामिल होंगे, पर क्रांति की अग्रगति के एक चरण में जाकर ही ये लोग शामिल होंगे।

ऐसी स्थिति में, देश के पैमाने पर संयुक्त मोर्चे के गठन की प्रारंभिक व मूल प्रक्रिया के बतौर इसके भ्रूण रूप का गठन जरूरी है जो मुख्यतः गुप्त रहेगा। इस भ्रूण रूप को ही लगातार विकसित करते हुए परिपूर्ण ढंग से संयुक्त मोर्चा की शक्ल में बदल डालना होगा। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व भी मुख्यतः गुप्त रहेगा, पर मोर्चा की गतिविधियां आम रूप से खुली होंगी।

रणनीतिगत संयुक्त मोर्चे के तहत व तत्वावधान में ही एक कार्यनीतिगत संयुक्त मोर्चा का भी गठन करना होगा

हमारे देश में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको लेकर शासक वर्ग की तमाम पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती आ रही हैं। जात-पांत, साम्प्रदायिकता, धर्मीय अल्पसंख्यक आदि

समस्याओं को लेकर 'फूट डालो-राज करो' की नीति के अनुसार शासक गुट की ओर से विभिन्न पॉलिसी व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आज जब भारत के विशाल क्षेत्रों में क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष के व्यावहारिक रूप के बतौर कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष व्यापक पैमाने पर जारी है तथा जनता की जनमुक्ति गुरिल्ला सेना (PLGA) व पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी (PGA) बन उठी है, तब उपरोक्त सवालों पर भी संशोधनवादी व पार्लियामेंटरी पार्टियों के साथ हर मामले में (संघर्ष के विषय, रूप व पद्धति के मामले में) एक साफ विभाजन रेखा खींचते हुए तथा शासक गुट द्वारा अपनायी जा रही विभिन्न पॉलिसियों का व्यापक राजनीतिक भण्डाफोड़ करते हुए हमारे लिए भी कुछ कार्यक्रम लेना उचित व जरूरी है और ऐसा हम लेते भी आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों का भी उद्देश्य होगा देश में चल रहे कृषि क्रांतिकारी संघर्ष के पीछे और लोगों को शामिल करना और उन्हें यह समझाना की एक मात्र क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष के जरिए ही इन तमाम समस्याओं का भी अंतिम रूप से हल निकल सकता है। इस कार्यनीतिगत मोर्चा को सांगठनिक स्वरूप देने की शुरूआत स्थानीय रूप से और जहां हमारा संघर्ष तीव्र है और इसका व्यापक प्रभाव है वहां से ही करनी होगी।

यह कार्यनीतिक मोर्चा हमारे रणनीतिक संयुक्त मोर्चे के तहत व उसके तत्वावधान में ही गठित व संचालित होगा। वे सभी संयुक्त गतिविधियां या कार्यनीतिक गठजोड़ जो दीर्घकालीन लोकयुद्ध की सेवा नहीं कर रहे हों, बिल्कुल बेकार होंगे। विभिन्न जन-संगठनों, राष्ट्रीयता के संगठनों, अन्यान्य क्रांतिकारी और पेटी-बुर्जुआ संगठनों के बीच तथा अन्यान्य क्षेत्रों में हमारे सभी कार्यों का मूल्यांकन सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में करना होगा।

इसके अलावा, जो जहां, जबतक और जितने परिमाण में जनता के आम दुश्मनों के विरूद्ध लड़ने को तैयार होते हैं, वहां, तबतक और उतने ही परिमाण में उनके साथ एकताबद्ध कार्यक्रम चलाने की कोशिश करनी होगी। एकताबद्ध कार्यक्रम चलाते समय भी सुधारवाद का विरोध करना और जन-विरोधी व कम्युनिस्ट-विरोधी गतिविधियों का विरोध करना हमारा बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

राष्ट्रीयता संबंधी सही लाइन को वास्तविक प्रयोग के द्वारा और समृद्ध बनावें

यह बात सबों को मालूम है कि भारत बहुराष्ट्रीयताओं (multinational) का एक अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंतवादी देश है। यहां विभिन्न राष्ट्रीयताओं की जनता आर्थिक, राजनीतिक, भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक तौर पर विकास के एक-एक चरण में

हैं और उनकी अपनी विशेष विशिष्टता तथा जातिगत (राष्ट्रीयतागत) परम्परा भी मौजूद है। यहां पर एक ओर, एक या एकाधिक अग्रसर राष्ट्रीयताएं मौजूद हैं, तो दूसरी ओर, पिछड़ी स्थिति में रहने के लिए मजबूर की गई उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं भी मौजूद हैं, जो राष्ट्र (nation) के रूप में संगठित नहीं हो सकी हैं।

देश के अग्रसर राष्ट्रीयताओं के अंदर प्रभावशाली, प्रतिक्रियावादी तथा दलाल बड़े बुर्जुआ वर्ग साम्राज्यवाद के साथ सांठ-गांठ कर दीर्घकाल से ही राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं पर निर्मम शोषण व अत्याचार करते आ रहे हैं।

सभी मार्क्सवादी-लेनिनवादियों को मालूम है कि आज की राष्ट्रीयताओं की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का ही अभिन्न अंश है। फिर, वर्तमान समय की राष्ट्रीयताओं की समस्या (nationality problem) मूलतः किसान समस्या है। किसी भी राष्ट्रीयता का विशाल बहुसंख्यक भाग किसान ही होते हैं। किसान जनता राष्ट्रीयता आंदोलन की प्रधान वाहिनी है, उन्हें छोड़कर शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करना नामुमकिन है। इसे अस्वीकार करने का मतलब ही है राष्ट्रीयता आंदोलन में निहित जनवादी भावना व शक्ति को छोटा करके देखना। अतएव, वर्तमान समय की राष्ट्रीयता की समस्या (nationality problem)को नई जनवादी क्रांति से अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। यह राष्ट्रीयता आंदोलन राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति अर्थात् नव जनवादी क्रांति का अभिन्न अंग होते हुए विश्व सर्वहारा (प्रोलेतारीय) क्रांति का ही अभिन्न अंग है।

हमारे विचार से राष्ट्रीयता आंदोलन के मामले में राष्ट्रीय बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुवाओं की क्रांतिकारी भूमिका को इनकार करना भूल है। साधारणतः राष्ट्रीय बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ वर्ग अपने वर्ग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही राष्ट्रीयता का संघर्ष शुरू करते हैं लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ कभी भी राष्ट्रीयताओं के संघर्ष में नेतृत्व नहीं दे सकते। वे कभी भी राष्ट्रीयताओं के संघर्ष को अंत तक विजय के मार्ग से आगे बढ़ाकर नहीं ले जा सकते, बल्कि बीच में ही वे विश्वासघात करते हैं अथवा अन्य सभी संघर्ष के जैसा राष्ट्रीयताओं के संघर्षों को भी अपने संकीर्ण वर्ग स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए, मिजो नेशनल फ्रण्ट के नेता लाल डेंगा ने ऐसा किया है और फिलहाल झारखंड आंदोलन के कुछ नेता लोग भी ऐसा कर रहे हैं। आज दिन का उजाले जैसा साफ है कि झारखंड आंदोलन से संबंधित पार्टियों के नेताओं ने झारखंड आंदोलन के स्वार्थ को तिलांजलि देकर शोषक-शासक वर्ग तथा उसकी सरकार के साथ समझौते कर लिए हैं।

फिर राष्ट्रीयताओं के संघर्ष के मामले में पेटी-बुर्जुआ कभी भी अपने से कम्युनिस्टों के हाथों में नेतृत्व नहीं सौंपते अथवा बुर्जुआ या पेटी-बुर्जुआ राजनीति का विरोध किए बिना एवं जनता को क्रांतिकारी चेतना से जागरूक किए बिना किसी भी संघर्ष में सर्वहारा नेतृत्व अथवा कम्युनिस्टों का नेतृत्व कायम करना संभव नहीं है। केवल मात्र क्रांतिकारी राजनीति को अग्राधिकार देकर ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के रोशनी में खूब धैर्यपूर्वक पेटी-बुर्जुआ संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद के प्रभाव से जनता को मुक्त करके ही और अपनी पहल तथा राजनीतिक व सांगठनिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए ही कम्युनिस्ट लोग अन्य संघर्षों की तरह राष्ट्रीयता के संघर्षों के मामले में भी नेतृत्व कायम कर सकते हैं। इस रूप से ही राष्ट्रीयताओं के संघर्षों को भारत की नई जनवादी क्रांति तथा विश्व क्रांति की धारा के साथ जोड़ सकते हैं और इस तरह से ही वे राष्ट्रीयताओं के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रवाद के साथ तालमेल बिठाते हुए उसे वर्ग विचारों से लैस सही क्रांतिकारी राष्ट्रीयताओं के संघर्ष के मार्ग से संचालित कर सकते हैं। राष्ट्रीयता के संघर्ष में कम्युनिस्टों का नेतृत्व कहने से यही समझा जाता है।

हमारा संगठन शुरू से ही राष्ट्रीयता की समस्या और कम्युनिस्टों के कर्तव्य के बारे में एक सुस्पष्ट लाइन व कार्यभारों का निर्धारण करते हुए उसी के आधार पर राष्ट्रीयता बहुल इलाके में अपने कामकाजों को आगे बढ़ा रहा है। इस सवाल पर भी हमारे नेता कामरेड के.सी. के कई महत्वपूर्ण लेख मौजूद हैं जो उन्होंने 1968 से लेकर 1982 तक लिखे हैं। उनके द्वारा दी गई लाइन को ही आज हमारा संगठन राष्ट्रीयताबहुल विभिन्न इलाकों में व्यावहारिक रूप देने को कटिबद्ध है।

व्यावहारिक तौर पर झारखंड में उल्लेखित नीति का प्रयोग करने के परिणाम पर विचार-विश्लेषण करके देखा जाए। इस पिछड़े हुए इलाके की ठोस स्थिति की विशिष्टता के मुताबिक और जनता के चिन्तन व चेतना के स्तर तथा संग्रामी मिजाज के अनुसार हम अपनी पहल और स्वतंत्र कार्यक्रम के आधार पर जनता की रोजमर्रे की समस्याओं से शुरू कर विभिन्न समस्याओं को लेकर छोटी-बड़ी लड़ाइयों के कार्यक्रम सहित एक कृषि क्रांतिकारी कार्यक्रम को केन्द्रित कर क्रांतिकारी किसान संघर्ष निर्माण करने में सक्षम हुए हैं। इसी क्रम में झारखंड के विशाल इलाकों में क्रांतिकारी किसान कमिटी एक लोकप्रिय व प्रभावकारी संगठन के रूप में उभर आई है। क्रां.कि.क. के नेतृत्व में अभी तक करीब 20-30 हजार एकड़ से भी अधिक जमीन जनता ने जब्त किया है तथा जंगल की रक्षा व जंगल पर जनता का अधिकार कायम करने की लड़ाई जारी है। कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष के दौर से आत्मरक्षा दल, जनमिलिशिया दल व कुछ संख्यक एल.आर.जी.एस., प्लाटून व कम्पनी यानी पी.एल.जी.ए. का गठन राष्ट्रीयता बहुल इलाके में एक तात्पर्यपूर्ण

पहलू है। इस पी.एल.जी.ए. की सहायता से ही जनता ने वर्ग दुश्मनों की निजी सेनाओं पर जबरदस्त प्रहार किया है तथा कर रहा है। इसके अलावा अन्य जन-संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी स्वतंत्र पहलकदमी और स्वतंत्र कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष निर्माण करने के साथ-साथ झारखंड आंदोलन से संबंधित विभिन्न संगठनों के साथ जब, जहां और जितने परिमाण में संभव हो, एकताबद्ध कार्यक्रम ग्रहण करने का प्रयास जारी है। साथ ही साथ सही लक्ष्य व पथ के आधार पर संकीर्ण वर्ग विचारधारा तथा क्रांतिकारी संघर्ष विरोधी किसी भी चिंतन व क्रियाकलाप के विरूद्ध रचनात्मक आलोचना के जरिए एकता को निरंतर सुदृढ़ व शक्तिशाली करने का प्रयास जारी है। ठोस सच्चाई तो यह है कि झारखंड आंदोलन के लड़ाकू कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संबंध दिन-ब-दिन घनिष्ठ से घनिष्ठतर हो रहा है। अनुभव हमें दिखा रहा है कि प्रधानतः स्वतंत्र पहल और स्वतंत्र कार्यक्रम पर तथा राजनीतिक व सांगठनिक स्वतंत्रता पर निर्भर करके ही झारखंडप्रेमी लड़ाकू कार्यकर्ताओं और जनता के साथ एकताबद्ध कार्यक्रम ग्रहण किया जा सकता है एवं खूब धैर्य के साथ क्रमशः उन्हें पेटी-बुर्जुआ राजनीति और पेटी-बुर्जुआ संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है और वर्ग चेतना से समृद्ध सही क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के संघर्ष के मार्ग पर उन्हें संचालित किया जा सकता है।

आज हमारे संगठन के नेतृत्व में राष्ट्रीयताबहुल इलाके में जो संघर्ष गठित हुआ है और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसके नेतृत्व में पिछड़ी हुई उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के बीच से निकल आए सुयोग्य कम्युनिस्ट कैडर मौजूद हैं। ये सभी कैडर मजदूर वर्ग के हिरावल दस्ते के रूप में व्यापक राष्ट्रीयताओं की जनता को और राष्ट्रीयताओं के संघर्षों को पेटी-बुर्जुआ सुधारवादी व अवसरवादी नेतृत्व से विच्छिन्न कर वर्ग संघर्ष में तब्दील करने का निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं।

आज दिन का उजाले जैसा साफ है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में संचालित झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी आंदोलन (जिस आंदोलन में झारखंड इलाके के मजदूर-किसान तथा मेहनतकश जनता व्यापक रूप से भाग ले रही है तथा इस आंदोलन की धारा के साथ ओतप्रोत है) को ही लालखंड आंदोलन के नाम से परिभाषित किया जा रहा है। इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ता और जनता भी लालखंडी नाम से परिचित हो रहे हैं।

हाँ, लालखंड आंदोलन और लालखंडी नाम से परिभाषित और परिचित होने में कोई हिचकिचाहट तो हममें है ही नहीं, बल्कि हम इससे गौरव महसूस करते हैं। कहना अधिक है कि यह राष्ट्रीयता के आंदोलन के बारे में सही लाइन की सफलता को ही

अभिव्यक्त करती है।

इस लाइन की मूल बात है: अपनी स्वतंत्र पहलकदमी व स्वतंत्र कार्यक्रम के साथ-साथ राष्ट्रीयताओं के आंदोलन के साथ एकता व विरोध अर्थात्, आम दुश्मन के खिलाफ लड़ने में एकताबद्ध कार्यक्रम का लागू करने का प्रयास करना और जन विरोध ी व कम्युनिस्ट विरोधी कार्यवाही के खिलाफ तर्क-वितर्क व आलोचना- इन दोनों प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाकर ले जाना।

अत: राष्ट्रीयताबहुल इलाके में हमारी पार्टी का कर्तव्य है कि वह विभिन्न राष्ट्रीयताओं के विभिन्न गुटों के साथ हमारे अंतरविरोध को लचीले ढंग से हल करने की कोशिश करे तथा राष्ट्रीयता आंदोलन के इने-गिने प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर आम कार्यकर्ताओं व जनता के साथ एकताबद्ध हो जाए तथा उनके अंदर से ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनाने की कोशिश करे एवं उनको पार्टी में लाकर पार्टी का आधार मजबूत बनावे और कृषि क्रांति व राष्ट्रीयताओं की मुक्ति के आंदोलन को एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी एक सवाल अवश्य ही उठ सकता है, वह है- क्या राष्ट्रीयता बहुल इलाके में कुछ हद तक मजबूत पार्टी, स्वतंत्र पहलकदमी व स्वतंत्र कार्यक्रम और कुछ हद तक मजबूत जन आधार रहने के बावजूद तथा राष्ट्रीयताओं के नेताओं का अवसरवादी व आत्मसमर्पणवादी चरित्र का कुछ हद तक भण्डाफोड़ होने के बावजूद हम राष्ट्रीयताओं की मांगों और इच्छाओं को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु किसी संगठन का निर्माण करेंगे या नहीं? झारखंड आंदोलन के अवसरवादी-आत्मसमर्पणवादी नेतृत्व द्वारा आंदोलन के मूल स्वार्थ को तिलांजलि देने के बाद तथा नेताओं के चरम भ्रष्टाचारी चरित्र का जनता के सामने पर्दाफाश होने के बाद भी क्या झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु किसी संगठन का निर्माण करेंगे या नहीं?

इस सवाल पर गहराई से सोच-विचार करने के बाद केन्द्रीय कमिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह निर्णय है, जिन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ऐसा प्रभावकारी संगठन यानी झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने संबंधी एक प्रभावकारी संगठन बनाया जा सकता है, वे शर्तें कमोबेश पूरी होने के बाद अब ऐसे एक संगठन का निर्माण करना निहायत जरूरी है।

हम खुशी के साथ ऐलान कर रहे हैं कि झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु तथा झारखंड को एक शोषण मुक्त झारखंड यानी लालखंड बनाने हेतु कई साल पहले बड़े ही जोश-खरोश के साथ झारखंड आंदोलन संबंधी एक मंच का विधिवत उदय हो चुका है।

झारखंड आंदोलन संबंधी भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एम.सी.सी.आई.) की लाइन व व्यवहार के जरिए न केवल सी.पी.आई., सी.पी.एम. और लिबरेशन गुट का बल्कि झारखंड के धनबाद इलाके में मार्क्सवाद के नकाबपोश अन्य पार्टियों का राजनीतिक दिवालियापन भी साफ उजागर हो चुका है।

साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी राष्ट्रीयताओं के आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाने हेतु अभी-अभी हम कुछ हद तक समर्थ हुए हैं। यह बात सही है कि पूर्वोत्तर भारत में बहुत तरह की दिक्कतें और जटिलताएं मौजूद हैं। फिर भी इन दिक्कतों और जटिलताओं को झेलते हुए तथा उसे हल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमारे कामकाज को और विकसित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए:

(i) पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार की सशस्त्र लड़ाई को दिलोजान से समर्थन व मदद देनी होगी।

(ii) जब, जहां और जितने परिमाण में संभव हो तब, तहां और उतने ही परिमाण में आत्मनिर्णय के लड़ाइयों के साथ एकताबद्ध होकर मूल व सामान्य दुश्मनों के विरूद्ध संघर्ष चलाना होगा एवं साथ-साथ जनता विरोधी व कम्युनिस्ट-विरोधी क्रिया-कलापों के विरूद्ध लचीले ढंग से बहस जारी रखनी होगी।

(iii) आम दुश्मनों के विरूद्ध राष्ट्रीयताओं यानी, पिछड़ी हुई व उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की मेहनतकश जनता और विकसित राष्ट्रीयताओं की मेहनतकश जनता- इन दोनों के बीच एकता कायम करने हेतु दोनों की आम समस्याओं को ढूंढ़ निकालना होगा एवं उसपर महत्व देकर कामकाज व आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा।

(iv) राष्ट्रीयताओं की जनता के बीच तथा आम मेहनतकश जनता के बीच फूट व भेदभाव पैदा करने के साम्राज्यवादी षड्यंत्र तथा सी.पी.एम., कांग्रेस, भाजपा, सहित तमाम वोटबाज पार्टियों की कोशिशों को नाकाम करने हेतु तत्पर रहना होगा।

(v) राष्ट्रीयताओं की जनता के स्वार्थ-विरोधी तमाम प्रतिक्रियावादी पार्टियों का, खासकर सी.पी.एम. की चरम प्रतिक्रियावादी भूमिका का भण्डाफोड़ करना होगा।

हमें उम्मीद है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर यथोचित ध्यान दे पाने से हम पूर्वोत्तर भारत में अपनी स्वतंत्र पहल व स्वतंत्र कार्यक्रम पर प्रधान रूप से अमल करने के साथ-साथ राष्ट्रीयता आंदोलनों को भी सही दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

लोकयुद्ध के सटीक संचालन हेतु सात विभागों को सात स्कवाड (seven squad) के बतौर निर्मित करना एक बहुत ही जरूरी कर्तव्य है

इस बात से हमलोग सभी अवगत हैं कि क्रांति करने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी का होना अनिवार्य है। ऐसी एक पार्टी के नेतृत्व में अवश्य ही एक शक्तिशाली फौज और एक संयुक्त मोर्चा का रहना अत्यंत जरूरी है। इन तीनों को ही क्रांति सफल बनाने हेतु तीन जादूई हथियार कहा जाता है।

का. माओ ने कहा, "शस्त्र-बल द्वारा राजसत्ता छीनना, युद्ध द्वारा मसले को सुलझाना, क्रान्ति का केन्द्रीय कार्य और सर्वोच्च रूप है। क्रान्ति का यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी उसूल सर्वत्र लागू होता है, चीन पर और अन्य सभी देशों पर लागू होता है।" (युद्ध और रणनीति की समस्याएं)।

इस शिक्षा के अनुसार हमें भी युद्ध के द्वारा ही प्रतिक्रियावादी शासक गुटों की तानाशाह राज्य-मशीनरी, सेना, पुलिस व नौकरशाही को चकनाचूर कर जनता की राज्य-मशीनरी अथवा जनता के राज का निर्माण करना होगा।

वस्तुतः, युद्ध करना है तो पार्टी और जनफौज इसके क्रमशः प्रथम व द्वितीय महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। यह बात निश्चित है कि जो पार्टी युद्ध का निर्माण करेगी उस पार्टी को और भी कुछ महत्वपूर्ण कामों का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लेना होगा, नहीं तो युद्ध का निर्माण करना और उसे संचालित करना नामुमकिन हो जाएगा अथवा केवल कथनी में ही रह जाएगा। इन महत्वपूर्ण कामों को ही सात स्कवाड बनाने का काम कहा जाता है। अतः जो पार्टी युद्ध निर्माण और उसे संचालन करना चाहती है, उसके लिए अन्य सभी कामों के साथ-साथ इन सात स्कवाडों या विभागों का निर्माण करने के काम के लिए भी विशेष प्रयत्न करना होगा।

क्यों इन्हें स्कवाड बोला जा रहा है? इसीलिए कि हमारी क्रांति की लाइन ही ऐसी है। यहां युद्ध निर्माण करने की मानसिकता से कामकाज नहीं कर पाने से हम क्रांति के रास्ते से एक कदम भी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि हमारा युद्ध मूलतः गुरिल्ला युद्ध है, और चूंकि शक्तिशाली दुश्मन के साथ मुकाबला करने हेतु शुरूआती दौर में हमें काफी चलायमान रहना पड़ेगा, इसीलिए उक्त सात किस्म का विभाग बनाने के सवाल को भी चलायमान हालत में स्कवाड के रूप में बनाने के बारे में ही हमें सोचना होगा, अन्य किसी रूप में नहीं।

ये सात स्कवाड हैं– (1) प्रचार, (2) प्रेस, साहित्य व पार्टी शिक्षा, (3)कुरियर, (4)

डेन, पॉकेट, शेल्टर, (5) खुफिया तंत्र (एस्पायोनेज), (6) ऑर्डिनेन्स व तकनीकी (उत्पादन यूनिट सह) और (7) मेडिकल ।

केन्द्रीय मुखपत्र संबंधी समस्याओं के हल के लिए प्रयास जारी रखें

यह बात सही है कि केन्द्रीय मुखपत्र का जिस रूप से संचालन करना चाहिए, हमारी केन्द्रीय कमिटी अभी तक वैसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है इसलिए नियमित रूप से केन्द्रीय मुखपत्र का प्रकाशन होना संभव नहीं हो रहा है।

हालांकि, बांग्ला, हिन्दी आदि कुछ भाषाओं में अनियमित रूप से ही सही, फिर भी मुखपत्र निकलता है। पर अंग्रेजी में हमारे मुखपत्र के प्रकाशन की बात उल्लेख करने लायक नहीं है। इसके अलावा, असमिया, उड़िया और गुरूमुखी भाषा में भी मुखपत्र करीब नहीं के बराबर है। यह हमारी भारी कमजोरी है। खासकर, जब हम पूरे भारत में माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने हेतु एम.सी.सी.आई. की लाइन से उन्हें वाकिफ करना चाहते हैं, तब यह कमजोरी बहुत ही नुकसानदेह है।

हम जानते हैं कि मुखपत्र की भूमिका के बारे में कामरेड लेनिन की परिभाषा से हम कुछ दूर में ही हैं। इसलिए हम मुखपत्र के मामले में हमारी गंभीर कमियों को दूर करने के बारे में गंभीरतापूर्वक ही सोच रहे हैं। हम क्रमशः इस कमी को दूर करने हेतु कुछ कदम उठाएंगे। उदाहरणस्वरूप, हजारों समस्याओं के बावजूद सम्पादकमंडली की बैठक को नियमित करना एवं लेखों का अनुवाद करने खातिर अनुवादकों की टीम की भी नियमित बैठक का आयोजन करना आदि, आदि।

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप भी लेख प्रस्तुत करें और भेजने की कोशिश करें। हमारे साथियों को राजनीतिक व सैद्धांतिक लेख लिखने में दक्ष होना होगा।

पर एक बात हमें याद रखना है, वह यह है कि नियमित रूप से मुखपत्र निकालने का बहाना लेकर लड़ाई के मैदान से दूर हटकर शहर में बैठे रहने का तरीका अपनाने से नहीं चलेगा, बल्कि देहात में ही सबकुछ का केन्द्र बना लेना होगा। इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतें आएंगी देखकर उससे दूर हटने से भी काम नहीं चलेगा। दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन की बात को ध्यान में रखकर ही दिक्कतों का हल निकालना होगा।

इसके अलावा केन्द्रीय कमिटी की योजना के अनुसार जरूरी मार्क्सवादी साहित्य

के लिए प्रकाशन विभाग का भी सुचारू रूप से संचालन करना आवश्यक है। वह इसलिए आज जब महान माओ और माओ का चीन नहीं है, तब क्रांति के लिए जरूरतमंद तमाम लेख और पुस्तकों को खुद हमें छपा लेना होगा। अतएव इस दिशा में काम को आगे बढ़ाना हमारा अगले कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

पार्टी संगठन के अंदर सरल जीवन और कठोर मेहनत करने की परम्परा को बरकरार रखें; सदा विनयी व नम्र रहने की शैली अपनाएं

सर्वविदित है कि जीवन-यापन करने की शैली में भी दो वर्गों का, दो किस्म का दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। सर्वहारा वर्ग सरल जीवन और कठोर मेहनत का जीवन बिताने में अभ्यस्त है। स्वभावतः सर्वहारा की पार्टी में सरल जीवन और कठोर मेहनत करने जैसे गुणों का रहना अनिवार्य है।

पर इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेकर ही नकली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शुरू से ही बुर्जुआ जीवन यानी, ऐशो-आराम का जीवन बिताते आ रहे हैं। वाकई में कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी के अंदर सरल जीवन और कठोर मेहनत करने की शैली सम्पूर्ण रूप से अनुपस्थित है।

लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि नक्सलवाद और माओ का नाम लेकर ही भारत में सरकारी नक्सलपंथी लोग भी सरल जीवन और कठोर मेहनत की शैली को पसंद नहीं करते हैं। लगता है, इनलोगों की राय में सरल जीवन और कठोर मेहनत करने की शैली 'वाम' भटकाव की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है।

वस्तुतः क्रांतिकारी खेमे के अंदर भी कथनी में सरल जीवन और कठोर मेहनत की लम्बी-चौड़ी बात कहने के बावजूद बहुत से लोग करनी में इसका पालन करने में आना-कानी करते हैं। अतः ऐसे गलत रूझान, यानी सरल जीवन और कठोर मेहनत न करने के रूझान के विरूद्ध निरंतर संघर्ष चलाना होगा।

कामरेडो, हमारे शिक्षक व संस्थापक कामरेडों के सरल जीवन व कठोर मेहनत करने की कम्युनिस्ट जीवन-शैली को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उन दिवंगत नेताओं द्वारा स्थापित की गई यह शैली हमारी क्रांतिकारी परम्परा है। हम विरासत से यह परम्परा प्राप्त किए हैं। अतः इस क्रांतिकारी व कम्युनिस्ट परम्परा को बरकरार रखना हमारा पवित्र कर्तव्य है।

वस्तुतः पार्टी संगठन के अंदर सरल जीवन और कठोर मेहनत की शैली को एक संस्कृति के रूप में विकसित करना जरूरी है। इस शैली के तहत ही केन्द्रीय नेतृत्व से

लेकर सभी को जीवन बिताने में अभ्यस्त होना होगा। हर किसी को अपनी उम्र के मुताबिक काम करना होगा। हर किसी को अपना शरीर चुस्त-दुरूस्त रखना होगा एवं दीर्घसमय तक पैदल चलने की आदत बरकरार रखनी होगी। सशस्त्र संघर्ष से जूझ रही किसी पार्टी के लिए इस गुण का बने रहना अत्यावश्यक है।

साथ ही विनयी व नम्र होना भी कम्युनिस्ट का एक और महत्वपूर्ण गुण है। उक्त गुण को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यद्यपि कि इसके बारे में भी हमारे संगठन के अंदर कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। इस कमी के खिलाफ निरंतर संघर्ष चलाते रहें और विनयी और नम्र बने रहने की परम्परा को बरकरार रखने हेतु हर क्षण भरपूर कोशिश करें। घमंड और दादागिरी की मानसिकता को कभी भी पनपने न दें।

हम हर समय से ही ठीक थे, ठीक हैं और आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं– ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि हमारे अंदर भी कुछ भूलें हैं, कुछ कमियां हैं, ऐसे सोचना चाहिए और भूल व कमी के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते हुए अपने को क्रमश: अधिक से अधिक सही की ओर ले जाना चाहिए।

वस्तुत: सरल जीवन और कठोर मेहनत की जीवन शैली एवं विनयी व नम्र होने जैसे कम्युनिस्ट गुणों को भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र की क्रांतिकारी परम्परा के रूप में रक्षा व विकसित करने हेतु सदा संघर्ष करें।

केन्द्रीय कमिटी के बारे में दो टुक बातें

कामरेडो, आज की परिस्थिति में विभिन्न इलाके में, खासकर झारखंड, बिहार, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब, यू.पी. व उत्तराखण्ड में क्रांतिकारी लड़ाई जिस रूप से आगे बढ़ रही है उस रूप से सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक और सैनिक कार्यवाही के मामले में नेतृत्व देने के लिए क्या केन्द्रीय कमिटी उतनी चुस्त-दुरूस्त व योग्य हो पायी है? नहीं, ऐसा नहीं हो पायी है।

वस्तुत: लड़ाई की अग्रगति के हर चरण में यानी, हर घुमाव व मोड़ पर राजनीतिक, सांगठनिक व फौजी दिशा-निर्देशन देने के मामले में एवं समयानुसार गलत लाइन के खिलाफ सैद्धांतिक, राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष चलाने तथा लेख व प्रबंध आदि लिखने के बारे में केन्द्रीय कमिटी की कमजोरी बहुत ही स्पष्ट है।

किसी भी कमिटी, खासकर, उच्चतम कमिटी के सदस्यों के लिए सिर्फ एक ही इलाके में लगन से काम करना काफी नहीं है बल्कि, एक इलाके के साथ-साथ प्रेस, प्रचार व साहित्य, कुरियर, मेडिकल, स्पायोनेज (जासूसी), शस्त्र आदि डिपार्ट यानी 7 स्कवाड का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए हर सदस्य पर अलग-अलग जिम्मे का

बंटवारा होना चाहिए। हमें भलीभांति समझ लेना है कि क्रांतिकारी लड़ाई की अग्रगति के साथ-साथ उल्लेखित डिपार्ट अगर नहीं बनेंगे तो अग्रगति के सामने बाधाएं उत्पन्न होंगी। साथ ही कमिटी के सदस्यों के बीच विभिन्न फ्रण्ट की जिम्मेवारी का बंटवारा भी रहना चाहिए। साथ-साथ आज की परिस्थिति में जब एक ओर, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच सही एकता कायम करने और दूसरी ओर, जारी सशस्त्र संघर्ष को और उच्च स्तर में उठाने संबंधी निश्चित जिम्मा आ पड़ा है, तब केन्द्रीय कमिटी के अंदर भी ऐसी तमाम जिम्मेवारियों और कामों का बंटवारा रहना चाहिए।

और एक बात पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। वह बात है– क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की अग्रगति के साथ-साथ नेतृत्व को और गतिशील, सृजनशील, कर्मठ, निष्ठावान, सक्रिय तथा हर मामले में योग्य होना बहुत ही जरूरी है। यथेष्ट प्रयास के द्वारा ही इन सब गुणों को क्रमशः हासिल किया जा सकता है। ढीली-ढाली मानसिकता तथा कामकाज के घिसेपिटे तरीके इसके सामने बाधक हैं। इनके खिलाफ हमें निरंतर संघर्ष चलाना होगा। अपनी कमजोरी के खिलाफ खुद ही संघर्ष करने का तरीका अपनाना होगा।

कामरेडो, आपलोग केन्द्रीय कमिटी के कामकाज के बारे में तथा कमिटी सदस्यों के बारे में रचनात्मक आलोचना करें– यह केन्द्रीय कमिटी का आह्वान है। आलोचना और आत्मालोचना की प्रक्रिया के दौर से आगे बढ़कर ही हम और फौलादी बनेंगे तथा कठिन से कठिन समस्या को निश्चित रूप से हल कर पायेंगे।

क्रांतिकारी शक्तियों के साथ एकता की प्रक्रिया के बारे में

सबों को मालूम है कि एम.सी.सी. की तरफ से हम 1977 से ही बहुत से कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ एकता-प्रयास के तहत बातचीत करते आ रहे हैं। इस प्रयास को सफल बनाने हेतु हम शुरू से ही दो-तीन निम्न बुनियादी पॉलिसियों का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करते आ रहे हैं : (i) एकता-संघर्ष-एकता की नीति के अनुसार मूल-मूल राजनीतिक सवालों पर एकता स्थापित करने के उद्देश्य से मतभेद के बिन्दुओं पर ही ज्यादा बल देकर बातचीत करना और उन बिन्दुओं पर साझी समझदारी हासिल करने का भरपूर प्रयास करना; (ii) राजनीतिक बिन्दुओं पर बातचीत करने के साथ-साथ व्यवहार (या प्रयोग) में कौन क्या कर रहा है या करना चाहता है– इस पर भी बातचीत करना; और (iii) बड़ा ग्रुप जैसी मानसिकता से नहीं, बल्कि छोटा ग्रुप-बड़ा ग्रुप का भेद किए बगैर सभी को समान मर्यादा और महत्व देकर बातचीत करना आदि-आदि।

दीर्घ एकता प्रयास के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक– दोनों प्रकार की

उपलब्धियां ही हमें हासिल हुईं। हम सकारात्मक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार 2003 में इस एकता-प्रयास में एक गुणात्मक छलांग आया। कई माओवादी क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ एम.सी.सी. की एकता-प्रक्रिया पूरी हुई। कैसे मिली यह सफलता? अनुभवों ने हमें सिखाया है कि राजनीतिक-सांगठनिक-सैनिक लाइन आदि पर बातचीत करने के साथ-साथ जिनसे वार्ता जारी है- ऐसे सभी ग्रुपों को छोटा-बड़ा भेदभाव किए बिना समान मर्यादा और महत्व देना तथा उनकी अच्छाइयों से सीखने का आग्रह रखना बहुत ही जरूरी है और सच्चे माओवादी क्रांतिकारियों के साथ सही एकता स्थापित करने का मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी दृष्टिकोण भी यही है।

अब हम हमारे एकता-प्रयास में जो छलांग दृष्टिगोचर हुई है, उसके बारे में हम संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करेंगे।

आर. सी. सी. आई. (एम)

वस्तुत: आर.सी.सी.आई.(एम) का इतिहास नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद से ही जुड़ा हुआ है। नवम्बर, 1983 में UCCRI (ML) की सुधारवादी व अर्थवादी लाइन से अलग होकर रिवोल्युशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (माओवादी) का गठन हुआ एवं आर.सी.सी.आई.(एम) के नाम से इस ग्रुप का परिचय सामने आया। पर अनेक जटिल समस्याओं के दौर से गुरजते हुए तथा टूटन व विभाजन की प्रक्रिया के दौर से आगे बढ़ते हुए इस ग्रुप ने विभिन्न मुद्दों पर क्रांतिकारी आंदोलनों तथा कुछ सशस्त्र कार्रवाइयों का संचालन भी सफलतापूर्वक किया है। इस ग्रुप का कामकाज मूलत: पंजाब में ही है।

इस संगठन के साथ 1996 में हमारा संपर्क हुआ और दोनों संगठनों के बीच का आपसी संबंध क्रमश: घनिष्ठ बनता गया तथा एक-दो औपचारिक द्विपक्षीय मीटिंग के बाद दोनों की सहमति से यह तय किया गया कि एकता और विरोध के प्वाईंट तय कर विरोध के प्वाईंट पर बहस संचालित करते हुए यह स्पष्ट कर लिया जाए कि एक पार्टी में आने की क्या संभावना है । उसी के आधार पर विभिन्न बिन्दुओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता शुरू हुई और वार्ता के दौरान कुछ बुनियादी विषयों पर सहमति स्थापित हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति स्थापित नहीं हो पायी और देखा गया कि सहमति के बिन्दु इतनी शक्तिशाली है कि दोनों के बीच विलय होना संभव है। आखिरकार 2003 की पहली जनवरी को बड़े ही जोश-खरोश के साथ आर. सी. सी. आई. (एम.) और एम. सी. सी. के बीच एकता स्थापित हो गयी और दोनों संगठनों की ओर से एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया गया। विलय के बाद एम. सी. सी. का नाम एम.सी.सी.आई. कर दिया गया । जहां तक माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने का सवाल है आर.सी.सी.आई.(एम) और एम.सी. सी. का विलय हमारे पहले सफल कदम के रूप में चिन्हित है। तमाम क्रांतिकारियों ने

इस विलय का स्वागत किया है।

आर. सी. सी. एम.

आर.सी.सी.एम. [रेवोल्युशनरी कम्युनिस्ट सेंटर (माओइस्ट)] का इतिहास एम.सी. सी. के इतिहास से ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस ग्रुप से जुड़े हुए कामरेड एम.सी.सी. के क्रांतिकारी व गौरवमयी परंपरा का अभिन्न अंश भी हैं। पर एम.सी.सी. की प. बंगाल प्रादेशिक कमिटी के अंदर कुछ आंतरिक विवाद का तत्कालीन प्रा. कमिटी के सचिव 'बा' और सी.सी. से प. बंगाल की देख-रेख के लिए नियुक्त प्रतिनिधि 'भ' द्वारा अत्यंत नौकरशाही तरीके से हल ढूंढ़ने की कोशिश के कारण प्रा. कमिटी में तीव्र असंतोष पैदा हुआ और आखिरकार इस असंतोष के कारण कुछ साथियों ने एम.सी.सी. से 1997 में संबंध विच्छेद कर आर.सी.सी.एम. का गठन किया। खास कोई राजनीतिक मतभेद का आधार नहीं रहने के बावजूद एम.सी.सी. से निकलकर RCC(M) का गठन एम. सी.सी. का लम्बे राजनीतिक जीवन में एक दुखद घटना थी– ऐसा ही हमने माना।

अलग होने के बाद 5-6 वर्ष तक आर.सी.सी.एम. ने कुछ कामकाज करने का प्रयास किया। बाद में, 2001 में एम.सी.सी. के अंदर से 'बा'-'भ' गुट को निकाल-बाहर कर देने के बाद, आर.सी.सी.एम. ने पुनः एम.सी.सी. के साथ संपर्क स्थापित किया और एम.सी.सी. ने भी आर.सी.सी.एम. से बातचीत करने का निर्णय लिया।

इसके बाद द्वि-पाक्षिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई और आलोचना-अत्मालोचना के जरिए विरोध को हल कर लिया गया और यह पुनः एम. सी. सी. आई. में विलय कर गया । जहां तक माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने का सवाल है, आर.सी. सी.एम. का एम.सी.सी.आई. में विलय होना भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया।

सी. पी. आई. (एम-एल) (सेकेण्ड सी. सी.)

यह संगठन सी. पी. आई. (एम-एल) का एक अंश था जो का. चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद गठित हुआ था । सेकेण्ड सी.सी. का इतिहास कामरेड सी.एम. के नेतृत्व में स्थापित सी.पी.आई.(एम-एल) की गौरवमयी व क्रांतिकारी परम्परा से जुड़ा हुआ है। 1978 के बाद यह ग्रुप लिनपंथी के रूप में चर्चित हुआ और 1980-82 में बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसने कुछ सशस्त्र लड़ाई का भी निर्माण किया था, जो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन लिन के सवाल की वजह से करीब अन्य सभी एम-एल ग्रुपों से भी यह अलग-थलग था । फिर यह ग्रुप भी बहुत से आंतरिक संकट व टूटन की प्रक्रिया से गुजरा है। सेकेण्ड सी.सी. के जिस ग्रुप के साथ हमारा लम्बे समय से संबंध था, उस ग्रुप

ने पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में सशस्त्र किसान संघर्ष का निर्माण करने का प्रयास किया था और कुछ हद तक संघर्ष उठाया भी था। पर वे सभी संघर्ष आगे नहीं बढ़ पाये।

हमारे साथ इस ग्रुप की कई दौर की बातचीत सम्पन्न हुई थी और मूल-मूल कुछ राजनीतिक मुद्दों पर सहमति भी स्थापित हुई थी। पर लिन सवाल पर उनका स्टैण्ड के कारण बातचीत बीच-बीच में रूक जाती थी तथा और आगे नहीं बढ़ पाती थी। इसी बीच इस ग्रुप के अंदर ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के साथ एकता-वार्ता होने के सवाल पर और खासकर, एम.सी.सी. के साथ एकता स्थापित करने के सवाल पर तीव्र दो-लाइन का संघर्ष हुआ। अंततः इसके बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने महासचिव के खिलाफ विद्रोह कर दिया और हमारी पार्टी से एकता-वार्ता की इच्छा जाहिर की। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में एकता के वृहत्तर हितों के मद्देनजर इन्होंने लिन सवाल को छोड़ देने का निर्णय ले लिया। बाकी कुछ बुनियादी सवालों पर यूनिटी में ज्यादा रुकावट नहीं थी। हालांकि इतिहासगत तौर पर कुछ-कुछ मतभेद के बिन्दु भी मौजूद हैं। पर ये सब विलय के लिए बाधास्वरूप नहीं थे। आखिरकार 2003 की मई में सी.पी.आई.(एम-एल) (सेकेण्ड सी.सी.) और एम. सी. सी. आई. के बीच एकता-प्रक्रिया पूरी हो गई। यह एकता अन्य ग्रुपों के साथ एकता से अलग एक महत्व रखनेवाली है क्योंकि 1969 में सी. पी. आई. (एम-एल) पार्टी के गठन के बाद के इतिहास में खासकर, जब एम.सी.सी. सी. पी.आई.(एम-एल) में शामिल नहीं हुई तब से सी.पी.आई.(एम-एल) के किसी अंश के साथ एम.सी.सी.आई. का विलय एक बहुत बड़ी राजनीतिक तात्पर्य वहन करने वाली घटना है। एम-एल धारा और एम.सी.सी. धारा - इन दोनों धाराओं को मिलाकर एक महाधारा के निर्माण की प्रक्रिया में यह एक मील के पत्थर के रूप में चिन्हित करने वाली घटना है।

आर.सी.सी.आई.(एम-एल-एम)(सांगठनिक कमिटी)

आर.सी.सी.आई.(एम-एल-एम) नामक ग्रुप का पुराना इतिहास कुछ हद तक आर. सी.सी.आई.(एम) [जिससे हमारी एकता स्थापित हो गई है] से जुड़ा हुआ है। यह ग्रुप भी मूलतः पंजाब में ही अपना कामकाज जारी रखे हुए था। आर.सी.सी.आई. (एम-एल-एम) (सांगठनिक कमेटी) नामक यह नवगठित ग्रुप फिलहाल माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकता का निर्माण करने के सवाल पर अपने ग्रुप के शीर्ष नेता के खिलाफ बगावत करते हुए अपने संगठन की करीब 80-85 प्रतिशत शक्ति को साथ में लेकर निकल आया और तुरंत ही एम.सी.सी.आई. के साथ संपर्क स्थापित किया। इसके बाद इस ग्रुप के साथ भी दो दौर की द्वि-पक्षीय वार्ता संपन्न होने के पश्चात् दोनों संगठनों

के बीच एकता स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उसके अनुसार 25 सितम्बर 2003 में यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस रूप से माओवादी शक्तियों के साथ गोलबंद होने के मामले में एम.सी.सी.आई. और आर.सी.सी.आई.(एम-एल-एम) की एकता और एक सफल कदम के रूप में चिन्हित हुई। इस ग्रुप का भी काम तकरीबन पूरे पंजाब में ही है और मजदूरों, किसानों तथा महिलाओं के बीच इसने अच्छा-खासा जनाधार विकसित किया है। इसके नेतृत्व में जुझारू जन संघर्ष भी होते रहे हैं तथा इसके साथ विलय के बाद पंजाब में सशस्त्र संघर्ष के निर्माण व विकास-विस्तार के क्षेत्र में और भी अच्छी सम्भावनाएं सामने आयी हैं।

सी.पी.आई.(एम-एल) (नक्सलबाड़ी)

यह संगठन एक समय सी.पी.आई.(एम-एल) पार्टी का एक अंश था जो कामरेड सी.एम. की मृत्यु के कुछ समय बाद से सी.आर.सी. के नाम से सामने आया। इस ग्रुप ने ऐसी लाइन ग्रहण की जो पूर्णरूप से भारतीय क्रांति के लिए हानिकारक साबित हुई। अन्त में इस ग्रुप का शीर्ष नेता क्रांति के साथ गद्दारी कर शासक गुट से जा मिला। इस ग्रुप के ही एक हिस्से ने बाद में माओइस्ट यूनिटी सेंटर का गठन किया और 2000 में एक दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर सी.पी.आई.(एम-एल)(एन.बी.) बनाया।

हमारे साथ इस ग्रुप का 5-6 से अधिक द्वि-पक्षीय बातचीत का दौर चला और एकता व मतभेद के बिन्दुओं को भी तय किया गया। इसके आधार पर एम.सी.सी.आई. का मत रहा कि मतभेद के कुछ बिन्दु रहने के बावजूद अब दोनों के बीच में विलय-प्रक्रिया पूरी होनी संभव है। पर एन.बी. की ओर से अभी भी ऐसा फैसला लिया जाना संभव नहीं हो पाया है। इस कारण से ही इन दो संगठनों के बीच अभी-अभी विलय प्रक्रिया पूरी हाने की संभावना के बारे में निश्चित कुछ कह पाना नामुमकिन है।

सी. पी. आई. (एम-एल) (जनशक्ति)

यह आन्ध्र प्रदेश में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के आन्तरिक संघर्ष से अलग होकर हथियारबन्द संघर्ष की धारा आरंभ करनेवाले चन्द्र पुल्ला रेड्डी के नेतृत्व में गठित एक संगठन था । यह आरंभ में सी. पी. आई. (एम- एल) में शामिल नहीं था । बाद में यह एस. एन. एस. आदि के साथ जुड़कर भटकाव में चला गया । फिर इसके कई टुकड़े हुए । फिलहाल इसके एक टुकड़े ने आन्ध्र, बिहार आदि में पी. डब्ल्यु. और एम. सी. सी. आई. के नेतृत्व में बढ़ रहे क्रांतिकारी संघर्षों से प्रभावित होकर अपने संगठन के कार्यों की समीक्षा की और इसी धारा में अपने संगठन को ढालने की सोच बनाई । इस आधार पर

हमारे साथ उन्होंने वार्ता की पेशकश की। इसीबीच उनके साथ दो-तीन बैठकें हुई हैं। इसका एक सार्थक नतीजा भी दिखाई पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि अभी भी हम वार्ता के दौर में ही हैं।

सी.पी.आई. (एम-एल) लिबरेशन के राजनीतिक दिवालियापन का भण्डाफोड़ करें

यह स्पष्ट हो चुका है कि लिबरेशन गुट के नेताओं ने क्रांति का विरोध करने का बीड़ा उठा लिया है।

राजनीतिक रूप से नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक संघर्ष के जरिए चुनाव का बॉयकाट करने और सशस्त्र क्रांति को जारी रखने की जो लाइन उभर आई है और जो भारतीय क्रांति के लिए निर्धारित हो गई, उसका विरोध करना यानी, यों कहिए कि नक्सलबाड़ी की राजनीति, उसकी कार्यशैली व पद्धति तथा पथ का येन-केन-प्रकारेण विरोध करना ही लिबरेशन गुट का मुख्य राजनीतिक काम बन गया है। सचमुच ही लिबरेशन गुट सशस्त्र क्रांति की लाइन को यानी, सशस्त्र कृषि क्रांति, इलाकावार सत्ता दखल तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को तिलांजलि देकर वोट की राह का राहगीर बन चुका है। दरअसल, नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद राज्य (state) चरित्र, क्रांति का स्तर, क्रांति के दोस्त व दुश्मन, वोट बॉयकाट आदि मुद्दों पर क्रांतिकारी खेमे द्वारा मोटे तौर पर स्वीकृत बुनियादी लाइनों का कथनी और करनी में विरोध करना तथा इसके खिलाफ खड़ा हो जाना ही सर्वाधुनिक संशोधनवाद की खास विशेषता है। यों कहिए कि माओ विचारधारा का खास कोई महत्व नहीं है जैसी बात कहना और माओ का नाम लेकर माओ लाइन का तथा माओवाद का जी-जान से विरोध करना ही सर्वाधुनिक संशोधनवाद की एक और विशेषता है। सी.पी.आई.(एम-एल) पार्टी के इतिहास में शायद सबसे बड़ी बिडम्बना इस बात की है कि जिस लाइन के लिए कामरेड चारू मजूमदार अंतिम दिन तक संघर्ष करते रहे उसी लाइन का विरोध आज कामरेड चारू मजूमदार का नाम लेकर ही किया जा रहा है तथा संसद उपासक लिबरेशन गुट के सदर-दफ्तर (यानी दिल्ली ऑफिस) का नाम कामरेड चारू मजूमदार के नाम से ही रखा गया है। जीवित रहने से ऐसे लोगों को चिन्हित करने खातिर कामरेड चारू मजूमदार शायद गद्दार और संशोधनवाद के झण्डाबरदार जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल करते।

बहरहाल वर्ग संघर्ष के मैदान पर नजर डाली जाए। देहाती क्षेत्रों में "सही किसानों के हाथ में जमीन" और "क्रांतिकारी किसान कमिटी के हाथ में तमाम राजनीतिक

हुकूमत" नारों के आधार पर विकसित क्रांतिकारी किसान आंदोलन का विरोध करने हेतु तथा किसानों को गुमराह करने के नापाक इरादों से लिबरेशन गुट ने 'जमीन के राष्ट्रीयकरण' का नारा दिया है। आज यह जग जाहिर हो चुका है कि मौजूदा शोषणमूलक व्यवस्था के अंदर 'जमीन के राष्ट्रीयकरण' का नारा दरअसल सामंती-हिमायती नारा के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। असल में इस नारे के जरिए जमींदारों, जोतदारों और धनी किसानों के स्वार्थ की ही रक्षा होगी।

शहरी औद्योगिक क्षेत्र में लिबरेशन गुट की लाइन व कामकाज की शैली व पद्धति सी.पी.एम. सहित बाकी संशोधनवादी जैसी ही है। विदित है कि कुछ दिन पहले से ही लिबरेशन गुट 'वाम महासंघ' का नारा लगाते आ रहा है और इस 'वाम' महासंघ की लफ्फाजी की आड़ में ही सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के साथ उसकी सांठगांठ होती जा रही है। इसी बीच सी.पी.आई., सी.पी.एम. और लिबरेशन गुट मिलकर जारी क्रांतिकारी किसान संघर्ष के विरूद्ध कुत्सा प्रचार सहित अन्य प्रतिक्रांतिकारी कार्यवाहियों का भी संचालन कर रहे हैं।

जहां तक हमारे साथ सी.पी.आई.(एम-एल) लिबरेशन गुट के संबंध का सवाल है, उसको समझने के लिए इतिहास की ओर झांकना होगा। 1982 में जब विनोद मिश्र के नेतृत्वाधीन सी.पी.आई.(एम-एल) लिबरेशन ग्रुप के साथ केन्द्रीय स्तर पर जारी एकता-वार्ता आई.पी.एफ. में शामिल होने के सवाल पर टूट के कगार पर पहुंच गई थी उसी समय उनके प्रतिनिधि ने साफ कहा था कि उनकी केन्द्रीय कमिटी गया, औरंगाबाद और नवादा जिलों (जहां हमारा खास काम है) की ओर उनके कामकाज की गति बढ़ाने का निर्णय ले ली है। इस निर्णय की बात सुनने के बाद, ताकि दोनों संगठन (यानी एम.सी.सी. और लिबरेशन) के बीच तनाव पैदा न हो इस मकसद से हमने हमारी केन्द्रीय कमिटी की ओर से हमारे इलाके के अंदर से गुजरते हुए इलाका विस्तार की लिबरेशन की इस योजना पर पुनः सोच-विचार करने हेतु 12 अप्रैल, 1982 को लिबरेशन की केन्द्रीय कमिटी के पास चिट्ठी भेजी थी। लेकिन उनलोगों ने तुरंत इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तब हमने फिर एक यादगारी चिट्ठी भेजी। एक साल के बाद उनलोगों ने एक छोटी सी चिट्ठी के जरिए यह जानकारी दी कि समूचे बिहार में ही उनका काम है। इसलिए किसी भी पॉकेट में अगर एम.सी.सी. का कुछ काम है तो लिबरेशन के बिहार राज्य स्तरीय कमिटी के साथ बैठकर एम.सी.सी. के लोग बातचीत कर सकते हैं, पर सार्विक तौर पर अपने निर्णय में परिवर्तन लाने की कोई जरूरत वे महसूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल, उनका कहना था कि समूचा बिहार ही उनका है, फिर एम.सी.सी. कहां से आ गयी ?

साफ जाहिर है कि लिबरेशन गुट ने चिट्ठी का जवाब लिखा था दादागिरी की भावना से यानी, बिहार में दादा बनकर रहने के मानसिकता से।

पहले बड़े ग्रुप की अहंवादी भावना, उसके बाद दादागिरी की भावना और आज उसके परिणामस्वरूप अनिवार्यत: आक्रमणकारी की भूमिका– यह है हमारे प्रति सी.पी. आई.(एम–एल) लिबरेशन गुट द्वारा अपनाया गया रूख। सी.पी.आई.(एम–एल) लिबरेशन का नेता विनोद मिश्र जब जीवित था तो उसने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि वह एम.सी.सी. को पीट–पीटकर गोलमेज बैठक पर बैठने के लिए मजबूर कर देगा। इन बातों से भी साफ है कि लिबरेशन गुट हमारे खिलाफ कितना आक्रामक रूप लिए बैठा है। वाकई में, जब से लाइन का बुनियादी परिवर्तन करते हुए लिबरेशन गुट पूरे तौर पर एक संसदवादी पार्टी बन गया तब से शोषक वर्ग के लोगों और सामंती हिमायत करने वाले दबंग लोगों के पार्टी में व्यापक रूप से घुस आने के कारण पहले तो पार्टी का वर्गीय चरित्र बदल गया और बाद में सत्ता से मिलकर क्रांतिकारी किसान आंदोलन विरोधी, जन–विरोधी, संशोधनवादी तथा प्रतिक्रियावादी पार्टी में वह तब्दील हो गया। इस बदलाव के साथ–साथ लिबरेशन ग्रुप ने बिहार में विभिन्न क्रांतिकारी ग्रुपों को अपने हमले का निशाना बनाया और कुछ क्रांतिकारी कामरेडों की एक सोची–समझी पॉलिसी के तहत हत्या की। एम.सी.सी. पर भी उसने आक्रमण किया एवं हमारे कार्यकर्ताओं और जनता की लगातार हत्या की तथा पुलिस का मुखबिर बनकर और पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से 1994 में लई–मटगढ़ा हत्याकाण्ड (जिसमें हमारे ग्यारह कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई) को अंजाम दिया। फिर, झारखंड में "एम.सी.सी. व लालखंडियों को उखाड़ फेंकने हेतु झुमरा पहाड़ मार्च" को क्रियान्वित कर लिबरेशन गुट अपनी आक्रमणकारी भूमिका को स्पष्ट उजागर कर चुका है और अभी भी ऐसे कुकर्म जारी रखे हुए है।

हमारी नीति है, हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आक्रमण कर बैठा तो अवश्य ही आत्मरक्षा खातिर जवाबी कार्रवाई चलाने का अधिकार हमारा रहेगा। हालांकि इसमें हम वर्ग दिशा व जनदिशा का ध्यान रखेंगे।

एम.सी.सी. मानती है कि संशोधनवाद एक बुर्जुआ विचारधारा है, एक बुर्जुआ सिद्धांत है और संशोधनवाद के हर प्रकार के आक्रमण का मुकाबला करने हेतु हमें भी सदा तत्पर रहना होगा।

याद रखें, संशोधनवाद आज के युग का मुख्य खतरा है और इसलिए संशोधनवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष किये बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अत: संशोध नवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष जारी रखते हुए मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को बुलन्द रखें।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध

RIM के साथ हमारे संबंध के बारे में

क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयतावादी आंदोलन [Revolutionary Internationalist Movement (RIM)] नामक यह संगठन कई देशों के माओवादी शक्तियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्माण करने हेतु पहल लेनेवाला एक संगठन है। RIM के साथ हमारा संबंध 1996 से ही कायम हुआ। 1997 के अक्टूबर में ही रीम के प्रतिनिधियों के साथ पहली औपचारिक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कुछ मूल राजनीतिक मुद्दों को लेकर यानी साम्राज्यवादी संकट का मूल्यांकन, युग का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत संबंधी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मूल-मूल और प्रधान अंतर्विरोध के सवाल, माओवाद के बारे में अपनी-अपनी समझ आदि मुद्दों पर बहस हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की बातों को समझने हेतु कोशिश की। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों के बीच में कहां सहमति है और कहां मतभेद- इसके बारे में एक प्रारम्भिक धारणा बनी। बाद की मीटिंग में मतभेद के बिंदुओं पर और भी बातचीत जारी रखने का निर्णय हुआ।

दूसरी बैठक सितम्बर, 1999 में हुई। हालांकि इसमें मतभेद के बिंदुओं पर बातचीत न होकर MCC और CPI(M-L)(PW) के बीच की आपसी झड़प और उसे हल करने की सोच पर बातचीत हुई। साथ ही साथ हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ने की जरूरत पर रजामंदी जताई। हमारी सी.सी. का मत था कि कम्युनिस्ट आंदोलन के पिछले 165 वर्षों के दौरान कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित सवाल पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के अनुभव रहने के बावजूद 'दुनिया के मजदूरों एक हो' और 'दुनिया के मजदूरों और उत्पीड़ित जनता एक हो' जैसे नारों को साकार रूप देने हेतु पुराने अनुभवों से शिक्षा लेकर नए ढंग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सवाल पर चाहे कितनी ही समस्या क्यों न रहें, पर हमारे लिए समस्याओं से लड़ते हुए उनका समाधान करने हेतु एक सकारात्मक निर्णय लेना आवश्यक है। इसके बाद सन् 2000 के नवम्बर-दिसम्बर में रीम प्रतिनिधियों के साथ हमारी तीसरी बैठक संपन्न हुई, जहां मतभेद के विभिन्न बिन्दुओं पर कई दिन तक खुलकर वाद-विवाद और बहस हुई और अंत में कुछ बुनियादी बिन्दुओं पर साझी समझदारी बनी। हमने हमारी ओर से उसी मीटिंग में ही रीम के तीन बुनियादी दस्तावेजों पर बत्तीस प्वाइंट संशोधन (ammendments) पेश किये।

सन् 2002 की अप्रैल में रीम के साथ चौथी बैठक सम्पन्न हुई और उसी बैठक

में ही रीम की ओर से एम.सी.सी. को रीम की सदस्यता दी गई। तब से एम.सी.सी. रीम के अंतर्भुक्त एक सदस्य संगठन के रूप में अस्तित्वमान है।

हालांकि अभी भी बहुत सी समस्याएं मौजूद हैं। फिर भी समस्याओं के हल हेतु हमने एकता–संघर्ष–एकता की नीति का अनुसरण करते हुए रीम के साथ बातचीत व बहस जारी रखने की मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी नीति पर अमल करते रहने का निर्णय ग्रहण किया है।

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) [CPN(Maoist)] के साथ हमारा संबंध

सी.पी.एन.(माओवादी) के साथ हमारा संबंध करीब 17–18 वर्ष पुराना है। जाहिर है कि हम दोनों के बीच का बिरादराना संबंध बहुत ही मजबूत है और एक–दूसरे के सहयोग पर आधारित है।

जग जाहिर है कि सी.पी.एन.(माओवादी) के नेतृत्व में नेपाल में 1996 से लोकयुद्ध की शुरूआत हुई और क्रमशः वहां लोकयुद्ध तीव्र से तीव्रतर होते गया। आज तो यह लोकयुद्ध न केवल नेपाल को ही झकझोर रहा है बल्कि इसने पूरे दक्षिण एशिया को भी हिलाकर रख दिया है। केवल इतना ही नहीं, सी.पी.एन.(माओवादी) के नेतृत्व में हिमालय पर्वत के शिखर पर लोकयुद्ध की जो लाल पताका बुलंदी से फहरायी गयी है उसने तमाम दुनिया के माओवादी आंदोलन में भी एक नया जोश पैदा किया है। पर हम जानते हैं कि अमरीकी साम्राज्यवाद और उसकी शागिर्द विस्तारवादी भारत सरकार नेपाल के लोकयुद्ध को कुचलने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। आज उक्त बुरे प्रयास को नाकाम करने और नेपाल में जारी लोकयुद्ध को मदद करने का मतलब ही है भारत में लोकयुद्ध को और भी व्यापक तथा और भी तीव्र करना। हम अवश्य ही मदद के इस पहलू पर विशेष ध्यान देते रहेंगे। इसके अलावा, समय–समय पर राजनीतिक मुद्दों पर दोनों के बीच में मत विनिमय करने के काम पर भी हम विशेष ध्यान देंगे।

दक्षिण एशिया में कम्पोसा (CCOMPOSA) का गठन पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास हेतु एक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण पहलू है

सबों को मालूम है कि दक्षिण एशिया अभी क्रांतिकारी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। खासकर नेपाल में जारी लोकयुद्ध इसमें एक विशेष भूमिका निभा रहा है। इसके

अलावा, एम.सी.सी.आई. और सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लू) के नेतृत्व में भी भारत के विशाल क्षेत्र में कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष यानी लोकयुद्ध क्रमश: और भी तेज होते जा रहा है। साथ-साथ बांग्लादेश, भूटान आदि देशों में भी माओवादी पार्टियों का जन्म होने के कारण सशस्त्र क्रांति के विकास की संभावना दिखाई पड़ रही है। एक बात में कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का क्रांतिकारी उभार 'एशिया, अफ्रीका व लातिन अमेरिका क्रांति का तूफानी केन्द्र है'– इस कथन की ही जीती-जागती मिसाल है।

ऐसी स्थिति में, सन् 2001 में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों के ग्यारह संगठनों को लेकर को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एण्ड ऑर्गेनाईजेसन्स ऑफ साउथ एशिया [यानी दक्षिण एशिया की माओवादी पार्टी और संगठनों की समन्वय समिति, (CCOMPOSA)] नामक एक संगठन दक्षिण एशिया को केन्द्र कर बन उठा। फलस्वरूप, दक्षिण एशिया के पैमाने पर बढ़ रहे क्रांतिकारी संघर्षों के बीच सहयोग कायम करने तथा एक-दूसरे को मदद-मुहैया करने का एक वास्तविक आधार बन उठा। यद्यपि कि कम्पोसा का लक्ष्य-उद्देश्य और कार्यक्रम कैसा होना चाहिए– इस पर अभी भी सभी के चिंतन में एकरूपता नहीं आई है। बहरहाल कम्पोसा की पहल से कुछ कार्यक्रम लिया जाना संभव हुआ है और हो रहा है। कम्पोसा की ओर से एक अनियतकालीन पत्रिका भी निकाली जा रही है। हमारे विवेचन से कम्पोसा के गठन से साम्राज्यवाद खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और दक्षिण एशिया के सभी दलाल शासक गुट भयभीत हो उठे हैं और इसके विपरीत, दक्षिण एशिया की क्रांतिकारी जनता इससे प्रफुल्लित हो उठी है।

आज जब साम्राज्यवाद के सरगना अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में सभी प्रतिक्रियावादी शासकगण आतंकवाद के विरोध के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, तब कम्पोसा की भूमिका और उसे ठोस करने की जरूरत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद है कि इसके मद्देनजर कम्पोसा का अगला कदम व कार्यभार को निर्धारित किया जाएगा।

हमारी कुछ विशिष्टताएं

सभी जानते हैं कि 1964 के उत्तरार्द्ध से लेकर आज तक के 40 वर्षों के दौरान हमारा संगठन किस प्रक्रिया से बना और विकसित हुआ है। पहले तो "चिन्ता" और "दक्षिण देश" ग्रुप के रूप में हमारा व्यापक परिचय बना। फिर 1969 की 20 अक्टूबर को हमारे संस्थापक नेता व शिक्षक कामरेड के.सी. के नेतृत्व में माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एम.सी.सी.) के नाम से हमारा संगठन अस्तित्वमान हुआ। 1982 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाइन का अनुसरण करते हुए और उसे आगे बढ़ाते हुए आखिर 2003 में कई माओवादी क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ एकता स्थापित होने के बाद संगठन का नाम भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एम.सी.सी.आई.) रखा गया। इसी बीच समूचे भारत में एक

प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बतौर एम.सी.सी.आई. की मान्यता सर्वविदित है।

सवाल है कि एम.सी.सी.आई. संगठन की विशिष्टताएं क्या रहीं जिससे कि एकदम शुरूआती दौर से ही कई प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए एक छोटा सा संगठन अपेक्षाकृत बड़ा तथा आज की स्थिति तक पहुंचने वाला संगठन बन गया?

पहली विशिष्टता : भारत में दीर्घदिन से जड़ जमाए बैठे संशोधनवादियों के साथ राजनीतिक व सांगठनिक मामले सहित हर मामले में सैद्धांतिक व व्यावहारिक तौर पर एक सुस्पष्ट विभाजन-रेखा खींच देने के सवाल को हम शुरू से ही क्रांतिकारी मार्ग से आगे बढ़ने हेतु एक अहम प्रस्थान बिन्दु मानते आ रहे हैं। हमारी समझ से यह एक ऐसा बिन्दु है जिसे ठीक ढंग से हल किये बिना सही लाइन व सही क्रांतिकारी मार्ग से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस समझ के आधार पर जहां तक विभाजन रेखा खींचने में हम सफल हुए वहीं तक हमें सफलता भी मिली।

दूसरी विशिष्टता : 1969 में प्रस्तुत रणनीति और कार्यनीति संबंधी दस्तावेज ने ही हमारे लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जिसपर आधारित होकर ही हम भारत की ठोस स्थिति का विश्लेषण करते हुए चुनावी पथ व चुनाव में हिस्सा लेने के सवाल को रणनीतिक महत्व के बराबर देखते हुए तथा इसे पूरे तौर पर खारिज करते हुए सशस्त्र कृषि क्रांति व दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते को मुक्ति के एकमात्र रास्ते के रूप में ग्रहण करने में सक्षम हुए हैं।

तीसरी विशिष्टता : सशस्त्र कृषि क्रांति (जो कि नवजनवादी क्रांति की अन्तर्वस्तु या धुरी है) को व्यावहारिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू से ही किसान आंदोलन के लक्ष्य-उद्देश्य और संगठन के रूप व कार्यक्रम के मामले में सी.पी.आई., सी.पी.एम. आदि संशोधनवादियों के साथ सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए क्रांतिकारी किसान कमिटी संबंधी अवधारणा को सामने रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी किसान संघर्षो खासकर, सत्ता दखल के लक्ष्य की ओर उन्मुख किसान संघर्षों का संचालन करते आ रहे हैं। हम इस विभाजन-रेखा को भारत में सशस्त्र कृषि क्रांति की शुरूआत करने हेतु एक महत्वपूर्ण व निर्णायक विभाजन-रेखा के रूप में मानते आ रहे हैं। इस अवधारणा के व्यावहारिक प्रयोग ने हमें गुप्त, गैरकानूनी व हथियारबंद तौर-तरीकों से लाखों-लाख किसान जनता को गुरिल्ला युद्ध में कैसे शामिल किया जाए- इस मामले में बहुत ही सकारात्मक अनुभव और उपलब्धियां हासिल करने में काफी मदद की है।

चौथी विशिष्टता : सारे कामकाज में दीर्घकालीन लोकयुद्ध का निर्माण करने संबंधी दृष्टिकोण अपनाने पर हम सदा जोर देते आये हैं और शुरू से ही जनफौज व लाल आधार क्षेत्र निर्माण करने के काम को मौजूदा समय के प्राथमिक, प्रधान व केन्द्रीय कर्तव्य

के रूप में साकार करने हेतु अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कुछ अनुकूल इलाके को रणनीतिक इलाके के बतौर चुनकर तथा उसके अनुरूप कैडर पॉलिसी ग्रहण करते हुए अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करते आए हैं तथा आ रहे हैं।

पांचवीं विशिष्टता : पार्टी की नेतृत्वकारी संस्थाओं में आने के लिए नेतृत्व की सही पद्धति के रूप में सिद्धांत और व्यवहार को मिलाना और इस प्रक्रिया के दौर से आगे आये साथियों को लेकर ही नेतृत्वकारी साथियों की एक टीम (चाहे वह जरूरत की अपेक्षा कम ही क्यों न हो) बनाने में हम सक्षम हुए हैं जिसके आधार पर कमोबेश नेतृत्व का एक धारावाहिक रूप बरकरार रहा है। खासकर, कामरेड के.सी. व कामरेड अमूल्य सेन के गुजर जाने के बाद इस धारावाहिकता को बरकरार रखने में तथा उसे लगातार आगे बढ़ाने में हम सक्षम हुए हैं।

छठी विशिष्टता : वर्ग लाइन को दृढ़तापूर्वक लागू करते हुए मूल वर्ग से यानी, भूमिहीन व गरीब किसान वर्ग से ऐसे कुछ वर्ग संतानों तथा भूमि की संतानों को (चाहे वह संख्या में कितने ही कम क्यों न हो) न केवल हम योद्धा, कार्यकर्ता व संगठक के रूप में निर्मित कर पाये हैं, बल्कि उन्हें पार्टी की केन्द्रीय कमिटी से लेकर स्पेशल एरिया, राज्य, रीजनल आदि नेतृत्कारी कमिटियों तक में ले आने में सक्षम हुए हैं और सचमुच वे योग्यता व दक्षता के साथ आज पार्टी व क्रांति का नेतृत्व दे रहे हैं।

सातवीं विशिष्टता : हमारे संगठन के दो केन्द्रीय सम्मेलन होने के बावजूद दीर्घदिन से ही हम अपने संगठन को एक केन्द्र (पार्टी नहीं) के रूप में मानते आ रहे हैं और इसीलिए तमाम सच्चे कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों (जिन्हें आज हम सच्चे माओवादी क्रांतिकारी कहते हैं) को एकताबद्ध करके ही एक अखिल भारतीय पार्टी बनायी जा सकती है, इसके लिए प्रयास भी करते आ रहे हैं। एकता निर्माण करने के सवाल पर हमने हर समय छोटा ग्रुप-बड़ा ग्रुप का भेदभाव किए बगैर सभी को समान मर्यादा और महत्व देकर बातचीत जारी रखने की पॉलिसी को दृढ़तापूर्वक अमल में लाने की कोशिश की है और आज भी वैसा ही करना उचित समझते हैं। एकता के मामले में सभी को समान मर्यादा व महत्व देना– यह अवश्य ही आज हमारी एक विशिष्टता के रूप में सामने आयी है।

ऊपर में हमारी बहुत सी विशिष्टताओं के अंदर केवल कुछेक का ही यहां उल्लेख किया गया है। यही विशिष्टताएं एम.सी.सी.आई. की ऐतिहासिक क्रांतिकारी धारा को एक विशेष पहचान देती हैं।

सकारात्मक उपलब्धियाँ

हमारा प्रस्थान बिन्दु था– संशोधनवाद के साथ सुस्पष्ट विभाजन-रेखा खींचना और क्रांतिकारी दिशा तय कर क्रांति के तीन जादूई हथियारों का निर्माण करने के लक्ष्य को हासिल करना, ताकि भारत की नव जनवादी क्रांति को सम्पन्न कर समाजवादी क्रांति तथा विश्व सर्वहारा क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। इस लक्ष्य की दिशा में हम जो कर पाये हैं, वह हमारी सकारात्मक उपलब्धियों में गिना जाएगा। वे उपलब्धियाँ निम्न हैं:

1. इस लम्बे अन्तराल में हम संगठन के भीतर और बाहर के नये पुराने संशोधनवाद को सिद्धांत और व्यवहार में काफी हद तक पराजित कर पाने में सक्षम हुए और मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के आधार पर अपनी क्रांतिकारी सैद्धांतिक-राजनीतिक लाइन को उन्नत और विकसित करने में भी बहुत हद तक कामयाब हुए।

2. हम अपनी रणनीतिक व कार्यनीतिक लाइन को भी आगे बढ़ाने और उसे आज के स्तर में उन्नत व विकसित कर पाने में बहुत हद तक सफल हुए।

3. हम मजबूत पार्टी कार्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम हुए।

4. हम सी.पी.आई.(एम-एल) के सच्चे माओवादी क्रांतिकारियों सहित अन्यान्य सच्चे माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने में कुछ हद तक सफल हुए। साथ ही साथ बाकी माओवादी शक्तियों को छोटा-बड़ा का भेद किए बगैर एकताबद्ध करने के प्रयास में जुटे रहने का निर्णय लेने में भी हम सक्षम हुए।

5. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम माओवादी क्रांतिकारियों के साथ एकताबद्ध होने के प्रयास में कुछ हद तक सफल हुए।

6. हम आज एक अखिल भारतीय माओवादी पार्टी बनाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के कगार पर हैं।

7. सैनिक विषयों के हर मामले में चुस्त-दुरूस्त होने के लिए हमने केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन (CMC) का तथा उसके दिशा-निर्देशन में स्पेशल एरिया, राज्य आदि मिलिटरी कमीशनों का और विभिन्न स्तरों के कमानों का भी गठन किया है। साथ ही जनफौज व आधार क्षेत्र बनाने के लक्ष्य से अभी-अभी के फौजी संगठन के रूप में हमने पी.एल.जी.ए. का गठन किया है और आगे बढ़कर इसे पी.एल.ए. (जनमुक्ति सेना) में बदल डालने की एक रूप रेखा भी प्रस्तुत की है। साथ ही हमने अपनी सैनिक लाइन का भी विकास किया है। फिर छापामार इलाकों को आधार क्षेत्र में बदल डालने के कार्य में भी हम संलग्न हुए हैं। साथ ही साथ लड़ाई के नये-पुराने सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर

एक उन्नत चरण की लड़ाइयां लड़ने में भी हम सक्षम हुए हैं।

8. रणनीतिक और कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चे के निर्माण में अपनी पहलकदमी से विभिन्न शक्तियों को जोड़ने में हम कारगर भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।

9. हम स्वतंत्र पहलकदमी पर सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध व दीर्घकालीन लोकयुद्ध का विस्तार करने तथा क्रांतिकारी आन्दोलन का भी विकास-विस्तार करने में सफल हुए हैं।

10. हम अपनी स्वतंत्र पहलकदमी और स्वतंत्र कार्यक्रम के आधार पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीयता आंदोलन और कम्युनिस्टों के कर्तव्य– इस सवाल पर सिद्धांत व व्यवहार दोनों मामले में ही एक सही पॉलिसी ग्रहण करने में सक्षम हुए हैं।

11. क्रांतिकारी संस्कृति के निर्माण में भी हमने सफलता पाई है।

12. अपनी आर्थिक नीति और आर्थिक उत्पादन-कार्यों के रचनात्मक विकास में भी हम संलग्न हो चुके हैं।

नकारात्मक पहलू

हमारी यात्रा ने शुरू से आज तक की एक लम्बी अवधि को पूरा किया है और यह बड़ी ही चुनौतीपूर्ण रही है। यह जैसे बाहर से चुनौतीपूर्ण रही, उसी तरह भीतर से भी चुनौतीपूर्ण रही है। इसमें अब तक के हमारे कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1. हमारे भीतर मौजूद अवसरवादी तत्व लम्बे समय तक संगठन की सर्वोच्च कमिटी में अपना आसन जमाये रहा, जिससे संगठन का काफी नुकसान हुआ और राजनीतिक व सैनिक क्षेत्र में विकास अवरूद्ध हुआ। खासकर, पार्टी को भी दो विपरीत तत्वों की एकता के रूप में देखते हुए तथा इस नियम को सजीव ढंग से लागू करते हुए पार्टी को और गतिशील व सक्रिय बनाने का काम भारी बाधित हुआ और सामरिक लाइन, सामरिक संगठन व सामरिक कार्यवाही आदि तमाम पहलुओं के विकास के काम में भी भारी गतिरूद्धता आई। यह घिसेपिटे लीक पर लम्बे समय तक चलने की प्रवृत्ति का इजहार है।

2. एक परिपक्व कम्युनिस्ट क्रांतिकारी पार्टी-संगठन के लिए इतने लम्बे समय तक दूसरे एक क्रांतिकारी संगठन के साथ हथियारी झड़प में लगे रहना एवं उसका यथाशीघ्र सही राजनीतिक हल न निकाल पाना भी हमारा एक नकारात्मक पहलू रहा है। (इस पर एम.सी.सी.आई. की आत्मालोचना देखें)।

3. हम केन्द्रीय कमिटी की पहल से पूरी कतार को पार्टी लाइन तथा अन्य विषयों पर शिक्षित करने के मामले में जो भी कुछ कर पाये हैं, वह जरूरत की तुलना में कम है।

4. हमने अपनी लाइन के अनुसार देहातों के कामकाज में जो भी कुछ सफलताएं हासिल कीं उनकी अपेक्षा शहरों के कामकाज का विकास हम बहुत कम कर पाये।

उपसंहार

लम्बे समय तक के राजनीतिक और संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा करने से यह स्पष्ट है कि सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार लड़ाई व दीर्घकालीन लोकयुद्ध के निर्माण व विकास की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए एकता–संघर्ष–एकता की नीति को अमल में लाकर दृढ़तापूर्वक एक छोटे से ग्रुप से विकसित होकर एक अखिल भारतीय पार्टी के निर्माण में हम सफल हुए । साथ–ही–साथ जनफौज व आधार क्षेत्र के निर्माण की मंजिल में पहुँचने के मामले में भी एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम आ खड़े हुए । यह भी स्पष्ट हुआ कि एक सही लाइन और उस पर डटे रहकर प्रयोग में जाने के क्रम में ही सही क्रांतिकारी व लड़ाकू तत्वों के साथ, चाहे वर्ग संघर्ष के क्षेत्र में हो या राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय की लड़ाई के क्षेत्र में, सच्ची एकता कायम करना संभव है । एक सही लाइन सही व्यवहार से ही स्थापित होती है । एक सही लाइन को स्थापित होने में देर होना स्वीकार्य है बशर्ते कि वह दुरूस्त हो । अब तक की समीक्षा यह बताती है कि एकता के लिए सही लाइन पर अडिग रहना आवश्यक है । एकता के लिए किसी भी कीमत पर लाइन से भटकना क्रांति को तिलांजलि देने के समान है, जबकि सही लाइन पर अडिग रहकर कायम की गई एकता एक मजबूत और चट्टानी एकता होती है ।

घिसेपिटे ढंग से लम्बे समय तक चलना संगठन के गुणात्मक विकास में बाधक होता है । अतएव सृजनशील ढंग से विकास के हर चरण में उचित निर्णय लेना ही गुणात्मक विकास के दौर को आगे बढ़ाता है । सन् 1999 में नेताओं की तस्वीर सजाने संबंधी निर्णय, पी. डब्लू. के साथ सन् 2000 में लिया गया एकतरफा झड़प बन्द करने का निर्णय, ‘माओ विचाराधारा’ के बदले ‘माओवाद’ शब्द का प्रयोग करने संबंधी निर्णय और सच्चे क्रांतिकारियों के साथ एकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी निर्णय आदि बिल्कुल सही समय पर लिये गये सही निर्णय थे । इन निर्णयों ने संगठन के अन्दर व बाहर के सभी अच्छे–बुरे तत्वों में हलचल पैदा कर दी और गलत तत्वों को दरकिनार कर सही तत्वों को गुणात्मक व ऐतिहासिक रूप से छलांग लगाने में मदद पहुँचाई । हमारी पार्टी की सैनिक लाइन का विकास करने में, PLGA की स्थापना में तथा छापामार आधार क्षेत्र के निर्माण की पहल शुरू करने में उक्त निर्णयों ने विद्युत की सी ऊर्जा पैदा कर दी । सबसे

आश्चर्यजनक लाभ संगठन के सही तत्वों के भीतर स्वयं की शक्ति पर भरोसा करने और निर्भरशीलता को तोड़ने के क्षेत्र में हुआ है । आज हमारा संगठन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक खासा महत्व रखता है और जनता की आशा व आकांक्षा का केन्द्र बन गया है । इसके पीछे एकमात्र सही लाइन और सही कार्यपद्धति पर डटे रहना ही मुख्य कारण है ।

कामरेडो, आज की अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थिति को क्रांति में बदल डालने के लिए एक एकताबद्ध अखिल भारतीय पार्टी की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि माओवादी क्रांतिकारियों के बीच की एकता की आकांक्षा भी आज की तरह की तहेदिल की आकांक्षा के बतौर इससे पहले इतने जोरदार ढंग से नहीं दिखाई पड़ी। अतः सच्चे माओवादी क्रांतिकारियों को एकताबद्ध कर तथा एम-एल धारा व एम.सी.सी. धारा को मिलाकर एक महाधारा का सृजन कर एक केन्द्र के अधीन एक एकताबद्ध पार्टी के निर्माण पर सर्वाधिक बल देते हुए ही भारतीय क्रांति के व्यावहारिक कामकाजों यानी, फौज व आधारक्षेत्र का निर्माण करने सहित एक संयुक्त मोर्चा के गठन के कामकाजों को आगे बढ़ाकर ले जाना होगा।

आवें, कामरेड के.सी. सहित भारतीय क्रांति के महान नेता, शिक्षक व अमर शहीदों ने एक मुक्त भारत यानी वर्गहीन-शोषणहीन एक समाजवादी-साम्यवादी भारत का जो सपना देखा था, उसे साकार करने हेतु तमाम कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हुए दिलोजान से वास्तविक कामकाज में लग जाएं। चाहे रास्ता कितना ही टेढ़ा-मेढ़ा व कठिन क्यों न हो, अंतिम जीत हमारी ही होगी।

इनकलाब-जिन्दाबाद !

★ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिन्दाबाद !

★ महान विश्व सर्वहारा क्रांति जिन्दाबाद !

★ भारत की महान नई जनवादी क्रांति जिन्दाबाद !

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

केन्द्रीय कमिटी

भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र

(MCCI)

***

पार्टी इतिहास के कुछेक पहलू

भारत में हमारी दोनों पार्टियों के ऐतिहासिक विलय के फलस्वरूप एकताबद्ध पार्टी के सामने आने के पहले के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास सीपीआई (एम-एल) धारा और एमसीसी धारा – इन दोनों धाराओं के अलग-अलग रूप में लम्बे दिनों तक बने रहने और विकसित होते रहने का इतिहास रहा है। आज के इस महामिलन की ऐतिहासिक घड़ी में दोनों धाराओं के पिछले इतिहास के कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना भी एक ऐतिहासिक कार्यभार है। इस क्रम में हम एमसीसी धारा की ओर से यह दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका एक ऐतिहासिक महत्व हमेशा बना रहेगा।

एम.सी.सी.आई की ओर से प्रस्तुत पार्टी इतिहास के कुछेक पहलू और भारत में एकताबद्ध क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के सवाल पर उसका स्टैण्ड

भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की अग्रगति और क्रांतिकारी संघर्षों के विकास के क्षेत्र में एम.सी.सी.आई. और सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लू.) का एक हो जाना यानी, इन दोनों क्रांतिकारी धाराओं का महामिलन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसका तात्पर्य भी अपरिसीम है। इसके फलस्वरूप क्रांति की जीत की गारंटी के बतौर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के महान आदर्श द्वारा संचालित एक एकताबद्ध अखिल भारतीय पार्टी की मांग पूरी होने जा रही है।

कहना नहीं होगा कि यह एकीकरण एक ऐसे समय में हो रहा है जबकि विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन एक संकट के दौर से गुजर रहा है और उसने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के सामने एक ऐतिहासिक चुनौती पेश की है।

1871 के महान पेरिस कम्युन की पराजय के बाद 1917 के नवम्बर में महान लेनिन-स्तालिन की रहनुमाई वाली बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूस के सर्वहारा वर्ग ने सशस्त्र क्रांति के जरिए बुर्जुआ राज्य-मशीनरी को ध्वस्त कर दुनिया में पहली बार सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता की स्थापना की और समाजवाद का निर्माण किया।

इसके बाद महान माओ-त्सेतुङ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए साम्राज्यवादी-सामंतवादी राज्य-व्यवस्था को ध्वस्त कर नव जनवादी सामाजिक व्यवस्था और समाजवादी राज्य-व्यवस्था का निर्माण किया।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद उत्तर वियतनाम, उत्तर कोरिया, मंगोलिया आदि समेत पूर्वी यूरोप के देशों को लेकर एक विशाल समाजवादी खेमा बन उठा जिसकी आबादी उस समय की दुनिया की कुल आबादी की एक-तिहाई थी।

पर 1953 की 5 मार्च को हुई महान स्तालिन की मृत्यु के तुरंत बाद गद्दार ख्रुश्चेव संशोधनवाद के आविर्भाव के चलते राजनीतिक सत्ता रूस के सर्वहारा वर्ग के हाथों से निकल कर पूंजीपतियों के हाथों में चली गई और इस तरह करीब 36 वर्षों बाद महान नवम्बर क्रांति की पराजय हुई। बाद के काल में दूसरे-दूसरे राज्य भी समाजवाद के रास्ते का परित्याग कर पूंजीवाद की राह पर चल पड़े।

ठीक उसी प्रकार 1976 के 9 सितम्बर को हुई महान माओ-त्सेतुङ की मृत्यु के

बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में घात लगाकर छिपे तेङ–हुआ गुट जैसे पूंजीवाद के राहियों ने सर्वहारा वर्ग के हाथों से राजसत्ता छीन ली और समाजवादी चीन को अध:पतित कर उसे एक पूंजीवादी राज्य में बदल डाला। मौजूदा स्थिति में दुनिया में कहीं भी सर्वहारा वर्ग के हाथों में राजसत्ता नहीं है या कहीं भी समाजवादी व्यवस्था नहीं रह गई है।

विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की ऐसी एक संकटकालीन परिस्थिति में, जब संशोधनवाद ही प्रधान खतरा है, ऐसे एक समय में, विश्व क्रांति और भारतीय क्रांति के हित में इन दोनों क्रांतिकारी पार्टियों के महामिलन ने विश्व साम्राज्यवाद और सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों व संशोधनवादियों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है।

भारत में इन दोनों क्रांतिकारी पार्टियों के उद्भव व विकास की दो स्वतंत्र धाराएं रही हैं। हालांकि इन दोनों स्वतंत्र धाराओं का लक्ष्य व उद्देश्य एक ही था, इसके बावजूद उनके बीच विचारधारात्मक, राजनीतिक और सांगठनिक सवालों पर मतभेद रहने के चलते इतने दिनों तक ये दोनों मिलकर एक महाधारा में रूपांतरित नहीं हो पाई थीं। आज इन दोनों स्वतंत्र धाराओं के बारे में कुछ चर्चा जरूरी है।

भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में शुरू से ही अवसरवाद और संशोधनवाद जड़ जमाए बैठा था और उस संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में तथा भारतवर्ष में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की रोशनी में कृषि क्रांतिकारी राजनीति के उद्भव व विकास के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक पहलू पर चर्चा इन दोनों धाराओं के मिलन की पृष्ठभूमि में अत्यंत ही प्रासंगिक है।

1956 में आयोजित रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस ने गद्दार ख्रुश्चेव द्वारा महान स्तालिन के खिलाफ कुत्सा, दुष्प्रचार व आक्रमण से शुरू करने, फिर उसके तीन जहरीले सिद्धांतों– 'शांतिपूर्ण संक्रमण', 'शांतिपूर्ण प्रतियोगिता' और 'शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व' को सामने लाने तथा उसके बाद 1961 की 22वीं कांग्रेस में 'समग्र जनता का राज्य' और 'समग्र जनता की पार्टी' जैसे सिद्धांतों के जरिए आधुनिक संशोधनवाद का उद्भव हुआ। इन संशोधनवादी सिद्धांतों को केन्द्रित कर समूचे विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में ही एक भारी बहस शुरू हो गई। माओ–त्सेतुङ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता की हिफाजत करने और संशोधनवाद से मार्क्सवाद–लेनिनवाद की रक्षा करने हेतु ख्रुश्चेव संशोधनवाद को बेनकाब करने के लिए खुली बहस में उतर पड़ी। एक के बाद एक नौ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जरिए उसने ख्रुश्चेवी संशोधनवाद के स्तालिन विरोधी दुष्प्रचार और उसके जहरीले खर–पतवारों के असली स्वरूप का पर्दाफाश कर

दिया। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में रूस और चीन के बीच का यह सैद्धांतिक संघर्ष ही 'महान बहस' (Great Debate) के नाम से जाना जाता है। इस महान बहस के प्रभाव से विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में रूसी पार्टी के नेतृत्व में संशोधनवादी धारा और चीनी पार्टी के नेतृत्व में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की क्रांतिकारी धारा के बीच दुनियाव्यापी ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी परिणति महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (GPCR) में हुई। इसने पूरी दुनिया के पैमाने पर एक नये विभाजन को जन्म दिया। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा (अब माओवाद) को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में ग्रहण करते हुए नयी-नयी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों का जन्म होना शुरू हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में संशोधनवाद के खिलाफ विचारधारात्मक, सैद्धांतिक व राजनीतिक संघर्ष को और क्रांतिकारी धारा के उद्‌भव एवं उसके विकास को इस महान बहस और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की धारावाहिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखना होगा। भारत की पार्टी में भी रूस-चीन की महान बहस को केन्द्रित कर दो लाइन का संघर्ष क्रमशः तीव्र होता रहा। 1962 में प्रतिक्रियावादी भारत सरकार द्वारा चीन पर हमला करने के बाद यह बहस और भी तीखी व गहरी हो गई। सोवियत पार्टी ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए चीन को आक्रमणकारी घोषित किया। डांगे के नेतृत्व में एक हिस्से ने जो महान बहस में ख्रुश्चेव की लाइन के पक्ष में था, भारत सरकार का पक्ष लिया। नेतृत्व के एक दूसरे हिस्से के कुछेक लोगों ने (ज्योति बसु, नम्बुदरीपाद आदि ने) चीन-भारत सीमा-संघर्ष के सवाल पर निरपेक्ष रहने का दिखावा करते हुए अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की । नेतृत्व का यह हिस्सा महान बहस के दौरान ख्रुश्चेव संशोधनवाद के खिलाफ कुछ बोलने के बावजूद चीनी पार्टी की लाइन से सभी विषयों पर सहमत नहीं था। इनके अलावा एक और हिस्सा चीन के पक्ष में खड़ा हो गया और उसने यह घोषणा की कि भारत सरकार आक्रमणकारी है। सीमा-संघर्ष को आधार बनाकर भारत सरकार ने डांगे के अनुयाइयों को छोड़कर जिन लोगों ने चीन का समर्थन किया था या भारत को ही आक्रमणकारी घोषित किया था, उन्हें भारत सुरक्षा कानून के तहत थोक भाव में गिरफ्तार कर लिया। इस अग्निगर्भ जैसी परिस्थिति में जेल में बंद नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय क्रांति का रास्ता क्या होगा, संसदीय रास्ता होगा या सशस्त्र संघर्ष का रास्ता, रूसी क्रांति का रास्ता होगा या चीनी क्रांति का रास्ता, रणनीति व कार्यनीति, तेलंगाना के संघर्ष की विफलता के कारण आदि सवालों पर बहस जारी रही। वस्तुतः जेल में ही पार्टी विचारधारात्मक और राजनीतिक सवालों पर एक ओर नेतृत्व के पद पर बैठे लोगों का अधिकांश हिस्सा और दूसरी ओर, नेतृत्वकारी कामरेडों के एक छोटा अंश सहित

लड़ाकू कार्यकर्ताओं का ज्यादातर हिस्सा– इस तरह मोटे तौर पर मुख्यत: दो हिस्सों में विभाजित हो गई।

जेल से निकलने के बाद कुछ कामरेडों ने ख्रुश्चेव संशोधनवाद और डांगेपंथियों का विरोध करने के साथ ही साथ भारतीय क्रांति का लक्ष्य और मार्ग, संघर्ष के रूप व पद्धति आदि पर सवाल उठाया। उन्होंने यह जानना चाहा कि जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तकरीबन एक ही समय गठित हुई, तो क्या कारण है कि चीनी पार्टी ने दीर्घकालीन लोकयुद्ध के दौर से साम्राज्यवाद–सामंतवाद को उखाड़ फेंककर सत्ता दखल कर लिया एवं उसने समाजवाद की स्थापना की और हम इतने पीछे पड़े रह गए? क्या हमारे देश में इससे पहले क्रांतिकारी परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ी? क्या भारतवर्ष के मजदूर–किसानों और मेहनतकश जनता ने देशी–विदेशी शोषण, शासन व उत्पीड़न के खिलाफ बार–बार हथियार नहीं उठाया? क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने असीम वीरता, आत्मत्याग और निष्ठा के ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए? फिर भी भारत की जनता के बहादुराना संघर्ष क्यों बार–बार असफल हुए? क्यों वे विजय के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सके?

इन सारे ज्वलंत सवालों का सामना होने पर तत्कालीन नकली चीनीपंथी नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यापक हिस्से में चीन का समर्थन करने की मानसिकता को भांप लिया और जिन लोगों ने ख्रुश्चेवी लाइन का समर्थन किया था, उन्हें संशोधनवादी करार देते हुए उन कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि वह खुद चीनी पार्टी के पक्ष में है, क्रांति के पक्ष में है। चतुराईपूर्वक वे उपरोक्त सवालों से कन्नी काट गए, पार्टी को संशोधनवाद से अलग कर उसे क्रांति के रास्ते पर लाने के लिए सातवीं कांग्रेस आयोजित करने की रट लगाते रहे और कार्यकर्ताओं को यह समझाते रहे कि कांग्रेस में इन सारे सवालों पर बहस होगी। अंतत: 1964 के नवम्बर में पार्टी की सातवीं कांग्रेस का आह्वान कर उन्होंने पार्टी को तोड़ डाला।

प्रसंगवश यहां उल्लेख करना जरूरी है कि सातवीं कांग्रेस के आयोजन के पहले उसमें पेश किए जाने वाले दस्तावेजों पर कलकत्ता जिला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस जिला सम्मेलन में कामरेड कन्हाई चटर्जी भी प्रतिनिधि थे। कामरेड चटर्जी ने सातवीं कांग्रेस के दस्तावेज को संशोधनवादी करार देते हुए जवाबी दस्तावेज पेश किया। इस दस्तावेज पर जब उस जिला सम्मेलन में मत–विभाजन हुआ, तो उन्हें ग्यारह मत मिले। सातवीं कांग्रेस के इस दस्तावेज को डांगे छाप दस्तावेज के रूप में चिन्हित करते हुए उन्होंने

जो भाषण दिया था, उसके चलते उन्हें विभिन्न रूपों में अपमानित होना पड़ा और उन्हें धमकी दी गई कि उनका पार्टी कार्ड छीन लिया जाएगा।

काफी गाजे-बाजे के साथ सातवीं कांग्रेस के आयोजन के जरिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का गठन किया गया। पर कांग्रेस बुलाने के काफी पहले से ही कार्यकर्तागण जो वक्तव्य रख रहे थे या जो सवाल उठा रहे थे, उन्हें कांग्रेस ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। महान बहस के सवाल पर उन्होंने कोई ठोस स्टैण्ड संबंधी दस्तावेज नहीं दिया। इस तरह उन्होंने मध्यममार्ग अपनाया। वस्तुतः इस कांग्रेस से जो पार्टी गठित हुई वह और भी एक संशोधनवादी पार्टी थी। इसके नेतृत्व पर पूरी तरह संशोधनवादी व अवसरवादी काबिज थे। साथ ही इस कांग्रेस से जो कार्यक्रम गृहीत हुआ उसे मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लेबुल में दक्षिणपंथी और 'वाम' पंथी अवसरवाद तथा ख्रुश्चेवी संशोधनवाद की एक खिचड़ी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह सर से लेकर पैर तक एक संशोधनवादी कार्यक्रम था। इस पार्टी के नेताओं ने यहां तक कि 1962 के चीन-भारत युद्ध के सवाल पर भारत को आक्रमणकारी कहने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वे डांगेपंथियों की तरह ही साम्राज्यवाद व सामंतवाद के वफादार दलालों की भूमिका निभाते रहे।

इस परिस्थिति में पार्टी के अंदर के सच्चे क्रांतिकारी हिस्से ने विद्रोह करना ही न्यायोचित समझा। जेल से निकलने के बाद से कलकत्ता को केन्द्रित कर कामरेड कन्हाई चटर्जी और कामरेड अमूल्य सेन आदि तथा दार्जिलिंग को केन्द्रित कर कामरेड चारू मजूमदार आदि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ एवं पार्टी की संशोधनवादी लाइन के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष संचालित करते आ रहे थे।

कलकत्ता, हावड़ा और हुगली आदि जिलों के कार्यकर्ताओं के बीच कामरेड कन्हाई चटर्जी व कामरेड अमूल्य सेन के नेतृत्व में तथा त्रिपुरा में कामरेड चन्द्रशेखर दास के नेतृत्व में संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़ता रहा। संशोधनवाद के खिलाफ कारगर रूप से और सुसंगठित रूप से विचारधारात्मक संघर्ष संचालित करने के लिए 1964 में सातवीं कांग्रेस की समाप्ति के बाद ही उन्होंने सी.पी.आई.(एम) के भीतर गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी केन्द्र की स्थापना की। इस केन्द्र के नेतृत्व में 1965 की मार्च से "चिन्ता" नामक पत्रिका प्रकाशित होती रही जिसमें संशोधनवाद विरोधी दस्तावेज छपते रहे और वह पत्रिका गुप्त रूप से पार्टी में प्रचारित भी होती रही। 1965 की मार्च से लेकर 1966 के मध्य तक उसके कुल 6 अंक निकले। इसमें प्रकाशित दस्तावेजों में चर्चा के विषय थे:

(क) भारतीय राज्य का वर्ग-चरित्र; (ख) क्रांति के रास्ते के रूप में चीनी क्रांति का रास्ता; (ग)नव औपनिवेशिक शोषण के एक हथियार के बतौर पी.एल. 480 की भूमिका और (घ) सातवीं कांग्रेस का कार्यक्रम एवं संशोधनवादी नेतृत्व का स्वरूप तथा भारतीय क्रांति व किसान समस्या आदि। इन दस्तावेजों को आधार बनाकर पार्टी में बहस छिड़ गई। संशोधनवादी नेतृत्व इससे डर गया। उसने पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी के मुखपत्र– 'देश हितैषी' में अशोक मुखर्जी के नाम से 'संशोधनवाद और संकीर्णतावादी रूझान'– शीर्षक से एक पर एक कई लेखों के जरिए "चिन्ता" में छपे दस्तावेजों पर आक्रमण किया तथा इन दस्तावेजों के वक्तव्यों को विकृत कर उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच प्रचारित किया। इसी प्रकार अंग्रेजी मुखपत्र 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' और हिन्दी मुखपत्र 'स्वाधीनता' के पन्नों में 'चिन्ता' के खिलाफ हमले जारी रहे। इतने सबकुछ के बावजूद पार्टी में बहस व्यापक रूप से फैल गई और पार्टी के बाहर जन संगठनों व समर्थकों के बीच भी बहस शुरू हो गई। स्थिति का मूल्यांकन कर गुप्त रूप से प्रकाशित हो रही 'चिन्ता' को बंद कर दिया गया और उसकी जगह 1966 की जुलाई से 'दक्षिण देश' नामक खुली पत्रिका प्रकाशित होती रही।

पहले "चिन्ता" और बाद में "दक्षिण देश" पत्रिकाओं को केन्द्रित कर जिन सारे कामरेडों ने इस 'राजनीतिक लाइन' का पक्ष लिया, उन्हें एक संगठन में एकताबद्ध किया गया। उस समय वह संगठन 'दक्षिण देश' ग्रुप के नाम से परिचित हुआ।

1966 के अंत में दार्जिलिंग जिले के कुछ कामरेडों से दक्षिण देश ग्रुप का संपर्क हुआ। 1967 की शुरूआत में (नक्सलबाड़ी के संघर्ष से पहले) कामरेड चारू मजूमदार के साथ कामरेड कन्हाई चटर्जी की लम्बी बातचीत हुई। तत्कालीन परिस्थिति में विभिन्न बुनियादी सवालों पर सहमत होने के बावजूद 1967 के आम चुनाव में जंगल संथाल को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कामरेड कन्हाई चटर्जी सहमत नहीं हो सके थे। पर दोनों नेताओं ने ही एक-दूसरे से घनिष्ठता महसूस की थी। एक ओर तो संशोधनवाद के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष को और भी तेज करने तथा दूसरी ओर, अपनी ताकत के मुताबिक किसान क्षेत्रों में कामकाज को आगे बढ़ाने की जरूरत दोनों नेताओं ने ही महसूस की थी तथा एक-दूसरे से घनिष्ठ संपर्क बनाये रखने का निर्णय भी हुआ था।

सच्चाई यह है कि मई, 1967 में भारत में बसंत के बज्रनाद– नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक विद्रोह के पहले से लेकर बाद में 1969 में सी.पी.आई.(एम-एल) के गठन के बाद तक दक्षिण देश ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर,

वर्दवान, वीरभूम और चौबीस परगना आदि जिलों में संगठन खड़ा किया। इसके साथ-साथ इस समय असम व त्रिपुरा में भी संगठन खड़ा किया गया और तत्कालीन बिहार में संपर्क बढ़ाकर कामकाज शुरू करने की पहल ली गई।

जो भी हो, नक्सलबाड़ी के संघर्ष के बाद उसके समर्थन में नक्सलबाड़ी संघर्ष सहायक कमिटी गठित हुई। 1967 के सितम्बर में कामरेड चारू मजूमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी फिर मिले। दूसरे सवालों के साथ-साथ संशोधनवाद का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं की जो भारी संख्या संशोधनवादी पार्टी से विद्रोह कर बाहर आ गई है, उसे असंगठित स्थिति में न छोड़कर उन्हें को-ऑर्डिनेशन में एकताबद्ध करने के सवाल पर दोनों नेता सहमत हुए। इसके बाद 1967 के 12-13 नवम्बर को ['ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज (AICCR) – 'क्रांतिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति'] गठित हुई। इस कमिटी से चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव गृहीत हुए। इसके बाद 1968 की 14 मई को 'ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज (AICCCR) के नाम से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ।

को-ऑर्डिनेशन कमिटी और उसके साथ हमारा संबंध

चीन की पार्टी द्वारा नक्सलबाड़ी के संघर्ष का मजबूती के साथ और बेलाग समर्थन करने तथा सी.पी.एम. के नेतृत्व के बेनकाब हो जाने के चलते अत्यंत स्वाभाविक रूप से समूचे भारतवर्ष में एक राजनीतिक सरगरमी पैदा हुई। क्रांतिकारी सिद्धांत से अच्छी तरह लैस और क्रांतिकारी शैली से गठित एक सचमुच की क्रांतिकारी पार्टी का गठन करने तथा क्रांतिकारी संघर्ष को विकसित करने का एक अभूतपूर्व सुअवसर सामने आ गया।

अत्यंत स्वाभाविक रूप से इस काम में हिरावल भूमिका निभाने के मामले में हमने नक्सलबाड़ी के नेताओं पर पर्याप्त आस्था रखी थी। नक्सलबाड़ी के संघर्ष के तुरंत बाद कामरेड चारू मजूमदार के साथ बातचीत के क्रम में हमने अपना यह मत व्यक्त किया था कि नक्सलबाड़ी आंदोलन के समर्थन में जो लोग आगे आए हैं उन्हें असंगठित स्थिति में छोड़ देने के बजाए एक को-ऑर्डिनेशन में शामिल किया जाय।

पर हमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि नक्सलबाड़ी संघर्ष को केन्द्रित कर जो लोग आगे आए हैं वे सारे के सारे विचारधारा, उसूल, शैली व पद्धति के मामले में समान मत रखते हैं या सभी सच्चे क्रांतिकारी हैं। ठीक यही कारण है कि को-ऑर्डिनेशन कमिटी का गठन करने के पक्ष में अपनी राय जाहिर करने के साथ ही साथ एक सचमुच की क्रांतिकारी पार्टी और क्रांतिकारी संघर्ष का गठन करने के लिए कामकाज की एक सुसंबद्ध

पॉलिसी और कार्यपद्धति का अनुसरण करने की अपरिहार्यता पर हमने बल दिया था। एक क्रांतिकारी नीति व शैली के आधार पर जनसेना व ग्रामीण आधार इलाके का निर्माण करने के दौर से जिन्हें एकताबद्ध किया जा सकता है, उन्हें एकताबद्ध कर यानी, जो लोग कथनी और करनी दोनों में ही क्रांतिकारी हैं, एकमात्र उन्हीं को लेकर एक सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करने के लिए हमने कामकाज की एक सुसंबद्ध पॉलिसी ग्रहण करने पर जोर दिया था।

उस समय जब कामरेड चारू मजूमदार के साथ हमारी बातचीत हुई तो वे और बाकी लोग भी इस लाइन से सहमत थे।

स्वाभाविक रूप से ही को-ऑर्डिनेशन में शामिल हो जाने के बाद हमने को-ऑर्डिनेशन के अंदर और उसके बाहर इसी लाइन का अनुसरण करने की बात रखी।

एक सही नीति और शैली के आधार पर और क्रांतिकारी कामकाज के दौर से सच्चे क्रांतिकारियों के बीच एकता कायम करना तथा अपने स्वतंत्र केन्द्र का विलोप कर क्रमशः खुद भी एक ही केन्द्र के तहत एकताबद्ध हो जाना, ठोस रूप से कहें तो हमारा लक्ष्य यही था। इसी लक्ष्य के साथ हम पश्चिम बंगाल, बिहार व असम में को-ऑर्डिनेशन कमिटी में शामिल हुए। वस्तुतः हमारे सारे कामकाज को-ऑर्डिनेशन के नाम से ही चलते रहे।

स्वाभाविक रूप से ही देहाती क्षेत्रों में संघर्ष का निर्माण करने के मामले में भी, स्वतंत्र पहलकदमी लेने के बजाए हमने ज्यादा बल इसपर दिया कि को-ऑर्डिनेशन ही सुसंबद्ध योजना व पहलकदमी ले और हम अपने कामकाज व पहलकदमी को को-ऑर्डिनेशन की ही उस संभावित पहल से एकरूप कर दें।

पर बिल्कुल ही पुरानी संशोधनवादी पद्धति से को-ऑर्डिनेशन कमिटी का गठन करने के चलते अधिकांश राज्यों में ही मुख्यतः सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व से आए सुपरिचित नीतिभ्रष्ट अवसरवादियों को ही को-ऑर्डिनेशन के ऊंचे स्तर की नेतृत्वकारी कमिटियों में घुसने का मौका मिला। को-ऑर्डिनेशन के नेतृत्व पर काबिज ये मुट्ठीभर अवसरवादी बिल्कुल शुरू से ही उपरोक्त सही कार्यनीतिगत लाइन का विरोध करते रहे।

एक तरफ तो को-ऑर्डिनेशन के नेतृत्व पर काबिज मुट्ठीभर अवसरवादियों के अवसरवादी क्रियाकलाप और दूसरी ओर, उदारतावादियों की समझौतापरस्ती की नीति– इन दोनों के चलते उपरोक्त कार्यनीतिगत लाइन का अनुसरण करना तो दूर की बात रही, यहां तक कि को-ऑर्डिनेशन में लिए गए ढेरों सटीक निर्णयों को भी लागू नहीं किया जा

सका।

जो को-ऑर्डिनेशन कमिटी समूचे भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को एकताबद्ध करने और क्रांतिकारी पार्टी व क्रांतिकारी संघर्ष का निर्माण करने के लिए गठित हुई थी उसी को-ऑर्डिनेशन के नेतृत्व पर काबिज होकर जब अवसरवादीगण इस किस्म के उल्टे-सीधे क्रियाकलाप जारी रखे हुए थे, तब बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की ओर से इसका विरोध होता रहा और क्रमशः यह विरोध और भी तीखा रूप लेता रहा।

इस निरंतर बढ़ते जा रहे विरोध का सामना करने और अपनी गलत नीतियों व तौर-तरीकों को जारी रखने के लिए अवसरवादीगण एक ओर तो को-ऑर्डिनेशन के अंदर ही विभिन्न जगहों में अघोषित ग्रुपों व गुटों में गोलबंद होते रहे और दूसरी ओर, हमारे खिलाफ 'गुटबाजी' करने का आरोप लगाना भी उन्होंने जारी रखा। यहां उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ साथियों की सलाह पर हम एक बार अपने संगठन को तोड़कर को-ऑर्डिनेशन के नेतृत्व में आ जाने और 'दक्षिण देश' पत्रिका को को-ऑर्डिनेशन के हाथों में सौंप देने को राजी हो गए थे। पर हमारी कुछ शर्तें थीं, मसलन एक सही पॉलिसी को मानकर चलना होगा; को-ऑर्डिनेशन की प्रथम घोषणा के अनुसार कार्यक्रम का मसौदा प्रस्तुत करना होगा; देहातों में सशस्त्र संघर्ष का निर्माण करने के लिए खुद की सीमित शक्ति के विन्यास की योजना लेनी होगी और सिर्फ एक आम आह्वान करके इसे स्वयंस्फूर्तता पर छोड़ देने की इजाजत नहीं दी जा सकती; (वस्तुतः यदि ऐसा किया जाता तो दक्षिण और उत्तर भारत में श्रीकाकुलम जैसे और भी संघर्षों का निर्माण किया जा सकता था); को-ऑर्डिनेशन के अंदर आलोचना और आत्मालोचना की पद्धति और केन्द्रीय रूप से विचारधारात्मक संघर्ष संचालित करने की पद्धति को लागू करना होगा; को-ऑर्डिनेशन की पत्रिकाओं के संपादक मंडल में "दक्षिण देश" के संपादक मंडल में से कम से कम एक साथी को शामिल करना होगा या संयुक्त संपादक मंडल का गठन करना होगा; और यदि किसी बुनियादी उसूल के सवाल पर मतभेद दिखाई दें, तो उसे छिपाए रखने या दबा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती बल्कि उसे संगठन के अंदर विचार-विमर्श के लिए जारी करना होगा तथा संगठन में विचार-विमर्श के जरिए जो लाइन गृहीत होगी, उसे सबों को मानकर चलना होगा। पर उन्होंने उस समय इसका कोई जवाब नहीं दिया।

ऐसी एक परिस्थिति में, खासकर जबकि अवसरवादीगण को-ऑर्डिनेशन के अंदर और बाहर संगठित थे और विभिन्न अघोषित गुटों व ग्रुपों में गोलबंद थे तथा सबसे बड़ी

बात, जहां आलोचना व आत्मालोचना और विचारधारात्मक संघर्ष संचालित करने की पद्धति चालू ही नहीं थी, वहां उस वक्त एकतरफा रूप से हमारे संगठन को भंग कर देने एवं "दक्षिण देश" पत्रिका को बंद कर देने का मतलब वस्तुत: अवसरवादियों के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देना ही होता।

इस परिस्थिति में को-ऑर्डिनेशन के नेतृत्व पर काबिज मुट्ठीभर अवसरवादियों ने एक अजीबो-गरीब (पुरानी संशोधनवादी पार्टी से विरासत के रूप में प्राप्त) फूटपरस्त सांगठनिक नीति का सहारा लिया और जिन लोगों ने उनकी अवसरवादी लाइन का विरोध किया, उन सभी को, खासकर "दक्षिण देश" की लाइन के समर्थकों को छांटकर (खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में) को-ऑर्डिनेशन कमिटी को पुनर्गठित करने की लाइन ली।

इसी तरह उदारतावादियों के प्रत्यक्ष व परोक्ष समर्थन से और अवसरवादियों के षड्यंत्रों के चलते ही हमारे साथ को-ऑर्डिनेशन कमिटी का अलगाव हो गया। यह बताना गैरजरूरी है कि तभी से हम एक ओर को-ऑर्डिनेशन के साथ और बाद के काल में सी. पी.आई.(एम-एल) के साथ एकता का दरवाजा खुला रखना, (उनकी सही नीतियों व कार्यों का समर्थन करना, गलत नीतियों और कार्यों का विरोध करना और अवसरवादियों के साथ समझौताहीन संघर्ष जारी रखना) तथा दूसरी ओर एक सही नीति के आधार पर एवं सही लाइन पर काम करने के दौर से उन तमाम लोगों को एकताबद्ध करना जिन्हें कि एकताबद्ध करना संभव है और योजना के मुताबिक काम करने की स्वाधीन पहलकदमी लेना- इन्हीं नीतियों का अनुसरण करते आए हैं।

वस्तुत: इसके पहले तक को-ऑर्डिनेशन से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से योजना के मुताबिक कार्यक्रम लेने पर बल देने का कोई सवाल ही हमारे सामने नहीं था। यह 1968 के अंतिम दिनों की बात है। नक्सलबाड़ी संघर्ष से लेकर उस समय तक के हमारे कामकाज और हमारी सफलता व विफलता, ये सारी चीजें मुख्यत: को-ऑर्डिनेशन के साथ ही हर तरह से जुड़ी रही हैं।

सी.पी.आई.(एम-एल) का गठन और हमारी भूमिका

जो भी हो, को-ऑर्डिनेशन के साथ संबंध-विच्छेद होने के कई माह बाद को-ऑर्डिनेशन के कामकाज का कोई यथार्थपरक मूल्यांकन किए बिना ही अचानक सी. पी.आई.(एम-एल) पार्टी के गठित होने की घोषणा की गई। 1969 की पहली मई को

कलकत्ता के शहीद मैदान की विशाल जनसभा में कानू सन्याल ने घोषणा की कि विगत 22 अप्रील को महान लेनिन के जन्म दिन के अवसर पर भारतवर्ष में एक नई पार्टी सी.पी.आई.(एम-एल) का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इसके बाद भी जो लोग पार्टी के बाहर रहेंगे उन्हें पार्टी-विरोधी शक्ति माना जाएगा।

इतने कुछ के बावजूद, पार्टी के गठन की घोषणा के बाद भी हमने यही आशा बनाए रखी थी कि नव गठित पार्टी का नेतृत्व समूची परिस्थिति की समीक्षा करेगा। हमने तब भी यही चाहा था कि यथार्थपरक समीक्षा और आलोचना-आत्मालोचना के दौर से नये आधार पर नई एकता गठित हो। इसी आकांक्षा के साथ तत्कालीन सी.पी.आई.(एम-एल) के नेतृत्व के पास हमारी ओर से चिट्ठी भी दी गई थी।

पर यहां तक कि शिष्टाचार के नाते भी हमारी चिट्ठी का जवाब देना तो दूर की बात रही, समूची परिस्थिति और को-ऑर्डिनेशन के कामकाज की आत्मालोचनामूलक समीक्षा किए बिना ही को-ऑर्डिनेशन कमिटी की, मुख्यत: अवसरवादियों की प्रभाव वाली, उच्च स्तर की कमिटियों को ही थोक भाव में नवगठित पार्टी की सांगठनिक कमिटी के रूप में स्वीकृति दे दी गई। सांस्कृतिक क्रांति को केन्द्रित कर महान चीन की पार्टी ने 'जाने-माने नीतिभ्रष्टों' को पार्टी में घुसने देने के खिलाफ जो सारी चेतावनियां दी थीं, उनकी शिक्षाओं को साफ ठुकरा दिया गया। इसी के परिणामस्वरूप ऊंचे स्तरों की अधिकांश सांगठनिक कमिटियों में ही अवसरवादियों का प्रभाव और उनकी प्रमुखता बरकरार रही।

साथ ही यह भी सही है कि नव गठित सी.पी.आई.(एम-एल) को एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में मान्यता देने के बाद भी पार्टी का गठन करने की शैली व पद्धति पर उस समय दक्षिण देश ग्रुप ने कुछ आलोचना रखी थी। पार्टी में एकताबद्ध होने की आकांक्षा के साथ अपने ग्रुप को भंग कर देने से पहले मतभेद के बिन्दुओं पर बातचीत करने का आह्वान करते हुए नवगठित सी.पी.आई.(एम-एल) के नेतृत्व के पास चिट्ठी भी भेजी गई थी। पर पार्टी नेतृत्व ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने मौखिक रूप से, ग्रुप तोड़कर पार्टी में शामिल होने को कहा। दक्षिण देश ग्रुप ने इस प्रक्रिया को पार्टी-जनवाद के लिए खतरनाक और आत्मसमर्पण की धमकी के रूप में देखा और सामयिक रूप से उस पार्टी से अलग रहने का निर्णय लिया।

वस्तुत: सी.पी.आई.(एम-एल) के गठित होने के बाद और उनके साथ एकताबद्ध होने की प्रचेष्टा के विफल होने के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के चलते ही हमने 1969

में 20 अक्टूबर को "माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र" के रूप में स्वतंत्र केन्द्र गठित किया। उस समय ऐसा करना ऐतिहासिक रूप से ही अनिवार्य हो गया था। बाद में 1970 में आयोजित सीपीआई (एम-एल) की आठवीं पार्टी-काँग्रेस के समय भी ये स्थितियां जारी रहीं और एकता की हार्दिक आकांक्षा के बावजूद तथा इस पार्टी-काँग्रेस को मान्यता देने के बावजूद हम उस काँग्रेस में एकताबद्ध नहीं हो सके।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता के बारे में

भारत की नव जनवादी क्रांति को सफल करने के लिए निश्चित रूप से सच्चे क्रांतिकारियों को एक ही केन्द्र में एकताबद्ध होना होगा। यह इतिहास की मांग है, क्रांतिकारियों की मांग है और कार्यकर्ताओं व जनता की मांग है।

वस्तुतः 1969 में जब हमने स्वतंत्र रूप से क्रांतिकारी केन्द्र का गठन किया, उसके बाद भी हम अपनी स्वाधीन पहलकदमी से कामकाज को जारी रखने के साथ ही साथ सच्चे क्रांतिकारियों से एकताबद्ध होने की बात कहते आ रहे हैं और इसके लिए प्रयास भी करते आ रहे हैं। पर हमने कभी भी एकताबद्ध होने को मात्र एक आवेग या नारे के रूप में नहीं देखा है। एकताबद्ध होना एक व्यावहारिक मामला है जिसे सिर्फ एक सही प्रक्रिया, पद्धति और हार्दिक कोशिशों के दौर से ही हासिल किया जा सकता है। आज एकताबद्ध होने की विषय-वस्तु महज पुराने सवालों तक ही सीमित नहीं रह सकती। आज की परिस्थिति में जो महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं, वे हैं : (क) आज के युग और माओवाद के बारे में; (ख) आज के दौर की कार्यनीतिक लाइन या रास्ता और कार्यनीतिगत नारे; (ग) संसद व विधानसभा में 'भाग लेने' या उनके 'बहिष्कार' के सवाल पर सही नीति; (घ) संघर्ष के विभिन्न रूपों और पद्धति (कानूनी व गैर-कानूनी, खुले व गुप्त, शांतिपूर्ण व सशस्त्र आदि) के इस्तेमाल के मामले में तथा कार्यनीतिक सवालों पर सही दृष्टिकोण; (ङ)जनआंदोलन और जन संगठन के लक्ष्य, उसके तौर-तरीके या दिशा (orientation); (च) किसान संघर्ष का कार्यक्रम और उसकी पद्धति व कार्यनीति; (छ) संयुक्त मोर्चा के गठन का लक्ष्य और उसकी पद्धति; (ज)प्रचार आंदोलन व उसकी कार्यपद्धति और (झ) नेतृत्व की पद्धति।

पार्टी के कई हिस्सों में विभाजित हो जाने और 'इमर्जेन्सी' के खत्म हो जाने के बाद 1976-77 में सी.पी.आई.(एम-एल) के कुछ ग्रुपों ने हमारे साथ सम्पर्क किया और एकताबद्ध होने की अपील की। हमने भी उनकी अपील पर यथोचित प्रतिक्रिया दिखाई। इसके बाद के दौर में सी.पी.आई.(एम-एल) के करीब सभी छोटे-बड़े ग्रुपों के साथ हमारी

एकता-वार्ता चली।

पर अधिकांश ग्रुपों ने ही एकता-वार्ता को, सिद्धांतों का गुब्बार खड़ा करके, उसे एक किस्म की विलासिता की मजलिस में अध:पतित कर डाला। उन्होंने एक ठोस योजना के तहत इलाके के आधार पर सत्ता दखल के लिए गरीब और भूमिहीन किसानों के बीच लगे रहकर काम करना, इसके लिए कार्यकर्ता नियुक्त करना, शहरी काम को देहाती कार्यों के मातहत और उसके अधीन के रूप में देखना, युद्ध का निर्माण करने के लक्ष्य से जन आंदोलन और जन संगठन के रूपों व पद्धति को निर्धारित करना और नेतृत्व की पद्धति का निर्धारण करना आदि सवालों पर यानी, व्यावहारिक सवालों पर अस्पष्ट व उल्टी-सीधी बातें पेश कीं। उन्होंने एकताबद्ध होने के लिए विरोध के बिन्दुओं को सामने लाने और उन पर आम सहमति बनाने के बदले, जिन सारे सैद्धांतिक सवालों पर मोटे तौर पर सहमति है, सिर्फ उन्हीं पर बल देना जारी रखा और चाहे जैसे भी हो, एकता का निर्माण करने की ओर वे लुढ़कते रहे। एंगेल्स ने इस किस्म की एकता की तुलना उस 'गरम खिचड़ी' से की है जिसके ठंढे होने के साथ ही साथ उसके दाने अलग-अलग पड़े दिखाई देने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके साथ हमारे मतभेद दिखाई पड़े और एकता-वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम के विफल हो गई। उसी समय हमने सी.पी.आई.(एम-एल) (यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन) के साथ घनिष्ठता महसूस की और उनके साथ दोस्ताना संबंध बन उठे और दोनों की सहमति से इलाका विभाजन कर बिहार में अपना-अपना कामकाज आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया था। बाद में 'यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन' ने दूसरे एक ग्रुप के साथ एकताबद्ध होकर सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.यू) के नाम से काम शुरू किया। 1979-80 के करीब पी.यू. से एकता-वार्ता शुरू हुई और कई वर्षों तक बिरादराना संबंध बनाए रखते हुए जारी रही। बाद में कुछ राजनीतिक व सांगठनिक सवालों पर गंभीर मतभेद सामने आने के बाद एकता-वार्ता टूट गई और 1990 से दोनों संगठनों के बीच आपसी संबंध में तनाव व कटुता पैदा होने लगी। बाद में इसने आपसी टकराव का रूप ले लिया।

सी.पी.आई.(एम-एल) (पी.डब्लू.) के साथ एकताबद्ध होने की प्रक्रिया और भारत में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की रोशनी में अखिल भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन

1981 के अक्टूबर में सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लू.) और एम.सी.सी. के बीच

सर्वोच्च प्रतिनिधियों के स्तर पर एकता-वार्ता शुरू हुई। उस समय तत्कालीन दोनों मुख्य नेताओं कामरेड कन्हाई चटर्जी और कोंडापल्ली सीतारमैय्या के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में आठ दिनों तक लम्बी बातचीत चली। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने ही यह स्वीकार किया कि दोनों संगठनों के बीच एकताबद्ध होने का वास्तविक आधार मौजूद है। उस बैठक के तीन-चार माह बाद के.एस. के गिरफ्तार हो जाने के चलते वार्ता बंद रही। बाद में पी.डब्लू. के नेता सत्यमूर्ति के नेतृत्व में वार्ता जारी रही। और फिर के.एस. की रिहाई के बाद पुनः बातचीत शुरू हुई तथा विभिन्न किस्म के क्रियाकलाप जारी रहे। तत्पश्चात पी.डब्लू. की केन्द्रीय कमिटी में संकट दिखाई पड़ा, फलतः एकता-वार्ता बंद रही। संकट की अवधि में पी.डब्लू. की केन्द्रीय कमिटी टूट गई। उसके बाद 1987-88 से के.एस. के नेतृत्व वाली पी.डब्लू. के साथ की एकता-वार्ता के दौरान ढेर सारे राजनीतिक व सांगठनिक सवालों पर एकता बन उठी। नतीजे के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जन संगठनों के क्षेत्र में एकताबद्ध क्रियाकलापों का प्रसार हुआ। 1990 के करीब पार्टी एकता के मामले में नई पार्टी के नाम, पार्टी के मुखपत्र, नेताओं की तस्वीरों का क्रम और पार्टी कांग्रेस के लिए एकताबद्ध दस्तावेजों को तैयार करने जैसे सवालों पर सहमति कायम हुई। हालांकि दोनों संगठन मिलने के करीब तक आ गए थे, पर तभी पी.डब्लू. पार्टी में पुनः संकट दिखाई पड़ा। अतः एकता-वार्ता बंद हो गई। बाद में पी.डब्लू. के नेतृत्व की ओर से के.एस. को उनके पार्टी विरोधी कार्यों के चलते पार्टी से निकाल दिया गया।

तदोपरांत 1992 से कामरेड गणपति के नेतृत्व वाली सी.पी.आई.(एम-एल) (पी. डब्लू.) के साथ पुनः एकता-वार्ता शुरू हुई। संयुक्त क्रियाकलापों के मामले में दोनों संगठनों ने पहलकदमी ली और A3 का गठन हुआ। बाद में बातचीत के क्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सवालों पर गंभीर मतभेद सामने आए। कई बार की बातचीत के जरिए चूंकि दोनों संगठन इन मतभेदों को हल नहीं कर सके, अतः 1995 के मई माह में एकता-वार्ता टूट गई। बाद के काल में एम.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी ने इस एकता-वार्ता और उसमें आए ठहराव की समीक्षा की तथा 2002 की नवम्बर बैठक में सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उस एकता-वार्ता के संबंध में निर्णय लेते समय हमने पर्याप्त धैर्य नहीं बरता था और जल्दीबाजी के शिकार हुए थे। निश्चित रूप से उस समय की उस टूट का देश की और बाहर की क्रांतिकारी शक्तियों व जनता पर कुछ-न-कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। बाद में सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लू.) और सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.यू.) के बीच एकता-वार्ता शुरू हुई और 1998 में दोनों पार्टियां एक हो गईं।

पी.डब्लू. और पी.यू. के बीच एकता होने के बाद नव गठित पी.डब्लू. के साथ भी यह टकराव जारी रहा। भारतीय क्रांति का यह एक काला अध्याय था। दोनों संगठन इसे नियंत्रित करने में विफल रहे, फलतः टकरावों की यह परिस्थिति जारी रही। अंततः 7 जनवरी, 2000 को एम.सी.सी. ने एकतरफा रूप से इस टकराव को बंद करने की घोषणा की और पी.डब्लू. ने भी यथोचित प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि इसमें RIM व अन्यान्य बिरादराना संगठनों की भी एक भूमिका रही। दोनों ही पार्टियों ने एक के बाद एक की गई कई बैठकों के जरिए इसकी पद्धति व इसका तौर-तरीका निर्धारित किया कि कैसे अब टकरावों को नहीं होने दिया जाए। धीरे-धीरे परिस्थिति स्वाभाविक होती चली गई और पुनः बिरादराना संबंध कायम हुए। इस नई परिस्थिति में एम.सी.सी. ने पुनः एकता-वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया और पी.डब्लू. के नेतृत्व ने उसे सादर स्वीकार किया।

अंततः पिछले 2003 की फरवरी में दोनों पार्टियों के सचिवों की उपस्थिति में केन्द्रीय स्तर के उच्चतर प्रतिनिधिमंडलों के बीच एकता-वार्ता शुरू हुई। अत्यंत हार्दिक और गरमजोशी से भरे-पूरे क्रांतिकारी माहौल में लगातार दस दिनों तक वार्ता चलती रही। दोनों पार्टियां ही अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय और सांगठनिक सवालों सहित अन्यान्य सवालों पर अपने बीच के मतभेदों का काफी हद तक समाधान कर परस्पर सहमति पर पहुंची।

पिछले कई वर्षों से जो तीखा टकराव चल रहा है और जिसके चलते अच्छे-खासे बेशकीमती कामरेडों ने अपनी जान गंवाई है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिसके चलते भारतीय क्रांति को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके लिए दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने गहरी वेदना का इजहार किया और तीखी, गहरी व हार्दिक आत्मालोचना की। इस गहरी अनुभूति और परस्पर आस्था व विश्वास से भरपूर माहौल में दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने, पुनः जिससे कि ऐसी परिस्थिति का उद्‌भव नहीं हो, इसके लिए क्रांतिकारी शपथ ग्रहण किया।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के आदर्श और सर्वहारा लाइन की विजय की इस बेला में आज भारत के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन में बहु आकांक्षित क्रांतिकारियों के बीच की एकता की संभावना और एक अखिल भारतीय एकताबद्ध पार्टी का निर्माण मुहाने पर आ पहुंचा है। देश और दुनिया के क्रांतिकारियों की तथा हमारे वर्ग और व्यापक जनता की जो मांग थी उसे पूरा करने के मामले में दोनों पार्टियां दृढ़ संकल्पित हैं और इससे आनन्दित भी। ठीक उसी प्रकार साम्राज्यवाद-सामंतवाद, संशोधनवाद और समूचा प्रतिक्रियावादी व प्रतिक्रांतिकारी खेमा भी इस मिलन की प्रक्रिया से आतंकित है।

भारतीय क्रांति के हित में दोनों पार्टियों द्वारा संकीर्णतावादी, कठमुल्लावादी, व्यक्तिवादी, दादासुलभ दृष्टिकोण और ग्रुप मानसिकता आदि को पराजित करने और सर्वहारा लाइन की जीत के चलते एकताबद्ध पार्टी के निर्माण की जो मिसाल कायम हुई है उसका प्रभाव काफी दूरगामी होगा। महान नक्सलबाड़ी आंदोलन की इस युगसंधि बेला में दो स्वतंत्र रूप से सामने आई व विकसित हुई क्रांतिकारी धाराओं का वास्तविक अस्तित्व आज इस महामिलन के दौर से जिस नई क्रांतिकारी महाधारा का सृजन करने जा रहा है, वह महाधारा निश्चित रूप से महान शहीद साथियों के सपनों को साकार करने के कर्तव्यों को पूरा करेगी और भारत की छाती से साम्राज्यवाद, सामंतवाद और संशोधनवाद का नामोनिशान मिटा देगी। यह एकताबद्ध पार्टी नये सूर्य की रोशनी से जगमगा उठेगी और एक नये भारत की रचना करेगी इतना तो तय है।

* * *

पूर्ववर्ती सीपीआई (एमएल) [पीडब्ल्यू] की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा

हमारे देश में माओवादी आन्दोलन पिछले साढ़े तीन दशकों से चला आ रहा है। इस प्रक्रिया में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्धमार्क्सवादी-लेनिनवादीऋ घुमावदार रास्तों से होकर गुजरी है, जिस दौरान शोषण-मुक्त समाज की रचना करने के महान लक्ष्य के खातिर हजारों लोग शहीद हुए। इस दौरान पार्टी ने टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता तय किया है। बड़ी-बड़ी जीतें हासिल की हैं और गम्भीर सामयिक पराजय भी। यह पार्टी मौत तक को चुनौती देने वाली कुर्बानियों की भी गवाह रही है। फ़िर भी इस लम्बे अन्तराल में पार्टी ने सार्थक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। 35 सालों से अधिक इस अन्तराल में पार्टी ने राज्य के नृशंस दमन का डटकर मुकाबला किया और अब लाखों की तादाद में जनता इसके प्रभाव में है। 1972 में गम्भीर सामयिक पराजय का सामना करने के बावजूद पार्टी पूरे आन्दोलन को भटकाने का प्रयास करने वाले दक्षिणपंथी तथा वामपंथी, प्रधानतः दक्षिणपंथी-अवसरवादी रुझानों से लोहा लेते हुए, और साथ ही पहले के दौर की वामपंथी भूलों को सुधारते हुए दोबारा खड़ी होकर आगे बढ़ने में कामयाब हो पायी है। इस पूरे दौर में पार्टी ने अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में आधुनिक संशोधनवाद के खिलफ़ चले विश्वव्यापी संघर्ष के

हिस्से के रूप में हमारे देश में आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बड़ी अहम् भूमिका अदा की है। यही आधुनिक संशोधनवाद दुनिया के पैमाने पर साम्यवाद के सामने मुख्य विचारधारात्मक खतरा रहा है। हमारे देश-समाज के सर्वोत्कृष्ट इन्सानों के खून से रंगे, आत्मोत्सर्ग तक के लिए सबसे ज्यादा समर्पित तमाम कामरेडों के खून से रंगे माओवाद के लाल झण्डे को पार्टी ने भारत भूमि पर लहराये रखा है।

देश में क्रान्तिकारी आन्दोलन के दौरान और विकास के साथ-साथ पार्टी ने जनता की हथियारबन्द छापामार शक्तियों को खड़ा किया। भारतीय क्रान्ति के इतिहास में पहली बार व्यवस्थित रूप से जनता की फौज खड़ी की गयी और इसे पीजीए अर्थात् जन छापामार सेना के रूप में आकार दिया गया। इतने लम्बे समय, दो दशकों से भी ज्यादा समय से प्रतिक्रियावादी भारतीय राजकीय बलों के साथ इस कदर सशस्त्र संघर्ष लड़ने वाले, वह भी आधार इलाके स्थापित करने के मकसद से सशस्त्र कृषि क्रान्ति को आगे बढ़ाने वाले, जनता के सशस्त्र बल हमारे देश के इतिहास में पहले कभी न देखे गये थे। इसी प्रक्रिया में पार्टी भी सुदृढ़ होती चली गयी।

इसी के साथ हमने अपने आंदोलन की उपलब्धियों का सुदृढ़ीकरण किया और इसका उन नये इलाकों तक विस्तार किया जहाँ के लोगों के लिए स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी भी एक नयी चीज थी। साथ ही, हमने देश के अनेक हिस्सों में क्रान्तिकारी जन संगठन तेयार किये और इससे पार्टी का जनाधार और गहराता गया।

माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसी) का इतिहास भी इसी तरह का रहा है और अब भारतीय क्रान्ति की इन दो प्रमुख धाराओं का विलय हो जाने पर अब एक वेगवान नदी तैयार हुई है जिसकी प्रचण्ड लहरें सारे दुश्मनों को नष्ट कर डालेंगी। इस तरह समाजवाद और साम्यवाद की लम्बी यात्रा के पहले मुकाम, यानी नयी जनवादी क्रान्ति को हासिल करने में कामयाबी मिल सकेगी। हमारे देश का आकार, जनसंख्या, संश्लिष्टता, और दुनिया में इसका भू-राजनीतिक स्थान ऐसा है कि भारत की जनवादी क्रान्ति की सफलता साम्राज्यवाद की जंजीर को इतनी बुरी तरह कमजोर कर देगी कि शक्ति-सन्तुलन केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बदलेगा।

इसी जिम्मेदारी के एहसास के साथ और आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम हाल तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), अर्थात् सीपीआई (एमएल) पीपुल्स वार, के पूरे दौर की राजनीतिक एवं सांगठनिक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

विहंगम्-दृष्टि

पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले 1960 के उस तूफ़ानी दशक में भारत के सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुंग विचारधारा से प्रेरणा लेकर अपने आन्दोलन में जड़ जमाये संशोधनवाद के खिलाफ़ संघर्ष शुरू कर दिया। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में यह शुरुआत उस 'महान बहस' से हुई थी जिसे ख्रुश्चेवी आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में पहल करते हुए आगे बढ़ायी थी।

इसी सन्दर्भ में अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के अनेक अनूठे व अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ-साथ कामरेड चारू मजुमदार (सीएम) और कन्हाई चटर्जी (केसी) जैसी कई सच्ची व अडिग कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तियाँ संशोधनवाद के खिलाफ़ मैदान में उतर आयीं। 1964 में आयोजित माकपा की 7वीं काँग्रेस में यही संघर्ष दो परस्पर विपरीत रास्तों - संसदवाद के रास्ते और दीर्घकालीन लोक युद्ध के रास्ते के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के झंझावती घटनाक्रम ने भारत की राजनीतिक फ़िज़ा को और ज्यादा गरमा दिया। कामरेड सीएम के नेतृत्व में महान नक्सलबाड़ी का जो बिगुल बजा वह सचमुच "भारत पर बसन्त का वज्रनाद" साबित हुआ, जैसा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने काव्यात्मक रूप में उसकी तस्वीर खड़ी की। इसने एकदम-से भाकपा, माकपा किस्म के संशोधनवादी नेतृत्व के कुरूप चेहरे का नकाब उतार फेंका। "चीन का रास्ता हमारा रास्ता" और "माओ त्से-तुंग विचारधारा हमारी विचारधारा" जैसे सशक्त नारों की गूँज भारत के कोने-कोने तक और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों तक पहुँची। नक्सलबाड़ी ने इस तरह भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में काफ़ी लम्बे समय से चले आ रहे संशोधनवाद के साथ गुणात्मक विच्छेद कर दिया और भारत में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुंग विचारधारा को मजबूती से स्थापित कर दिया। तभी से माओ त्से-तुंग विचारधारा भारत में संशोधनवादियों और सच्चे क्रान्तिकारियों के बीच विभाजन रेखा बन गयी। अतः "नक्सलबाड़ी का रास्ता भारतीय क्रान्ति का एकमात्र रास्ता" सदा गूँजते रहने वाला नारा बन गया। इस आन्दोलन ने मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और बुद्धिजीवियों के बीच से निकली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों की एकदम नयी पीढ़ी को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की ओर प्रेरित व आकर्षित किया। (इसे हम पहले मार्क्सवाद-लेनिनवाद माओ त्से-तुंग विचारधारा या मा-ले-मा विचारधारा कहते थे। अब से हम इसे मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद या मा-ले-मा कहेंगे।)

पूँजीवाद की पुनर्स्थापना के बाद सोवियत संघ सामाजिक-साम्राज्यवादी देश व नयी महाशक्ति बना, और इसने संयुक्त राज्य अमरीका की ताकत को चुनौती दी। दुनिया का कम्युनिस्ट आन्छोलन अब दो खेमों में बँट गया। ज्यादातर पार्टियाँ सोवियत आधुनिक संशोधनवादियों के पाले में जा खड़ी हुईं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ के नेतृत्व में इस नये प्रति-क्रान्तिकारी केन्द्र को चुनौती दी। इससे दुनियाभर की सभी सच्ची क्रान्तिकारी शक्तियों का विचारधारात्मक एवं राजनतिक ध्रुवीकरण हो गया। खासकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के देशों में ये शक्तियाँ चीन-पक्षधर खेमे में चली आयीं। इसी दौरान वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन ने महाशक्ति अमरीका पर जबरदस्त प्रहार करते हुए दुनिया की तमाम साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों को उद्वेलित किया। एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में चारों ओर राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का ज्वार आया।

1960 के दशक में महान बहस से लेकर महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति तक के उथल-पुथल के दौर में समूचे विश्व की मार्क्सवादी-लेनिनवादी शक्तियों के बीच नया ध्रुवीकरण हुआ। मार्क्सवाद- लेनिनवाद-माओवाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा मानने वाली नयी-नयी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों का उदय हुआ।

1967 में नक्सलबाड़ी में छिड़ी सशस्त्र किसान क्रान्ति ने भारतीय जनवादी क्रान्ति के इतिहास को एक बड़ा ही निर्णायक मोड़ दिया। 1951 के बाद तेलंगाना में संशोधनवादी नेतृत्व के विश्वासघात के बाद नक्सलबाड़ी ने भारत की सशस्त्र किसान क्रान्ति में सचमुच एक निर्णायक मोड़ ला दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्धमार्क्सवादी-लेनिनवादीत्र्क को यह गौरव प्राप्त होता है कि इसने सशस्त्र किसान क्रान्ति की शुरुआत की और पुनपरा-वायलार, तेभागा ओर तेलंगाना के बहादुराना सशस्त्र किसान संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाया। नक्सलबाड़ी का संघर्ष तेलंगाना के महान सशस्त्र किसान संघर्ष से आगे बढ़कर लगायी गयी छलांग थी, क्योंकि यह जड़ जमाये संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ़ तीखे विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्ष तथा विद्रोह का परिणाम भी था।

मार्क्सवादी-लेनिनवाद-माओवाद के मार्गदर्शन में नक्सलबाड़ी में छिड़ा सशस्त्र किसान क्रान्तिकारी संघर्ष भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को कैंसर की तरह पीड़ित करने वाले संशोधनवाद के खिलाफ़ पहला गम्भीर प्रहार था। यही वजह है कि एक साथ संशोधनवादी व काँग्रेसी शासक इस सशस्त्र किसान क्रान्ति को खून की नदियों में डुबोने के इरादे से कूद पड़े। इस किसान क्रान्ति ने जहाँ देशभर में पूरी नयी पीढ़ी को प्रेरणा दी, वहीं इसने शासक वर्गों की नींद भी उड़ा दी। नक्सलबाड़ी की चिंगारियाँ देश के

कोने-कोने तक पहुँची - श्रीकाकुलम, मुसहरी, देबरा, गोपीवल्लभपुर, लखीमपुर-खिरी और बीरभूम तक। हजारों शहीदों ने अपना जीवन क्रान्ति के लिए अर्पित किया। भारतीय समाज के हीरे-नगीने यही रहे।

हालांकि बाद में क्रान्तिकारी आन्दोलन को सामयिक पराजय का सामना करना पड़ा, फिर भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की चमकती लाल पताका और नक्सलबाड़ी की लपटें देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी रोशनी बिखेरती रहीं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के बीज अब विशाल भारत भूमि में जम गये थे। दक्षिणपंथी अवसरवाद और वामपंथी भटकावों से जूझते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन ने दोबारा ताकत अर्जित कर ली। 1972 के पैमानों को काफी पीछे छोड़ते हुए यह अब बहुत आगे तक विकास करता गया। दुश्मन की गोलियाँ अपने सीने में खाने वाले बहादुर साथियों की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं गयीं। दुश्मन के दमनकारी युद्ध को करारा जवाब दिया गया और आन्दोलन उत्तरोत्तर ऊँचे स्तरों तक पहुँचने लगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) अर्थात् सीपीआई (एमएल) और इसकी क्रान्तिकारी विरासत को आगे बढ़ाने वाली दो पार्टियों सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) और सीपीआई (एमएल) (पीयू) के उदय एवं विकास का इतिहास इसी तूफानी दौर के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पिछले 35 सालों में हमने न केवल मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल झण्डे को लगातार ऊँचा उठाये रखा है, बल्कि हमने अपने क्रान्तिकारी व्यवहार के दौरान भारत की ठोस परिस्थितियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद को लगातार अमल में भी उतारा है। अपने व्यवहार के दौरान हमने आन्दोलन के सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभवों का मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के आधार पर विश्लेषण तथा संश्लेषण करते हुए क्रान्तिकारी कार्यदिशा (लाइन) को ढाला तथा विकसित किया है। इस रोशनी में हमने किसान जता को, खासकर गरब व भूमिहीन किसानों को गोलबन्द करते हुए व उन पर भरोसा करते हुए देहाती क्षेत्र में खेतिहर क्रान्तिकारी छापामार युद्ध को विकसित किया, और इस प्रकार दीर्घकालीन लोक युद्ध को जारी रखने, विकसित करने में अनेक शानदार सफलताएँ हासिल की हैं। हमने प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा साम्राज्यवाद के समर्थन से छेड़े गये अनेक दमनकारी अभियानों और अनवरत घोर दमन का प्रतिरोध करते हुए अपने संघर्ष को लगातार जारी रखा है।

जन युद्ध को आगे बढ़ाने और जन सेना खड़ी करने व आधार इलाके स्थापित करने की लाइन को लागू करने के दौरान ही नक्सलबाड़ी तथा सीपीआई (एमएल) की

विरासत को आगे बढ़ाने वाली दो पार्टियों सीपीआई द्धएमएलत्रः द्धपीडब्ल्यूत्रः और सीपीआई द्धएमएलत्रः द्धपीयूत्रः का अगस्त 1998 में एकीकृत सीपीआई द्धएमएलत्रः द्धपीडब्ल्यूत्रः में विलय हो गया। ये दोनों पार्टियाँ 22 अप्रैल, 1969 को गठित सीपीआई द्धएमएलत्रः का अंग रह चुकी हैं। इन दोनों ने एकीकृत सीपीआई द्धएमएलत्रः पार्टी की 8वीं काँग्रेस अर्थात् सीपीआई द्धएमएलत्रः के रूप में भारत की पुनर्गठित क्रान्तिकारी सर्वहारा पार्टी की पहली काँग्रेस द्वारा पारित क्रान्तिकारी लाइन को आगे बढ़ाया है। दोनों पार्टियों ने आठवीं काँग्रेस के पार्टी कार्यक्रम एवं पार्टी संविधान को अपनाया और नक्सलबाड़ी किसान जनउभार के बाद से सीपीआई द्धएमएलत्रः के अनुभवों का सार-संकलन किया तथा अतीत के इन्हीं अनुभवों के संश्लेषण से निकलीं शिक्षाओं के आधार पर अपने पूरे-के-पूरे क्रान्तिकारी व्यवहार को आगे जारी रखा।

एकीकृत पीपुल्स वार पार्टी अपनी जन सेना को छापामार सेना पीजीए के रूप में तथा छापामार ज़ोन विकसित करने में सफ़ल रही, जिनकी दिशा आन्ध्र, झारखण्ड, बिहार, दण्डकारण्य व उड़ीसा के विस्तृत देहाती क्षेत्रें में एक परिपूर्ण पीएलए तथा आधार इलाके स्थापित करने की है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में चलाये जा रहे इस दीर्घकालीन लोक यु) का लक्ष्य देहाती क्षेत्रें से शहरों को घेरने की रणनीति के जरिये कृषि क्रान्ति की धुरी पर नयी जनवादी क्रान्ति को सम्पूा करने का है। हमारे गौरवशाली क्रान्तिकारी इतिहास के बीते हुए 35 वर्षों के प्रस्तुत सार-संकलन को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

साढ़े तीन दशकों के इस अन्तराल में हमारी पार्टी तथा अन्य माओवादी संगठनों के हजारों कामरेडों ने देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के दौरान अपने प्राणों की आहूति दी है। इनमें इन पार्टियों के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बहुत सारे बु()जीवी भी शामिल रहे हैं। दुश्मन के तीखे आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन अब आधार इलाकों के विकास की ओर विकसित हो रहा है। इसने देश में पहली बार जन छापामार सेना और क्रान्तिकारी जनता की राजनीतिक सत्ता, अर्थात् स्थानीय स्तर पर नयी जनवादी सरकार का भ्रूण रूप स्थापित किया। इसी प्रक्रिया में पार्टी स्वयं भी विकसित हुई। देश के माओवादी क्रान्तिकारियों में एकता लाने के लगातार प्रयास करते हुए पार्टी ने इसमें खासकर दो प्रमुख सीपीआई द्धएमएलत्रः पार्टियों के विलय से सार्थक सफ़लता हासिल की। इसने अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर विभिूा माओवादी पार्टियों के बीच करीबी रिश्ते स्थापित करने में भी सकारात्मक भूमिका अदा की।

1970 की काँग्रेस के बाद तमाम निर्णायक मोड़ों पर हमने अन्तरराष्ट्रीय एवं देश की परिस्थिति पर चर्चा करने तथा आन्दोलन की समीक्षा करने व व्यवहार के दौरान उभरी

समस्याओं का समाधान करने और अपनी नीतियाँ, कार्यनीति एवं योजनाएँ सूत्रब) करने के लिए तथा पूरी पार्टी को इन्हें अपनी लाइन के अनुरूप लागू करने को प्रेरित करने के लिए प्लेनम और सम्मेलन आयोजित किये। इन सम्मेलनों तथा प्लेनमों ने इन महत्वपूर्ण मोड़ों पर अतीत के व्यवहार का विश्लेषण करने और अपनी उपलब्धियों एवं खामियों से सबक लेने के प्रयास के तहत राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षाएँ भी सामने लायी हैं। सन् 2001 में नौवीं काँग्रेस में पारित पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों के रूप में पार्टी की राजनीतिक-सामरिक लाइन की दृढ़तापूर्वक रक्षा करना तथा उसे समृ) करना इसी प्रक्रिया की परिणति रही।

इस पूरे काल में पार्टी ने लेनिन के इस कथन के आधार पर आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की मार्क्सवादी-लेनिनवादी प)ति को अपनाने पर जोर दिया कि -

ह्कोई पार्टी कितनी सच्ची है और अपने वर्ग तथा मेहनतकश जनता के प्रति अपनी प्रतिब)ता को व्यवहार में किस तरह अमल करती है यह तय करने का सबसे महत्वपूर्ण व यकीनी तरीका है, उसका अपनी गलतियों के प्रति रवैया देखना। एक गम्भीर पार्टी का लक्षण है - गलती को खुले मन से स्वीकार करना, इसके कारणों का पता लगाना, इसे जन्म देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करना और इसे सुधारने के तरीकों पर रेशा-रेखा चर्चा करना। पार्टी को इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, इसी तरीके से वर्ग और फि़र आम जनता को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए।ह

प्रस्तुत राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा हमारी पार्टी के उदय और विकास को, भारत के दीर्घकालीन लोक यु) के प्रमुख निर्णायक मोड़ों को, आन्दोलन के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को और साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा समय के समृ) अनुभवों से निकली शिक्षाओं को रेखांकित करती है। इस प्रकार यह राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा एक ओर पुनर्गठित सीपीआई द्धएमएलऋ के अनुभवों और दूसरी ओर, विलय से पूर्व लम्बे समय तक अलग-अलग अस्तित्व कायम रख चुकीं दो पार्टियों पीयू व पीडब्ल्यू तथा एकीकृत सीपीआई द्धएमएलऋ द्धपीडब्ल्यूऋ के अनुभवों का संश्लेषण करती है।

पिछले साढ़े तीन दशकों में हमारी पार्टी पाँच दौरों से होकर गुजरी है। ये दौर आन्दोलन में किसी-न-किसी निर्णायक मोड़ तक के हैं। विभिा दौरों में इस तरह के विभाजन से हम यह बेहतर समझ सकते हैं कि हमने भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक निर्णायक मोड़ पर अपने व्यवहार की खामियों का विश्लेषण कैसे किया और अपनी लाइन को किस प्रकार समृ) किया। इन पाँच दौरों को मोटे तौर

पर इस तरह बाँटा गया है –

द्ध1ऋ 1964–67 : महान शुरुआत – देश में नयी जनवादी क्रान्ति के नये उभार के लिए विचारधारात्मक एवं राजनीतिक तैयारियों का दौर।

द्ध2ऋ 1967–72 : व्यापक सशस्त्र जन उभार और पार्टी का गठन।

द्ध3ऋ 1972–77 : 1972 के बाद की सामयिक पराजय, नये व्यापक जनउभार के लिए सार–संकलन और तैयारियाँ।

द्ध4ऋ 1977 – मार्च 2001 : जन यु) का फ़िर से उभरना और फ़ैलना।

द्ध5ऋ 2001 के बाद : देश में आधार इलाकों को खड़ा करने के कार्यभार को लेकर छापामार यु) को तीव्र करने और एकीकृत क्रान्तिकारी सर्वहारा पार्टी के गठन की प्रक्रिया।

भाग–1

अध्याय–1

महान शुरुआत : 1964–67

अप्रैल 1969 में हमारी पार्टी सीपीआई द्धएमएलऋ के गठन से लेकर अब तक के 35 वर्षों के अनुभवों का सार–संकलन करने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि पर सरसरी निगाह डालनी चाहिए। आइये, यह देखें कि पार्टी का पुनर्गठन तथा आठवीं काँग्रेस किस पृष्ठभूमि में आयोजित हुई, उस वक्त की घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय स्थितियाँ क्या रहीं और तब से लेकर आज तक मार्क्सवादी–लेनिनवादी खेमे में आने वाले अहम् परिवर्तन क्या रहे हैं ?

हमारे देश के सच्चे मार्क्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारियों ने 1950 के दशकों तथा 1960 के दशकों की शुरुआत में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा में जड़ जमाये संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ़ अविराम आन्तरिक पार्टी संघर्ष चलाया था। बाद में यह संघर्ष भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्धमार्क्सवादीऋ माकपा के भीतर उसके नव–संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ़ जारी रहा। बहुत सारे देशों में सच्चे क्रान्तिकारियों ने, खासकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कामरेड माओ के मार्गदर्शन में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फ़ैलाये गये अन्तरराष्ट्रीय संशोधनवाद, खासकर आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ़ समझौताविहीन संघर्ष चलाया। चीन में दक्षिणपंथी अवसरवादियों के पूँजीवाद की पुनर्स्थापना करने के प्रयासों को किल करने के लिए 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' छेड़ दी गयी। इसी पृष्ठभूमि में भारत

की उत्पीड़ित जनता को मुक्ति का सच्चा रास्ता दिखानेवाला नक्सलबाड़ी सशस्त्र संघर्ष उभर आया।

आइये, उस घटनाक्रम को संक्षेप में याद करें।

कामरेड सीएम के आठ दस्तावेजों ने नयी क्रान्तिकारी लाइन का विचाराधात्मक-राजनीतिक आधार तैयार किया

जनवरी 1965 से 1967 के बीच प्रकाशित हुए कामरेड चारू मजुमदार के ऐतिहासिक आठ दस्तावेजों ने भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के भीतर की क्रान्तिकारी धारा के संशोधनवाद के साथ गुणात्मक विच्छेद का विचारधारात्मक-राजनीतिक आधार तैयार किया और महान नक्सलबाड़ी जनउभार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये दस्तावेज भारत की ठोस स्थितियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुंग विचारधारा का सृजनात्मक अमली रूप थे। ये इस अर्थ में ऐतिहासिक हैं कि इनसे संसदीय जड़वामनता से दूर हटना ौरन शुरू हो गया और अब तक भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में जड़ जमाये संशोधनवाद से दो-हाथ करते हुए पूरी शिद्दत के साथ क्रान्तिकारी राजनीति प्रस्तुत हुई थी। इन दस्तावेजों के कुछ प्रमुख बिन्दुओं के संक्षिप्त विवरण से यह तीखा संघर्ष और नयी पार्टी का आधार तैयार किया जाना सा दिखायी देता है।

पहला दस्तावेज तो की पहले, जनवरी 1965 में आया था। शीर्षक था - **ह्वर्तमान स्थिति में हमारे कार्यभार।ह** इसमें उन्होंने गुप्त संगठन की आवश्यकता और किसान जनता को बहादुराना तरीके से जागृत करते हुए कृषि क्रान्ति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

िर अगस्त 1966 के एक और लेख में कामरेड सीएम ने बताया कि **ह्यह पार्टी नेतृत्व भारत में जनवादी क्रान्ति का दायित्व उठाने से इन्कार कर रहा है और ालस्वरूप आधुनिक संशोधनवाद की शातिराना कार्यनीति अपना रहा है। अर्थात्, यह शब्दों में क्रान्तिकारी होना और कार्यों में पूँजीपति वर्गों का दुमछल्ला होना है। ...... वर्तमान पार्टी व्यवस्था और इसके जनवादी ढाँचे को तोड़ कर ही अब क्रान्तिकारी पार्टी उबर सकती है। इसलिए इस पार्टी के तथाकथित 'रूप' या 'संवैधानिक ढाँचे' का पालन करना मार्क्सवादी-लेनिनवादियों को निष्प्रभावी बना देगा और उन्हें संशोधनवादी नेतृत्व के साथ सहयोग करने को बाध्य करेगा।ह**

आगे उन्होंने यह कहा कि **ह्क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के सामने मुख्य कार्यभार**

कानूनी ट्रेड यूनियन या किसान सभा आन्दोलन का नेतृत्व करना कभी नहीं हो सकता। क्रान्तिकारी ऊान के आज के युग में ट्रेड यूनियन या किसान सभा आन्दोलन मुख्य परिपूरक शक्ति नहीं हो सकती। इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि ट्रेड यूनियन या किसान सभाएँ पुरानी पड़ चुकी हैं। ट्रेड यूनियन और किसान सभाएँ मूलतः मार्क्सवादी–लेनिनवादी कार्यकर्ताओं और मजदूर वर्ग तथा किसान जनता के बीच एकता तैयार करने के लिए संगठन होते हैं। यह एकता तभी सुदृढ़ होगी जब मार्क्सवादी–लेनिनवादी कार्यकर्ता क्रान्तिकारी प्रतिरोध आन्दोलन की कार्यनीति अपनाकर मजदूर वर्ग एवं किसान जनता के बीच क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने के काम में आगे बढ़ेंगे। क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग एवं मार्क्सवादी–लेनिनवादी कार्यकर्ताओं को किसान संघर्षों की सूरत में प्रतिरोध अथवा 'छापामार' संघर्षों के जरिये किसान संघर्षों को सक्रिय नेतृत्व देना होगा।ह

'इस अवसर को उठाओ' शीर्षक एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा है कि –

हवर्तमान युग मे हमारा मुख्य कार्यभार तीन मुख्य नारों पर आधारित होगा।

पहले, मजदूरों एवं किसानों की एकता।

दूसरे, क्रान्तिकारी प्रतिरोध आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष।

तीसरे, क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण।

तीन बुनियादी बिन्दु हैं – द्ध1ऋ मजदूर वर्ग के नेतृत्व के तहत मजदूर–किसान एकता, द्ध2ऋ सचेत रूप से जन आधार पर सशस्त्र संघर्ष स्थापित करना और द्ध3ऋ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को मजबूती के साथ स्थापित करना।ह

हकिसान संघर्ष को संशोधनवाद से लड़ते हुए आगे बढ़ाओह शीर्षक इस दौर के अपने आखिरी लेख में उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से संयुक्त मोर्चे की सै)ान्तिक बुनियाद रखी– **हरूसी क्रान्ति की सफलता का मुख्य कारण संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति का सही अमल था। संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति का सवाल भारत में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की जनवादी क्रान्ति की कार्यनीति का रूप अलग होगा। भारत में भी नागा में, मिज़ो, कश्मीर और अन्य इलाकों में निम्न–पूँजीवादी नेतृत्व के अधीन संघर्ष छेड़े जा रहे हैं। इसीलिए जनवादी क्रान्ति में मजदूर वर्ग को उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर आगे बढ़ना होगा। ढेरों अन्य नये इलाकों में पूँजीवादी या निम्न–पूँजीवादी पार्टियों के नेतृत्व के अधीन संघर्ष उभरेंगे। मजदूर वर्ग इनके साथ भी गठजोड़ बनाकर चलेगा और इस गठजोड़ का मुख्य आधार होगा, साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष तथा आत्म–निर्णय का अधिकार। मजदूर वर्ग लाजिमी**

तौर पर इस अधिकार को, अलग होने के अधिकार के साथ-साथ स्वीकार करता है।ह

उन्होंने यह भी समझाया कि वर्तमान शासक वर्गों के एकता के नारे का अर्थ किस तरह इजारेदार पूँजी द्वारा शोषण के लिए एकता होता है – **‘‘‘कश्मीर भारत का अभि्न अंग है’ – यह नारा शासक वर्ग लूट के हित में देता है। कोई मार्क्सवादी इस नारे का समर्थन नहीं कर सकता। प्रत्येक राष्ट्रीयता के आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार करना मार्क्सवादियों का अनिवार्य कर्तव्य है। मार्क्सवादियों को कश्मीर, नागा आदि सवालों पर लड़ाई लड़ने वालों के पक्ष में समर्थन व्यक्त करना चाहिए।ह**

इस प्रकार नयी गठित होने वाली पार्टी की क्रान्तिकारी लाइन के अनेक पहलू भाकपा और माकपा के भीतर चले विचारधारात्मक-राजनीतिक संघर्ष के दौरान लिखे कामरेड सीएम के आठ दस्तावेजों में दिखायी देते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी संघर्ष की सै)ान्तिक बुनियाद का काम किया। इन दस्तावेजों ने नयी पार्टी की स्थापना और क्रान्तिकारी आन्दोलन के भावी विकास के लिए राजनीतिक एवं विचारधारात्मक आधार का काम किया। यही नहीं, कामरेड सीएम ने ख्रुश्चेवी संशोधनवाद के विरु) संघर्ष में अन्तरराष्ट्रीय बहस में भी भूमिका निभायी। वे सोवियत संघ को सामाजिक-साम्राज्यवादी के रूप में चि]नत करने वाले पहले व्यक्तियों में थे। उन्होंने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के अनुभवों को दक्षिण एशिया के देशों में पहुँचाने के लिए बुनियाद रखी।

नक्सलबाड़ी जन उभार
और उसकी ऐतिहासिक महत्ता

18 मार्च 1967 को आयोजित हुए किसान सम्मेलन ढ्ढकन्वेन्शनत्र्ह से लेकर चार महीनों तक दार्जिलिंग जिले के सिलिगुड़ी उप-मण्डल के किसानों ने विद्रोह किया। वास्तव में इस सशस्त्र जनउभार की जमीन 1965-66 में ही तैयार की गयी थी जब माकपा के ‘सिलिगुड़ी ग्रुप’ ने तराई क्षेत्र में छापामार यु) छेड़ने के लिए किसानों का आ]वान करने वाले सिलसिलेवार पर्चे निकाले थे। 1966 में तीर-कमान और कुछ राइफलें इकट्ठा की गयी थीं। 1966 के उत्तरा) में सिलिगुड़ी में क्रान्तिकारी किसान कमेटी संगठित की गयी थी। किसान कमेटियाँ बनायी गयीं। इन्होंने खुद को हथियारबन्द कर लिया और बड़े जमींदारों तथा जोतदारों की जमीन व ़सल जब्त करने का अभियान छेड़

दिया। 3 मार्च 1967 को किसानों के एक समूह ने जमीन के एक पट्टे पर लाल झण्डे गाड़ दिये और पकी ृसल को काट लिया। असंख्य लाल झण्डों के इस नज़ारे ने जमींदारों के दिल में दहशत पैदा कर दी। पूरा देहाती क्षेत्र **हसशस्त्र किसान क्रान्ति के रास्ते पर आगे बढ़ो!ह** के नारों से गूँज उठा। जमींदारों तथा उनके गिरोहों की ओर से हुए हर प्रतिरोध को ध्वस्त किया गया। उनकी जमीनें एवं अनाज छीन लिया गया। मई 1967 तक इसने राज्य के खिलाफ सशस्त्र किसान जनउभार का रूप ले लिया था। 23 मई को ग्राम झारू गाँव में एक इन्सपेक्टर की हत्या हुई और उसी 25 तारीख को पुलिस की गोलीबारी में 9 महिलाएँ और बच्चे मारे गये। यह जनउभार जुलाई तक चला। आखिर केन्द्रीय अ)-सैनिक बलों ने जब भयंकर निर्मम तरीके से आक्रमण किया तभी आन्दोलन को दबाया जा सका।

जनउभार हालांकि थोड़े समय में दबा दिया गया, ङि भी भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में इसने बड़ा भारी महत्व ग्रहण किया। यह भाारतीय राजनीति में ऐतिहासिक सन्धि-काल बना। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नक्सलबाड़ी के बाद भारतीय राजनीति पहले जैसी नहीं रही, क्यों कि इसके असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। नक्सलबाड़ी की चिंगारी जल्द ही दावानल बन गयी। इसकी आग ने भारत के व्यापक भूखण्डों को समेट लिया, मसलन श्रीकाकुलम, बीरभूमि, देबरा-गोपीवल्लभपुर, मुसहरी, लखीमपुर-खिरी आदि। अगले कुछ वर्षों में यह सशस्त्र किसान आन्दोलन दर्जन से ज्यादा प्रदेशों तक ैल गया।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नक्सलबाड़ी के जनउभार को **हभारत पर बसन्त के वज्रनादह** के रूप में सराहा। 28 जून 1967 को रेडियो पेकिंग इसे **हभारतीय जनता द्वारा छेड़े गये क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष का अगला पंजाह** कहा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र 'पीपुल्स डेली' ने 5 जुलाई 1967 के अपने सम्पादकीय में **हदार्जिलिंग इलाके के किसानों की बगावतह** को **हक्रान्तिकारी तूानह** और **हभारतीय जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष के लिए बड़े भारी महत्व का घटनाक्रमह** कहा। इसने ठीक से चि]नत किया कि हभारतीय क्रान्ति को किसानों पर भरोसा करने, देहाती क्षेत्रें में आधार इलाके स्थापित करने, दीर्घकालिक सशस्त्र संघर्ष पर टिके रहने और देहाती क्षेत्रें का इस्तेमाल करते हुए शहरों को घेरकर आ़त: काबिज करने के रास्ते पर चलना होगा।ह

इसने भारत के क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों का आ]वान किया कि हजन यु) की लचीली रणनीति एवं कार्यनीति को समग्रता में प्रयोग में लाकर किसान जनता को

बहादुराना तरीके से जागृत करो, क्रान्तिकारी सशस्त्र बलों को खड़ा करो तथा विस्तारित करो, क्रान्तिकारी शक्तियों के दम पर कुछ समय तक मजबूत रहने वाले साम्राज्यवादियों एवं प्रतिक्रियावादियों के सशस्त्र दमन से निबटो ......ह

इसने यह अन्देशा व्यक्त किया कि **हृदार्जिलिंग की चिन्गारी दावानल बन जायेगी और यह आग निश्चित रूप से भारत के व्यापक हिस्सों तक ़ैलेगी। तय है कि अन्ततोगत्वा भारत के कोने–कोने में क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष का बड़ा तू़ान आयेगा।ह**

नक्सलबाड़ी का जन उभार 1960 के दशक के उत्तरा) में दुनियाभर में आये क्रान्तिकारी ऊ़ान का अनिवार्य अंग रहा। यह कामरेड माओ के मार्गदर्शन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दुनिया को झकझोरने वाले महान विचारधारात्मक–राजनीतिक मन्थन की उपज था। एक ओर कामरेड माओ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी ओर भगोड़े ख्रुश्चेव के अधीन संशोधनवादी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चले 'महान बहस' ने समूचे विश्व में कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कम्युनिस्ट कहलाने वाली हर पार्टी को या तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की संशोधनवादी लाइन या ़िर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की क्रान्तिकारी लाइन के समर्थन में सुस्पष्ट विचारधारात्मक अवस्थिति अपनानी पड़ रही थी। 'जनता के चीन' में हाल में शुरू हुई 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' भी संशोधनवादियों और क्रान्तिकारी माओवादियों के बीच विभोजन रेखा बन गयी थी।

दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इस संघर्ष ने कम्युनिस्ट खेमे के बीच तीखा स्वरूप गहण कर लिया। इस तरह नक्सलबाड़ी भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में संशोधनवाद और क्रान्ति के बीच इस तीखे संघर्ष को जिस हद तक अभिव्यक्त करती रही, उसी हद तक यह अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी अभिव्यक्त करती रही। यह भाकपा और माकपा के भीतर की उन क्रान्तिकारी शक्तियों की लामबन्दी का केन्द्र बिन्दु बन गया जिन्होंने नयी क्रान्तिकारी पार्टी के गठन की प्रक्रिया की पहल करा शुरू किया था। माकपा के भीतर के क्रान्तिकारियों ने कलकत्ते में बैठक कर 'नक्सलबाड़ी किसान संघर्ष सहायता कमेटी' का गठन कर लिया। यही आगे चलकर नयी पार्टी का नाभिक बना। भारतीय क्रान्ति की कार्यसूची पर ़िर से सशस्त्र संघर्ष को स्थान देकर इसने पूरे उपमहाद्वीप के माओवादियों का मर–मिटने को तैयार हो के लिए आ]वान किया।

नक्सलबाड़ी ने देश की जनता को व्यावहारिक तौर पर सशस्त्र संघर्ष का रास्ता दिखाया। इसने न केवल सि)ान्त में संशोधनवाद के साथ निर्णायक विच्छेद किया, बल्कि

व्यवहार में भी इसका रास्ता दिखाया। इस प्रकार इसने जनयु) और सशस्त्र बल से सत्ता हथियाने के रास्ते के बीज बो दिये। **ह्वनक्सलबाड़ी एक ही रास्ताह** भारत के साथ ही समूचे दक्षिण एशिया के सच्चे क्रान्तिकारियों का नारा बन गया। नक्सलबाड़ी की चिंगारी ने श्रीकाकुलम, बीरभूम, देबरा-गोपीवल्लभपुर, मुसहरी और लखीमपुर-खिरी में क्रान्ति की आग लगा दी। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू में नक्सलबाड़ी से प्रेरित संघर्षों का सशक्त ज्वार उठा और भारत के प्राय: प्रत्येक प्रदेश में माओवादी संगठनों के अंकुर ्रूटे।

नक्सलबाड़ी के जन उभार की ऐतिहासिक महत्ता संशोधनवाद और क्रान्ति के बीच विभाजन रेखा के रूप में रही। जैसा कि कामरेड माओ के मातहत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्देशा लगाया था, यह चिंगारी जल्द ही ऐसी लपटें बन गयीं जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने आगोश में ले लिया।

अध्याय-2
पार्टी गठन और
सशस्त्र किसान उभार : 1967-72

नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम और अन्य किसान सशस्त्र संघर्षों के जनउभारों से देश में उपजे ऊान ने देश पर ऐसा प्रभाव डाला कि भारतीय राजनीति की तस्वीर ही बदल गयी।

पहली बात यह कि इन संघर्षों ने अब तक स्थापित चुनावी रास्ते से हटकर पार्टी के नेतृत्व में आधार इलाकों के परिप्रेक्ष्य के साथ भ्रूण रूप में जनता की राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हुए देश की मुक्ति का नया रास्ता दिखाया।

दूसरी बात यह कि इन संघर्षों ने जनता को दुश्मन के सशस्त्र बलों से हथियार जब्त करते हुए तथा भ्रूण रूप में जन सेना गठित करते हुए छापामार बलों के निर्माण का रास्ता दिखाया।

तीसरी यह कि इन्होंने लाखों किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रें एवं बु)जीवियों, महिलाओं, दलितों, जनजातियों आदि को जन यु) की राजनीति से जागृत किया।

चौथी बात यह कि इन संघर्षों ने सर्वहारा की पार्टी के तौर पर नेतृत्व स्थापित करने और उसी दौरान जनउभार संगठित करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की तालमेल कमेटी ढ्ढएआईसीसीसीआरऋ के गठन से लेकर 1969 में

पार्टी के गठन तक के दौर में इस काम को कदम-ब-कदम अंजाम दिया गया। यह आन्दोलन को क्रान्तिकारी रास्ते से हटाने के लिए प्रयासरत भटकावों तथा अवसरवाद के भिन्न-भिन्न रूपों से संघर्ष करते हुए ही सम्भव हो पाया।

आखिरी बात यह कि यह वह दौर था जब बेमिसाल साहस के साथ क्रूर यातनाओं, जेल यात्रओं तथा शहादतों के जरिये हजारों कामरेडों की बहादुराना कुर्बानियाँ देश की जनता को प्रेरित कर रही थीं। लोग समझने लगे थे कि समाज के क्रान्तिकारी रूपान्तर के लिए ऐसी भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है।

पार्टी का गठन

देश के विभिन्न राज्यों में जंगल की आग की तरह नक्सलबाड़ी की तर्ज़ पर संघर्षों के फैलने की इसी पृष्ठभूमि में यह फौरी जरूरत बनी कि इन संघर्षों के बीच तालमेल करने वाला एक केन्द्र हो, एक केन्द्रीकृत क्रान्तिकारी भूमिगत पार्टी हो, नये किस्म की लेनिनवादी पार्टी हो।

नक्सलबाड़ी जनउभार के सतह पर आने के बाद नयी पार्टी के गठन की प्रक्रिया में दो साल लगे। मगर यह कहा जा सकता है कि क्रान्तिकारी पार्टी के गठन के लिए विचारधारात्मक-राजनीतिक संघर्ष 1964 में ही, 7वीं काँग्रेस के समय से ही चल पड़ा था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 1965-67 के बीच कामरेड सीएम के आठ दस्तावेजों ने ऐसी पार्टी के लिए विचारधारात्मक-राजनीतिक आधार प्रदान किया। नक्सलबाड़ी और उसके तत्काल बाद इस तरह के अनेक आन्दोलनों ने क्रान्तिकारी पार्टी के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी। नयी पार्टी के गठन की ओर पहला सांगठनिक कदम नवम्बर 1967 में अखिल भारतीय तालमेल कमेटी के गठन से उठा था।

यह अखिल भारतीय तालमेल कमेटी 12-13 नवम्बर, 1967 को सात राज्यों से आये क्रान्तिकारी कामरेडों को लेकर गठित की गयी थी। इसने दिसम्बर 1967 में **'लिबरेशन'** पत्रिका में अपना **'घोषणापत्र'** जारी किया। अखिल भारतीय तालमेल कमेटी के गठन को पेकिंग रेडियो ने समर्थन दिया। उसने **'घोषणापत्र'** प्रसारित भी किया।

कमेटी को उन तमाम किसान आन्दोलनों के साथ तालमेल करने की फौरी आवश्यकता महसूस हुई जो नक्सलबाड़ी के जनउभार के बाद उभरे थे। इस तालमेल को नये किस्म की पार्टी के गठन की तैयारी माना जा रहा था। तालमेल कमेटी ने अपने

घोषणापत्र में ठीक चि]नत किया–

ह्वदेश के विभ्िा हिस्सों में क्रान्तिकारी किसान संघर्ष अभी उभर रहे हैं या उभरने वाले हैं। मजदूर वर्ग के हिरावल के नाते हमारा यह आवश्यक क्रान्तिकारी कर्तव्य है कि जहाँ तक सम्भव हो, हम इन संघर्षों को विकसित करें और इनका नेतृत्व करें। इसके मद्देनजर पार्टी के भीतर और बाहर के उन सभी क्रान्तिकारी तत्वों को मार्क्सवाद–लेनिनवाद, यानी माओ त्से–तुंग की विचारध्धारा से मार्गदर्शन लेकर क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने के लिए अपनी गतिविधियों के बीच तालमेल करना होगा और अपनी उन तमाम शक्तियों को एकताब) करना होगा जो आज देश के तमाम हिस्सों में अलग–थलग पड़े हुए हैं और जन संघर्ष के विभ्िा मोर्चों पर काम कर रहे हैं। मदुरै में आखिरी व निर्णायक विश्वासघात के बाद अब और देर करना उचित नहीं होगा। यह तालमेल अब ग़ौरी जरूरत बन गया है।

ह्वयही कारण है कि विभ्िा राज्यों के कामरेडों ने इसी तर्ज पर सोचने और जूझने वाली अखिल भारतीय तालमेल कमेटी का गठन करना तय किया है। कमेटी की ओर से हम घोषण करते हैं कि इसके मुख्य कार्यभार इस प्रकार होंगे –

द्ध1ऋ सभी स्तरों पर जुझारू व क्रान्तिकारी संघर्षों, खासकर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी की तर्ज पर किसान संघर्षों को विकसित करना और उनके बीच तालमेल करना।

द्ध2ऋ मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश जनता के जुझारू, क्रान्तिकारी संघर्षों को विकसित करना, अर्थवाद का मुकाबला करना और इन संघर्षों को कृषि क्रान्ति की दिशा में मोड़ना।

द्ध3ऋ संशोधनवाद और नवसंशोधनवाद के खिलाफ़ समझौताविहीन विचारधारात्मक संघर्ष छेड़ना, कामरेड माओ त्से–तुंग की विचारधारा को, जो कि वर्तमान युग का मार्क्सवाद–लेनिनवाद है, को लोकप्रिय बनाना और इस आधार पर पार्टी के भीतर और बाहर के सभी क्रान्तिकारी तत्वों को एकताब) करना।

द्ध4ऋ कामरेड माओ त्से–तुंग की विचारधारा की रोशनी में भारतीय स्थितियों के ठोस विश्लेषण के आधार पर क्रान्तिकारी कार्यक्रम और कार्यनीतिक लाइन के लिए तैयारियाँ करना।ह्व

छः महीने बाद 14 मई 1968 को नक्सलबाड़ी किसान जनउभार की वर्षगाँठ की पूर्वसन्ध्या पर कमेटी ने अपनी पहली बैठक के बाद की तमाम घटनाओं की समीक्षा की। बदली स्थितियों में कमेटी ने नया घोषणापत्र जारी करने और कामरेड सुशीतल राय चौधरी

के संयोजकत्व में कमेटी का नाम बदलकर ह्नअखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की तालमेल कमेटीह्न ङ्कएआईसीसीसीआरङ्क रखने का निर्णय किया। इन क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी में **लिबरेशन** और बांग्ला में **देशब्रती** राजनीतिक पत्र जारी किये।

अब तक बरद्वान प्लेनम हो चुका था और आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर के कामरेड उसमें भाग ले चुके थे। बरद्वान प्लेनम से पहले माकपा के नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के क्रान्तिकारियों को निष्कासित कर दिया था। आन्ध्र प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के प्रतिनिधि–मण्डलों ने प्लेनम का प्रारूप ङ्कमसविदाङ्क अस्वीकार कर दिया और वैकल्पिक प्रारूप प्रस्तावित किया। मगर प्लेनम ने वही पुरानी संशोधनवादी लाइन पारित की। इसी पृष्ठभूमि में पूरे भारत के सच्चे क्रान्तिकारियों ने माकपा को छोड़ दिया, एआईसीसीआर को एआईसीसीसीआर बना दिया और नयी पार्टी के गठन की तैयारियाँ शुरू कर दीं। नक्सलबाड़ी जनउभार के बाद क्रान्तिकारियों ने माकपा के विरु) विद्रोह किया। माकपा को छोड़कर वे तालमेल कमेटी में शामिल हो गये।

एआईसीसीसीआर के नये **घोषणापत्र** ने भारतीय क्रान्ति के निशाने तथा दोस्त कौन हैं और देश की मुक्ति का रास्ता क्या होगा यह समझाया –

ह्नआज अमरीकी साम्राज्यवाद, सोवियत संशोधनवाद, बड़े भारतीय जमींदारों और दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग भारतीय जनता के मुख्य दुश्मन हैं, हमारी मेहनतकश जनता की पीठ पर भारी बोझ बने चार पहाड़ हैं।

ह्नइन जानी दुश्मनों के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शासन को उखाड़ ॅेंककर ही जनता की जनवादी क्रान्ति सफल हो सकेगी। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रान्ति की मुख्य शक्ति किसानों को देहाती क्षेत्रें में क्रान्तिकारी आधार इलाके स्थापित करने होंगे, दीर्घकालिक हथियारबन्द संघर्ष चलाना होगा, देहाती क्षेत्रें से शहरों को घेरना होगा और अन्त में शहरों पर कब्जा कर अन्तिम देशव्यापी विजय हासिल करनी होगी। मजदूर वर्ग और किसानों के बीच मजबूत गठबन्धन संयुक्त मोर्चे के आधार का काम करेगा, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान, निम्न–पूँजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग शामिल होंगे।ह

नये **घोषणापत्र** ने स्पष्ट किया कि **ह्नअगर भारतीय जनता के दुश्मनों को उखाड़ ॅेंकना हो, तो षड्यन्त्रकारी तरीकों को नहीं, वरन् केवल जन दिशा को ही अपनाना होगा।ह**

इसने पुरजोर दोहराया कि **ह्नसभी रूप–रंग के संशोधनवादी, चाहे वे डांगेपंथी भगौड़े हों या नव–संशोधनवादी गुट के, अमरीकी साम्राज्यवाद, सोवियत**

नव-उपनिवेशवाद तथा अपने देश के प्रतिक्रियावादियों के पिट्ठू साबित हुए हैं। यह निर्विवाद है कि वे भारतीय जनता के दुश्मन हैं। बरद्वान में इन नव-संशोधनवादी नेताओं ने मार्क्सवाद-विरोधी, संशोधनवादी विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर आखिरी मोहर लगाकर पारित किया है। लेकिन क्रान्तिकारियों तथा जनता की ओर से हुए विरोध के कारण वे पहले से ज्यादा धूर्त व शातिर हो चुके हैं। उस पार्टी में, जिसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद, यानी अध्यक्ष माओ की विचारधारा को नकारने वाली अवस्थिति अपना लीौर हिंसक क्रान्ति के रास्ते को अस्वीकार कर संसदीय मार्ग अपना लिया है, अब केवल अवसरवादी ही रह सकते हैं, मार्क्सवादी-लेनिनवादी नहीं। बरद्वान के बाद अब कफी स्पष्ट हो गया है कि डांगेपंथी भगौड़ों की ही तरह, नव-संशोधनवादी भी प्रति-क्रान्तिकारी खेमे से जुड़ गये हैं और मार्क्सवाद-लेनिनवाद का जुबानी जमा-खर्च करते हुए उभर रही कृषि क्रान्ति के खिलाफ सक्रिय रूप से विध्वंसक कारवाई कर रहे हैं। जो लोग अभी भी आन्तरिक पार्टी संघर्ष की गुंजाइश देख रहे हैं वे संशोधनवाद-विरोधी यो)ाओं की कतारों में भ्रम फैला रहे हैं और उनके सुदृढ़ीकरण में बाधा डाल रहे हैं।ह

इसने सभी क्रान्तिकारियों को नयी पार्टी के निर्माण के लिए सारी शक्तियों को एक करने का आ]वान इस प्रकार किया –

हइस ऐतिहासिक घड़ी में हम देश भर के उन सभी क्रान्तिकारियों से एक बार फिर अपील करते हैं जो अध्यक्ष माओ की विचारधारा को स्वीकार करते हैं कि अपनी शक्तियों को एकताब) करें तथा अपने संघर्षों के बीच तालमेल करें, ताकि भारतीय क्रान्ति की विजय और करीब आ सके। आइये, हम अध्यक्ष माओ की विचारधारा के लाल झण्डे के तहत लामबन्द हों, उनकी विचारधारा पर भारत की ठोस स्थितियों में अमल करें। आइये, हम नक्सलबाड़ी की तर्ज़ पर क्रान्तिकारी संघर्ष छेड़ते हुए भारत की सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करें, क्योंकि क्रान्तिकारी पार्टी के बिना क्रान्ति विजयी नहीं हो सकती।ह घोषणापत्र ने आग्रहपूर्वक कहा – **हउन क्रान्तिकारियों से, जिनकी अध्यक्ष माओ में पक्की आस्था है और जिन्होंने संशोधनवादियों व नव-संशोधनवादियों के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया है पर फिर भी अपने अलग ग्रुप बनाये रखे हैं, कि इन ग्रुपों को विसर्जित करें और खुद को अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की तालमेल कमेटी के भीतर सुदृढ़ करें। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त अलग-अलग ग्रुपों का अस्तित्व भारतीय क्रान्ति के मकसद के लिए कफी नुकसानदेह होगा।**

एआईसीसीसीआर के नेतृत्व के अधीन तकरीबन 13 प्रदेशों में वहाँ के सशस्त्र खेतिहर संघर्षों की बढ़ती लहरों के बीच तालमेल करने के लिए और उनका नेतृत्व करने के लिए प्रदेश तालमेल कमेटियाँ गठित की गयीं।

कामरेड चारू मजुमदार ने इन आन्दोलनों का मार्गदर्शन किया। उन्हीं के नेतृत्व में एआईसीसीसीआर ने नये किस्म की पार्टी के निर्माण के लिए 'पार्टी संगठन' पर प्रस्ताव पारित किया। कामरेड लेनिन के सौवें जन्म दिवस 22 अप्रैल 1969 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का जन्म हुआ। पार्टी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए और पार्टी काँग्रेस की तैयारी के लिए एक तालमेल कमेटी गठित की गयी। कलकत्ते में आयोजित विराट रैली में पार्टी के गठन की घोषणा की गयी। पार्टी गठन से ठीक पहले कलकत्ते के तमाम परिसरों में छात्र आन्दोलन की लहर आयी थी। माओवादी छात्र मोर्चे – प्रगतिशील छात्र तालमेल कमेटी (पीएससीसी) ने कलकत्ते में और आसपास के संस्थानों के प्रायः सभी छात्र संघों पर अपनी पकड़ कायम की थी। आन्ध्र प्रदेश में नक्सलबाड़ी को खुलकर समर्थन देने वाले गुण्टूर मेडिकल कालेज के छात्र थे। इन्होंने नक्सलबाड़ी के समर्थन में एकजुटता कमेटी बनायी। देश के अनेक क्षेत्रों में तमाम संघर्ष चलाने और अखिल भारतीय स्वरूप अख्तियार करने के बाद पार्टी ने मई 1970 में 8वीं कांग्रेस आयोजित की।

पार्टी की आठवीं काँग्रेस

पार्टी की आठवीं काँग्रेस कलकत्ते में 15-16 मई 1970 को आयोजित हुई। यह काँग्रेस जनवरी 1965 में कामरेड चारू मजुमदार के पहले दस्तावेज के प्रकाशन के बाद तत्कालीन पार्टी में गहरी जड़ जमाये संशोधनवादी रुझानों के विरुद्ध चलाये गये सतत विचारधारात्मक-राजनीतिक संघर्ष की परिणति थी। पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों में सशस्त्र किसान आन्दोलन का नेतृत्व करने में और संशोधनवाद तथा अर्थवाद के खिलाफ संघर्ष करने में क्रान्तिकारियों द्वारा हासिल अनुभवों का संश्लेषण किया।

भारत की ठोस स्थितियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद (मा-ले-मा) के सिद्धान्त पर ठोस रूप से अमल करते हुए काँग्रेस ने भारतीय समाज का चरित्र अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामन्ती के रूप में सही तरीके से विश्लेषित किया, समाजवादी परिप्रेक्ष्य के साथ नयी जनवादी क्रान्ति की आम कार्यदिशा प्रस्तुत की और देहाती क्षेत्रों से शहरों को घेरने की दीर्घकालिक जनयुद्ध की रणनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत

की। काँग्रेस ने 'पार्टी कार्यक्रम' और 'पार्टी संविधान' पेश किया और पारित किया। इसके अलावा कामरेड सीएम ने अपने पहले सम्बोधन में 'राजनीतिक एवं सांगठनिक रिपोर्ट' पेश की। पार्टी को एक ठोस ढाँचा देते हुए क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए 'केन्द्रीय कमेटी' का चुनाव किया गया। देशभर से आये 35 प्रतिनिधियों ने काँग्रेस में हिस्सा लिया और 21-सदस्यीय केन्द्रीय कमेटी चुनी। इस सीसी ने नौ-सदस्यीय पोलितब्यूरो चुना और क्षेत्रिय ब्यूरो गठित कियें

यह ऐतिहासिक काँग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की राह पर एक ऐसा गुणात्मक मोड़ था जिसने दशकों से चले आये संशोधनवादी व्यवहार को समाप्त कर दिया और भारतीय क्रान्ति के लिए नया क्रान्तिकारी रास्ता आलोकित किया। यह काँग्रेस दोनों तरह के संशोधनवाद का निषेध रही, भाकपा के ख्रुश्चेवी संशोधनवाद का और 1964 की 7वीं काँग्रेस से माकपा का चरित्र तय कर रहे नव-संशोधनवाद का जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समान दूरी की वकालत कर रहा था। भाकपा और बाद में माकपा दोनों ही पार्टियाँ भारतीय क्रान्ति के लिए क्रान्तिकारी कार्यक्रम, रास्ता, रणनीति एवं कार्यनीति सूत्र) करने में सर्वथा किल रही थीं। वे संसदवाद और वर्ग सहयोग की दलदल में धँसी रहीं और भारतीय क्रान्ति को धोखा देती रहीं।

यह सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ ही थी जिसने पहली बार भारत के साथ ही, समूची दुनिया की ठोस स्थितियों के ठोस विश्लेषण के बाद भारतीय क्रान्ति के लिए मूलतः सही कार्यक्रम, रास्ता, रणनीति और कार्यनीतिक कार्य दिशा द्धलाइनत्र्ञ तैयार कर ली। यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ मजदूर वर्ग की उस सबसे विकसित वैज्ञानिक सि)ान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद से लैस रही, जिसका भाकपा जमकर विरोध कर रही थी और जिसे माकपा अपने कर्मों के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं थी। सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ नये किस्म की पार्टी थी - एक भूमिगत पार्टी जिसने संसदीय रास्ता खारिज किया, संशोधनवाद की सभी किस्मों का विरोध किया और अन्ततः देहाती क्षेत्रें से सत्ता दखल करते हुए आखिर शहरों को घेरते हुए देशव्यापी विजय हासिल करने की दीर्घकालीन लोक यु) की लाइन सामने लायी।

यही वजह है कि हमारी पार्टी की 1970 की काँग्रेस की भारत में क्रान्ति के दैदीप्यमान पथ-प्रदर्शक के रूप में बड़ी ही अहमियत है। इसने माकपा के भीतर की उस क्रान्तिकारी धारा द्वारा अपनायी गयी कार्यदिशा और नीतियों को सुदृढ़ किया जो माकपा के संशोधनवाद से नाता तोड़ने पर पहले एआईसीसीसीआर के रूप में और फिर 1969 में

सीपीआई ‹एमएल› के रूप में पुनर्गठित हो गयी।

काँग्रेस ने वह ऐतिहासिक **पार्टी कार्यक्रम** पारित किया जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में पहली बार क्रान्तिकारी कार्यक्रम पेश हुआ था। इसने माओ त्से-तुंग विचारधारा को वर्तमन समय के मार्क्सवाद-लेनिनवाद के रूप में पहचाना और भारतीय क्रान्ति को महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का अंग माना। इसने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय क्रान्ति को दो मंजिलों से गुजरना होगा - नयी जनवादी मंजिल और समाजवादी मंजिल। इसने दीर्घकालीन लोक यु) की उस लाइन पर फि से विश्वास जताया जिसे क्रान्तिकारियों ने नक्सलबाड़ी जनउभार के दिनों से ही नयी जनवादी अवस्था में भारतीय क्रान्ति का रास्ता मान लिया था। इसने यह माना कि चार बड़े पहाड़ों को उखाड़ फेंकना होगा - सामन्तवाद, दलाल नौकरशाह पूँजीवाद, अमरीकी साम्राज्यवाद और सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद। इसने नयी जनवादी अवस्था में चार क्रान्तिकारी वर्गों - मजदूर वर्ग, किसान, निम्न पूँजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग को सही-सही चि]नत किया और यह भी कि मजदूर-किसान संश्रय ‹गठबन्धन› के आधार पर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में इन चार वर्गों का रणनीतिक क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनाना होगा।इसने भारतीय समाज के बहु-राष्ट्रीय चरित्र को पहचाना और राष्ट्रीयताओं के आत्म-निर्णय के लिए होने वाले सभी जायज संघर्षों को समर्थन देने का आ]वान किया। इसने देश में क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए गुप्त पार्टी के महत्व पर बल दिया।

सचमुच यह एक ऐतिहासिक काँग्रेस रही जिसने देश में बड़े साफ़ तरीके से नयी क्रान्तिकारी लाइन स्थापित की। भारत की पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टी की पहली काँग्रेस के रूप में, संशोधनवाद के सभी रूप-रंगों से हमेशा के लिए पूरी तरह नाता तोड़ देने वाली पहली काँग्रेस के रूप में, भारतीय क्रान्ति के लिए नयी क्रान्तिकारी लाइन स्थापित करने वाली काँग्रेस के रूप में भारत के क्रान्तिकारी इतिहास में इस आठवीं काँग्रेस को अनोखा व स्थायी स्थान प्राप्त हुआ है।

दावानल की तरह आन्दोलन का विस्तार

किसानों के सशस्त्र संघर्ष जल्द ही नक्सलबाड़ी के रास्ते पर जंगल की आग की तरह फैलते गये - श्रीकाकुलम, लखीमपुर-खिरी ‹तराई›, देबरा-गोपीवल्लभपुर, बीरभूम और देश के अन्य क्षेत्रें, जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल व आन्ध्र प्रदेश के अन्य भागों में, तमिलनाडू, केरल, उत्तर प्रदेश आदि में। इस तरह सशस्त्र क्रान्तिकारी किसान संघर्ष नक्सलबाड़ी से शुरू होकर देश के अनेक भागों तक फैलता गया। पश्चिम बंगाल में स्थित

आन्दोलन के केन्द्र-बिन्दु के अलावा आन्ध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में इसका मजबूत आधार रहा।

इनमें से प्रमुख था श्रीकाकुलम का सशस्त्र संघर्ष। यह संघर्ष तब उभरा जब 31 अक्टूबर 1967 को गिरिजन संघम के सम्मेलन के लिए जा रहे कामरेड कोरण्णा और मंगण्णा को लेविदी गाँव के जमींदारों ने मार डाला। श्रीकाकुलम का सशस्त्र किसान जन उभार तीन सालों तक चला। इस दौरान किसानों ने खुद को छापामार दस्तों के रूप में संगठित किया और जमींदारों तथा पुलिस पर अनेक बार धावा बोलते हुए जमींदारों की जमीन, फसल व सम्पत्ति पर कब्जा किया। लेकिन हजारों की संख्या में राजकीय पुलिस बल सीआरपीएफ तैनात कर तथा सैकड़ों गाँवों में जनजाति के लोगों पर फासीवादी दमन का सिलसिला चलाकर 1970 के अन्त तक आते-आते आन्दोलन को कुचल दिया गया। इस आन्दोलन के दौरान बहुत सारे नेता शहीद हुए, जैसे कामरेड पंचादी, कृष्णमूर्ति, वेम्पटपू सत्यम, आदिभटला कैलासम, निर्मला, सुब्बाराव पाणिग्रही, चगन्ती भास्कर राव और देविनेनी मल्लिकार्जुन।

1968 के पूर्वा) मे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लखीमपुर-खिरी में कुख्यात जमींदारों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की। तीखे पुलिस दमन के बावजूद आन्दोलन फैलता गया और बहुत सारे जमींदारों को अपने गाँव छोड़कर भागना पड़ा।

बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले के मुसहरी में 1968 के मध्य में भूमि संघर्षों की शुरुआत हुई और फसल कब्जाना एक बड़े अभियान की तरह चल पड़ा। जमींदारों व पुलिस के हमलों का मुकाबला करने के लिए छापामार टुकड़ियाँ खड़ी की गयीं।

मिदनापुर जिले में देबरा-गोपीबल्लभपुर में 1968 में छात्रें व बु)जीवियों ने किसानों को संगठित कराना शुरू किया। 1969 तक उन्होंने सशस्त्र किसान छापामार संघर्ष शुरू कर दिया जिससे कई जमींदारों को गाँव छोड़कर भागना पड़ा। 1971 की शुरुआत में पुलिस के शिविरों पर भी हमले किये जाने लगे। देबरा में हजारों किसानों को जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र कारवाइयों के लिए लामबन्द किया गया। यह संघर्ष बिहार द्धअब झारखण्डऋ के सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरभंज तक फैला।

संघर्ष के इन इलाकों से लगे हुए खड़गपुर मण्डल के रेलवे मजदूरों को संगठित करते हुए मजदूर आन्दोलन खड़ा किया गया। मजदूरों के एक हिस्से ने किसान संघर्षों में भी भाग लिया।

बीरभूम में संघर्ष 1968 के मध्य से तब फैलने लगा जब नक्सलबाड़ी जनउभार से प्रेरित छात्रें व युवाओं ने जिले के जमींदारो के खिलाफ किसानों को संगठित करने का बीड़ा

उठाया। छापामार दस्ते तैयार किये गये और जमींदारों व पुलिस से लगभग 200 बन्दूकें छीन ली गयीं। 1971 के मध्य तक आते–आते पुलिस, अ)र्-सैनिक एवं सैनिक बलों ने जब भयंकर दमन अभियान छेड़ दिया तभी आन्दोलन ठण्डा पड़ता गया।

इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप देश में पहली बार क्रान्तिकारी कमेटियों के गठन के जरिये जनता की क्रान्तिकारी सत्ता को भ्रूण रूप में स्थापित किया गया। ये प्रयास खासतौर पर श्रीकाकुलम, बीरभूम एवं अन्य इलाकों में भी सार्थक रहे। पहली बार दुश्मन के बलों एवं जमींदारों से हथियार छीने गये और जन मुक्ति सेना के भ्रूण के रूप में छापामार टुकड़ियाँ भी बो लगीं। इसी कारण से दीर्घकालीन लोक यु) का रास्ता अस्तित्व में आया। केवल सि)ान्त के माध्यम से ही नहीं, वरन् उपरोक्त क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्षों के ठोस व्यवहार के माध्यम से भी। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि देश के विभिा क्षेत्रें में जो सशस्त्र संघर्ष उभरे थे, वे कुछ ही इलाकों तक सीमित रहे और भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से लगे हुए भी नहीं रहे। यही नहीं, दुश्मन का आक्रमण कफी तीखा रहा और हमारी छापामार शक्तियों के पास निम्न स्तर के साधन ही रहे तथा नेतृत्व के पास हथियारबन्द संघर्ष चलाने का ज़रा भी अनुभव नहीं रहा।

कलकत्ते और आसपास के इलाकों में लोग मजबूती के साथ नक्सलबाड़ी किसान जनउभार के समर्थन में खड़े हुए। छात्रें, युवाओं, मजदूरों व बु()जीवियों ने बड़ी तादाद में संशोधनवाद के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी एकजुटता दर्शाते हुए आवाज उठायी। उन्होंने नक्सलबाड़ी कृषक संग्राम सहायक समिति बनायी। इस यह एनकेएसएसएस के आ]वान पर साझे मोर्चे की सरकार के निर्मम अत्याचारों के खिलफ सैकड़ों जनसभाओं में हजारों लोग गोलबन्द किये गये, जहाँ नक्सलबाड़ी के जनउभार के प्रति मजबूत एकजुटता व्यक्त की गयी।

किसानों के इन उभारों से प्रेरित होकर मजदूरों ने अपने जनवादी अधिकार हासिल करने के लिए पहले से चल रहे घेराव आन्दोलन तेज कर दिये। यह आन्दोलन औद्योगिक पट्टियों में और यहाँ तक कि द“तरों के क्षेत्र में भी ैलता गया। नौकरशाहों, मालिकों व बड़े व्यावसायिक घरानों की लगाम पर आँच आने लगी।

छात्र समुदाय ने भाकपा व माकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियों तथा एआईएसए व एसएआई जैसे संशोधनवादी नेतृत्व वाले संगठनों के खिलफ बगावत कर डाली। पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेण्ट ेडरेशन ढ्ढपीजीएसएऋ ने सामने आकर नेतृत्व की बागडोर सम्भाली, भारी तादाद में छात्रें व युवाओं को गोलबन्द किया और क्रान्तिकारी राजनीति का प्रसार करने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की। उन्होंने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की

क्रान्तिकारी राजनीति को प्रचारित किया व लोकप्रिय बनाया। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण निम्न नारे दिये और व्यवहार में लागू किये, इस तरह रहे –

द्ध1ऋ गाँव चलो –

इस नारे के जवाब में हजारों छात्र एवं नौजवान शहरों-कस्बों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों तथा प्रदेश से लगे हुए बिहार तथा उड़ीसा की ओर चल दिये। वे भूमिहीन व गरीब किसानों के साथ घुलमिल गये, उन तक उन्होंने क्रान्तिकारी राजनीति पहुँचायी, नक्सलबाड़ी जनउभार की अहमियत समझायी और सामन्तवाद-विरोधी संघर्ष विकसित करने के लिए किसानों को लामबन्द किया।

द्ध2ऋ अतीत से इतिहास की समीक्षा –

उन्होंने बु)जीवियों, विशेषकर इतिहासकारों, समाज शास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों का अतीत में इतिहास की समीक्षा करने के साथ-साथ जनता के, विशेषकर किसानों के साम्राज्यवाद-विरोधी व सामन्तवाद-विरोधी संघर्षों का खुलासा करने का आ]वान किया। इससे जनता आजादी और जनता के जनवाद के लिए हुए अपने अनवरत संघर्षों के बारे में जान सकी।

द्ध3ऋ मूर्ति भंजन आन्दोलन –

तथाकथित बंगाल पुनर्जागरण के उन नायकों की मूर्तियाँ हमले का निशाना बनीं जिन्होंने अंग्रेजों व जमींदारों के क्रूर दमनचक्र के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठायी थीं। इनमें से कुछ नायकों ने तो औपनिवेशिक शासकों व उनके कारिन्दों का समर्थन तक किया था। आधिकारिक इतिहास के खिलाफ हुए इस विद्रोह ने मूर्ति भंजन आन्दोलन का रूप ले लिया और अतीत के इतिहास के अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक नजरिया पैदा किया।

द्ध4ऋ हथियार जब्ती अभियान –

वर्ग दुश्मनों व पुलिस से हथियार छीनना एक बड़े अभियान के रूप में चलाया गया। छात्रें व युवाओं ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया।

इन क्रान्तिकारी संघर्षों व गतिविधियों ने बहुत सारी नाटक संस्थाओं, उपन्यासकारों, लेखकों, गीत-संगीतकारों तथा बु)जीवियों पर भी असर डाला। सैकड़ों क्रान्तिकारी नाटक खेले गये, गीत रचे गये, उपन्यास एवं कहानियाँ लिखीं व प्रकाशित की गयीं। पूरे प्रदेश में क्रान्तिकारी संस्कृति का प्रसार हुआ। बड़ी तादाद में ये संस्कृति कर्मी ग्रामीण इलाकों की ओर चल पड़े और शासक शोषक वर्गों तथा उनकी सरकार के तमाम जुल्मों को चुनौती दे हुए क्रान्तिकारी किसान संघर्षों को मजबूत करने में जुट गये।

कलकत्ता शहर के इन संघर्षों तथा अभियानों ने जनता को तो प्रेरित किया, मगर

शहरी छापामार यु) पर जरूरत से ज्यादा जोर दिये जाने के कारण माहौल धीरे-धीरे ठण्डा पड़ता गया।

कामरेड सीएम की शहादत

16 जुलाई 1972 को किसी कोरियर ﴾संदेशवाहक﴿ को क्रूर यातना देकर उससे सूचनाएँ उगलवाकर कलकत्ते के एक शेल्टर ﴾गोपनीय स्थल﴿ से कामरेड सीएम को गिर“तार कर लिया गया। अपनी गिर“तारी के समय कामरेड सीएम दमे की बीमारी के साथ-साथ हृदय रोग से ग्रस्त थे। 12 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के दौरान उन्हें किसी से मिलने का मौका तक नहीं दिया गया। इसी तरह 28 जुलाई को दिन उगते ही उनका देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस इतनी भयभीत रही कि उसने पूरे इलाके को भारी बलों के सहारे शहर से काट दिया। उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों के अलावा किसी को भी उनके मृत शरीर के पास नहीं जाने दिया गया।

कामरेड सीएम की शहादत से भारतीय क्रान्ति को ही नहीं, वरन् विश्व क्रान्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। इसके साथ ही संशोधनवादियों के विश्वासघात के दशकों बाद मुकम्मिल विचारधारात्मक- राजनीतिक बुनियाद पर खड़े होकर छेड़े गये भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन और पुनर्गठित पार्टी सीपीआई ﴾एमएल﴿ के इतिहास के पहले गौरवशाली अध्याय का अन्त हो गया।

अध्याय-3

1972 के बाद की सामयिक पराजय और नये ऊान की तैयारियाँ : 1972-77

चार प्रमुख पहलुओं के आधार पर इस ॅसलाकुन दौर का विश्लेषण किया जा सकता है -

पहला यह कि भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के लिए यह सबसे कठिन दौर रहा। उन दिनों मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी खेमे का प्रत्येक कम्युनिस्ट अग्नि-परीक्षा से गुजर रहा था। देखना यह था कि कौन दुश्मन के हमलों का सामना कर पाता है और कौन घुटने टेक देता है(कौन उत्पीड़ित जनता के साथ दृढ़ता से खड़ा हो पाता है और कौन दुश्मन के खेमे की ओर भाग खड़ा होता है(कौन मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सबक ले पाता है और कौन संशोधनवादी सबक लेता है(कौन सचमुच पहल करके जनता को जन यु) के लिए ᳟िर से संगठित कर पाता है और कौन केवल बहसों में उलझ जाता है(कौन सच्चे व सक्षम नेता के रूप

में उभरता है और कौन नकली के रूप में ?

दूसरा यह कि यह राजकीय शक्तियों के भारी दमन के बीच राजनीतिक एवं विचारधारात्मक विभ्रम का दौर रहा। इसी दौर में भगौड़ापन, विश्वासघात, टूट-ूट और निष्क्रियता हालात को और संगीन बना रही थी।

तीसरा यह कि यह वह दौर भी रहा जब धारा के विपरीत बहने वालों तथा सीमित इलाकों में सशस्त्र संघर्ष पर अडिग रहने वालों ने महान, वीरोचित बलिदान दिये और बेइन्तहाँ साहस का परिचय दिया।

और आखिर में, यह कि यह अतीत की समीक्षा करने, सबक लेने, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के पुन:एकीकरण के लिए प्रयास शुरू करने, एक ओर नये ऊान की तैयारियाँ करने और दूसरी ओर अवसरवादी तत्वों का पर्दाश करने का नाजुक दौर भी रहा।

आन्दोलन की सामयिक पराजय और पार्टी की ूटें

कुछ विचारधारात्मक, राजनीतिक एवं सांगठनिक कमजोरियों, जिसमें गम्भीर कार्यनीतिक भूलें भी शामिल हैं(तीखे दमन एवं बड़े नुकसानों(अनुभवहीनता तथा दक्षिणपंथी अवसरवादियों द्वारा अन्दरूनी तोड-ोड़ की कारवाइयों और इनके लस्वरूप हुई सामयिक पराजय तथा राजनीतिक/विचारधारात्मक भ्रान्तियों के परिणामस्वरूप पार्टी में ूट पड़ने लगी। पार्टी की पहली ूट नवम्बर 1971 में एस0एन0एस0 के विश्वासघात से पैदा हुई। कामरेड सीएम की शहादत के बाद साल भर के भीतर पार्टी कई-कई खण्डों में विभाजित हो गयी। 8वीं काँग्रेस के बाद केवल दो सालों के भीतर अनेकों केन्द्रीय कमेटी सदस्यगण शहीद हो गये, कुछ गिर"तार हुए और कुछ अन्य भटक गये या धोखा दे गये। शेष बचे दो सी0सीएम कामरेड शर्मा और सुनीती कुमार घोष के प्रदेश कमेटियों के साथ जीवन्त रिश्ते नहीं रहे।

इस प्रकार भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में 1972 के बाद के दौर में पार्टी कई छोटे-छोटे ग्रुपों में बँटती गयी। इनमें से कुछ कालान्तर में अलग-अलग लाइन और व्यवहार लागू करने वाली स्वतन्त्र पार्टियों के रूप में सुदृढ़ हो गये। कुछ ने 1967-72 के गौरवशाली संघर्षों के क्रान्तिकारी इतिहास के असली वारिस होने का दावा करते हुए अपनी-अपनी नयी सीसी का गठन कर लिया, जबकि कुछ अन्य ने सभी क्रान्तिकारी शक्तियों को एकताब) करने व सीपीआई ़एमएलऋ को पुनर्गठित करने की अपनी इच्छा

जाहिर की।

1972 की सामयिक पराजय और पार्टी का अनेकों छोटे-छोटे ग्रुपों के रूप में विखण्डन हमारी पार्टी के इतिहास का सबसे अन्धकारमय अध्याय रहा है। सीसी के भंग हो जाने पर भारतीय क्रान्ति के लिए कोई केन्द्र न रह जाने के कारण सहसा ऐसे अलग-थलग ग्रुप एवं पार्टियाँ अस्तित्व में आयीं जो 1980 तक चन्द इलाकों या प्रदेशों तक सीमित रहीं।

देश के कुछ हिस्सों में एक ओर पूर्ववर्ती सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ् ऽपीडब्ल्यूश् एवं सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ् ऽपीयूश् तथा कुछ अन्य संगठन और दूसरी ओर एमसीसी जैसे विभि़ा नये केन्द्रों के नेतृत्व में आन्दोलन के पुनर्जीवित होने पर क्रान्तिकारी जनता में नयी आशाएँ जग गयीं। सीपीआई द्धएमएलत्र्ञ् के कुछ ग्रुप 1980 तक आते-आते मृतप्राय हो गये, कुछ और ज्यादा विखण्डित होते गये और कुछ संशोधनवादी बन गये।

डीवी-टीएन-सीपीआर ग्रुप

'महान बहस' के प्रभाव में डीवी, टीएन, सीपीआर माकपा के नेतृत्व के साथ कुछ हद तक अन्दरूनी राजनीतिक संघर्ष चलते आ रहे थे। नक्सलबाड़ी संघर्ष के बाद ३रवरी 1968 में पलाकोल्लू प्लेनम और अप्रैल 1968 में बरद्वान प्लेनम आयोजित हुए। इन प्लेनमों में उन्होंने आधुनिक संशोधनवाद के विरु) वैकल्पिक दस्तावेज रखे। डीवी, टीएन, सीपीआर नक्सलबाड़ी को तो समर्थन देते रहे, पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवादी के रूप में चि]नत नहीं कर रहे थे। निम्न मुद्दों पर उनकी स्पष्ट अवस्थिति नहीं रही - द्ध1त्र्ञ् चीन को विश्व समाजवादी क्रान्ति का आधार मानना, द्ध2त्र्ञ् मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को मार्गदर्शक मानना, द्ध3त्र्ञ् दीर्घकालीन लोक यु) को भारतीय क्रान्ति के रास्ते के तौर पर स्वीकार करना, द्ध4त्र्ञ् चुनावों का बहिष्कार। इन पर स्पष्ट अवस्थिति न होने के अलावा उनकी यह पक्की राय रही कि उन्हें अभी तुरन्त माकपा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फ़िर भी के भीतर रहते हुए गुप्त राज्य कमेटी बनाने वाले डीवी, टीएन, सीपीआर को अन्ततोगत्वा माकपा से बाहर निकलना ही पड़ा।

प्रदेश के नेतृत्व पर श्रीकाकुलम जिला कमेटी का का़्ी दबाव रहा कि वह सशस्त्र संघर्ष शुरू करने व आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन तथा सहयोग दे। नेतृत्व ने आधे-अधूरे मन से आन्दोलन का नेतृत्व करना स्वीकार तो कर लिया, पर सशस्त्र संघर्ष छेड़ने में कई अड़चनें डालीं। एआईसीसीसीआर में शामिल होने में उन्हें हिचक थी। श्रीकाकुलम के कामरेडों में भारी दबाव के कारण और 'नक्सलबाड़ी एकजुटता कमेटी' के विचारों पर

गौर करने के बाद डी0वी0 के नेतृत्व वाली प्रदेश कमेटी ने मात्र एक मत के बहुमत से एआईसीसीसीआर में शामिल होने का फैसला किया। अन्ततोगत्वा वे नवम्बर 1968 में शामिल हुए। हालांकि सघन चर्चा के बाद वे एआईसीसीसीआर के बुनियादी बिन्दुओं पर सहमत हुए, फिर भी बाद के घटनाक्रम ने साबित किया कि चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर, क्रान्किारी परिस्थति मौजूद होने के सवाल पर तथा जन युद्ध से सम्बन्धित कार्यनीति पर, पार्टी गठन की पद्धतियों आदि पर उनके कई इतराज़ थे।

डीवी–टीएन–सीपीआर का व्यवहार उनकी अपनी सोच के मुताबिक ही जारी रहा। इसके फलस्वरूप एआईसीसीसीआर को अपनी आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी के साथ रिश्ते तोड़ देने पड़े। एआईसीसीसीआर की राजनीतिक समझदारी के विपरीत टीएन ने (1) केरल के क्रान्तिकारियों द्वारा पुलिस थाने पर छापा मारे जाने की निंदा की, (2) श्रीकाकुलम सशस्त्र संघर्ष को केवल नाममात्र का समर्थन दिया, (3) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा से इस्तीफे देने में ढुलमुलन दिखाया।

ये तीनों बातें चूँकि एआईसीसीसीआर की बुनियादी समझदारी के विरुद्ध थीं, फरवरी 1969 में अखिल भारतीय कमेटी ने एपीसीसीसीआर से रिश्ता तोड़ने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद डीवी, टीएन, सीपीआर ने अपनी एपीसीसीसीआर बनायी।

बहुत जल्द ही वे श्रीकाकुलम के सशस्त्र संघर्ष का विरोध करने लगे। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ केवल आत्म–रक्षा तक सीमित रहने और राजकीय बलों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष न करने की वकालत की। उन्होंने सैनिक संरचनाओं को केवल आत्म–रक्षा टुकड़ियों तक सीमित रखने, सशस्त्र छापामार दस्ते न बनाने और छापामार युद्ध छेड़ने के लिए दुश्मन से हथियार न छीनने के पक्ष में बातें रखीं। अप्रैल 1969 में उन्होंने अपना 'तात्कालिक कार्यक्रम' जारी किया।

डीवी–टीएन–सीपीआर ग्रुप ने गोदावरी घाटी में सशस्त्र आत्म–रक्षा दस्ते बनाये। लेकिन जल्द ही उनमें तत्काल जमींदारों के भी खिलाफ हथियार उठाने के सवाल पर फूट पड़ी। सीपीआर ने अपनी पार्टी बनायी और सशस्त्र आत्म–रक्षा दस्ते बनाये।

माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र

एमसीसी नक्सलबाड़ी संघर्ष का समर्थन करते हुए कुछ कार्यनीतिक मतभेदों तथा पार्टी गठन की पद्धति के सवाल पर मतभेद के कारण सीपीआई (एमएल) में शामिल नहीं हुआ। इसके इतिहास को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है।

पहला चरण 1964 से 1968 तक का है और तब से शुरू होता है जब माकपा

की पहली काँग्रेस में संशोधनवादी लाइन स्थापित हुई। **दक्षिण देश** ग्रुप द्धइसके द्वारा निकाले जा रहे बांग्ला पत्रिका के नाम से ग्रुप का यह नाम पड़ाऋ के रूप में कार्य करते हुए इसने संशोधनवादी लाइन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और क्रान्तिकारी लाइन विकसित करने के लिए गुप्त क्रान्तिकारी केन्द्र स्थापित किया। अमूल्य सेन और कन्हाई चटर्जी इस ग्रुप के दो मुख्य संस्थापक रहे। यह मुख्यतः विचारधारात्मक संघर्षों का दौर रहा। साथ ही साथ प्रमुख कामरेड ट्रेड यूनियन मोर्चे, छात्र मोर्चे एवं नौजवान मोर्चे पर नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते रहे। नेतृत्वकारी कामरेड मजदूरों और किसानों के आन्दोलनों से भी जुड़े रहे। इस दौर में उठाये गये सै)ान्तिक मुद्दे इस प्रकार रहे – द्ध1ऋ राजनीतिक और सांगठनिक क्षेत्रें में संशोधनवादियों से स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना, द्ध2ऋ भारतीय क्रान्ति के रोज़ाना क्रान्तिकारी व्यवहार को सि)ान्त के साथ जोड़ना, द्ध3ऋ राजनीतिक एवं कार्यनीतिक लाइन को महज औपचारिकता के तौर पर विकसित करने के बजाय इसे सक्रियता के विभिा क्षेत्रें में ठोस आकार देना, द्ध4ऋ इन क्रान्तिकारी नीतियों, कार्यशैली तथा कार्यप)ति के आधार, और क्रान्तिकारी संघर्षों के दौरान तथा क्रान्तिकारी सि)ान्त के मार्गदर्शन से क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण करना।

दूसरा चरण 1969 से 1978 तक का है। यह पार्टी की लाइन, नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने का दौर रहा। यह **हलाल कृषि क्रान्तिकारी प्रतिरोध यु)ह** स्थापित करने के रास्ते की ओर बढ़ने का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का दौर रहा। इसका सूत्रपात 'दक्षिण देश' द्धहिन्दी में **'लाल पताका'**ऋ में **'भारतीय क्रान्ति का परिप्रेक्ष्य'** और **'भारतीय क्रान्ति की कार्यनीतिक लाइन – परिप्रेक्ष्य'** शीर्षक दो लेखों के प्रकाशन से और 20 अक्टूबर 1969 को एमसीसी के गठन से हुआ। इस आधार पर सुन्दरबन, 24 परगना, हुगली, मिदनापुर, कांक्सा, गया और हजारीबाग में काम शुरू किया गया।। इनमें सबसे ज्यादा उत्साहव)र्क कांक्सा और हजारीबाग के अनुभव रहे। वहाँ मजदूरी बढ़ाने,
़सल जब्त करने, खाद की समस्या, जमींदारों से अनाज जब्त करने, विभिा रूपों का राजनीतिक एवं सामाजिक उत्पीड़न और ऐसे अन्य मुद्दों पर व्यापक आन्दोलन खड़ा किया गया। व्यापक जन आन्दोलन भी खड़ा किया गया, कुछ कुख्यात जमींदारों को सज़ा द गयी और दुश्मन को निःशस्त्र तथा जनता को सशस्त्र करने के लिए कदम उठाये गये। कुछ छापामार दस्ते और आत्म-रक्षा दस्ते खड़े किये गये। कांक्सा के संघर्षों के माध्यम से पहली बार क्रान्तिकारी किसान कमेटियों की अवधारणा विकसित हुई। 1972-77 के दौर में आन्दोलन को भारी दमन का सामना करना पड़ा।

तीसरा चरण 1979 से 1988 तक का है। यह दूसरे चरण के सकारात्मक व

नकारात्मक सबक लेने और सि)ान्त तथा व्यवहार दोनों को ही समृ) करने का दौर रहा। इस चरण में एमसीसी ने बिहार पर ध्यान केन्द्रित किया। जन सेना ओर आधार इलाके के निर्माण के परिप्रेक्ष्य के साथ बिहार-बंगाल स्पेशल एरिया कमेटी ढ्ढविशेष इलाका कमेटीत्र्व की स्थापना की गयी, 'क्रान्तिकारी किसान संघर्षों के लिए तैयारी कमेटी' का गठन किया गया और जल्द ही 'क्रान्तिकारी किसान परिषदें' उभर आयीं। इस चरण में जुझारू संघर्ष विकसित हुए तथा जमींदारों की सत्ता ध्वस्त की गयी, हजारों एकड़ भूमि जब्त कर भूमिहीनों में बाँटी गयी और जमींदारों की सम्पत्ति जब्त कर वितरित की गयी। मगर इसी दौर में संगठन के दो संस्थापक सदस्य गुजर गये। अमूल्य सेन मार्च 1981 में और कन्हाई चटर्जी जुलाई 1982 में।

अब यह आन्दोलन हजारीबाग, गिरिडीह, गया, औरंगाबाद सहित बिहार के अनेक जिलों तक विकसित हो चुका है। आज बिहार में एमसीसी एक शक्तिशाली चुनौती बना हुआ है।

एमएल खेमे मे तीन रुझान

1970 के दशक के उत्तरा) में सीपीआई ढ्ढएमएलत्र्व और अन्य कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ग्रुपों की शक्तियों का मोटे तौर पर तीन रुझानों के तहत स्पष्ट ध्रुवीकरण हुआ –

पहला रुझान – भगौड़े एसएनएस, कानू सन्याल, असीम चटर्जी जैसे संशोधनवादियों, टीएन-डीवी-सीपी रेड्डी आदि जैसे दक्षिणपंथी विपथगामियों ढ्ढभटकाव पैदा करने वालोंत्र्व का है। इन सभी ने नक्सलबाड़ी आन्दोलन पर और कामरेड चारू मजुमदार पर वैमनस्यपूर्ण प्रहार किये। वे पार्टी की बुनियादी लाइन और कार्यक्रम से भटक गये। 1970 के दशक के अन्त तक आते-आते इन सभी की पार्टियाँ संसदीय चुनावों में भागीदारी करने लगीं। इनमें से कुछ ने सशस्त्र दस्ते बनाये तो रखे, पर सुधारवादी व्यवहार में ये आकण्ठ डूब गये और इनका राजनीतिक सत्ता हथियाने के इरादे से अब कोई ठोस व्यवहार नहीं रह गया। ढ्ढपिछले दो दशकों से इस रुझान में लगातार टूट देखी गयी है जिससे ये विसर्जन, विघटन एवं निष्क्रियता और विश्वासघात तक के शिकार हो गये हैं।त्र्व

दूसरा रुझान – यह वामपंथी दुस्साहसवादी ग्रुपों का रहा। इसमें महादेव मुखर्जी के नेतृत्व वाला तथा अन्य लिन प्याओ के पक्षधर ग्रुप और कुछ लिन प्याओ-विरोधी ग्रुप भी शामिल हैं, जैसे कामरेड जौहर की शहादत के बाद कुछ वर्षों तक विनोद मिश्र ग्रुप। यही वीएम ग्रुप धीरे-धीरे 1980 के दशक की शुरुआत तक आते-आते अपने विपरीत

में बदल गया और संसदीय लाइन पर चल पड़ा। ये वाम दुस्साहसवादी ग्रुप जड़सूत्रवादी तरीके से स्फाये की कार्यनीति को लाइन मानते रहे, सशस्त्र संघर्ष के अलावा संघर्ष व संगठन के अन्य किसी भी रूप को अपनाने की आवश्यकता को खारिज़ करते रहे और अतीत की गलतियों से सबक लेने से इन्कार करते रहे। आज यह रुझान समाप्तप्राय हो चुका है। इनमें से कई कामरेड दुश्मन के हाथों मारे गये या निष्क्रिय हो गये, जबकि बचे हुए पहले या तीसरे रुझान में शामिल हो गये।

तीसरा रुझान – यह उन एमएल शक्तियों का है जिन्होंने मूलतः मार्क्सवादी–लेनिनवादी नजरिये से अतीत का सार–संकलन किया, नक्सलबाड़ी आन्दोलन और सीपीआई द्धएमएलऋ की लाइन के सभी सकारात्मक बिन्दुओं को आत्मसात किया, वाम–संकीर्णतावादी कार्यनीति को त्याग दिया और जन दिशा के आधार पर गम्भीर क्रान्तिकारी व्यवहार में जुट जाना शुरू किया। कामरेड केएस के नेतृत्व वाली सीपीआई द्धएमएलऋ की आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी, पंजाब के कामरेड शर्मा, पश्चिम बंगाल के कामरेड सुनीती घोष तथा बाद की सीपीआई द्धएमएलऋ द्धपीयूऋ और कुछ अन्य ग्रुप इस रुझान में शामिल रहे। ये सभी संगठन मूल सीपीआई द्धएमएलऋ में शामिल रहे।

सीपीआई द्धएमएलऋ के ग्रुपों के अलावा इस तीसरे रुझान में अन्य महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी संगठन एमसीसी भी शामिल रहा। सामयिक पराजय के बाद शुरुआती दौर में इस तीसरे रुझान में शामिल शक्तियाँ अपेक्षाकृत छोटी रहीं। लेकिन दीर्घकालिक जनयु) की सही लाइन पर अमल करते हुए और उपरोक्त सभी रुझानों से आयी क्रान्तिकारी शक्तियों से एकता करते हुए ये अन्ततोगत्वा माओवादी खेमे की दो प्रमुख धाराओं में सुदृढ़ हो गये – सीपीआई द्धएमएलऋ का प्रतिनिधित्व करने वाली सीपीआई द्धएमएलऋ द्धपीडब्ल्यूऋ की धारा और एमसीसीआई की धारा।

8वीं काँग्रेस में चुनी गयी सीसी के भंग हो जाने के बाद और किसी नयी सीसी के अस्तित्व में न होने के कारण 9वीं काँग्रेस आयोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति रूसी क्रान्ति व चीनी क्रान्ति के इतिहास में कहीं भी सुनी नहीं गयी है। सामयिक पराजय के बाद लम्बे समय तक नेतृत्व में निरन्तरता नहीं रही। सीसी के अस्तित्व में न होने के कारण अखिल भारतीय पैमाने पर पार्टी को एकताब) करना लम्बे समय तक महज एक मनोगत चाहत बनकर रह गयी।

1972 के बाद के दौर में ग्रुपों एवं व्यक्तियों की ॣट और एकता भारतीय क्रान्तिकारी राजनीति की चारित्रिक विशेषता बन गयी। मा–ले–मा विचारधारा से सम्बन्धित मामलों में जड़सूत्रवाद, सांगठनिक मामलों में तंग संकीर्णता, नेतृत्व के बीच वाम या

दक्षिणपंथी अवसरवाद और निम्न–पूँजीवादी अहंकार के कारण कोई भी दो ग्रुप स्थायी क्रान्तिकारी एकता हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते रहे।

सामयिक पराजय का सार–संकलन और उसके सबक

1980 के बाद अपने आन्दोलन की समीक्षा करने और इससे उचित सबक निकालने से पहले हमें नक्सलबाड़ी जनउभार, नक्सलबाड़ी के बाद देशभर में आये ऊान और बाद की सामयिक पराजय की उपलब्धियों एवं खामियों और शिक्षाओं को याद करना चाहिए। **हमारी आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट द्धअतीत का सार–संकलन करते हुए सशस्त्र संघर्ष की राह पर विजयपूर्वक आगे बढ़ेंऋ** जो कि हमारी पार्टी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, में पार्टी के गठन से लेकर 1972 तक के दौर सार–संकलन है। इसे 1974 में आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी ने तब लिखा था जब वह केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी ऽसीओसी, सीपीआई द्धएमएलऋ३ में रही। इसे 1980 में सीपीआई द्धएमएलऋद्धपीडब्ल्यूऋ के गठन के समय समृ) किया गया। आठवीं काँग्रेस की सकारात्मक उपलब्धियों को इस रिपोर्ट **(एससीआर)** में इस प्रकार दर्ज किया गया है –

(1) भारतीय समाज के स्वरूप का सही आकलन।

(2) भारतीय समाज के बुनियादी अन्तरविरोधों तथा प्रधान अन्तरविरोध का सही विश्लेषण।

(3) वर्तमान भारतीय क्रान्ति की मंजिल तथा चरित्र का सही आकलन।

(4) राजनीतिक रणनीति, यानी कौन हमारे दोस्त हैं और कौन दुश्मन, का सही आकलन।

(5) भारतीय क्रान्ति के रास्ते की सही समझदारी।

(6) संशोधनवादी पार्टियों के प्रभाव को ध्वस्त किये बिना भारत की जनवादी क्रान्ति में जनता की जीत नामुमकिन है – इस बात को समझना।

(7) सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद भी साम्यवाद का मुखौटा ओढ़े हुए दुनिया की जनता का खतरनाक दुश्मन बनकर उभरा है – इस बात को समझना।

(8) अलग होने सहित आत्म निर्णय के लिए संघर्षरत सभी राष्ट्रीयताओं की जनता को एकताब) करने के मकसद से चलते हुए यह समझना कि राष्ट्रीयता के सवाल का समाधान लेनिनवादी सि)ान्त के अनुसार करने की जरूरत है।

(9) यह समझना कि मुक्ति केवल सशस्त्र संघर्ष से ही सम्भव है और जन सेना

के बिना जनता के पास कुछ भी नहीं होता।

(10) मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में स्वीकार करना।

अतः **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** का निष्कर्ष यह रहा कि इन सकारात्मक पहलुओं के कारण भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर निम्न प्रभाव पड़ा - द्ध1ऋ संशोधनवाद पर करारी चोट की गयी, द्ध2ऋ सशस्त्र संघर्ष कार्यसूची पर आया, द्ध3ऋ वर्तमान सशस्त्र संघर्ष ने आम तौर पर शोषित जनता और युवाओं की सोच में क्रान्तिकारी बदलाव लाया, द्ध4ऋ तीखे संघर्षों के इलाकों में लोग यु) में तप गये, द्ध5ऋ इससे देशभर में संघर्ष के अधिक जुझारू रूपों को बढ़ावा मिला और अब तक पूँजीवादी नेतृत्व द्वारा संघर्ष के रूपों पर लगायी गयी सीमाएँ निरर्थक हो गयीं, देशभर में पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी।

भारतीय क्रान्ति के चरित्र तथा मंजिल की समझदारी और इसकी राजनीतिक तथा सामयिक रणनीति सही तो रही, पर इस रणनीति को लागू करने वाली कार्यनीति, कार्यप)ति, कार्यशैली मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के अनुरूप नहीं रही। आठवीं काँग्रेस के समय हमारी पार्टी की समझदारी के इन दोषपूर्ण पहलुओं के कारण बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े हैं। संक्षेप में, एससीआर के अनुसार हमारी उस वक्त की समझदारी के नकारात्मक पहलू बिन्दुवार इस प्रकार हैं -

द्ध1ऋ युग की प्रकृति के बारे में गलत समझदारी।

द्ध2ऋ उस वक्त की अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्थितियों का गलत आकलन।

द्ध3ऋ पार्टी संगठन की उपेक्षा। दूसरे शब्दों में कहें, तो ऐसा रवैया रहा कि क्रान्ति की विजय के लिए केवल क्रान्तिकारी स्थितियों का होना ही काफी है।

द्ध4ऋ उपरोक्त गलत समझदारी और आकलनों के ही अनुरूप संघर्ष में अपरिपक्व आ]वान तथा नारे जारी किये जाने।

द्ध5ऋ यह सोचना कि वर्ग दुश्मनों का सफाया संघर्ष का एकमात्र तरीका है।

द्ध6ऋ जन संगठनों और जन संघर्षों के निर्माण को संशोधनवाद के बराबर समझने का गलत दृष्टिकोण।

द्ध7ऋ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्गों, धनी किसान और संयुक्त मोर्चे के प्रति गलत रवैया।

द्ध8ऋ शहरों में छापामार यु) पर अनुचित जोर।

(9) नेतृत्व के सभी स्तरों पर नौकरशाही।

(10) किसी व्यक्ति का क्रान्तिकारी प्राधिकार होना चाहिए, यह गलत दृष्टिकोण।

एससीआर के सबक और कार्यभार

(1) मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा हमारी चिन्तन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला सै)ान्तिक आधार है।

(2) संशोधनवाद को रेशा-रेशा परास्त करना होगा।

(3) पार्टी की आम कार्यदिशा (लाइन) पर दृढ़ रहें।

(4) हमारी समझदारी में अतीत की गलतियों को दूर करें और दृढ़ता के साथ वामपंथी भटकावों को परास्त करें।

(5) संयुक्त मोर्चे के काम के महत्व पर जोर दिया जाय। सचेत रहें कि संयुक्त मोर्चे के मामले में ह्संकीर्णतावादी रुझानों का विरोध करने के नाम पर अब दक्षिणपंथी भटकाव का शिकार होने का खतरा है।ह

(6) ह्जन संगठन और जन संघर्षोंह का निर्माण करें(इसका मुख्य मकसद होगा ह्क्रान्ति के लिए जनता को संगठित करना।"

(7)नये किस्म की पार्टी खड़ी करें और ह्मार्क्सवादी प)ति से आन्तरिक पार्टी संघर्ष चलायें।ह

(8) पार्टी के भीतर हर तरह की आवश्यक शिक्षा दें, खासकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद ह्तब इसे माओ विचारधारा कहा जाता थाäृ के बारे में।

(9) सभी सच्चे मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी संगठनों व ग्रुपों के एकीकरण के लिए काम करें।

(10) आंशिक संघर्षों को पूरी तरह नकार न दें और इन्हें हथियारबन्द संघर्ष के साथ जोड़ें।

(11) लाल सेना और आधार इलाकों का निर्माणे करें।

समग्रता में एससीआर ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को पुनर्जीवित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसने भारत के सच्चे कम्युनिस्ट कान्तिकारियों के पुनः एकीकरण के लिए आधार तैयार किया। **पहले,** इसने पार्टी को अब तक के वाम दुस्साहसवादी रुझान से बाहर निकालने में मदद की और नयी शक्तियों को दोबारा आन्दोलन खड़ा करने के लिए शिक्षित किया तथा पार्टी को सही आधार पर पुनर्गठित करने के लिए मदद पहुँचायी। **दूसरे,** इसने सामयिक पराजय के दौर में हावी रहे दक्षिणपंथी अवसरवाद के साथ ही वाम संकीर्णता के खिलाफ, विशेषकर पहले रुझान के खिलाफ राजनीतिक वाद-विवाद में मदद पहुँचायी। **तीसरे,** इसने आन्दोलन के पुनरुत्थान के लिए सै)ान्तिक आधार प्रदान करने में मदद पहुँचायी। **चौथे,** इससे पिछली उपलब्धियों

की, आलोचनात्मक रूप से ही सही मजबूती के साथ हिमायत करते हुए इसने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की पुनः एकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया। और **आखिरी** बात यह कि कामरेड सीएम की भूमिका पर सन्तुलित नजरिया अपनाते हुए इसने कम्युनिस्ट आन्दोलन में नेतृत्व की भूमिका पर युक्तियुक्त समझदारी बनाने में मदद की।

भारतीय क्रान्ति में कामरेड सीएम की भूमिका

कामरेड सीएम की शहादत के तुरन्त बाद कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी खेमे में मूलतः दो गलत रुझान रहे – एक ने उनका निन्दा गान गाते हुए आन्दोलन के सामयिक पराजय के लिए अकेले उन्हीं को दोषी ठहराया, जबकि दूसरे ने जितनी भूलें हुई थीं उनमें से किसी को भी देखने से इन्कार किया। **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** ने इन दोनों रुझानों का निषेध किया।

सीएम के प्रमुख योगदान

आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट (एससीआर) ने कामरेड सीएम को जनयुद्ध की राजनीति को पहली बार देश में लाने वाले महान मार्क्सवादी–लेनिनवादी के रूप में विश्लेषित किया। उनके सकारात्मक पहलुओं को दर्ज करते हुए **एससीआर** में कहा गया है कि "अतीत में 40 वर्षों तक पार्टी में मजबूती से जड़ जमा चुके संशोधनवाद के खिलाफ विद्रोह करने वालों में कामरेड सीएम सर्वप्रथम रहे।" इसमें यह भी कहा गया है कि मूलतः उन्होंने ही 'महान बहस' में तमाम कामरेडों को चीन के रास्ते पर चलने और भारतीय क्रान्ति के ठोस अमल में मा–ले–मा विचारधारा लागू करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया। इन्हीं सकारात्मक योगदानों की हिमायत करते हुए आन्दोलन को फिर से खड़ा करना और फिर मजबूती हासिल करना सम्भव हो पाया।

कामरेड सीएम ने मुख्यतः 1940 के दशक से जलपाईगुड़ी के किसानों के बीच काम किया और उनके बीच लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान पाया। जब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी हुआ तभी से वे भूमिगत हो गये। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही जब पार्टी को प्रतिबन्धित किया गया, तो वे किसानों बीच के गुप्त रूप से सांगठनिक कार्य करते रहे। 1942 में वे भाकपा की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सदस्य बने। 1943 के भयंकर अकाल के दौरान उन्होंने जलपाईगुड़ी में फसल जब्त करने का आन्दोलन संगठित किया। 1946 में उन्होंने तेभागा आन्दोलन में भाग लिया और उत्तरी बंगाल में किसानों के जुझारू संघर्ष संगठित किये। इस आदोलन ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और सशस्त्र किसानों द्वारा क्रान्तिकारी आन्दोलन विकसित

करने की उनकी सोच को आकार दिया। बाद में उन्होंने दार्जिलिंग जिले के चाय बागान मजदूरों के बीच काम किया।

1956 के पालघाट काँग्रेस में पार्टी के साथ उनके विचारधारात्मक मतभेद बढ़ गये। भारत–चीन युद्ध के दौरान उन्हें फिर से जेल हुई। पार्टी की फूट के समय वे माकपा में शामिल तो हुए, मगर उन्होंने नेतृत्व को असली निर्णायक विचारधारात्मक सवालों से बचते हुए पाया। तभी उन्होंने **'ऐतिहासिक आठ दस्तावेज'** लिखे और ये भारत में माओवादी आन्दोलन के उदय के लिए राजनीतिक–विचारधारात्मक आधार बन गये।

वे उन चन्द क्रान्तिकारियों में से प्रथम रहे जिन्होंने लगातार विकसित होती जा रही क्रान्तिकारी परिस्थिति के प्रतीक और भारत में सामन्ती तथा दलाल पूँजीपति वर्गों से राज्य सत्ता छीनने के इरादे से किसानों को सशस्त्र क्रान्ति की पूर्वबेला के तौर पर नक्सलबाड़ी के किसान उभर की अगुवाई की।

भारत की जनवादी क्रान्ति में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद लागू करने और क्रान्ति के लिये सही रास्ता सूत्रबद्ध करने में उन्होंने मुख्य भूमिका अदा की। 'महान बहस' में आधुनिक संशोधनवाद से लड़ने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिपादित कार्यदिशा का समर्थन करने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे देश में माओवादी विचारधारा लाने वाले अगुवा कामरेडों में रहे। देश के अनेक हिस्सों में चल रहे किसानों के सशस्त्र क्रान्तिकारी संघर्षों के बीच तालमेल करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एआईसीसीसीआर की स्थापना में पहल की। नक्सलबाड़ी से प्रेरित किसान क्रान्ति ओर सीपीआई (एमएल) की स्थापना में हिस्सेदारी करने के इच्छुक सभी लोगों को साथ लाने में उनकी मुख्य भूमिका रही।

फिर भी, इस सकारात्मक भूमिका के बावजूद कामरेड सीएम की कुछ गंभीर खामियाँ रहीं। **एससीआर** में इन खामियों को सही तरीके से चिह्नित करते हुये कहा गया है कि **"एआईसीसीसीआर की स्थापना के बाद जब नक्सलबाड़ी की लपटें देश के कई हिस्सों तक फैलती रहीं और संघर्षों में एक के बाद एक जीत हासिल होती गयी, तो कामरेड सीएम में कुछ अहंकार भी विकसित हुआ। उनके इर्द–गिर्द के कुछ कामरेडों द्वारा गैर–जरूरी बखान किये जाने और गलत तथा अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्ट पेश किये जाने के कारण यह और भी बढ़ा। इस तरह उन्हें सामूहिक निर्णयों के बजाय अपने ही व्यक्तिगत निर्णयों में ज्यादा विश्वास होता गया।"** (**एससीआर**, पृष्ठ 44, 45)

फिर भी भारतीय क्रान्ति में उनके भारी योगदान को देखते हुए **एससीआर** का निष्कर्ष यह है कि **"प्रमुख रूप से वे मार्क्सवादी– लेनिनवादी और महान क्रान्तिकारी रहे; शोषित जनता के सबसे प्रिय नेता जिन्होंने भारतीय क्रान्ति को सही रास्ते पर लाया।"** (पृष्ठ 46)

पार्टी को पुनर्गठित करने के प्रयास

नवम्बर 1972 तक आते–आते 12–सदस्यीय आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी में से केवल एक साथी ही बचे रहे जो तमाम शक्तियों को दोबारा एकत्रित कर सकते थे। शेष या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार थे। कामरेड कोण्डापल्ली सीतारमैया ने राज्य के कुछ नेतृत्वकारी सदस्यों के साथ मिलकर क्षत–विक्षत इकाइयों में से बहुतों को फिर से संगठित किया। इससे पहले मार्च 1972 में राज्य कमेटी के तीन सदस्य मौजूद रहे (इनमें दो नवम्बर में गिरफ्तार हो गये)। इन्होंने नक्सलबाड़ी के दौर की क्रान्तिकारी सारवस्तु को बरकरार रखते हुए भूलों को सुधारने का प्रयास किया। इस कमेटी ने यथासम्भव जनता के जुझारू संघर्ष खड़े करने और जन संगठन तैयार करने का फैसला किया। इसने यह भी तय किया कि वर्ग दुश्मनों के सफाये को केवल वर्ग संघर्ष के हिस्से के रूप में ही चलाया जाय।

अगस्त 1973 में पार्टी ने क्रान्तिकारी शक्तियों को लामबन्द करने के लिए अपनी राजनीतिक पत्रिका **'पिलुपू'** (आह्वान) शुरू की। पत्रिका ने राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की अवस्थिति से अवगत कराने के साथ ही सीपीआई (एमएल) के अन्दर और बाहर एपीसीसीसीआर के हमलों का जवाब देने के लिए विचारधारात्मक–राजनीतिक संघर्ष जारी रखी। **'पिलुपू'** ने सीएम की लाइन की हिफ़ाज़त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा तत्कालीन आन्दोलन पर हावी दक्षिण तथा 'वाम' भटकावों का मुकाबला किया। इसने आन्दोलन को सही रास्ते पर ले चलने में महत्वूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही इसने संगठनकर्ता की भूमिका और हमारी आत्मगत शक्तियों को सुदृढ़ करने तथा प्रशिक्षित करने में भूमिका भी निभायी।

अगस्त 1974 में चूँकि राज्य कमेटी का अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का फैसला हुआ। इसमें कामरेड केएस (तेलंगाना क्षेत्र के प्रतिनिधि), हाल में जेल से भाग निकले कामरेड अप्पालासूरी (तटीय आन्ध्र के प्रतिनिधि) और हाल में ज़मानत पर रिहा हुए कामरेड महादेवन (रायलसीमा के प्रतिनिधि) रहे।

आन्ध्र प्रदेश में पार्टी को पुनर्गठित करने के साथ ही साथ केएस के नेतृत्व में एपीपीसी ने कामरेड सीएम की शहादत के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के केन्द्रीय कमेटी सदस्यों से सम्पर्क करने के प्रयास किये। इसने कामरेड महादेव मुखर्जी से सम्पर्क किया जिन्होंने अपने नेतृत्व में केन्द्रीय कमेटी बना ली थी। उनकी बेइन्तहाँ संकीर्णता के कारण उनके साथ संवाद की भी गुंजाइश नहीं रह गयी। केन्द्रीय कमेटी को फिर से स्थापित करने के सवाल पर कामरेड एमएम के साथ व्यापक चर्चा करने का तो सवाल ही नहीं था। 1970 की काँग्रेस में आन्ध्र प्रदेश से चुने गये चार केन्द्रीय कमेटी सदस्यों में से दो मारे जा चुके थे और दो जेल में रहे। जनवरी 1974 में कामरेड केएस पुनर्गठित केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी की बैठक में शरीक हुए। इसमें पंजाब के कामरेड शर्मा (जो सीओसी के सचिव चुने गये), बंगाल के कामरेड सुनीती घोष और बिहार के कामरेड रामनाथ रहे। इनमें कामरेड शर्मा और सुनीती घोष 1970 की काँग्रेस में ही सीसी सदस्य चुने गये थे।

सीओसी ने अतीत का विस्तृत आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन करने, सभी छोटे–बड़े ग्रुपों को जहाँ तक हो सके एक पार्टी में एकताबद्ध करने और फिर काँग्रेस आयोजित कर केन्द्रीय कमेटी का चुनाव करने के प्रस्ताव पारित किये। कुल तीन आत्मालोचनात्मक रिपोर्टें पेश हुईं। सीओसी इन तीन अलग–अलग समीक्षाओं में से किसी पर भी सहमति नहीं बना पायी। सितम्बर 1975 की बैठक में इन सभी समीक्षाओं को वापस लेने और बजाय इसके, कार्यनीतिक लाइन तैयार करने का फैसला हुआ। यह उम्मीद रही कि कार्यनीतिक लाइन से व्यवहार के दौरान एकता मजबूत होगी और समान आत्मालोचनात्मक समीक्षा के लिए यह आधार बनेगा। सघन चर्चा के बाद **'क्रान्ति का रास्ता'** शीर्षक कार्यनीतिक लाइन तैयार तो हुई, पर यह एकता में सहायक नहीं हो पायी। मई 1977 की बैठक में बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों रामनाथ और सुनीती घोष ने इस्तीफा दिया और केएस की गिरफ्तारी के कारण अन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये। इस प्रकार राजनीतिक मतभेदों के कारण सीओसी एक संगठन में बँध नहीं पाया। अब केन्द्र को पुनर्गठित करने के इस पहले प्रयास के ठप्प हो जाने के बाद आन्ध्र प्रदेश के कामरेडों ने अपने प्रदेश में मजबूत कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलन खड़ा करने पर अपनी सारी ऊर्जा केन्द्रित की।

भाग–2

जन युद्ध का फिर से उभरना और फैलनाः 1977–2001

1977 के बाद के ढाई दशकों में सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलन को आन्ध्र प्रदेश, दण्डकारण्य, उड़ीसा, बिहार–झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्टश्के नये–नये इलाकों की ओर धीरे–धीरे पुनर्जीवित होते और फैलते देखा गया। आन्ध्र प्रदेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु इस दौर में श्रीकाकुलम से हटकर उत्तरी तेलंगाना बना। इस दौर में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} औरसीपीआई (एमएल) {पीयू} का गठन और उनके नेतृत्व में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विकास हुआ, जबकि सीपीआई (एमएल) के अधिकांश ग्रुप सुधारवाद, संसदीय पार्टियों या दक्षिणपंथी–अवसरवाद में पतित हो गये।

1972 की सामयिक पराजय का सामना करने पर विस्तृत समीक्षा के जरिये पूर्ववर्ती दौर से सबक लेने के बाद मार्क्सवाद–लेनिनवाद– माओवाद की रोशनी में मुख्यतः सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} और सीपीआई (एमएल) {पीयू} के नेतृत्व में पार्टी धीरे–धीरे दोबारा ताकतवर हो गयी। पूरी पार्टी को नयी समझदारी से शिक्षित किया गया, व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ किया गया और विस्तारित किया गया। इस प्रक्रिया में यह कुछ अन्य सच्ची शक्तियों को एकीकृत कर पायी और अधिक मजबूत केन्द्र स्थापित कर पायी। धीरे–धीरे पार्टी का प्रभाव देश के कई हिस्सों में फैलने लगा। आन्तरिक तौर पर भी यह भीतर से उभर आयी दक्षिणपंथी–अवसरवादी लाइनों को परास्त करते हुए संकटों से उबर पायी। इस तरह यह राजनीतिक तथा विचारधारात्मक रूप से मजबूत होती गयी। पार्टी ने विदेशों में बिरादराना पार्टियों के साथ भी रिश्ते विकसित तथा गहराये। आखिर सीपीआई (एमएल) की दो प्रमुख धाराओं का अगस्त 1998 में विलय हो गया और एकीकृत केन्द्रीय कमेटी के तहत एक पार्टी बन गयी। इस विलय के फलस्वरूप कई अन्य सच्चे क्रान्तिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गये।

दो दशकों में सामन्तवाद–विरोधी किसान क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष में ब्रेकथ्रू करते हुए पार्टी के जन आधार का उल्लेखनीय विकास हुआ। पार्टी छात्रों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं दलितों तथा बुद्धिजीवियों तक में अपना असर फैलाने में कामयाब रही। यह प्रचार, आन्दोलन एवं संघर्षों के जरिये देश के साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन को भी गहरा पायी। कुल मिलाकर, पार्टी का जन आधार मजबूत हुआ और नये क्षेत्रों तक विस्तारित हो गया।

इन दो दशकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन अनेक घुमावदार व टेढ़े–मेढ़े रास्तों से होते हुए विकसित हुआ। पार्टी ने देश में, अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर तथा आन्दोलन में आये बदलावों का विश्लेषण किया, तदनुरूप अपनी कार्यनीति में बदलाव किये और अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा आन्दोलन के हिस्से के रूप में भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाया।

सबसे अहम बात यह है कि दो दशकों के इस दौर में पार्टी ने दुश्मन से हथियार छीनते हुए सशस्त्र छापामार दस्ते विकसित किये और खुद को हथियारों से लैस किया। हथियारबन्द टुकड़ियाँ धीरे–धीरे अपनी मजबूती बढ़ाती गयीं और दुश्मन के आक्रमणों का डटकर मुकाबला कर पायीं। इससे इस पूरे दौर में सशस्त्र संघर्ष टिका रह सका। इस तरह पार्टी देश के कुछ रणनीतिक इलाकों में पीजीए का निर्माण करने और जन सत्ता के निकायों के भ्रूण रूप स्थापित करने में कामयाब हो पायी।

अन्त में, इसने सोवियत तथा देंगपंथी किस्मों के संशोधनवाद और नवसंशोधनवाद के खिलाफ निरन्तर विचारधारात्मक एवं राजनीतिक लड़ाई लड़ी। देश के भीतर इसने दक्षिणपंथी–अवसरवाद के सभी रूपों का विरोध किया और साथ ही मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन का व्यापक प्रचार किया।

अध्याय–4
पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू का पुनर्गठन और विकास

1970 के दशक में आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी में यूँ तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। मगर इसने **आत्मालोनात्मक समीक्षा** को आधार बनाकर पाटी कतारों को वाम दुस्साहसवाद से बाहर निकालने के गम्भीर प्रयास किये। 1977 में सीओसी के मृतप्राय (डिफंक्ट) हो जाने के बाद आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी ने तत्काल अन्य क्रान्तिकारी ग्रुपों के साथ एकता बनाने के प्रयास नहीं किये। पिछले अनुभवों ने यह सीख दी थी कि बिना किसी सार्थक आन्दोलन के, केवल अतीत की समीक्षा को आधार बनाकर एकता के प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसीलिए अब एपीएससी ने अपने **एससीआर** के आधार पर व्यापक क्रान्तिकारी आन्दोलन खड़ा करने पर सारी ऊर्जा केन्द्रित कर दी। नतीजे के रूप में यह केवल छात्रों, युवाओं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मोर्चों पर ही सशक्त

प्रदेशव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं खड़े कर पायी, बल्कि इसने करीमनगर व अदिलाबाद जिलों में भी क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन विकसित किये। इन्हें सशक्त सामन्तवाद–विरोधी संघर्षों के तौर पर न सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में पहचाना जाने लगा। इसके बाद ही एपीएससी ने इस आन्दोलन के सफल विकास के आधार पर एकता प्रयासों की पहल की। आन्दोलन के ज्वार से **आत्मालोचनात्मक समीक्षा** का खरापन पुष्ट हुआ और अब यह एकता प्रयासों के आधार के रूप में काम आ सकी। तभी से **एससीआर** और उसकी शिक्षाओं के बल पर खड़े किये गये आन्दोलन के आधार पर पार्टी यूनिटी तथा सीपीआई (एमएल) की तमिलनाडू राज्य कमेटी जैसे एम0एल0 ग्रुपों ने जब कामरेड केएस के नेतृत्व वाले एपीपीसी से पेशकश की, तो उनके साथ एकता के प्रयास किये गये।

राजनीतिक वाद–विवाद

1972 के बाद के दौर में भारत में मार्क्सवादी–लेनिनवादी खेमें में तीखे राजनीतिक वाद–विवाद चलते रहे। हम सशस्त्र संघर्ष, पार्टी लाइन और कामरेड सीएम पर हमला बोलने वाले एसएनएस, कानू सन्याल, असीम चटर्जी, नागभूषण पटनायक और अन्य नेताओं के खिलाफ लड़े।

इतिहास की उस निर्णायक घड़ी में महान नक्सलबाड़ी के साथ ही अन्य आन्दोलनों और लाइन, जिसका प्रतिनिधित्व सीपीआई(एमएल) करती थी, के ऐतिहासिक महत्व को नकारते हुए क्रान्तिकारी होने का दावा करने वाले इन संशोधनवादियों एवं दक्षिणपंथी–अवसरवादियों का पर्दाफश करना सच्चे क्रान्तिकारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार रहा। अतीत के आत्मालोचनात्म्क मूल्यांकन का काम हाथ में लेते हुए सीपीआई (एमएल) की क्रान्तिकारी लाइन की हिफ़ाजत का कार्यभार केएस के नेतृत्व में एपीएससी ने अपने ऊपर ले लिया। इसने यह काम मुख्यतः 1973 से लेकर अपने मुखपत्र **'पिलुपू'** में छपे राजनीतिक वाद–विवादों के माध्यम से जारी रखा।

इन लेखों में टीएन–डीवी और सीपीआर ग्रुपों की दक्षिणपंथी–अवसरवादी लाइन का पर्दाफाश किया गया। इन ग्रुपों की अवधारणा लम्बे समय तक राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष से परहेज करने व बचने की और संघर्ष को सामन्तवाद–विरोधी जुझारू जन संघर्षों तक सीमित रखने की रही। हमने इन कानूनवादी–सुधारवादी रुझानों को खारिज किया और कहा कि इनका हश्र अन्ततोगत्वा संसदीय चुनावों में भागीदारी करना होगा। 1977 में हम तब सही साबित हुए जब इन ग्रुपों ने अपनी

संसदीय यात्रा शुरू की। दक्षिणपंथी–अवसरवादियों ने जन दिशा को लागू करने के नाम पर वाम लाइन को हमले का निशाना बनाया। लेकिन उन्होंने जन युद्ध तथा सशस्त्र बल से राजनीतिक सत्ता हथियाने के कुंजीभूत कारक का निषेध करते हुए सुधारवादी एवं संशोधनवादी तरीके से जन दिशा लागू करने की बात उठायी। उनके "प्रतिरोध संघर्ष" भी सत्ता हथियाने एवं आधार क्षेत्र स्थापित करने से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे।

हमने महादेव मुखर्जी के लिन–पक्षीय धड़े और वीएम के लिन–विरोधी धड़े, दोनों ही "वाम" दुस्साहसवादी रुझानों की आलोचना की। हमने यह समझाया कि वर्ग दुश्मनों के सफाये की लाइन के नाम पर जन संगठनों तथा जन आन्दोलनों को खारिज करना कैसे गलत है। हमने यह कहा कि वर्ग दुश्मनों का सफाया केवल संघर्ष के तमाम रूपों में से एक है, कि यह "एकमात्र रूप" नहीं है और यही लाइन नहीं है, जैसा कि सेकण्ड सीसी कहती रही।

इन वाम संकीर्णतावादी ग्रुपों ने भी आन्दोलन को भारी नुकसान पहुँचाया, क्योंकि इनके कारण सुधारवादियों एवं दक्षिणपंथी–अवसरवादियों का विरोध करने वाली अधिकांश सम्भावनाशील क्रान्तिकारी शक्तियाँ बर्बाद हुईं। लिन–पक्षीय व लिन–विरोधी ग्रुपों ने एमएल खेमे के बहुत सारे कामरेडों को आकर्षित किया। मगर इन्हें आगे बढ़ाना और दोबारा एकीकृत करना इन ग्रुपों के लिए संकीर्णतावादी लाइन व व्यवहार के कारण सम्भव नहीं था।

सार रूप में कहें, तो दक्षिण और 'वाम' दोनों ही रुझान क्रान्तिकारी जन दिशा को नकारते रहे। पहला रुझान बढ़ते–बढ़ते सुधारवाद और संशोधनवाद तक पहुँच गया, जबकि दूसरा विघटन की ओर।

दक्षिण और 'वाम' रुझानों से, प्रमुखता से दक्षिणपंथी–अवसरवादी रुझान से लड़ते हुए हमने **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** में समेटी गयी समुचित शिक्षाओं को ग्रहण किया और पार्टी लाइन के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए अपनी लाइन को समृद्ध किया। इसके साथ ही **'अपनी कार्यनीतिक लाइन'** में सूत्रबद्ध की गयी सही कार्यनीति को भी विकसित किया।

तेलंगाना क्षेत्रीय सम्मेलन

फरवरी 1977 में पार्टी लाइन पर चर्चा को निष्कर्ष तक पहुँचाने और **'क्रान्ति का रास्ता'** तथा **'एससीआर'** दस्तावेज पारित करने के लिए तेलंगाना क्षेत्रीय सम्मेल आयोजित किया गया। यह बिखरी हुई क्रान्तिकारी शक्तियों के पुनर्गठन और पिछले

पाँच वर्षों के राजनीतिक वाद–विवादों के जरिये नक्सलबाड़ी तथा श्रीकाकुलम के सशस्त्र संघर्षों; कामरेड सीएम और सीपीआई (एमएल) की 8वीं काँग्रेस की क्रान्तिकारी लाइन की हिफ़ाजत के दौर का समापन था।

सम्मेलन ने तेलंगाना में बढ़ते क्रान्तिकारी आन्दोलन की समीक्षा की और नेतृत्व का चुनाव किया। इसने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किये, जैसे– (1) जनता के बीच पार्टी का आधार व्यापक करना, (2) सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए दस्तों को जंगल में भेजना। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के आठ जिलों को दो क्षेत्रों में बाँटा गया और दो क्षेत्रीय कमेटियाँ चुनी गयीं।

कार्यनीति में परिवर्तन – अगस्त 1977 प्रस्ताव

मार्च 1977 के संसदीय चुनावों में फासीवादी इन्दिरा गाँधी बुरी तरह पराजित हो गयी और जनता पार्टी सत्ता में आयी। आपातकाल समाप्त हुआ। जनता पार्टी आपातकाल का विरोध करते हुए और जनवादी अधिकारों की बहाली का अभियान चलाते हुए सत्ता में आयी थी। इसने ज्यादातर क्रान्तिकारियों को ज़मानत पर रिहा किया। पार्टी पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया। इस बदली राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाने और पहले तेलंगाना क्षेत्रीय सम्मेलन में निर्णयों को लागू करने के लिए **'वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और हमारे कार्यभार'** नामक दस्तावेज तैयार किया गया। **"अगस्त प्रस्ताव"** के नाम से जाने गये इस दस्तावेज को विभिन्न जिलों में विस्तृत चर्चा के बाद पारित किया गया। इस दस्तावेज ने इस दौर के लिए पार्टी को उचित कार्यनीति प्रदान की।

1976 में दुश्मन ने राज्य कमेटी सदस्य कामरेड महादेव की हत्या कर दी थी। मार्च 1977 में राज्य कमेटी सचिव कामरेड केएस गिरफ्तार कर लिये गये। राज्य कमेटी में अकेले कामरेड अप्पालासूरी ही बचे रह गये थे। इसलिए अगस्त 1977 में तीन अन्य सदस्यों को लेकर राज्य कमेटी को पुनर्गठित किया गया। कई जिला कमेटियाँ भी गठित की गयीं। उसी वक्त कामरेड अप्पालासूरी गिरफ्तार कर लिये गये। उनके पास **"अगस्त प्रस्ताव"** की प्रति भी मिली और उन्होंने यह बयान दिया कि वे **"अगस्त प्रस्ताव"** से नाइत्तेफ़ाक रखते हैं। नेतृत्व की यह आलोचना करते हुए कि नेतृत्व कार्यनीति बदलने के नाम पर सशस्त्र संघर्ष छोड़ रहा है, कामरेड राऊफ़ और कुछ अन्य साथियों ने जेल में रहते हुए ही पार्टी छोड़ दी।

इतिहास ने सिद्ध किया कि बदली परिस्थिति और आन्दोलन की तत्कालीन

ठोस स्थितियों के अनुरूप अगस्त प्रस्ताव में सूत्रबद्ध कार्यनीति में किया गया बदलाव सही रहा। भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्ताव का विरोध करने वाले दोनों कामरेड अप्पालासूरी और राऊफ़ गलत साबित हुए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि **"अगस्त प्रस्ताव"** में सूत्रबद्ध बदली कार्यनीति के अनुसार तत्कालीन स्थितियों का लाभ उठाकर ही पार्टी आपातकाल के बाद के दौर में समर्थ शक्ति के रूप में विकसित हो पायी। सशस्त्र संघर्ष के विकास को नुकसान पहुँचाने के बजाय बदली कार्यनीति ने सशस्त्र संघर्ष को नये जोश के साथ आगे बढ़ाने के लिए व्यापक जन आधार विकसित किया।

कार्यनीति में बदलाव के अनुरूप 'पीसी' ने अपने आधिकारिक मुखपत्र के रूप में पाक्षिक **'क्रान्ति'** शुरू किया और क्रान्तिकारी साहित्य खुलकर प्रकाशित करना शुरू किया। आरएसयू (रैडिकल स्टूडेण्ट यूनियन) और आरवायएल (रेडिकल यूथ लीग) की मासिक पत्रिका के रूप में **'रेडिकल मार्च'** को कानूनी तरीके से निकाला गया। इन मुखपत्रों ने पार्टी कतारों और छात्रों, युवाओं को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में केन्द्रीय भूमिका निभायी।

"व्यापक आधार वाले एकीकृत जन संगठनों का निर्माण करने के नाम पर जन संगठनों में क्रान्तिकारी राजनीति को हल्का (डायल्यूट) मत करो" और **"आरएसयू की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम पत्र"** शीर्षक दस्तावेजों के मार्फत जन संगठनों को सही क्रान्तिकारी दिशा दी गयी और प्रदेशभर में रैडिकल छात्र एव युवा संगठनों का निर्माण किया गया। **'रैडिकल'** शब्द क्रान्तिकारी का पर्यायवाची बन गया। फरवरी और जून 1978 में आरएसयू और आरवायएल के राज्य सम्मेलन आयोजित किये गये। जनवरी 1978 में राज्य कमेटी ने **'आगामी विधान सभा चुनाव और हमारे कार्यभार'** दस्तावेज जारी किया और चुनाव बहिष्कार अभियान संगठित किया। **'ढपोरशंखी विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करो ! कृषि क्रान्ति के लिए तैयार हो जाओ!'** – इस आह्वान ने प्रदेश भर की उत्पीड़ित जनता को प्रेरित किया। 1978 की गर्मियों की छुट्टियों में राज्य कमेटी ने छात्रों व नौजवानों को देहात के गरीबों के साथ घुलमिल जाने और नयी जनवादी क्रान्ति तथा उसकी धुरी सशस्त्र कृषि क्रान्ति की राजनीति का प्रसार करने के लिए 'गाँव चलो अभियान' में शामिल होने का आह्वान किया। तभी से 1984 तक हर साल छात्रों एवं नौजवानों ने गिरफ़्तारियों तथा पुलिस ज़ुल्म का सामना करते हुए इन अभियानों को चलाया। 1978 के पहले अभियान में करीब 200 छात्र शामिल हुए,

जबकि 1984 तक आते–आते यह संख्या इतनी बढ़ी कि 1100 छात्रों–युवाओं ने 150 प्रचार टीमों में संगठित होकर 2419 गाँवों तक कृषि क्रान्ति की राजनीति पहुँचायी।

क्रान्तिकारी छात्र आन्दोलन के तेज विकास, आन्ध्र प्रदेश के छात्र–युवाओं के उग्र परिवर्तनकारी राजनीतिकरण और देहाती किसान जनता के साथ उनके घुलमिल जाने ने शासक वर्गों की नींद उड़ा दी। आरएसयू प्रदेश के 21 में से 18 जिलों तक फैल गया और विभिन्न मुद्दों पर छात्रों की प्रदेशव्यापी हड़तालें संगठित करता रहा। इसने प्रदेश के बहुत सारे कालेजों के छात्र संघों पर कब्जा कर लिया और साम्राज्यवाद, युद्ध, साम्प्रदायिकता के खिलाफ तथा मजदूर वर्ग, किसान जनता और राष्ट्रीयता आन्दोलन के समर्थन में राजनीतिक आन्दोलन संगठित किये। इसने चुनाव बहिष्कार अभियानों में सक्रिय हिस्सेदारी की। इसने एआईआरएसएफ (अखिल भारतीय रेवोल्यूशनरी स्टूडेण्ट फेडरेशन) गठित करने की पहल की। 1985 की शुरुआत में शासक वर्गों ने छात्रों एवं युवाओं के संगठनों पर चौतरफा हमले शुरू करने के साथ–साथ किसानों एवं मजदूर वर्ग के आन्दोलनों पर भी आक्रामक कारवाइयाँ कीं। तब से लगभग सभी जन संगठन पूर्ण गोपनीयता से काम करने लगे। सितम्बर 1977 से लेकर जन नाट्य मण्डली (जेएनएम) ने भी पूरे प्रदेश में अभियान चलाये। इस पूरे दौर को राजनीतिक अभियानों और छात्र एवं युवा मोर्चों पर संघर्ष एवं सांगठनिक गतिविधियों ने 1978 के मध्य में हुए किसान संघर्षों के लिए जमीन तैयार करने का काम किया।

इस तरह पार्टी ने पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक व साहित्यिक संगठनों के मार्फत मजदूर वर्ग, किसानों, छात्रों व युवाओं के संघर्षों की लहर खड़ी करके आपातकाल के तत्काल बाद के दौर का कारगर तरीके से लाभ उठाया। आपातकाल समाप्त किये जाने से पहले और तत्काल बाद नागरिक अधिकार आन्दोलन में भी तेज़ी आयी। इस दौर में पार्टी की नयी कार्यनीति ने जनता के विभिन्न तबकों के बीच क्रान्तिकारी जन आधार का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार करते हुए और सशस्त्र संघर्ष का स्तर ऊँचा करने की तैयारी करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन का फिर से उभार पैदा करने में बड़ी सहायता की। संघर्ष और संगठन के कानूनी एवं गैर–कानूनी रूपों के बीच कारगर तरीके से मेल किया गया। पार्टी ने दुश्मन की कार्यनीति के अनुरूप खुले, अर्द्ध–खुले तथा गुप्त जन संगठनों और इन रूपों का आपस में उचित तालमेल करते हुए खुले तथा भूमिगत जन कार्यों को संगठित किया। इस दौरान पार्टी ने अपना गोपनीय ढाँचा कायम रखा।

करीमनगर और आदिलाबाद के किसान संघर्षों का ज्वार

जून 1978 में जगित्याल का किसान संघर्ष झंझावत की तरह उठ खड़ा हुआ। तीन महीनों तक सरकार ने क्रूर दमन का दौर चलाया और अक्टूबर में जगित्याल व सिरिसिल्ला तहसीलों को "अशान्त क्षेत्र" घोषित कर दिया। राज्य कमेटी ने इन संघर्षों का विस्तार करने के साथ ही दमन के बीच सुदृढ़ीकरण करने के लिए सम्यक योजना बनायी। नतीजतन थोड़े ही समय में पूरे करीमनगर व अदिलाबाद जिलों में किसान संघर्ष उभर आये। 1979 के अन्त तक छात्र, युवा, मजदूर, किसान और साहित्यिक मोर्चों पर पार्टी कार्य आन्ध्र प्रदेश के कोने–कोने तक पहुँच चुके थे। करीमनगर और अदिलाबाद के किसान संघर्षों की लहर पार्टी को वाम दुस्साहसवादी लाइन से सही क्रान्तिकारी लाइन तक रूपान्तरित करने के उन लम्बे प्रयासों का परिणाम रही, जो फरवरी–मार्च 1972 की राज्य कमेटी बैठक के **प्रस्तावों**, 1974 की **आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट**, जनवरी 1977 के पहले तेलंगाना क्षेत्रीय सम्मेलन और अगस्त 1977 के **प्रस्ताव** के माध्यम से किये गये थे।

जैसे–जैसे क्रान्तिकारी गतिविधियों का विस्तार हुआ, वैसे–वैसे पार्टी में भर्ती बढ़ती गयी। गिरफ्तार किये गये कामरेड रिहा किये गये। इनमें से ज्यदातर साथी विभिन्न संघर्षों से आये थे और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नये थे। जुलाई 1978 में राज्य कमेटी ने सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू किया। यह अभियान पार्टी के सुदृढ़ीकरण में तो सफल हुआ, मगर अंशकालिक कार्यकर्ताओं की स्थानीय पार्टी इकाइयाँ तैयार करने में असफल रहा। इस कमी के बावजूद पार्टी संगठन ने 1977–79 के बीच तेजी के साथ विस्तार किया। 1979 तक आते–आते पार्टी में 120 पेशेवर क्रान्तिकारी (पीआर) काम कर रहे थे। 1978 में सत्यमूर्ति और 1979 में केएस जेलों से बाहर आये और राज्य कमेटी में लिये गये।

1979 के अन्त तक पार्टी के सामने करीमनगर, अदिलाबाद, वारंगल और खम्मम में आधार इलाके स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य के साथ छापामार ज़ोन विकसित करने का फौरी कार्यभार आ उपस्थित हुआ। इस वक्त आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा आन्दोलन मोटे तौर पर चार स्तरों में विभाजित रहा – (1) उत्तरी तेलंगाना के उपरोक्त चार जिले, जहाँ सामन्तवाद–विरोधी संघर्ष तीखे होते जा रहे थे और जहाँ सामन्ती तथा राजकीय आक्रमण से लड़ने की सारी तैयारी पूरी करते हुए छापामार ज़ोन तैयार किया जाना था, (2) तेलंगाना और रायलसीमा के अन्य जिले, जहाँ सामन्तवाद–विरोधी संघर्ष अभी–अभी शुरू हो चुके थे और जिन्हें तीखा किया जाना

था, (3) भिन्न सामाजिक–आर्थिक स्थितियों वाले दक्षिणी तटीय जिले, जहाँ कानूनी अवसरों से लाभ उठाने के प्रयास किये जा रहे थे, खेतिहर मजदूरों एवं गरीबों के बीच राजनीतिक कार्यक्रम तथा कार्य किये जा रहे थे और (4) दीर्घकालीन लोक युद्ध की रणनीति के हिस्से के बतौर कस्बों व शहरों में काम।

पीडब्ल्यू का गठन

सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) का गठन 22 अप्रैल 1980 को एपीएससी और टीएनएससी (आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू की राज्य कमेटियों) के विलय के बाद हुआ। बाद में मई में महाराष्ट्र का सच्चे क्रान्तिकारी शक्तियों का ग्रुप सीपीआई (एमएल) (पीडब्ल्यू) से आ जुड़ा। कर्नाटक में पार्टी के उस वक्त कुछेक सदस्य ही थे। प्रदेशों में पार्टी की स्थिति उस वक्त ऐसी थी –

कामरेड अप्पू को दिसम्बर 1969 में टीएनएससी का सचिव चुना गया (8वीं काँग्रेस में उन्हें सीसी सदस्य भी चुना गया)। पर सचिव बनने के एक साल बाद वे शहीद हो गये। उनकी शहादत और अन्य अनेक नेताओं की गिरफ्तारी तथा शहादत के बाद तमिलनाडू का आन्दोलन विकसित नहीं हो सका। दिसम्बर 1969 में राज्य सम्मेलन आयोजित करने से लेकर 1980 तक टीएनएससी ने अपनी कोई समीक्षा ही नहीं की थी।

1970 के दशक के दौरान तमिलनाडू की पार्टी चार ग्रुपों में बँट गयी। एक धड़ा विनोद मिश्र ग्रुप में शामिल हुआ, तो दूसरा एसएनएस की लाइन पर चल पड़ा। तीसरे ग्रुप ने सीएम की लाइन ली और 1979 तक आते–आते इसने कुछ हद तक जन संगठनों की जरूरत महसूस करना शुरू किया। फिर भी यह ग्रुप मुख्यतः संकीर्णतावादी अवस्थिति लिये हुआ था। 1977 में इस ग्रुप में एक और फूट पड़ी। एक धड़ा कामरेड कन्नामणी के साथ गया और दूसरा कामरेड मणिक्कम के नेतृत्व में गोलबन्द हुआ। अप्रैल 1980 में इस दूसरे ग्रुप की एपीएससी के साथ एकता हुई और पीपुल्स वार पार्टी अस्तित्व में आयी।

1979 में जब एपीपीसी के साथ एकता वार्ता चल रही थी तब कामरेड मणिक्कम के नेतृत्व में धर्मापुरी के किसान आन्दोलन में नयी जमीन तोड़ने की बुनियाद डाली जा रही थी। शुरुआती कार्य दक्षिण अरकोट, त्रिची, तंजोर में किया जा रहा था, जहाँ बाद में किसान संघर्ष फूट पड़े। इसके अलावा हमारा अच्छा–खासा प्रभाव और जनाधार चेन्नई, सेलम तथा मदुरै में भी था। लेकिन नेतृत्व में जन आन्दोलन कैसे खड़ा

किया जाय इस पर स्पष्ट समझदारी न होना और नेतृत्व में संकीर्णता, व्यक्तिवाद, नौकरशाही तथा अराजक संगठन पद्धति होना आन्दोलन के विकास में बड़ी बाधाएँ खड़ी कर रहा था। वीएस के अवसरवाद की जड़े यहीं से तलाशी जा सकती हैं जहाँ पार्टी के साथ अपने मतभेद हल किये बगैर वे ग्रुप में शामिल हो गये।

लेकिन एपीपीसी के साथ एकता वार्ता और जन आन्दोलन के निर्माण, खासकर जन संगठन और जन संघर्षों के निर्माण के बारे में हासिल हुई समझदारी से तमिलनाडू में दूसरी पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह पैदा हुआ। नतीजतन विलय से पहले ही धर्मापुरी में संघर्ष फूट पड़े। 1980 में जब हमने दुश्मन के दमन का सामना किया, तो जन संघर्षों का पहला दौर चला। कुछ सौ गाँवों से सामन्ती शोषण–उत्पीड़न के खिलाफ हजारों लोग लामबन्द किये गये। एमजीआर सरकार का जो दमन शुरू हुआ उसमें कामरेड बालन समेत बीस से ज्यादा कामरेडों की जघन्य हत्या की गयी और वक्ती तौर पर धर्मापुरी–उत्तरी आरकोट के आन्दोलन को सामयिक पराजय का सामना करना पड़ा।

विलय के बाद पूरे प्रदेश में छात्रों, युवाओं, मानवाधिकारों तथा सांस्कृतिक जन संगठनों का निर्माण किया गया। धीरे–धीरे ट्रेड यूनियन कार्य भी बढ़ाये गये। क्रान्तिकारी प्रचार, राजनीतिक गोलबन्दी और जुझारू जन संघर्षों के फलस्वरूप विभिन्न शहरों तथा गाँवों में जन संगठनों का निर्माण किया गया और उनकी ताकत बढ़ती गयी। इस अवधि में हमारा आन्दोलन कुछेक जिलों को छोड़ कर पूरे तमिलनाडू में फैल पाया। चेन्नई में हमारे युवा संगठन के झण्डेतले चुनाव लड़े और कई बड़े–बड़े कारखानों में ट्रेड यूनियन चुनाव जीत लिये। सेलम में पावरलूम मजदूरों की यूनियन बहुत मजबूत बनकर उभरी। मदुरै जैसे कई शहरों में हमारा युवा संगठन बहुत सक्रिय रहा। हमारे सांस्कृतिक संगठन के तहत सैकड़ों बुद्धिजीवी लामबन्द हुए। जन कला मंच के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

धर्मापुरी में हमारी पार्टी अपनी सामयिक पराजय से उबर पायी और जन उभार तैयार किया गया। हजारों लोगों ने सामन्तवाद–विरोधी संघर्षों में भाग लिया। गम्भीर दमन का साहस के साथ सामना करते हुए कामरेड अप्पू–बालन की मूर्तियों का अनावरण करने के लिए हजारों लोगों को लामबन्द किया गया। पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में कुछ सौ कार्यकर्ता काम कर रहे थे। कुल मिलाकर 1984–85 में हमारी पार्टी तथा जन संगठन समूचे तमिलनाडू पर अच्छा प्रभाव डालने की स्थिति में थे।

लेकिन एक ओर एससी में गुटबाजी, सांगठनिक अराजकता, नौकरशाही तथा

राजनीतिक मतभेद और दूसरी ओर सीसी के पहले संकट में वीएस–मणिकम गुट का अवसरवाद तमिलनाडू में आन्दोलन के आगे बढ़ने के सामने अवरोध बन गये। वीएस–मणिकम गुट की अवसरवादी राजनीति और विसर्जनवादी व्यवहार से तमिलनाडू में पार्टी और आन्दोलन तबाह हो गया।

उस वक्त एक तरफ धर्मापुरी में किसान आन्दोलन का तीखा दमन हुआ, तो दूसरी तरफ आन्दोलन में जन उभार देखा गया। आधार क्षेत्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य के साथ छापामार जोन के निर्माण की सुस्पष्ट दीर्घकालीन योजना बनाकर सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत न करना नेतृत्व की गम्भीर कार्यनीतिक गलति रही। जन उभार और कार्यकर्ताओं की भर्ती से लाभ उठाकर हमें सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करनी चाहिए थी। साथ ही तमिलनाडू में समग्र राजनीतिक परिस्थिति और हमारे आन्दोलन का विकास इसके लिए अनुकूल था। लेकिन तमिलनाडू के आन्दोलन के मार्गदर्शन में सीसी नेतृत्व की तत्कालीन विफलता से वहाँ की पार्टी और आन्दोलन के विकास को गम्भीर नुकसान पहुँचाया। साथ ही अवसरवादी नेतृत्व को बेनकाब न कर पाने और तमिलनाडू के बहुसंख्यक कामरेडों का दिल न जीत पाने के लिए यह भी एक कारण रहा।

सार–संक्षेप के रूप में कहें तो 1980 के दशक के पहले पाँच वर्षों में सश्सस्त्र संघर्ष को शुरू करने और क्रान्तिकारी आन्दोलन को छलांग के साथ आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर होने के बावजूद वीएस–मणिकम गुट के षड़यन्त्रकारी नेतृत्व के विश्वासघात के कारण आन्दोलन गहरी खाई में गिर पड़ा। सीसी को समुचित कार्यनीति अपनाते हुए आन्दोलन का मार्गदर्शन करना चाहिए था।

सीपीआई (एमएल) (पीडब्ल्यू) के गठन के बाद शुरू से ही व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संकीर्णतावाद और सांगठनिक अराजकता का शिकार रही। सामूहिक चिन्तन और व्यवहार के साथ यह सामूहिक नेतृत्व के रूप में कभी कार्य नहीं कर पायी। 1987 में विश्वासघातियों को उखाड़ फेंकने के बाद गठित हुई एससी समान समझदारी वाले सामूहिक नेतृत्व के महत्व को समझ नहीं पायी। इसने कमटी में मौजूद व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संकीर्णतावाद जैसे उन गलत रुझानों से दृढ़तापूर्वक संघर्ष नहीं किया जो सामूहिक चिन्तन और एकीकृत कार्यों के विरोधी रहे। समग्रता में यह प्रदेश कमेटी भी समान समझदारी वाली नेतृत्वकारी कमेटी के रूप में विकसित नहीं हो पायी। 2002 में शुद्धिकरण अभियान आयोजित करने तक, यानी लम्बे समय तक सीसी भी यह समझ नहीं पायी कि टीएनएससी ऐसी नेतृत्वकारी कमेटी के रूप में

विकसित हो चुकी है। टीएनएससी को विकसित करने के लिए सीसी ठोस मार्गदर्शन नहीं कर पायी। इसके लिए जो भी प्रयास किये गये वे इस कार्यभार को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे।

महाराष्ट्र में नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के संघर्षों की ओर आकर्षित हुए कुछ कामरेडों के एक साथ जुट जाने पर 1972 में पार्टी इकाई उभरीं। महाराष्ट्र के तत्कालीन नेतृत्व ने जब एसएनएस–सीपीआर विलय में हिस्सेदारी की, तो 1975 में कुछ कामरेड इसके विरोध में टूट कर अलग हो गये। इन्होंने अलग इकाई बना ली। इस इकाई ने करीमगनगर ओर अदिलाबाद के संघर्षों से प्रभावित होकर एपीएससी के साथ सम्पर्क स्थापित किया। इस इकाई ने पीडब्ल्यू में शामिल होकर जून 1980 में 'बम्बई नगर सम्मेलन' आयोजित किया, जिसने पार्टी के बुनियादी दस्तावेज पारित किये।

मई 1977 में जब सीओसी समाप्तप्राय हो गयी तब तक एपीएससी ही इसका मुख्य घटक रही थी। एपीएससी ने नक्सलबाड़ी की सामयिक पराजय से सबक लेकर अतीत का सार–संकलन करते हुए 1974 में **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट' (एससीआर)** तैयार की थी। इस आधार पर एपीएससी ने आन्ध्र प्रदेश में पार्टी का पुनर्गठन शुरू किया। 1977–80 के बीच के तीन सालों में सीपीआई (एमएल) की एपीएससी ने मजबूत जन आन्दोलन खड़ा किये। ये आन्दोलन आन्ध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों तक फैले, खास तौर पर करीमगनर और अदिलाबाद जिलों तक जहाँ 1980 में पीडब्ल्यू के गठन के समय एक सशक्त कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलन चल रहा था। तेलंगाना के किसानों और पूरे आन्ध्र प्रदेश के छात्रों, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों के बीच इसने अच्छा–खासा व्यापक जन आधार तैयार किया।

यही है पीडब्ल्यू पार्टी का 1980 तक का संक्षप्ति इतिहास। 1980 में पीडब्ल्यू के गठन के बाद यह आन्दोलन समूचे तेलंगाना, उत्तरी आन्ध्र और दण्डकारण्य तक फैला।

आधार इलाके के हिस्से के रूप में छापामार ज़ोनों के निर्माण का परिप्रेक्ष्य

पीडब्ल्यू ने अपना ग्रामीण कार्य ठोस योजना और परिप्रेक्ष्य के साथ शुरू किया। वह यह कि आन्दोलन के सुदृढ़ीकरण और सशस्त्र संघर्ष के तीखा होते जाने के दौरान उत्तरी तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र को छापामार ज़ोन के रूप में रूपान्तरित किया जाय और इससे लगे हुए दण्डकारण्य क्षेत्र को इस परिप्रेक्ष्य के साथ पिछवाड़े

(रियर) के रूप में विकसित किया जाय कि इसे आधार इलाके के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य को बढ़ते दमन के मद्देनजर 1980 में ही एपीएससी के कामरेड केएस के नेतृत्व में तैयार किया था।

दरअसल राजकीय दमन सितम्बर 1978 में शुरू हुआ – किसान संघर्षों की शुरूआत के चन्द महीनों के अन्दर। बड़े पैमाने पर पुलिस के शिविर स्थापित किये जाने लगे। जगित्याल एवं सिरिसिल्ला तालुकों (तहसीलों) को अक्टूबर में "अशान्त क्षेत्र" घोषित किया गया। दुश्मन के सशस्त्र बलों के भारी आक्रमण की सम्भावना को देखते हुए पार्टी ने सबसे पहले **'जगित्याल परिप्रेक्ष्य'** और बाद में **'करीमनगर और अदिलाबाद के किसान संघर्षों को नयी ऊँचाई तक ले जाने के लिए तैयार हों'** शीर्षक से **'छापामार ज़ोन परिप्रेक्ष्य'** तैयार किया गया। पार्टी ने आधार इलाके स्थापित करने के मकसद से उत्तरी तेलंगाना और दण्डकारण्य को छापामार ज़ोन के रूप में रूपान्तरित करने की ठोस योजना बना ली और इसे पूरी शिद्दत के साथ लागू करना शुरू किया। इसी के अनुरूप उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी घाट और सीमावर्ती महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) के जंगलों में सशस्त्र किसान दस्ते भेजे गये। योजना के अनुसार दण्डकारण्य में धीरे–धीरे व्यापक जन आधार तैयार किया गया। फिर फरवरी 1987 मे अदिलाबाद, पूर्वी मण्डल (जिसमें विशाखापटनम और पूर्वी गोदावरी जिले आते हैं) और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उड़ीसा के जंगल क्षेत्रों को समेटने वाली अलग 'जंगल कमेटी' बना ली।

एक परिप्रेक्ष्य तथा ठोस योजना होने, ऊपरी कमेटी की ओर से लगातार साथियों को समझाते रहने और सीधे नेतृत्व दिये जाने के कारण ही हम एक विस्तृत, लगे हुए इलाके में सशस्त्र संघर्ष का विस्तार कर पाये। इसी प्रक्रिया में हम उत्तरी तेलंगाना (एनटी), दण्डकारण्य (डीके) तथा आन्ध्र–उड़ीसा सीमा (एओबी) क्षेत्रों में तीन छापामार ज़ोन विकसित कर पाये। इसका अन्य क्षेत्रों व राज्यों के संघर्षों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सशस्त्र संघर्ष दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र, रायलसीमा और बाद में आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय जिलों के कुछ पिछड़े हिस्सों तक भी विस्तार कर पाया। 2001 में नौवीं काँग्रेस से पहले दक्षिणी तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला क्षेत्रों में भी छापामार ज़ोन अस्तित्व में आ सके। डीके, एनटी, एओबी को आधार इलाकों के रूप में विकसित करने के मकसद से छापामार ज़ोन बनाने की योजना ने देश में पीडब्ल्यू के नेतृत्व में चल रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन में निर्णायक मोड़ ला दिया।

पार्टी के दो प्रमुख आन्तरिक संकट

पीडब्ल्यू के गठन के चार वर्षों बाद सीसी में संकट उभर आया। दरअसल अप्रैल 1980 में सीसी के गठन के एक साल के भीतर 9वीं काँग्रेस रखने का फैसला हुआ था। लेकिन तमिलनाडू के सीसी सदस्य वीर स्वामी (वीएस) व मणिक्कम ने अपने राजय की राजनीतिक–सांगठनिक समीक्षा (पीओआर) लिखने और तमिलनाडू राज्य सम्मेलन आयोजित करने में जान–बूझकर देर की। इस वजह से काँग्रेस को स्थगित करना पड़ा था। फिर मई 1984 की सीसी बैठक में अन्तरराष्ट्रीय स्थितियों में बदलावों के कारण **राजनीतिक प्रस्ताव** पारित करने के बाद वर्ष 1985 के पहले तीन महीनों में काँग्रेस आयोजित करने का फैसला किया गया। लेकिन 1985 की शुरुआत में सत्यमूर्ति (एसएम) और वीएस के नेतृत्व में अवसरवादी गुट ने पार्टी में संकट पैदा किया, जिसके कारण काँग्रेस नहीं हो सकी। इस तरह पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की पहली सीसी, जो अप्रैल 1980 में बनी और 1985 की शुरुआत तक काम करती रही, 1985–87 के संकटों के दौरान पंगु हो गयी। अप्रैल 1987 में इसने खुद को भंग कर दिया।

इस संकट के मुख्य कारण को आन्दोलन के सामने आयी समस्याओं का निराकरण करने के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कौन–सी कार्यनीति अपनायी जाय इसको लेकर कई सवाल आन्दोलन के सामने खड़े थे पार्टी नेतृत्व इन सवालों का सही समाधान खोजने की स्थिति में नहीं रहा। इन सवालों का गम्भीरता से जवाब खोजने के बजाय केन्द्रीय नेतृत्व ने साजिशाना तरीके अपनाकर पार्टी में संकट पैदा कर दिया। आन्दोलन को आगे बढ़ाने में आड़े आ रही अपनी कमजोरियों को ढँकने और अपनी विफलताओं के लिए आत्मालोचना करने के लिए खुद को तैयार न कर पाने के कारण सीसी में एसएम–वीएस गुट ने "वाम" शब्दाडम्बर में ढँकी वैकल्पिक लाइन रखी, जो वास्तव में सारतः दक्षिणपंथी लाइन ही थी। लेकिन इस विसर्जनवादी–अवसरवादी गुट द्वारा अपनाये गये पार्टी–विरोधी तौर–तरीकों के कारण उसकी गलत लाइन के खिलाफ रेशा–रेशा दो दिशाओं का संघर्ष करना सम्भव नहीं हो पाया। इस पार्टी–विरोधी गुट को पराजित करने के बाद ही कहीं आन्दोलन आगे बढ़ पाया। पार्टी लाइन के इर्द–गिर्द अब पार्टी और ज्यादा दृढ़ता से कमोबेश एकीकृत हो गयी।

संकट को पैदा करने में सहायक परिस्थितियाँ स्वयं सीसी के गठन की प्रक्रिया में ही मौजूद रहीं। क्रान्तिकाररियों को एक साथ लाना तो सही था। मगर सीसी गठित

करने से पहले विचारधारात्मक, राजनीतिक एवं सांगठनिक तैयारियो में गम्भीर खामियाँ रहीं। इनमें **राजनीतिक प्रस्ताव** तैयार न करना; तमिलनाडू की 1970 के दशक की **राजनीतिक एवं सांगठनिक समीक्षा (पीओआर)** तैयार न करा लेना और **पार्टी संविधान** के अनुरूप एकीकृत पार्टी के लिए आवश्यक सांगठनिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में निर्णय न करना शामिल हैं। स्पष्ट है कि एकता से पहले विचारों की पूरी एकता नहीं हो पायी थी।

इसके बाद तीन सालों का ऐसा समय बीता जब आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक और महाराष्ट्र की चारों राज्य इकाइयाँ किसी केन्द्रीय नेतृत्व के बिना कार्य करती रहीं।

अगस्त 1990 के केन्द्रीय प्लेनम में नयी सीसी चुनी गयी। इसे सीओसी कहा गया। मगर समुचित कार्यनीति अपनाकर आन्दोलन आगे बढ़ाने में अब कोई भूमिका न निभा पा रहे अवसरवादी केएस– बन्दैया गुट के कारण 1991 के मध्य में पार्टी में एक और आन्तरिक संकट सतह पर आया। अपनी असफलताओं को ढँकने के लिए और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर अपने मनोगत आकलन तथ दक्षिणपन्थी–अवसरवादी कार्यनीति थोपने के लिए केएस–बन्दैया गुट ने अराजक एवं अति–जनवादी तौर–तरीकों को अपनाते हुए पार्टी को तोड़ने एवं विसर्जित करने के प्रयास किये। मुट्ठीभर अवसरवादी तत्वों को छोड़कर पूरी पार्टी इस गुट के खिलाफ उसूली संघर्ष छेड़ने में एकताबद्ध होकर खड़ी हुई और इसके विघटनकारी मंसूबों पर पानी फेर सकी। यह संकट लगभग एक साल तक खिंचा और आखिर जून 1992 में इस गुट को पार्टी से निष्कासित किया गया।

दूसरे अन्दरूनी पार्टी संकट और इससे लड़ने के लिए अपनाये गये तौर–तरीकों ने एक बड़े शिक्षा अभियान का काम किया और पार्टी की कार्यशैली में सुधार लाया, सीसी में सामूहिक नेतृत्व तथा टीम कार्यप्रणाली को विकसित किया और सभी पार्टी कमेटियों को जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर मजबूत किया। इसने पूरी पार्टी के विचारधारात्मक–राजनीतिक स्तर को उन्नत किया और नये कार्यभार प्रस्तुत किये।

सार–संक्षेप में कहें, तो पार्टी की कतारों ने 1985–87 और 1991–92 के अन्दरूनी पार्टी संकटों के दौरान तत्कालीन सीसी सचिवों के नेतृत्व में काम कर रहे अवसरवादी गुटों के खिलाफ संघर्ष किया, उनके विघटनकारी मंसूबों को परास्त किया और दृढ़ता से एकता कायम रखी। दोनों मौकों पर पार्टी दुश्मन के भारी दमन अभियानों का मुकाबला करने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरने में कामयाब

हुई। यह इसलिए सम्भव हुआ कि पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक शिक्षा दी गयी, कमजोरियों व भटकावों के विरुद्ध पार्टी में शुद्धिकरण अभियान चलाये गये और पार्टी कतारों का क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता का स्तर ऊँचा तथा सशस्त्र संघर्ष के प्रति जड़ाव पक्का रहा।

मिसाल के तौर पर, 1981 में नौकरशाही के विरुद्ध और 1984 में "छः बुराइयों" – अवसरवादी गठजोड़, नौकरशाही, कानूनवाद, तकनीकी सावधानियों के उल्लंघन, आर्थिक फिजूलखर्ची और महिला साथियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे विजातीय वर्ग रुझानों के विरुद्ध सुसंगत संघर्ष किया गया। आन्ध्र प्रदेश में "छः बुराइयों" के विरुद्ध शुद्धिकरण अभियान 1984 से लेकर 1987 तक चलाया गया। इस शुद्धिकरण अभियान के दौरान सभी पार्टी कमेटी बैठकों में आलोचना–आत्मालोचना चलायी गयी, पार्टी इतिहास पर इससे सीखने के लिए तथा छः बुराइयों को सुधारने के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक कक्षाएँ तथ चर्चाएँ आयोजित की गयीं। पार्टी इतिहास से सम्बन्धित ज्यादातर दस्तावेजों को पाँच खण्डों में प्रकाशित किया गया और आन्ध्र प्रदेश तथा दण्डकारण्य में पूरी पार्टी को शिक्षा दी गयी।

अन्दरूनी पार्टी संकटों से निकलने वाले सबक

(1) क्रान्तिकारियों के बीच विलय को अन्तिम रूप देने से पहले एकता हासिल करने के लिए विचारधारात्मक, राजनीतिक एवं सांगठनिक तैयारियाँ पूरी कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के समय की गलतियाँ जितनी गम्भीर होंगी, उतनी ही विलय के बाद अवसरवादी प्रवृत्तियों तथा भटकावों के उभरने व विकसित करने की गुंजाइश होगी।

(2) नेतृत्व को जनवादी केन्द्रीयता के उसूलों का पालन करना चाहिए। कमेटी की कार्यप्रणाली में जनवादी केन्द्रीयता के पालन के लिए कारगर सामूहिक कार्यशैली और विशिष्ट व्यक्तिगत जिम्मेदारी जरूरी है। हमें अपनी निम्न–पूँजीवादी खामियों को सुधारना चाहिए, वर्ग संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिए और आलोचना तथा आत्मालोचना को हमेशा व्यवहार में लागू करना चाहिए।

(3) अगर पार्टी नेतृत्व को नेतृत्व के ही एक हिस्से में अवसरवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ना हो, तो उसे सही तौर–तरीकों का पालन करना चाहिए। भटकावों का शिकार हुए कार्यकर्ताओं को लेनिनवादी तौर–तरीकों से सुधारा जाना चाहिए। केवल तभी विसर्जनवादियों को अलगाव में डालना और इनसे प्रभावित

बहुसंख्यक कामरेडों को पार्टी के साथ दृढ़ता से व एकताबद्ध रूप से खड़ा किया जा सकता है। कोई भी साथी अपनी निम्न–पूँजीवादी प्रवृत्तियों को छोड़े बगैर सफल नहीं हो सकता; वह हार भी सकता है।

(4) पार्टी एकता के विपरीत काम करने वाले किसी का भी, यहाँ तक कि नेतृत्व का भी विरोध करते या उससे लड़ते वक्त सारे मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को आलोचनात्मक नजरिये से विचार करना चाहिए। पूर्वाग्रह, सतहीपन, यान्त्रिक सोच और ऐसी अनचाही प्रवृत्तियों को द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण और पार्टी कार्यकर्ताओं की सतर्कता से ध्वस्त किया जाना चाहिए।

(5) मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के बारे में कार्यकर्ताओं की चेतना उन्नत करने और पार्टी लाइन तथा वर्ग संघर्ष को लेकर शिक्षा–दीक्षा देने के गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए। हमारे अनुभवों के हिसाब से मा–ले–मा की रोशनी में हमने 1995 के अखिल भारतीय विशेष सम्मेलन (एआईएससी) की **राजनीतिक एवं सांगठनिक समीक्षा** में कुछ मार्गदर्शक बातें सूत्रबद्ध की हैं। **पार्टी संविधान** में भी हमने इस पर कुछ संशोधन किये कि गलत लाइनों व भटकावों को परास्त करते हुए पार्टी में बेहतर एकता हासिल करने के लिए अन्दरूनी पार्टी संघर्ष किस तरह चलाया जाना चाहिए।

कामरेड कोण्डापल्ली सीतारमैया (केएस) का आकलन

केएस ने भारत के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की राजनीति में लगभग पाँच दशकों तक, खास कर 1972 में कामरेड सीएम की शहादत के बाद बड़ी प्रभावी भूमिका निभायी। हमारी पार्टी में विचारधारात्मक, राजनीतिक, सांगठनिक रूप से दो दशकों तक नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने के बाद अन्ततः उन्हें निष्कासित किया गया।

क्रान्तिकारी आन्दोलनों और नेताओं का सही आकलन करने के लिए हमें द्वन्द्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करना चाहिए। जब हम ऐतिहासिक रूप से केएस की भूमिका को परखते हैं, तो हम उनकी क्रान्तिकारी भूमिका के साथ ही अवसरवादी, विसर्जनवादी भूमिका को भी देख पाते हैं। इसी पद्धति से हम उनका सही विश्लेषण कर सकते हैं और उनकी सकारात्मक भूमिका की रोशनी में नकारात्मक भूमिका को समर्थन देने तथा उनकी नकारात्मक भूमिका की रोशनी में सकारात्मक भूमिका को खारिज करने की गलतियों से बच सकते हैं। तभी हम सही–सही देख पायेंगे कि किस दौर में उनकी कौन–सी प्रवृत्ति

ज्यादा प्रभावी रही।

योगदानः– केएस ने पार्टी की क्रान्तिकारी लाइन एवं पार्टी एकता की हिफ़ाज़त तथा नक्सलबाड़ी एवं श्रीकाकुलम के संघर्षों की परम्परा एवं कार्यभारों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दृष्टि का प्रदर्शन ऐसे समय पर किया जब आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी के बड़े हिस्से को खो दिया गया था, सीसी अस्तित्व में नहीं थी और कामरेड सीएम की शहादत के बाद पार्टी दक्षिणपंथी–अवसरवाद के आन्तरिक एवं बाहरी हमलों, संशोधनवाद तथा टूट–फूट का सामना कर रही थी। उन्होंने आन्ध्र की पार्टी कतारों को खड़ा किया और संघर्ष में टिकाये रखा, जिस दौरान मार्क्सवाद–लेनिनावाद–माओवाद पर उनकी अगाध आस्था काम आयी। यह उन्होंने तब किया जब दुश्मन की फासीवादी शक्तियाँ एक के बाद एक नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम तथा अन्य संघर्षों को कुचल रही थीं, जिससे हजारों पार्टी कार्यकर्ता तथा नेता शहीद हो रहे थे, कई नेता क्रान्तिकारी खेमे को छोड़ जा रहे थे तथा कई बड़ी संख्या में देश की तमाम जेलों में जगह–जगह कैद थे।

केएस ने एसएनएस व तेजेश्वर राव, कानू सन्याल जैसे उन अवसरवादियों और डीवी–टीएन–सीपीआर जैसे उन दक्षिणपंथी–अवसरवादियों के हमलों का कारगर मुकाबला किया जो कामरेड सीएम पर धोखे से प्रहार कर रहे थे। उन्होंने क्रान्तिकारी संघर्षों और पार्टी की मूल तथा बुनियादी लाइन के सकारात्मक बिन्दुओं की हिमायत की।

आन्दोलन के सामयिक पराजय के लिए जिम्मेदार गलतियों और ऐतिहासिक रूप से हासिल की गयी जीतों का विश्लेषण करते हुए केएस ने **अत्मालोचनात्मक रिपोर्ट** तैयार की। उन्होंने नकारात्मक बिन्दुओं को रद्द करते हुए तथा सकारात्मक को जारी रखते हुए 1972 से 1977 के बीच पार्टी की कतारों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए खून–पसीना एक किया और काफी धैर्यपूर्वक प्रयास किये। उन्होंने पार्टी को नयी ऊर्जा देकर खड़ा करने में नींव रखने का काम किया। क्रान्तिकारी युद्ध में जनता का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने क्रान्तिकारी जन संगठनों की भूमिका को पहचाना और कामरेड सीएम को भी जन संगठन बनाने के लिए सहमत कराया। आन्ध्र प्रदेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन को पुनर्जीवित करने में यही उनका सबसे बड़ा योगदान रहा।

केएस ने **एससीआर** की रोशनी में क्रान्तिकारी संघर्षों का नेतृत्व करते हुए तथा आन्दोलन का विस्तार करते हुए जन–आधारित क्रान्तिकारी जुझारू पार्टी खड़ी

करने में बेजोड़ सांगठनिक दक्षता दिखायी। उन्होंने उत्तरी तेलंगाना के आन्दोलन का मार्गदर्शन किया, पार्टी की बुनियादी लाइन की दिशा में छापामार ज़ोन का परिप्रेक्ष्य ईजाद किया और दण्डकारण्य आन्दोलन की नींव रखी। पार्टी की बुनियादी लाइन को विशिष्ट स्थितियों में लागू करना केएस का एक प्रमुख योगदान रहा।

1980 में सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) की सीसी गठित करने का प्रमुख श्रेय केएस को जाता है। उन्होंने पार्टी को मार्क्सवादी–लेनिनवादी दृष्टि से हमारे देश में राष्ट्रीयता की समस्या के बारे में और व्यवहार में सही रवैया अपनाने की शिक्षा दी। केएस ने 1973 से 1982 के बीच हमारे देश में मा–ले–मा के वेश में तरह–तरह के अवसरवादियों की ओर से आ रहे तर्कों को पराजित करते हुए आन्ध्र राज्य कमेटी तथा केन्द्रीय कमेटी को पार्टी की राजनीतिक एवं सांगठनिक शक्ति बढ़ाने में नेतृत्व प्रदान किया।

केएस ने 1980 मे 12वें तथा 1987 में 13वें आन्ध्र प्रदेश राज्य सम्मेलनों में और आन्ध्र तथा दण्डकारण्य के आन्दोलनों को एक करते हुए आगे ले जाने में प्रमुख भूमिका निभायी। 1985 में प्रदेश तथ केन्द्र सरकारों ने जब अघोषित युद्ध छेड़ दिया, तो इसका डटकर मुकाबला करने की कार्यनीति आन्ध्र राज्य कमेटी ने केएस के नेतृत्व में ही ईजाद की।

सीसी के बहुमत के खोल में पार्टी को तबाह करने का षड़यन्त्र करने वाले एसएम–वीएस गुट के अवसरवाद को केएस के नेतृत्व में आन्ध्र और कर्नाटक की पार्टी इकाइयों ने सफलतापूर्वक परास्त किया। इस तरह केएस ने 1972 से 1987 तक पार्टी की लगभग सारी उपलब्धियों में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की।

नकारात्मक पहलू :– नकारात्मक पहलू, जो पहले भारी नहीं थे, धीरे–धीरे बढ़ते गये और आन्दोलन की प्रगति में रोढ़े बनने लगे। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में वे जड़सूत्रवाद का शिकार हुए और निरन्तर बदलती स्थितियों तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन को द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नजरिये से समझाने में असफल रहे।

व्यक्तिगत कार्यप्रणाली केएस की गम्भीर समस्या रही। केएस की व्यक्तिगत कार्यप्रणाली के ऐतिहासिक कारण हैं। श्रीकाकुलम संघर्ष के दौरान प्रदेश का नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया था। 1972 से 1979 तक पार्टी के पुनर्निमाण की प्रक्रिया के दौरान केएस को ही सारे निर्णय अकेले लेने पड़े थे। 1980 में नयी राज्य कमेटी बनी। मगर अकेले एसएम को छोड़, बाकी सभी सदस्य महज नक्सलबाड़ी एवं श्रीकाकुलम के प्रभाव में ही आन्दोलन में आये थे। उनका मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद में कम

ज्ञान और वर्ग संघर्ष का नेतृत्व करने का कम अनुभव था। वे महज केएस के अनुयायी ही रहे। केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों की स्थिति इससे भिन्न नहीं थी। इस बीच 1980 तक आते–आते आन्दोलन का व्यापक विस्तार हुआ। पार्टी की सदस्यता बढ़ी। कमेटियों की संख्या बढ़ गयी। लेकिन केएस ने व्यक्तिगत कार्यप्रणाली से उबरने के कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किये।

आन्दोलन के विकास के साथ–साथ पार्टी के सामने कई गम्भीर समस्याएँ आ उपस्थित हुईं। केएस टीम लीडर के नाते इन समस्याओं पर कमेटी में चर्चा करके हल ढूँढने या नयी समस्याओं के लिए समाधान सोचने को तैयार नहीं थे। समस्याओं को हल करने में सीमाएँ, लम्बे समय तक आन्दोलन से दूर रहने, व्यक्तिगत कार्यप्रणाली की मजबूत नकारात्मक प्रवृत्ति, जड़सूत्रवाद, स्वतःस्फूर्तता व मनोगतवाद के साथ–साथ बुढ़ापे ओर अस्वस्थता से उपजी सीमाएँ उनके इस रूपान्तर के प्रमुख कारण रहे। इन समस्याओं के कारण वे समस्याओं का जिस तरह 1985 से पहले निराकरण करते थे, अब ऐसा करने में असहाय रहे। यही नहीं, धीरे–धीरे वे पार्टी के सामने उपस्थित हुई समस्याओं के प्रति मार्क्सवाद–विरोधी दृष्टिकोण अपनाने लगे। एपीएससी में उभरती नयी सामूहिक कार्यप्रणाली उनकी व्यक्तिगत कार्यप्रणाली के बीच अन्तरविरोध उभरा, जो धीरे–धीरे तकरार बन गया। आन्दोलन की समस्याओं का निराकरण मार्क्सवादी–लेनिनवादी कार्यप्रणाली और सामूहिक नेतृत्व से करने के बजाय केएस अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रतिशोध लेते रहे। इससे पार्टी के आन्तरिक रिश्ते दुश्मनाना हो गये।

केएस उभरते नेतृत्व और उसकी पहलकदमी को स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे पितृसत्तात्मक रवैयों के साथ व्यक्तिगत कार्यप्रणाली के आदि थे। अपनी सीमाओं से पैदा हुई विफलताओं के कारण वे हीनता बोध से ग्रस्त रहने लगे। 1989 तक आते–आते वे आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वे आलोचना करने वाले कामरेडों पर गैर–सांगठनिक तरीके अपना कर हमला करने लगे। केएस ने इस गम्भीर कमजोरी को कभी महसूस नहीं किया और न ही कभी आत्मालोचना की।

केएस ने यह माना कि 1991 में इराक पर अमरीकी साम्राज्यवाद के सामरिक आक्रमण के बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने साम्राज्यवादी विश्व युद्ध और दूसरे युद्धों के बीच रूप, परिणाम और सघनता में फर्क न देखकर दोनों को बराबर माना।

केएस का वास्तविकता से सम्पर्क कट गया, वे पार्टी तथा जनता से कट गये

और चीजों को मनोगतवादी तरीके से देखने लगे। जब वास्तविकता सामने आती और उनके आकलनों को अन्य लोग स्वीकार नहीं कर पाते, तो वे इस सोच से हमले करने लगते, मानो उनका क्रान्तिकारी प्राधिकार अब घट रहा हो। कैरियरवाद ने उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया था। पूरी पार्टी ने लामबन्द होकर 'मरीज को बचाने के लिए बीमारी का इलाज करो' के आधार पर केएस को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने आत्मालोचना करने के बजाय अपनी पार्टी–विरोधी गतिविधियाँ तेज कीं और पार्टी में फूट पैदा की। फिर भी हमें उनकी क्रान्तिकारी सकारात्मक भूमिका को आदर्श मिसाल के रूप में लेना चाहिए। साथ ही, उनकी नकारात्मक भूमिका को, खासकर जो बाद के दौर में देखी गयी, खारिज करना चाहिए। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध तक वे हमारे सच्चे नेता व सकारात्मक शिक्षक रहे। बाद में वे हमारे नकारात्मक शिक्षक बने। केएस के इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह निकलता है कि गम्भीर गलतियाँ करने वाले कामरेड अगर आत्मालोचना की प्रक्रिया से अपना सुधार नहीं करते, तो वे क्रान्ति में बने नहीं रह सकते हैं।

पार्टी की राजनीतिक–सामरिक लाइन का विकास

सीपीआई (एमएल) की राजनीतिक–सामरिक लाइन भाकपा व माकपा की संशोधनवादी लाइन के खिलाफ सुसंगत, समझौताविहीन राजनीतिक वाद–विवाद और ठोस वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इसी ने नक्सलबाड़ी–श्रीकाकुलम और अन्य सशस्त्र जन उभारों का रूप लिया। नयी संशोधनवादी लाइन पुरानी संशोधनवादी लाइन से पूर्ण विच्छेद करते हुए उभरी। यह लाइन देश के विभिन्न भागों में दीर्घकालीन लोक युद्ध के विकास के लम्बे दौर में समृद्ध होती गयी है। यह वर्ग संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष और संशोधनवाद के विभिन्न रूप–रंगों तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन के दक्षिणपंथ एवं "वाम" रुझानों के साथ राजनीतिक वाद–विवाद और उतार–चढ़ाव, ज्वार–भाटा, आरोह–अवरोह के अनुभवों का संश्लेषण है। संक्षेप में कहें, तो 9वीं काँग्रेस द्वारा समृद्ध वर्तमान पार्टी लाइन बुनियादी तौर पर 1970 की 8वीं काँग्रेस द्वारा पारित लाइन है, जिसे देश में तीन दशकों के सशस्त्र संघर्ष के दौर में लगातार विकसित किया गया। यह क्रान्ति के तीन जादुई हथियार सर्वहारा पार्टी, जन सेना और क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे को उभारने से जुड़ी हुई है।

तमाम सम्मेलनों, प्लेनमों, विशेष बैठकों, कमेटी बैठकों ने लगातार अनुभवों का सार–संकलन कराया, आन्दोलन के सकारात्मक पहलुओं को आत्मसात व नकारात्मक

पहलुओं को रद्द कराया और समय–समय पर उचित सबक व कार्यभार निकाले। इनमें महत्वपूर्ण रहे – 1977 का पहला तेलंगाना क्षेत्रीय सम्मेलन, 1980 का 12वाँ आन्ध्र प्रदेश राज्य सम्मेलन, 1987 का 13वाँ राज्य सम्मेलन, पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू का 1995 का अखिल भारतीय विशेष सम्मेलन और 1983, 1987, 1993 तथा 1997 के पीयू के केन्द्रीय सम्मेलन।

लम्बे क्रान्तिकारी व्यवहार के दौरान जब हम किसी नयी स्थिति से रूबरू होते, तो नयी कार्यनीति सूत्रबद्ध करते रहे। हमने समय–दर–समय अपने व्यवहार का सार–संकलन किया। पार्टी सम्मेलन तथा काँग्रेस में हमने अपनी बुनियादी दस्तावेजों को समृद्ध किया। 8वीं काँग्रेस के बाद हमने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किये। वे हैं – वर्तमान परिस्थिति और हमारी कार्यनीति (एपीएससी का अगस्त 1977 का प्रस्ताव); आत्मालोचात्मक समीक्षा (एससीआर) – 1980, हमारी कार्यनीतिक लाइन (ओटीएल) – 1980; जगित्याल परिप्रेक्ष्य – 1978; छापामार ज़ोन परिप्रेक्ष्य – 1980; चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर केन्द्रीय कमेटी का प्रस्ताव – 1983; राजनीतिक प्रस्ताव– 1980, 1984, 1992; अखिल भारतीय विशेष सम्मेलन (एआईएससी) के दस्तावेज – 1995; सीसी के दो दिशाओं के संघर्ष के दस्तावेज – 1985 और समय–दर–समय सीसी तथा राज्य कमेटियों द्वारा जारी तमाम परिपत्र (सर्कुलर)। इसके अलावा शुद्धिकरण एवं शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में **पार्टी दस्तावेजों के पाँच खण्ड** और पीडब्ल्यू तथा अन्य पत्रिकाओं में राजनीतिक वाद–विवाद तथा अन्य महत्वपूर्ण हमलों से सम्बन्धित अनेक दस्तावेज प्रकाशित हुए। इन सभी के जरिये हमने अपनी पार्टी लाइन विकसित की और पार्टी के विचारधारात्मक-राजनीतिक–सांगठनिक–सामरिक स्तर को उन्नत करने के प्रयास किये।

राजनीतिक लाइन की सार–वस्तु को कामरेड सीएम के **'आठ दस्तावेजों'** द्वारा विकसित किया गया और 8वीं काँग्रेस द्वारा पारित किया गया। लाइन ने विश्वास जताया कि भारतीय क्रान्ति दो मंजिलों से होकर गुजरेगी तथा वर्तमान मंजिल कृषि क्रान्ति की धुरी पर नयी जनवादी क्रान्ति की होगी; कि भारतीय क्रान्ति का रास्ता दीर्घकालीन लोक युद्ध का रास्ता होगा; कि जनवादी क्रान्ति के दुश्मन साम्राज्यवाद, सामन्तवाद तथा दलाल नौकरशाह पूँजीवाद हैं और कि वर्तमान मंजिल पर क्रान्ति की प्रेरक शक्तियाँ मजदूर वर्ग, किसान, निम्न पूँजीपति वर्ग तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग हैं। राजनीतिक लाइन ने जन मुक्ति सेना के निर्माण और देश के पिछड़े रणनीतिक क्षेत्रों में आधार इलाकों की स्थापना का आह्वान किया। लाइन ने कार्यनीति के नाम पर

संसदीय मार्ग और संसदीय चुनावों में भागीदारी को खारिज किया। इसने एकदम शुरुआत से ही गुप्त पार्टी के निर्माण पर बल दिया।

पार्टी कार्यक्रम और कार्यनीति हालांकि सारतः सही रही, फिर भी कार्यनीति के सन्दर्भ में गम्भीर भटकाव रहे। यह भटकाव जन संघर्ष एवं जन संगठनों के विभिन्न रूपों को खारिज करने तथा वर्ग दुश्मनों के सफाये को संघर्ष का एकमात्र रूप मानकर चलने, ट्रेड यूनियनों के बहिष्कार, शहरी छापामार युद्ध पर अतिरिक्त जोर, पूँजीवादी शिक्षा संस्थानों पर हमला करने की वाम दुस्साहसवादी कार्यनीति, पूँजीवादी अदालतों के बहिष्कार आदि से सम्बन्धित रहे। आठवीं काँग्रेस में वर्ग दुश्मनों के सफाये की कार्यनीति को लाइन का दर्जा दिये जाने के कारण आन्दोलन को काफी नुकसान पहुँचा और कालान्तर में इससे क्रान्तिकारी शक्तियाँ अलगाव में पड़ीं। भारी पुलिस बल तैनात कर और साथ ही सुनियोजित ढंग से क्रान्तिकारी शक्तियों में घुसपैठ कराकर तथा पार्टी को भीतर से तबाह कर दुश्मन अपेक्षाकृत आसानी से आन्दोलन को दबा सका।

पार्टी की राजनीतिक लाइन की गलतियों को 1974 के **एससीआर** में सुधारा गया और सामयिक पराजय के बाद आन्ध्र प्रदेश में यह नयी समझदारी व्यवहार में परिलक्षित हुई। क्रान्तिकारी जन दिशा के आधार पर बड़े पैमाने पर अनेक जन संगठनों को खड़ा किया गया और वर्ग संघर्ष शुरू किये गये। आन्ध्र प्रदेश में जुझारू क्रान्तिकारी जन आन्दोलन दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बने।

इसी वक्त 1970 के दशक के दौरान कानू सन्याल, टीएन–डीवी–सीपीआर, एसएनएस की पीसीसी आदि कुछ पूर्ववर्ती एमएल ग्रुपों ने आठवीं काँग्रेस को "वाम दुस्साहसवादी", "वाम संकीर्णतावादी" और "जन विरोधी" तक करार देते हुए आठवीं काँग्रेस की लाइन की आलोचना की। वे जन दिशा के बारे में और इस बारे में कि कैसे कामरेड सीएम जन दिशा से भटक गये थे, अन्तहीन बातें करते रहे। परन्तु सार रूप में ये सारे ग्रुप असल में संशोधनवादी या दक्षिणपंथी–अवसरवादी लाइन की वकालत करते रहे। उन्होंने जन दिशा को दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन के परस्पर विरोध में खड़ा किया। दूसरे छोर पर सेकेण्ड सीसी, विनोद मिश्र के लिबरेशन जैसे कुछ एमएल संगठन रहे जो कामरेड सीएम की गलतियों की आलोचना करने से कतई इन्कार करते थे, उनके "राजनीतिक प्राधिकार" पर जड़सूत्रवादी तरीके से अड़े हुए थे, जन संगठन तथा जन संघर्ष के किसी भी रूप को खारिज करते थे और संघर्ष के "एकमात्र रूप" के रूप में वर्ग दुश्मन के सफाये की हिमायत करते थे। (1980 के दशक

की शुरुआत में इनमें से लिबरेशन ग्रुप ने पलटी खाकर दूसरा छोर पकड़ लिया और यह संशोधनवादियों के खेमे से जुड़ गया)।

विभिन्न एमएल ग्रुपों की इन गलत अवस्थितियों के विरुद्ध एपीएससी और बाद में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} ने कामरेड सीएम तथा आठवीं काँग्रेस की क्रान्तिकारी लाइन की हिफ़ाज़त की, खामियों को खुलकर चिह्नित किया और साहस के साथ इनको सुधारना शुरू किया। इस मार्क्सवादी–लेनिनवाद द्वन्द्ववादी पद्धति और दृष्टिकोण के ही कारण लाइन को आगे समद्ध किया जा सका और व्यवहार में परखा भी जा सका।

पीडब्ल्यू और पीयू ने भारतीय समाज के अधिक ठोस विश्लेषण के काम को हाथ में लिया और भारत में क्रान्तिकारी युद्ध की खास विशिष्टताओं तथा चीन की क्रान्ति–पूर्व स्थितियों के साथ समानताओं व भिन्नताओं का अध्ययन किया। राजनीतिक एवं सामरिक रणनीति व कार्यनीति के विकास में इसी का योगदान रहा। देश की विशिष्टताओं और खास विशेषताओं, जैसे जाति प्रश्न, राष्ट्रीयता प्रश्न, आदिवासी प्रश्न, महिला प्रश्न तथा धार्मिक अलपसंख्यकों के प्रश्न का ठोस अध्ययन किया। इससे इन तमाम सामाजिक तबकों को नयी जनवादी क्रान्ति के लिए लामबन्द करने की विशिष्ट कार्यनीति तैयार करने में मदद मिली।

दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन का ठोस अमल

जैसा कि कामरेड माओ ने कहा है, **"सशस्त्र बलों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना, युद्ध से मुद्दे को तय करना क्रान्ति का केन्द्रीय कार्यभार और उच्चतम रूप है। लेकिन (सभी देशों के लिए) उसूल तो वही रहता है, पर विभिन्न देशों में अलग–अलग स्थितियों के अनुरूप सर्वहारा की पार्टी इस पर अमल करती है।"**

दीर्घकालीन लोक युद्ध में नयी जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के लिए यह अत्यन्त जरूरी है कि जनता की सेना को पिछड़े देहाती क्षेत्रों में जहाँ दुश्मन कमजोर है वहीं तैयार किया जाय और मुक्त इलाके कायम किये जाये। आधार इलाके स्थापित करने के लिए दण्डकारण्य के जंगलों की ही तरह रणनीतिक क्षेत्रों को चुना गया जहाँ की भूरचना छापामार युद्ध चलाने के अनूकूल है। सामन्तवाद–विरोधी व राज्य–विरोधी संघर्षों को तीखा रूप देते हुए इन क्षेत्रों को पहले छापामार ज़ोन में रूपान्तरित करने की ठोस योजना के साथ काम शुरू हुआ। छापामार शक्तियों की संरक्षा व संचय के

लिए, इन्हें जन सेना के रूप में विस्तारित एवं रूपान्तरित करने के लिए और दुश्मन की शक्तियों को परास्त करने तथा उखाड़ फेंकने के लिए यह रणनीतिक क्षेत्र कुंजीभूत इलाकों का काम करेंगे। इन क्षेत्रों में क्रान्तिकारी सेना के टिके रहने व विकसित होने के लिए जरूरी संसाधन मौजूद हैं और मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुकूल स्थितियाँ भी हैं। इसलिए मुक्त क्षेत्र बनाने के ऊँचे लक्ष्य की ओर पहले कदम के रूप में इन क्षेत्रों को अपराजेय छापामार ज़ोन के रूप में विकसित करने का काम हाथ में लिया गया।

हमारे देश की विशिष्ट स्थितियों में दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन को लागू करने की प्रक्रिया के रूप में एपीएससी ने करीमनगर व अदिलाबाद में फल—फूल रहे किसान संघर्षों को ऊँचे स्तर तक ले जाने का फैसला करते हुए आह्वान किया — **"करीमनगर और अदिलाबाद के किसान संघर्षों को नये स्तर तक पहुँचाने के लिए तैयार हो जाओ।"** करीमनगर और अदिलाबाद जिलों से लगे हुए अन्य दो जिलों वारंगल और खम्मम में भी छापामार ज़ोन तैयार करने का कार्यभार हाथ में लिया गया, जहाँ वर्ग संघर्ष अपेक्षाकृत कम विकसित स्तर पर रहा।

चार जिलों करीमनगर, अदिलाबाद, वारंगल और खम्मम (उत्तरी तेलंगाना) में छापामार ज़ोन तैयार करने की योजना पर अमल करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में 1980 में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) की सीमाओं पर स्थित रणनीतिक क्षेत्र दण्डकारण्य में सात हथियारबन्द किसान छापामार दस्ते भेजे गये।

1980—84 के दौरान हमने उत्तरी तेलंगाना तथा दण्डकारण्य में जुझारू तरीके से किसान संघर्ष चलाये और जनता के विभिन तबकों के अनेक मुद्दों पर राजनीतिक आन्दोलन खड़े किये। हमने नये इलाकों में विस्तार किया और जनता की चेतना को उन्नत किया। 1983 तक खम्मम में तो पार्टी को गम्भीर पराजय सहनी पड़ी, पर निजामाबाद एक संघर्ष के इलाके के रूप में विकसित हुआ। 1984 के अन्त तक अदिलाबाद को उत्तरी तेलंगाना से अलग किया गया और दण्डकारण्य के संगठन से जोड़ दिया गया।

1985 में केन्द्र और राज्य सरकारों ने हम पर अघोषित युद्ध छेड़ दिया। इस अघोषित युद्ध का डटकर मुकाबले करने के लिए हमने मई 1985 में प्रतिरक्षात्मक युद्ध की कार्यनीति सूत्रबद्ध की। 1985—87 हमारे लिए काला दौर रहा। इस दौरान हमने अनेक नुकसान झेले और दुश्मन का पलड़ा भारी पड़ा। 1987—88 में हमने जन संगठनों का पुनर्निर्माण किया तथा जन आधार को एवं दस्तों को सुदृढ़ किया। हमने

मैदानों व जंगलों में नये दस्ते भी बनाये। इस तरह हम विभिन्न रूपों में सशस्त्र प्रतिरोध विकसित करते हुए दुश्मन का सामना करने में सफल रहे। 1988 के मध्य से शुरू करते हुए जन प्रतिरोध और सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन का पलड़ा 1989 के अन्त तक आते–आते भारी पड़ा। इस प्रकार सरकार के "अघोषित युद्ध" को शिकस्त दी गयी। इस दौर में सघन सशस्त्र संघर्ष हुआ। सरकारी शक्तियों और उनके दलालों पर जवाबी हमला करना हमारा मुख्य कार्यक्रम रहा।

दुश्मन की 1985–87 की पहली बड़ी आक्रमणकारी मुहिम को हम 1987 में तब तोड़ पाये जब हमने पूर्वी मण्डल में दारागड्डा एम्बुश और अदिलाबाद में अल्लमपल्ली एम्बुश संगठित करते हुए 18 पुलिस वालों को मार गिराया तथा कई राइफलें छीन लीं। इन जाँबाज एम्बुशों ने दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया छक्के छुड़ा दिये और कुछ देर के लिए उसकी बढ़त रोक दी, जबकि जनता का उत्साहवर्द्धन किया। इसने 1988 से जुझारू जन संघर्षों तथा जनता की सशस्त्र कारवाइयों की लहर खड़ी करने में मदद पहुँचायी।

1990 में शासक वर्गों के अन्तरविरोधों का लाभ उठाते हुए हमने कार्यनीति बदली। अब हमने जन आधार को सुदृढ़ किया, व्यापक जन संघर्ष खड़े किये, सशस्त्र टुकड़ियों को विस्तारित एवं सुदृढ़ किया तथा आन्दोलन का विस्तार किया।

1990 के अन्त से हमने प्रतिरक्षात्मक युद्ध की कार्यनीति के सहारे केन्द्र सरकार द्वारा तीन प्रदेशों (आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) में छेड़े गये दूसरे अघोषित युद्ध से मोर्चा लिया। इस दौर में हमें आन्ध्र में नेतृत्व के बीच से अनेक नुकसान उठाने पड़े। 1985 से लेकर आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा की पुलिस मशीनरी आधुनिकृत और पहले से कहीं ज्यादा फासीवादी हो गयी। दूसरी ओर जनता का सशस्त्र प्रतिरोध भी बढ़ता गया।

1990 के अन्त से एक बार फिर पूरे आन्ध्र प्रदेश में दुश्मन की सशस्त्र आक्रमणकारी मुहिम तेज कर दी गयी। मई 1992 में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} और जन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। फर्जी मुठभेड़ों की एकाएक बाढ़–सी आ गयी। पूरे उत्तरी व दक्षिणी तेलंगाना तथा पूर्वी मण्डल में श्वेत आतंक छाया रहा। पार्टी ने प्रतिरक्षात्मक युद्ध के जरिये इस क्रूर आक्रमण का बहादुरी से मुकाबला किया, एकाएक मौका देखकर तथा सोचे–समझे तरीके से एम्बुश तथा छापे संगठित किये और कुछ स्थानों पर जन मिलिशिया की टुकड़ियों को पुलिस तथा राजकीय सम्पत्ति के खिलाफ सशस्त्र कारवाइयों के लिए लामबन्द किया। अब पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक

बलों के साथ सशस्त्र झड़पें ज्यादा तीव्र हुईं और स्थानीय दुश्मनों के साथ झड़पें गौण हो गयीं।

1990 के दशक में पीडब्ल्यू के छापामार दस्तों की योजनाबद्ध जवाबी कारवाइयों तथा प्रतिरोध के दौरान कई पुलिस थानों व शिबिरों पर छापे मारे गये और हथियार छीने गये। 1996 में कारकागुडम व सिरपुर (ऊपरी) जैसे पुलिस थानों समेत एपी स्पेशल पुलिस व सीआरपीएफ के शिबिरों पर सिलसिलेवार छापों के बाद सरकार को भीतरी इलाकों से अनेक शिविर तथा पुलिस थाने हटाने पड़े। एम्बुशों ने पुलिस तथा अर्द्ध–सैनिक बलों को भीतरी इलाकों में प्रवेश करने से रोके रखा। दूसरे प्रदेशों से लाये गये विशेष बलों, जैसे पंजाब कमाण्डों बल को एम्बुशों ने करारे झटके दिये। दिसम्बर 1994 का लेंकलागड्डा एम्बुश इसका एक उदाहरण है। छापामारों द्वारा बहादुराना सशस्त्र प्रतिरोध से जन आन्दोलनों को नयी गति मिली और 1995 से इनमें वृद्धि हुई। विभिन्न मुद्दों पर वर्ग संघर्ष तथा भूमि कब्जाने के संघर्ष आम बात हो गयी। उत्तरी तेलंगाना के अनेक गाँवों में जनता की जनवादी सत्ता के निकायों के साथ–साथ तमाम जन कमेटियाँ उभर आयीं। पुलिस के खिलाफ हमारी कुछेक जीतों के बाद उत्पीड़ित जनता की पहलकदमी खुल गयीं।

माओ द्वारा प्रस्तुत छापामार युद्ध के उसूलों को अपना आधार बनाते हुए हमने स्थानीय स्थितियों के अनुरूप विभिन्न रूप ईजाद कर लिये। भारत में क्रान्तिकारी युद्ध की खास विशेषता यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास यहाँ चीन जैसी कोई जन सेना नहीं है। यहाँ छोटे–छोटे छापामार दस्तों से शुरू करते हुए जन सेना खड़ी करनी होगी और क्रमशः उच्चतर सैनिक संरचनाओं की ओर विस्तार करना होगा। अलग से जन सेना के न होने के कारण सशस्त्र छापामार दस्तों को लम्बे समय तक सांगठनिक व सैनिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियाँ उठानी होंगी। इसी तरह मजबूत जन सेना की गैर–मौजूदगी और केन्द्रीकृत भारतीय राज्य की श्रेष्ठता के कारण भारत में आधार इलाकों की स्थापना में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगेगा और जयादा समय तक छापामार ज़ोन अस्तित्व में रहेंगे।

'छापामार ज़ोन – हमारा परिप्रेक्ष्य' और 'रणनीति–कार्यनीति' दस्तावेजों में हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों का विश्लेषण किया, रणनीतिक इलाकों की तीन प्रकार की श्रेणयाँ बनायीं और तीनों प्रकार के इलाकों के लिए कार्यनीति सूत्रबद्ध की। इस ठोस विश्लेषण से छापामार ज़ोन व आधार इलाकों के बारे में हमारी समझदारी समृद्ध हुई और विभिन्न राज्य कमेटियों को आधार इलाके स्थापित करने

के मकसद से छापामार ज़ोन विकसित करने के लिए परिप्रेक्ष्य इलाकों का चयन करने में मदद मिली।

इस दौर में हमारा आन्दोलन उत्तरी तेलंगाना और दण्डकारण्य के छापामार ज़ोनों के अलावा पूरे आन्ध्र प्रदेश में भी बढ़ता गया। विभिन्न इलाकों में सामाजिक व भौगोलिक स्थितियों, वर्ग संघर्ष की तीव्रता और जनता की चेतना की स्थिति के सन्दर्भ में भिन्नताएँ हैं। दुश्मन ने भी सभी इलाकों में सशस्त्र तरीकों से आन्दोलन को कुचलने के इरादे से दमन बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिये हैं। अतः 1980 के दशक के अन्त तक सशस्त्र दस्ते केवल उत्तरी तेलंगाना व दण्डकारण्य में ही नहीं, बल्कि आन्ध्र प्रदेश के अन्य इलाकों में भी गठित किये गये।

पार्टी के नेतृत्व में चलाये गये दीर्घकालीन लोक युद्ध के दौरान हमने संघर्ष के रूपों तथा संगठन के रूपों के सम्बन्ध में समृद्ध अनुभव हासिल किये हैं। छापामार युद्ध, जन सेना, जनता की राजनीतिक सत्ता, छापामार ज़ोन, छापामार अड्डों व आधार इलाकों के बारे में हमारी व्यावहारिक एवं अवधारणागत समझदारी भी समृद्ध हुई है। छापामार ज़ोनों में छापामार सेना और छापामार युद्ध ही संगठन और संघर्ष के मुख्य रूप होंगे। जैसे–जैसे जन सेना सुदृढ़ होती जायेगी, वैसे–वैसे छापामार युद्ध भी तीव्र होता जायेगा।

हमने सशस्त्र संघर्ष के अपने समृद्ध अनुभवों को संश्लेषित किया और यह निष्कर्ष निकाला कि छापामार ज़ोनों में मुख्यतः हमारे और दुश्मन के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष होगा। दुश्मन की राजनीतिक सत्ता नष्ट की जायेगी और जनता की सत्ता निर्मित की जायेगी। लेकिन विनाश **मुख्य होगा और निर्माण गौण**। जब छापामार शक्तियाँ तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे और दुश्मन की शक्तियों पर हावी होंगे तब जनता की सत्ता स्थापित हो जायेगी। दूसरी ओर, जब दुश्मन के तीखे हमलों की सूरत में छापामार शक्तियाँ पीछे हटने को मजबूर होंगी तब दुश्मन अपनी सत्ता फिर से स्थापित कर लेगा। इस तरह छापामार ज़ोनों में सत्ता के लिए तीखा संघर्ष चलेगा। दूसरे शब्दों में कहें, तो छापामार ज़ोनों में राजनीतिक सत्ता छापामारों और दुश्मन की सशस्त्र ताकत तथा जन समर्थन के हिसाब से अक्सर एक के हाथ से दूसरे के पास चली जायेगी। अर्थात् यहाँ राजनीतिक सत्ता लम्बे समय तक दोलायमान अवस्था में रहेगी जब तक कि छापामार शक्तियाँ इसे दुश्मन के कब्जे से पूरी तरह मुक्त नहीं करते और आधार इलाके में रूपान्तरित नहीं करते।

इस तरह इलाका विशेष में एक साथ दोहरी सत्ता नहीं चल पाती।

सत्ता या तो छापामार शक्तियों की होती है या फिर दुश्मन वर्गों की। सत्ता में जल्दी–जल्दी एक का स्थान दूसरा ले सकता है। मगर एक ही स्थान पर एक ही समय दोनों वर्गों के हाथ में सत्ता नहीं रह पाती। इसीलिए छापामार युद्ध के विकास के दौर में जब छापामार ज़ोनों में जनता जन राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक पैमाने पर मैदानी जंग में आगे बढ़ रही हो, उस दौरान हमें उन रणनीतिक इलाकों में आधार इलाकों के अभिन्न अंग के रूप में छापामार आधार विकसित करना शुरू करना होगा जो दुश्मन के प्रतिकूल हों और जहाँ जन आधार तथा भूरचना हमारे अनुकूल हों।

मैदानी इलाकों में छापामार युद्ध और ज्यादा दीर्घकालिक होगा। लेकिन मैदानों के उन इलाकों में जहां भूरचना अनुकूल होगी, वहाँ थोड़े समय के लिए मौसमों का लाभ उठाकर बिल्कुल अस्थाई छापामार आधार विकसित किये जा सकते हैं और थोड़े समय के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित की जा सकती है। उसी समय कृषि क्रान्ति के कार्यक्रम को लागू करते हुए जनता को जागृत कर और बड़े पैमाने पर भर्ती बढ़ाते हुए जन छापामार सेना को विस्तारित कर छापामार युद्ध विकसित किया जा सकता है। मैदानों में सत्ता की स्थापना ज्यादा अस्थिर होगी और लहरों के रूप में होगी। कुछ गाँवों में जहाँ जनता की चेतना विकसित होगी, वहाँ राजनीतिक सत्ता के निकाय तैयार हो सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन राजनीतिक निकायों को विकसित करना और जन सत्ता को स्थापित करना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक उस स्तर तक पहुँचा नहीं जाता जहाँ जन छापामार सेना दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त दे रही हो।

छापामार ज़ोन के आसपास के कस्बों में मजदूरों, छात्रों, युवाओं एवं बुद्धिजीवियों को संगठित करने का काम एक महत्वपूर्ण कार्यभार के रूप में किया गया। शहरी इलाकों में काम की गुप्त पद्धतियाँ विकसित की गयीं। वहाँ के कामों को देहाती क्षेत्रों के जन युद्ध के हित साधने की दिशा में और देहात के कामों के साथ करीबी तालमेल करते हुए चलाया गया। कस्बे आपूर्ति केन्द्रों के रूप में; कार्यकर्ता, तकनीकी कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि के भर्ती केन्द्रों के रूप में और गाँवों में चल रहे सामन्तवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन के समर्थन में एकजुटता केन्द्रों के रूप में काम आते रहे हैं। कुछ हद तक साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन विकसित किये गये। क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ दुश्मन के कुत्सा प्रचार का प्रतिकार करने के लिए व्यापक अभियान चलाये गये।

मगर शहरी इलाकों के काम में कई भूलें हुईं। कई नेतृत्वकारी कार्यकर्ता खो देने के कारण गम्भीर नुकसान हुआ। नतीजतन आन्ध्र प्रदेश का शहरी आन्दोलन जो 1990 के दाक के मध्य तक अपेक्षाकृत मजबूत रहा, कालान्तर में कमजोर हो गया।

एआईएससी
और इसकी पार्टी लाइन विकसित करने में भूमिका

अखिल भारतीय विशेष सम्मेलन (1995) ने आठवीं काँग्रेस के बाद देश में तथा अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर आये महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों और पिछले 25 वर्षों से क्रान्तिकारी आन्दोलन तथा पार्टी द्वारा हासिल अनुभवों का रेशा–रेशा विश्लेषण करने के बाद संशोधित **'पार्टी कार्यक्रम'** व **'पार्टी संविधान'**, **'रणनीति–कार्यनीति'** पर दस्तावेज, **'छापामार ज़ोन – हमारा परिप्रेक्ष्य'** दस्तावेज, नया **'राजनीकि प्रस्ताव (वर्तमान राजनीति परिस्थिति और हमारे कार्यभार)'** पारित किये। सम्मेलन ने अतीत के बारे में 1980 की **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** को भी बुनियादी दस्तावेज मानते हुए अनुमोदित किया। सम्मेलन ने राजनीतिक–सांगठनिक समीक्षाओं के मार्फत डेढ़ दशकों के व्यवहार की भी समीक्षा की और केन्द्रीय **'राजनीतिक–सांगठनिक रिपोर्ट'** जारी की। **एआईएससी** ने पार्टी की बुनियादी लाइन की हिमायत करने की इस प्रक्रिया के जरिये और साथ ही मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की रोशनी में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास तथा पार्टी के लम्बे व्यवहार का विश्लेषण करते हुए पार्टी की राजनीतिक, सांगठनिक, सामरिक लाइन को समृद्ध किया। आठवीं काँग्रेस के बाद सम्मेलन की यह सफलता पहली अहम् उपलब्धि रही।

आठवीं काँग्रेस के बाद ढ़ाई दशकों के लम्बे अन्तराल में अनेक टेढ़े–मेढ़े रास्तों की व विजय–पराजय की भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए और 1978 के बाद पुनरुत्थान के दौर से गुजरते हुए पार्टी के पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण व विकास की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर एक नेतृत्व उभर आया था। एआईएससी की प्रक्रिया में यह नेतृत्व जिला, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर के सम्मेलनों में चुना गया। आठवीं काँग्रेस के बाद पहली बार एक अभियान के रूप में जनवादी तरीके से नेतृत्व का चुनाव हुआ था। यह सम्मेलन की दूसरी उपलब्धि रही।

इसके अलावा एआईएससी ने दोनों पार्टी संकटों पर चर्चा की और सबक लिये। इस आकलन ने पार्टी के भीतर दो दिशाओं का संघर्ष जनवादी केन्द्रीयता के

आधार पर एकता–संघर्ष–एकता के दायरे के भीतर एकता का स्तर उन्नत करने के मकसद से, गलत लाइन को पराजित करने या गलत भटकावों को सुधारने के परिप्रेक्ष्य के साथ और इस तरीके से सही अनुभवों व सही लाइन के समुचित आधार पर पार्टी को एकीकृत करते हुए कैसे चलाया जाय – इस पर बेहतर समझदारी विकसित की। यह एआईएससी की तीसरी अहम् उपलब्धि रही।

एआईएससी ने घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में पहले से ज्यादा शानदार होती क्रान्तिकारी परिस्थिति, आन्दोलन के स्तर एवं दिशा और इसके सामने प्रस्तुत चुनौतियों पर गौर करते हुए पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्यभार सूत्रबद्ध किये। तीन महत्वपूर्ण कार्यभारों में से एक यह तय हुआ कि मुख्यतः जन सेना तथा आधार इलाके तैयार करने के इरादे से विजय की ओर आगे बढ़ने के लिए तीन जादुई हथियारों को मजबूत किया जाय। इस आम दिशा की रोशनी में एआईएससी ने विभिन्न राज्यों की ठोस स्थिति के आधार पर प्रदेशव्यापी कार्यभार भी सूत्रबद्ध किये। यह भी एआईएससी की अहम उपलब्धि रही।

उपरोक्त पृष्ठभूमि और अहम् उपलब्धियों की रोशनी में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} के इतिहास में एआईएससी को एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ माना जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की राजनीतिक कार्यनीति की समीक्षा

1969–80 के दौर में **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** दस्तावेज में पार्टी की राजनीतिक समीक्षा की गयी है। 1980 के बाद पार्टी की राजनीतिक लाइन और व्यवहार की समीक्षा करने से पहले आइये, आठवीं काँग्रेस के बाद के घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रम को संक्षेप में देखें।

आठवीं काँग्रेस के समय अमरीकी साम्राज्यवाद और सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद दुनिया की जनता के मुख्य दुश्मनों के रूप में सामने आये। अमरीकी साम्राज्यवाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का मुख्य स्तम्भ तथा प्रतिक्रियावाद का प्रमुख गढ़ रहा, जबकि सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद अपने समाजवादी नकाब के कारण तथा साम्राज्यवादी मैदान पर देर से उतरा खिलाड़ी होने के नाते दुनिया की जनता के खतरनाक दुश्मन के रूप में उभरा।

हमारी पार्टी की आठवीं काँग्रेस के दो दशक बाद तक दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को, खासकर तीसरी दुनिया को जैसा चाहा लूटा; जनसंहार के सबसे

खतरनाक हथयारों से खुद को लैस किया; दुनिया को आपस में बाँटने के उनके मंसूबों के हिस्से के रूप में कभी–कभी दुनिया को एक और विध्वंसकारी विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया।

ठीक उसी समय जब 1970 में आठवीं काँग्रेस हो रही थी, अमरीकी साम्राज्यवाद वियतनाम और कम्पूचिया पर बेरहमी के साथ बमबारी कर रहे थे।

जैसे–जैसे इन महाशक्तियों का उत्पीड़न व शोषण बढ़ता गया, वैसे–वैसे दुनिया की जनता ने अपने प्रतिरोध व संघर्ष भी तेज कर दिये। 1980 के दशक में दोनों महाशक्ति उत्तरोत्तर कमजोर होने लगे। 1990 के दशक की शुरुआत होते–होते सोवियत महाशक्ति का पतन हो गया और अमरीकी महाशक्ति अन्य प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व जमा पाने की स्थिति मे नहीं रहा। दोनों महाशक्तियों का कमजोर होते जाना साम्राज्यवादी संकटों की गहनता को दर्शाता है।

इन दो दशकों में इसी से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व बाजार पर कब्जे के लिए अमरीका से टक्कर लेते जापान और जर्मनी की साम्राज्यवादी आर्थिक शक्तियों के रूप में उद्भव रहा। वे अमरीकी साम्राज्यवाद के विनम्र आज्ञाकारी की स्थिति से उबरकर धीरे–धीरे अपनी आर्थिक शक्ति व राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाते हुए स्वतन्त्र शक्ति बनते गये। सोवियत संघ के पतन के बाद ये अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष प्रतिद्वन्द्वी बन गये। हमारी पार्टी की आठवीं काँग्रेस के बाद के दो दशकों के दौरान साम्राज्यवादी दुनिया के शक्ति–सन्तुलन में जबरदस्त परिवर्तन हुए।

हालांकि आठवीं काँग्रेस के बाद दुनिया की वस्तुगत क्रान्तिकारी परिस्थिति दिन–ब–दिन बेहतर होती गयी है, फिर भी मनोगत शक्तियों का उसी अनुपात में विकास नहीं हो पाया है। यही नहीं, इस दौर में क्रान्तिकारी खेमे को और ज्यादा नुकसान उठाने पड़े।

1976 में कामरेड माओ के देहान्त, आधुनिक संशोधनवादी देंग गुट द्वारा पार्टी व राज्य के मुख्य–मुख्य पदों को हथिया लेने और समाजवादी चीन के पूँजीवादी बन जाने पर विश्व सर्वहारा अपने नेतृत्व से वंचित रह गया। इन घटनाओं ने विश्व सर्वहारा, उत्पीड़ित जनता तथा सभी क्रान्तिकारी शक्तियों और विश्व समाजवादी क्रान्ति को गम्भीर नुकसान पहुँचाया।

हमारे देश में भी पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारतीय शासक वर्गों का सोवियत–परस्त झुकाव 15 सालों तक चला। काँग्रेस पार्टी ने हालांकि 1972 में संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया,

फिर भी जल्द ही इसे गम्भीर आर्थिक व राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और 1975 में पूरे देश पर आपातकाल थोपना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने करीब तीन दशकों तक निर्विवाद रूप से सत्ता सम्भाले के बाद 1977 में सत्ता पर अपना इजारा तब खो दिया जब जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिये। तभी से केन्द्र में अस्थिरता स्थायी विशेषता बन गयी है। केन्द्र के तथा केन्द्र व राज्यों के शासक वर्गों के बीच और एक ही राज्य में शासक वर्गों के अलग–अलग धड़ों के बीच चलने वाली कुत्ता–बिल्ली की लड़ाई अभूतपूर्व रूप से तीखी हुई है।

आठवीं काँग्रेस के समय देश के उत्तर–पूर्व में चल रहे राष्ट्रीयता संघर्ष पिछले तीन दशकों में देश के अन्य हिस्सों तक फैल गये हैं।

कृषि में तथाकथित हरित क्रान्ति के नाम पर साम्राज्यवादियों तथा भारतीय दलाल शासक वर्गों द्वारा लायी गयी आधुनिक प्रणालियों ने देहाती इलाकों में अन्तरविरोध और भी तीखे कर दिये हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर साम्राज्यवादी जकड़बन्दी के कारण देश की राजनीति पर भी साम्राज्यवाद की पकड़ और ज्यादा कसती गयी है।

क्रान्तिकारी शक्तियाँ 1970 के दशक के लगातार तीव्र होते संकट का लाभ उठाने की स्थिति में तो नहीं थे। मगर 1980 के दशक में कुछ हद तक क्रान्तिकारी स्थितियों का लाभ उठाते हुए वे मजबूत होकर उभरे हैं। बावजूद इसके कि देश के कुछ क्षेत्रों में क्रान्तिकारी आन्दोलन उभरे हैं, क्रान्तिकारी शक्तियाँ अखिल भारतीय पैमाने पर अभी भी कमजोर रहीं और विभिन्न ग्रुपों व पार्टियों में विभाजित भी रही हैं।

इस दौर में सीपीआई (एमएल) (पीडब्ल्यू) ने साम्राज्यवाद, खासकर सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़े–बड़े अभियान चलाये। पार्टी ने कम्यूचिया में रूसी हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में घुसपैठ आदि का पर्दाफाश किया और सोवियत रूस के हिमायती भाकपा व माकपा का भी पर्दाफाश किया।

पार्टी ने विभिन्न संघर्षरत राष्ट्रीयताओं – असमी, नागा, मणिपुरी, जम्मू–कश्मीर आदि के साथ रिश्ते स्थापित करने के प्रयास करने की पहल की। पार्टी ने श्रीलंका में तमिल ईलम के संघर्ष में भारतीय शासक वर्गों की घुसपैठ का डटकर विरोध किया। परिणामस्वरूप संघर्षरत राष्ट्रीयताओं ने पीडब्ल्यू को मुख्य दुश्मन के खिलाफ अपने दोस्त और साथी के रूप में देखा।

राजनीतिक खामियाँ

इस दौर में पार्टी ने कुछ गम्भीर गलतियाँ भी कीं। इन्हें मुख्यतः 1991 से पहले

पारित किये गये अपने निम्न तीन राजनीतिक प्रस्तावों में निहित राजनीतिक कार्यनीति में देखा जा सकता है –

(1) सितम्बर 1980 के 12वें आन्ध्र प्रदेश राज्य सम्मेलन में पारित और बाद में मार्च 1981 में सीसी द्वारा अनुमोदित **सोवियत–विरोधी संयुक्त मोर्चा प्रस्ताव**।

(2) 1984 का **राजनीतिक प्रस्ताव**।

(3) अगस्त 1990 में केन्द्रीय प्लेनम में पारित **प्रस्ताव**।

हमने महाशक्तियों, तीन दुनिया के सिद्धान्त तथा विश्व युद्ध के बारे में कुछ गलत आकलन व समझ बनायी थी; माओ के दीर्घकालीन लोक युद्ध के रास्ते को यान्त्रिक तरीके से विश्व समाजवादी क्रान्ति पर लागू किया था आदि। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर हमारी अवस्थिति भी उसके संशोधनवादी बन जाने के काफी बाद, 1983 में अपनायी गयी।

हम एसएनएस तथा वीएम की तरह संशोधनवादी दलदल में धँसने से खुद को बचा पाये। मगर हमने भी तत्कालीन विश्व परिस्थिति के बारे में कुछ मनोगत आकलन किये थे। 'तीन दुनिया के सिद्धान्त' के बारे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की संशोधनवादी समझदारी के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव तो कर दिये थे, फिर भी कुछ त्रुटिपूर्ण समझ बनी रही।

तीन दुनिया का सिद्धान्त और सोवियत–विरोधी संयुक्त मोर्चा का आह्वान

हमने सोवियत–विरोधी संयुक्त मोर्चे का आह्वान किया था, जबकि इसके लिए अभी स्थितियाँ परिपक्व नहीं हुई थीं। यह न केवल अव्यावहारिक आह्वान था, बल्कि इससे पार्टी कतारों के बीच भ्रान्तियाँ भी पैदा हुईं। युद्ध के खतरे पर हमारा अतिरिक्त जोर देना संयुक्त मोर्चे के इस फौरी आह्वान का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सोवियत संघ की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से पहले हिटलर के जर्मनी से करते हुए और उसे युद्ध का ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खतरनाक व ज्यादा भयानक तथ प्रधान स्रोत बताते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व युद्ध अवश्वम्भावी है और इसे टालने के लिए सोवियत साम्राज्यवादियों के खिलाफ व्यापकतम संयुक्त मोर्चा बनाना होगा।

'तीन दुनिया के सिद्धान्त' के बारे में हमने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की समझदारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लिया था। मगर हमने कुछ गलत समझ

भी बनायी जो हमारी राजनीतिक कार्यनीति में पीडब्ल्यू के गठन के बाद लगभग एक दशक तक बरकरार रही, जैसे साम्राज्यवादी महाशक्तियों के खिलाफ युद्ध में तीसरी दुनिया की सरकारों की भूमिका का बढ़ा–चढ़ा आकलन करना।

विश्व युद्ध के खतरे पर अतिरिक्त जोर

हमने उम्मीद की कि दो महाशक्तियों के बीच तीखे अन्तरविरोध के कारण विश्व युद्ध जरूर होगा और तीसरे विश्व युद्ध के बाद क्रान्तियों का तीसरा दौर चल पड़ेगा। हमने इस बात पर जोर नहीं दिया कि साम्राज्यवाद पर सीधा प्रहार करने वाले झंझा–केन्द्रों एशिया, अफ्रीका व लातिन अमरीका के क्रान्तिकारी संघर्ष और अन्य कारक भी युद्ध को रोक सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं।

पीडब्ल्यू की समझ उस समय यह थी कि महाशक्तियों का उद्‌भव साम्राज्यवाद का उत्कर्ष है और उनकी यह हैसियत तब तक बनी रहेगी जब तक युद्ध या क्रान्ति उनका विनाश नहीं करती। 1987–1992 के बीच गोर्बाच्योव के सत्ता में आने के बाद सोवियत संघ के बदलावों; पूर्वी यूरोप के घटनाक्रम; जर्मनी, जापान तथा दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों के उद्‌भव आदि सहित दुनिया के पूरे घटनाक्रम का करीबी से अध्ययन व विश्लेषण करते हुए समय पर पार्टी को शिक्षित करने में हम पिछड़ गये। इसके कारण हम सोवियत महाशक्ति के पतन के बाद भी विश्व युद्ध के फौरी खतरे पर जोर देते रहे।

हम इस बात पर अड़े रहे कि दोनों महाशक्तियाँ हमारे देश पर प्रभुत्व के लिए तीखा संघर्ष कर रही हैं। जबकि वास्तव में भारत में अपने हितों को बनाये रखना सोवियत संघ के लिए बहुत हद तक मुश्किल हो रहा था और अमरीका तथा दूसरी तमाम साम्राज्यवादी शक्तियाँ बाजार व भारतीय राज्य पर अपनी पकड़े बढ़ाने के लिए नयी–नयी योजनाएँ बनाती जा रही थीं।

समकालीन दुनिया में प्रधान अन्तरविरोध का सवाल

आम तौर पर हमारी समझदारी सही रही। मगर एक समय हमने यह कहा कि प्रधान अन्तरविरोध एक ओर दोनों महाशक्तियाँ व उनके पिट्‌ठू तथा दूसरी ओर शेष दुनिया के बीच का है। इस बात को हमने 1992 के राजनीतिक प्रस्ताव में सुधारा। लेकिन फिर 1995 में एआईएससी ने दुनिया में प्रधान अन्तरविरोध को हटा देने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें लगा कि समकालीन दुनिया में प्रधान अन्तरविराध कौन–सा है यह तय करना सम्भव नहीं है और कामरेड माओ ने भी तो प्रधान अन्तरविरोध को

चिह्नित नहीं किया था। सन् 2001 के 9वें काँग्रेस में ही इस कमी को दूर किया गया और साम्राज्यवाद बनाम उत्पीड़ित राष्ट्रों एवं जनता के अन्तरविरोध को प्रधान अन्तरविरोध के तौर पर मजबूती से स्थापित किया गया।

1992 का राजनीतिक प्रस्ताव

दुनिया की परिस्थिति के बारे में उपरोक्त त्रुटिपूर्ण समझदारी मई 1992 के **राजनीतिक प्रस्ताव** में सुधारी गयी। 1992 के **राजनीतिक प्रस्ताव** ने सोवियत महाशक्ति के पतन के बाद दुनिया में आये ठोस परिवर्तनों, साम्राज्यवाद के सर्वव्यापी संकट की गहनता और खास तौर पर 1991 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नव–उदार नीतियों के रूप में साम्राज्यवाद की नयी विश्वव्यापी आक्रामक मुहिम का विश्लेषण किया।

1992 के **राजनीतिक प्रस्ताव** ने देश में हिन्दू फासीवादी शक्तियों के खतरनाक विकास को ध्यान में लिया और इस बात को भी कि कैसे शासक वर्ग व साम्राज्यवादी शक्तियाँ साम्प्रदायिक चाल चलकर जनता में असुरक्षा–बोध पैदा करते हुए फासीवादी शासन थोपने के लिए भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं। प्रस्ताव ने साम्राज्यवादी वैश्वीकरण, हिन्दू फासीवाद की आक्रामक मुहिम तथा बढ़ते राजकीय दमन और जायज व जनवादी जन आन्दोलनों के दमन का प्रतिरोध करने के लिए पूरी पार्टी तथा जनता का आह्वान किया।

राजनीतिक प्रस्ताव की उपरोक्त समझदारी के आधार पर साम्राज्यवादी वैश्वीकरण तथा राजकीय दमन के खिलाफ सभी क्रान्तिकारी शक्तियों तथा अन्य साम्राज्यवाद–विरोधी शक्तियों को साथ लेकर संयुक्त मोर्चे खड़े करने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये। हमने **डंकल प्रारूप** और **विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)** के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किये। 6 दिसम्बर 1992 को भाजपा के नेतृत्व में हिन्दू फासीवादी शक्तियों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के फौरन बाद **सीओसी** ने हिन्दू फासीवादी शक्तियों के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर व्यापक आधर वाले संयुक्त मोर्चे गठित करने का आह्वान करते हुए **परिपत्र (सर्कुलर)** भी जारी किया।

राष्ट्रीयता आन्दोलनों के साथ करीबी तालमेल स्थापित करने के प्रयास भी हुए। राष्ट्रीयता आदोलनों के समर्थन में तथा भारतीय राज्य द्वारा इन आन्दोलनों के फासीवादी दमन के खिलाफ एकजुटता सभाएँ आयोजित की गयीं।

लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण

की नयी नीतियों तथा हिन्दू फासदीवाद की आक्रामक मुहिम का देश–समाज पर जितना ज्यादा संगीन असर पड़ रहा था, उसके मुकाबले हमारी ओर से हुई उपरोक्त प्रतिक्रिया नाकाफी रही।

सार–संक्षेप के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हमने संसदीय व विधान सभा चुनावों, इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा एनटीआर की सरकार की बर्खास्तगी; बाबरी मस्जिद के विध्वंस; साम्राज्यवादी वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण आदि नीतियों; राष्ट्रीयता आन्दोलनों व इन पर राजकीय दमन; आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य सामाजिक तबकों की जायज मांगों के लिए संघर्षों, मजदूर वर्ग के संघर्षों जैसी देश की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में हस्तक्षेप करने के प्रयास किये। हमने खास कर 1977 में आपातकाल के बाद के दौर, 1990 के पूर्वाद्ध में दमन में आंशिक राहत और 1995–96 के बीच राजनीतिक स्थितियों में आये बदलावों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया। हमने जन युद्ध में बढ़–चढ़कर आगे बढ़ने की तैयारियाँ करने के लिए नयी स्थितियों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस दौर में हम देश में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं में कारगर तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सके। सभी क्षेत्रों में हिन्दू फासीवादी शक्तियों की आक्रामक मुहिम रोकने के, खास कर मुसलमानों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने के हमारे प्रयास कमजोर रहे। इस प्रकार 1991 के बाद की नयी स्थितियों में हमने ठोस राजनीतिक कार्यभारों को ठीक से चिह्नित तो कर लिया। मगर अपनी कार्यनीति पर कारगर अमल करने के लिए पार्टी की पूरी कतारों व जनता को गोलबन्द करने व गति देने में हम सफल नहीं हो पाये।

अध्याय–5

भूतपूर्व पीयू का गठन और विकास

नवम्बर 1978 में जेल से बाहर निकले मुट्ठीभर कामरेडों ने सीपीआई (एमएल) (पार्टी यूनिटी) का गठन किया। जेल मे रहते हुए उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अतीत की समीक्षा के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दों पर एक–से विचार विकसित कर लिये थे। सीएम के नेतृत्व वाली सीपीआई (एमएल) में ये सभी सक्रिय रहे। बाद में इनमें से कुछ महादेव मुखर्जी के नेतृत्व वाली दूसरी सीसी (सेकण्ड सीसी) में शामिल हो गये। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अतीत की समीक्षा के आधार पर किसी क्रान्तिकारी ग्रुप से एकता करने के प्रयास किये। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो

पाये। उन्होंने महसूस किया कि अतीत की समीक्षा के आधार पर क्रान्तिकारी संघर्ष विकसित किये बिना एकता के प्रयास हकीकत में उतारे नहीं जा सकेंगे। इस एहसास के साथ उन्होंने संगठन बनाया और सम्मेलन आयोजित कयिा। नवम्बर 1978 में आयोजित हुए सम्मेलन में तीन दस्तावेज पारित हुए – **सीपीआई (एमएल) की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में, एकता के विषय में, सफ़ाये की लाइन बारे में।** समानधर्मी क्रान्तिकारियों के साथ एकता के प्रयस जारी रहे। इस सम्मेलन में संघर्षों का नेतृत्व करने के लिए संगठन बनाने का फैसला हुआ। तदनुरूप नेतृत्वकारी कमेटी गठित की गयी। क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन खड़ा करने के लिए दक्षिण–मध्य बिहार का क्षेत्र चुना गय। यह चुनाव रणनीतिक उद्देश्यों से किया गया था। बिहार के अन्य हिस्सों और पश्चिम बंगाल के नादिया तथा मुर्शीदाबाद इलाकों में भी काम शुरू किया गया।

जब 1978 में पीयू का गठन हुआ तब तीन प्रस्ताव पारित किये गये। पहला था, **सीपीआई (एमएल) के बारे में**। इस प्रस्ताव में 1970 की पार्टी काँग्रेस में पारित पार्टी की विचारधारात्मक–राजनीतिक लाइन, पार्टी गठन और पार्टी कार्यक्रम की बुनियादी लाइन को सही माना गया। प्रस्ताव में कामरेड चारू मजुमदार की संशोधनवाद तथा नव–संशोधनवाद से लड़ाई लड़ने, भारतीय क्रान्ति तथा सशस्त्र संघर्ष का विचारधारात्मक–राजनीतिक आधार स्थापित करने और नक्सलबाड़ी संघर्ष का नेतृत्व करने तथा पार्टी का गठन करने में बेमिसाल भूमिका को सराहा गया। प्रस्ताव मे यह भी कहा गया कि बुनियादी तौर पर पार्टी कार्यक्रम सही था, पर इसमें कुछ खामियाँ रहीं। खामियों में युग के व विश्व युद्ध के सवाल पर गलत आकलन शाकमल रहे।

एकता के विषय में दस्तावेज में इस तीसरे रुझान को कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी खेमे के रूप में पहचानते हुए इसी के साथ एकता करने की हिमायत की गयी थी। इस खेमे में **एपीएससी, सीओसी, एमसीसी** आदि रहे। इसने यह भी चिह्नित किया कि दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी अवसरवाद तथा जड़सूत्रवाद से लड़ते हुए आज आन्दोलन के सामने सबसे गम्भीर व मुख्य खतरा दक्षिणपंथी अवसरवाद व विसर्जनवाद का है। इस बात ने एपीएससी द्वारा तैयार किये **'एससीआर'** तथा **'कार्यनीतिक लाइन'** के दस्तावेजों को समृद्ध करने में मदद की। 1979 के अन्त में एपीएससी एवं पीयू के दस्तावेजों को संयुक्त दस्तावेज बनाते वक्त इन पहलुओं को जोड़ने में भी मदद की।

पीयू की पहली एकता एक छोटे संगठन बिहार के एआईसीसीसीआर का

घटक रह चुके 'कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठन' **(सीकेएस)** के साथ हुई। सीपीआई (एमएल) की बिहार राज्य कमेटी के तत्कालीन सचिव **एसएनएस** के साथ मतभेदों के कारण **सीकेएस** उसमें शामिल नहीं हुआ था। **सीकेएस** में फूट पड़ी और औरंगाबाद तथा पलामू जिलों की सीमा पर काम करने वाले हिस्से का सीपीआई (एमएल) (पीयू) के साथ विलय हुआ। इससे 1980 में सीपीआई (एमएल) (यूओ), अर्थात् यूनिटी ऑर्गनाइजेशन बना।

1980 में एपीएससी के साथ एकता सम्पन्न नहीं हो पायी। यूओ और कामरेड शर्मा तथा अप्पालासूरी के नेतृत्व वाले भूतपूर्व सीओसी, सीपीआई (एमएल) के हिस्सों का विलय हुआ। इससे फिर पीयू बनी। इन दोनों संगठनों के बीच मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारा पर तथा भारतीय क्रान्ति के अनेक बुनियादी मुद्दों, मसलन रणनीति व कार्यनीति पर, देश की तथा अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति पर व्यापक सहमति रही, हालांकि चीनी राज्य के चरित्र जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ मतभेद भी रहे। सीओसी की मान्यता यह रही कि चीन अभी समाजवादी ही है, जबकि पीयू ने 1980 में ही चीन को संशोधनवादी घोषित किया था। यह तय हुआ कि चीन के सवाल पर संयुक्त संगठन मिलकर अध्ययन करेगा और उसके बाद अन्तिम निर्णय लेगा। दोनों ही संगठन अतीत की लाइन में कुछ प्रमुख खामियों के प्रति रचनात्मक रुख अपनाते हुए आत्मालोचनात्मक रहे।

पीयू के साथ कुछ और छोटे संगठनों का भी विलय हुआ। 1990 में पंजाब की 'केन्द्रीय टीम' {सीटी, सीपीआई (एमएल)} का 'तालमेल केन्द्र' (कोऑर्डिनेशन सेण्टर) नाम का घड़ा, जिसे 'संग्राम ग्रुप' भी कहा जाता था, पीयू के साथ एक हो गया। 1988 में सीसीआरआई (एमएल) का बिहार धड़ा पीयू के साथ हो गया।

इस तरह आन्दोलन पुनरुत्थान के दौर में पूर्ववर्ती पीयू विकसित होती चली गयी।

1987 में पीयू ने अपना केन्द्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसके दो पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। एक यह कि इसने तत्कालीन महासचिव द्वारा प्रस्तुत दक्षिणपंथी–विपथगामी लाइन के खिलाफ संघर्ष किया। दूसरा यह कि सम्मेलन ने नया **पार्टी कार्यक्रम** व **संविधान** पारित किया। 1970 के **कार्यक्रम** की प्रमुख विशेषताओं को बरकरार रखते हुए इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण नये पहलू शामिल किये गये थे। इनमें प्रमुख पहलू इस प्रकार रहे – (1) भारतीय समाज का चरित्र अर्द्ध–औपनिवेशिक, अर्द्ध–सामन्ती है, (2) भारत के बड़े पूँजीपति वर्ग का दलाल चरित्र

है, (3) बड़े दलाल पूँजीपति वर्ग और बड़े जमींदार वर्ग भारत के शासक वर्ग हैं, (4) क्रान्ति के निशाने सामाजिक–साम्राज्यवाद सहित साम्राज्यवाद, दलाल बड़े पूँजीपति वर्ग और बड़े जमींदार वर्ग हैं, (5) मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्से–तुंग विचारधारा हमारा विचारधारात्मक आधार है, (6) दीर्घकालीन लोक युद्ध, छापामार ज़ोन, आधार इलाके और जन सेना को खड़ा करते हुए सत्ता पर कब्जा करना होगा। 1987 के सम्मेलन में पारित इस कार्यक्रम में कुछ नये पहलू भी शामिल किये गये थे। इनमें थे – (1) अर्द्ध–औपनिवेशिक तथा अर्द्ध–सामन्ती देश के समग्र ढाँचे के भीतर कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए हैं, खास कर पुरानी जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन और "हरित क्रान्ति" के जरिये। अर्द्ध–सामन्ती ढाँचे के भीतर पूँजीवादी तत्वों का समावेश हुआ है। इसके फलस्वरूप पंजाब जैसे कुछ इलाकों में क्षेत्रीय पैमाने पर एक किस्म का पूँजीवाद विकसित हुआ है, जो विकृत, ठहरावग्रस्त और सामन्ती अवशेषों को साथ लिये हुए है। इस परिवर्तन के कारण देहाती इलाकों में कुछ नये वर्ग उभरे हैं। (2) दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग देश का शासक वर्ग है और देश के विकास तथा क्रान्ति के रास्ते का एक अवरोध। यह साम्राज्यवाद का मुख्य वाहक है। यह क्रान्ति के निशानों में से एक है। इसीलिए इसने दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्गों बनाम व्यापक जनता के बीच के अन्तरविरोध को भारतीय समाज का एक प्रमुख/बुनियादी अन्तरविरोध माना। भारत के इस दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग को साम्राज्यवाद का अधीनस्थ माना गया। यह माना गया कि यह वर्ग एक निश्चित पहचान रखता है, कि यह महज साम्राज्यवाद की यान्त्रिक कठपुतली नहीं है और इसे अपनी वृद्धि की आकांक्षा के लिए मूलतः निर्भरता के ही दायरे में "साम्राज्यवाद तथा सामाजिक–साम्राज्यवाद के साथ सौदेबाजी एवं दाँवपेंच करने की क्षमता की तुलनात्मक स्वतन्त्रता" हासिल है। दलाल इजारेदार पूँजीपति वर्ग खुद की सेवा करने के लिए साम्राज्यवाद की सेवा करते हैं। इससे यह प्रभाव पड़ा मानो उसे "स्वतन्त्र" वर्ग माना जा रहा हो। इसीलिए पीयू ने यह तय किया कि एकता के सवाल पर वह लचीला रुख अपनायेगी। इसीलिए 1998 में पीडब्ल्यू के साथ एकता के समय पीयू ने इस अन्तरविरोध के सवाल पर ऐसा ही किया। (3) पीयू ने यह माना कि "बहुसंख्यक छोटे व मझोले पूँजीपति वर्ग राष्ट्रीय पूँजीपति हैं, हालांकि ये साम्राज्यवाद तथा दलाल पूँजीपति वर्गों पर कुछ हद तक निर्भर हैं।" (4) इसने यह माना कि भारतीय मजदूर वर्ग हमारी क्रान्ति में चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि भारतीय मजदूर वर्ग का विकास तथा आकार काफी बड़ा है आदि–आदि।

पीयू ने बिहार के मगध क्षेत्र में 1980 के मध्य तक आते–आते सार्थक सामन्तवाद–विरोधी संघर्ष खड़ा किया, जिसके बाद यह कोयल–कैमूर (पलामू जिले) की ओर विस्तार करने लगा। आन्दोलन का सीधा प्रभाव मगध क्षेत्र के चार जिलों में करीब हजार गाँवों तक फैला। इनमें से आधे गाँवों में जन संगठन 'मजदूर किसान संग्राम समिति (एमकेएसएस)' की गाँव कमेटियाँ रहीं। 200 से ज्यादा गाँवों में 'ग्राम रक्षा दल' रहे। उस वक्त पूर्ण–कालिक व अंश–कालिक कार्यकर्ताओं को लेकर चार या पाँच सशस्त्र छापामार दस्ते काम करते रहे। इन सशस्त्र दस्तों के सहयोग से भूमि सेना जैसी जमींदारों की कुख्यात निजी सेना को सशस्त्र जन प्रतिरोध के मार्फत परास्त कर दिया गया। दस्ते कभी–कभार पुलिस बलों के हथियार छीना करते रहे। इससे पूरे मगध क्षेत्र में ऐतिहासिक जन उभार आया। जमींदारों से करीब 50 हथियार छीने गये।

1983 की शुरुआत में ही एमकेएसएस के राज्य सम्मेलन पर पुलिस के सशस्त्र हमले से, जिसमें दर्जनों कामरेड घायल हुए थे, राज्य ने अपने दमन अभियान का सूत्रपात किया। सम्मेलन से ठीक पहले एमकेएसएस के एक कार्यकर्ता की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या राज्य की पहली फर्ज़ी मुठभेड़ को अंजाम किया गया था। 1985 में बिहार सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) तैनात कर दी। लेकिन इससे जनता की ओर से और भारी प्रतिरोध खड़ा हो गया। चारों ओर से लाखों लोग एसटीएफ की ज्यादतियों के खिलाफ गोलबन्द हुए। क्षेत्र में चारों ओर आयोजित रैलियों व जन सभाओं में हजारों लोगों ने शिरकत की। अन्य एम0एल0 पार्टियों को साथ लेकर आयोजित ऐसी ही एक जनसभा में 50,000 लोग शामिल हुए। इसके बाद एसटीएफ अस्थायी तौर पर पीछे हटने को बाध्य हुई। फिर भी 19 अप्रैल 1986 को राज्य ने जलियाँवाला बाग काण्ड कराया। अरवल में एक जन सभा पर नृशंस हमला किया गया, जिसमें 23 लोग हताहत हुए और 70 अन्य घायल हुए। विभिन्न क्रान्तिकारी व जनवादी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर इस नरसंहार के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदेश विधान सभा भवन की ओर कूच कर दिया। पूरे बिहार में 40 हजार लोग जगह–जगह हिरासत में लिये गये। इस रैली के कुछ ही दिन पहले एमकेएसएस को राज्य सरकार ने प्रतिबन्धित कर दिया।

1985 तक गाँव स्तर पर एमकेएसएस के 2000 कार्यकर्ता और 20 हजार

सदस्य रहे। संघर्ष के आम रूपों में जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार, फसल कब्जा करना, हड़ताल आयोजित करना, जन पंचायतें लगाना, गुण्डों का सफाया करना आदि रहे। निजी सेनाओं के खात्मे और राजकीय दमन के बाद 1990 के दशक में जन आन्दोलन ने राज्य–विरोधी स्वरूप ग्रहण कर लिया। केके क्षेत्र में जन सेना व आधार इलाके खड़े करने के परिप्रेक्ष्य के साथ मगध क्षेत्र में छापामार ज़ोन तैयार करने तथा जनता की सत्ता के निकाय स्थापित करने का नारा देने के लिए स्थितियाँ अभी परिपक्व हो चुकी थीं। लेकिन 1987 के केन्द्रीय सम्मेलन ने केवल इतना ही सार–संकलन किया कि "दक्षिणी मध्य बिहार सीमा क्षेत्र में विकसित हो रहे किसान संघर्ष की ओर पार्टी को ध्यान देना चाहिए।" संघर्ष की जरूरतों के अनुरूप समय पर नारे न दे पाने तथा ठोस योजनाएँ न बना पाने के कारण आन्दोलन में ठहराव आ गया और फिर गिरावट आयी।

पार्टी ने 1978 मे पलामू जिले के रणनीतिक महत्व को समझते हुए वहाँ प्रवेश किया। 1985 में कोयल–कैमूर क्षेत्र के पलामू जिले के केवल तीन इलाकों तथा रोहतास जिले के केवल एक ब्लाक में पार्टी की गतिविधियाँ चलती रहीं। अभी केवल दो दस्ते ही काम करते रहे। फिर 1988–90 में कोयल–कैमूर क्षेत्र में जन उभार आया। तभी कुछ और दस्ते तैयार कर लिये गये। लेकिन इस केके क्षेत्र में छापामार ज़ोन बनाने की कोई ठोस योजना न होने और नेतृत्व के एक बड़े हिस्से के गिरफ्तार हो जाने के कारण 1991 के बाद आन्दोलन ठहराव के दौर में चला गया।

पीयू के इतिहास में दो बड़े अन्दरूनी पार्टी संघर्ष हुए। एक 1987 में और दूसरा 1997 में। 1987 में आयी वैकल्पिक लाइन ने सीपीआई (एमएल) की बुनियादी लाइन को ही अपना निशाना बनाया था। इस लाइन के हिमायतियों ने मनोगत तरीके से यह आकलन किया कि अर्द्ध–सामन्ती रिश्तों में मूलतः परिवर्तन हो चुका है क्योंकि कृषि में पूँजीवादी सम्बन्ध विकसित हुए हैं और अब कृषि क्रान्ति कालातीत हो चुकी है। लेकिन इतना करने के बाद उन्होंने कोई ठोस कार्यनीति प्रस्तुत नहीं की, हालांकि इसकी तार्किक परिणति सशस्त्र आम बगावत ही होती। परन्तु 1987 में पीयू के केन्द्रीय सम्मेलन में इस लाइन को परास्त किया गया और नयी जनवादी क्रान्ति की धुरी के रूप में कृषि क्रान्ति के साथ ही दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन दोबारा स्थापित हो गयी। इस तरह पार्टी पहले से ऊँचे धरातल पर एकीकृत हो गयी।

1993 में एक सीओसी सदस्य ने पार्टी लाइन पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाये।

ये सवाल 1993 के सम्मेलन रखे गये थे, इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा सका। 1996 के बिहार राज्य सम्मेलन ने 1985–86 के दौरान मगध क्षेत्र में सघर्ष आगे बढ़ाने में विफल रहने का मूल्यांकन किया। लेकिन इसे भी सीओसी ने खारिज किया। 1997 के केन्द्रीय सम्मेलन में जब पीडब्ल्यू के साथ एकता प्रक्रिया के तौर पर 18 वर्षों की समीक्षा की जाने लगी तो उपरोक्त सारे सवालों की परिणति एक सम्पूर्ण संघर्ष के रूप में हुई। बिहार राज्य सम्मेलन के बहुमत द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद भी उनका समालोचनात्मक दस्तावेज केन्द्रीय सम्मेलन में पारित नहीं हो पाया। लेकिन इस दस्तावेज में की गयी कुछ मूल्यवान तथा सही आलोचनाओं को **केन्द्रीय राजनीतिक एवं सांगठनिक रिपोर्ट (पीओआर)** में शामिल कर लिया गया। 1997 में दो दिशाओं के इस संघर्ष ने पीयू की राजनीतिक लाइन को समृद्ध किया। इसका पीयू और पीडब्ल्यू की एकता प्रक्रिया पर भी सकारात्मक असर पड़ा।

पूर्ववर्ती पीयू में विजातीय वर्ग रुझानों का असर आन्दोलन के विकास के दौर में प्रमुख निर्णायक मोड़ों पर नेतृत्व के फैसलों तथा कार्यनीति में और संघर्ष के घिसे–पिटे रूपों तथा संगठन के पुराने स्वरूप को ही जारी रखे जाने में दिखता है। खास तौर पर मगध–कोयल कैमूर क्षेत्र में छापामार ज़ोन तैयार करने का नारा न देने और कोई कार्यभार तय करने के बाद उसे पूरा करने की ठोस योजना न बनाने में मनोगतवाद और दक्षिणपंथी रुझान दिखायी दिया। उसी तरह 1980 के मध्य में पश्चिम बंगाल के नादिया में किसानों को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करने के बाद संघर्ष को अधिक उन्नत अवस्था की ओर विकसित न करना भी पार्टी नेतृत्व में मनोगतवाद और दक्षिणपंथी रुझान को ही दर्शाता रहा। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में भी, जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और लिबरेशन ग्रुप को संशोधनवादी घोषित करने में अनपेक्षित विलम्ब से नेतृत्व का उदारतावाद दिखायी दिया है। कुछ क्षेत्रों में कानूनवाद, गैर–पेशेवराना रवैया और अति जनवाद पर रोक न लगाये जाने के रूप में उतारतावाद दिखायी देता है। इन्हीं विजातीय वर्ग रुझानों के कारण कुछ इलाकों में आन्दोलन धीमा पड़ा और ठहराव का शिकार हो गया।

यही नहीं, 1997 के केन्द्रीय सम्मेलन में मनोगतवाद, नौकरशाही तथा पितृसत्ता काफी मजबूत रही। मगर केवल स्वतःस्फूर्तता, उदारतावाद और कानूनवाद को ही चिह्नित किया गया। इन गलत रुझानों को सुधारने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया। इससे आन्दोलन पर नकारात्मक असर पड़ा।

राजनीतिक खामियाँ

(1) एमएल ग्रुपों के बीच एकता की सम्भावनाओं का बढ़ा–चढ़ा आकलन

पीयू ने एमएल ग्रुपों के बीच मतभेदों को कम करके आँकते हुए उनके बीच एकता की सम्भावनाओं को बढ़ा–चढ़ाकर आँकने की गलती की। विभिन्न एमएल ग्रुपों के समय के साथ विकास की दिशा का मूल्यांकन करने में गलती हुई। 1989 में इस बढ़े–चढ़े आकलन को सुधारने के लिए उन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के मानदण्ड तय किये गये जिनके साथ पीयू की एकता सम्भव होगी। इससे पहले बढ़े–चढ़े आकलन के कारण भ्रम पैदा होते रहे। जहाँ एकता नहीं हो पाती थी वहाँ निराशा पैदा हो जाती थी। साथ ही, एमएल पार्टियों के व्यवहार का आकलन करने के बारे में सोचा नहीं गया। यह सोचा गया कि केवल उनकी अतीत की समीक्षा से सहमति होना ही काफी होगा।

(2) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन एवं छापामार ज़ोन के सन्दर्भ में दक्षिणपंथी रुझान

समय पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवाद की भर्त्सना करने, समय पर लिबरेशन के संशोधनवादी चरित्र का आकलन न करने, सशस्त्र संघर्ष व सशस्त्र संगठन को कुछ समय तक जन संगठन व जन आन्दोलन के मातहत रखने, ठोस रूप से छापामार ज़ोन विकसित करने तथा पूरी पार्टी को इस ओर ले चलने के मामलों में पार्टी नेतृत्व में दक्षिणपंथी रुझान रहा।

(प) संशोधनवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर अवस्थिति न अपना पाना

यूनिटी ऑर्गनाइजेशन ने 1979 में ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पतित हो जाने के बारे में सही अवस्थिति अपना ली थी और 1980 में ही यह घोषित किया गया था कि चीन में संशोधनवादियों ने सत्ता हथिया ली हैं। लेकिन सीओसी के साथ विलय से पीयू का गठन हो जाने पर इस मुद्दे पर समझौता कर लिया गया। पीयू ने तब भी इस पर कोई राय नहीं रखी जब देंग ने सत्ता मे आने के बाद खुलकर माओ विचारधारा तथा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का निषेध करना शुरू किया, जिससे संशोधनवाद की यह बात पूरी दुनिया के लिए शीशे की तरह एकदम साफ हो चुकी थी। पीयू ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति को सही ठहराने का तो फैसला कर लिया मगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर स्पष्ट अवस्थिति 1989 में ही जाकर ली।

यूओ व सीओसी के बीच द्विपक्षीय एकता समझौते के तहत अधिक अध्ययन

करने तक अभी फिलहाल आपसी एकता के हित में 'चीन को समाजवादी देश मानने' की अवस्थिति पर कायम रहने की राय बनी थी। लेकिन इसके बाद अध्ययन करने और विस्तृत आकलन तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा देर की गयी। 1987 के सम्मेलन में भी पार्टी चीन के सवाल पर ठोस अवस्थिति तक पहुँच नहीं पायी। 1987 के सम्मेलन के प्रारूप **प्रस्ताव** में तो यह बात शामिल रही कि चीन अब समाजवादी देश नहीं रहा और संशोधनवादियों ने वहाँ सत्ता हथिया ली थी। लेकिन इसे पारित करने से ठीक पहले इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि बहस नहीं हो पा रही थी। अवस्थिति अपनाने में नेतृत्व की झिझक इसका प्रमुख कारण रही।

इस तथ्य को स्वीकारने में कि समाजवाद चीन में भी पलट दिया गया है, झिझक का कारण नेतृत्व द्वारा पहलकदमी लेने में, अध्ययन तथा बहस करने में तथा निष्कर्ष तक पहुँचने में झिझक रही। निर्णय लेने, अवस्थिति अपनाने और अध्ययन तथा बहस करने में साहसी होने में झिझक नेतृत्व की ओर से उदारतावाद का लक्षण है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवादी घोषित करने में आवश्यक विलम्ब के कारण पीयू की राजनीतिक साख को काफी नुकसान पहुँचा, क्रान्तिकारी खेमे में भ्रान्तियाँ पैदा हुईं और अन्य क्रान्तिकारी ग्रुपों से पीयू की दूरी बढ़ी। इससे पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू के साथ एकता प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। पूर्ववर्ती पीयू के साथ विलय वार्ता के प्रयास 1979–80 में मुख्यतः इसीलिए स्थगित कर दिये थे कि पीयू ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर अभी यही अवस्थिति अपनायी नहीं थी।

(पप) 'लिबरेशन' ग्रुप के प्रति उदार रवैया

देश के क्रान्तिकारी खेमे के लिए बहुत पहले 1981–82 में ही यह स्पष्ट हो चुका था कि वीएम के नेतृत्व वाला लिबरेशन ग्रुप दक्षिणपंथी–अवसरवादी लाइन पर चलते हुए तेजी से संशोधनवाद की ओर बढ़ रहा है। 1985 में वह संसदीय राजनीति में पाँव रखने लगा और खुद को खुली (कानूनी दायरे की) संशोधनवादी पार्टी में रूपान्तरित करने की तैयारी कर रहा था। इसने सशस्त्र संघर्ष छोड़ दिया था, हालांकि अपने अवसरवादी मकसदों के लिए अभी कुछ सशस्त्र दस्ते जारी रखे हुए थे।

जब ऐसी पार्टी के साथ एकता का कोई सवाल नहीं रह गया था, तो भी पूर्ववर्ती पीयू नेतृत्व ने लिबरेशन ग्रुप के प्रति उदार रवैया अपनाया और इसके साथ एकता करने का विचार बनाये रखा। लिबरेशन के दक्षिणपंथी–अवसरवादी राजनीति में पतित हो जाने की बात को देखने के बजाय एमएल एकता की भावना पीयू की

सोच पर हावी रहा। यही सबसे बड़ी खामी रही। पीयू ने 1987 में ही जाकर कहीं वीएम ग्रुप के प्रति सही अवस्थिति अपनायी। इस तरह इस सवाल पर उदारतावाद रहा।

आन्दोलन में बड़ी गम्भीर सामयिक पराजय के बाद पीयू पार्टी ने, खासकर पश्चिम बंगाल में टूट–फूट की निराशा की पृष्ठ भूमि में अतीत के सार–संकलन तथा सीपीआई (एमएल) के सभी क्रान्तिकारी पहलुओं को मूलतः सुरक्षित रखने की सही लाइन के आधार पर एकता स्थापित की थी। तभी से पार्टी सही लाइन पर सदा अडिग रही। शून्य से शुरू करते हुए इसने अच्छा–खासा संगठन विकसित कर लिया। इसने दक्षिण–मध्य बिहार में केन्द्रित होने का सही कदम उठाया और बहुत कम समय में काफी मजबूत किसान संघर्ष विकसित कर लिया। 1982 तक पीयू चार राज्यों बिहार, बंगाल, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश तक विस्तार कर चुकी थी। पार्टी में दक्षिणपंथी भटकाव के उभार के बावजूद पीयू में इस भटकाव से लड़ने की परम्परा भी रही है। 1990 के दशक तक पीयू को अपने जन आधार के सशक्त समर्थन के दम पर क्रान्तिकारी खेमे में सम्मान का दर्जा हासिल हो चुका था। अब इसने पीडब्ल्यू के साथ एकता के प्रयास फिर से शुरू किये। इसी की परिणति अगस्त 1998 में एकता और नये पीडब्ल्यू के गठन के रूप में हुई। पीयू पार्टी ने साबित कर दिया है कि हम अगर सही लाइन के आधार पर रहें ओर इस लाइन पर अविचल अमल करते रहें, तो हम कठिन–से–कठिन स्थितियों एवं बाधाओं को पार करते हुए मजबूत क्रान्तिकारी शक्ति बन सकते हैं।

(पपप) छापामार ज़ोन की ठोस योजना बनाने का सवाल

चीन के रास्ते को अपना रास्ता मानते हुए पीयू ने तत्कालीन चीन और वर्तमान भारत के बीच वस्तुगत स्थितियों की भिन्नता पर सही जोर दिया। पीयू ने भारत की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि ठोस रणनीति इन्हीं से निकलेगी। 1987 के सम्मेलन में भारत में दीर्घकालीन लोक युद्ध की विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा हुई। पीयू ने कुछ रणनीतिक इलाकों पर कामों को केन्द्रित करने को लेकर सही जोर दिया। इसी समझदारी के अनुसार उसने पलामू इलाके में प्रवेश किया। पीयू ने हमेशा कहा कि तत्कालीन दक्षिणी–मध्य बिहार संघर्ष की अग्रिम चौकी बनेगा, कि ..... "दक्षिणी–मध्य बिहार सीमा क्षेत्र में किसान संघर्ष के विकास पर पार्टी को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। यह हमारे सशस्त्र किसान संघर्ष खड़ा करने के साथ मेल

खायेगा।" यह कहने के बाद पार्टी अपने इस परिप्रेक्ष्य को ठोस रूप से विकसित करने में असफल रही।

1987 के सम्मेलन में पार्टी ने यह तो कहा कि आन्दोलन का चरित्र अब धीरे–धीरे सामन्तवाद–विरोधी से राज्य–विरोधी बनता जा रहा है और अब सशस्त्र प्रतिरोध संघर्ष से छापामार ज़ोन से आधार इलाकों तक विकसित करने का परिप्रेक्ष्य रहेगा। लेकिन इन इलाकों को छापामार ज़ोन में रूपान्तरित करने की ठोस तथा सचेत योजनाएँ विकसित करने में नेतृत्व असफल रहा। नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य से कतारों को लैस करने में असफल रहा। 1987 के सम्मेलन में जब पार्टी ने गलत लाइन को परास्त कर दिया था तब कतारों तक छापामार ज़ोन तैयार करने का परिप्रेक्ष्य पहुँचाने का सही समय आ चुका था। फिर भी ऐसा न कर पाने के कारण पार्टी स्वतःस्फूर्तता का शिकार हो गयी। आन्दोलन में आये ठहराव के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है। **छापामार ज़ोन विकसित करने में असफलता गम्भीर खामी रही।** 1993 के सम्मेलन के दौर में ही जाकर कहीं यह मुद्दा सार रूप में उठाया जा सका।

वर्ष 2001 में पार्टी की 9वीं काँग्रेस के बाद कोयल–कैमूर क्षेत्र में छापामार ज़ोन तथा छापामार आधार विकसित करने की ठोस योजना बनायी गयी।

इस मुख्य खामी के अलावा पार्टी में कानूनवाद के रुझान रहे हैं। बिहार, बंगाल और इससे ज्यादा आन्ध्र प्रदेश में यह एक महत्वपूर्ण समस्या रही। इस रुझान के बारे में सीसी के भीतर कोई तीखी आत्मालोचना नहीं रखी गयी। हालांकि इस दक्षिणपंथी भटकाव को सुधारने की शुरुआत हो गयी थी, फिर भी यह रुझान इस हद तक बना रहा कि छापामार ज़ोन तैयार करने की ठोस योजना के आधार पर कार्यकर्ताओं का राजनीतिकरण करने और संघर्ष को ऊँचे स्तर तक विकसित करने की स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि हासिल करने में असफलता रही।

● 1970 की वामपन्थी लाइन के प्रति अति–प्रतिक्रिया रही। यह मनोगतवादी दृष्टिकोण के कारण रहा।

● **एससीआर** तथा **कार्यनीतिक लाइन** को पारित करने में विफलता। पूर्ववर्ती पीयू की **केन्द्रीय राजनीतिक एवं सांगठनिक रिपोर्ट** में इस बात की आत्मालोचना आयी है कि एपी राज्य कमेटी के साथ भले ही एकता नहीं हो पायी थी, फिर भी संयुक्त रूप से स्वीकृत **एससीआर** तथा **कार्यनीतिक लाइन** को बुनियादी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था।

● शुद्धिकरण अभियान चलाने में विफलता। 1995 के बाद का दौर पूरी पार्टी

में शुद्धिकरण अभियान चलाने का सही समय था। लेकिन विजातीय वर्ग रुझानों की गहराई को समझने और पूरी पार्टी में शुद्धिकरण अभियान चलाने के ठोस उपाय तय करने में असफलता रही।

अध्याय–6
पीडब्ल्यू और पीयू में एकता

एकदम शुरुआत से ही सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} और सीपीआई (एमएल) {पीयू} ने एकता के सवाल को सर्वाधिक महत्व दिया। दोनों ने सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठनों की एकता पर जोर दिया, चाहे वे सीपीआई (एमएल) के अंग रहे हों या न रहे हों।

1970 के दशक में पीडब्ल्यू ने सच्ची एमएल पार्टियों के बीच एकता को सबसे फोरी कार्यभार समझा। इसे **'हमारी कार्यनीतिक लाइन'** में इस प्रकार बताया गया है –

"चूँकि हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा मजबूत, एकीकृत पार्टी का निर्माण करना है, हमारी पार्टी का यह प्रधान कार्यभार बनता है कि सच्ची एमएल पार्टियों, ग्रुपों तथा व्यक्तियों को एक ही ढाँचे में लाकर एकताबद्ध किया जाय।"

इस कार्यभार पर अमल करने के लिए 1980 में एक मानदण्ड तय किया गया जिसके अनुसार एमएल शक्तियों में से चुनावों में हिस्सा लेने वाले एक तरफ और चुनावों का बहिष्कार करने वाले दूसरी तरफ कर दिये गये।

इन दोनों श्रेणियों के अनुरूप 1979–80 में सीपीआई (एमएल) की एपीएससी और सीपीआई (एमएल) (पीयू) के बीच एकता वार्ता हुई। **अतीत के मूल्यांकन** और **कार्यनीतिक लाइन** पर उनके बीच समान समझ बनी। मगर पार्टी के बारे में, सीसी गठित करने के बारे में और काँग्रेस आयोजित करने के बारे में अवधारणाओं पर मतभेदों के कारण एकता कायम नहीं हो पायी। पीयू की यह राय रही कि विभिन्न सीपीआई (एमएल) संगठन जनवादी केन्द्रीयता पर अमल करने के बावजूद ग्रुप ही हैं; कि चूँकि वे मूल सीपीआई (एमएल) के अंग रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी नहीं माना जा सकता है। पीयू की मान्यता यह रही कि सीपीआई (एमएल) के प्रमुख क्रान्तिकारी ग्रुपों के एकीकरण के बाद ही पार्टी गठित की जा सकती है और फिर सीसी गठित की जा सकती है।

पीयू ने यह प्रस्ताव रखा कि पहले विलय हो जाय और फिर बाद में एकीकृत

पार्टी में जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर इस सवाल पर बहस हो। पीडब्ल्यू को यह लगा कि एकीकृत पार्टी और सीसी के गठन की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए सीसी गठन और काँग्रेस बुलाने के सवालों पर ही यदि गम्भीर मतभेद बने रहें, तो इससे दो पार्टियों के असली एकीकरण में कोई मदद नहीं मिलेगी। 1970 के दशक में सीपीआई (एमएल) के ग्रुपों के बीच चले एकता के तमाम प्रयासों और फिर तुरन्त फूट हो जाने के सिलसिले को देखते हुए पीडब्ल्यू ने यह आग्रह किया कि इस सवाल पर मतभेदों को विलय से पहले ही सुलझाया जाना चाहिए और तभी जनवादी केन्द्रीयता वास्तव में लागू हो पायेगी। 1980 और 1990 के दशकों के अनुभव पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की इस राय को पुष्ट कर रहे थे। मूल सीपीआई (एमएल) के ज्यादातर धड़े या तो संशोधनवादी पार्टियों के रूप मे पतित हो गये या विलुप्त हो गये थे।

एपीएससी, टीएनएससी और पीयू के बीच एकता प्रक्रिया के दौरान जब पीयू के साथ मतभेद उभरे, तब अप्रैल 1980 में एपीएससी और टीएनएससी ने आगे चलकर पीडब्ल्यू बना लिया था। उधर पीयू पार्टी का भी पंजाब के कामरेड शर्मा वाले सीओसी ग्रुप के साथ विलय हो गया। इसके बाद लिबरेशन ग्रुप ने भी एकता का प्रयास किया। लेकिन लिबरेशन की गलत राजनीति के कारण उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका।

पीडब्ल्यू और एमसीसी की पहली बार 1981 में भेंट हुई। तब से दोनों पार्टियो के बीच रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहे। कालान्तर में उनकी यह राय बनी कि उनकी एकता के लिए आधार मौजद है। इसी के साथ कामरेड केएस और केसी ने एकता वार्ता शुरू की थी। अतः स्वाभाविक तौर पर दोनों पार्टियों ने आपस में वार्ता जारी रखने को पहली प्राथमिकता दी। पीडब्ल्यू और पीयू के बीच एकता–वार्ता के विफल होने के बाद दोनों के बीच अब कोई नियमित रिश्ता नहीं रह गया था। बाद में 1980 के दशक के अन्त में जब पीयू ने चीन के सवाल पर पक्की राय कायम कर ली तभी से नियमित सम्पर्क फिर से शुरू हो गया। फिर 1991 में ही कहीं जाकर पीडब्ल्यू ने पीयू से मिलकर विभिन्न विचारधारात्मक तथा राजनीतिक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने का फैसला किया। लेकिन विचारों का आदान–प्रदान करने और समान राय तक पहुँचने के बजाय कामरेड केएस के नेतृत्व में पीडब्ल्यू के प्रतिनिधि–मण्डल ने पीयू के प्रतिनिधि–मण्डल के सामने पीयू, एमसीसी तथा पीडब्ल्यू का एकता अधिवेशन (कन्वेन्शन) आयोजित करने और अगस्त 1992 के अन्त तक काँग्रेस आयोजित करने का अव्यावहारिक प्रस्ताव रखा। पीयू के कामरेडों ने यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया,

पर अव्यावहारिक होने के कारण यह लागू नहीं हो पाया। उधर पीडब्ल्यू की सीओसी ने इस प्रस्ताव को तत्काल खारिज किया और वापस ले लिया।

1992–93 में चार पार्टियों पीडब्ल्यू, एमसीसी, पीयू और (महाराष्ट्र की) एमआरपीडब्ल्यू ने जब संयुक्त गतिविधियाँ शुरू कीं, तो चारों के बीच कुछ सकारात्मक समझदारी बन पायी। उस दौर में पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू और एमसीसी के बीच एकता वार्ता चल रही थी। इसी समय पीयू ने त्रिपक्षीय एकता–वार्ता का प्रस्ताव रखा। लेकिन पीडब्ल्यू तथा एमसीसी ने यह राय रखी कि इस समय पीयू के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू तथा एमसीसी के बीच लम्बे समय से एकता–वार्ता चल रही है और पीयू तथा एमसीसी के बीच कुछ गम्भीर राजनीतिक मतभेद भी हैं। इसीलिए पीडब्ल्यू और एमसीसी त्रिपक्षीय एकता–वार्ता के पीयू के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पायीं। इसलिए विलय–वार्ता विफल हो गयीं। इसके बाद पीडब्ल्यू और पीयू के प्रतिनिधि–मण्डलों के बीच देश की परिस्थिति तथा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पर विचारों का आदान–प्रदान करते हुए दोनों पार्टियों की यह राय बनी कि दोनों के बीच कई राजनीतिक पहलुओं पर समान समझदारी है। तब 1996 में दोनों के बीच एकता–वार्ता शुरू की गयी।

अब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होने लगी। पीडब्ल्यू ने आग्रहपूर्वक कहा कि एकता की पूर्वशर्त के तौर पर दोनों पार्टियों को अतीत का रेशा–रेशा मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी राजनीतिक–सांगठनिक समीक्षा (पीओआर) तैयार करनी चाहिए। पीडब्ल्यू ने यह काम 1995 में अपने विशेष सम्मेलन में पूरा किया, जबकि पीयू ने 1997 में अपने विशेष सम्मेलन में सभी बुनियादी दस्तावेजों पर एकता हासिल कर ली। इसके बाद उसूली विचारधारात्मक–राजनीतिक–सांगठनिक आधार पर दोनों का विलय हो गया। इन्होंने एकीकृत केन्द्र सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} की केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) का गठन करके अपनी एकता प्रक्रिया को अंजाम तक पहुँचाया। इसी प्रक्रिया में 9वीं काँग्रेस की तैयारी शुरू हो गयी।

1972 में सीपीआई (एमएल) पार्टी के विघटन के बाद जितने विलय हुए हैं, उनमें से इन दो पार्टियों के बीच हुआ यह विलय भारतीय क्रान्ति का सबसे सार्थक विलय रहा है। इस विलय ने देश के भीतर और बाहर के क्रान्तिकारी खेमे में उत्साह पैदा कर दिया। इस एकता के साथ अब सीपीआई (एमएल) की क्रान्तिकारी विरासत को आगे बढ़ाने वाले ज्यादातर सच्चे क्रान्तिकारियों के बीच एकता की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ये सभी अब हमारी पार्टी में एकताबद्ध हो चुके थे।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एकीकृत सीपीआई (एमएल) {पीपुल्स वार} में शामिल दोनों भूतपूर्व पार्टियों ने नक्सलबाड़ी की क्रान्तिकारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसके सभी सकारात्मक पहलुओं को आत्मसात किया; माओवादी नकाब ओढ़ी हुईं तथा सीपीआई (एमएल) के असली वारिस होने का दावा करने वाली तमाम तथाकथित एमएल पार्टियों के सतत प्रहारों एवं कुत्सा प्रचार के खिलाफ सीपीआई (एमएल) की और उसके नेतृत्वाधीन गौरवशाली संघर्ष की सर्वाधिक दृढ़ता से हिफाजत करते हुए 1970 के कार्यक्रम को समर्थन दिया; मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद का दृढ़ता से समर्थन किया और तमाम रूप–रंगों के संशोधनवादियों के खिलाफ अविराम संघर्ष किया; क्रान्तिकारी जन दिशा का सतत अनुसरण करते हुए तथा सशक्त जन आन्दोलनों को खड़ा करते हुए इन्हें सशस्त्र संघर्ष के साथ जोड़ा; माओवादी रणनीति को भारत की ठोस स्थितियों में सृजनात्मक रूप से लागू करते हुए दीर्घकालीन लोक युद्ध के रास्ते पर चलना जारी रखा तथा भारत की ठोस स्थितियो में संघर्ष के संसदीय रूप को पूरी तरह नकार दिया; पेशेवर क्रान्तिकारियों (पीआर) से बने कोर और भूमिगत ढाँचे वाली गुप्त पार्टी का निर्माण किया; भारत में जन युद्ध को आगे बढ़ाने के अपने–अपने अनुभवों के मार्फत सीपीआई (एमएल) की पहली काँग्रेस द्वारा पारित राजनीतिक लाइन को समृद्ध किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दुश्मन के बलों द्वारा छेड़े गये दमन अभियानों के बीच भी आन्ध्र प्रदेश, दण्डकारण्य और बिहार में शक्तिशाली क्रान्तिकारी आन्दोलन खड़ा किया। बहादुरी से दुश्मन का सामना करते हुए हमारे हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता ने अपने प्राणों की आहूति दी है।

फिर भी नयी पार्टी की यह समझ रही है कि सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के एकीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि सीपीआई (एमएल) की धारा की एक बड़ी शक्ति एमसीसी अभी बाहर रह गयी है। इसीलिए हमें इसके साथ बातचीत चलाने का प्रयास करना होगा। साथ ही साथ हमें मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ संयुक्त कार्यों को जारी रखते हुए मार्क्सवादी–लेनिनवादी खेमे के विभिन्न संगठनों के साथ विचारधारात्मक तथा राजनीतिक मामलों पर बातचीत चलानी होगी। विभिन्न क्रान्तिकारी संगठनों के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हमने यह तय किया कि उनके साथ राजनीतिक चर्चा करते हुए उनकी लाइन की कमजोरियों का खुलासा करेंगे।

अध्याय–7
क्रान्ति के तीन जादुई हथियारों को तराशा जाना

कामरेड माओ के द्वारा बताये गये क्रान्ति के तीन उपकरणों या तीन जादुई हथियारों को तराशने के कार्य में हमारी क्या उपलब्धि रही है? पार्टी की राजनीतिक–सामरिक लाइन सही है या नहीं, इसे क्रान्ति के तीन जादुई हथियारों के निर्माण में हुई प्रगति को और देश में जन युद्ध के समग्र विकास को देखकर तय किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति की वस्तुगत समझ हासिल करने के लिए आइये, हम 8वीं काँग्रेस से लेकर 9वीं काँग्रेस तक के विकासक्रम का सार–संकलन करें।

1972 की गम्भीर सामयिक पराजय से उबरने के बाद हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी आन्दोलन इन पिछले वर्षों में देश के कई राज्यों तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य छोटे–छोटे हिस्सों तक फैला। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अब हमारी पार्टी एक शक्तिशाली चुनौती बनकर उभरी। एकीकृत सीपीआई (एमएल) {पीपुल्स वार} दरअसल मूल सीपीआई (एमएल) और नक्सलबाड़ी की गौरवशाली विरासत की असली वारिस है, यह वही पार्टी है जिसने 1970 के कार्यक्रम के आधार पर भारत में जन युद्ध को आगे बढ़ाते हुए आकार ग्रहण किया।

सच्ची सर्वहारा पार्टी का निर्माण

जुलाई 1972 में कामरेड सीएम की शहादत के बाद कोई केन्द्रीय नेतृत्व, यानी सीसी अस्तित्व में नहीं रही। ज्यादातर पार्टी कमेटियाँ ऊपर से नीचे तक ध्वस्त रहीं। प्रत्येक प्रदेश में पार्टी कई–कई खण्डों में विभाजित रही। क्रान्तिकारी उफान अब शिथिल पड़ गया था और तमाम किसान संघर्षों की सामयिक पराजय हो चुकी थी। सबसे ज्यादा कठिन इस दौर में हमारा सर्वोच्च कार्यभार इस स्थिति से उबरना और एकदम शून्य से शुरू करते हुए पार्टी का पुनर्निर्माण करना रहा।

इस पुनर्गठन और पुनरुत्थान ने समाज के विभिन्न हिस्सों/क्षेत्रों से सर्वथा नयी पीढ़ी को पार्टी से ला जोड़ा। इस पुनरुत्थान ने उन ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से ढालकर तैयार किया, जिन्होंने आन्दोलन का निर्माण करने तथा नेतृत्व करने में अहम् भूमिका अदा कीं। संघर्ष के इस दौर में कुछ ही सालों में सैकड़ों पार्टी सदस्य प्रशिक्षित हुए। अब पार्टी कमेटियाँ गठित की गयीं। मुख्यतः प्रदेश व जिला स्तरों पर

नया नेतृत्व उभर आया।

आठवीं काँग्रेस की बुनियादी लाइन का अनुसरण करते हुए और अतीत से सबक तथा हाल के पुनरुत्थान के अनुभव हासिल करते हुए पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू को पुनर्गठित किया गया। यह न केवल 1980 में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} के गठन का आधार बना, वरन् सच्चे क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों के साथ बाद में हुए प्रत्येक विलय का भी आधार बना। भारत की सच्ची कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तियों के एकीकरण की हमारी प्रक्रिया में कुछ खामियों के बावजूद, हमने जिन तौर–तरीकों को अपनाया, वे मूलतः सही रहे।

हमने अपने ही अतीत के अनुभव से नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रान्तिकारियों के अनुभवों से भी कार्यनीति सीखी। हमने मार्क्सवादी कार्यनीति के उसूलों का दृढ़ता से पालन किया। साथ ही, सृजनात्मक रूप से कार्यनीति को विकसित करने का प्रयास किया। दीर्घकालीन लोक युद्ध की बुनियादी लाइन पर मजबूत पकड़ कायम रखते हुए हमने अगस्त 1977 में और 1990 में आन्ध्र प्रदेश में अपनी कार्यनीति को साहस के साथ बदला। बहुत से राज्यों में हमने स्वतःस्फूर्त संघर्षों में दखल दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। हमने सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक स्थितियों तथा आन्दोलन के स्तर के अनुरूप विभिन्न मोर्चों पर अलग–अलग इलाके में अलग–अलग कार्यनीति अपनायी। हमारी कार्यनीति का मकसद हरदम तीन जादुई हथियारों का निर्माण करना और आधार इलाकों की स्थापना करना रहा है। कार्यनीति पर समग्र ज्ञान तथा पकड़ होना नेतृत्व के लिए क्रान्ति को सफल नेतृत्व प्रदान करने की एक शर्त है। कार्यनीति के सन्दर्भ में कुछ उपलब्धियाँ हासिल करने के अलावा क्रान्ति को सफल नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरना भी जरूरी है।

अपने जन्म से, यानी 1969 से ही हमारी पार्टी एक गुप्त पार्टी रही है, जिसका मकसद शोषक–शासक वर्गों को उखाड़ फेंकते हुए राजनीतिक सत्ता छीन्ना रहा। हमारी पार्टी दशकों से चले आ रहे दुर्द्धर्ष सशस्त्र संघर्ष से गुजरते हुए विकसित हुई है, जिस दौरान इसने दमन अभियानों के रूप में युद्ध की निर्ममता का सामना किया। कई महान नेताओं सहित हजारों शहीदों ने अपना बलिदान देकर क्रान्ति के चमकते लाल रास्ते को तैयार किया है। गुप्त कार्यशैली में पर्याप्त अनुभव हासिल करने के बावजूद हमने अनेक गलतियाँ कीं और कई बड़े नुकसान उठाये। हमें वैज्ञानिक तौर–तरीकों का अभी और विकास करना होगा और गुप्त कार्यप्रणाली के उसूलों का सख्ती से पालन करना होगा। हमें खुले व कानूनी कार्यों का गुप्त व गैर–कानूनी कार्यों

के साथ कारगर तरीके से तालमेल करना होगा और इन पर अनुशासित तरीके से अमल सुनिश्चित करने के लिए अपने गैर–सर्वहारा वर्ग रुझानों से उबरने का प्रयास करना होगा।

हमारी पार्टी दो बड़े अन्दरूनी पार्टी संकटों के दौरान तप चुकी है और बेहतर आन्तरिक एकता कायम कर चुकी है। आत्मालोचना, आलोचना की पद्धति हमारी पार्टी जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। हमने एआईएससी के समय और फिर 9वीं काँग्रेस के दौरान गलत रुझानों को पहचाना। हमें इन निम्न–पूँजीवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ सतत संघर्ष चलाना होगा और इन्हें समय रहते सुधारना होगा।

क्रान्तिकारियों की एकीकरण पार्टी निर्माण का महत्वपूर्ण अंग

पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू ने जहाँ एक ओर आन्ध्र प्रदेश, दण्डकारण्य के आन्दोलन को मजबूत करने के लिए केन्द्रित होकर प्रयास किये, वहीं दूसरी ओर इसने 1980 के दशक में और 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में एमसीसी के साथ एकता–प्रक्रिया को भी महत्व दिया। लेकिन दो अन्दरूनी संकटों तथा दुश्मन के तीखे आक्रमणों का सामना करते हुए पार्टी का ध्यान एकता–वार्ताओं पर हर समय केन्द्रित नहीं रह सका। भले ही कभी–कभी ध्यान भटका हो, फिर भी पार्टी ने एकता का मकसद कभी भी नहीं त्यागा।

1977 के बाद हमने केवल बुनियादी दस्तावेजों पर एकता–वार्ता करने के बजाय पहले आन्दोलन खड़ा करने पर और इसी आधार पर क्रान्तिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करने पर जोर दिया। यह समझदारी सही साबित हुई। आन्ध्र और डीके में हमने 1977 और 1992 में जो आन्दोलन खड़े किये, उन्हीं से देश भर के क्रान्तिकारियों का ध्यान हमारी ओर खिंचा। जन संघर्षों के विभिन्न रूपों और दुश्मन के प्रत्याक्रमणों का सामना करते वक्त जनता तथा पार्टी की दृढ़ता के कारण ही आज तमाम क्रान्तिकारी शक्तियाँ हमारी पार्टी में भरोसा रख रही हैं। पार्टी द्वारा आन्ध्र तथा डीके के सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलनों को विकसित कर आधार इलाकों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य के साथ इन्हें ऊँचे स्तर पर पहुँचाते हुए छापामार ज़ोन तक विकसित करने में किये गये प्रयासों के कारण पूरे देश की माओवादी शक्तियाँ आकर्षित हुई हैं। बहुत सारी क्रान्तिकारी शक्तियों ने विकल्प तलाशते हुए किसी–न–किसी सम्पर्क के माध्यम से पार्टी से बातचीत शुरू की।

1993 में पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की सीसी ने 1987 में अलग हुए महाराष्ट्र पीडब्ल्यू

के साथ वार्ता की। 1994 में हमने महाराष्ट्र पीडब्ल्यू के साथ एकता पूरी कर ली। जब हम उनसे अलग हुए थे तब भी हमारे बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं रहे। एआईएससी की बाद में यह राय बनी कि अगर 1985–87 के अन्दरूनी संकट का निराकरण करने के लिए अखिल भारतीय प्लेनम बुलाया गया होता, तो इतिहास की धारा एकदम अलग तरीके से चल पड़ी होती।

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल में दक्षिणपंथी–विपथगामी (और कुछ वाम विपथगामी पार्टियों) से कुछ कामरेड हमारे साथ सम्पर्क साधने के बाद गहन अध्ययन करते हुए हमारी पार्टी लाइन को समझने लगे। इन शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए सीसी ने 1993 में निम्न मार्गदर्शक बिन्दु तैयार किये –

(1) भिन्न पार्टियों से हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आने वालों के साथ हमें अपने बुनियादी दस्तावेजों पर रेशा–रेशा चर्चा करने की जरूरत है। हमें बुनियादी दस्तावेजों पर उनकी राय तथा संशोधन ले लेने चाहिए।

(2) जो कामरेड अपनी पार्टी से बाहर निकलकर हमसे एक होना चाहते हैं, उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकलने के कारण लिख लेने चाहिए और अपने अतीत की गलत लाइन तथा व्यवहार के विषय में राजनीतिक–सांगठनिक समीक्षा भी लिखनी चाहिए। इनके पीओआर पर चर्चा करके उनकी विशेष बैठक/प्लेनम के रूप में उचित मंच पर इसे अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

(3) इन्हें पार्टी सदस्यता दी जानी चाहिए और इनके विकास के अनुरूप स्तर तय किया जाना चाहिए।

(4) पार्टी कमेटी का स्तर चाहे जो हो, इसमें केवल पीआर ही होने चाहिए। किसी नये प्रदेश में जहाँ हमारी पार्टी न हो वहाँ उनकी अगर कोई नेतृत्वकारी टीम हो, तो हमें प्रदेश या जिला तालमेल कमेटी बनानी चाहिए और दो वर्षों बाद उसके विकास के अनुरूप पूर्णरूपेण कमेटी गठित करनी चाहिए।

(5) सीसी ने यह निर्देश दिये कि अगर किसी का कोई मामूली मतभेद हो, तो वह अपने मतभेद दर्ज करके हमसे जुड़ सकता/सकती है।

उपरोक्त समझदारी के आधार पर 1994–95 के दौरान व्यापक चर्चा चलाने और उपरोक्त मानदण्डों पर चर्चा कर लेने के बाद सम्बन्धित ग्रुपों/पार्टियों के प्लेनम आयोजित करने के बाद विलय के अनेक मामलों को अन्तिम रूप दिया गया।

1996 में बंका (भागलपुर, बिहार) में कार्यरत सेकण्ड सीसी के एक ग्रुप का पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू में विलय हुआ।

एआईएससी के सफल समापन और नये राज्यों में विस्तारित पार्टी के सुदृढ़ीकरण के बाद पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू को अखिल भारतीय दर्जा मिला। इसकी पार्टी इकाइयाँ आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ (तब यह मध्य प्रदेश रहा), महाराष्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार (वर्तमान झारखण्ड सहित), उड़ीसा, हरियाणा इत्यादि। पीडब्ल्यू और पीयू के विलय ने एकीकृत पार्टी की हैसियत और बढ़ा दी। ऐसे समय पर एमसीसी के साथ वार्ताओं की विफलता निश्चित तौर पर नकारात्मक घटना रही। एक दशक से भी ज्यादा समय से हमारे बीच एकता की बड़ी आशाओं के बाद मई 1995 में वार्ताओं की विफलता सचमुच क्रान्तिकारी शक्तियों के लिए निराशा की बात रही।

पार्टी निर्माण के साढ़े तीन दशक पुराने इतिहास ने हमें कई सकारात्मक उपलब्धियाँ हासिल करायीं। लेकिन साथ ही, इसने हमें अर्द्ध–औपनिवेशिक, अर्द्ध–सामन्ती भारत में एक सच्ची सर्वहारा पार्टी का निर्माण करने की राह में आने वाली गम्भीर समस्याओं से भी रूबरू किया।

पहली बात यह कि सीपीआई (एमएल) का गठन भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में बड़ा ब्रेकथ्रू रहा है। इसने देश की उत्पीड़ित जनता को यह दिखा दिया कि क्रान्तिकारी पार्टी होती कैसी है? सर्वहारा वर्ग के विचारधारात्मक तथा राजनीतिक नेतृत्ववाली, एकदम सख्ती से भूमिगत ढाँचे वाली पार्टी; ऐसी जिसका नाभिक या कोर सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और विकसित तत्वों से बना होता है; जो सही मायने में जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर कार्य करती है; जो वर्ग संघर्ष तीखा करने के दौरान खुद का शुद्धिकरण करती है। हम हजारों पेशेवर क्रान्तिकारियों के कोर वाली क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण करने में तो सफल हुए, पर जनता के विभिन्न तबकों के बीच अंशकालिक कार्यकर्ताओं के विस्तृत ताने–बाने का निर्माण करने में हम असफल रहे। हमारी इस समस्या का सम्बन्ध उन दिनों अंशकालिक कार्यकर्ताओं के बारे में धारणा एवं समझदारी से रहा। पार्टी सदस्यता तब केवल उन्हीं को दी जाती रही जो क्रान्ति के लिए पूरा समय काम करने के लिए चल पड़ते हैं।

इस गलत समझदारी को बाद के दौर में सुधारा गया और अंशकालिक कार्यकर्ताओं को भी सदस्यता दी जाने लगी। मगर अभी पार्टी में अंशकालिक कार्यकर्ताओं की भूमिका कोई खास महत्व की नहीं बन पायी है। देश की उत्पीड़ित जनता पर पार्टी का जितना व्यापक प्रभाव है, उसकी तुलना मे अंशकालिक सेल बहुत कम हैं। इस तरह जन युद्ध के दौरान जनता का नेतृत्व करने की दृष्टि से अभी

स्थानीय पार्टी नेतृत्व कमजोर ही है। जनता की समस्याओं को सुलझाने तथा दुश्मन का प्रतिरोध करने के लिए अभी इलाकाई कमेटी या दस्ते के सदस्यों पर जनता की निर्भरता बनी हुई है, इस स्थिति ने पार्टी के भीतर अनेक गैर–सर्वहारा रुझानों को पैदा किया है, जैसे नौकरशाही, संकीर्णतावाद, व्यक्तिवाद, मनोगतवाद आदि। इस प्रकार पेशेवर क्रान्तिकारियों के स्थाई नाभिक (कोर) के इर्द–गिर्द अंशकालिक कार्यकर्ताओं के विस्तृत ताने–बाने का निर्माण करने की समस्या किसी न किसी रूप में आज भी पार्टी में बरकरार है।

दूसरी बात यह कि सामयिक पराजय और कामरेड सीएम की शहादत के बाद 1972 में सीसी के विघटन के दिनों से भारतीय क्रान्ति के एक निर्देशन–केन्द्र का गठन न हो पाना सभी को खलता रहा है। असंख्य केन्द्र और विभिन्न एमएल संगठनों में फूट–दर–फूट इस समीक्षा के दौर की विशेषता रही है। पीडब्ल्यू और पीयू ने 1978 में अपने विलय से पहले विभिन्न सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को एक करने के स्वतन्त्र प्रयास किये थे। इसमें उन्हें कुछ उपलब्धियाँ मिलीं।

तीसरी यह कि पार्टी विभिन्न स्तरों पर अपेक्षाकृत मजबूत तथा समर्थ पार्टी कमेटियों का निर्माण करने में कुछ हद तक सफल रही, जो कि पूर्ववर्ती दौर में नहीं हो पाया था। वर्ग दुश्मनों और उनके राजकीय तन्त्र के खिलाफ एक दीर्घकालिक संघर्ष, अर्थात् अन्दरूनी पार्टी संघर्ष तथा सशस्त्र संघर्ष दोनों एक साथ चलाते हुए केन्द्रीय नेतृत्व सुदृढ़ तथा मजबूत हुआ।

हमारे पार्टी निर्माण में नेतृत्व की निरन्तरता हमेशा एक गम्भीर समस्या रही है। 1972 में पहली सीसी भंग हुई। इसके बाद 1980 में ही कहीं जाकर पीडब्ल्यू और पीयू ने नये केन्द्र स्थापित किये। मगर दोनों केन्द्रों का अखिल भारतीय चरित्र नहीं नहीं रहा। पीडब्ल्यू के केन्द्रीय नेतृत्व का संघटन 1992 के बाद स्थिर होने तक बहुत ज्यादा बदलता रहा। अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में केन्द्रीय स्तर पर नेतृत्व की निरन्तरता की ऐसी समस्या शायद ही कभी रही हो।

पिछले एक दशक से इस समस्या का मूलतः निराकरण हो चुका है। नेतृत्व के कुछ गम्भीर नुकसानों के बावजूद केन्द्रीय नेतृत्व ज्यादा सुदृढ़ व मजबूत हुआ है। यह पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू में पहले एसएम–वीएस तथा बाद में केएस–बन्दैया के नेतृत्व में अवसरवादी–विसर्जनवादी गुटों के खिलाफ और पूर्ववर्ती पीयू में अशोक की दक्षिणपंथी–विपथगामी नीतियों के खिलाफ गंभीर अन्दरूनी पार्टी संघर्षों के बीच से विकसित हुआ है।

लेकिन अभी पार्टी में विर्भिन्न स्तरों पर नेतृत्व की निरन्तरता की समस्या बरकरार है। पार्टी का जन आधार केवल कुछ ही प्रदेशों तक सीमित होने के कारण हमारी पार्टी का प्रभाव और स्वीकार्यता उन्हीं प्रदेशों तक सीमित है जहाँ हमारा जन आधार है।

चौथे यह कि विभिन्न गैर–सर्वहारा रुझानों तथा विचारधारात्मक– राजनीतिक कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए शुद्धिकरण अभियान चलाते हुए पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों से कुछ प्रदेशों तथा विशेष ज़ोनों में सकारात्मक नतीजे मिले हैं। पार्टी का नेतृत्व तथा कार्यकर्ता ज्यादा गहराई से इन भटकावों तथा कमजोरियों को पकड़ पाये हैं और कुछ हद तक इनसे उबर पाये हैं। लेकिन कुछ प्रदेशों में तथा नेतृत्वकारी कमेटियों के भी एक हिस्से में यह समस्या अभी कुछ हद तक गम्भीर रूप से बनी हुई है।

पिछले कुछ सालों से कुछ सुधार होने के बावजूद अभी पार्टी के विभिन्न स्तरों पर मनोगतवाद, उदारतावाद, स्वतःस्फूर्तता, संकीर्णता, नौकरशाही, कानूनवाद, पितृसत्ता आदि की समस्याएँ अलग–अलग हद तक परेशानी का सबब बनी हुई है। पार्टी में, खास तौर से पूर्ववर्ती पीयू में पेशेवराना रवैये के अभाव की समस्या भी रही है जिसका सीधा असर सशस्त्र संघर्ष के विकास पर पड़ता है। पार्टी के सामने इस समस्या से जूझते हुए सच्ची बोल्शेविक सर्वहारा पार्टी में रूपान्तरित होने का अत्यन्त फौरी कार्यभार है।

आखिर में पार्टी का वर्ग आधार जो शुरुआती दौर में ज्यादा निम्न–पूँजीवादी चरित्र का रहा, कालान्तर में बुनियादी वर्गों का होता गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बहुसंख्या समाज के सबसे ज्यादा उत्पीड़ित तबके भूमिहीन तथा गरीब किसानों से आने वालों की है। जबकि मध्यम किसानों तथा शहरी एवं ग्रामीण निम्न पूँजीपति वर्गों के निचले हिस्सों से आने वाले भी बड़े अनुपात में हैं। खास तौर से 1995 के बाद विशेष सामाजिक तबकों से आये हुए कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा प्रोन्नति पर विशेष ध्यान दिये जाने के फलस्वरूप पार्टी में अब दलितों, महिलाओं तथा आदिवासियों के बीच से कार्यकर्ता ठीक–ठाक अनुपात में हैं। लेकिन इन उत्पीड़ित तबकों पर अभी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर से उन्हें नेतृत्वकारी स्तरों तक विकसित करने पर।

हमारे पार्टी निर्माण में मजदूर वर्ग पर संकेन्द्रण का अभाव एक बड़ी कमजोरी रही है। नतीजतन मजदूर वग की पृष्ठभूमि से आये कार्यकर्ता बहुत कम हैं। हालांकि

हमारे अर्द्ध–सामन्ती समाज में किसान ही भर्ती का प्रधान स्रोत होते हैं, फिर भी संगठित तथा असंगठित मजदूर वर्ग की बड़ी संख्या को देखते हुए इस बात की बड़ी जरूरत महसूस होती है कि इस बुनियादी प्रेरक शक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाय और उन्हें नेतृत्वकारी स्तरों पर विकसित किया जाय, ताकि वे क्रान्ति में अपनी अगुवा भूमिका अदा कर सकें।

जन सेना का निर्माण

भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में जन सेना का निर्माण एक सतत समस्या रही है। नक्सलबाड़ी से पहले वाले दौर को और उस दौर को अगर छोड़ा जाय जब संशोधनवाद हावी रहा, तो जन छापामारों द्वारा मागुर्जन में दुश्मन की शक्तियों से हथियार जब्त करने के बाद हमने पहली बार भ्रूण रूप में जन मुक्ति सेना (पीएलए) के गठन की घोषणा की थी। 1972 में आन्दोलन के गम्भीर सामयिक पराजय के बाद इसे विकसित नहीं किया जा सका।

हमारे देश में हम एकदम शून्य से सेना का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए जन सेना के निर्माण के काम में हमें काफी संश्लिष्टता का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण हमसे कुछ गम्भीर गलतियाँ भी हो रही हैं। ठोस अध्ययन में हमारी खामियों, सामरिक लाइन के बारे में आवश्यक सैद्धान्तिक ज्ञान के अभाव और पार्टी कमेटियों की कार्यप्रणाली में स्वतःस्फूर्तता के कारण हमने जन छापामार सेना के गठन की कोई सम्यक् योजना तैयार करने के बजाय समय–समय की आवश्यकताओं के अनुरूप दस्ते बनाने के फैसले किये।

शुरुआत से ही हमारी पार्टी सशस्त्र बल के जरिये राजनीतिक सत्ता छीन्ने और युद्ध के जरिये मुद्दों का समाधान करने की रणनीतिक अवधारणा को लेकर काम करती रही है। नक्सलबाड़ी तथा श्रीकाकुलम आन्दोलन की सामयिक पराजय के बाद हमने तेलंगाना में करीमनगर एवं अदिलाबाद के किसान जनउभार से पहले और बाद में छापामार दस्तों का निर्माण करने के प्रयास किये। हमने छापामार ज़ोन परिप्रेक्ष्य के हिस्से के तौर पर डीके में 1980 में दस्तों का निर्माण शुरू किया। हम अपने छापामार ज़ोन परिप्रेक्ष्य के अनुसार चुने गये उत्तरी तेलंगाना के जिलों में 1983 से नियमित दस्ते गठित करते रहे हैं। ये दस्ते सांगठनिक तथा सामरिक, दोनों ही प्रकार के कार्यभार लागू करते रहे हैं। तब से हमारी पार्टी छापामार दस्ते और छापामार युद्ध विकसित करती रही है।

बिहार के मगध क्षेत्र में 1981 से सशस्त्र दस्ते गठित किये गये। इन्हें जमींदारों और उनकी निजी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र किसान दस्तों के रूप में गठित किया गया। इनमें छापामार तथा मिलिशिया के सदस्य, दोनों ही रहे। इन दस्तों के अलावा सांगठनिक पहलुओं तथा दमन के पहलुओं के मद्देनजर कभी–कभी पार्टी संगठनकर्ताओं को मिलाकर अस्थायी दस्ते भी गठित किये जाते रहे हैं।

उत्तरी तेलंगाना तथा दण्डकारण्य को उच्च–स्तरीय छापामार ज़ोन के रूप में विकसित करने के लिए तैयार किये गये दिशा–निर्देशों में हमने कुछ शर्तें रखीं। ये शर्तें प्लाटून को सेना का आम रूप बनाने और ऊपर से नीचे तक केन्द्रीकृत सैन्य कमाण्ड तैयार करने की रहीं। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के लिए किस तरह अमल होगा, मसलन छापामार बलों को विकसित कर नियमित सैन्य संरचनाएँ कैसे बनायी जाती हैं; आवश्यक कमाण्ड कैसे गठित किया जाता है; इन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता होगा; नियमित सेना तथ मिलिशिया के बीच किस तरह का रिश्ता होगा; आधार इलाके तथा सेना के बीच किस तरह का रिश्ता होगा; सेना तथा राजनीतिक सत्ता के बीच किस तरह का रिश्ता होगा इत्यादि बारीकियों पर हमारी कोई गहरी समझ नहीं रही। इसीलिए हम 1995 में जन छापामार सेना के निर्माण का फैसला नहीं कर सके।

पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू के इलाकों में जब पहले के दिनों की तुलना में युद्ध की तीक्ष्णता बढ़ी और दमन भी गम्भीर रूप से बढ़ा, तो प्रतिरोध का कार्यभार भी और ज्यादा अहमियत का बनता गया। दरअसल कुछ इलाकों में हमने पहले 1993 में ही 'विशेष सैन्य दस्ते' गठित कर लिये थे, पर ये विशेष दस्ते ज्यादा समय तक चलने वाला आम रूप नहीं ग्रहण कर पाये। 1995 के बाद 'स्थानीय छापामार दस्ते' (एलजीएस), 'केन्द्रीय छापामार दस्ते' (सीजीएस) और प्लाटून भी बनाये गये। मगर अभी इन्हें अलग सैन्य कमाण्ड के तहत नहीं लाया गया। सैन्य मामलों पर विशेषज्ञता हासिल करने तथा ध्यान केन्द्रित करने के विशेष प्रयासों के हिस्से के रूप में 1996 मे अलग उप कमेटी, केन्द्रीय 'स्कोमा' (सामरिक मामलों पर उप कमेटी) गठित की गयी। हमने सैन्य सिद्धान्त को व्यवहार में उतारने का और अपने छापामार बलों की लड़ाकू क्षमता, तकनीक तथा निपुणता विकसित करने के प्रयास किये। कुछ प्रदेशों में हमने राज्य स्कोमा भी गठित का लिये। इन सभी उपायों से सामरिक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हुई और हमारे सशस्त्र प्रतिरोध में सुधार हुआ। वास्तव में पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की सीसी ने राजनीतिक, सांगठनिक तथा सामरिक स्थितियों का सही सार–संकलन करते हुए **"छापामार ज़ोन – हमारा परिप्रेक्ष्य"** दस्तावेज में यह

आकलन किया था कि

"वर्तमान परिस्थिति में सामरिक कार्यभार के साथ–साथ राजनीतिक–सांगठनिक कार्यभार भी महत्व ग्रहण कर रहे हैं। हमें दुश्मन की आक्रामक मुहिम का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित तथा निपुण सशस्त्र संगठनों को विकसित करना चाहिए। एक ओर राजनीतिक एवं सांगठनिक कार्यभारों को और दूसरी ओर सामरिक कार्यभारों को दक्षता से पूरा करने के लिए एक–एक कार्यभार के लिए अलग–अलग संगठन बनाना और उन्हें विकसित करने पर विशेष ध्यान देना नितान्त आवश्यक है।"

1994–95 से राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 'विशेष छापामार दस्ते' (एसजीएस) गठित किये गये। लेकिन उस वक्त हमने इन्हें आम रूप के तौर पर नहीं अपनाया। मई 1999 में सांगठनिक और सामरिक दस्तों को अलग करने के बाद सैन्य संरचनाएँ बढ़ती गयीं। 1999 में हमने सीजीएस प्रणाली को भंग किया और प्लाटून, एसजीएस, एलजीएस का गठन शुरू किया। इस तरह विशेषज्ञता हासिल करते हुए सामरिक एवं सांगठनिक कार्यभारों के लिए अलग–अलग दस्ते गठित किये गये।

फिर भी पीजीए और कमान के अलग ढाँचों का निर्माण कैसे किया जाय, इस पर हमारी समझदारी अभी स्पष्ट नहीं हो पायी थी। इसीलिए 1995 के विशेष सम्मेलन के समय पीजीए के गठन के लिए स्थितियाँ परिपक्व होने के बावजूद सीसी में मनोगतवाद तथ स्वतःस्फूर्तता के कारण इस कार्यभार को तब हाथ में नहीं लिया जा सका। सीसी ने पीजीए गठित करने का निर्णय अगस्त 2000 में किया और 2 दिसम्बर 2000 को इसे लागू किया गया।

बिहार में पूर्ववर्ती पीयू के इलाकों में 1987 में क्षेत्रीय कमेटी (आरसी) के नेतृत्व में कमाण्डरों की कमेटियाँ गठित की गयीं। 1993 में इन्हें 'सैनिक संचालन टीमों' (एसएसटी) के रूप में रूपान्तरित किया गया। ये टीमें दस्तों की सैनिक गतिविधियों तथा विश्राम की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहीं। इन्होंने सशस्त्र आक्रमणों के बीच तालमेल रखा। इन टीमों को पहले मगध में और फिर कोयल–कैमूर में गठित किया गया। इनका गठन कमाण्ड करने की समझ से किया गया था, पर ठोस अध्ययन तथा नियोजन के अभाव में ये टीमें इस दिशा में विकसित नहीं हो पायीं। 1997 में पूर्ववर्ती पीयू ने बिहार में 'सामरिक मामलों की कमेटी' (एमएसी) गठित की।

कालान्तर में विकास करते हुए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करते

हुए हमारी जानकारी बढ़ी। इसी की परिणति पीजीए के गठन और जन सेना का सीधा मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करने के लिए एक अलग, परिपूर्ण 'केन्द्रीय सैन्य आयोग' (सीएमसी) के गठन के रूप में हुई। अध्ययन और व्यवहार के दौरान आखिर इस सम्बन्ध में हमारी समझदारी स्पष्ट हुई और 9वीं काँगेस ने इसे समृद्ध किया।

'जन छापामार सेना' अपने स्वरूप में ही जनता के साथ अपने अटूट रिश्तों से बेशुमार ताकत व आवश्यक आवश्यकताएँ ग्रहण करती रही है। जनता के साथ करीबी से घुलमिल कर वह ताकतवर शक्ति बनी हैं। पीजीए जन राजनीतिक गोलबन्दी करती है और राजनीतिक–सैनिक प्रशिक्षण देती है। इससे जनता राजनीतिक एवं सैनिक गतिविधियों में सक्रिय शिरकत कर पाती हैं।

1995 में हमने उत्तरी तेलंगाना तथ दण्डकारण्य के छापामार ज़ोनों और पूर्वी मण्डल में जनता की राजनीतिक सत्ता के निकायों के निर्माण का कार्यभार हाथ में लिया। शुरू से ही हम **"क्रान्तिकारी जन कमेटियों को सारी सत्ता !"** का नारा देकर जनता को शिक्षित करने के कार्यभार पर जोर देते रहे। इस दृष्टि से 'ग्राम राज्य कमेटियों' (जीआरसी) या 'क्रान्तिकारी जन कमेटियों' (आरपीसी) ने ऐसे समय पर जनता की राजनीतिक सत्ता के निकायों के रूप में जनता का नेतृत्व किया जब जन संघर्षों तथा सशस्त्र प्रतिरोध के परिणामस्वरूप राज्य के साथ ही सामन्ती शक्तियों तथा जाति/जनजातियों के बड़े–बुजुर्गों का प्राधिकार कमजोर कर दिया गया था। इन निकायों के जरिये भ्रूण रूप में जनता की सत्ता स्थापित की गयी। जीआरसी यूँ तो कुछ ही गाँवों में स्थापित की गयीं, मगर इनके जरिये हम जनता के बीच नयी राजनीतिक सत्ता की समझ विकसित करने लगे। छापामार ज़ोनों में जनता की चेतना अब एक नया नजरिया पाकर विकसित हुई। फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विकास केवल सापेक्षिक अर्थों में ही हो पाया है।

उत्तरी तेलंगाना के छापामार ज़ोनों में दुश्मन के तीखे दमन के कारण जीआरसी का अस्तित्व समाप्त हुआ। दण्डकारण्य के गडचिरोली जैसे उन इलाकों में जीआरसी का निर्माण मुश्किल हो गया, जहाँ दुश्मन तीव्र दमन कर रहा है। अगर जीआरसी के इस रूप के जरिये कारगर तरीके से राज्य–विरोधी संघर्ष चलाने हों, तो जनता की चेतना को बढ़ाना आवश्यक होगा। सरकारी सुधारों को परास्त करने के लिए हमें जनता की चेतना बढ़ानी होगी। **अगर इस जीआरसी को अपनी नयी राजनीतिक सत्ता टिकाये रखनी हो और दुश्मन का कारगर तरीके से मुकाबला करना हो, तो जनता के सशस्त्र बलों की मौजूदगी के बिना कोई विकल्प नहीं है।**

अगर हम इस नयी राजनीतिक सत्ता को पीजीए के साथ जोड़ नहीं पाते हैं, तो इसे टिकाना और विकसित करना सम्भव नहीं होगा। इस पहलू को पहले हम स्पष्ट तरीके से ग्रहण नहीं कर पाये, इसीलिए जीआरसी को टिकाये नहीं रख सके।

जन युद्ध के आगे बढ़ने के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों में राज्य अपने कमजोर हो रहे प्रशासनिक निकायों को सुरक्षित रखने के लिए एक और फासीवादी दमन, तो दूसरी ओर सुधारों का सहारा लेता रहा है। राजकीय दमन और सुधारों को परास्त कर राज्य सत्ता को ध्वस्त करते हुए ही जनता की राजनीतिक सत्ता को मजबूती दी जा सकेगी।

'जन मिलिशिया' पीजीए का आधार बल है। जन मिलिशिया के बिना पीजीए का विकास नहीं हो सकता। यही नहीं, हमारे नियमित सशस्त्र बलों को दुश्मन का कारगर तरीके से मुकाबला करना हो, तो मिलिशिया से सहायता लेना नितान्त आवश्यक है। जब मिलिशिया, स्थानीय दस्ते तथा क्षेत्रीय बल दुश्मन के खिलाफ छापामार गतिविधियों और उसे तंग करने की कारवाइयों में लग जाते हैं, तो दुश्मन के लिए हमारे नियमित सशस्त्र बलों पर हमले सीधे केन्द्रित करना तथा नुकसान पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। जन मिलिशिया ही नियमित सेना में भर्ती का प्रधान स्रोत है। जन मिलिशिया की इस भूमिका को समझने के बावजूद हम जन मिलिशिया का व्यापक ताना–बाना तैयार करने में कोई खस तरक्की नहीं कर पाये। इसके कारण अभी हमारा प्रतिरोध भी व्यापक नहीं बन पाया है।

उच्च स्तर पर जिस तरह प्लाटून, एसजीएस जैसे सशस्त्र बल नितान्त आवश्यक हैं, उसी तरह इलाकाई स्तर पर मिलिशिया भी नितान्त आवश्यक है। गाँव–गाँव में जीआरसी के नेतृत्व में नयी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए और दुश्मन के खिलाफ जनता के युद्ध को चलाये रखने के लिए जन मिलिशिया अनिवार्य है। मिलिशिया के बिना स्थानीय वर्ग दुश्मनों को दबाना, मुखबिरों पर लगाम लगाना, दुश्मन को तंग करने की गतिविधियाँ संचालित करना और जनता को हथियारों से लैस करना सम्भव नहीं होगा। जनता के सशस्त्र बल के बिना इतिहास में कहीं भी राजनीतिक सत्ता हासिल करना और उसे टिकाये रखना सम्भव नहीं हो पाया है। यह भविष्य में भी सम्भव नहीं होगा। यह इतिहास–सिद्ध सत्य है।

जन युद्ध के लिए जनता को तैयार करना

क्रान्ति की विजय के लिए जन संगठन बिल्कुल अपरिहार्य हैं। जन संगठनों

के ही मार्फत जनता संगठित हो पाती है, वर्ग संघर्षों की ओर खिंची जाती है और संघर्षों के जरिये एहसास कर पाती है कि शोषक वर्गों की राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने के अलावा और इसके स्थान पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के अलावा खुद को सारे उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्त करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारी पार्टी 1979 की सामयिक पराजय के बाद जनता को क्रान्ति के लिए संगठित करने के लिए जन संगठनों का महत्व बहुत जल्द समझ पायी थी। 1970 के मध्य से मा–ले–मा के मार्गदर्शन में अतीत की हमारी वाम संकीर्णतावादी भूलों को सुधारते हुए हमने जन संगठनों का निर्माण शुरू किया।

जन संगठन और जन संघर्ष के महत्व को समझते हुए हमने हमेशा इस बात को मन में रखा कि समग्रता में क्रान्ति के लिए राज्य के खिलाफ युद्ध या सशस्त्र संघर्ष ही संघर्ष का मुख्य रूप होगा और संगठन का मुख्य रूप होगी, सेना।

इस पर माओ ने कहा है कि, **"....... युद्ध संघर्ष का मुख्य रूप है, सेना संगठन का मुख्य रूप। जन संगठन और जन संघर्ष जैसे अन्य रूप भी नितान्त महत्वपूर्ण हैं और सचमुच अपरिहार्य भी। किसी भी सूरत में इन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इनका मकसद होता है, युद्ध की सेवा करना। युद्ध छिड़ जाने से पहले सभी संगठन और संघर्ष युद्ध की तैयारी के लिए होते हैं ......"**

इसका अर्थ यह है कि एकदम शुरुआत से ही जन संगठनों और जन संघर्षों के निर्माण की दिशा, परिप्रेक्ष्य और पद्धति युद्ध की तैयारी के तौर पर ही होनी चाहिए। अगर यह दिशा त्यागी जाती है, तो हमारे जन संगठनों तथा जन संघर्षों का कानूनवाद तथा अर्थवाद में फँस जाना तय है। तब हम जनता को राजनीतिक सत्ता दखल के लिए तैयार नहीं कर पायेंगे। इस तरह के परिप्रेक्ष्य के बिना खड़े किये गये जन संगठन क्रान्ति को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पायेंगे।

जहाँ एक ओर जन संगठन और जन संघर्ष सशस्त्र संघर्ष और युद्ध की सेवा करते हैं, वहीं दूसरी ओर सशस्त्र संघर्ष और युद्ध जन आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जन संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष के बीच यही द्वन्द्वात्मक अन्तर्सम्बन्ध है। सशस्त्र संघर्ष के विकास के साथ– साथ जन संगठन और जन संघर्ष के रूप लगातार बदलते रहते हैं। सशस्त्र संघर्ष में बढ़ाये गये प्रत्येक कदम से जन संगठनों को विस्तार करने, अपना आधार गहराने और जन आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। हमारी पार्टी के अनुभवों ने निर्विवाद रूप से इस बात को साबित किया है।

परिणामस्वरूप जन संगठनों ने चन्द मोर्चों से कई मोर्चों तक; जनता के विभिन्न तबकों के बीच नये इलाकों तथा नये राज्यों तक विस्तार करते हुए मात्रा और गुण दोनों में अपनी ताकत का विकास किया है। जन संगठनों के जरिये विभिन्न संघर्षों के दौरान जनता को हजारों और लाखों तक की तादाद में गोलबन्द किया गया। जन संगठनों ने पार्टी के लिए बेहतर जन आधार तैयार किया, बड़ी संख्या में नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं को तैयार किया और पार्टी एवं जनता के छापामार बलों में तथा अनेक मोर्चों में भर्तियाँ करायीं। हमारे क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास में सभी जन संगठनों ने सार्थक भूमिका अदा की है, अपने सैकड़ों नेताओं तथा सदस्यों की कुर्बानी दी है और राजनीतिक प्रतिष्ठा, प्रभाव तथा लोकप्रियता हासिल की है।

उपरोक्त दिशा में हमारे जन संगठनों ने वर्ग संघर्ष की प्रकृति, मोर्चे के प्रकार, काम के उद्देश्य, आन्दोलन के स्तर तथा उतार–चढ़ाव, दमन के स्तर, जनता की चेतना के आधार पर संगठन के रूपों को चुना। संगठन के खुले, अर्द्ध–खुले, कानूनी, अर्द्ध–कानूनी, गुप्त, अर्द्ध–गुप्त रूपों को अपनाते हुए एक रूप से दूसरे में रूपान्तर भी किया गया। इसी समझदारी के आधार पर संघर्ष के रूप भी अपनाये गये। हड़ताल, जमीन पर कब्जा, प्रदर्शन, रैली, सभा, धरने, सामाजिक बहिष्कार, जन अदालत, अकाल छापे, जमींदारों तथा अन्य वर्ग दुश्मनों की सम्पत्ति पर कब्जा, बन्द आदि आम रूपों को अपनाया गया।

हमारे सभी जन संगठन मुख्यतः सशस्त्र संघर्ष के बीच तप कर निकले हैं। जन युद्ध के लिए जन राजनीतिक शिक्षा के केन्द्रों के रूप में जन संगठनों की बड़ी अहम् भूमिका रही है। जन संगठनों के नेतृत्व ने दक्षिणपंथी–अवसरवादी जन संगठनों के नेतृत्व के साथ राजनीतिक वाद–विवाद चलाने में भी अहम् भूमिका निभायी है। इनके साहसपूर्ण संघर्षों ने सामन्तवाद की चूलें हिलाकर रखी हैं, शासक वर्गों तथा उनके सशस्त्र बलों को बड़ी–बड़ी चुनौतियाँ दी हैं। हजारों गांवों तथा तमाम शहरों में समाज के उत्पीड़ित तबकों के संघर्षों ने शासक वर्गों के प्रभुत्व तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक उत्पीड़न पर प्रहार किये हैं। जन संगठनों ने जमींदारों के सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक वर्चस्व को ध्वस्त करने और खुद को जनता की राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने में बड़ी अहम् भूमिका अदा की है। बाद में यही जन संगठन, खासकर किसान, महिला, युवा जन संगठन क्रान्तिकारी जन राजनीतिक सत्ता के निकायों के लिए बुनियाद बनने लगे।

आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना और आन्ध्र–उड़ीसा सीमा क्षेत्रों में हम 1992–94

की उस पस्ती को तोड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसे दुश्मन की भयानक आक्रामक मुहिम ने जनता के बीच चल रहे हमारों कामों में अड़ंगे लगाकर पैदा किया था। धीरे–धीरे हमने इन कठिनाइयों से उबरने में कामयाबी पायी और श्वेत आतंक के बीच जन संगठनों तथा जन आन्दोलन का निर्माण करने का हुनर हासिल किया तथा इसकी कार्यनीति अपना ली। इस तरह 1995–96 में हम पर लगाये गये प्रतिबन्ध में नाममात्र की राहत के छोटे–से दौर के बाद जुलाई 1996 में हमारी पार्टी तथा जन संगठनों पर दोबारा प्रतिबन्ध लगाये जाने और 1997 की शुरुआत से ही दुश्मन की पहले से ज्यादा भयानक आक्रामक मुहिम चलने के बावजूद हम विभिन्न मुद्दों पर बड़े पैमाने के जन संघर्ष आगे बढ़ाते रह सके।

1995 के बाद के दौर में विभिन्न प्रदेशों में हमारे क्रान्तिकारी जन संगठनों या हमारी पहलकदमी से बनाये गये तमाम कवर संगठनों के नेतृत्व में जन आन्दोलनों का पुनरुत्थान देखा गया। आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र–उड़ीसा सीमा, दण्डकारण्य में बड़े पैमाने के किसान संघर्ष और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, पंजाब में छोटे पैमाने के किसान संघर्ष किये गये। आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में मजदूरों के संघर्ष; आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र–उड़ीसा सीमा, दण्डकारण्य, तमिलनाडू, कर्नाटक में महिलाओं के संघर्ष और कुछ प्रदेशों में छात्रों तथा युवाओं के संघर्ष किये गये। इन संघर्षों में किसानों के राज्य–विरोधी संघर्षों की सबसे ज्यादा अहमियत रही।

इन सभी प्रदेशों में किसानों के विभिन्न मुद्दों पर राज्य–विरोधी संघर्षों में तेजी से वृद्धि हुई। पूरे उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र–उड़ीसा सीमा और आन्ध्र प्रदेश में किसानों ने खेती की पैदावार की लाभदायक कीमतों के लिए; खाद की कीमतों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ; मानकों से कम गुणवत्ता वाले एवं मिलावट के साथ बीजों तथा कीटनाशकों की आपूर्ति के विरूद्ध; बिजली की कटौती, कम वोल्टेज तथा बढ़ी हुई दरों के मुद्दे पर, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होने वालों को सरकार द्वारा राहत प्रदान करने में की गयी हीलाहवाली के खिलाफ; कृषि आगतों की कीमतें बढ़ाये जाने के खिलाफ; डब्ल्यूटीओ के मार्फत साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ; टर्मिनेटर बीजों के खिलाफ और अन्य मुद्दों पर संघर्ष किये। कुछ अन्य मुद्दों पर भी संघर्ष किये गये, जैसे सूदखोरों तथा वित्तीय कम्पनियों द्वारा वसूले गये ब्याज की जबरदस्त ऊँची दरों के खिलाफ; जंगल के ठेकेदारों, सरकारी नौकरशाही तथा पुलिस द्वारा शोषण के खिलाफ; महिलाओं, दलितों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के

उत्पीड़न के खिलाफ। गाँव, मण्डल, इलाके तथा जिला स्तरों पर संगठित इन संघर्षों में हजारो–हजार लोग गोलबन्द किये गये।

दण्डकारण्य में बालाघाट, राजनन्दगाँव, बस्तर आदि से ताँबे, बॉक्साइट, लौह अयस्क जैसे विभिन्न खनिज–पदार्थों की लूट के खिलाफ संघर्ष किये गये। भारतीय दलाल बड़े पूँजीपति वर्गों तथा साम्राज्यवादियों द्वारा की गयी इस डाकाजनी व लूट के खिलाफ आदिवासियों को 'जंगल बचाओ' के नारे के तहत गोलबन्द किया गया। आदिवासियों के इलाकों में बाहरी लोगों के आ बसने के खिलाफ; अकाल तथा सरकार की उपेक्षा के खिलाफ; तेन्दू पत्ते, बाँस तथा अन्य वनोपज की दरें बढ़ाने के लिए; महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ और अन्य मुद्दों पर व्यापक संघर्ष किये गये। दण्डकारण्य के देहाती हिस्सों में भूमि कब्जाने के आन्दोलन किये गये। तेन्दू पत्ता की दरें बढ़ाने और अकाल के खिलाफ प्रदर्शनों में दसियों हजार लोगों ने शिरकत की।

दुश्मन की भयानक आक्रामक मुहिम के बावजूद आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र–उड़ीसा सीमा, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड और देश के अन्य हिस्सों – तमिलनाडू में धर्मापुरी–सेलम, कर्नाटक में रायचुर, बिहार–बंगाल–उड़ीसा सीमा क्षेत्र आदि में अनेक संघर्ष छेड़े गये। इसीलिए दुश्मन को अपने हमले तेज करने के लिए ज्यादा भारी मात्रा में विशेष पुलिस बलों तथा अर्द्ध–सैनिक बलों को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र से लैस करके एवं खास तौर से प्रशिक्षित करके तैनात करना पड़ा। दुश्मन ने पाँच प्रदेशों आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा बिहार में अपनी दमनकारी गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल व सहयोग की योजना बनाते हुए जून 1998 में केन्द्र गृह सचिव को मातहत 'संयुक्त तालमेल कमेटी' (ज्वाइण्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी – जेसीसी) और अप्रैल 2000 में 'जेओसी' (ज्वाइण्ट ऑपरेशन्स कमाण्ड) गठित किया। दुश्मन अभी पार्टी तथा जन संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को दूसरे प्रदेशों तक विस्तारित करने की सोच रहा है। साथ ही, जनता का ध्यान जुझारू क्रान्तिकारी संघर्षों से हटाने के लिए राज्य बड़े पैमाने पर सुधार और अनुदान कार्यक्रम भी चला रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में शुरुआती दौर में हमारे जन संगठनों ने थोड़े समय तक खुला काम किया। लेकिन मुख्यतः उनकी कार्यप्रणाली गुप्त ही रही है। कुछ अन्य इलाकों में जहाँ वर्ग संघर्ष कमजोर रहा, जन संगठन खुला काम करते रहे। दण्डकारण्य में शुरू से ही जन संगठन भूमिगत रहे और गुप्त तरीके से काम करते रहे। आन्ध्र प्रदेश में पहली बार 1992 में जन संगठनों पर औपचारिक तौर पर प्रतिबन्ध

लगाया गया। लेकिन अघोषित प्रतिबन्ध तेलंगाना में 1980 से, समूचे आन्ध्र प्रदेश में 1985 से और समूचे दण्डकारण्य में शुरुआती दिनों से रहा। बिहार में 1986 में एमकेएसएस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। बावजूद इन प्रतिबन्धों के, इन सभी प्रदेशों/क्षेत्रों में लगातार हजारों से लाखों तक जनता सभाओं तथा रैलियों में शिरकत करती रही।

एक समय पर विभिन्न प्रदेशों में और एक ही प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हम संगठन और संघर्ष के विभिन्न रूप अपनाते रहे हैं। इसके अलावा एक ही क्षेत्र या प्रदेश में स्थितियाँ ठहरी हुई नहीं होतीं, वरन् लगातार बदलती रही हैं। संगठन के रूपों और संघर्ष के रूपों में तदनुरूप बदलाव लाने की जरूरत प्रस्तुत होती रहती है। प्रत्येक क्षेत्र तथा राज्य में और एक निश्चित समय पर समुचित कार्यनीति तय करने के लिए यही ध्यान रखने लायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब तक संघर्ष के रूपों तथा संगठन के रूपों के प्रति द्वन्द्वात्मक नजरिया नहीं अपनाया जाता तब तक कारगर जन संगठनों तथा शक्तिशाली जन आन्दोलनों को खड़ा करने में सफलता नहीं मिल पाती है।

लेकिन व्यवहार के दौरान नयी–नयी स्थितियों का सामना करने पर हमने कुछ गलतियाँ की हैं, जिनके कारण जन संगठनों का विकास और आन्दोलन बाधित हुआ। इस लम्बे दौर में हमारी उपलब्धियाँ प्रधान थीं, जबकि खामियाँ गौण। हमारी खामियाँ संघर्षों में शिरकत करने वाली शक्तियों के सुदृढ़ीकरण में असफलता; कम सदस्य संख्या; जन संगठनों के नेतृत्व में निरन्तरता विकसित करने में असफलता; निचले तथा ऊपरी निकायों के बीच तालमेल में असफलता; गुप्त तथा खुले काम के बीच तालमेल करने में असफलता; जन संघर्षों में संकीर्णतावादी रुझान; 1984 से पहले खुले काम पर जरूरत से ज्यादा जोर; जन संगठनों व जन आन्दोलनों को खड़ा करने में स्वतःस्फूर्तता; नये इलाकों तक विस्तार करने में नियोजन का अभाव आदि रहीं। आम तौर पर ये खामियाँ प्रदेशव्यापी जन संगठनों तथा अखिल भारतीय जन संगठनों पर लागू होती हैं।

पार्टी कमेटियों में विभिन्न स्तरों पर कमजोरियों; मोर्चा विशेष में स्पष्टता, विशेषज्ञता तथा अनुभव की कमी; स्वतःस्फूर्तता का प्रचलन और कमेटियों पर काम के भारी बोझ के कारण जन संगठनों की सम्बन्धित स्तर की कमेटी को सही समय पर और ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जन संगठनों का करीबी से मार्गदर्शन करने में पार्टी कमेटियों के सामने संघर्ष के इलाकों में दुश्मन द्वारा केन्द्रीकरण किया जाना

और जन संगठनों के नेतृत्व की मुठभेड़ों में हत्या करके श्वेत आतंक फैलाना एक बड़ी समस्या है।

कुछ पार्टी इकाइयों में संघर्ष और संगठन के रूपों को लेकर यान्त्रिक समझदारी रही है। संघर्ष और संगठन के रूप न तो जड़ हो सकते हैं और न ही स्थिर। एक क्षेत्र में प्रचलित रूपों की दूसरी क्षेत्र में यान्त्रिक तरीके से नकल करने पर प्रतिकूल परिणाम सामने आते है। एक ही क्षेत्र में आज अपनाये गये रूप कल भी अपनाये जाये, यह जरूरी नहीं। बदलती स्थितियों के अनुरूप सृजनात्मक रूप से कार्यनीति को अमल करने और तुरन्त एक रूप के बजाय दूसरे रूप को अपनाने के लिए विभिन्न पार्टी कमेटियों तथा जन संगठन के नेतृत्व को निपुणता हासिल करनी चाहिए।

हमारे जन कार्यों में कानूनवाद मुख्यतः दो रूपों में दिखायी देता है। **पहला,** पार्टी के नेताओं को खुले जन संगठनों के नेता के स्थान पर रखना और ऐसा लम्बे समय तक चलने देना और **दूसरा,** तबकाई मांगों और आम जनवादी चरित्र की अन्य मांगों का समाधान करने के लिए काम की कानूनी/खुली पद्धतियों तथा कानूनी/खुले संघर्षों पर यकीन करना। भारत में कानूनी या खुले जन आन्दोलन की गुंजाइश के बढ़े–चढ़े आकलन के कारण और हमारे देश में जन युद्ध की दीर्घकालिक प्रकृति के बारे में स्पष्टता के अभाव के कारण कानूनवाद पैदा होता है।

हमारे जन संगठनों के नेतृत्व में निम्न पूँजीवादी व्यक्तिवाद तथा अहम्वाद, अराजकतापूर्ण रवैये तथा अनुशासन का अभाव, संकीर्ण नजरिया, नौकरशाही आदि विशेषताएँ आम तौर पर पायी जाती हैं।

जहाँ हमारे जन संगठनों को खुलकर काम करने का मौका मिल ही नहीं पाता, वहाँ कवर संगठन बनाना अनिवार्य हो जाता है। कवर संगठन बनाने के पीछे मकसद खुले जन कार्य करते हुए अपनी शक्तियों को दुश्मन के सामने खुलने न देना होता है। कवर संगठनों के विषय में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कानूनी या भूमिगत जन संगठनों का विकल्प नहीं होते। हमें कवर संगठनों में पार्टी की इकाइयाँ बनाकर उनको निर्देशित करन होगा।

आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र–उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में कवर संगठन बनाने के हमारे प्रयास 1985 से शुरू हुए। मगर इस दिशा में कुछ प्रगति 1995 के बाद के दौर में ही हो सकी। हम कवर संगठनों के माध्यम से बड़ी तादाद में जनता को गोलबद करने में कामयाब हो पाये। इस तरह हमारे जन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाकर जनता को नेतृत्वहीन बना देने के शासक वर्गों के प्रयास विफल किये जा

सके।

कवर संगठन संचालित करने में हमारी कुछ खामियाँ रही हैं। ढीली–ढाली बातें करने के कारण संगठन का खुलासा हो जाना; कवर संगठनों के कार्यक्रमों में पार्टी के जरिये ऐसी भारी जन गोलबन्दी करना कि उन संगठनों का खुलासा ही हो जाय; कवर संगठनों की बैठकों में उन वक्ताओं को बुलाना जिनका खुलासा हो गया हो; कवर संगठनों के नेतृत्व को अपने इलाके में बुलाना और इस तरह पार्टी एवं दस्ते के तमाम सदस्यों तथा आसपास के गाँवों के सामने उनका खुलासा कर देना; कवर संगठनों के नेतृत्व में चल रहे संघर्षों में पार्टी तथा दस्ते को शामिल करना और इन संघर्षों को सफल बनाने के लिए दुश्मन को धमकियाँ तक दे डालना; कवर संगठनों के लिए प्रगतिशील या उग्र परिवर्तनकारी किस्म के नाम चुनना; कवर संगठनों के मंच से हमारे नारे देना तथा हमारे गीत गाना; रातों–रात कवर संगठन बना देना और इस तरह पुलिस को चौकन्ना कर देना आदि हैं। कवर संगठनों में काम के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में सक्षम व अनुभवी पेशेवर क्रान्तिकारी तथा संगठनकर्ता नियुक्त नहीं किये जा रहे हैं।

जहाँ तक क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की बात है, किसी भी स्तर पर रणनीतिक संयुक्त मोर्चे का निर्माण सशस्त्र संघर्ष के विकास और जनता के विभिन्न हिस्सों में पार्टी की सांगठनिक शक्ति पर निर्भर करता है। संयुक्त मोर्चे के विकास में गुणात्मक छलांग दरअसल तभी लग पायेगी जब सशस्त्र संघर्ष देश के व्यापक हिस्से तक विस्तार कर लेगा और बड़े पैमाने पर राजनीतिक सत्ता के निकाय स्थापित किये जायेंगे। इलाके के स्तर के सत्ता के निकाय हमारे संयुक्त मोर्चे के नाभिक होंगे। इसी आधार पर इलाकाई/क्षेत्रीय स्तर पर मजदूर–किसान गठबन्धन को आधार बनाकर चार वर्गों को लेकर व्यापक आधार वाला संयुक्त मोर्चा गठित करना होगा। इस संयुक्त मोर्चे में सभी सामन्तवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी वर्गों को साथ लाने के प्रयास करने होंगे।

हालांकि अखिल भारतीय पैमाने पर राष्ट्रीय जनवादी मोर्चे (एनडीएफ) के गठन के लिए अपेक्षाकृत मजबूत जन सेना, देशव्यापी राजनीतिक प्रभाव वाली मजबूत पार्टी और सशस्त्र संघर्ष के काफी बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है, फिर भी हमें अपनी पार्टी, सेना, क्रान्तिकारी जन संगठनों की ताकत और अपने सशस्त्र संघर्ष के विस्तार तथा तीव्रता के अनुसार अलग–अलग स्तर पर क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे गठित करने के प्रयास करने चाहिए। सामन्तवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी वर्गों से जुड़े विभिन्न

संगठनों के साथ किसी भी स्तर की संयुक्त गतिविधियों के रूप में बनाये गये हमारे सभी कार्यनीतिक गठबन्धनों तथा साझे मोर्चों को रणनीतिक संयुक्त मोर्चे, अर्थात् एनडीएफ का निर्माण करने के लक्ष्य के अधीन होना चाहिए।

हम अभी संयुक्त मोर्चे के काम पर अच्छी तरह ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाये हैं और किसी भी स्तर पर कोई विशेषज्ञता भी नहीं हासिल हो पायी है। इस बात का संयुक्त मोर्चे की गतिविधियों पर गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है। हम अभी स्वतःस्फूर्त जन आन्दोलनों में हस्तक्षेप करने के लिए या अन्य संगठनों के साथ साझे मंच तैयार करने के लिए शक्तियाँ नियुक्त नहीं कर पाये हैं। इसीलिए क्रान्तिकारी वर्गों से जुड़ी शक्तियों को अपने पक्ष में लाने में हम सफल नहीं हो पाये हैं। संकीर्णता के कारण हम कभी–कभी समान मुद्दों पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर साझी गतिविधियाँ करने से दूर रहते हैं। हमारी पार्टी तथा जन संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण संयुक्त मोर्चे के काम में तैनात किये गये हमारे कामरेड़ों को गम्भीर सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता है। इसीलिए तय है कि लम्बे दौर में लगातार धैर्यपूर्वक काम करते रहने से ही हम संयुक्त मोर्चे पर अपना नेतृत्व स्थापित कर पायेंगे।

शहरी इलाकों में पार्टी कार्य

1995 तक हमारा शहरी इलाकों का काम मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही रहा। अन्य प्रदेशों में शहरी आन्दोलन अभी प्रारम्भिक दौर में ही रहे।

अपनी **'आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट'** दस्तावेज में शहरी आन्दोलन के सन्दर्भ में 1970 के दशक की वाम दुस्साहसवाद की गलतियों में सुधार किया गया था। इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि शहरी इलाकों की कार्यनीति दीर्घकालीन लोक युद्ध की लाइन के अनुरूप ही होनी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में पार्टी **'शहरी इलाकों में हमारे काम'** शीर्षक से एपीएससी द्वारा 1973 में जारी किये गये **'परिपत्र'** और **'हमारी कार्यनीतिक लाइन'** शीर्षक से 1980 में जारी सीसी के दस्तावेज के मार्गदर्शन में काम करती रही है।

इन दस्तावेजों में शहरी इलाकों के महत्व पर और कुंजीभूत क्षेत्रों के मजदूरों के बीच अपने प्रयासों को केन्द्रित करने, इन मजदूरों के संघर्षों का किसानों के सशस्त्र संघर्षों के साथ करीबी रिश्ते स्थापित करने और साथ ही छात्रों, युवाओं, बुद्धिजीवियों तथा मध्यम वर्गों के बीच काम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया

गया है। इसी नजरिये के परिणामस्वरूप छात्र आन्दोलन के साथ–साथ सिंगरेनी कोयला खदानों के मजदूर आन्दोलन में और बाद में हैदराबाद के मजदूर वर्ग के बीच अच्छा–खासा ब्रेकथ्रू हासिल किया जा सका है। जहाँ भी पार्टी उपरोक्त दस्तावेजों में पेश किये गये बुनियादी परिप्रेक्ष्य के खिलाफ काम करती रही, उसे कुछ नुकसान हुआ है। इन दस्तावेजों की कुछ सीमाएँ भी हैं।

1980 में सीसी के गठन के समय छात्र आन्दोलन ही प्रमुख रूप से शहरी आन्दोलन रहा। उस वक्त हैदराबाद और विशाखापटनम में हमारी पार्टी की मजदूरों के बीच कुछ ताकत थी, पर अन्य इलाकों में इस तरह के बीज अभी जम नहीं पाये थे। तब हमने युवाओं के बीच काम करना अभी शुरू ही किया था (हम साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में, नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में और कर्मचारियों के बीच भी काम कर रहे थे, पर प्रस्तुत समीक्षा में इन कामों को समेटा नहीं जा रहा है)। 1980 से 1984 के बीच छात्र आन्दोलन लगभग सभी जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों तक फैला। सिंगरेनी कोयला खदानों में 'सिंगरेनी कार्मिका सामाख्या' (सिकासा) अपने काबिल संगठनकर्ताओं के साथ तमाम ट्रेड यूनियनों में सबसे प्रभावशाली यूनियन के रूप में उभरी। अब हैदराबाद, वारंगल, विशाखापटनम और अन्य कस्बों में भी मजदूर आन्दोलन सक्रिय हुए। वारंगल कस्बा युवा आन्दोलन के अलावा छात्रों तथा बुद्धिजीवियों के आन्दोलनों के सबसे मजबूत केन्द्र के रूप मे उभरा।

1985 में शुरू हुए पहले दमन अभियान के समय हमारे छात्र, युवा और मजदूर आन्दोलनों को बड़ा आघात लगा। जिला और तहसील केन्द्रों के हमारे ज्यादातर संगठनकर्ताओं को या तो हमें पीछे हटाना पड़ा या फिर राज्य ने फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। स्थानीय संगठन भंग हो गया। कुछ कामों को तो पूरी तरह छोड़ दिया गया। लेकिन 1986 से छात्रों, युवाओं तथा मजदूरों के बीच गुप्त संगठन बनाये जाने लगे। जब 1990 के चन्द महीनों के लिए हमें कुछ राहत मिली, तो हजारों की तादाद में शहरी लोगों ने हमारी खुली गतिविधियों में शिरकत की। मजदूर आन्दोलन ने कुछ हद तक गति पकड़ ली। छात्र आन्दोलन भी कुछ गति पकड़ सका।

1991 से शुरू हुए दुश्मन के दूसरे दमन अभियान में दुश्मन ने मजदूरों के बीच के सभी खुले तत्वों की हत्या कर डाली। यदि समग्रता में देखें, तो वर्ष 1985 से गुप्त संगठन भले ही हमारी प्रधान पद्धति रही हो और इससे हमें कई सफलताएँ भी मिल चुकी हों, फिर भी दुश्मन के दमन के दौरान हमारा नेतृत्व सही फैसले करने में असफल रहा। इसी वजह से हमारा शहरी आन्दोलन काफी सिकुड़ गया और पार्टी को भारी

नुकसान उठाना पड़ा।

हमने सशस्त्र किसान संघर्षों को उचित प्राथमिकता दी और शहरी आन्दोलन भी खड़े किये। मगर हमने शहरी कामों में नेतृत्वकारी कामरेडों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नियुक्त नहीं किया। नतीजतन 1984 से पहले अनेक संगठनकर्ताओं तथा पेशेवर क्रान्तिकारियों ने शहरी आन्दोलन में काम तो किया। मगर हम अपनी इन शक्तियों को दूरगामी तथा फौरी प्राथमिकताओं के बीच तालमेल करते हुए ठीक से तैनात नहीं कर पाये। शहर से शक्तियों को तुरन्त नतीजे न मिल पाने के कारण, संगठनकर्ताओं की कमी के कारण या अन्य आवश्यकताओं के कारण आनन–फानन में हटाया जाता रहा।

बावजूद इसके कि 1980 के दस्तोवज **'हमारी कार्यनीतिक लाइन'** में हमने कहा है कि नयी मजदूर यूनियनें संगठित न की जाये, फिर भी 1981 में ही हमारे तब तक के प्रयासों से **'सिकासा'** यूनियन उभर आयी थी। हमारा यह काम चाहे कितना भी स्वतःस्फूर्त रहा हो, सिंगरेनी, हैदराबाद, विशाखापटनम, वांरगल और अन्य इलाकों में जहाँ–जहाँ हमने एक पूरे दशक तक अपने प्रयास केन्द्रित किये, वहाँ के अनुभवों से यह सबक मिला है कि हमें बहुसंख्यक सदस्यों वाली यूनियन में शामिल तो होना ही चाहिए। पर साथ ही हमें नेतृत्व में आने के लिए भी जूझना चाहिए। साथ ही, हमें नयी मजदूर यूनियन खड़ी करने के मामले में अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए।

एक दशक के अनुभवों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि 'सिकासा' के विभिन्न आह्वान, विभिन्न संघर्ष और सांगठनिक रूप भी वास्तव में ट्रेड यूनियन के ढाँचे में ठीक नहीं बैठते हैं। यह दीगर बात है कि दुश्मन के दमन को चुनौती देते हुए वहाँ के मजदूरों ने बहुत बड़े पैमाने पर 'सिकासा' के आह्वानों का साथ दिया। फिर भी हमें कानूनी अवसरों का लाभ उठाते हुए व्यापक पैमाने पर मजदूरों को गोलबन्द करने के लिए पूरी तरह छिपे–छिपाये तत्वों के मार्फत ही आवश्यक सांगठनिक रूप अपनाने चाहिए थे या फिर जरूरत के अनुसार अन्य यूनियनों में शामिल होकर काम करना चाहिए था।

हमारी **'कार्यनीतिक लाइन'** गुप्त पार्टी निर्माण पर जोर देती है। चूँकि कस्बे और शहर दुश्मन के मजबूत गढ़ होते हैं, इसलिए स्थानीय नेतृत्व को खुल जाने से बचाना तथा गुप्त साधनों की रक्षा करना नितान्त आवश्यक है!

शहरों में मजबूत स्थानीय संगठन कायम रखने में हमारी विफलता और दुश्मन के सामने पार्टी शक्तियों का जल्दी खुल जाने के लिए कतारों को पर्याप्त राजनीतिक

एवं सांगठनिक प्रशिक्षण न देना, अर्थवाद के रुझान का होना, गुप्त संगठन में खलल पैदा करने वाले संघर्ष के रूपों का अपनाया जाना, सांगठनिक ढाँचों में एक के ऊपर एक संस्तर तैयार न करना, 'टेक' उसूलों का पालन न करना, शहरी आन्दोलन को दीर्घकालीन लोक युद्ध के हिस्से के तौर पर संगठित करने के सवाल पर स्पष्टता का अभाव होना, शहरी कामों में विशेषता का अभाव होना, परिणामस्वरूप शहर के आन्दोलन का अध्ययन करने तथा फैसले करने में स्वतःस्फूर्तता का हावी रहना, ढीली–ढाली भर्ती करना, ऊपर से नेतृत्वकारी कामरेडों द्वारा निगरानी करने में कमी होना, गुणवत्ता के बजाय मात्रा को ज्यादा अहमियत देना आदि महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार रहे हैं।

नौवीं काँग्रेस और पार्टी की राजनीतिक–सामरिक लाइन समृद्ध करने में इसकी ऐतिहासिक महत्ता

9वीं काँग्रेस ने विचारधारात्मक और राजनीतिक रूप से परिपक्व पार्टी को उभरते हुए देखा – एक नये किस्म की पार्टी को, जो दशकों पुराने तीखे वर्ग संघर्ष के बीच तप कर उभरी है। पार्टी ने अब अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया था। एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में इसका संगठन मौजूद है, अपनी जन छापामार सेना पीजीए है और अनेक विभाग तथा जन संगठन कार्यरत हैं।

काँग्रेस में पार्टी की लाइन पहले से ज्यादा सुदृढ़ और समद्ध हो पायी। 1970 की 8वीं काँग्रेस द्वारा सूत्रबद्ध पार्टी की बुनियादी लाइन पर दृढ़ता से अडिग रहते हुए 9वीं काँग्रेस ने मा–ले–मा के बारे में विकसित हुई समझदारी तथा जन युद्ध को आगे बढ़ाने के दौरान सालों से अर्जित समृद्ध अनुभवों के आधार पर और पिछले तीन दशकों के राजनीतिक विकासक्रम का जायजा लेकर आवश्यक परिवर्तन किये तथा बहुत सारी अवधारणाओं को समृद्ध किया। इस काँग्रेस ने क्रान्ति के तीन औजारों पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चे को ढालने और कार्यनीति को सूत्रबद्ध करने के दौरान उभर आये "दक्षिणपंथी" तथा "वामपंथी" भटकावों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक संघर्ष किया। जन सेना, छापामार ज़ोन, आधार इलाकों और क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की अवधारणाओं के विषय में नौवीं काँग्रेस ने समझदारी का स्तर उन्नत किया।

9वीं काँग्रेस ने इस प्रकार उपरोक्त अवधारणाओं के सम्बन्ध में पीडब्ल्यू के 1995 के एआईएससी तथा पीयू के 1997 के केन्द्रीय सम्मेलन की समझदारी की खामियों को दुरुस्त किया, क्रान्ति के तीनों हथियारों को ढालने की प्रक्रिया में पार्टी

नेतृत्व की सचेत भूमिका पर बल दिया और फलस्वरूप देश में चल रहे जन युद्ध में नया ब्रेकथ्रू हासिल करने के लिए जमीन तैयार की।

कॉंग्रेस ने दुनिया की परिस्थिति, साम्राज्यवाद के सर्वव्यापी संकट, वर्तमान दुनिया के बुनियादी अन्तरविरोधों के तीखे होते जाने का और प्रधान अन्तरविरोध का सही आकलन करते हुए इन अन्तरविरोधों के केन्द्र–बिन्दु (फोकस) का सही विश्लेषण प्रस्तुत किया। राजनीतिक परिस्थिति के विश्लेषण के आधार पर कॉंग्रेस ने इतिहास के इस मोड़ पर आ उपस्थित हुए हमारे नये कार्यभारों को चिह्नित किया।

कॉंग्रेस ने अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के सामने उपस्थित विभिन्न विचारधारात्मक–राजनीतिक सवालों पर अपना रुख स्पष्ट किया। इनमें नये अन्तरराष्ट्रीय (इण्टरनेशनल) के गठन का सवाल, सर्वहारा की मार्गदर्शक विचारधारा, पूँजीवाद का आम संकट तथा दुनिया पर इसका प्रभाव, प्रधान अन्तरविरोध का सवाल, युद्ध का खतरा, वर्तमान युग की प्रकृति के बारे में समझ, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों की अहमियत तथा विश्व सर्वहारा क्रान्ति की दो धाराओं को एकीकृत करने की आवश्यकता, अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में संशोधनवाद का खतरा आदि शामिल रहे। इस प्रकार कॉंग्रेस ने वर्तमान विश्व परिस्थिति तथा अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन (आईसीएम) से सम्बन्धित उपरोक्त सवालों पर पार्टी की समझदारी को समृद्ध किया और सुस्पष्ट सर्वहारा अवस्थितियाँ अपनायीं।

कॉंग्रेस की ऐतिहासिक महत्ता उस परिस्थिति में निहित है जहाँ सीपीआई (एमएल) की परम्परा की प्रमुख क्रान्तिकारी शक्तियों का विलय हो चुका था। अगस्त 1998 में सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} और सीपीआई (एमएल) {पीयू} के विलय और अन्य सीपीआई (एमएल) संगठनों से निकल आये कुछ ग्रुपों तथा तत्वों के हमारी पार्टी में विलय के बाद अब हम यह कह सकते हैं कि सीपीआई (एमएल) धारा के कुछ सच्चे क्रान्तिकारी ग्रुपों तथा तत्वों को छोड़कर अप्रैल 1969 में गठित सीपीआई (एमएल) से उभर आई सच्ची क्रान्तिकारी शक्तियों का एकीकरण बहुत हद तक पूरा हो चुका है।

कॉंग्रेस ने जन युद्ध को तीव्र करने और देश के अन्य भागों तक विस्तारित करने का दृढ़ संकल्प किया। इसने समूची पार्टी का आह्वान किया कि मुक्त क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे और इसे अंजाम देने के लिए ठोस योजनाएँ तैयार करें। कॉंग्रेस ने देश में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के साथ तालमेल स्थापित करने का अपना दृढ़निश्चय व्यक्त किया। इसने पूरी शिद्दत के साथ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के एकीकरण के कार्यभार को जारी रखने का निश्चय भी

किया। इसने क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा तैयार करने के परिप्रेक्ष्य के साथ प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरों पर अधिक राजनीतिक महत्व के मुद्दों में राजनीतिक तौर से दखल देने और शक्तिशाली जन आन्दोलन खड़े करने की आवश्यकता को भी चिह्नित किया। काँग्रेस ने पार्टी का इस बात के लिए आह्वान किया कि वह गहन रूप से शुद्धिकरण अभियान से गुजरते हुए विभिन्न गैर–सर्वहारा रुझानों से खुद को मुक्त करे और इस तरह अपना सर्वहाराकरण करे तथा अपने तमाम सारे कार्यभारों को पूरा करने के लिए खुद को चुस्त–दुरुस्त करे।

9वीं काँग्रेस में चिह्नित खामियाँ

उपरोक्त उपलब्धियों के साथ–साथ हमारी एकीकृत पीडब्ल्यू की दोनों घटक पूर्ववर्ती पार्टियों के अपने क्रान्तिकारी व्यवहार के दौरान अनेक खामियाँ रहीं और उनसे कुछ गम्भीर गलतियाँ हुइ थीं। इनका विवरण इस प्रकार है –

पहली यह कि हम पेशेवर क्रान्तिकारियों के कोर और अंश–कालिक कार्यकर्ताओं, दोनों के व्यापक ताने–बाने वाली मजबूत पार्टी का निर्माण नहीं कर पाये। पूर्ववर्ती **पीयू** में नेतृत्व के एक हिस्से तथा कार्यकर्ताओं में और नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियों तक में पेशेवराना रवैये का अभाव था, जिसके कारण आन्दोलन की रफ्तार बाधित हुई और पार्टी में कानूनवाद को बढ़ावा मिला।

दूसरी यह कि सशस्त्र छापामार दस्ते तो बनाये गये और पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू में प्लाटून तथा विशेष दस्ते भी बनाये गये। लेकिन चीन से भिन्न हमारे इस देश की स्थितियों में, जहाँ कि सेना को एकदम शून्य से खड़ा करना पड़ा है, जन सेना का निर्माण कैसे किया जायेगा, इस पर समुचित समझदारी का अभाव रहा है। एक ओर पूर्ववर्ती पीयू पेशेवर तरीके से नियमित छापामार दस्तों का निर्माण करने के कार्यभार पर जोर नहीं दे पायी, जिसके कारण उसके दस्ते ज्यादातर अस्थाई या अर्द्ध–स्थाई किस्म के रहे। दूसरी ओर पीडब्ल्यू ने अपने दस्ते तथा प्लाटून स्थाई आधार पर तो बनाये, पर सही समय पर सैनिक दस्तों को सांगठनिक दस्तों से अलग करने और कारगर केन्द्रीय कमान तैयार करने में यह असफल रही। इसके कारण केन्द्रीकृत कमान के मातहत जन छापामार सेना का विकास बाधित रहा।

तीसरी यह कि जनता की जनवादी सत्ता के निकाय जन युद्ध के स्तर के बराबर स्थापित नहीं किये जा सके। उत्तरी तेलंगाना तथा दण्डकारण्य के छापामार ज़ोनों में स्थितियाँ जनता की सत्ता के निकाय स्थापित करने के लिए परिपक्व रही

हैं। लेकिन वहाँ पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू इस कार्यभार को केवल आंशिक रूप से ही पूरा कर पायी। सैकड़ों गाँवों में सामन्ती शक्तियों के पुराने प्राधिकार को उखाड़ फेंका गया तथा राज्य को भी काफी कमजोर कर दिया गया। मगर इससे पैदा हुई शून्यता को भरते हुए जनता की नयी सत्ता स्थापित नहीं की जा सकी। छापामार ज़ोनों की तैयारी के दौर में भी जनता की चेतना एवं तैयारी जन राजनीतिक सत्ता के निकायों की स्थापना के लिए अभी पर्याप्त विकसित नहीं रही है। इसके कारण स्वाभाविक तौर पर आन्दोलन में अर्थवाद और सुधारवाद जैसे रुझान उभर आये हैं।

चौथी यह कि दुश्मन की आक्रामक मुहिमों और सुधार तथा अनुदान आदि कार्यक्रमों का जवाब देने के लिए समुचित कार्यनीति सूत्रबद्ध नहीं की जा सकी। बदलती जमीनी स्थितियों का ठोस अध्ययन न होने और समय पर आवश्यक योजनाएँ न बनाये जाने के कारण पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू के नियोजन और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच खाई रही है। पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू अपनी शक्तियों की तैनाती में लचीलापन नहीं ला पायी और दुश्मन की भयानक आक्रामक मुहिमों की सूरत में अपनी शक्तियों को अस्थाई तौर पर पीछे हटाने की कार्यनीति नहीं अपना सकी। पार्टी अपने राजनीतिक प्रस्ताव में तय किये कार्यभारों की रोशनी में शहरी इलाकों में राजनीतिक कार्यनीतिक नारों पर अमल नहीं कर पायी।

पाँचवीं यह कि पार्टी विकासोन्मुख और बदलती स्थितियों का जायजा लेते हुए शहरी कामों के सन्दर्भ में आवश्यक परिप्रेक्ष्य नीति तथा कार्यपद्धति विकसित नहीं कर पायी। इसके कारण पार्टी को दमन झेलने वाले इलाकों में बड़ी मात्रा में अपने कार्यकर्ता खोने पड़े। पार्टी अन्य इलाकों की अपनी शक्तियों का कारगर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पायी।

आखिरी यह कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जन संघर्ष हुए हैं पर इन जन संघर्षों को राजनीतिक चरित्र प्रदान करने, इन्हें आगे बढ़ रहे जन युद्ध के साथ कारगर तरीके से जोड़ने में कुल मिलाकर कोई सफलता नहीं मिल पायी। जन संगठनों की सदस्य संख्या सीमित रही और इनका जन चरित्र नहीं बन पाया। पूर्ववर्ती पीयू में कानूनी आन्दोलनों की गुंजाइश पर अतिरिक्त जोर रहा है। पार्टी के निर्माण तथा सशस्त्र संघर्ष के निर्माण की कीमत पर जन आन्दोलनों का निर्माण करने पर जरूरत से ज्यादा जोर रहा है। पूर्ववर्ती पीयू के जन संगठनों में कानूनवाद प्रमुख रुझान के रूप में उभरा, जबकि तीखे राजकीय दमन की स्थितियों में जन आन्दोलनों का निर्माण करने में पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की कुछ खमियाँ रहीं।

पार्टी का समग्र मूल्यांकन उसकी नीतियों, कार्यनीति तथा योजनाओं और तदनुरूप क्रान्ति के तीन जादुई हथियार पार्टी, जनता की सेना तथा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने के लिए किये जाने वाले व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए।

9वीं काँग्रेस ने अतीत का सार–संकलन करते हुए निम्न सबक निकाले :

(1) अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाएँ तथा परिप्रेक्ष्य तय करते हुए और ठोस वस्तुगत सच्चाईयों का अध्ययन करते हुए हमें हमेशा मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी सिद्धान्त को अपनी दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयोग में लाना चाहिए। सिद्धान्त को और ठोस स्थितियों के अनुरूप सिद्धान्त को ठोस रूप से लागू करने की उपेक्षा करने पर हम अन्धी गली में भटक सकते हैं। हमारे देश में जन सेना के निर्माण के सवाल पर यह पहलू सबसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से उभर कर सामने आया है। हमारा अनुभव यह बताता है कि केवल आम उसूलों को दोहराते रहने से कोई काम नहीं बनता और यह भी कि मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को ग्रहण करना वास्तव में सभी क्षेत्रों में क्रान्ति को आगे बढ़ाने के ठोस व्यवहार से जुड़ा हुआ है।

(2) सभी क्षेत्रों में समय–समय पर अपने कार्यभार तय करते वक्त हमें हमेशा क्रान्ति के तीन जादुई हथियारों को तैयार करने तथा मजबूत करने के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी के ऊपर से लेकर निचले स्तरों तक हमारे सारे कामों को इसी लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार की उपेक्षा किये जाने पर अपेक्षाकृत कमजोर पार्टी संगठन, केन्द्रीय कमाण्ड के बिना केवल भ्रूण रूप में सेना और संयुक्त मोर्चे की सक्रियता में रुकावट के रूप में परिणाम सामने आये हैं। क्रान्ति के उपरोक्त तीन उपकरणों को मजबूत किये बगैर हम अपना जन युद्ध आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

(3) हमें अपने सभी क्रान्तिकारी कार्यों में जन दिशा के महत्व के सवाल पर पार्टी की कतारों को शिक्षित करना चाहिए। अगर इस बात को केवल नेतृत्व ही समझता हो, तो यह नाकाफी है। न ही इसे केवल उसूलों के रूप में अपने दस्तावेजों, साहित्य और भाषणों में व्यक्त करना काफी है। जन दिशा को हमारे रोज–ब–रोज के व्यवहार में ठोस अमल करते हुए और पार्टी में जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर लागू करते हुए समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया जाना चाहिए। जन दिशा से भटकाव होने की सूरत में सांगठनिक क्षेत्र में अंशकालिक पार्टी सेलों तथा व्यापक

आधार वाले जन संगठनों, जन आन्दोलनों एवं संयुक्त मोर्चे के निर्माण की उपेक्षा होगी; राजनीतिक एवं विचारधारात्मक क्षेत्रों में संकीर्णतावाद तथा मनोगतवाद पैदा होगा; सामरिक क्षेत्र में जनता को हथियारों से लैस कर जन मिलिशिया के निर्माण की उपेक्षा होगी और सशस्त्र बल कमजोर रह जायेंगे तथा सशस्त्र प्रतिरोध भी कमजोर होाग।

(4) हमें हमेशा 'राजनीतिक कमान में' रखनी चाहिए। हमारी सारी गतिविधियों का लक्ष्य राज्य सत्ता पर कब्जा होना चाहिए, चाहे ये क्रान्ति के तीन उपकरणों के निर्माण के लिए की जा रही हों, चाहे हमारे रोज़ाना जन कार्यों के रूप में हों, चाहे जन आन्दोलन का निर्माण करने की हों।

इस केन्द्रीय कार्यभार की उपेक्षा किये जाने पर आन्दोलन में अर्थवाद पनपेगा और जनता मुख्यतः सुधारवादी व्यवहार तक ही सीमित रह जायेगी।

(5) पार्टी द्वारा निर्धारित प्रधान कार्यभारों को समय–समय पर विशेष अभियान लेकर और समयबद्ध योजनाओं के मार्फत पूरा किया जाना चाहिए। नेतृत्व की सीधी निगरानी में इस तरह के विशेष अभियानों के बिना पार्टी सदस्यता, जन मिलिशिया, जनता की राजनीतिक सत्ता के निकायों, दुश्मन के बलों के खिलाफ जवाबी आक्रामक मुहिमों, भटकावों के शुद्धिकरण इत्यादि का गुणात्मक सुधार सम्भव नहीं है। आवश्यकताओं के अनुसार नेतृत्व को जमीनी स्तर तक (ग्रासरूट्स तक) जाना चाहिए, परिस्थिति का ठोस अध्ययन सुनिश्चित करना चाहिए और अभियानों को संचालित करना चाहिए। नियमित तौर पर योजनाओं और अभियानों की समीक्षा की जानी चाहिए।

(6) जन युद्ध संचालित करने के दौरान बदलती स्थितियों का अध्ययन करने के लिए पार्टी नेतृत्व को खुद को तथा पूरी पार्टी को शिक्षित करना चाहिए और समय–समय पर समुचित कार्यनीति को तथा कार्यभारों को सूत्रबद्ध करना चाहिए। स्थितियों में आने वाले बदलावों का विश्लेषण करने से इन्कार करने पर निष्क्रियता पैदा होगी और पहलकदमी खो जायेगी। दुश्मन की कार्यनीति में आने वाले बदलावों के आकलन में देर किये जाने पर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और दुश्मन का पलड़ा भारी हुआ है। राजनीतिक आह्वान और नीतियाँ समय पर सूत्रबद्ध की जानी चाहिए।

(7) हमारे इर्द–गिर्द के समाज के प्रभाव और पार्टी तथा सशस्त्र बलों में गैर–सर्वहारा वर्गों के निरन्तर आगमन के कारण हमें हमेशा पार्टी के भीतर विजातीय विचारधारात्मक तथा राजनीतिक भटकावों के खतरे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। समयबद्ध अभियानों के जरिये लगातार शुद्धिकरण किया जाना चाहिए; आलोचना

तथा आत्मालोचना पार्टी के भीतर और जनता के सामने भी की जानी चाहिए। पार्टी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेही होना चाहिए और पूरी पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

(8) पार्टी कमेटियों को सम्बन्धित स्तरों की पार्टी को और अन्दोलन को वास्तविक नेतृत्व देना चाहिए। उन्हें नेतृत्व करने तथा आन्दोलन के सामने उपस्थित समस्याओं का समय पर निराकरण करने की निपुणता व कला अर्जित करनी चाहिए, क्षममावान क्रान्तिकारी उत्तराधिकारी तैयार करने चाहिए और नेतृत्व की निरन्तरता सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी स्तरों पर सचेत रूप से सामूहिक कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियों को अपना उचित नियोजन करते हुए खुद को स्वतःस्फूर्तता का शिकार होने के खतरे से बचाना चाहिए।

भाग–3

काँग्रेस के बाद की परिस्थिति

अध्याय–8

एमसीसीआई के साथ रिश्ते और एकता प्रक्रियाः 1981–2004

देश के माओवादी आन्दोलन की दो प्रमुख धाराओं सीपीआई (एमएल) की धारा और एमसीसी की धारा का अब एक पार्टी में विलय होने वाला है। अलग–अलग इतिहास होने के बावजूद चूँकि दोनों ने गम्भीरता के साथ सशस्त्र संघर्ष के जरिये इलाकावार राजनीतिक सत्ता दखल के लिए देश में जन युद्ध को आगे बढ़ाने के प्रयास किये, इसलिए वे अपनी पार्टियों के विलय के कगार पर पहुँच पाये। पिछले तीन दशकों के इतिहास में एक ओर पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू तथा पीयू और दूसरी ओर एमसीसी – ये दो प्रमुख धाराएँ सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} और एमसीसी के रूप में विकसित हुईं। अपने ढाई दशक पुराने सम्बन्धों के दौरान इन दो पार्टियों के आपसी रिश्तों में देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन में निहित तरह–तरह की खामियों को अभिव्यक्त करने वाले अनेक उतार–चढ़ाव आये। अपने कटु अनुभवों से सीखते हुए ये दो धाराएँ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के मार्गदर्शन में परिपक्व हुईं और देश में आज अखिल भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की ओर अपना सफर तय कर चुकी हैं। इस दौरन भारतीय क्रान्ति नक्सलबाड़ी द्वारा निर्धारित और कामरेड सीएम तथा कामरेड केसी के बताये नये रास्ते से होती हुई, सार्थक कदमों से डग भरती हुई आगे बढ़ी है।

इस दौरान दोनों धाराओं ने तीखे दमन का मुकाबला किया है, हजारों कामरेडों ने अपनी शहादतें दी हैं। मिलकर इन्होंनें जन युद्ध को ऐसे मुकाम तक पहुँचाया है जिसे आज तक भारत के इतिहास में कभी देखा नहीं गया। दीर्घकालीन लोक युद्ध के रास्ते पर अडिग रहते हुए, आधार इलाकों के निर्माण की दिशा में सशस्त्र संघर्ष को उत्तरोत्तर तेज करते हुए और 'जन मुक्ति सेना' के निर्माण की ओर डग भरते हुए दोनों पार्टियों ने समाजवाद और फिर साम्यवाद की लम्बी यात्रा के पहले पड़ाव के तौर पर नयी जनवादी क्रान्ति की मजबूत बुनियाद डाली है।

लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में कुछ काले धब्बे भी रहे हैं जिन्होंने इन शक्तियों की महान क्रान्तिकारी छवि को बेदाग नहीं रहने दिया। खास तौर पर किसी–किसी दौर में हमारे रिश्तों का गैर–कामरेडाना हो जाना और आपसी झड़प का काला अध्याय सामने आना हमें एहसास दिलाता है कि हमें गम्भीरता से आत्म–मन्थन करना होगा, ताकि हम आपसी रिश्ते कायम करने तथा एकता प्रयास जारी रखने के दौरान अपनी ओर से हुई भूलों का पता लगा सके। ऐसा करके ही हम सबक निकाल सकते हैं और ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता हासिल कर सकते हैं।

पूर्वचर्ती पीयू और एमसीसी के बीच 1990 के दशक की शुरुआत से ही गम्भीर तनाव पैदा हुए थे। मगर 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में, खास तौर पर 1997–99 के बीच ये रिश्ते और भी खराब हो गये। एकीकरण की प्रक्रिया की समस्याओं तथा इनसे सम्बन्धित मुद्दों को समझने के लिए और आपसी रिश्तों के लम्बे सिलसिले और फिर एकता–प्रक्रिया में हुए विलम्ब का समुचित आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए इन एकता–प्रयासों तथा आपसी रिश्तों के कालक्रम को मोटे तौर पर चार दौरों में विभाजित किया जा सकता है।

दो दशकों के इस कालक्रम में अपने रिश्तों के इतिहास पर निगाह डालते हुए इस अनुभव को उसके सकारात्मक और नकारात्मक, दोनो ही पहलुओं के साथ समझने के लिए आइये, इन चार दौरों की छानबीन करें।

1981–91 के बीच के एकता प्रयास

मोटे तौर पर इसी दौर में हमारी दो पार्टियों के बीच एकता–प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

पहली बार 1980 के अन्त तक में एमसीसी के साथ रिश्ते स्थापित किये गये। तब से 1988 तक नियमित बैठकें तो हुईं, पर इनमें केवल अनुभवों का आदान–प्रदान

किया जर सका, औपचारिक चर्चा हुई और बिरादराना रिश्ते कायम रखे गये। इस दौरान सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक मतभेदों को हल करते हुए एकता की ओर बढ़ने के कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये। एकता वार्ता में कोई उल्लेखनीय विकास इस दौर में आंशिक तौर पर इसलिए नहीं हो पाया कि केवल दो वर्षों के अन्दर–अन्दर कामरेड केएस गिरफ्तार हुए तथा एमसीसी के दो शीर्षस्थ नेता कामरेड अमूल्य सेन एवं केसी का देहान्त हो गया; फिर 1985 में हमारी सीसी में गहरा संकट आ उपस्थिति हुआ जिसकी परिणति 1987 में उसके भंग हो जाने के रूप में हुई।

फरवरी 1983 की बैठक में ही यह तय हुआ कि इतिहास से सम्बन्धित मुद्दे हमारी दो पार्टियों के विलय के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। इस बैठक में यहाँ तक बात पहुँची कि दो संगठनों के विलय के लिए कौन–कौन से दस्तावेज तैयार कर लिये जायें। बैठक में यह तय हुआ कि दोनों सीसी संयुक्त रूप से **पार्टी कार्यक्रम, संविधान, रणनीति एवं कार्यनीति, क्रान्तिकारी कार्यशैली एवं कार्यपद्धति** तथा **अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन के बुनियादी तत्वों** को समेटते हुए आपसी सहमति से दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। हालांकि विलय की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्यवाही के सन्दर्भ में छोटे–छोटे मतभेद रहे, फिर भी दोनों संगठनों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यथाशीघ्र दोबारा मिल बैठना तय किया।

मई 1983 में एक पत्र के माध्यम से एमसीसी की तत्कालीन सीसी ने पीडब्ल्यू की सीसी को दोनों संगठनों के बीच एकता–प्रक्रिया को उसकी परिणति तक पहुँचाने के सन्दर्भ में कुछ प्रस्ताव भेजे। उन्होंने उपरोक्त दस्तावेजों को तैयार करने के लिए संयुक्त कमेटी बनाने और उन्हें पार्टी की कतारों के बीच वितरित करने का सुझाव रखा। उन्होंने साथ ही, कुछ अन्य ग्रुपों/पार्टियों के साथ चर्चा करने और इस पूरी प्रक्रिया को 1984 तक सम्पन्न करने का सुझाव भी रक्षा। अपने इस पत्र में उन्होंने यह कहा कि "हमारी सीसी ने यह तय किया है कि इस विलय प्रक्रिया के साथ–साथ हमारी सीसी अन्य क्रान्तिकारी शक्तियों को एक ही पार्टी केन्द्र में एकताबद्ध करने के श्रमसाध्य प्रयास करेगी, जैसे सीओसी/ पीयू; शान्ती राय के नेतृत्व वाली यूसीसीआरआई (एमएल) और सत्यन ग्रुप। अगर इनमें से किसी के साथ एकता स्थापित करना सम्भव नहीं हो पाता, तो एमसीसी और पीपुल्स वार का एक केन्द्र के रूप में विलय किया जायेगा और नयी क्रान्तिकारी पार्टी के गठन की घोषणा की जायेगी। हमने अनुमान लगाया है कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया 84 तक पूरी हो जायेगी।" जून के अन्त से पहले

पीडब्ल्यू की सीसी ने इस पत्र का जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने एकता की प्रक्रिया को उसकी परिणति तक पहुँचाने के लिए कई सुझाव रखे, जिनमें दो दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करने की ठोस जिम्मेदारी लेने, द्विपक्षीय आधार पर (अन्य सुझाये गये संगठनों को शामिल किये बगैर) विलय की ओर बढ़ने और विलय के लिए होने वाली चर्चाओं के दौरान सांगठनिक समस्याओं को हल करने के सुझाव शामिल रहे।

जब कामरेड केएस जेल से बाहर आये, तो सितम्बर 1984 में एक बैठक हुई, जिसमें विलय प्रक्रिया को यथाशीघ्र सम्पन्न करने और एकीकृत सीसी गठित करने का संयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया। इस द्विपक्षीय बैठक ने पिछले चार वर्षों की एकता प्रक्रिया की समीक्षा की और दस्तावेजों को तैयार करने के लिए समयबद्ध योजना तक तय कर ली। बैठक ने यह प्रस्ताव किया कि दस्तावेजों को 15 नवम्बर 1984 तक तैयार कर लिया जाय और दूसरे पक्ष के पास 15 जनवरी 1985 तक संशोधन के लिए भेज दिये जायें। इस बैठक में दोनों संगठनों के विलय की प्रक्रिया के सन्दर्भ में कुछ बारीकियाँ भी तय की गयीं, जैसे विलय के बाद पार्टी को नया नाम देना और दो केन्द्रीय मुखपत्र निकालना – अंग्रेजी में **"पीपुल्स वार"** आौर हिन्दी में **"लाल पताका"**।

दुर्भाग्य से इस बैठक के बाद पीडब्ल्यू की अन्दरूनी घटनाओं ने कुछ देर तक एकता प्रक्रिया को बाधित किया। पीडब्ल्यू की सीसी में उभरे संकट ने करीब दो वर्षों तक सीसी की कार्यवाही को वस्तुतः ठप्प कर दिया। फिर अप्रैल 1987 में सीसी को भंग किया गया। 1987 से 1990 तक के तीन वर्षों के दौरान जब सीसी अस्तित्व में नहीं रही, तो एपीएससी ने एमसीसी के साथ एकता–प्रक्रिया पूरी करने के गम्भीर प्रयास जारी रखे। इसके लिए आधार अवश्य मौजूद रहा, क्योंकि एमसीसी ने संकट के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाया और एपीएससी के साथ रिश्ते कायम रखे थे। उस दौरान पीयू ने जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवादी कहकर उसकी खुलकर भर्त्सना की, तो एपीएससी ने उसके साथ रिश्ते पुनर्जीवित किये।

सीसी की गैर–मौजूदगी के कारण एपीएससी ने केएस को एमसीसी के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन अपने मनोगतवाद के चलते उन्होंने विलय की प्रक्रिया के प्रति अपना रुख मनमाने ढंग से बदलना शुरू किया। उन्होंने दस्तावेज तैयार करने को समय की बर्बादी बताया और कुछ नये मानदण्ड सुझाये। केएस की हाल में सामने आयी सीमाओं को एपीएससी और एमसीसी दोनों ही समझते रहे।

इसीलिए तो बाद के दिनों में भी दोनों संगठनों के बीच सम्पर्क जारी रहा।

जुलाई 1988 में एमसीसी ने यह लिखा कि उनकी योजना मार्च/अप्रैल 1989 में केन्द्रीय सम्मेलन आयोजित करने की है और सम्मेलन में वे अपनी **"समीक्षात्मक रिपोर्ट"** पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी सुझाया कि प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक के लिए तय किये हुए सभी दस्तावेज उसी वर्ष नवम्बर/दिसम्बर तक तैयार कर लिये जाये।

अप्रैल 1989 में एमसीसी और पीडब्ल्यू की एपीपीसी के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। विलय प्रक्रिया को सम्पन्न करने के इरादे से पूरी पीसी बैठक में उपस्थित हुई। दोनों पक्षों ने पिछले 8 वर्षों से चली आ रही विलय वार्ता की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की और सर्वसम्मति से दोनों संगठनों का एक एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में विलय करने के लिए ठोस कदम तय किये। विलय के लिए बुनियादी दस्तावेजों के रूप में निम्न पाँच दस्तावेज तय किये गये – (1) राजनीतिक प्रस्ताव, (2) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रस्ताव, (3) पार्टी कार्यक्रम, (4) पार्टी संविधान, (5) रणनीति एवं कार्यनीति। इनमें पहले, दूसरे और चौथे को पीडब्ल्यू को तैयार करने था, जबकि तीसरे और पाँचे को एमसीसी को तैयार करना था। यह तय किया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों पर संशोधन जून 1989 के अन्त तक एक–दूसरे को भेजे जायेंगे और यह कि प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने तथा दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने एवं पारित करने के लिए सितम्बर 1989 में पीडब्ल्यू के 4 प्रतिनिधियों तथा एमसीसी के 3 प्रतिनिधियों को लेकर 'संयुक्त आयोग' (ज्वाइण्ट कमीशन) की बैठक रखी जायेगी। उपरोक्त दस्तावेजों को अन्तिम रूप देकर पारित करने के बाद इसी संयुक्त बैठक को नयी पार्टी के गठन का उद्घोष करने वाला 'विलय घोषणापत्र' भी जारी करना था।

इन चर्चाओं तथा द्विपक्षीय बैठकों की प्रक्रिया के दौरान दो राजनीतिक बिन्दुओं पर मतभेद सुलझाये नहीं जा सके। ये मुद्दे दुनिया में प्रधान अन्तरविरोध के सवाल पर और विश्व युद्ध के खतरे के आकलन पर थे।

इसी के आसपास पीडब्ल्यू के प्रतिनिधि–मण्डल के दो सदस्य पीयू के प्रतिनिधि–मण्डल से मिले। दोनों ने तय किया कि एमसीसी को साथ लेकर एकता के सवाल पर एक 'कन्वेन्शन' रखा जाय। इस बात को अप्रैल 1991 में एमसीसी को लिखे एक पत्र में सम्प्रेषित किया गया। पत्र में यह भी कहा गया कि पीयू के कामरेडों से कहा गया है कि वे कन्वेन्शन आयोजित करने के प्रस्ताव पर एमसीसी के साथ खुद

चर्चा करें। केएस ने इस आशय का प्रस्ताव अपने मनोगतवाद के कारण रखा था। अव्यावहारिक होने के कारण प्रस्तावित कन्वेन्शन नहीं हो पाया। इस निर्णय के बारे में जब एमसीसी और पीडब्ल्यू की सीओसी को पता चला, तो दोनों ने इसका विरोध किया।

एकता प्रक्रिया को अब अगस्त 1991 में रखी गयी एमसीसी और पीडब्ल्यू की द्विपक्षीय बैठक में तय करना निश्चित हुआ। यह बैठक पीडब्ल्यू की सीओसी में संकट के कारण नहीं हो पायी। द्विपक्षीय बैठक अब जून 1992 तक स्थगित की गयी। पीडब्ल्यू ने एमसीसी को सूचित किया कि सीओसी में उभरे मतभेदों के कारण वह अब अपने अन्दरूनी मतभेदों के सुलझने तक विलय वार्ता जारी रखने की स्थिति में नहीं होगी। पार्टी इस समय ऐसे आन्तरिक संकट से गुजर रही थी जिसमें स्वयं मुख्य नेता ही शामिल रहे।

इन अन्दरूनी मतभेदों के कारण सीओसी के गठन के बाद फरवरी 1991 में एमसीसी के साथ चल रही चर्चा वहीं की वहीं रुकी रह गयी। कुछ ही महीनों में जब हमारी पार्टी में संकट तीखा हो उठा, तो हमने एकता वार्ता स्थगित कर दी और अखिल भारतीय जन संगठनों में संयुक्त गतिविधियाँ जारी रखीं। इस दौरान हमारा नया नेतृत्व मजबूती से खड़ा हुआ और इसने आन्दोलन के 15 वर्षों की समीक्षा सहित नये दस्तावेज तैयार कर लिये। हमने अपना नया **राजनीतिक प्रस्ताव** तैयार करने के बाद मार्च 1993 से एकता–वार्ता फिर से शुरू की।

दोनों पार्टियों का इतिहास अलग–अलग रहा है। फिर भी 1980 के दशक में चर्चाओं के दौरान दोनों ही इस समान समझदारी पर पहुँचे कि वे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए **रणनीति एवं कार्यनीति** पर दोनों की समझदारी एक–सी रही; दोनों ही सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाने में गम्भीरता से लगे रहे और दोनों के नेतृत्व रणनीतिक इलाकों में केन्द्रित करते हुए केन्द्रीय कार्यभार के तौर पर जन सेना का निर्माण करने तथा आधार इलाके स्थापित करने के मकसद से कृषि क्रान्ति को आगे बढ़ाते रहे हैं। पहले सीपीआई (एमएल) के पिछले इतिहास की समझ पर दोनों के बीच मतभेद रहे। मगर 1980 के दशक की चर्चा के जरिये वे नक्सलबाड़ी जन उभार तथा पार्टी की 8वीं काँग्रेस की ऐतिहासिक महत्ता के साथ ही कामरेड सीएम की महान भूमिका के बारे में समान समझ पर पहुँच पाये। इसके अलावा दोनों धाराओं के नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर दोनों में एकमत था। इन बातों ने दोनों पार्टियों के बीच भावी चर्चा के लिए मुकम्मिल आधार मुहैया कराया।

यही बात हाल की चर्चा के दौरों और विलय के रूप में इनकी परिणति पर भी लागू होती है।

एक दशक से ज्यादा समय तक चली इस पूरी प्रक्रिया में दोनों संगठनों के विलय में हुए विलम्ब के लिए हमारी ओर से निम्न कारण रहे – शुरुआती दौर में कामरेड केएस की गिरफ्तारी तथा कामरेड केसी की शहादत से एकता–प्रक्रिया बाधित हुई; पीडब्ल्यू की सीसी में पहला संकट तथा सीसी के भंग हो जाने से एकता–प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई; कुछ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर हमारा गलत आकलन जिससे हमारे बीच एकता के रास्ते में अवरोध खड़ा करनेवाले प्रमुख मतभेद पैदा हुए और एकता–वार्ता को औपचारिक व अ–गम्भीर तरीके से चलाना।

1992–95 के बीच एकता प्रयास

पीडब्ल्यू में संकट के कारण एकता के सवाल पर चर्चा के लिए होने वाली द्विपक्षीय बैठक खटाई में पड़ गयी। मगर रिश्ते अवरिाम जारी रहे। उस वक्त हमने यह तय किया कि हम पहले अपनी पार्टी की अन्दरूनी समस्या को सुलझा लेंगे और फिर एमसीसी के साथ एकता–वार्ता शुरू कर देंगे। अगस्त 1990 में पार्टी के केन्द्रीय प्लेनम के समय हमने दो सालों में विलय प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया। लेकिन एमसीसी के कामरेड पीडब्ल्यू की अन्दरूनी स्थितियों का द्वन्द्वात्मक विश्लेषण कर पा रहे थे। उन्होंने रिश्ते जारी रखने और नये नेतृत्व के साथ विलय वार्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन बुनियादी दस्तावेजों पर चर्चा को स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि पीडब्ल्यू की सीओसी को सोवियत महाशक्ति के पतन के बाद बदली अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के मद्देनजर अपने **राजनीतिक प्रस्ताव** को अभी अन्तिम रूप देना था। फिर भी एमसीसी और पीडब्ल्यू के साथ ही पीयू और एमआरएससी–पीडब्ल्यू (पीडब्ल्यू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी) ने संयुक्त गतिविधियों का सिलसिला जारी रखा। 1992 की शुरुआत में बढ़ते राजकीय दमन और साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ संयुक्त रैली आयोजित करने का फैसला हुआ। तदनुरूप अप्रैल में यह रैली हुई और व्यापक वामपंथी तथा प्रगतिशील शक्तियों पर इसका सकारात्मक असर पड़ा। बाद में इससे अखिल भारतीय राजनीतिक जन संगठन का गठन करने में मदद मिली।

मार्च 1993 में लगभग 2 वर्षों के विराम के बाद एकता–वार्ता फिर से शुरू हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि **पार्टी कार्यक्रम** और **रणनीति एवं कार्यनीति** के प्रारूपों पर पीडब्ल्यू अपने संशोधनों को लिखित रूप में एमसीसी को भेजेगी। पीडब्ल्यू के ये संशोधन भारतीय समाज में **बुनियादी** और **प्रमुख अन्तरविरोधों** के सवाल पर,

"क्रान्तिकारी किसान कमेटी को सारी सत्ता" के सवाल पर, **राष्ट्रीयता प्रश्न** पर, **नये जनवादी राज्य पर** इत्यादि। यह भी तय हुआ कि पीडब्ल्यू **पार्टी कार्यक्रम** के उन हिस्सों को दोबारा लिखेगी जहाँ–जहाँ दोहराव लग रहा हो। **'राजनीतिक प्रस्ताव'** दस्तावेज को अन्तिम रूप देने के लिए यह तय हुआ कि एमसीसी अगली बैठक तक इसके प्रारूप पर अपने बड़े और छोटे, दोनों प्रकार के सभी संशोधन तैयार कर लेगी।

इसके अलावा यह तय हुआ कि एमसीसी **संविधन** के प्रारूप पर अपने संशोधन तैयार करेगी। साथ ही, यह तय हुआ कि एमसीसी भारतीय राज्य के बारे में अर्द्ध–सामन्ती और **नव–औपनिवेशिक किस्म के अर्द्ध–औपनिवेशिक राज्य** के रूप में सूत्रीकरण के विषय में पिछली बैठकों में आपसी सहमति से तय हो चुके अतिरिक्त अनुच्छेद (पैरा) को तैयार कर पीडब्ल्यू के पास भेजेगी। **चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में** दस्तावेज के प्रारूप में भी इसी तरह एमसीसी **कामरेड स्तालिन** पर अपने पूर्व–प्रस्तावित संशोधन को पीडब्ल्यू के पास भेजेगी। **वर्तमान युग** के **चरित्र पर** और **चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं काँग्रेस में प्रस्तुत हुई माओ विचारधारा की परिभाषा** पर विस्तृत और तीखी बहस हुई। इन सवालों पर आगामी द्विपक्षीय बैठकों में आगे चर्चा करना तय हुआ।

उस बैठक में एमसीसी ने **अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पर**, **रूस, अमरीका तथा अन्य प्रमुख साम्राज्यवादी देशों** पर और **विश्व युद्ध के खतरे** इत्यादि पर अपनी एक टिप्पणी प्रस्तुत की।

जुलाई 1994 की द्विपक्षीय बैठक **वर्तमान युग के चरित्र** और **माओ विचारधारा की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में** समान समझदारी पर पहुँची। बैठक में **'संयुक्त घोषणापत्र'** भी तैयार कर लिया गया। यह तय हुआ कि **युग और विचारधारा** के सवाल पर दोनों पार्टियों की कतारों को शिक्षित किया जायेगा।

सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} के प्रतिनिधि–मण्डल ने एमसीसी की ओर से तैयार किये गये प्रारूप दस्तावेजों **कार्यक्रम** तथा **राणनीति–कार्यनीति** पर अपने संशोधन उनको सौंप दिये। एमसीसी का प्रतिनिधि–मण्डल सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} द्वारा तैयार किये गये दो प्रारूप दस्तावेजों **संविधान** तथा **राजनीतिक प्रस्ताव** पर अपने संशोधनों के साथ ही **पार्टी कार्यक्रम** तथा **रणनीति–कार्यनीति** पर पीडब्ल्यू के संशोधनों पर अपनी धारणा एवं संशोधन दिसम्बर 1994 के अन्त तक भेजने पर सहमत हुआ। दोनों पार्टियों ने **राष्ट्रीयता संघर्षों** तथा **जाति प्रश्न** पर

भी चर्चा की। इन विषयों पर वे समान राय पर पहुँचीं। दोनों प्रतिनिधि–मण्डलों ने यह भी तय किया कि अगली बैठक में विलय के लिए बातचीत को अन्तिम रूप दिया जायेगा और अगली बैठक में दोनों पार्टियों के बीच मौजूद मतभेदों को हल करते हुए एक पार्टी में विलय के लिए दोनों पक्ष पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करेंगे। यह भी तय हुआ कि अगर विलय नहीं हो पाता है, तो क्रान्तिकारी ग्रुपों का मंच बनाया जायेगा।

एमसीसी ने जनवरी 1995 तक अपने संशोधन भेज दिये। लेकिन उन्होंने बताया कि तत्कालीन पीडब्ल्यू के **राजनीतिक प्रस्ताव** पर संशोधन रखना उनके लिए सम्भव नहीं होगा, "क्योंकि इसका पूरा दृष्टिकोण और व्याख्या हम जिस तरह रखते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है, खास तौर से रूस की स्थिति के बारे में। हमारी मार्च '93 की बैठक में हमने आपसे कहा था कि रूस की वर्तमान स्थिति पर अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हमें कुछ और समय तक देखना–परखा होगा। करीब दो सालों तक देखने के बाद हम अभी अपनी पहली अवस्थिति पर ही दृढ़ हैं। इसीलिए जब तक हम इस मुद्दे पर किसी समान सहमति तक नहीं पहुँच पाते हैं, कामरेड लेनिन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं या 10वीं काँग्रेस से केवल कुछ उद्धरण भर पेश करना व्यर्थ होगा।" उन्होंने **अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पर** अपने दृष्टिकोण एवं अवस्थिति की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त वक्तव्य भेज दिया।

अब दोनों प्रतिनिधि–मण्डल मई 1995 में मिले। अपने मतभेदों पर रेशा–रेशा चर्चा करने के बाद भी वे समान समझदारी तक नहीं पहुँच पाये। अन्ततः दोनों पक्षों ने अपनी पार्टियों की एकता की राह में बाधा बन रहे प्रमुख राजनीतिक मतभेदों को चिह्नित किया।

इस तरह बैठक में दोनों पार्टियों ने एकमत से कुछ समय के लिए एकता वार्ता स्थगित करने और परस्पर सहयोग रखने का फैसला किया, "क्योंकि बावजूद इसके कि मा–ले–मा, राष्ट्रीयता प्रश्न और देश के बुनियादी अन्तरविरोधों पर हम एक राय बना पाये हैं, एकता अभी सम्भव नहीं है क्योंकि निम्न सात बिन्दुओं पर मतभेद बने हुए हैं।" यह तय हुआ कि दोनों पक्ष मतभेदों के बिन्दु लिखित रूप से पार्टी सदस्यों के पास ले जायेंगे, महान शिक्षकों की कृतियों का गहराई से अध्ययन करेंगे और अक्सर एक–दूसरे के साथ अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन पर चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रक्रिया से समान समझदारी हासिल की जा सके। मतभेदों के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार रहे – (1) दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद में आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का आकलन; (2)महाशक्ति की परिभाषा; (3) रूस की वर्तमान

हैसियत; (4) वर्तमान दुनिया में जापान, यूरोपीय संघ (खास कर जर्मनी) की स्थिति; (5) साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच से एक महाशक्ति के स्थान से हट जाने की जन संघर्षों में क्या भूमिका होगी; (6) वर्तमान विश्व परिस्थिति में तीन दुनियाओं का विभेदीकरण; (7) अमरीकी महाशक्ति की वर्तमान स्थिति।

उपरोक्त राजनीतिक मतभेद ही इस मोड़ पर एकता हासिल न कर पाने का वास्तविक कारण रहे। लेकिन जब दोनों पक्ष इस आकलन पर पहुँचे कि एकता तुरन्त हासिल नहीं की जा सकती है, तो हमें अपनी द्विपक्षीय राजनीतिक चर्चाओं को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने के बजाय सिर्फ अपने मतभेदों को दर्ज करना चाहिए था। हमारी इस खामी ने एकता–वार्ता में अनावश्यक विलम्ब पैदा करने में भूमिका निभायी। साथ ही इससे बाद के हमारे परस्पर सम्बन्धों पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह एकता–प्रक्रिया में हमारी ओर से रही खामियों में से एक है।

1996–2000 का दौर
(तनावग्रस्त रिश्तों का दौर)

जब एकता–वार्ता अभी चल ही रही थीं तब एमसीसी ने 1994 में तत्कालीन पीडब्ल्यू का तीन पार्टियों एमसीसी, पीडब्ल्यू, पीयू को लेकर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों का संयुक्त मंच तैयार करने और इस मंच का इस्तेमाल अखिल भारतीय जन संगठनों की गतिविधियों और अन्य सामन्तवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी, राज्य–विरोधी गतिविधियों में तालमेल करने का प्रस्ताव खारिज किया। परिणामस्वरूप अन्य सभी सच्ची क्रान्तिकारी शक्तियों को एक एकताबद्ध मंच पर लाने की योजना अमल में नहीं आ सकी। 1995 में पीडब्ल्यू तथा एमसीसी के बीच विलय–वार्ता की विफलता के बाद पीडब्ल्यू ने 1996 और 1997 में फिर से तत्कालीन पीयू के साथ मिलकर 'संयुक्त मंच' बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन एमसीसी ने इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि तत्कालीन पीयू और तत्कालीन एमसीसी के बीच रिश्ते तनावग्रस्त थे।

1996 में अखिल भारतीय जन संगठन का निर्माण केसे किया जाय, इस सवाल पर गम्भीर मतभेदों के कारण एमसीसी इससे बाहर निकल गयी। अब सौहार्दपूर्ण रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। फिर भी दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठकें जारी रहीं। इस दौर में पीडब्ल्यू और पीयू के बीच संयुक्त गतिविधियाँ और विलय–वार्ता जारी रही। पीयू और एमसीसी के बीच मुख्यतः बिहार में विकसित हो रही स्थानीय समस्याओं

को हल करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें होती रहीं।

इन सारी बातों के बावजूद एमसीसी और पीयू के बीच तनाव बढ़ते गये और स्थिति एक–दूसरे की हत्या करने तक पहुँची। इस दौरान अलग–अलग प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से पीडब्ल्यू की सीसी (अस्थाई) और 'कोरिम' (रिम की कमेटी) ने आपस में संघर्षरत दोनों पार्टियों से अपील की कि वे अपनी झड़पें रोक दें और विवादित मुद्दों पर विचार–विमर्श के माध्यम से समाधान ढूँढें। फिर भी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया।

इस दौरान पीयू के साथ सूचनाओं एवं अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए शुरू की गयी वार्ता 1996 के बाद एकता–वार्ता की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई। इसकी परिणति अगस्त 1998 में दोनों पार्टियों के विलय के रूप में सामने आयी। दोनों पार्टियों की संयुक्त सीसी (अस्थाई) ने अपनी पहली बैठक में ही इन झड़पों को एकतरफा तरीके से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। हमने 3–4 महीनों तक एमसीसी पर सभी हमले रोक रखे। लेकिन न तो हमने अपनी सीसी (अस्थाई) में लिये गये फैसलों से और न ही जमीनी हकीकतों से एमसीसी को अवगत कराया। इसीलिए स्थितियों में कोई सुधार नहीं हो पाया और एकीकृत पीडब्ल्यू एवं एमसीसी के बीच झड़पें बढ़ती तीव्रता के साथ बदस्तूर जारी रहीं। एक ओर तो हम एमसीसीआई को क्रान्तिकारी खेमे में बताते रहे, जबकि दूसरी ओर हमने अपने लेखों तथा प्रचार साहित्य में यह लिखा कि एमसीसीआई में ऐसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि जिस तरह के तत्वों पर वह निर्भर करने लगी है और जिस तरह की गैर–सर्वहारा पद्धतियाँ वह अपना रही है, अगर वह इसमें सुधर नहीं करती, तो वह क्रान्तिकारी खेमे से बाहर जा सकती है। हमारे आपसी पत्र व्यवहार में भी हमने एमसीसी को उकसाने वाली बातें लिखीं। एमसीसी की कुछेक भूलों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने और उनके बारे में एक बुरी तस्वीर पेश करने के हमारे गलत दृष्टिकोण के कारण दोनों पार्टियों के बीच दूरी बढ़ी। हमारी निम्न–पूँजीवादी अल्पदृष्टि के ही कारण दो दशकों से एमसीसी के साथ करीबी रिश्ते होने के बावजूद हमने दूरगामी हित नहीं देखे, गैर–दुश्मनाना अन्तरविरोधों को दुश्मनाना अन्तरविरोध के रूप में देखते हुए व्यवहार किया। यही नहीं, हमारे बीच गलतफहमियाँ 1999 की द्विपक्षीय बैठक की उस विफलता के बाद भी बढ़ीं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी भी थी। इससे दोनों पार्टियों के बीच झड़पों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2001 से 2004 का दौर
(एकीकृत पार्टी की ओर ऐतिहासिक सन्धि–काल)

दो पार्टियों के बीच इन झड़पों से न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी माओवादियों को गहरा क्षोभ महसूस हुआ। अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की ओर से झड़पों को रोकने और मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए एकताबद्ध होने की शिद्दत से अपीलें की गयीं। इस पृष्ठभूमि में एमसीसी ने जनवरी 2000 में एकतरफा युद्ध–विराम घोषित किया। मार्च 2000 में हमने भी इसका सकारात्मक जवाब दिया और सभी इकाइयों को फौरन झड़पें रोकने के निर्देश दिये। लेकिन मार्च 2000 में एमसीसी की पहल का स्वागत करते हुए हमने झड़पों के लिए एमसीसी को ही मुख्य जिम्मेदार बताया और घोषित किया कि जैसे ही एमसीसी रोक लगाता है, झड़पें अपने–आप रुक जायेंगी। हमारी ओर से यह गम्भीर गलती रही, क्योंकि हमने अपनी ओर से हुई गलतियों को चिह्नित किये बगैर एमसीसी को ही झड़पों के लिए मुख्य दोषी ठहराया।

मार्च 2001 में पीडब्ल्यू की 9वीं काँग्रेस हुई। काँग्रेस की राजनीतिक–सांगठनिक समीक्षा में हमने यह सही कहा कि **"हमें एमसीसी के साथ वार्ता करनी चाहिए और बिरादराना रिश्ते कायम रखने का प्रयास करना चाहिए।"** लेकिन हमने झड़पों के लिए तथा बिहार–झारखण्ड की तनावग्रस्त स्थिति के लिए एमसीसी को ही दोष दिया और अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए कोई आत्मालोचना नहीं की। हमने यह कहा कि एमसीसी द्वारा अपनाये गये दुश्मनाना रवैये और एक दशक से ज्यादा समय तक पूर्ववर्ती पीयू के खिलाफ उसके हमलों के ही कारण ये झड़पें हुई हैं।

लेकिन इस काँग्रेस के तुरन्त बाद एमसीसीआई ने पीडब्ल्यू की सीसी को काँग्रेस के फैसलों के लिए बधाई पत्र भेजा। 1998–2000 के दौर में द्विपक्षीय वार्ता रखने के प्रयास करने के बावजूद इसमें सफलता नहीं मिल पायी थी। काँग्रेस के ठीक पहले दोनों पक्षों के कामरेड सम्पर्क के स्थान पर पहुँचे थे। मगर एमसीसी में उस वक्त चल रहे संकट के कारण वार्ता बहाल नहीं हो पायी थी। अन्ततः लम्बे अन्तराल के बाद दोनों पार्टियों की सीसी के प्रतिनिधि–मण्डलों ने अगस्त 2001 में मुलाकात की।

यह बैठक ऐतिहासिक रही। इसने हमेशा के लिए झड़पों को बन्द करने की शर्तें तय कीं। तनावग्रस्त रिश्तों के उस दौर को भारतीय क्रान्ति में **काला अध्याय** बताने वाला प्रस्ताव पारित हुआ और दोनों पक्षों ने इसे फिर कभी न दोहराने का प्रण किया। दोनों पार्टियों ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की और सीधे जनता के सामने

जाकर सार्वजनिक रूप से आत्मालोचना की। इस रवैये का भारत की समूची जनता ने, खास कर बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल की जनता ने, दोनों पार्टियों की कतारों ने और अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन ने स्वागत किया। उक्त बैठक में संयुक्त गतिविधियों का सकारात्मक असर पड़ा। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा। इसके अलावा स्थानीय टकरावों के समय बिहार–झारखण्ड में प्रदेश स्तर की संयुक्त बैठकें और दोनों पार्टियों के स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्यों/राज्य कमेटी के सदस्यों तथा केन्द्रीय कमेटी सदस्यों के प्रतिनिधि–मण्डलों द्वारा अनेक बार हस्तक्षेप करने पर निचले स्तर के तनाव दूर करने में सहायता मिली।

इन प्रयासों के बावजूद कुछ गाँवों में छिटपुट झड़पें होती रहीं, क्योंकि लगभग पूरे एक दशक तक तनावों का लम्बा दौर चला आया था। दोनों पार्टियों की सैक/एससी और सीसी ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, जिससे तनाव बहुत हद तक दूर किये जा सके।

जुलाई 2002 में लगभग एक साल तक रिश्ते सामान्य बनाने के सफल प्रयासों के बाद दोनों पार्टियों की सीसी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि–मण्डल एक–साथ बैठे। उन्होंने एक–दूसरे की ताजा राजनीतिक अवस्थितियों को सुना और विलय–वार्ता की योजना बना ली। अन्ततः फरवरी 2003 में हुई एक बैठक में दोनों पार्टियों के उच्चाधिकार–प्राप्त प्रतिनिधि–मण्डलों ने चर्चा की और ज्यादातर राजनीतिक, विचारधारात्मक एवं सामरिक मुद्दों पर निष्कर्षात्मक समाधान ढूँढ लिये। दोनों ने इस बैठक को ऐतिहासिक बैठक और विलय की प्रक्रिया में मील का पत्थर बताया। यह बैठक दरअसल हाल की विलय–वार्ता का पहला चरण था। इसमें दोनों प्रतिनिधि–मण्डलों ने सम्यक् रूप से और तहेदिल से अपनी–अपनी आत्मालोचना प्रस्तुत की। ज्यादातर राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बनी, पर एमसीसीआई के प्रतिनिधि–मण्डल ने यह राय रखी कि "दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग बनाम व्यापक जनता" के बुनियादी अन्तरविरोध के सम्बन्ध में पीडब्ल्यू की 9वीं काँग्रेस का सूत्रीकरण एकीकरण की प्रक्रिया में अवरोध बनेगा। एकता के हित और भारतीय क्रान्ति के भावी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पीडब्ल्यू के प्रतिनिधि–मण्डल ने इस मुद्दे पर अपनी राय सुरक्षित रखने, इसे नये दस्तावेजों में शामिल न करने और एकीकृत पार्टी काँग्रेस में भी इस पर आग्रह न करने का साहसिक फैसला किया।

अगली बैठक सितम्बर 2003 में रखी गयी। इस बैठक में हमने **मा–ले–मा** पर दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया और **रणनीति–कार्यनीति, कार्यक्रम** तथा **राजनीतिक**

प्रस्ताव के प्रारूपों की रूपरेखाएँ तैयार कीं। फिर जनवरी–फरवरी 2004 में दोनों प्रतिनिधि–मण्डलों ने फिर मिलकर उपरोक्त दस्तावेजों के ज्यादातर हिस्सों को अन्तिम रूप दिया।

इसी बैठक में यह तय हुआ कि सितम्बर 2004 में एकता के निष्कर्ष तक पहुँचा जायेगा। अब दोनों पार्टियों की सीसी की इस वर्तमान बैठक में अन्ततोगत्वा विलय के लिए सारी तैयारियाँ पूरी कर ली जायेंगी।

एमसीसीआई के साथ तनावग्रस्त रिश्तों के सन्दर्भ में आत्मालोचना

1970 के दशक के अन्त और 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर एक लम्बे दौर तक देश की तीन मुख्य क्रान्तिकारी पार्टियों पीडब्ल्यू, एमसीसी और पीयू के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे हैं। 1970 के अन्त में तत्कालीन पीयू ने एमसीसी और सीपीआई (एमएल) की तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी (जो 1980 में गठित सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} का मुख्य घटक रही) से सम्पर्क साधने और एकता वार्ता आयोजित करने की मंशा से पहल की। तीनों पार्टियों ने भारत की ठोस स्थितियों में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को लागू करते हुए दीर्घकालीन लोक युद्ध को विकसित करने के गम्भीर प्रयास किये हैं। उन्होंने आधुनिक संशोधनवाद और क्रान्तिकारी खेमे के भीतर के दक्षिण तथा वाम भटकावों के खिलाफ सतत संघर्ष किया और क्रमशः कामरेड सीएम और केसी की क्रान्तिकारी लाइनों की हिमायत की। शुरुआती दौर में एमसीसी के महासचिव कामरेड केसी, पूर्ववर्ती पीयू के नेतृत्व और पीडब्ल्यू के पूर्ववर्ती सचिव कामरेड केएस ने इन तीनों पार्टियों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीनों ने दीर्घकालीन लोक युद्ध के जरिये राजनीतिक सत्ता दखल के लिए नक्सलबाड़ी की लाइन को आगे बढ़ाने के प्रयास किये। फलस्वरूप तीनों पार्टियाँ भारतीय क्रान्ति के प्रमुख हिरावल संगठनों के रूप में उभरीं। हमारी पार्टी और एमसीसी भारत के माओवादी आन्दोलन की दो भिन्न धाराओं की तो रही हैं, पर दोनों ही देश में सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती आयी हैं। क्रान्तिकारी युद्ध चलाये जाने के दौर के ज्यादातर हिस्से में तीनों पार्टियों के बीच सर्वहारा उसूलों और मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के आधार पर सौहार्दपूर्ण एवं कामरेडाना रिश्ते रहे हैं। तीनों ने एकताबद्ध होने और भारत में एकीकृत क्रान्तिकारी सर्वहारा पार्टी का निर्माण करने के लिए गम्भीरता से प्रयास किये हैं।

पहली बार वर्ष 2001 की द्विपक्षीय वार्ता के समय रखी गयी और फिर पार्टी की कतारों तथा आम जनता तक ले जायी गयी आत्मालोचना के क्रम में हम इस आत्मालोचना को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2001 में झड़पों को रोकने के मकसद से फौरी आत्मालोचना की गयी। 2003 की संयुक्त बैठक के दौरान व्यापक चर्चा के बाद दोनों पार्टियों की सीसी ने अपनी–अपनी विस्तृत एवं गम्भीर आत्मालोचा पेश की। इसके सार–संक्षेप को पर्चे के रूप में आम जनता तक ले जाया गया। अब हम अपनी आत्मालोचना को लिखित रूप में यहाँ पेश कर रहे हैं। बिहार–झारखण्ड प्रदेशों में तत्कालीन पीयू और एमसीसी के बीच तनावों की उत्पत्ति एवं विकास के मुख्य कारण प्रमुखता से निम्न मुद्दों की उपज रहे हैं – **पहला** एक ही इलाके में काम करते हुए जनता के बीच के अन्तरविरोधों को हल करने और व्यवहार के दौरान उभरी समस्याओं से निबटने का नजरिया (अप्रोच) और दृष्टिकोण; **दूसरा,** दो पार्टियों के बीच भिन्न–भिन्न कार्यप्रणाली में अभिव्यक्त होनेवाले विचारधारात्मक तथा राजनीतिक मतभेद। इसी के परिणामस्वरूप 1991 से दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गये। वर्ष 2001 तक एक–दूसरे की जो हत्याएँ हुईं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इन समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया गया, जिसके कारण तनाव बढ़े। परिणति के रूप में 1996 तक आते–आते खून–खराबा, हत्या, आगजनी इत्यादि होने लगी। बाद में जब हमारी पार्टियों ने मिलकर विलय–वार्ता शुरू की, तो उस मोड़ पर भी अपनी संयुक्त बैठकों के प्रस्तावों को पारित करने में तथा कतारों को वर्ग दृष्टिकोण से लैस करने में हमारे नेतृत्व की भूलों के कारण धमकी, सफाया जैसी घटनाएँ छिटपुट रूप से चलती रहीं। हमारे (1997 तक पूर्ववर्ती पीयू और बाद में नयी पीडब्ल्यू) इस गलत नजरिये के कारण हमारे अपने वर्ग भाइयों के साथ खून–खराबा किया गया। अगर हमने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समुचित लेनिनवादी कार्यशैली और माओवादी मार्गदर्शन को अपनाया होता, तो यह सब इस तरह नहीं हुआ होता। इसके विपरीत हमने हमदर्दों एवं निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की हत्या करने, गाँव की आम जनता के घर ध्वस्त करने तथा सम्पत्ति नष्ट करने के तौर–तरीके अपनाये। तकरीबन आधे दशक तक दोनों पक्षों की ओर से हुई इन झड़पों के कारण इलाके के लोग दहशत के माहौल में जीते रहे है। हम समय पर इन गम्भीर परिणामों का एहसास नहीं कर पाये। **निर्णयों को लागू करने में अपनी ओर से हुई भूलों के साथ ही संकुचित हित, सर्वहारा दृष्टिकोण से भटकाव तथा बोल्शेविक आदर्शों के आधार पर एमसीसीआई के साथ दोस्ताना अन्तरविरोधों को हल करने के**

उसूलों की अवहेलना सहित अपनी अन्य खामियों के लिए सीपीआई (एमएल) {पीपुल्स वार} की केन्द्रीय कमेटी अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करती है।

बिहार–झारखण्ड में अपने रिश्तों के बीच तनाव के दौर में हमने अपनी दो पार्टियों के बीच झड़पों को ज्यादातर स्थानीय सन्दर्भों में ही देखा। हमने न तो भारतीय क्रान्ति के दूरगामी हितों पर पड़ने वाले इनके नकारात्मक असर को ध्यान में रखा और न ही अपनी दोनों पार्टियों के बीच समग्र बिरादराना रिश्तों पर पड़ने वाले इनके नकारात्मक असर को।

बाद के दौर में जब अगस्त 1998 में पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू तथा पीयू का अगस्त 1998 में एक पार्टी के रूप में विलय हुआ, तो हमारी केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने अपनी पहली बैठक में ही **एमसीसीआई के खिलाफ हर तरह की कारवाइयों के साथ ही पहले से तनावग्रस्त वातावरण को और बिगाड़ सकने वाले हर तरह के प्रचार पर एकतरफा रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया।** सीसी (अस्थाई) ने इस समस्या में प्रमुख रूप से शामिल रही बिहार राज्य कमेटी को भी इस पर सहमत करा लिया। लेकिन हमारी सीसी (अस्थाई) की प्रमुख विफलता यह रही कि इसने अपने इस निर्णय से बिहार तथा झारखण्ड की प्रेस को, अन्य बिरादराना क्रान्तिकारी ग्रुपों को और यहाँ तक कि खुद एमसीसीआई की केन्द्रीय कमेटी को भी अवगत नहीं कराया। हालांकि एमसीसीआई को सूचित न करने का एक कारण हम दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन न हो पाना रहा, फिर भी अपना प्रस्ताव एमसीसीआई तक न पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हम इस गम्भीर भूल की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मालोचना करते हैं। इस भूल के परिणाम भयानक हुए। बिहार–झारखण्ड में हमारी पार्टियों के बीच खून–खराबा पूरे दो सालों तक होता रहा। उन दिनों हम निहायत बेफिक्री के नजरिये से यह कहते रहे कि "हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल आत्मरक्षा के खातिर जवाबी कारवाई कर रहे हैं।" **यह बिरादराना पार्टी के प्रति सर्वहारा नजरिये से एक गम्भीर भटकाव था।**

बिहार–झारखण्ड में करीब आधे दशक तक वर्ग दुश्मन के खिलाफ वर्ग संघर्ष बुरी तरह प्रभावित रहा। जहाँ दोनों पार्टियों को मिलकर वास्तव में छापामार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई छेड़नी चाहिए थी, वहाँ हमने हमेशा मुख्यतः एमसीसीआई को ही दोष देते हुए अपने ही कामरेडों की हत्या तक की। यह भारत के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन का **काला अध्याय** रहा है।

एमसीसी के बारे में पूर्ववर्ती पीयू ने बिहार में पर्चों के माध्यम से कुछ कुत्सा प्रचार किया। अपने पहले वाले विलय से वर्तमान सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} के गठन के बाद अपनी पत्रिकाओं तथ अन्य प्रचार साहित्य में तीखा वैमनस्यपूर्ण लेख छपे। एक तरफ तो हम एमसीसीआई को क्रान्तिकारी खेमे में बताते रहे, जबकि दूसरी तरफ अपने साहित्य में हमने यह लिखा कि एमसीसीआई में पतित होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरह के तत्वों पर वह निर्भर करने लगी है और जिस तरह की गैर–सर्वहारा पद्धतियों को वह अपना रही है, अगर वह इसमें सुधार नहीं करती, तो वह क्रान्तिकारी खेमे से दूर चली जा सकती है। एमसीसी को बदनाम करने के लिए उसकी कुछेक भूलों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने का गलत नजरिया अपनाकर हमने गलत आरोप साबित करने का प्रयास किया। यह दूरगामी हितों पर ध्यान दिये बगैर निम्न पूँजीवादी अल्पदृष्टि का एक लक्षण है। बावजूद इसके कि हम दो दशकों से एमसीसीआई के कामों से जुड़े रहे हैं, हमने गैर–दुश्मनाना अन्तरविरोध को दुश्मनाना अन्तरविरोध की तरह हल करनते रहे। हम अपने निम्न–पूँजीवादी वर्ग दृष्टिकोण के कारण परिस्थिति और समस्या का आकलन करने में **मार्क्सवादी प्रणाली से भटक गये।**

जब दोनों पक्षों के हमारे अपने वर्ग के लोगों ने दोनों पार्टियों द्वारा अपनायी गयी प्रतिक्रियात्मक पद्धति का विरोध किया, जब क्रान्ति का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों एवं प्रगतिशील तत्वों ने झड़पें रोकने की हमसे अपील की, और जब देश एवं विदेश के विभिन क्रान्तिकारी ग्रुपों तथा मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टियों ने हमसे झड़पों को सुलझाने तथा भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने की अपील की, तो **हमने शुरुआत में इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया।** जब एमसीसी ने जनवरी 2000 में एकतरफा युद्ध–विराम की घोषणा की, तो हमारी सीसी ने मार्च 2000 में इसका स्वागत करते हुए झड़पों को रोकने की मुख्य जिम्मेदारी एमसीसी पर डाली। यह हमारी ओर से गम्भीर गलती थी। जब काफी नुकसान हो चुका था, तब कहीं हमने झड़पें रोकीं और हमारे रिश्तों में नये अध्याय की शुरुआत हो पायी, जो आगे चलकर भारत की एक क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में विलय तक पहुँची है। इस दौर में द्विपक्षीय बैठक रखने के गम्भीर प्रयास न करने के लिए हम भी जिम्मेदार रहे हैं। अगर द्विपक्षीय बैठक हुई होती, तो हम चर्चा के जरिये झड़पों को रोक पाये होते। गम्भीरता के अभाव और संकीर्णतावाद के कारण यह गलती हुई।

इस सन्दर्भ में हमारी विशिष्ट आत्मालोचना

(1) खून–खराबे के लिए, लोगों को मानसिक आघात पहुँचाने के लिए एवं हजारों परिवारों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए तथा **काले अध्याय** के दौरान कुछ हद तक क्रान्तिकारी खेमे में हम पर भरोसा खोये जाने के लिए हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हम जनता को और क्रान्तिकारी खेमे को आश्वस्त करते हैं कि इसके बाद **हम फिर कभी अपने वर्ग भाइयों के खिलाफ इस तरह के जानलेवा हमले नहीं करेंगे।**

(2) 1990 के दशक की शुरुआत में कामरेड सत्यनाराण सिंह की हत्या और हमारी ओर से हुई कुछ अन्य गलतियों ने हमारी दो पार्टियों के बीच रिश्ते बिगाड़ने में योगदान दिया। **यह हमारी राजनीतिक कमजोरी के कारण हुआ।**

(3) हम बिहार राज्य पार्टी कमेटी द्वारा 1995 में "एमसीसी को उखाड़ फेंको" का नारा देने की महागम्भीर गलती का गहराई से एहसास कर रहे हैं। हालांकि इस नारे को तत्कालीन सीसी ने फौरन हटवा लिया था, फिर भी द्विपक्षीय रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ा। इसका मूल कारण है, हमारा उतावलापन और संकीर्ण नज़रिया।

(4) हमारी पत्राचार की पद्धति, लेखों तथा अन्य प्रचार साहित्य की अन्तर्वस्तु और इन्हें लिखने की शैली सही नहीं रही। हमारी यह गलत शैली एमसीसीआई के चरित्र के गलत आकलन के कारण उपजी है। **हमारा मनोगतवाद इसके लिए जिम्मेदार रहा।**

(5) "हमारी गलतियाँ कम हैं और हमारी जवाबी कारवाई आत्म–रक्षा के लिए है।" यही हमारे तर्कों तथा रवैये का निचोड़ तथा सार रहा। आत्मालोचनात्मक रवैये के बजाय हमने मुख्यतः एमसीसी को ही दोष दिया। **समस्या का समाधान करने के प्रति यह हमारा संकीर्णतावाद तथा गैर–सर्वहारा नजरिया रहा।**

(6) हम गाँव की जनता के बीच के अन्तरविरोधों में उलझ गये। एक ग्रुप पर आधारित होकर हम एमसीसीआई के स्थानीय जनाधार पर हमला करते रहे। अन्तरविरोधों को जनता के बीच एकता हासिल करने के मकसद के साथ, वर्ग नजरिये से हल करने के बजाय और इन अन्तरविरोधों को गैर–दुश्मनाना तरीके से हल करने के बजाय हमने **पक्षपाती और गैर–सर्वहारा नजरिया अपनाया।**

(7) समस्याओं का समाधान राजनीतिक वाद–विवाद से करने के बजाय हम बार–बार जवाबी कारवाई करने की पद्धति में उलझ गये और इसे प्राथमिकता देते रहे। नेतृत्व की ओर से **राजनीतिक दृष्टि के अभाव** के कारण हम तर्कों और कतारों

के पीछे–पीछे चलते रहे। सार–संक्षेप में कहें, तो हमारी इन गलतियों की विचारधारात्मक एव राजनीतिक जड़ें हमारे उस मनोगतवाद, संकीर्णतावाद और अल्पदृष्टि में हैं, जिसके चलते स्थानीय हित वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये। फलस्वरूप हमारी दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गये। साररूप में गैर–सर्वहारा प्रवृत्तियाँ, स्पष्ट रूप से कहें, तो निम्न पूँजीवादी प्रवृत्तियाँ इस मुद्दे से निबटते समय हमारी सोच और व्यवहार पर हावी रहीं। परिणामस्वरूप इन समस्याओं को द्वन्द्वात्मक नजरिये से हल करने के बजाय हमने इस अन्तरविरोध को गलत तरीके से हल किया। इस सन्दर्भ में हम यह विश्वास दिलाते हैं कि इन गैर–सर्वहारा प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा दाँव पर लगा देंगे।

इस खून–खराबे के बदले हम अपनी आपसी झड़पों में मारे गये सभी शहीदों को लाल सलाम पेश करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस नकारात्मक अनुभव से सीखेंगे और अपने वर्ग मित्रों के खिलाफ फिर कभी हथियार नहीं उठायेंगे, चाहे मतभेद कितने भी तीखे क्यों न हो जायें। राजनीतिक मतभेदों को राजनीतिक वाद–विवाद से हल करते हुए और क्रान्तिकारी व्यवहार के जरिये अपनी राजनीति के औचित्य को साबित किया जाना चाहिए। इसके लिए बन्दूक का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से मारे गये शहीदों को एक बार फिर लाल सलाम पेश करते हुए **हम अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और इनके कारण जिन परिवारों को दुख–तकलीफ सहना पड़ा उन सभी से क्षमा मांग रहे हैं।** हम, सीपीआई (एमएल) {पीडब्ल्यू} की सीसी की ओर से भारत की क्रान्तिकारी जनता, खास तौर से बिहार–झारखण्ड की जनता से याचना करते हैं कि वे हमें अपनी इन गलतियों के लिए माफ कर दें। भले ही हमें अपनी इन महागम्भीर गलतियों का एहसास देर से हुआ हो, फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस तरह के आत्मघाती कृत्यों को कभी नहीं दोहरायेंगे।

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने प्रिय शहीदों के सपनों को साकार करते हुए जन युद्ध को तेज करेंगे, कि हम अपने महान नेताओं मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन, माओ की शिक्षाओं को लागू करेंगे और भारतीय जनवादी क्रान्ति को सफलता की ओर आगे बढ़ायेंगे और भविष्य में एक सच्चे, परिपूर्ण साम्यवादी समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ेंगे। हम अपनी गलतियों को सुधारने और सच्चे सर्वहारा क्रान्तिकारियों के रूप में खुद को फिर से ढालने का प्रण करते हैं।

दूसरे देशों के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के साथ रिश्ते

भारत का क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलन को अविभाज्य और अनिवार्य हिस्सा है। भारत का सर्वहारा वर्ग विश्व सर्वहारा क्रान्ति का एक लड़ाकू दस्ता है। भले ही देश विशेष में क्रान्ति को विजय तक पहुँचाने के लिए उस देश की क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी ही प्रधान जनता का सक्रिय समर्थन भी नितान्त आवश्यक होता है। विभिन्न देशों में वहाँ की क्रान्ति का नेतृत्व करने वाली बिरादराना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जीवन्त रिश्ते कायम रखना, विभिन्न देशों की क्रान्तियों के अनुभवों का आदान–प्रदान करना, रचनात्मक भावना से आपसी सलाह मशविरा करना तथा आपसी मदद एवं सहायता करना, एकजुटता आन्दोलन खड़े करना, साम्राज्यवाद तथा विश्व प्रतिक्रियावाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चों का निर्माण करना तथा संयुक्त संघर्ष संचालित करना, संशोधनवाद के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ना और मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की हिफ़ाज़त करना – यही हैं किसी देश की क्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनायीजाने वाली अन्तरराष्ट्रीय नीतियाँ। इस तरह के व्यवहार से ही देश विशेष की कम्युनिस्ट पार्टी सचमुच सर्वहारा अन्तरराष्ट्रवाद पर कायम रहती है। हमारी पार्टी इसी समझदारी के साथ विदेशों की बिरादराना पार्टियों के साथ रिश्ते कायम करती रही है।

हमारे पहले सम्बन्ध नेपाल में जन युद्ध छेड़े जाने से काफी पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) – नेकपा (माओवादी) के साथ रहे हैं। काफी पहले से हम उनके साथ सकारात्मक द्विपक्षीय रिश्ते कायम रखते आये हैं। नेकपा (माओवादी) ने जो जन युद्ध छेड़ रखा है उसने दुनिया भर में, खास कर दक्षिण एशिया पर सकारात्मक असर डाला है। दोनों पार्टियों ने सर्वहारा अन्तरराष्ट्रवाद की भावना से भारत और नेपाल में चल रहे जन युद्धों को समर्थन दिया है, अनेक प्रकार से एक–दूसरे की सहायता की है, अनुभवों का आदान–प्रदान किया है और भारतीय विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त वक्तव्य जारी किये हैं। दोनों पार्टियों के बीच विकसित होते करीबी तालमेल का परिणाम अन्ततः जून 2001 में कोम्पोसा (दक्षिणी एशिया की माओवादी पार्टियों तथा संगठनों की तालमेल कमेटी) की पहल और गठन के रूप में सामने आया।

कोम्पोसा का गठन नेपाल, भारत, बांगलादेश एवं श्रीलंका देशों की माओवादी पार्टियों के मंच के रूप में भारतीय विस्तारवाद को निशाना बनाने, दक्षिण एशिया की सभी माओवादी शक्तियों के बीच तालमेल को गहराने, दक्षिण एशिया में जन युद्ध को

तेज करने, आपसी अनुभवों एवं सहायता का आदान–प्रदान करने तथा एकजुटता व्यक्त करने, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद का प्रचार करने आदि के लिए हुआ है। यह भी तय किया गया है कि यह मंच आम सहमति के आधार पर ही काम करेगा, जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर नहीं। इन मार्गदर्शक बिन्दुओं के बावजूद नेकपा (माओवादी) और कोम्पोसा के कुछ अन्य भगीदारों ने इस मंच के मुश्तरका घोषणापत्र में क्रान्तिकारी अन्तरराष्ट्रवादी आन्दोलन (रिम) की भूमिका एवं अहमियत के उल्लेख के सन्दर्भ में अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपने का प्रयास किया। एक साल तक संघर्ष करने के बाद ही जाकर कहीं जुलाई 2002 में वार्षिक आम सभा की बैठक में घोषणापत्र से रिम के सन्दर्भ में मूल आपत्तिजनक सूत्रीकरण को हटाया जा सका।

कोम्पोसा के तमाम सम्मेलनों में अब तक इसी शुरुआती **घोषणापत्र** को और तमाम **प्रस्तावों** को पारित किया गया है। कोम्पोसा ने दक्षिण एशिया के उपरोक्त सभी देशों में नियमित वक्तव्य जारी किये हैं और विभिन्न मुद्दों पर प्रचार किया है। क्षेत्र के माओवादी आन्दोलनों की रिपोर्टों को एक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता रहा है।

1995 तक हमारी पार्टी केवल दक्षिण एशिया की पार्टियों के साथ ही बिरादराना रिश्ते कायम कर पायी थी। 1996 में पहली बार हम देश के बाहर मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टियों की किसी बैठक में शामिल हुए। तब तक इन मंचों पर उपस्थित रहने वाली दक्षिणपंथी तथा संशोधनवादी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टियों ने विदेशों में पीडब्ल्यू को एक किस्म के आतंकवादी संगठन के रूप में दर्शाया था। 1996 में बेल्जियम की पीटीबी द्वारा आयाजित मई दिवस समारोह में हिस्सेदारी करते हुए और **"भारत में सशस्त्र संघर्ष – हमारे अनुभव"** शीर्षक से अपना आलेख प्रस्तुत करते हुए हमने तमाम देशों में काम कर रही बहुत सारी बिरादराना पार्टियों को अपने आन्दोलन से परिचित कराया। फिर उसी साल हमारी पार्टी के प्रतिनिधि ने जर्मनी में एमएलपीडी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सेदारी की और विश्वव्यापी सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तियों की एकता पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन दो आयोजनों में भाग लेकर हम विदेशों में अपनी पार्टी और क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में फैली गलत धारणाओं को दूर कर पाये।

इन दो बैठकों में हिस्सेदारी करते हुए हम दक्षिण एशिया से बाहर की कुछ माओवादी पार्टियों के साथ रिश्ते स्थापित करने में कामयाब हो पाये। हमने दिसम्बर 1998 में फिलिपीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी और तुर्की की टीकेपी/एमएल के साथ

मिलकर **"माओ और जन युद्ध"** विषय पर अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। 1990 के दशक में जितनी भी अन्तरराष्ट्रीय बैठकें आयोजित हुईं, उनमें इस सेमिनार की विशेष तौर पर अधिक सार्थकता इसलिए रही कि इसने सच्चे मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी संगठनों के साथ सम्बन्ध मजबूत करने में मदद पहुँचायी। इस सेमिनार में पारित किये गये प्रस्ताव राजनीतिक तौर पर अन्य बहुत सारे अन्तरराष्ट्रीय मंचों के प्रस्तावों से गुणात्मक रूप से बेहतर रहे। इसमें यह घोषणा की गयी कि मा–ले–मा विचारधारा या माओवाद मार्क्सवाद–लेनिनवाद की विकसित अवस्था है। इस सेमिनार ने समकालीन दुनिया में जन युद्ध को क्रान्तिकारी कार्यसूची पर लाकर केन्द्रिय स्थान दिया।

इस सेमिनार के बाद हमारी पार्टी ने फिलिपीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी और टीकेपी/एमएल के साथ मिलकर ज्यादा तालमेल के साथ कार्य करना और दुनिया भर की सभी सच्ची माओवादी शक्तियों की बैठक आयोजित करने के प्रयास करने का फैसला किया, खास तौर से जन युद्ध का नेतृत्व करने वाली या उन्हें सक्रिय समर्थन देने वाली शक्तियों की। फिर भी हम तीन पार्टियों के बीच खास सक्रियता के साथ तालमेल अभी नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके हम तीनों दो अन्तरराष्ट्रीय जन संगठनों में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इनमें से एक जनता के जनवादी अधिकारों और जनवादी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनों की शक्तियों के समर्थन में लड़ने के लिए बनाया गया है, तो दूसरा साम्राज्यवाद के खिलाफ, खासकर दुनियाभर में अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए है।

उपरोक्त तीन अन्तरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने और द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम करने पर हम विभिन्न क्रान्तिकारी आन्दोलनों के बारे में कुछ समझदारी विकसित कर पाये हैं। जन युद्ध का नेतृत्व करने वाली कुछ माओवादी पार्टियों के बीच कुछ हद तक समान समझ और तालेमल विकसित हो सका है। विदेश के संगठनों के साथ हमारे बिरादराना रिश्तों का विकास होने पर हम अन्य देशों की क्रान्तिकारी शक्तियों तथा जनता के बीच अपने आन्दोलन के बारे में थोड़ा–बहुत प्रचार कर पाये हैं। हम अपने देश में भी अन्य देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के बारे में थोड़ा बहुत प्रचार कर पाये हैं।

'रिम' के साथ रिश्ते

विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर उसूली आधार पर हिस्सेदारी करते हुए बिरादराना रिश्ते विकसित करने के साथ–साथ हमने रिम के साथ भी बिरादराना रिश्ते विकसित

किये हैं। कामरेड माओ की मृत्यु के बाद 1976 में चीन में वहाँ के प्रतिक्रान्तिकारियों द्वारा सत्ता हथिया लेने के तत्काल बाद रिम ने संशोधनवाद के खिलाफ लड़ने और मा–ले–मा को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका अदा की। परन्तु तीसरे इण्टरनेशनल से सक लिये बगैर एक इण्टरनेशनल का निर्माण करने की सम्भावनाओं के बारे में रिम का आकलन बढ़ा–चढ़ा है। रिम जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर इण्टरनेशनल के नये भ्रूण के रूप में खुद को केन्द्र समझने की गलती कर रहा है। इस प्रकार रिम के साथ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सांगठनिक सवालों पर हमारे मतभेदों के अलावा हम आज के दौर में नये इण्टरनेशनल का निर्माण करने की अवधारणा, सम्भाव्यता और पद्धति के सवाल पर भी उससे नाइत्तेफ़ाक रखते हैं।

हमारी पार्टी का यह मानना है कि दुनिया की मौजूदा स्थितियों में जनवादी केन्द्रीयता के आधार पर नये इण्टरनेशनल का निर्माण करना अपरिपक्व तथा अव्यावहारिक कदम होगा। 1943 में तीसरे इण्टरनेशनल को भंग किये जाने के कारणों का गहरा अध्ययन तथा समीक्षा किये बिना और यह समझे बिना कि क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कामरेड माओ के नेतृत्व में नया इण्टरनेशनल नहीं बनाया, एक और इण्टरनेशनल के गठन की दिशा में बढ़ना उचित नहीं होगा। इसके अलावा हम यह मानते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय मंच के संचालन के लिए जनवादी केन्द्रीयता के उसूल पर रिम का आग्रह और इस मंच को "नये इण्टरनेशनल के भ्रूण के रूप में केन्द्र" समझना दुनियाभर की माओवादी शक्तियों के बीच एकता कायम करने में सहायक सिद्ध नहीं होगा तथा यह संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अन्तरराष्ट्रीय कार्यभार और हमारी भूमिका

आज दुनिया के माओवादियों के सामने दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और नितान्त फौरी कार्यभार हैं। इन्हीं के जरिये हमारी पार्टी को अपने अन्तरराष्ट्रवादी दायित्व का निर्वाह करने के लिए भूमिका निभानी होगी। विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच पार्टी का व्यापक ताना–बाना तैयार करके हमें इन दोनों कार्यभारों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

दुनिया की सभी सच्ची माओवादी शक्तियों के लिए पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार एक मंच पर एकत्रित होना है। यह मंच विचारधारात्मक–राजनीतिक विचारों का आदान–प्रदान कर सकत है, संशोधनवाद के सभी रूपों तथा अन्य

विजातीय विचारधाराओं का मुकाबला करते हुए मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा समाजवाद की हिफ़ाज़त करने के लिए अभियान ले सकता है, विभिन्न पार्टियों के बीच परस्पर सहायता का प्रबन्ध कर सकता है और अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के राजनीतिक एवं सांगठनिक स्तर को उन्नत करने के लिए विचारधारात्मक–राजनीतिक बहसें आयोजित कर सकता है। यह सच्ची माओवादी शक्तियों का कोर बनकर दुनियाभर की अन्य क्रान्तिकारी शक्तियों के माओवादी खेमे में ध्रुवीकरण के लिए मददगार हो सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्यभार विश्वव्यापी साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन के निर्माण में सहयोग करना, इसमें हिस्सेदारी करना और इस आन्दोलन को कारगर ढंग से आकार ग्रहण करने में मदद करने के लिए सही दिशा देना है। जब इस आन्दोलन अग्रिम पंक्ति में सुस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने वाले तथा संघर्षों को सक्रिय रूप से नेतृत्व देने वाले माओवादियों का कोर होगा तभी इस कार्यभार को पूरा करना सम्भव होगा।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की भूमिका हालांकि सीमित ही रही है, फिर भी हमने अपने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में मूलतः सही लाइन का अनुसरण किया है और उपरोक्त प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मददगार की भूमिका निभायी है। हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आन्दोलन के बारे में थोड़ा–बहुत प्रचार कर पाये हैं और सच्ची मा–ले–मा शक्तियों के साथ रिश्ते विकसित कर पाये हैं। फिर भी मुख्यतः विदेश के संगठनों के साथ तालमेल करने और विभिन्न पार्टियों की लाइनों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करने के सन्दर्भ में हमारी कुछ खामियाँ रही हैं। हमारे सामने फौरी कार्यभार विदेशों में रह रहे असंख्य भारतीयों के बीच कारगर तरीके से काम करने की शुरुआत करना है।

***

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा

सितम्बर 2004 में दो ऐतिहासिक क्रान्तिकारी धाराओं एमसीसीआई और सीपीआई (एमएल) पीडब्ल्यू के विलय के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ। भाकपा (माओवादी) के गठन के सवा दो साल बाद हम नौवीं काँग्रेस - एकता काँग्रेस आयोजित कर रहे हैं। यह क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की एक ऐतिहासिक घटना है।

इन सवा दो सालों के अन्तराल में हमारी पार्टी तथा पीएलजीए ने लोक युद्ध को नयी-नयी ऊँचाइयों तक पहुंचाया है। इससे व्यापक जन समुदाय में नयी आशाएँ और आकांक्षाएँ जागृत हुई हैं। इस प्रक्रिया में तकरीबन 700 वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी प्राणों की आहूति दे दी है। हम अपने इन प्रिय शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अन्तराल की समीक्षा करते हुए हम इन महान शहीदों के सपनों तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति

दो पार्टियों के विलय तथा भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद के इन दो वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति विश्व क्रान्ति के और भी अनुकूल हो उठी है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में संकट अधिक गहरा गया है।

विलय के समय अमरीकी साम्राज्यवाद ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान के नाम पर दुनिया के अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों, उत्पीड़ित राष्ट्रों तथा जनता के खिलाफ आक्रामक रूप से नृशंस युद्ध छेड़ रखा था। 11 सितम्बर 2001 की चिन्ता चिन्ता का विषय है। नेपाल का यह घटनाक्रम अवश्य ही भारत के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों तथा साम्राज्यवादियों के इस तरह काम आ रहा है कि वे माओवादी विचारधारा, रणनीति एवं उसके अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद पर तोहमतें लगा पा रहे हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा लिये गये मौजूदा स्टैण्ड के चलते संशोधनवादी तथा प्रतिक्रियावादी खुशियाँ मना रहे हैं और भारतीय माओवादियों से उनकी राह पर चलने का आग्रह कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि लोक युद्ध के पिछले दस सालों के दौरान असीम कुर्बानियाँ दे चुकी नेपाल की क्रान्तिकारी जनता निश्चित रूप से इन मौजूदा कठिन परिस्थितियों से उबर पायेगी।

श्रीलंका में सरकार तथा लिट्टे के बीच सन् 2002 में हुआ युद्ध–विराम सन् 2006 के मध्य तक आते–आते टूट गया। तामिल राष्ट्रीय मुक्ति योद्धाओं और राजपक्षे के नेतृत्वाधीन सिंहली अहंकारवादी शासन के बीच युद्ध फिर उमड़ पड़ा है। इस युद्ध के अधिक सघन हो जाने की सम्भावना है।

इस प्रकार समग्रता में देखें, तो दुनिया का प्रधान अन्तरविरोध यानी साम्राज्यवाद बनाम उत्पीड़ित जनता व राष्ट्रों के बीच का अन्तरविरोध और दुनिया के दूसरे सारे अन्तरविरोध दिनों–दिन अधिक तीखे होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप सारी विश्व–परिस्थिति ज्यादा–से–ज्यादा अनुकूल होती जा रही है और आत्मगत शक्तियों को, जो अभी कमजोर स्थिति में हैं, परिपक्व होने के लिए स्थितियाँ पैदा कर रही हैं।

देश की परिस्थिति

साम्राज्यवादी संकट और अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रम का हमारे देश की घरेलू परिस्थिति पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है। अपने बढ़ते अलगाव को दूर करने के लिए जुलाई 2005 में भारत–अमरीका असैनिक परमाणु समझौते पर दस्तखत और परमाणु अप्रसार सन्धि पर सदस्य देश न होने के बावजूद भारत को परमाणु रिएक्टर देने पर अपनी रज़ामन्दी के जरिये अमरीकी साम्राज्यवादी भारत पर अपना शिकंजा कसते हुए अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक (*शत्रुजीत*) में और गुप्त रूप से अन्य स्थानों पर संयुक्त सैनिक अभ्यास किये जा रहे हैं। संप्रग सरकार ऐसी नीतियों पर अमल कर रही है जो देश को अमरीकी साम्राज्यवादियों के दानवी शिकंजे में और भी मजबूती से जकड़ने की ओर धकेल रही हैं। देश की भूमि, पूंजी तथा संसाधनों को साम्राज्यवादियों के हाथों बेच देने वाली देशद्रोही संप्रग सरकार के खिलाफ समूची क्रान्तिकारी जनवादी शक्तियों के व्यापक साझे संघर्ष के लिए परिस्थिति परिपक्व हो उठी है।

सत्ता हासिल करने के बाद से संप्रग सरकार न केवल पहले की राजग सरकार के तथाकथित विकास के माडल को जारी रखे हुए है, बल्कि साम्राज्यवादियों से पूंजी, माल तथा तकनोलॉजी के भारी प्रवाह के लिए भी भारत के दरवाजे खुले रखे हुए है। वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े व्यावसायिक घरानों को विशेष आर्थिक जोन, खदान, औद्योगिक एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, सूचना प्रोद्योगिकी तथा साफ्टवेयर पार्क, मल्टीप्लेक्स, शापिंग

माल आदि की स्थापना के लिए खेती की उत्कृष्टतम जमीन सहित तमाम जमीन छीनने का मौका देती रही है। वालमार्ट–भारती साझे उद्यम के उदाहरण से जाहिर होता है कि फुटकर व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति जनता के बढ़ते विरोध को देखते हुए संप्रग सरकार ने इसे पिछले दरवाजे से अनुमति दे डाली है। इस प्रकार विकास के नाम पर इसने जनता की भारी आबादी को चरम गरीबी, भुखमरी, खुदकुशी, आवास–विहीनता, बीमारी और असुरक्षा के भँवर में धकेल दिया है। दूसरी ओर इसने दस फीसदी धनलोलुप ऊपरी तबके को अधिकाधिक छूट दे रखी है जिससे वे गरीब–गुरबा के कन्धों पर चढ़कर लाखो–करोड़ों में धन कमाने की सहूलियतें पाते हैं। यही वजह है कि आज अमीर–गरीब के बीच की खाई देश के इतिहास में पहले से कहीं अधिक बढ़ गयी है।

नतीजे के रूप में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों की इन्हीं साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित नीतियों के विरुद्ध जनता का विरोध तेज हो रहा है। विभिन्न प्रदेशों में जो भी पार्टी सत्ता में रहे, काँग्रेस हो या भाजपा, बीजू–जद या फिर सपा या भाकपा–माकपा का वाम मोर्चा, नीतियाँ वही लागू की जा रही हैं। मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक निगमों के निजीकरण, फुटकर व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मजदूरों की छँटनी और अन्य मुद्दों पर यदाकदा मिमियाने वाले संशोधनवादी संप्रग सरकार की इन नीतियों के सबसे बड़े पैरोकार बन गये हैं। पश्चिम बंगाल में जहाँ उन्हीं की तूती बोलती है, वहाँ टाटा, सलेम, बिड़ला, अम्बानी जैसे घरानों को कौढ़ियों के मोल जमीन बेचने में लगे ये सामाजिक–फासीवादी यह साबित कर रहे हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े व्यावसायिक घरानों को रिझाने में काँग्रेस तथा भाजपा को भी मात दे सकते हैं। बुद्धदेव विश्व बैंक की नीतियों को लागू करनेवाला ज्यादा भरोसेमन्द *दलाल* साबित हुआ है।

चारों ओर लोग अपने जल, जंगल, जमीन और इज्ज़त की रक्षा के खातिर सड़कों पर उतर रहे हैं और राज्य के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। पिछले दो सालों से टाटा इस्पात के खिलाफ उड़ीसा में कलिंगनगर के आदिवासियों के संघर्ष जिन्दल की बाक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ उत्तरी आन्ध्र के आदिवासियों के संघर्ष; एस्सार, टाटा एवं साम्राज्यवादी कम्पनियों द्वारा लौह अयस्क के खनन के खिलाफ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संघर्ष; टाटा, मित्तल एवं अन्य कम्पनियों द्वारा खनिज सम्पदा की लूट के खिलाफ झारखण्ड के आदिवासियों के संघर्ष; पोलवरम् परियोजना के चलते आन्ध्र प्रदेश के खम्मम एवं अन्य जिलों के आदिवासियों के संघर्ष; माकपा की दलाल सरकार द्वारा टाटा मोटर्स को दी गयी

भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सिंगूर की जनता के बहादुराना संघर्ष और कोका कोला, पेप्सी के खिलाफ संघर्षों तथा अनेक अन्य संघर्षों की गूँज देश भर में सुनायी देती रही है।

इस प्रकार बुनियादी जनता के विस्थापन का सवाल, जो जंगल से लेकर शहर तक लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है, देश के अन्दर एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। देश में विस्थापन के खिलाफ विरोध लहरों की तरह उठ खड़ा हुआ है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों को माओवादी आन्दोलन के प्रभाव से दूर करने के इरादे से 'अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी (वन अधिकार मान्यता) विधेयक' के नाम से 'वन विधेयक' लाया गया है। जिसके तहत तकरीबन एक करोड़ जंगल के निवासियों को जमीन का मालिकाना हक देने का दावा किया जा रहा है। इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य है खनिज सम्पदाओं के धनी जंगलों को साम्राज्यवादियों व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हवाले कर देना और उन पर उनका नियन्त्रण अधिक मजबूत करना। यह जनजातीय आबादी के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें भारतीय संविधान के दायरे के भीतर सीमित रखने का प्रयास भी है। कहने की जरूरत नहीं कि 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में श्रीकाकुलम के जनजातियों के विद्रोह के बाद आन्ध्र प्रदेश में लागू किये गये 1/70 अधिनियम का जो हश्र हुआ वही इसका भी होगा। अन्ततोगत्वा गैर-जनजातीय व्यक्ति ही इससे लाभान्वित होंगे। बड़े पैमाने पर आदिवासी आबादी को उसकी पारम्परिक निवास-भूमि से उजाड़ दिया जाना और उसके पारम्परिक अधिकारों का छीना जाना उपरोक्त तथाकथित सुधारों का मखौल उड़ाता है।

कुल मिलाकर अमीर-परस्त, साम्राज्यवाद-परस्त उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों ने देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संकटों को अधिक तीखा कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, विदर्भ, तेलंगाना और देश के अन्य हिस्सों में किसान आन्दोलन इन दो सालों में बढ़े हैं। मजदूर वर्ग, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ी जातियों के संघर्ष अधिक मजबूत हो उठे हैं। कई प्रदेशों में मूल्य-वृद्धि के खिलाफ संघर्ष, खेती की उपज के लाभदायक मूल्य के लिए संघर्ष, खेती में बिजली की आपूर्ति के लिए संघर्ष और ऐसे अन्य संघर्ष जुझारू होते जा रहे हैं। जनता को बाँटने के शासक वर्गों के घिनौने प्रयासों के बावजूद बढ़ते संकट के प्रतिकूल असर के चलते मजदूर वर्ग, किसान तथा समाज के अन्य उत्पीड़ित तबकों की एकता अधिक मजबूत होती जा रही है।

हजारों सालों से जातिगत उत्पीड़न तथा दमन का शिकार रहे दलितों ने अपनी मुक्ति की उम्मीद के साथ आत्म-सम्मान के संघर्ष को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के खैरलांजी गाँव में दलितों के जनसंहार और कानपुर में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने पर देश भर में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में दलितों के उफान से यही दिखायी दे रहा है।

थोड़े-से विराम के बाद राष्ट्रीयताओं के संघर्ष धीरे-धीरे जोर पकड़ रहे हैं। एनएससीएन और सरकार के बीच युद्ध-विराम अभी जारी होने के बावजूद पिछले दो सालों में कश्मीरी जनता के संघर्ष, निरंकुश 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम' के विरुद्ध मणिपुर की जनता के संघर्ष, मणिपुर में पीएलए के सशस्त्र हमले, असम में उल्फा के सशस्त्र हमले अधिक तेज हुए हैं। एनएससीएन के भारत व नागालैण्ड को महासंघ बनाने और 'महा नागालैण्ड' के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार करने से इन्कार कर देने के बाद नागालैण्ड की परिस्थिति अत्यन्त नाजुक हो उठी है। अलग प्रदेश का दर्जा दिये जाने की मांग तेलंगाना में तेजी के साथ आन्दोलन का स्वरूप ले रही है और विदर्भ में भी पुनर्जीवित होने के आसार दिखायी दे रहे हैं। लेकिन शासक वर्ग राष्ट्रीयता के आन्दोलनों के साथ कोई समझौता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि झूठे आश्वासनों के जरिये इन संघर्षों को ठण्डा किया जा सके।

उपरोक्त तमाम घटनाक्रम ने - विशेष कर बढ़ते कृषि संकट के फलस्वरूप किसानों के बढ़ते संघर्षों, बढ़ते अमरीकी हस्तक्षेप तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता की राजनीतिक गोलबन्दी की अच्छी सम्भावना, बढ़ती साम्राज्यवादी लूट के खिलाफ बढ़ते साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलनों और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के खिलाफ संघर्षों ने - और हमारी दो पार्टियों के एकीकरण तथा जन युद्ध के बढ़ते कदमों ने जनता को उत्साहित किया है और भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अनुकूल जमीन तैयार कर दी है। इसके साथ-साथ देश में तमाम बुनियादी अन्तरविरोधों के सघन और तीखे होते जाने से भारत में क्रान्तिकारी युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जमीन अधिक उर्वर हो गयी है। पूरे देश में आत्मगत शक्तियों के विकास के लिए इसने जमीन को बेहद उर्वर बना दिया है। अगर इन अवसरों का ठीक से प्रयोग किया जाय और पूरी पहलकदमी के साथ जनता की राजनीतिक गोलबन्दी की जाय, तो यह निश्चित है कि हम छापामार युद्ध को उन्नत स्तर तक पहुंचा सकेंगे और क्रान्तिकारी आन्दोलन को दूर-दूर तक फैला देंगे।

विहंगम्–दृष्टि

हमारी दो पार्टियों के विलय और एकीकृत भाकपा (माओवादी) के गठन से सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी छापामार युद्ध के सघन होने और नये–नये क्षेत्रों में छापामार युद्ध को विस्तारित करने के लिए अनुकूल जमीन तैयार हुई है। इससे पार्टी कमेटियों का अपेक्षाकृत बेहतर सुदृढ़ीकरण हुआ है, पीएलजीए की फौजी संरचनाएँ मजबूत हुई हैं, अधिक व्यापक क्षेत्रों में जन आन्दोलन का अधिक कारगर तरीके से निर्माण करने के लिए अधिक अवसर तैयार हुए हैं और क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे के निर्माण के लिए आधार तैयार हुआ है। केन्द्रीय कमेटी, क्षेत्रीय ब्यूरो और प्रादेशिक स्तर पर केन्द्रीकृत योजना के तहत आन्दोलन को अधिक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों के आन्दोलनों के बीच बेहतर तालमेल कायम करने में मदद मिली है। केन्द्रीकृत कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण की कुछ कार्रवाइयों ने पिछले दो सालों के दौरान भारतीय अवाम को उत्साहित किया है और भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर समग्रता में असर डाला है, जैसे जहानाबाद जेलब्रेक एवं बहुविध रेड, गिरिडीह रेड, मधुबन एवं आर उदयगिरी की बहुविध रेड, जन्दाहा कार्रवाई, बिहार के मुंगेर जिले में पुलिस अधीक्षक का सफाया, भाजपा प्रमुख वेंकैया नायडू के हेलिकाप्टर को जला डालने की कार्रवाई, बिहार के ही औरंगाबाद जिला अन्तर्गत खूंखार प्रतिक्रियावादी व नरपिशाच अशोक सिंह (जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिंह का रिश्तेदार भी था) सहित 6 प्रतिक्रियावादियों का सफाया, उत्तर प्रदेश के चन्दौली में पीएसी के 17 कर्मियों का सफाया, झारखण्ड के जल संसाधन मंत्री तथा खूंखार प्रतिक्रियावादी कमलेश कुमार सिंह की कुर्की–जब्ती तथा घर ध्वस्त, चतरा के बनियाडीह में बूबी ट्रैप में सीआरपीएफ के 13 कर्मियों की हत्या, सारण्डा तथा बोकारो में क्रमशः सीआरपीएफ के 12 कर्मियों तथा एसटीएफ के 14 कर्मियों का सफाया, माईन का पता लगानेवाले तीन विशेषज्ञों समेत सीआरपीएफ के 12 कर्मियों का किरिबुरू (सारण्डा) में सफाया, 1 पुलिसकर्मी का सफाया समेत झुमरा पुलिस शिविर पर संक्षिप्त औचक हमला, झारखण्ड के लातेहार में 3 पुलिसकर्मियों का सफाया समेत एरिया एम्बुश, बिहार के डुमरिया थानान्तर्गत मैगरा में विधायक राजेश पासवान का उसके 4 कारिन्दों समेत सफाया, दन्तेवाड़ा के पदेड़ा में माइनप्रूफ वाहन के विस्फोट एवं सीआरपीएफ के 24 कर्मियों का सफाया, मुरकीनार में नागा बल के 11 कर्मियों एवं 11 पुलिसकर्मियों का सफाया, एनएमडीसी में 8 का सफाया तथा दण्डकारण्य व बिहार–झारखण्ड की अन्य अनेक कार्रवाइयाँ, बेलपहाड़ी तथा लालगढ़ एम्बुश, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में तीन पुलिसकर्मियों का सफाया तथा 36 अन्य को घायल करने वाले दो बूबी ट्रैप, आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पुलिस

अधीक्षक पर हमला एवं तीनों जोनों में रेड व एम्बुश और पीएलजीए के इस तरह के बीसियों बहादुराना कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण। इसके साथ-साथ इलाकाई स्तर पर सरकारी सत्ता के ध्वस्त किये जाने व जनता की सत्ता को मजबूत किये जाने से दुश्मन के हमलों से जनता की रक्षा हुई है।

पिछले दो सालों में देश भर में हमारी पीएलजीए की कार्रवाइयों में पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों के 315 कर्मियों का सफाया हुआ है और 485 हथियार तथा 16, 000 राउण्ड गोलियाँ जब्त हुई हैं। सैकड़ों सामन्ती प्रतिक्रियावादियों, कुख्यात राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों, मुखबिरों, एसपीओ, राज्य-प्रायोजित निजी सशस्त्र गिरोहों के सदस्यों और अन्य जनविरोधी तत्वों का सफाया किया गया है। विभिन्न स्तरों पर सभी कार्यक्षेत्रों में जनता को अनेकों संघर्षों में गोलबन्द किया गया है। देश के उत्पीड़ित अवाम पर इन तमाम गतिविधियों का सकारात्मक और गहरा असर पड़ा है। वे यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में जन युद्ध ही उनके सामने एकमात्र विकल्प है। इस कारण से संयुक्त मोर्चा के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण में सार्थक विकास हुआ है।

इस अन्तराल में हमने नेतृत्व, कार्यकर्ताओं, पीएलजीए के वीर योद्धाओं, आरपीसी, जन मिलिशिया, क्रान्तिकारी जन संगठनों के सदस्यों और क्रान्तिकारी आन्दोलन के हमदर्दों के बीच से गम्भीर नुकसान भी उठाया है। आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तरी तेलंगाना में नेतृत्व के बीच से नुकसान बहुत गम्भीर रहा है, जबकि दण्डकारण्य में हमने विभिन्न क्रान्तिकारी जन संगठनों के हमारे नेताओं एवं कार्यकर्ताओं, हमारी आरपीसी तथा जन मिलिशिया की टुकड़ियों के सदस्यों और हमारे आन्दोलन से सम्बन्धित जनता के बीच से 250 से अधिक कामरेड खो दिये हैं। पश्चिम बंगाल में नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं का एक खासा बड़ा हिस्सा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार-झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर बिहार-उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड और अन्य प्रदेशों में हमारी पार्टी के अनेक नेता व कार्यकर्ता, पीएलजीए के कमाण्डर व योद्धा और जन संगठनों के कार्यकर्ता शहीद हुए या गिरफ्तार हुए हैं।

इस अन्तराल में शहादत हासिल करनेवालों में प्रमुख थे - पीबी सदस्य कामरेड शमशेर सिंह शेरी (केएस), तीन प्रादेशिक सचिवों सहित प्रादेशिक कमेटियों के 11 सदस्य : कामरेड साकेत राजन (कर्नाटक एससी सचिव); कामरेड बुर्रा चिन्नैया उर्फ माधव (एपी एससी सचिव); कामरेड मैमुद्दीन उर्फ रवि (3यू सैक सचिव); एपी एससी के कामरेड रवि कुमार (श्रीधर), समला वेंकटेशन (सुदर्शन), राघवुलू (ओबुलेसू); एओबी एसजेडसी के कामरेड गौतम; डीके एसजेडसी के कामरेड मंगतू एवं विकास; एनटी एसजेडसी के कामरेड

यादन्ना और छत्तीसगढ़ एससी के कामरेड भीम (प्राण) एवं श्रवण। हमने डीसी सदस्य भी खोये हैं। इनमें एनटी से दस कामरेड – कामरेड रमेश, बाबन्ना, सीनू, श्रीकान्त, रणजीत, गिरी रविन्द्र (सूर्यम), जगदीश, मल्लेशम, मधु, पदमा; एपी से दस कामरेड – कामरेड रवि, मोहन, सीनू, गणेश, राममोहन (नरेश), सुरेश, मुरली, क्रान्ति, मल्लिकार्जुन, प्रशान्ती; बीजे से कामरेड मंजीत; सीजी से कामरेड अजय, श्याम बिहारी, मानस; ओएस से कामरेड राजू, तूफान और डब्ल्यूबी से कामरेड नियम। हमने कई एसी सदस्य, कई पार्टी सदस्य, पीएलजीए के योद्धा और क्रान्तिकारी जन संगठनों के सदस्य खो दिये हैं। कुल मिलाकर हमने 628 कामरेड खो दिये हैं। इनमें एपी में 152, एनटी में 89, डीके में 264, एओबी में 30, बीजे में 53, महाराष्ट्र में 5, कर्नाटक में 5 कामरेड, 3यू में 3, पश्चिम बंगाल में 2, सीजी में 17, ओएस में 8 कामरेड शहीद हुए हैं। शहीदों में खासी तादाद पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ने वाली और युद्ध में असाधारण साहस व दृढ़ता का प्रदर्शन करनेवाली महिला कामरेडों की रही है।

इस अन्तराल में हमारे कई वरिष्ठ कामरेडों, एससी सदस्यों, डीसी सदस्यों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कुछ को अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुना दी है। पीबी के दो सदस्यों समेत सीसी के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। फास्ट-ट्रैक की अदालत ने तीन अन्य कामरेडों के अलावा वरूणदा को पाँच साल और तापस को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। पश्चिम बंगाल में एससी के तीन अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एपी में एससी के एक सदस्य को जेल हुई है। बीजे में सैक के दो चार सदस्य और 3यू तथा सीजी में एक-एक सैक सदस्य गिरफ्तार हुए हैं।

कई प्रदेशों तथा केन्द्रीय स्तर के नेतृत्व के इस तमाम नुकसान के बावजूद समग्रता में हमारा आन्दोलन कई मोर्चों पर आगे बढ़ा है। साथ ही, पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने और उसे मजबूत करने में हमारी गम्भीर कमजोरियाँ तथा खामियाँ अभी कायम हैं।

विलय के बाद शासक वर्ग की प्रतिक्रिया

विलय के बाद दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों के खिलाफ पहले से चला आ रहा नृशंस राजकीय आक्रमण, खास कर आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन पर यह आक्रमण नयी ऊँचाई तक पहुँच चुका है। बारीक तालमेल करते हुए किये जानेवाले ये हमले विभिन्न प्रदेशों में तेज हुए हैं। दुश्मन की समग्र बहुआयामी रणनीति तथा पिछले दो वर्षों में दुश्मन की कार्यनीति में हुए बदलाव

को समझना और हमारी जवाबी कार्यनीति एवं हमारी कार्यपद्धति में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना तथा हमारे सामने उपस्थित हो रही गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिए समूची पार्टी को दिशा देना बेहद जरूरी है। इसीलिए आइये, हम माओवादी आन्दोलन के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में दुश्मन की प्रतिक्रिया और उसके द्वारा उठाये गये कदमों को संक्षेप में समझ लें।

नवम्बर 2004 में प्रधानमन्त्री का यह वक्तव्य शासक वर्गों की प्रतिक्रिया को सार रूप में व्यक्त करता है कि माओवादी *''भारत के लिए जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्व के लड़ाकुओं से भी ज्यादा बड़ा खतरा हैं।''* राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार एमके नारायणन ने यह हल्ला मचाया कि नक्सलियों ने नेपाल से आन्ध्र प्रदेश तक एक कम्पैक्ट क्रान्तिकारी जोन तैयार का लिया है। उधर रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जी ने नक्सल विद्रोह को आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर खतरा बताया।

भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद एक महीने के भीतर अक्टूबर 2004 में अधिक कारगर ढंग से और तालमेल करते हुए नक्सल आन्दोलन से निबटने के लिए विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में नक्सलवाद पर कार्यबल गठित कर लिया गया। इस कार्यबल में नौ प्रदेशों – आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के नोडल अफसर और इण्टेलिजेन्स ब्यूरो, सीआरपीएफ तथा सशस्त्र सीमा बल के प्रतिनिधि शामिल हैं।

नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए इन प्रदेशों में अधिकांश खर्च केन्द्र सरकार दे रही है। मार्च 2005 में केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की कि 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के 'पिछड़ा जिला पहल' (बीडीआई) घटक के दायरे में नौ प्रदेशों के 55 नक्सल–प्रभावित जिले लाये जायेंगे। इसके तहत अवरचना (infrastructure) को विकसित करने के लिए तीन सालों तक प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष सौ फीसदी अनुदान के रूप में रु. 15 करोड़ की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता राशि निर्धारित किया जाता है। नक्सल आन्दोलन का अध्ययन करने और उससे निबटने के लिए तरीके खोज निकालने के लिए सेना का कोर ग्रुप तैयार किया गया है। अप्रैल 2005 में पहली बार सेना के कमाण्डरों के सम्मेलन में *''आन्ध्र प्रदेश से बिहार और नेपाल सीमा के वन क्षेत्रों तक नक्सल गलियारे में चरमपन्थ की दशा का विश्लेषण''* किया गया और इसने गृह मन्त्रालय के साथ उस सम्बन्ध में निकट सम्पर्क कायम कर लिये। प्रारम्भिक कदम के रूप में सेना ने अपने एक सेवा–निवृत्त ब्रिगेडियर और कुछेक कनिष्ठ कमीशण्ड अफसरों

(जेसीओ) को छत्तीसगढ़ में काँकेर काउण्टर-इन्सरजेन्सी एण्ड जंगल वारफेयर स्कूल में पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुमति दे दी। इसी महीने में बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए नक्सल समस्या से निबटने के लिए केन्द्रीय गृहमन्त्री शिवराज पाटिल के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों की एक सर्वोच्च कमेटी गठित की गयी। जिसका बाद में 13 प्रदेशों तक विस्तार किया गया।

सितम्बर 2005 में आयोजित अपनी पहली बैठक में मुख्यमन्त्रियों की स्थाई कमेटी ने नक्सलवाद का कारगर मुकाबला करने; नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए समयबद्ध रूप से सुरक्षा तथा विकास दोनों ही पहलुओं से कार्ययोजना तैयार करने; राजकीय पुलिस के साथ ही गुप्तचर जाल को मजबूत तथा उच्चीकृत (upgrade)करने; नक्सल-सम्बन्धी मुद्दों से निबटने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने; बीडीआई, काम के लिए अनाज कार्यक्रम तथा रोजगार गारण्टी योजनाओं के लिए दिये जा रहे धन का सम्पूर्ण तथा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने; नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में भूमिहीनों तथा गरीबों को अतिरिक्त भूमि के वितरण समेत भूमि सुधारों के कारगर अमल को उच्च प्राथमिकता देने आदि के लिए सामूहिक नजरिया अपनाने और परस्पर तालमेल से प्रतिक्रिया करते हुए अमल करने का फैसला किया। 13 प्रदेशों के मुख्यमन्त्रियों की स्थाई कमेटी ने अप्रैल 2006 की अपनी बैठक में अधिक तालमेल के साथ साझी कार्रवाइयों, एकीकृत संयुक्त कमानों, सभी नक्सल-प्रभावित प्रदेशों में ग्रेहाउण्ड किस्म के विशेष बल स्थापित व प्रशिक्षित करने, विभिन्न प्रदेशों में बेहतरीन तालमेल के साथ खुफिया तन्त्र स्थापित करने और गुप्तचर सूचनाओं का आपसी बँटवारा करने और छापामार युद्ध-विरोधी युद्ध-कौशल में विशेष प्रशिक्षण देने की योजनाएँ तैयार कर लीं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमन्त्री ने यह चेतावनी दी कि *''आन्तरिक सुरक्षा के लिए हमारे देश के सामने अब तक उपस्थित हुई चुनौतियों में नक्सलवाद ही सबसे बड़ी चुनौती है।''*

28 अप्रैल 2005 को अमरीकी साम्राज्यवादियों ने भाकपा (माओवादी) और उल्फा को 'अन्य चुनिन्दा आतंकवादी संगठनों' की सूची में रख दिया। भारतीय शासक वर्गों तथा साम्राज्यवादी गिद्धों ने खूब हो-हल्ला मचाया कि माओवादियों का प्रभाव तेजी से फैल रहा है, कि यह *''2003 में नौ प्रदेशों तथा 55 जिलों से 15 प्रदेशों तथा देश के 602 प्रशासनिक जिलों में से अन्दाजन 220 प्रशासनिक जिलों तक फैल चुका है।''* यह स्पष्ट है कि हमारी दो माओवादी पार्टियों के विलय के बाद हमारे देश के शासक वर्गों तथा साम्राज्यवादियों को माओवादी आन्दोलन का भूत सताता रहा है।

सीआरपीएफ ने अपने 2.10 लाख बल को बढ़ाकर 2.75 लाख तक पहुंचाने की योजना बना ली है। पांच प्रदेशों में सीआरपीएफ की तैनाती 23 बटालियन से बढ़ाकर 37 बटालियन कर दी गयी है। मनोरंजन के कार्यों तथा आपात स्थितियों के लिए आरक्षित रखी जाने वाली सीआरपीएफ के महानिदेशक की आरक्षित बटालियनें भी छापामार युद्ध-विरोधी कार्यों में तैनात करनी पड़ी हैं। माओवादी आन्दोलन से लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेशों में इण्डिया रिजर्व बटालियन की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने मलनाड़ क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ उसी विशेष कार्यबल को तैनात किया है जिसे पहले वीरप्पन को मार गिराने के लिए स्थापित किया गया था। आन्ध्र प्रदेश के ग्रेहाउण्ड हैदराबाद में कई प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को छापामार युद्ध-विरोधी युद्ध-कौशल में प्रशिक्षण दे चुके हैं। कुछ प्रदेशों में नक्सलवादी आन्दोलन से निबटने के लिए कानून लागू करने वाली केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संस्थाओं की एकीकृत कमान स्थापित की गयी है। मिजोरम के आइजल में स्थापित *'काउण्टर इन्सरजेन्सी एण्ड जंगल वारफेयर स्कूल'* (छापामार युद्ध-विरोधी एवं जंगल युद्ध-कौशल स्कूल) में *''छापामार से छापामार की तरह लड़ने''* के लिए विभिन्न प्रदेशों के पुलिसकर्मियों एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दिया गया है। मार्च 2005 में अमरीका के फौजी जवानों ने छापामार युद्ध-विरोधी कार्रवाई तथा जंगल युद्ध-कौशल में भारत के साथ पहला साझा इन्फेण्ट्री अभ्यास किया। नक्सल-विरोधी बल में सेवा-निवृत्त पुलिस अफसर भर्ती किये जा रहे हैं। युवाओं के बीच से बड़ी संख्या में होमगार्ड भर्ती किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में नक्सल-विरोधी कार्रवाइयों के दौरान सुरक्षा बलों को लाने-ले जाने और घायल सुरक्षा कर्मियों को हटाने के घोषित प्रयोजन के लिए वायु सेना के हेलिकाप्टरों के प्रयोग की अनुमति दे डाली है। लेकिन उसकी मंशा आवश्यकता पड़ने पर हवाई हमले छेड़ देने की है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गृह, प्रतिरक्षा तथा वित्तीय मन्त्रियों को लेकर 'सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी' (सीसीएस) गठित की गयी है। यह कमेटी थल सेनाध्यक्ष जनरल जेजे सिंह और गुप्तचर सेवाओं के प्रमुखों समेत देश के शीर्षस्थ सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ नियमित विचार-विमर्श करती है। इस प्रकार यह कमेटी माओवादी आन्दोलन और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व के आन्दोलनों पर काबू पाने के लिए बहुआयामी रणनीति लागू करने में तालमेल के साथ चलने का प्रयास करती है। सितम्बर 2006 में जनता को माओवादी प्रभाव से दूर हटाने के लिए कुछ क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सुधार लागू करने के इरादे से वित्तमन्त्री चिदम्बरम के नेतृत्व में नक्सलवाद पर 'मन्त्रियों के अधिकार-सम्पन्न समूह' (एम्पावर्ड

ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) गठित किया गया जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। केन्द्रीय गृह मन्त्रालय में विशेष 'नक्सल डेस्क' भी स्थापित किया जा चुका है। जून 2006 में नक्सल आन्दोलन से निबटने में सेना को शामिल करने के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा किया गया प्रस्ताव तात्कालिक रूप से भले ही इसलिए स्थगित रखा गया हो कि उत्तर-पूर्व, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तथा चीन के साथ देश की लम्बी सीमाओं से सेना के जवानों को हटाने में कठिनाई महसूस करनेवाला प्रतिरक्षा मन्त्रालय इसके लिए तैयार नहीं है। फिर भी केन्द्र सरकार निकट भविष्य में सेना तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसने अवरचना की स्थापना के लिए रु400 करोड़ का अनुमोदन कर मैरीन पुलिस थानों को स्थापित करने का भी फैसला किया। आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों ने इजराइल से मानवरहित वायुयान (यूएवी) तथा स्थानीय तौर पर एचएएल में तैयार किये गये 'लक्ष्य' खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है।

केन्द्र तथा प्रदेश सरकारों का सबसे घटिया हथकण्डा है पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों में सशस्त्र संघर्ष के इलाकों से स्थानीय युवाओं को भर्ती करके; गरीब आदिवासियों तथा अन्य बेरोजगार युवाओं के बीच से वेतनभोगी एसपीओ का जाल तैयार करके; आदिवासी बटालियनें तैयार करके; गाँवों को लूटने तथा जलाने, क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं तथा हमदर्दों की हत्या करने, बलात्कार तथा अन्य अत्याचारों को अंजाम देने की पुलिसिया कार्रवाइयों में आदिवासियों को साथ चलने को मजबूर करके; भाड़े के अवैध निजी सशस्त्र गिरोहों को प्रशिक्षण देकर तथा हथियारों से लैस कर आदि तरीके अपनाकर जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ खड़ा करना। उत्तर-पूर्व के जनजातीय जवानों से बनी नागा तथा मिजो बटालियनों को खास तौर पर गोण्ड आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है ताकि माओवादी क्रान्तिकारियों तथा उत्तर-पूर्व के राष्ट्रीय मुक्ति योद्धाओं के बीच एकजुटता के सम्बन्ध टूट जायें।

माओवादी आन्दोलन को कुचलने के इरादे से केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश में अपनायी जा रही अपनी नृशंस आतंककारी मुहिम के साथ-साथ सुधार की रणनीति को अन्य प्रदेशों में लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर पेश कर रहा है। जहाँ एक ओर शासक वर्गों का मुख्य जोर फौजी तरीकों से क्रूर दमन करने पर है, वहीं वे विभिन्न तरीकों से माओवादियों के खिलाफ बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ रहे हैं, जिसके तहत भूमिगत कार्यकर्ताओं के माँ-बाप के साथ विचार-विमर्श किया जाता है, माओवादियों के मजबूत गढ़ बने गाँवों को एवं नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के बच्चों को गोद लिया जाता है तथा परिवारों को आर्थिक

सहायता दी जाती है, विभिन्न तरीकों से आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रचण्ड के प्रतिस्पर्द्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र के तथाकथित सिद्धान्त को भारत के माओवादियों द्वारा अनुसरण के लिए आदर्श के रूप में प्रचारित किया जाता है और इन सभी के अलावा मुखबिरों का व्यापक तानाबाना, भितरघाती घुसपैठिये, वेतनभोगी एसपीओ का तानाबाना खड़ा करना, लातिन अमरीकी शैली में खूंखार निजी गिरोहों से काम लेना जो पुलिस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करनेवाले हर किसी को धमकी देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मार डालते हैं आदि-आदि। आन्ध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की फासीवादी सरकार यह दावा करते हुए भी कि माओवादी आन्दोलन खत्म हो चुका है, विशेष नक्सल-विरोधी ग्रेहाउण्ड बल की ताकत दुगुनी कर रही है।

पुलिस बलों तथा मुखबिरों के गिरते मनोबल में जान फूँकने के लिए आकर्षक प्रलोभन दिये जाते हैं जिनमें छत्तीसगढ़ में बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्रों के माओवादी गढ़ों में तैनात 11, 000 पुलिस कर्मियों के लिए रु.10 लाख की और एसपीओ के लिए रु.2 लाख की जीवन बीमा, माओवादियों के साथ युद्ध में मारे जानेवालों के आश्रितों को नौकरी, माओवादी हमले के चन्द घण्टों के भीतर घायल कर्मियों को हवाई जहाज से उठाये जाने, मुखबिरों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना आदि शामिल है।

भारत के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा क्रान्तिकारियों पर सर्वाधिक नृशंस युद्ध छेड़ने और झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में उनके सघन फौजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण फौरी कारण है – खनिज सम्पदा के इन धनी क्षेत्रों को काबिज कर निर्बाध ढंग से वहाँ की सम्पदा को लूटने की उनकी आवश्यकता। उपरोक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हमें पिछले दो वर्षों के हमारे कामों और हमारे नेतृत्व में चल रहे क्रान्तिकारी युद्ध की समीक्षा करनी होगी।

दुश्मन की आक्रमणकारी मुहिम को परास्त करने और जन युद्ध में अधिक से अधिक बढ़त हासिल करने के लिए सामरिक पहलू समेत उपरोक्त सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

चार प्रमुख कार्यभारों की समीक्षा

अब आइये, हम पिछले दो सालों के अपने अनुभवों का आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन करें, मूल्यवान सबक निकालने के लिए इनका संश्लेषण करें ताकि देश व दुनिया की निहायत अनुकूल परिस्थिति से पैदा होने वाले शानदार अवसरों का लाभ उठाते हुए भारतीय क्रान्ति को एक बड़ी छलांग की ओर ले जाया जा सके।

सीसी की पहली बैठक ने इन दो सालों के लिए चार मुख्य कार्यभार तय किये थे। वे इस प्रकार थे –

1. प्रधान कार्यभार था देश भर में जन युद्ध को विकसित तथा घनीभूत करना; छापामार जोनों को आधार क्षेत्रों में रूपान्तरित करने के लिए ठोस समयबद्ध योजना लेना; राजनीतिक सत्ता के निकायों तथा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे का निर्माण कर उसे मजबूत करना; जन आन्दोलन एवं जन संगठन समेत सभी गतिविधियों को केन्द्रीय कार्यभार की दिशा के अनुरूप ढालना; पार्टी, पीएलजीए तथा संयुक्त मोर्चे को मजबूत करना और मुक्त क्षेत्र कायम करने के परिप्रेक्ष्य के साथ तमाम क्षेत्रों को कदम-ब-कदम इस दिशा में विकसित करना। इसके साथ ही जहाँ संघर्ष अभी निम्न स्तर पर रहा है, उन क्षेत्रों को छापामार जोन के निर्माण के परिप्रेक्ष्य के साथ सघन तथा विस्तारित करना। इस प्रधान कार्यभार की पूर्ति के लिए सीसी ने विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटियों को निर्देश दिये कि वे अपने ठोस समयबद्ध कार्यभार सूत्रबद्ध करें और इन कार्यभारों की पूर्ति में प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान करें।

2. विभिन्न स्तरों पर विलय प्रक्रिया को पूरा करने, नयी पार्टी कमेटियों का गठन करने तथा पहले की कमेटियों को पुनर्गठित करने, दोनों छापामार सेनाओं का विलय करने तथा समूचे पीएलजीए की फौजी संरचनाओं में एकरूपता लाने, विभिन्न स्तरों पर कमीशन एवं कमान स्थापित करने और दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों के जन संगठनों का विलय करने का कार्यभार था।

3. पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों पर शिक्षा के लिए कक्षाएँ आयोजित करने, समूची पार्टी को पार्टी की विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर एकीकृत करने, दस्तावेजों पर बहस को प्रोत्साहन देने तथा पार्टी लाइन को अधिक मजबूत करने एवं अधिक उन्नत एकता हासिल करने के लिए प्रादेशिक एवं निचले स्तरों के सम्मेलन आयोजित करने और पार्टी में सभी स्तरों पर विचारों की एकता, इच्छा की एकता तथा कार्यों की एकता हासिल करने के लिए काँग्रेस सम्पन्न करने का कार्यभार था।

4. मजदूर वर्ग के बीच पार्टी का निर्माण करने तथा इसे मजबूती देने, मजदूर वर्ग के जुझारू आन्दोलन का निर्माण करने, क्रान्ति के तीसरे हथियार के रूप में संयुक्त मोर्चे के कार्य का निर्माण कर उसे मजबूती देने के लिए राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक आधार वाले जन आन्दोलन विकसित करने के कार्यभार थे।

सीसी, पीबी, सीएमसी, तमाम आरबी तथा अन्य केन्द्रीय निकायों एवं विभागों ने देश में युद्ध के विकास हेतु उपरोक्त कार्यभारों को सम्पन्न करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास किये और समय-समय पर सीसी की दूसरी बैठक में, पीबी, सीएमसी तथा तमाम आरबी की विभिन्न बैठकों में कुछ ठोस फैसले किये। पिछले दो सालों में उपरोक्त कार्यभारों पर अमल के दौरान कुछ गलत रुझान और पार्टी लाइन से भटकाव भी सामने आये जैसे कर्नाटक में अल्पमत की दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन।

पार्टी निर्माण

सभी स्तरों पर पार्टी कमेटियों का विलय और उनमें मजबूती लाना

विलय के तत्काल बाद हमने शेष क्रान्तिकारी शक्तियों को एक करने के अपने प्रयास जारी रखे, लम्बे समय तक क्रान्तिकारी आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले क्रान्तिकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को अपने पार्टी के दायरे में लाने के इरादे से उनसे सम्पर्क करने तथा चर्चा आयोजित करने की कोशिशें कीं। नवम्बर के दूसरे सप्ताह में देश भर में विलय की अहमियत को बताते हुए एक व्यापक राजनीतिक प्रचार-अभियान चलाया गया। बैठकें आयोजित की गईं, प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गयीं और व्यापक प्रचार चलाया गया। इन शक्तियों की ओर से विलय के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया रही और इनमें से कुछ ने हमारी पार्टी से जुड़ना शुरू किया।

सीसी के फैसले के मुताबिक समूची पार्टी में सभी स्तरों पर विलय प्रक्रिया पूरी करने के कार्यभार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। सभी स्तरों पर दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों की इकाइयों का विलय पूरा करने में लगभग एक साल लगा। केन्द्रीय कमेटियों के विलय के बाद कई महीनों तक हमारे तमाम आरबी और प्रदेशों/विशेष इलाकों/विशेष जोनों की नेतृत्वकारी कमेटियाँ इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम में ही लगी रहीं। प्रदेश-स्तरीय प्लेनम/विशेष बैठकें आयोजित की गयीं और दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों की पार्टी इकाइयों का विलय किया गया तथा पार्टी कमेटियों का पुनर्गठन किया गया। कई प्रदेशों में कुछ सबकमेटियों तथा विभागों के

साथ–साथ एसएमसी तथा सचिवालय भी गठित किये गये। सम्बन्धित फौजी संरचनाओं और जन संगठनों की इकाइयों का विलय किया गया। इस प्रकार पार्टी कमेटियों का विस्तार करने तथा उनमें मजबूती लाने के लिए, विभिन्न विभागों के गठन के लिए और नये–नये इलाकों की ओर पार्टी का विस्तार करने के लिए हमारे विलय से अच्छी गुंजाइश पैदा हुई।

बीजे में विलय से पहले के वर्षों में दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों के बीच गम्भीर तनाव व्याप्त रहे, फिर भी विलय प्रक्रिया बड़े उत्साह के बीच सम्पन्न हुई। दोनों पक्षों ने तहे दिल से और गहराई से आत्मालोचना की और कामरेडाना भावना के साथ समस्याओं का समाधान हो गया। बीजेबी सैक को विलय के बाद बीजे सैक के रूप में पुनर्गठित किया गया और पश्चिम बंगाल के एमबीपी क्षेत्र को बीजेबी से अलग कर डब्ल्यूबीएससी के तहत लाया गया। बीजे सैक के अन्तर्गत पड़ने वाले उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को भी अलग किया गया और सम्बन्धित प्रदेश की नेतृत्वकारी कमेटियों के तहत लाया गया। एओबी एसजेडसी के तहत पड़ने वाला बासधारा डिविजन अलग किया गया और उड़ीसा एसओसी के तहत लाया गया। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कमेटी बनायी गयी और उड़ीसा में एसओसी बनायी गयी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रदेशों की देखरेख के लिए एक नया आरबी गठित किया गया।

3यू में सैक और निचले स्तरों की कमेटियाँ पुनर्गठित की गयीं। यूके में दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों के कामरेडों के बीच पूर्वाग्रह और गलतफहमियाँ काफी गम्भीर थीं और इसके लिए मालेमा पर आधारित होकर समस्याओं की गहराई से चर्चा कर और कामरेडाना भावना के तहत आलोचना–आत्मालोचना चलाकर इसके समाधान के प्रयास किये गये।

पंजाब में विलय जल्द ही सम्पन्न हुआ। लेकिन दोनों प्रादेशिक इकाइयों के विलय से पहले आवश्यक तैयारियाँ नहीं की गयी थीं। इसके कारण राजनीतिक मतभेदों का समाधान करने में ज्यादा समय लगा। हरियाणा, दिल्ली, केरल और असम की कमेटियाँ पुनर्गठित की गयीं। केरल में कमेटी के दो सदस्यों की विध्वंसक गतिविधियों के कारण वहाँ की कमेटी जल्दी ही निष्प्रभावी हो गयी। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश प्लेनम आयोजित किया गया और एक नयी प्रादेशिक नेतृत्वकारी कमेटी चुनी गयी। बाकी प्रदेशों में पुरानी कमेटियाँ बरकरार रहीं।

कुल मिलाकर इलाकाई स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक हमारी कमेटियाँ पिछले दो वर्षों में अधिक सुदृढ़ हुई हैं। कुछ कमेटियाँ विस्तारित की गयीं और कुछ जिला कमेटियों/डिविजनल कमेटियों/जोनल कमेटियों में सचिवालय गठित किये गये। मुख्यत:

स्थानीय तौर पर भर्ती हुए कामरेडों, आदिवासियों तथा अन्य उत्पीड़ित वर्गों से अनेक नये सदस्यों को इन कमेटियों में पदोन्नत किया गया। फिर भी गम्भीर कमजोरियाँ अभी बनी हुई हैं। इसी तरह महिला कार्यकर्ताओं के विकास व उच्चतर कमेटियों में उनकी पदोन्नति के कार्य में कमजोरियाँ रही हैं। कुछ गांवों में जहाँ हमारे एक से ज्यादा पार्टी सेल रहे, वहां हमने गाँव पार्टी कमेटी भी बना दी हैं।

एकरूपता की समस्या

विलय प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बावजूद पार्टी में एकरूपता की समस्या अभी मौजूद है। अप्रैल 2006 में आयोजित पीबी की बैठक में इसके कारणों को चिह्नित किया गया। पीबी ने इसका इस प्रकार समाहार किया – *''एकीकृत पार्टी के गठन के बाद पिछले 18 महीनों में सभी स्तरों पर दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों की कतारों के बीच सम्बन्धों का सकारात्मक विकास हुआ है। कुल मिलाकर जमीनी स्तर तक समूची पार्टी में एकता की भावना व्याप्त रही है। लेकिन अभी भी एकरूपता हासिल करने में अनेक ऐतिहासिक कारणों, अवधारणागत कारणों, व्यवहार-सम्बन्धी, आचरण-सम्बन्धी और अन्य कारकों के चलते कुछ समस्याएँ मौजूद हैं।''*

पीबी ने यह बताया कि बुनियादी दस्तावेजों, अवधारणाओं, पूर्ववर्ती पार्टियों के आन्दोलनों के ऐतिहासिक विकास की सांगोपांग शिक्षा जरूरी है और वक़्त का फ़ौरी तकाज़ा है कि हम दुश्मन के लगातार बढ़ रहे चौतरफा आक्रमण को शिकस्त देने के लिए लौह मुट्ठी की तरह अपनी शक्तियों को एकजुट करें। इसके लिए एकीकृत पार्टी की समूची कतार को सभी कुछ के ऊपर पार्टी के हितों, हमारे देश की उत्पीड़ित जनता के हितों और नये वर्गविहीन समाज को कायम करने के उदात्त लक्ष्य को रखना होगा और अनुकरणीय क्रान्तिकारी आदर्श के रूप में मिसाल पेश करनी होगी।

विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन

सीसी की पहली बैठक ने बुनियादी दस्तावेजों पर समूची पार्टी कतारों की शिक्षा आयोजित करने, विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन आयोजित करने और काँग्रेस सम्पन्न करने और इस प्रकार समूची पार्टी में विचारों की एकता, इच्छा की एकता तथा कार्यों की एकता हासिल करने का तीसरा प्रमुख कार्यभार निर्धारित किया था। तदनुरूप अधिकतर प्रदेशों में पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों पर कक्षाएँ आयोजित हुईं। पांच प्रदेशों को छोड़कर सभी प्रदेशों में विभिन्न

स्तरों पर सम्मेलनों का सफल आयोजन हुआ। पांच प्रदेशों में दुश्मन के आक्रमणों की तीव्रता, हमारे पॉकेटों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन, हाल के महीनों में प्रदेश के नेतृत्व को पहुँचे नुकसानों, आरबी के भीतर समुचित तालमेल की समस्या और प्रदेश की पार्टी में उभरी सांगठनिक समस्याओं के चलते सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका।

कुछ प्रदेशों में सम्मेलन आयोजित करने के सिलसिले में इन कमियों के बावजूद कुल मिलाकर हम भारी दमन के बीच सम्मेलन की प्रक्रिया सम्पन्न करने, पार्टी में विचारों की उन्नत एकता हासिल करने और कार्यकर्ताओं को पार्टी लाइन को दृढ़ता से ग्रहण करने की शिक्षा देने में सफल रहे। राजनीतिक बहसें खुले व बेबाक ढंग से जनवादी वातावरण में आयोजित हुईं और पार्टी के दस्तावेजों को समृद्ध करने के लिए प्रतिनिधियों की ओर से खुलकर अनेक संशोधन रखे गये। इससे पार्टी की कतारों का उत्साहवर्द्धन हुआ। प्रत्येक प्रदेश के लिए रेशा-रेशा समीक्षा और कार्यों पर चर्चा के बाद ठोस फौरी कार्यभार निर्धारित किये गये।

सम्मेलन की प्रक्रिया में कुछ गम्भीर खामियाँ भी रहीं, जैसे पर्याप्त संख्या में महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने में कमी, कुछ मामलों में चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय नियुक्त न कर पाना या प्रतिनिधियों के बीच पहले से वितरण के बिना सम्मेलनों में अचानक प्रस्तुत किये गये मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देना और जन संगठनों की फ्रैक्शन कमेटियों, कुछ विभागों आदि की पार्टी इकाइयों के कामरेडों के मत तथा संशोधन नहीं लेना।

पार्टी निर्माण में कमजोरियाँ

अनेक नये कार्यकर्ताओं को पदोन्नत करके भले ही हमने अपनी पार्टी कमेटियों का विस्तार कर लिया हो, फिर भी ये कमेटियाँ अभी विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सांगठनिक रूप से कमजोर हैं। कुछ हद तक इनका सुदृढ़ीकरण हुआ है, मगर कमजोरियाँ काफी गहरी हैं। हमारी नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियों की प्रमुख कमजोरी अपनी विचारधारा को गहराई से समझने, अपने पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों के सार को, विशेष कर रणनीति तथा कार्यनीति को ग्रहण करने और अपने कार्यक्षेत्रों की ठोस स्थितियों में इन्हें लागू करने के मामले में रही हैं। इसीलिए इस विचारधारात्मक-राजनीतिक खामी के चलते हमारी नेतृत्वकारी कमेटियाँ आन्दोलन को आगे बढ़ाने और आन्दोलन को आगे बढ़ाने के दौरान आ उपस्थित होने वाली समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नेतृत्व प्रदान करने में पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं। निचली कमेटियों की ऊपरी कमेटियों पर अतिरिक्त निर्भरता है। ऊपरी कमेटियों के लिए यह

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वे निचली कमेटियों को विकसित करने के ऐसे सही तौर-तरीके अपनायें ताकि उन्हें अपनी समस्याओं का स्वतन्त्र रूप से समाधान करने में मदद मिल सके। सांगठनिक रूप से हमारी पार्टी कमेटियों में दिशा की कमी है और कुछ हद तक पार्टी सेलों का निर्माण करने तथा इन्हें स्थानीय पार्टी तथा जनता का नेतृत्व करने का प्रशिक्षण देने की क्षमता में कमी है। हमारी पार्टी और आन्दोलन का जनता के बीच व्यापक प्रभाव होने के बावजूद जन संगठन की इकाइयों, फौजी इकाइयों तथा अन्य संगठनों के निर्माण तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में भी कमजोरी दिखायी देती है। हमें इन कमेटियों की खामियों को दूर करने और सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में भी ऐसी पर्याप्त काबिल मजबूत तथा कारगर राजनीतिक कमेटियों के रूप में सुदृढ़ करने के सचेत तथा योजनाबद्ध प्रयास करने चाहिए जो स्वतन्त्र रूप से युद्ध का नेतृत्व करने के योग्य हों।

जमीनी स्तर का हमारा पार्टी संगठन अभी कमजोर है। गाँव स्तर पर हमारी पार्टी इकाइयाँ खास उल्लेखनीय नहीं हैं। कुछ प्रदेशों में हमने गाँव स्तर पर पार्टी इकाइयाँ गठित तो कर ली हैं, पर वे अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। हमें इन इकाइयों को सक्रिय करना होगा ताकि इन्हें स्थानीय स्तर पर जनता का नेतृत्व करने में सक्षम वास्तविक पार्टी नेतृत्व के रूप में रूपान्तरित किया जा सके। अनेक इलाकों में हमारी पार्टी की गतिविधियाँ अभी दस्ता-केन्द्रित ही है। इससे जनता निष्क्रिय समर्थक बन जाती है और गाँव स्तर पर संघर्ष उठाने तथा मुद्दों का समाधान ढूँढने में दस्तों पर ही निर्भर रह जाती है। हमें पार्टी इकाइयों को गाँव स्तर पर सक्रिय नेतृत्वकारी इकाइयों के रूप में ढालना होगा और हमारी समस्त गतिविधियों को इन्हीं इकाइयों के माध्यम से चलाना होगा। हमारे दस्तों तथा ऊपरी पार्टी कमेटियों को सिर्फ इनका मार्गदर्शन करना होगा और समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं उठाना होगा, क्योंकि इससे पार्टी इकाइयों की पहलकदमी मारी जाती है।

चूंकि हम अर्द्ध-सामन्ती, अर्द्ध-औपनिवेशिक समाज में पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि यहां गैर-सर्वहारा रुझान काफी मजबूत होंगे। हमारे व्यवहार में आधिपत्यवाद, नौकरशाही, अनुभववाद, तंग मानसिकता, पितृसत्ता आदि के रूप में सामन्ती विचारधारा, संस्कृति एवं विचार अक्सर प्रतिबिम्बित होते हैं। इनके अलावा निम्न पूंजीवादी व्यक्तिवाद, अहम्, अतिजनवादी रुझान, उदारतावाद, जड़सूत्रवाद, अविवेकी ज़िद, रूमानियत, ढुलमुलपन इत्यादि पूंजीवादी रुझान भी मौजूद रहते हैं। अतः पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने तथा प्रशिक्षित करने और इन कमजोरियों को दूर करने में नेतृत्व तथा नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियों की भूमिका का काफी अधिक महत्व है। उत्पीड़ित जनता के साथ एकाकार होने,

वर्ग संघर्ष में सक्रिय रूप से भागीदारी करने, मालेमा का अध्ययन करने और इन्हीं गैर–सर्वहारा रुझानों के खिलाफ सचेत तथा सतत रूप से संघर्ष करने के दौरान ही एक मजबूत सर्वहारा पार्टी उभर सकती है।

पार्टी निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमजोरियों में से एक यह है कि मजदूर वर्ग के बीच से हमारी भर्ती बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी वर्गों से कुछ भर्ती तो हो रही है, लेकिन इन्हें नेतृत्वकारी कमेटियों तक पदोन्नत करने के सम्बन्ध में हमारी कमजोरियाँ गम्भीर हैं। हमारे सामने बुनियादी वर्गों से, खास कर दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, भूमिहीन एवं गरीब किसानों तथा शहरी मजदूर वर्ग के बीच से अधिकाधिक कार्यकर्ता भर्ती करने और वर्ग संघर्ष के दौरान उन्हें सर्वहारा क्रान्तिकारी नेता के रूप में ढालने का सबसे पहला कार्यभार है।

अन्य बिरादराना पार्टियों के साथ एकता वार्ता और हमारे रिश्ते

इस अन्तराल में हमने सीपीआई(एमएल)–नक्सलबाड़ी, आरसीसीआई (मालेमा), तालमेल कमेटी, सीपीआई (एमएल)सेकेण्ड (सीसी), सीपीआई (एमएल) (न्यू लाइन) और सीपीआई (एमएल)–जनशक्ति के एक धड़े के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित कीं। सीपीआई (एमएल)–नक्सलबाड़ी ने माओवाद, छापामार आधारों आदि पर सवाल उठाये और वे रिम का अंग न रहने वाली पार्टियों के साथ एकता में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसीलिए उन्होंने एकता वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी और केवल साझी गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। हमने उन्हें अपने अनुभवों का संश्लेषण और हमारे बुनियादी दस्तावेजों पर उनकी ठोस राय लिख भेजने को कहा है। आरसीसीआई (मालेमा) ने यह बताया कि वे हमारे दस्तावेजों पर अपना दृष्टिकोण और एकता की सम्भावनाओं के विषय में अपनी राय लिख भेजेंगे। हमने सीपीआई (एमएल)–जनशक्ति के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रखे। चूंकि हम जनशक्ति को लम्बे समय से दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन पर चल रही पार्टी समझते हैं, इसीलिए हमने उनके साथ तब तक एकता वार्ता न करने का फैसला किया जब तक वे अपनी अतीत की लाइन तथा व्यवहार का आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन नहीं करते और अतीत के साथ स्पष्ट विच्छेद नहीं करते। दरअसल विलय से पहले भी दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों का यही मानना रहा है। इसीलिए हमने अपनी यह राय उन तक पहुँचायी कि उन्हें अपना पीओआर तैयार करना होगा और हमें सौंपना होगा ताकि हम उसे देखने के बाद एकता वार्ता के बारे में फैसला कर सकें। जनशक्ति के कामरेडों ने हमें आश्वस्त किया कि वे जल्द से जल्द अपना पीओआर भेजेंगे, लेकिन अभी दो वर्ष बीतने पर भी उन्होंने इसे नहीं भेजा है।

इस दरम्यान उनके संगठन को गम्भीर नुकसान उठाना पड़ा और कुछ महीने पहले उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे एकता की प्रक्रिया और भी विलम्बित हो गयी है।

कुल मिलाकर इस अन्तराल में कुछ ग्रुप हमारी पार्टी में भर्ती हुए। अभी अन्य क्रान्तिकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों के क्रान्तिकारी हिस्सों के साथ एकता की गुंजाइश बाकी है। इसीलिए सच्ची माओवादी शक्तियों को एकताबद्ध करने का कार्यभार अभी भी हमारी पार्टी के सामने मौजूद है।

सीसी की कार्यप्रणाली

एकीकृत पार्टी के गठन के बाद सीसी की केवल दो बैठकें आयोजित हुईं। पहली बैठक विलय के समय आयोजित हुई थी। यह मुख्यतः समूची पार्टी में विलय प्रक्रिया चलाने, विलय के बारे में राजनीतिक प्रचार चलाने और कुछ प्रदेशों में सांगठनिक ढाँचों में परिवर्तन करने आदि से सम्बन्धित मुद्दों पर केन्द्रित रही। इस बैठक से कुछ हद तक पूर्ववर्ती पार्टियों के सदस्यों के बीच परस्पर समझदारी विकसित करने में मदद मिली। इस बैठक की कुछ सीमाएँ रहीं क्योंकि कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हो पाये थे।

सीसी की दूसरी बैठक एक साल के अन्तराल के बाद आयोजित हुई। लेकिन दुश्मन के दमन से उपजी तकनीकी समस्याओं के चलते इसे बीच में रोक देना पड़ा। इसमें केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा बेहद जरूरी मुद्दों को लिया गया क्योंकि कम से कम समय में बैठक सम्पन्न करना जरूरी हो गया था। जेल से रिहा होने वाले एक सीसी सदस्य को कमेटी में शामिल किया गया। सीसी ने पीबी सदस्य, सीसी सदस्य तथा पश्चिम बंगाल के अनेक कामरेडों की गिरफ्तारी के कारणों की समीक्षा की, इन गिरफ्तारियों के बाद की परिस्थिति का आकलन किया और पार्टी की गम्भीर कमजोरियों तथा खामियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी किये। बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले किये गये जैसे दो प्रदेशों के लिए नये आरबी का गठन, पंजाब की कृषि में उत्पादन सम्बन्धों पर अध्ययन टीम का गठन, आगामी काँग्रेस के लिए मानदण्डों, योजना तथा दिशा-निर्देशों का निर्धारण और कुछ सांगठनिक समस्याएँ। सीसी की बैठकों के आयोजन में समस्याओं और सीसी की दोनों बैठकों के आयोजन की सीमाओं के चलते पीबी और विभिन्न आरबी ने ही इस अन्तराल में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सभी प्रदेशों को समेटने वाले पाँच आरबी के गठन से अलग-अलग प्रदेशों की परिस्थिति की सामूहिक समझदारी हासिल करने, आन्दोलन का मार्गदर्शन करने और समस्याओं का

बेहतर तरीके से समाधान करने में मदद मिली है। इनमें से चार आरबी सुचारू रूप से कार्यरत रहे, जबकि नवगठित आरबी की सम्पूर्ण बैठक से पहले ही प्रभारी पीबी सदस्य की गिरफ्तारी के कारण थोड़े ही समय में इसके सामने समस्याएँ पैदा हो गयीं। कुल मिलाकर तमाम आरबी ने सीसी की दो बैठकों के बीच के अन्तराल में अपने नेतृत्वाधीन कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित इलाकों के राजनीतिक, सांगठनिक तथा सामरिक मामलों पर फैसले किये। लेकिन अभी सामूहिक कार्यप्रणाली विकसित करने, प्रदेशों में पार्टी के भीतर या अन्य पार्टियों के साथ पार्टी लाइन से भटकाव होने की स्थिति में राजनीतिक वाद-विवाद चलाने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरत-फुरत परिपत्र भेजने और अपने तालमेल तथा सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए उचित तन्त्र कायम करने के मामले में अभी कमजोरियाँ तथा खामियाँ मौजूद हैं। तमाम आरबी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से सभी मामलों का समाधान करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, ठोस स्थितियों के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और स्थितियों के अनुरूप कार्यनीति अपनानी चाहिए। उन्हें दुश्मन के तीखे दमन के बीच भी अपने ब्यूरो को सुचारू रूप से चलाते रहने और प्रदेशों के साथ तालमेल कायम रखने के लिए फूल-प्रूफ (बिल्कुल सुरक्षित) तन्त्र कायम करना चाहिए। इस पहलू में अभी स्वतःस्फूर्तता और उदारतावाद बरकरार है।

जहाँ तक पीबी की कार्यप्रणाली का सवाल है, यह अपेक्षाकृत बेहतर रही और इस अन्तराल में पीबी की अपेक्षाकृत ज्यादा बैठकें आयोजित हुईं। लेकिन केवल दो ही बैठकों में सभी सदस्य शामिल हो पाये। कामरेड वरूण दा मई 2005 में गिरफ्तार हो गये और एक बैठक उनके बिना ही आयोजित हुई। अप्रैल 2006 में आयोजित पीबी की बैठक में दो अन्य कामरेड उपस्थित नहीं रहे। कामरेड केएस अक्टूबर 2005 के अन्त में गुजर गये और दिसम्बर 2005 के अन्त में कामरेड विजय दा गिरफ्तार हो गये। इस प्रकार विलय के एक साल के भीतर नक्सलबाड़ी के समय से ही पार्टी से जुड़े रहे तीन वरिष्ठ पीबी सदस्यों की इस अनुपस्थिति के चलते पीबी तथा सीसी की समग्र कार्यप्रणाली पर गम्भीर असर पड़ा। पीबी को जीएस तथा अन्य पीबी सदस्यों के बीच, तमाम पीबी सदस्यों के बीच और पीबी तथा आरबी के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए आवश्यक तन्त्र विकसित करना होगा।

इस अन्तराल में पीबी ने राजनीतिक-सांगठनिक मामलों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण फैसले किये, आरबी की बैठकों में उसके सदस्य उपस्थित रहे और आरबी विशेष के अधीन प्रदेशों के आन्दोलनों की समस्याओं का समाधान करने में सम्बन्धित आरबी का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, सबकमेटियों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, परिपत्र जारी

किये, *पीपुल्स वार/लाल पताका* पत्रिका के दो अंक निकाले, राजनीतिक अभियानों का आह्वान किया और विभिन्न राज्यों के आन्दोलन को समझने का सामूहिक रूप से प्रयास किया। दूसरे प्रदेशों के आन्दोलन को समझने के साथ-साथ वहाँ के प्रभारी पीबी सदस्य की सहायता करने के लिए कभी-कभी पीबी के कुछ सदस्य अन्य आरबी तथा अन्य प्रदेशों की बैठकों में उपस्थित होते रहे। इससे एक ओर सम्बन्धित आरबी और प्रदेश कमेटियों को इन पीबी सदस्यों के माध्यम से अन्य प्रदेशों के अनुभवों को समझने में मदद मिली और दूसरी ओर इन पीबी सदस्यों ने भी उन प्रदेशों के अनुभवों से सीखा। पीबी सदस्य भी अपने नेतृत्वाधीन आन्दोलनों का सीमित अनुभव रखते हैं और इसी वजह से इस तरह का मेलजोल आन्दोलन के बारे में समग्रता में पीबी की सामूहिक समझदारी विकसित करने के लिए बेहद जरूरी रहा है। खास तौर से विलय की पृष्ठभूमि में और दोनों पूर्ववर्ती पार्टियाँ जिन आन्दोलनों का नेतृत्व करती रही हैं उनके बारे में पीबी समेत पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटियों की समझदारी में कमी की पृष्ठभूमि में इससे परिस्थिति और आन्दोलन की दशा की वस्तुगत समझदारी विकसित करने में मदद मिली।

पीबी ने समूची पार्टी को राजनीतिक दिशा तथा मार्गदर्शन देने और सीसी बैठकों के बीच के अन्तराल में उपस्थित होने वाली सांगठनिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास तो किया। लेकिन समग्रता में पार्टी तथा आन्दोलन के सामने मौजूद समस्याओं और विभिन्न प्रदेशों की ठोस स्थितियों का गहराई से अध्ययन करने में खामियाँ रही हैं। विभिन्न प्रदेशों की पार्टी कमेटियों को सही व ठोस मार्गदर्शन देने के लिए इन पहलुओं में गहराई से जाना जरूरी होगा। समूची पार्टी को विचारधारात्मक तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने में भी कमी रही है। पत्रिका भी योजनानुसार समय पर नहीं आ पायी। विलय के कार्यभार, सम्मेलनों को आयोजित करने के कार्यभार जैसे कुछ कार्यभारों का कुछ हद तक कुछ प्रदेशों के आन्दोलन की समस्याओं पर पीबी का ध्यान केन्द्रित करने के मामले में असर रहा। कुल मिलाकर उपरोक्त खामियों के कारण पीबी अपनी भूमिका को कारगर तरीके से नहीं निभा सका और बदलती स्थितियों के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन नहीं दे सका।

हमारी कमजोरियों का सार-संकलन

सीसी अभी एक सामूहिक टीम के तौर पर विकसित नहीं हो पायी है। देश में पार्टी तथा जन युद्ध का कारगर तरीके से नेतृत्व करने के लिए सीसी के सदस्यों को समग्रता में पार्टी तथा आन्दोलन के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं पर अभी अपनी पकड़ कायम करना

है, अपने सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक स्तर, सांगठनिक क्षमताओं को उन्नत करना है और ठोस स्थितियों का अध्ययन करना है। सीसी के कुछ सदस्यों में अभी इस तरह की तंग सोच है कि वे खुद को समूची पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मानने के बजाय किसी खास प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। अपने खुद के अनुभव को ही निरपेक्ष या श्रेष्ठ समझने और अपने अनुभव को यान्त्रिक तरीके से दूसरों पर थोपने का प्रयास करने के रूप में अनुभववादी तथा जड़सूत्रवादी सोच भी मौजूद है। अतः इस अनुभववादी व्यवहार के साथ ही प्रान्तीयतावादी दृष्टिकोण और खानों में बाँटकर देखने के दृष्टिकोण के चलते समूची पार्टी की आवश्यकताओं के अनुरूप सामूहिक निर्णय लेने में बाधाएँ पैदा हो रही हैं। यह सबसे ज्यादा तीखे रूप से सम्बन्धित प्रदेशों/स्पेशल जोनों/स्पेशल एरियाओं में आन्दोलनों के आकलन के दौरान, कामरेडों के स्थानान्तर के दौरान, नये-नये इलाकों की ओर विस्तार आदि के दौरान दिखायी देता है।

अभी भी वास्तविक परिस्थिति के बारे में मनोगतवादी समझ और पीबी सदस्यों के प्रभार के तहत प्रदेशों की उपलब्धियों की तस्वीर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और कमजोरियों, गलतियों तथा खामियों को कम करके पेश करने की प्रवृत्ति मौजूद है। इससे आन्दोलन के बारे में वस्तुगत समझदारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। पीबी के फैसलों को सम्बन्धित पीबी सदस्य द्वारा सम्बन्धित आरबी और प्रदेशों में लागू करने के मामले में भी उदारतावाद मौजूद है। कुछ उपलब्धियों के बाद आत्ममुग्धता और दुश्मन के प्रति ढ़िलाई तथा तकनीकी उसूलों का सख्ती से पालन करने में उदारतावाद मौजूद रही है। हमें इन गैर-सर्वहारा रुझानों से उबरना होगा और परिस्थिति का वस्तुगत आकलन करने का सचेत रूप से प्रयास करना होगा, दुश्मन की और हमारी मजबूती तथा कमजोरियों को वस्तुगत रूप से समझना होगा ताकि सही कार्यनीति को तय किया जा सके। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों की कमजोरियों तथा खामियों को बरकरार रखने में और जिन नुकसानों से बचा जा सकता था उनसे बचने में हमारी असफलता में पीबी में मनोगतवाद तथा उदारतावाद की भी भूमिका रही।

केन्द्रीय प्रकाशन ब्यूरो (सीपीबी) की कार्यपद्धति

सीपीबी के काम में खुली पत्रिका निकालना और अंग्रेजी व हिन्दी में खुली कानूनी पत्रिकाओं का प्रकाशन शामिल है। पिछले दो सालों में पत्रिका का अंग्रेजी अंक पहले वर्ष के दौरान नियमित रूप से आया जबकि अगले वर्ष यह वस्तुतः द्वैमासिक के रूप में आया। अनियमितता का मुख्य कारण सम्पादक मण्डल के सदस्यों द्वारा लिखे गये लेखों का अभाव रहा। हिन्दी संस्करण का केवल एक ही अंक निकाला जा सका। यह एक गम्भीर खामी है क्योंकि विलय के बाद हिन्दी क्षेत्र में पाठक वर्ग का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इस बीच दो प्रदेशों

में पत्रिका नियमित तौर पर निकलती रही है।

इस काल में हिन्दी के तीन प्रकाशन निकले, जिनमें से दो हमारे आन्दोलन से सम्बन्धित रहे। पत्रिका का सम्पादक मण्डल सही ढंग से काम नहीं कर पाया।

किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रकाशन विभाग बेहद महत्वपूर्ण है ताकि पार्टी की राजनीतिक लाइन और इसका दृष्टिकोण व्यापकतम जनता तक ले जाया जा सके। भारत जैसे देश में केन्द्रीय प्रकाशन विभाग सभी अन्तरराष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर की घटनाओं पर हमारे दृष्टिकोण और विचारों को प्रकाशित करने की भूमिका निभा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय कमेटी इस पर ज्यादा ध्यान दे।

मात्र दो बैठकों के बाद ही ब्यूरो प्रमुख की गिरफ्तारी के चलते सीपीबी की कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई। पत्रिका की गुणवत्ता, वितरण और विषयवस्तु को सुधारने के कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये। कुल मिलाकर बैठकें तो हुईं, लेकिन अभी ब्यूरो की कार्यप्रणाली सुधारने की जरूरत है। सम्पादक मण्डल की कार्यप्रणाली भी काफी सुधारने की जरूरत है।

अन्तरराष्ट्रीय विभाग की रिपोर्ट

इस विभाग ने दो स्तरों पर कार्यभार लिये :

1. विश्व भर की अन्य सच्ची माओवादी पार्टियों के साथ तालमेल करना और इनके बीच एकता बढ़ाना।

2. साम्राज्यवाद–विरोधी अन्तरराष्ट्रीय जन संगठनों के साथ तालमेल और इनका निर्माण।

यह विभाग भी एक विभाग के रूप में सही ढंग से काम नहीं कर पाया। जहां तक अन्तरराष्ट्रीय जन संगठनों का सवाल है, यहां भी कुछ विकास हो पाया है। दो साम्राज्यवाद–विरोधी मोर्चे ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाये। लेकिन इनमें से एक कुछ हद तक हमारे सामने आ रहे मुद्दों को अन्तरराष्ट्रीय पटल पर रखने में सहायक हुआ।

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में हाल में कुछ माओवादी पार्टियों के साथ और विशेष तौर पर रिम के घटक पार्टियों के साथ सम्बन्धों में सुधार में कुछ विकास हुआ है। चूंकि माओवादी आन्दोलन कमजोर स्थिति में है, इसलिए इस क्षेत्र में काम धीमी गति से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस क्षेत्र में हम अपनी सर्वहारा अन्तरराष्ट्रवादी भूमिका निभाते रहे।

गैर-सर्वहारा रुझान

विलय से पहले दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों में मौजूद रहने वाले कुछ गैर-सर्वहारा रुझान नयी पार्टी में भी बरकरार रहे। विलय से पहले विभिन्न प्रदेशों में चलाये गये शुद्धिकरण अभियानों का कुछ सकारात्मक असर रहा। परन्तु हमारी एकीकृत पार्टी के उच्चतम निकायों समेत विभिन्न पार्टी कमेटियों में विभिन्न रूपों में मनोगतवाद, स्वत:स्फूर्तता, उदारतावाद, संकीर्णता, व्यक्तिवाद तथा नौकरशाही दिखायी देती हैं। मनोगतवाद दुश्मन के हमले के स्वरूप एवं पैमाने का आकलन तथा तदनुरूप हमारे तौर-तरीकों एवं कार्यशैली को बदलने, दुश्मन की कार्यनीति का अध्ययन करने, विभिन्न क्षेत्रों में ठोस स्थितियों का अध्ययन करने और उन स्थितियों के अनुरूप संघर्ष के रूप तथा संगठन के रूप अपनाने, विशिष्ट स्थितियों का ख्याल किये बिना कार्यनीति का यान्त्रिक अमल करने आदि-आदि के रूप में दिखायी देता है। परिणामस्वरूप चूंकि हम एसओजी के हमले के तीखेपन का आकलन नहीं कर पाये, इसीलिए एकीकृत पार्टी के गठन के बाद मात्र 9 महीनों में 2 सीसी सदस्यों समेत पश्चिम बंगाल में हमें गम्भीर नुकसान का सामना करना पड़ा। पिछले दो सालों के दौरान दुश्मन की तथा हमारी स्थिति का आकलन करने में और समय पर अपनी शक्तियों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए पीछे हटने की सही कार्यनीति तथा उपाय अपनाने और तेजी से बदलती स्थितियों के अनुरूप संघर्ष के समुचित रूपों तथा संगठन के रूपों का ईजाद करने के मामले में हमारे मनोगतवाद के कारण आन्ध्र प्रदेश में हमें गम्भीर नुकसान उठाना पड़ा। एक पीबी सदस्य समेत अनेक कामरेड इसीलिए गिरफ्तार हुए कि जब दुश्मन अपने तौर-तरीके व कार्यनीति गुणात्मक रूप से बदल चुका था तो भी हमने अपनी पुरानी कार्यप्रणाली नहीं बदली। बीजे में चार सैक सदस्यों और एक सीसी सदस्य समेत अनेक कामरेड गिरफ्तार हुए। 3यू में एक सीसी सदस्य गिरफ्तार हुए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी इसी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

दैनंदिन योजना, कार्यशैली तथा तौर-तरीकों और केन्द्रीय कार्यभार को प्राथमिकता न देकर एक काम के बाद दूसरा काम यूँ ही करते जाने के रूप में विभिन्न पार्टी कमेटियों की कार्यप्रणाली में स्वत:स्फूर्तता दिखायी देती है। कार्यप्रणाली में स्वत:स्फूर्तता और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभारों पर सारा ध्यान केन्द्रित करने में कमी के लिए सीसी/पीबी/विभिन्न आरबी तथा सीसी सदस्य विशेष की ओर से समुचित योजनाबद्धता में कमी, निर्णय प्रक्रिया में तदर्थवाद और कमेटियों तथा सदस्य विशेष को तरह-तरह के अनेक काम सौंपना मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण रहे हैं। कमेटियों के लिए समुचित तन्त्र का अभाव भी स्वत:स्फूर्त

कार्यशैली में योगदान देता रहा है।

सीसी तथा विभिन्न पार्टी कमेटियों में उदारतावाद सही समय पर फैसला करने में, लिये गये फैसलों को दृढ़ता से लागू करने में, अपनी सोच तथा कार्यपद्धति को न बदलने में, अर्थात् कमेटियों तथा सदस्यों को परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप न ढालने, दुश्मन के हमलों का शिकार हो सकने वाले कामरेडों को अन्यत्र स्थानान्तरित न करने, मुखबिरों की गद्दारी और परिस्थिति की गम्भीरता का आकलन करने में ढीला-ढाला रवैया अपनाने के रूप में और गलत रुझानों को सही समय पर दुरुस्त करने के मामले में, कमेटियों तथा सदस्यों में गलत रुझानों तथा भटकावों की आलोचना करने के मामले में, अपनी खुद की कमजोरियों तथा खामियों की आत्मालोचना करने के मामले में, अभिलेखों (रिकार्डों) को सर्वाधिक गोपनीयता से रखने के मामले में, सही हिसाब-किताब रखने के मामले में, खर्चे घटाने और आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करने आदि के मामले में दिखायी देता है। नेतृत्व की ओर से उदारतावाद के चलते इस अन्तराल में कई गम्भीर नुकसान उठाने पड़े हैं।

कमेटी संचालन में नौकरशाही स्पष्ट रूप से दिखती है। यह निम्नलिखित रूपों में प्रतिबिम्बित होती है:- अपनी राय दूसरों पर थोपना, दूसरों के विचार न सुनना, कतारों पर ध्यान न देना, उनके साथ कर्मचारी या अधीनस्थ के रूप में व्यवहार करना, उनमें व उनके काम में हमेशा गलती ढूँढना और उनके प्रति नकारात्मक रुख रखना आदि।

संगठन के क्षेत्र में संकीर्णतावाद साफ दिखायी देता है। यह निम्नलिखित रूपों में प्रकट होता है:- जो आपका विरोध करते हैं उनसे एकताबद्ध न होना, जनता की कतारों पर भरोसा न कर सिर्फ उन चन्द लोगों पर भरोसा करना जो आपसे सहमत रहते हैं, जो आपका विरोध करते हैं उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि। यह संकीर्णतावाद सामूहिक एकता को बाधित करता है, साथ ही जनता से हमारे सम्बन्ध को कमजोर करता है। इस तरह यह नेतृत्व को कतार से और पार्टी को जनता से अलग कर देता है। इस रवैये की वजह से हमें नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े हैं।

हमारे संगठन में व्यक्तिवाद भी कई रूपों में प्रतिबिम्बित होता है। जैसे:- आत्मकेन्द्रित सोच से प्रस्थान करना, कमेटी पर अपनी राय थोपने का प्रयास करना और जब ऐसा सम्भव नहीं होता तो चिढ़ जाना, डींग हांकना, हमेशा आत्ममुग्धता व आत्म-प्रशंसा से बात करना, जो आपसे सहमत न हों उनके प्रति वैरपूर्ण व प्रतिशोधात्मक भाव रखना, अपने लिए हमेशा विशेष रिआयत की मांग करना, किसी कमेटी व पद्धति के अनुसार काम न करना, दूसरों पर अनुशासन थोपना व खुद किसी भी अनुशासन से ऊपर रहना इत्यादि। यह प्रवृत्ति संगठन के

अन्दर सामूहिक पहलकदमी को विकसित करने व पूरी पार्टी में सोच व कार्य की एकता को विकसित करने में एक बाधा है।

पीबी ने समूची पार्टी को राजनीतिक दिशा तथा मार्गदर्शन देने और सीसी बैठकों के बीच के अन्तराल में उपस्थित होने वाली सांगठनिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास तो किया। लेकिन समग्रता में पार्टी तथा आन्दोलन के सामने मौजूद समस्याओं और विभिन्न प्रदेशों की ठोस स्थितियों का गहराई से अध्ययन करने में खामियाँ रही हैं। विभिन्न प्रदेशों की पार्टी कमेटियों को सही व ठोस मार्गदर्शन देने के लिए इन पहलुओं में गहराई से जाना जरूरी होगा। समूची पार्टी को विचारधारात्मक तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने में भी कमी रही है। पत्रिका भी योजनानुसार समय पर नहीं निकल पायी। विलय के कार्यभार, सम्मेलनों को आयोजित करने के कार्यभार जैसे कुछ कार्यभारों का कुछ हद तक कुछ प्रदेशों के आन्दोलन की समस्याओं पर पीबी का ध्यान केन्द्रित करने के मामले में असर रहा। कुल मिलाकर उपरोक्त खामियों के कारण पीबी अपनी भूमिका को कारगर तरीके से नहीं निभा सका और कुछ आरबी तथा प्रदेश कमेटियों में बदलती स्थितियों के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन नहीं दे सका।

हम दुश्मन की आक्रमणकारी मुहिम को तभी परास्त कर सकेंगे, अपने नेतृत्व को तभी सुरक्षित रख सकेंगे और आन्दोलन को तभी अगली उन्नत मंजिल तक आगे बढ़ा सकेंगे जब हम इन कमजोरियों तथा गलत रुझानों को दुरुस्त कर लेंगे। समूची पार्टी में इन रुझानों को दूर करने के लिए शुद्धिकरण अभियान लिया जाना चाहिए और शुद्धिकरण की प्रक्रिया सतत रूप से चलायी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के रुझान अलग-अलग रूपों में फिर से उभर सकते हैं।

सैनिक मोर्चा

भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद सीसी (अस्थाई) तथा सीएमसी की पहली बैठक में विभिन्न स्तरों पर कमीशन तथा कमान गठित करने और समूची पीएलजीए के मुख्य, द्वितीय तथा आधारभूत बलों की संरचनाओं में एकरूपता लाने का फैसला किया गया। तदनुरूप पीएलजीए की शक्तियों के एकीकरण के प्रक्रिया शुरू हुई और अधिकतर प्रदेशों में बहुत हद तक पीएलजीए की संरचना का पुनर्गठन सम्पन्न हुआ। प्रदेश/स्पेशल एरिया/स्पेशल जोन और क्षेत्रीय (बीजे में) स्तरों पर कमीशन गठित किये गये। जोनल/जिला/डिविजनल और सबजोनल स्तरों पर कमानों का गठन किया गया। कुछ इलाकों

में इलाकाई कमान गठित करने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। लेकिन ये अभी केवल कुछ ही इलाकों में सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं। इन कमानों को मजबूत करने और उन्हें कारगर रूप से कार्य करने लायक बनाने की निहायत फौरी जरूरत है।

युद्ध के क्षेत्र को सघन बनाना तथा विस्तारित करना

छापामार युद्ध को सघन तथा विस्तारित करने, पीएलजीए को पीएलए में, छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में तथा छापामार जोनों को आधार इलाकों में रूपान्तरित करने के प्रधान कार्यभार के अन्तर्गत सीएमसी ने कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान (टीसीओसी), पीएलजीए में भर्ती अभियान, पीएलजीए सप्ताह आदि के रूप में राजनीतिक-सामरिक अभियान चलाये।

उपरोक्त प्रधान कार्यभार की पूर्ति के रूप में हमने प्रत्याक्रमण की कुछ ऐसी बहादुराना कार्रवाइयाँ संचालित कीं जिनसे भारतीय जनता में उत्साह का संचार हुआ और दुश्मन की रूह काँप उठी। इनमें कुछ कार्रवाइयाँ ऐतिहासिक रहीं, जैसे - चन्दौली, मधुबन, गिरिडीह, जहानाबाद, उदयगिरी, बनियाडीह, विंजारम, पदेड़ा, मुरकीनार, कोतचेरुवु, एनएमडीसी, बोकारो इत्यादि।

पिछले दो वर्षों में हमारी पीएलजीए ने 130 छोटी और बड़ी कार्रवाइयाँ संचालित कीं, 315 पुलिस कर्मियों का सफाया किया, 485 हथियार जब्त किये, सैकड़ों कर्मियों को घायल किया। सैकड़ों प्रतिक्रियावादियों, पुलिस के दलालों, राजनेताओं इत्यादि को सजा दी गयी।

हम डीके तथा बीजे में जन युद्ध को सघन बनाने में सफल हुए। पिछले 25 सालों से और विशेष कर पिछले एक साल से चलाया जा रहा दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड का हमारा छापामार युद्ध आगे बढ़ा है। लामबन्दी के केन्द्र के रूप में काम कर रहे प्लाटूनों और कम्पनियों के रूप में केन्द्रीकृत हमारे सशस्त्र बल बड़ी केन्द्रीकृत कार्रवाइयों को संचालित करते हैं, जबकि हमारी विकेन्द्रीकृत टुकड़ियाँ छोटी तथा मध्यम स्तर की कार्रवाइयों को अंजाम देती हैं। लामबन्दी की अपनी अधिक उन्नत क्षमताओं के चलते हम दुश्मन को घण्टों तक रोक पाने में कामयाब हो पाये हैं, बहुत कम दिनों के अन्तराल पर कार्रवाइयाँ कर पाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीकृत सशस्त्र बलों की तैनाती करते हुए और उन्हें समन्वित करते हुए हम इन बलों को केन्द्रीकृत करके बड़ी कार्रवाइयों तथा हमलों को अंजाम दे पाते हैं। मिलिशिया का व्यापक तौर पर गठन और पुलिस के खिलाफ प्रतिरोध कार्रवाइयों में

वीरतापूर्ण भागीदारी – दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड में प्राप्त हो रहे इन सभी उन्नत स्तर के अनुभवों से छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करने का आधार तैयार हुआ है।

हम छापामार युद्ध का नये क्षत्रों तक विस्तार भी कर पाये हैं। हम छह प्रदेशों में अपनी छापामार गतिविधियों में कुछ प्रगति हासिल कर पाये। कुछ अन्य प्रदेशों में पीएलजीए की इकाइयाँ गठित हुई हैं। हमारे सीसी के निर्णय के अनुरूप आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना तथा आन्ध्र-उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में हमने युद्ध को तेज करने का प्रयास किया। परन्तु आन्ध्र प्रदेश और उत्तरी तेलंगाना में दुश्मन के नृशंस आक्रमण, खास कर नवम्बर 2005 से दुश्मन के सुसंयोजित कार्ययोजना के दौरान और अमल में हमारी खामियों के कारण गम्भीर नुकसान उठाने के चलते हम असफल रहे।

दुश्मन के बलों को ध्वस्त करने तथा हथियार जब्त करने की अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए हमारी पीएलजीए ने दुश्मन के प्रचण्ड हमलों से राजनीतिक सत्ता के निकायों की रक्षा, नेतृत्व की रक्षा तथा अध्ययन शिविर, प्रशिक्षण शिविर, पार्टी कमेटियों की बैठकें संचालित करने, अपनी पार्टी की अन्य गतिविधियों में सहायता करने आदि के रूप में हमारे रणनीतिक कार्यभारों को लागू करने में सक्रिय भूमिका अदा की। पीएलजीए की सजगता और उसका साहसी प्रतिरोध नहीं होता, तो हमारी पार्टी अपनी गतिविधियों को सफल रूप से संचालित नहीं कर पायी होती। पीएलजीए ने कुछ इलाकों में जनता को उत्पादन में गोलबन्द करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में खुद भी हिस्सा लिया।

इस अन्तराल में हमने छापामार युद्ध को सघन तथा विस्तारित करने के अपने प्रयासों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के तीनों जोनों में युद्ध को टिकाये रखने की विकट समस्या का सामना भी किया। हमारी शक्तियों को पहुँचे नुकसान के मामले में एओबी में परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर तो है, पर यह कहा जा सकता है कि तीनों जोनों में ही हमारा प्रतिरोध समग्रता में कमजोर रहा है। छोटी-छोटी छापामार इकाइयों के जरिये विभिन्न किस्म की योजनाबद्ध कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए और बदलती परिस्थिति के अनुरूप हमारे छापामार बलों की संरचनाओं को अक्सर बदलते रहने का लचीलापन अपनाते हुए, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा प्रेरणा के जरिये अपने बलों को ढालते हुए और इन सभी में नेतृत्व के प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हुए अपने बलों के एक हिस्से को पीछे हटाने की योजना बनाने के बजाय छापामार युद्ध को तेज करने पर हमारा एकांगी जोर; विशेष पुलिस बलों के भारी संकेन्द्रण का सामना करने पर हमारी पीएलजीए के बलों की दाँवपेंच संचालित करने की क्षमता

बढ़ाने के लिए सशस्त्र संघर्ष के इलाके का विस्तार करने में विफलता; मैदानी इलाकों के लिए गुप्त कार्यपद्धति तथा कार्यशैली ईजाद करने में विफलता और अनेक गम्भीर तकनीकी गलतियाँ; और सर्वाधिक महत्वपूर्ण – भारी दमन के बीच जनता के साथ नियमित रूप से सजीव सम्बन्ध कायम रखने और हमारे जनाधार को मजबूत करने में हमारी असफलता आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तरी तेलंगाना में गम्भीर नुकसान के मुख्य कारण रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष के क्षेत्रों में दुश्मन मुखबिरों तथा एसपीओ के व्यापक तानेबाने का निर्माण कर पाया, हमारे दस्तों के आवागमन की सटीक सूचनाएँ हासिल कर पाया। जबकि गुप्तचर सूचनाएँ एकत्रित करने के मामले में हम काफी कमजोर रहे।

उत्तरी बिहार में मधुबन बहुविध रेड, डीके में दौला रेड, डुमरिया रेड आदि कुछ कार्रवाइयों में गम्भीर कमजोरियाँ रहीं। जहानाबाद जेलब्रेक जैसी कुछ सफल आक्रमणकारी मुहिमों के दौरान भी राजनीतिक–सामरिक कमजोरियाँ देखी गयीं। इन रेडों, एम्बुशों, मुठभेड़ों तथा प्रत्याक्रमण की अन्य कार्रवाइयों से सबक लेना निहायत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचा जा सके और बड़ी से बड़ी आक्रमणकारी मुहिमें संचालित की जा सकें।

पिछले दो सालों से हमने देशभर में छापामार युद्ध को सघन बनाया और विस्तारित किया है। इस प्रक्रिया में हमने स्थानीय स्तर पर दुश्मन की सत्ता को नष्ट किया है और जनता की सत्ता के निकायों को कायम किया है। खास तौर पर डीके में इलाकाई स्तर के सत्ता के निकायों (एआरपीसी) का निर्माण हो चुका है और इन्हें मजबूत किया जा चुका है। इस आधार पर हम उन्नत स्तर के सत्ता के निकायों और छापामार आधार–क्षेत्रों का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इलाकाई स्तर पर इस नयी सत्ता की हिफ़ाज़त करते हुए हम छापामार युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं और चलायमान युद्ध में इसका रूपान्तर कर रहे हैं ताकि आधार क्षेत्रों की स्थापना की जा सके।

सीएमसी, एसएमसी तथा कमानों की कार्यप्रणाली

इस अन्तराल में सीएमसी ने देशभर में जन युद्ध को सघन तथा विस्तारित करने के प्रधान कार्यभार के अमल पर ध्यान केन्द्रित किया। इसने उच्च स्तर की सैनिक संरचनाओं का गठन करने और छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध की मंजिल तक उन्नत करने के इरादे से पीएलजीए की मजबूती तथा गुणवत्ता बढ़ाने के कार्यभार पर विशेष ध्यान दिया। इसने पीएलजीए को पीएलए में रूपान्तरित करने के मकसद से भर्ती अभियान चलाये,

पीएलजीए के बलों के लिए कुछ प्रशिक्षण शिविर चलाये और जन मिलिशिया की टुकड़ियों को गठित करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये। इसने पीएलजीए को हथियारों से लैस करने और हथियारों को उच्चीकृत करने, यानी पीएलजीए की समग्र लड़ाकू क्षमता को उन्नत करने का प्रयास किया। इसने दुश्मन की किलेबन्दी को तोड़ने, एमपीवी को ध्वस्त करने, एम्बुशों के जरिए दुश्मन के बलों को ध्वस्त करने आदि के अध्ययन का कार्य करने का प्रयास किया। लेकिन यह नाकाफी रहा। साथ ही आन्ध्र प्रदेश में दुश्मन द्वारा लागू की जा रही एलआईसी की कार्यनीति का हमने गम्भीरता के साथ अध्ययन नहीं किया और उसके मद्देनजर जवाबी कार्यनीति का निर्धारण करने में भी हमारी कमजोरी रही। इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बेहद फौरी जरूरत बनी हुई है क्योंकि इसके बिना हमारे युद्ध को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। सीएमसी ने दुश्मन के नृशंस आक्रमण को परास्त करने के लिए फौजी कार्यनीति ईजाद करने का पूरा प्रयास किया, विभिन्न टीसीओसी तथा बड़ी-बड़ी फौजी कार्रवाइयों में पीएलजीए का तालमेल बैठाया तथा प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। इसने फौजी प्रशिक्षण शिविरों तथा कक्षाओं के आयोजन और दो भाषाओं में *अवामी जंग* (जिसके तीन अंक निकल चुके हैं) तथा अन्य फौजी साहित्य प्रकाशित कर पीएलजीए का समग्र राजनीतिक-सामरिक स्तर उन्नत करने पर ध्यान केन्द्रित करने का भी प्रयास किया। एक प्रशिक्षकों के लिए और दूसरा प्रशिक्षकों तथा कुछ प्लाटून कमाण्डरों के लिए – इस प्रकार दो फौजी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये। प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों के पीएलजीए सदस्यों के लिए भी आयोजित किया गया। पीएलजीए के बलों को प्रशिक्षण देने वाली एक केन्द्रीय प्रशिक्षक टीम स्थापित की गयी। चलायमान सैनिक स्कूल की अवधारणा देना अभी शुरू किया गया है और कुछ क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण देने के मकसद से इसका गठन भी हुआ है। स्थानीय स्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण के इस पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

कमीशनों को सभी फौजी गतिविधियों को निर्देशित करने वाले सामूहिक निकाय के रूप में अभी विकसित नहीं किया जा सका है। फौजी मामलों में कमीशनों की विशेषज्ञता अभी नाकाफी है और युद्ध से सम्बन्धित मामलों में विशेषज्ञता पर, खास कर ठोस जमीनी अध्ययन पर आधारित दुश्मन की कार्यनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत बनी हुई है। दुश्मन की कमजोरियों का अध्ययन करने के प्रयास किये गये हैं। मगर विभिन्न प्रदेशों में दुश्मन का फौजी मुकाबला करने के मामले में पीएलजीए के अनुभवों का अभी इस प्रकार सर्वांगीण रूप से सार-संकलन नहीं किया जा सका है कि इनसे सही सबक निकाले

जा सकें। युद्ध के क्षेत्र के अनुभवों का इस प्रकार संश्लेषण किये जाने और एक प्रदेश से प्राप्त ज्ञान को दूसरे प्रदेश तक पहुँचाये जाने पर युद्ध को आगे बढ़ाने और गलतियों को अन्यत्र दोहराने से बचने में बड़ी मदद हो सकती है। कमीशनों को पीएलजीए की तीनों शाखाओं के बीच कारगर ढंग से तालमेल करने की कुशलता सीख लेनी होगी। इन्हें युद्ध की रफ्तार को कायम रखने में सक्षम होना होगा और मात्र कभी-कभी की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों तक सीमित नहीं रहना होगा। प्रत्येक टीसीओसी और बड़ी फौजी कार्रवाई के बाद इन्हें अपनी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना होगा और आगे की योजना बनानी होगी। इन्हें दुश्मन को किसी न किसी तरीके से लगातार उलझाये रखने के लिए पीएलजीए तथा मिलिशिया को प्रशिक्षण देना होगा।

सैनिक मोर्चे पर कमजोरियाँ तथा खामियाँ

युद्ध के संचालन में और सैनिक मोर्चे पर समग्रता में अनेक कमजोरियाँ मौजूद हैं। प्रथम यह कि हमारा प्रशिक्षण अभी दुश्मन की कार्यनीति का मुकाबला करने की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। दुश्मन ने छापामार जोनों, जीबी क्षेत्रों तथा सशस्त्र संघर्ष के अन्य इलाकों में समस्त पुलिस थानों की किलेबन्दी कर रखी है, वह अपनी आवाजाही को गुप्त रूप में तथा चुस्ती-फुर्ती से चला रहा है और उसके बलों के बीच तालमेल बेहतर है तथा विलय से पहले के समय की तुलना में काफी अधिक बेहतर हुआ है। दुश्मन सटीक सूचनाओं के आधार पर औचक हमलों (नतचतपेम ंजजंबा) का सहारा ले रहा है। लेकिन हमारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं से काफी कम बना हुआ है।

हमें अपने बलों को दुश्मन की किलेबन्दी तोड़ने, मौका पाकर तथा जानबुझकर किये गये एम्बुशों के जरिये बड़ी संख्या में दुश्मन का सफाया करने, सृजनात्मक तरीकों से बिछाये गये बूबी ट्रैप्स के जरिये दुश्मन को लुभाने का प्रशिक्षण देना होगा। हमें दुश्मन पर हावी होने और अचानक हमला करने के लिए फायर और मूवमेण्ट तकनीक का प्रयोग करना होगा। हमारे कमाण्डरों को कठिन स्थितियों का विश्लेषण करने और सृजनात्मक तौर-तरीकों का प्रयोग कर दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की क्षमता अर्जित करने के लिए आवश्यक उन्नत राजनीतिक स्तर तक विकास करना होगा। पीएलजीए के सदस्यों की युद्ध-कुशलता को उन्नत करना होगा। हम युद्ध के जरिये ही युद्ध की कला सीख सकते हैं। हम युद्ध के संचालन में काफी अनुभव हासिल कर चुके हैं। अब हमारा सबसे पहला कार्यभार है तीन दशकों से भी ज्यादा सशस्त्र संघर्ष के जरिए फौजी मोर्चे पर हासिल किये गये इन्हीं अनुभव का संश्लेषण करना और प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट स्थितियों,

हमारी आत्मगत शक्तियों की मजबूती तथा दुश्मन की आक्रामक मुहिम के स्वरूप एवं पैमाने के अनुरूप उसका मुकाबला करने की समुचित कार्यनीति तथा तौर-तरीके ईजाद करना।

विशिष्ट इलाकों में दुश्मन की आक्रामक मुहिम की विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएँ होती हैं। हमें इनका अध्ययन करना होगा और तदनुरूप अपने प्रत्याक्रमण तथा कार्यनीति का ईजाद करना होगा।

कारगर प्रतिरोध खड़ा करने और दुश्मन के बलों को गम्भीर नुकसान पहुँचाने की राह में हमारी एक अन्य गम्भीर खामी हमारे कमजोर आधारभूत बल हैं। युद्ध में मजबूत जन मिलिशिया तथा सुदृढ़ ताकत और जन भागीदारी के बिना मुख्य तथा द्वितीय बलों को मजबूत करना और दुश्मन पर अहम् जीतें हासिल करना सम्भव नहीं है। चीन तथा वियतनाम के अनुभवों से हमें मार्गदर्शन लेना होगा। डीके में गाँव स्तर पर अधिक मजबूत मिलिशिया की टुकड़ियों और जन मिलिशिया दस्तों की इकाइयों के कारण ही हम अपेक्षाकृत अच्छे नतीजे हासिल कर पाये हैं। हम डीके में मिलिशिया प्लाटून गठित करने में भी कामयाब हुए हैं। इन मिलिशिया टुकड़ियों में हजारों की तादाद में जनता संगठित की जा चुकी है। वहाँ की जनता मुख्य तथा द्वितीय बलों के साथ तालमेल करते हुए टीसीओसी में सक्रियता से भाग ले रही है। वह लगातार दुश्मन का प्रतिरोध कर रही है और उसे बेहाल कर रही है। जिन प्रदेशों में मिलिशिया की टुकड़ियों का कोई व्यापक तानाबाना नहीं है वहाँ हमारे प्रतिरोध में गम्भीर सीमाएँ मौजूद हैं। इसके अलावा जहाँ भी मिलिशिया की टुकड़ियाँ मौजूद हैं वहाँ हम तेज रफ्तार के साथ मुख्य तथा द्वितीय बलों का विस्तार कर पाये हैं, जैसा कि डीके में। लेकिन अन्य क्षेत्रों में हमारे बल चींटी की चाल से बढ़ रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम केवल मुख्य बलों के ही सहारे युद्ध को नहीं जीत सकते। जन मिलिशिया दुश्मन को बढ़ने से रोकने के लिए कदम-ब-कदम अवरोध खड़ा करते हुए उसे बेहाल करने और रोकने में चमत्कार कर सकती है।

आधुनिक युद्ध में मानव की सृजनात्मकता के अलावा उच्च तकनोलॉजी और आधुनिक हथियार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि हम दुश्मन के उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण के स्तर तक कभी नहीं पहुँच पायेंगे, फिर भी अपने हथियारों व लड़ाकू क्षमता के लगातार आधुनिकीकरण के पहलू की हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे प्रयास अभी नाकाफी हैं। हम अभी अपने सभी योद्धाओं को न्यूनतम हथियारों से भी लैस नहीं कर पाये हैं और हमारी अनेक फौजी संरचनाओं में अस्त्र-शस्त्र का बेहद

गम्भीर अभाव है। डीके में जहाँ पीएलजीए में भर्ती के मामले में उल्लेखनीय बढ़त हासिल हुई है और मिलिशिया की टुकड़ियों की संख्या अधिक है, वहाँ हम इन तमाम शक्तियों को हथियारों से लैस नहीं कर पाये हैं। इसका व्यापक पैमाने पर युद्ध का संचालन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बीजे में भी हमारे पीएलजीए के बलों के पास हथियारों का बड़ा ही गम्भीर अभाव है। आन्ध्र प्रदेश के तीनों जोनों में जहाँ दुश्मन की आक्रामक मुहिम काफी संगीन बनी हुई है, वहाँ सबसे पहला कार्यभार हथियारों का आधुनिकीकरण करना और गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हथियारों के अलावा हमें अपने बलों को विस्फोटकों, ग्रेनेडों आदि से लैस करने पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। आर्टिलरी की हमारी आवश्यकता दुश्मन की किलेबन्दी को तोड़ने की आवश्यकता के चलते बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं से हमें फौरन जूझना होगा।

एक अन्य समस्या है सर्वोच्च कमेटियों समेत अनेक पार्टी इकाइयों में सैन्यबोध की कमी। फौजी पहलू को सीएमसी और विभिन्न एसएमसी का ही कर्तव्य समझने की प्रवृत्ति और यह समझने की प्रवृत्ति भी मौजूद है कि पीएलजीए के मुख्य बल ही लड़ाई लड़ते हैं। जब कार्यकर्ताओं को एक्शन टीम जैसी फौजी इकाइयों के लिए, फौजी संरचनाओं के नेतृत्व के लिए, फौजी प्रशिक्षकों के लिए और गुप्तचर, हथियारों के उत्पादन, भण्डार एवं परिवहन तथा फौजी मोर्चे से सम्बन्धित अन्य विभागों समेत विभिन्न फौजी कार्यों के लिए नियुक्त करना होता है, तो पार्टी कमेटियों में तंग सोच पायी जाती है। यह तंग मानसिकता और स्थानीयता की सोच हमारे युद्ध पर और फौजी मोर्चे को मजबूत करने पर प्रतिकूल असर डालती है।

हम अपनी कमजोरियों का यदि समाहार करें, तो पहली कमजोरी यह है कि हमारी युद्ध-कुशलता युद्ध की आवश्यकताओं के स्तर तक विकसित नहीं है। इसीलिए हमें पीएलजीए की युद्ध-कुशलता उन्नत करनी होगी, अपने कमीशनों, कमानों तथा कमाण्डरों की विश्लेषण क्षमताएँ उन्नत करनी होंगी, दुश्मन की आवाजाही तथा कार्यनीति का गहराई से अध्ययन करना होगा और उसे फौजी तरीके से परास्त करने के लिए जवाबी कार्यनीति तैयार करनी होगी। दूसरी कमजोरी यह है कि हमारी पीएलजीए और मिलिशिया संख्या के मामले में कमजोर है और पिछले दो वर्षों में सार्थक रूप से बढ़ नहीं पायी है। कमजोर मिलिशिया और जमीनी स्तर का कमजोर संगठन कई इलाकों में पीएलजीए की धीमी बढ़त और बढ़त में ठहराव का आधार है। अकेले डीके को छोड़ दिया जाय, तो अन्य प्रदेशों में जन मिलिशिया की बढ़त खास उल्लेखनीय नहीं है। बीजे में व्यापक स्तर पर

मिलिशिया मौजूद है, पर सुदृढ़ीकरण कमजोर है। मिलिशिया की इकाइयों की भारी बढ़त के बिना छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में रूपान्तरित करना सम्भव नहीं है। दुश्मन के बलों पर जोरदार प्रहार करने के लिए जनता को जागृत करना होगा तथा उसकी वर्ग घृणा को प्रयोग में लाना होगा, सृजनात्मक तरीके से जनता की सुप्त सम्भावनाओं तथा कुशलताओं को सामने लाना होगा और युद्ध को केवल अपनी पीएलजीए तथा दुश्मन के बलों के बीच सीमित न रखते हुए जनता बनाम राज्य के युद्ध के रूप में रूपान्तरित करना होगा। कुछ प्रदेशों में हमारी आत्मगत शक्तियों की कमी के चलते पहले से मौजूद प्लाटूनों को तोड़ना भी पड़ा है। तीसरी कमजोरी यह है कि हमारी लड़ाकू ताकत कमजोर है। हमारे अधिकतर बलों के पास अभी भी कोई स्वचालित या अर्द्ध-स्वचालित हथियार नहीं हैं। हमारे प्रतिरोध की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ता है। हमारी शक्तियाँ बहादुराना तरीके से लड़ती हैं और कुछ सफलताएँ हासिल करती हैं। मगर कमजोर लड़ाकू ताकत के चलते हमें गम्भीर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अगर हमें दुश्मन के बलों को अधिकतम नुकसान पहुँचाना हो और अपने नुकसान को घटाना हो, तो हमें अपने हथियारों को उच्चीकृत करना होगा। चौथी कमजोरी यह है कि हमारा प्रशिक्षण अभी पर्याप्त स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है। पाँचवीं कमजोरी यह है कि दुश्मन ने अपनी कार्यनीति को बहुत हद तक बदल डाला है, फिर भी दुश्मन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हम अभी घिसेपिटे और पुराने पड़ चुके तौर-तरीकों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ भी दुश्मन ने कारगर उपाय किये हैं, खास कर उन्हीं क्षेत्रों में हम एम्बुशों में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाये हैं। दुश्मन की ओर की कमजोरियों तथा खामियों को चिह्नित करने के लिए विशेषीकृत अध्ययन जरूरी है। इन तमाम राजनीतिक-सामरिक कमजोरियों को दूर करते हुए हमें पीएलजीए को मजबूत करना होगा और छापामार युद्ध को तेज करना होगा ताकि सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध में छलांग लगायी जा सके।

जन संगठन, जन संघर्ष और संयुक्त मोर्चा

सीसी की पहली बैठक में तय किया गया चौथा कार्यभार, अर्थात् मजदूर वर्ग के बीच पार्टी का निर्माण करना तथा उसे मजबूत करना, मजदूर वर्ग का जुझारू तथा राजनीतिक आन्दोलन खड़ा करना, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक आधार वाले जन आन्दोलनों का निर्माण करना ताकि क्रान्ति के तीसरे जादुई हथियार के रूप में संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया जाय तथा उसे मजबूत किया जाय, आंशिक रूप से सफल हो पाया है। पिछले दो सालों में

हमने शहरी कार्य में कोई खास प्रगति हासिल नहीं की। शहरी कार्यों की सही दिशा के मामले में अभी समस्या बरकरार है। हमें शहरी कार्यों पा नीतिगत पत्र तैयार करना है और समूची पार्टी को शिक्षित करना है तथा सभी पार्टी कमेटियों को समुचित दिशा देनी है। शहरी क्षेत्रों में कार्य की क्षमता रखनेवाले कार्यकर्ताओं को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करने की भी जरूरत है। सभी जन कार्यों को आम जनता के ठोस संगठनों का निर्माण करने की दिशा में हों, सशस्त्र संघर्ष तथा रणनीतिक संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की दिशा में होना होगा। रणनीतिक संयुक्त मोर्चे का बुनियादी रूप हमारे छापामार जोनों तथा छापामार आधारों में उभर रही जनता की नयी सत्ता का संयुक्त मोर्चा है।

छापामार आधारों (जीबी) की समीक्षा

विलय से पहले ही डीके तथा एओबी के रणनीतिक क्षेत्रों में समूचे छापामार जोन को मुक्त क्षेत्र में रूपान्तरित करने के परिप्रेक्ष्य के साथ पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू ने छापामार आधारों (जीबी) को कायम करने का कार्यभार हाथ में लिया था। विलय के समय तक इस काम में कुछ प्रगति भी हुई थी। इसी तरह पूर्ववर्ती एमसीसीआई की भी विलय से पहले बीजे में छापामार आधार-क्षेत्रों की स्थापना की ठोस योजना थी। एकीकृत पार्टी के गठन के बाद यह कार्यभार तीनों रणनीतिक क्षेत्रों के लिया गया। एकीकृत पार्टी की सीसी की पहली बैठक और सीएमसी ने आधार-क्षेत्रों की स्थापना के लक्ष्य के साथ प्रत्येक रणनीति क्षेत्र की ठोस स्थितियों का अध्ययन करने, छापामार आधारों की स्थापना के लिए कुछ पॉकेट चुनने और ठोस योजना तथा नेतृत्व के संकेन्द्रण के जरिये पहले एक या दो जीबी इलाकों में काम शुरू करने का फैसला किया। प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्र में ऐसे कुछ छापामार आधारों (जीबी) को पहले विकसित करते हुए, जो छापामार जोन में केन्द्र बिन्दु का काम करेंगे, आधार क्षेत्रों को कायम करने और इनका प्रयोग कर अपनी पार्टी, जन सेना तथा संयुक्त मोर्चा को अधिक मजबूत करने और अपनी सत्ता को समूचे छापामार जोन में विस्तारित करने का परिप्रेक्ष्य रहा है।

तदनुरूप प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्र में जीबी इलाके चिह्नित किये गये, इनमें से एक या दो को तत्काल संकेन्द्रण के लिए चुना गया और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं छापामार बलों को नियुक्त करने, जनता को राजनीतिक तौर पर गोलबन्द करने तथा सुदृढ़ करने, दुश्मन के प्राधिकार को ध्वस्त करने और जनता की राजनीतिक सत्ता कायम करने के लिए योजनाएँ तैयार की गयीं। इस योजनाबद्ध कार्य के फलस्वरूप हम कुछ जीबी स्थापित कर सके और निकट भविष्य में कुछ अन्य स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। हम इन जीबी के तहत कई

गाँवों में आरपीसी गठित करने में सफल रहे हैं। खास तौर पर डीके में गाँव स्तर पर ही नहीं, बल्कि इलाकाई स्तर पर भी आरपीसी का गठन एक सार्थक उपलब्धि है और हमारे देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में एक नया अनुभव भी। डीके तथा एओबी में हमारे जीबी क्षेत्रों पर दुश्मन के बार-बार होने वाले हमलों को हमारे मुख्य, द्वितीय तथा आधारभूत बलों के नेतृत्व में जनता की सक्रिय हिस्सेदारी से परास्त किया गया है। डीके में गाँव स्तर पर हमारी पार्टी इकाइयों की संख्या बढ़ाकर और गाँव की पार्टी कमेटियों का भी गठन कर, हमारी सैनिक संरचनाओं को बढ़ाकर, इन्हें मजबूत कर तथा कम्पनी स्तर की संरचना तक पहुँचाकर, अधिक से अधिक लोगों को मिलिशिया में शामिल कर, विभिन्न राजनीतिक, सामरिक तथा सांगठनिक अभियानों में जनता को राजनीतिक तौर पर गोलबन्द कर और बड़े पैमाने पर किसान, महिला तथा सांस्कृतिक जन संगठनों का विस्तार कर, और आरपीसी के रूप में जनता के प्राधिकार का सुदृढ़ीकरण, विस्तार तथा स्थापना डिविजन तथा स्पेशल जोन के स्तर पर करते हुए और पार्टी कमेटियों के साथ ही जनता की राजनीतिक सत्ता के जीबी-स्तरीय निकाय गठित करते हुए हमारे छापामार आधारों को अधिक सुदृढ़ किया गया है। पश्चिमी बस्तर में प्रतिक्रान्तिकारी सलवा जुडुम अभियान में अनेक आरपीसी ध्वस्त हुए हैं और अब इन्हें पुनर्गठित किया जा रहा है।

हम मजदूर वर्ग के भीतर पार्टी का किसी सार्थक हद तक निर्माण या मजदूर वर्ग के जुझारू आन्दोलन का निर्माण तो नहीं कर पाये, मगर हमने व्यापक आधार वाले मोर्चों का निर्माण करने में कुछ नतीजे हासिल किये और संयुक्त मोर्चे के कार्य में कुछ प्रगति की है। जन मोर्चे पर एकीकृत पार्टी के गठन के बाद से दो वर्षों के भीतर ठीक-ठाक गतिविधि हुई है। सीसी के निर्णय के अनुरूप दो स्तरों पर संयुक्त मोर्चा संगठनों का निर्माण करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं – एक रणनीतिक दृष्टिकोण से और दूसरा कार्यनीतिक स्वरूप का। इन मोर्चों के जरिये हमने दैनंदिन ज्वलन्त मुद्दों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है।

पार्टी के नेतृत्वाधीन मोर्चे ने राजनीतिक आह्वान लागू किये जैसे राजनीतिक बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान, सलवा जुडुम के विरुद्ध अभियान, आन्ध्र प्रदेश में क्रान्तिकारी आन्दोलन पर राज्य द्वारा प्रायोजित हमलों तथा राजकीय दमन के विरुद्ध अभियान और महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन। कार्यनीतिक स्तर पर साम्राज्यवादी शोषण एवं लूट, साम्राज्यवादी वैश्वीकरण तथा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारों द्वारा लागू की गयी नवउदारवादी नीतियों, इराक पर साम्राज्यवादी आधिपत्य तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के युद्धोन्मादी कृत्यों, राजकीय दमन तथा विभिन्न

काले कानूनों, खनन, बहु–उद्देश्यीय, अवरचनागत और अन्य तथाकथित विकास परियोजनाओं के लिए जंगल तथा खेती की जमीन से आदिवासियों तथा किसानों के विस्थापन, दलितों तथा मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों और ऐसी अन्य समस्याओं का विरोध करने वाले सभी तत्वों को लेकर व्यापक मोर्चा तैयार करने के प्रयास किये गये।

उपरोक्त पहलू हमारे जन मोर्चे पर सकारात्मक पहलू रहे, पर खामियाँ तथा कमजोरियाँ भी काफी गम्भीर रही हैं। दोनों मोर्चों के केन्द्रीय कोर में आन्तरिक समस्याएँ रही हैं और विचारों तथा कार्यों में एकता की कमी रही है।

मोर्चों के केन्द्रीय कोर एवं अखिल भारतीय जन संगठनों के साथ तालमेल करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए गठित सुकोमो की इस अन्तराल में पाँच बैठकें हुईं। सुकोमो ने जन संगठनों के फ्रैक्शनों और नवगठित अखिल भारतीय निकायों का मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन एक प्रमुख समस्या यह रही कि सुकोमो के सदस्य अन्य गतिविधियों के अलावा प्रदेशों के विभिन्न कार्यों में भी शामिल रहे हैं, जिससे अधिक नियमित रूप से मार्गदर्शन देने में सीमा बनी रही। इस तरह सुकोमो की केवल तीन बैठकें ही सम्पूर्ण बैठकें हो सकीं।

सुकोमो की एक प्रमुख समस्या प्रदेशों के साथ तालमेल स्थापित करने के मामले में रही है। बार–बार परिपत्र (सर्कुलर) लिखे जाने के बावजूद यह समस्या लम्बे समय से चली आ रही है। जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाता, तब तक अखिल भारतीय जन संगठनों की जड़ों को गहराने की सम्भावना बहुत कम है।

इससे सामूहिक कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई और कुछ हद तक सामूहिक समझदारी तक पहुँचने पर असर पड़ा है। खुले जन संगठनों का मार्गदर्शन करने में आ रही गम्भीर तकनीकी समस्याओं और अन्य कामों के चलते सदस्यों की सीमाओं के बावजूद सुकोमो ने फ्रैक्शन कमेटियों के साथ करीबी सम्पर्क कायम रखने और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। सुकोमो की एक प्रमुख कमी यह रही कि वह नेतृत्व को आवश्यक विचारधारात्मक–राजनीतिक दिशा नहीं दे सका और ।3 तथा ।4 के भीतर लम्बे समय से चले आ रहे आन्तरिक मतभेदों का समाधान करते हुए विचारों की एकता नहीं ला सका। समग्रता में जन संगठनों का नेतृत्व खुद को जन मोर्चों पर वास्तविक पार्टी नेतृत्व के रूप में नहीं देख पाता रहा है और ऊपर से जारी किये गये निर्णयों को लागू करने वाले कर्मी की भूमिका अदा करता रहा है। हमें उन्हें इस मन:स्थिति से बाहर निकालने का गम्भीर प्रयास करना होगा और जन मोर्चों पर पार्टी के नेतृत्व को ढालना होगा। इसके अलावा हमें अखिल

भारतीय जन संगठनों का निर्माण केवल जन नेताओं के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठनकर्ताओं के आधार पर करना होगा और संगठनों के निर्माण पर केन्द्रित करना होगा, न कि मात्र प्रचार पर।

ı1 के सन्दर्भ में सुकोमो ने इसे पुनर्गठित करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया और लिये गये निर्णय लागू नहीं किये जा सके। इस क्षेत्र में अपार सम्भावनाएँ हैं और प्रयासों में कमी एक अन्य कमजोरी है। जहाँ तक ı2 का सवाल है, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। लेकिन इससे कोई खास लाभ नहीं हुआ क्योंकि वर्कशॉप का मुख्य मकसद छात्र आन्दोलन का फिर से निर्माण करने के लिए सुकोमो के लिए अनुभवों का संश्लेषण करने का था। छात्र आन्दोलन काम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ı5 के विषय में मुख्य कमजोरी फ्रैक्शनल कमेटी सदस्यों के बारे में गलत मूल्यांकन रहा जिनमें से ज्यादातर साथी पीछे हट चुके हैं। इसके बावजूद इस संगठन का धीमा विकास हुआ है और यह संगठन कई प्रदेशों में फैल सका है।

ı4 के निर्माण में एक अन्य कमजोरी इसका सेमिनार किस्म का दृष्टिकोण रहा है जो सम्पर्कों को सुदृढ़ करने में ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। साथ ही इसने सामन्तवाद–विरोधी संघर्ष को अपने कार्यभारों में शामिल भी नहीं किया है। ı3 ने देश में घट रही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना में हस्तक्षेप करने की पहलकदमी नहीं ली। हमें व्यापकतम सम्भव मोर्चे का निर्माण करने के लिए विभिन्न हिस्सों को गोलबन्द करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर जन आन्दोलन का निर्माण करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था। इससे मुद्दा विशेष पर ध्यान केन्द्रित होता और संगठन भी क्रान्तिकारी, प्रगतिशील एवं जनवादी शक्तियों के लिए गोलबन्दी का एक केन्द्र बन पाता।

अखिल भारतीय जन संगठनों और अखिल भारतीय पैमाने पर जन आन्दोलन के निर्माण में कमजोरी को जन मोर्चे पर पार्टी की समग्र कमजोरी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। जन समर्थन और राजनीतिक प्रभाव के मामले में हमारी स्थिति अच्छी होते हुए भी दैनंदिन मुद्दों पर गोलबन्दी के साथ ही जनता की राजनीतिक गोलबन्दी के मामले में हमारी अभी कोई खास उपलब्धि नहीं रही है। राष्ट्रीयता के आन्दोलनों से तालमेल बिठाने और उनके सन्दर्भ में अपनी कार्यनीति को लागू करने के क्षेत्र में भी कमजोरी रही है। हमारे आरबी और एससी/सैक/एसजेडसी जन कार्य के लिए पर्याप्त सक्षम कार्यकर्ता नियुक्त कर राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अभी ठोस योजना नहीं बना पायी हैं। एक व्यापक और मजबूत जनाधार का निर्माण करने में ऊपर से लेकर नीचे तक गम्भीर समस्या मौजूद रही है। केन्द्रीय स्तर

पर अखिल भारतीय जन संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया में भी यह समस्या दिखायी देती है। हम जन मोर्चों पर मजबूत पार्टी नेतृत्व नहीं तैयार कर रहे हैं और उनकी भूमिका जनवादी तरीके से नहीं निर्धारित कर रहे हैं। जन आन्दोलन के निर्माण पर इन सभी कारकों का प्रतिकूल प्रभाव रहा है।

क्रान्ति में जीत हासिल करने के लिए तीसरे जादुई हथियार के तौर पर संयुक्त मोर्चे को तैयार करने की दिशा के साथ जन आन्दोलन का सूत्रपात करने, ठोस जन संगठनों का निर्माण करने के महत्व को ध्यान में रखना निहायत जरूरी है। कहने की कोई जरूरत नहीं कि जनता की राजनीतिक गोलबन्दी के बिना कोई मजबूत पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा नहीं हो सकता है। यह इसलिए कि जन आन्दोलन और जन कार्य पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा में भर्ती और समर्थन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रोत हैं। मुख्य रूप से सही जन दिशा तथा वर्ग दिशा अपनाकर ठोस जन आधार का निर्माण करने में कमजोरी के चलते भर्ती का वर्तमान निम्न स्तर बना हुआ है। अनेक क्षेत्रों में यह सही है कि दुश्मन की आक्रामक मुहिम को परास्त करना जन मोर्चों पर छलांग मारने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसी के साथ जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों ही तरह से युद्ध के लिए गोलबन्द किये बिना हम केवल अपनी पीएलजीए के जरिये ही दुश्मन की आक्रामक मुहिम को परास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भी जहाँ हमारी सैनिक संरचनाएँ अपेक्षाकृत मजबूत हैं और जनता को संगठित करने के लिए तथा जन संगठन की इकाइयाँ खड़ी करने के लिए एवं इनको नियमित रूप से सुचारू बनाने के लिए कुछ लचीलापन कायम है, वहाँ भी हमने इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये हैं। परिणामस्वरूप पार्टी के राजनीतिक प्रभाव और सांगठनिक सुदृढ़ीकरण के बीच एक बड़ी खाई बनी हुई है।

एपी, एनटी तथा एओबी में सामन्तवाद-विरोधी संघर्षों और विभिन्न जन मुद्दों पर संघर्षों के लम्बे इतिहास के चलते व्यापक जन आधार अस्तित्व में आया है। दमन में थोड़ी भी राहत मिलने पर लाखों लोग सभाओं और रैलियों में शरीक होते हैं। दमन के बीच भी हजारो-हजार लोग स्वत:स्फूर्त रूप से शवयात्राओं तथा सभाओं में हिस्सेदारी करते रहे हैं। लेकिन इन्हें राज्य के खिलाफ जुझारू आन्दोलनों में रूपान्तरित या सांगठनिक रूप से सुदृढ़ नहीं किया जा सका है। इसीलिए हम जनता को युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल करने में असफल रहे हैं। अगर इस कमजोरी को दूर किया जाय, तो हम एपी के तीनों जोनों में एक सशक्त जन आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं।

बीजे में हमारे पास अच्छा जनाधार और समर्थन है, सांगठनिक ढाँचे बने हुए हैं। परन्तु

ालो–अप (बाद के काम के मामले में बेहद कमजोर होने के चलते हम जनता को यु) में या राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बीजे में अपेक्षाकृत मजबूत सैनिक संरचनाओं के चलते हमारी अच्छी स्थिति है और हजारों की तादाद में गाँव स्तर की क्रान्तिकारी किसान कमेटी की इकाइयाँ मौजूद हैं। कुछ क्षेत्रों में संगठनकर्ताओं के चलने–फिरने में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन है क्योंकि दुश्मन के लिए प्रतिकूल स्थितियों के चलते वह अभी प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाता है। ाि भी यहाँ जनता के बीच हमारे कार्यों और जन संघर्षों को खड़ा करने में हम काफी कमजोर हैं। जन संगठन की हमारी इकाइयाँ सक्रिय नहीं हैं और हम इन्हें नियमित रूप से सुचारू नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल हमारी मुख्य कमजोरी सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में रही है। क्रान्तिकारी किसान कमेटी को गाँव स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सुदृढ़ करना होगा और उन्हें राजनीतिक–सै)ान्तिक रूप से लैस कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। जन संगठनों की तमाम स्तर की बाकी कमेटियों को भी मजबूत करना होगा ताकि वे पहल ले सकें। हमें पुराने इलाकों में सामन्तवाद–विरोधी संघर्ष को और भी सघन व गहरा करना चाहिए तथा जनता के रोज–ब–रोज के मुद्दों व विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए।

3यू में जन आन्दोलनों तथा जन संगठनों का निर्माण करने के हमारे प्रयास आवश्यकता से बहुत ही कम हैं। खास तौर पर उत्तरी बिहार ऐसा इलाका होने के नाते जहाँ बड़े–बड़े जमींदारों का दबदबा कायम है, वहाँ सामन्तवाद–विरोधी संघर्षों को हमारे आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु एवं रीढ़ होना चाहिए। जमींदारों की जमीन पर कब्जे, ासल दखल और विभिन्न सामन्ती प्रथाओं के खिला भूमिहीन एवं गरीब किसानों को बड़े पैमाने पर गोलबन्द किया जा सकता है। कुछ जमींदारों का सााया आम जनता में उत्साह तो पैदा कर सकता है। परन्तु यह अपने आप में जुझारू जन आन्दोलन तैयार नहीं कर सकता या स्थानीय नेतृत्व स्थापित नहीं कर सकता है।

पश्चिम बंगाल में भी हमने कुछ राजनीतिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है और जनता के बीच हमारा प्रभाव बढ़ा है। लेकिन हमारा जन संगठन और जन आन्दोलन हमारे राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप नहीं हैं। इसीलिए जन संगठन के निर्माण और स्थानीय स्तर पर सांगठनिक सुदृढ़ीकरण में हमारी कमजोरी से पश्चिम बंगाल में हमारी भर्ती, समग्र प्रतिरोध और मजबूत पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा का निर्माण प्रभावित हुआ है।

डीके में हमारा जनाधार अपेक्षाकृत गहरा तथा स्थिर है और अधिकतर गाँवों में जनता पार्टी के सांगठनिक दायरे में लायी जा चुकी है। इससे हमें दुश्मन का कारगर रूप से मुकाबला

करने में मदद मिली है। दैनंदिन मुद्दों तथा राजनीतिक मुद्दों, दोनों ही पर जनता की गोलबन्दी अपेक्षाकृत ज्यादा है, जन संगठनों की सदस्यता अधिक है और गाँवों के अलावा ऊपरी स्तरों तक सांगठनिक सुदृढ़ीकरण अधिक है तथा जन संगठनों की इकाइयाँ नियमित रूप से सुचारू हैं। हम इन जन संगठनों को स्पेशल जोन के स्तर तक विकसित कर पाये हैं। हमने विभिन्न तबकों, वर्गों तथा पार्टियों के साथ साझे मोर्चे बनाने और संयुक्त संघर्ष चलाने में कुछ प्रगति भी हासिल की है। जनता की यह निरन्तर गतिविधि और उसके सांगठनिक सुदृढ़ीकरण ने पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा में लगातार भर्ती के लिए आधार प्रदान किया है। पिछले दो सालों में जन संगठन की इकाइयों की संख्या बढ़ी हैं और भर्ती लगभग दुगुनी हुई है। दुश्मन की आक्रामक मुहिम के खिलाफ़ कारगर प्रतिरोध के साथ-साथ जनता के बीच व्यवस्थित काम के ही कारण भर्ती में यह छलांग लग पायी है।

कर्नाटक में शुरुआत में अच्छा राजनीतिक प्रभाव रखने वाले व्यापक आधार वाले संघर्ष तथा मोर्चे संगठित किये गये। लेकिन खुद को अल्पमत कहलाने वाले पार्टी के एक हिस्से द्वारा अपनायी गयी गलत लाइन के चलते जन संघर्षों को सशस्त्र संघर्ष के विपरीत खड़ा करके देखा गया और सशस्त्र संघर्ष की कीमत पर जन संघर्षों पर अतिरिक्त जोर दिया गया। अन्ततोगत्वा समूचे प्रदेश के आन्दोलन पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। कर्नाटक के अल्पमत के कामरेड़ों का प्रदेश के जन संगठनों को अखिल भारतीय जन संगठनों के साथ सम्बद्ध करने से इन्कार और स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने पर उनका जोर उनके दक्षिणपन्थी भटकाव को दर्शाता है जो अन्ततः दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन में परिणत हो गया है।

महाराष्ट्र में जहाँ जन आन्दोलन तथा जन संगठन का लम्बा इतिहास रहा है, वहाँ पिछले दो सालों में कोई खास विकास नहीं देखा गया है। जनता के कुछ तबकों के बीच कवर संगठन बनाने के कुछ सफल प्रयास किये गये हैं और संयुक्त मोर्चे की गतिविधियों में कुछ प्रगति हुई है। तामिलनाडू में जहाँ हमने 2002 के अन्त में फौजी प्रशिक्षण शिविर पर दुश्मन के हमले के बाद कार्यकर्ताओं की बहुसंख्या और नेतृत्व का अच्छे-खासे हिस्से के रूप में नुकसान उठाना पड़ा, वहाँ धीरे-धीरे काम चल पड़ा है और पिछले दो सालों में जन संगठन की इकाइयाँ गठित हुई हैं जो गुप्त रूप से कार्य कर रही हैं। कवर संगठन बनाने और उसके झण्डेतले काम करने तथा इन्हीं संगठनों से कार्यकर्ताओं को भर्ती करने का तामिलनाडू का अनुभव, चाहे छोटे पैमाने का ही क्यों न हो, समूची पार्टी के लिए काफी उपयोगी है।

हरियाणा में हमारे जन कार्यों तथा जन आन्दोलनों के चलते नतीजे अच्छे रहे हैं और जन संगठनों का अपेक्षाकृत सुदृढ़ीकरण हो सका है। पंजाब और केरल में जन मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है, पर यह खास उल्लेखनीय नहीं है। असम में जनता के बीच कार्य का विस्तार पिछले दो वर्षों में दो जिलों से छः जिलों तक हुआ है और कुछ संघर्षों का जनता पर अच्छा असर पड़ा है।

लेकिन समग्रता में देश में हमारी ताकत और राजनीतिक प्रभाव की तुलना में हमारी जन गोलबन्दी और जन संगठनों में जनता का सुदृढ़ीकरण अभी कमजोर है। दैनंदिन तथा राजनीतिक मुद्दों पर जन गोलबन्दी तथा ठोस जन संगठनों के निर्माण और जनता के बीच बुनियादी कार्य के बिना पार्टी, सेना तथा संयुक्त मोर्चा को मजबूत करना या युद्ध को तेज करना सम्भव नहीं है। हमारी सभी पार्टी कमेटियों को जन मुद्दों को उठाते हुए मजबूत जनाधार का निर्माण करने और जनता को इकाइयों में सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमारी समूची दिशा जनता को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जन युद्ध में गोलबन्द करने की होनी चाहिए।

सांस्कृतिक मोर्चा

प्रदेशों में सांस्कृतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के कुछ प्रयास किये गये। डीके और बीजे में हम गाँव तथा इलाके के स्तर पर सांस्कृतिक इकाइयों का गठन करते हुए व्यापक पैमाने पर सांस्कृतिक आदोलन का निर्माण करने में सफल हुए हैं। सांस्कृतिक मोर्चे पर कार्यरत कामरेडों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशाप आयोजित किये गये। डीके में फिलहाल सैकड़ों सांस्कृतिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। अखिल भारतीय पैमाने पर प्रगति अच्छी नहीं है। समुचित योजना लेकर इस गतिविधि को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। खास कर बढ़ते साम्राज्यवादी सांस्कृतिक आक्रमण के सन्दर्भ में हमें उन सभी प्रदेशों में सांस्कृतिक मोर्चा विकसित करना होगा जहाँ हमारी पार्टी की उपस्थिति है। हमें सांस्कृतिक कार्यों पर एक परिप्रेक्ष्य तैयार करना होगा और समूची पार्टी को शिक्षित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जन सेना के साथ-साथ सांस्कृतिक सेना भी विकसित हो।

महिला मोर्चे पर हमारे कार्य

महिला मोर्चे पर हमारे कार्य अभी क़तई संतोषजनक नहीं हैं। महिला आन्दोलन का निर्माण करने तथा कार्यकर्ताओं की भर्ती करने और महिलाओं के बीच से नेतृत्व प्रोत्साहित करने की अपार सम्भावनाओं तथा आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक प्रदेशों में भर्ती अभी बेहद कमजोर है, महिला कार्यकर्ताओं का चयन-श्रेणियाँ-पदोन्नति अभी भी किसी व्यवस्थित

योजना के अनुरूप नहीं तय की जाती है और हमारे प्रयास नाकाफी हैं। पितृसत्ता का रुझान इस सम्बन्ध में हमारे प्रयासों में भारी रुकावट पैदा कर रहा है।

डीके, बीजे, एपी के तीनों जोनों, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पार्टी, सेना तथा जन संगठनों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन अन्य प्रदेशों में समग्रता में आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कमजोर है। अनेक प्रदेशों में महिला कार्यकर्ताओं को भर्ती करने, विकसित करने तथा पदोन्नत करने और महिला मुद्दों को उठाने में विशेष प्रयासों की कमी बनी हुई है। पार्टी और पीएलजीए में महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोन्नत करने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कमियाँ मौजूद हैं। हमारी नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियों को इन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और जिन प्रदेशों में हमारा संगठन अपेक्षाकृत मजबूत है वहाँ महिला उपकमेटी गठित करनी चाहिए। जहाँ यह सम्भव नहीं है वहाँ कम-से-कम एक एससी सदस्य को महिला मोर्चे पर विशेषज्ञता के लिए नियुक्त करना चाहिए। लगातार विचारधारात्मक-राजनीतिक शिक्षा और आन्दोलन में महिलाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पितृसत्तात्मक रुझानों को दुरुस्त किया जाना चाहिए।

विलय के समय महिला मोर्चे पर विशेषज्ञता कायम करने, पार्टी में महिलाओं के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं की देखरेख करने, महिला कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने और महिलाओं के बीच कार्यरत मोर्चा संगठन का मार्गदर्शन करने के अलावा महिला संगठनों तथा आन्दोलन का निर्माण करने में सहायता देने के लिए सीसी की पहली बैठक में सीएमएससी के नाम से एक उपकमेटी बनायी गयी। पिछले दो वर्षों में महिला परिप्रेक्ष्य पत्र पर प्रारम्भिक चर्चा सम्पन्न हुई है, संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु इस पत्र को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। सीएमएससी ने जाँच-पड़ताल की कुछ गतिविधियाँ संचालित कीं, महिला मुद्दों पर टिप्पणियाँ तैयार कीं, पत्रिकाओं के लिए लेख भेजे, विडियो कार्यक्रम जारी किये, कुछ महिला कार्यकर्ताओं के लिए कक्षाएँ आयोजित कीं, सांगठनिक मार्गदर्शन दिया, कुछ इलाकों में जमीनी स्तर का अध्ययन किया और सीसी के सामने सुझाव रखे।

2007 के अन्त तक नया महिला संगठन खड़ा करने के लिए तैयारी के रूप में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का महिलाओं पर अच्छा असर पड़ा और अनेक बुद्धिजीवियों समेत कई गैर-पार्टी महिलाओं ने हिस्सेदारी की। लेकिन सेमिनार का फालो-अप (बाद का काम) तालमेल तथा दमन से सम्बन्धित समस्याओं के चलते पर्याप्त नहीं हो

सका है। प्रस्तावित नये महिला संगठन का घोषणापत्र तैयार हो चुका है और इसे अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

सीएमएससी ने कुछ गतिविधियाँ अवश्य संचालित कीं, पर उसके अधिकतर सदस्यों के मुख्यत: अन्य कामों में शामिल रहने के चलते इसमें गम्भीर सीमाएँ रही हैं। अधिकतर प्रदेशों में उपकमेटी का अभाव और विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी सीसी सदस्य द्वारा सीएमएससी को सूचना न देना महिला समस्याओं का सही आकलन करने में सीएमएससी की एक अन्य सीमा का कारण रहा है। सार रूप में कहा जाय, तो जहाँ एक ओर इस उपकमेटी का गठन सकारात्मक विकास रहा है और इसने महिला मोर्चे पर हमारे कामों के विकास में योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर अधिक पूर्णकालिक सदस्य शामिल करके तथा प्रदेशों की उपकमेटियों तथा महिला आन्दोलनों के साथ अधिक तालमेल कायम करके इस उपकमेटी को मजबूत करने की निहायत फौरी जरूरत है।

विभिन्न प्रदेशों में आन्दोलन का संक्षिप्त आकलन

पिछले दो सालों में हम समग्रता में आन्दोलन को टिकाये रख पाये हैं, डीके तथा बीजे में छापामार युद्ध को तेज कर पाये हैं और सीमित ही सही, कुछ नये इलाकों तक विस्तार कर पाये हैं। लेकिन एपी तथा एनटी में हमें गम्भीर नुकसान उठाना पड़ा है और एओबी में ठहराव का सामना करना पड़ रहा है। समग्रता में आन्ध्र प्रदेश का समूचा आन्दोलन अस्थाई तौर पर सामयिक पराजय की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। पिछले दो सालों की उपलब्धियों तथा विफलताओं का आकलन करते हुए हमें समूची पार्टी में विभिन्न स्तरों पर विलय–प्रक्रिया सम्पन्न करने, विशेष कर इस मामले में बीजे सैक की भारी जिम्मेदारी, के साथ ही समूची पार्टी को पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों की शिक्षा देने और विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन की प्रक्रिया तथा काँग्रेस सम्पन्न करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा। आइये, सही कार्यनीति तैयार करने के लिए आन्दोलन की समग्र स्थिति को देखें।

एपी में (एपी, एनटी, एओबी में) हमने वार्ता के दौर की परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। 2004 के अन्त तक वार्ता के दौर में व्यापक राजनीतिक अभियान ने तीनों जोनों पर अच्छा राजनीतिक असर डाला और हमारी आत्मगत ताकत को बढ़ाया। लेकिन जनवरी 2005 की शुरुआत से वार्ता टूट जाने पर जल्दी ही हमें नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन

की बहुआयामी आक्रमण की योजना विश्व बैंक की सम्पूर्ण सहायता तथा साम्राज्यवादी सहयोग से तेजी के साथ लागू हुई। दमन के साथ-साथ सुधार को मिलाते हुए दुश्मन ने दुगुनी ताकत के साथ विभिन्न तरीके अपनाकर जनता को हम से दूर करते हुए हमें अलगाव में डालने के योजनाबद्ध प्रयास किये। दुश्मन ने एक के बाद एक जोन चुना और कुछ समय तक अपनी शक्तियों को बड़े पैमाने पर वहाँ इस तरह संकेन्द्रित किया कि हमारी शक्तियों को पुनर्जीवित होने के लिए कोई गुंजाइश ही न मिल सके। उसका लक्ष्य एक-एक जोन में सुनियोजित, सुसंयोजित रणनीति के जरिये हमारे नेतृत्व को ध्वस्त करने और सटीक सूचनाओं के आधार पर औचक हमले लागू करने का रहा है। मुखबिरों के व्यापक तानेबाने और अन्य गुप्तचर तानेबाने उसके लिए योजनाबद्ध हमले करने का मुख्य स्त्रोत बन गये हैं। इसके अलावा नेतृत्व का खात्मा करने के लिए बड़े पैमाने पर निजी सशस्त्र गिरोहों तथा भितरघाती घुसपैठियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सशस्त्र संघर्ष के हमारे सभी क्षेत्रों में सभी पुलिस थानों की किलेबन्दी, यहाँ तक कि कई स्थानों पर कई परतों में किलेबन्दी के चलते रेड के जरिये दुश्मन को गम्भीर नुकसान पहुँचाना काफी कठिन हो चला है। अक्सर दुश्मन के बल नागरिकों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से हमारे आन्दोलन के दमन के लिए बहुत हद तक सड़कें तथा संचार साधन विकसित किये जा रहे हैं। दुश्मन ने हमारे आन्दोलन को कुचलने के बेहद क्रूर तौर-तरीके विकसित किये हैं। सीसी सदस्य हो या कोई दस्ता सदस्य, किसी भी गिरफ्तार कामरेड को कभी अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता, बल्कि फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या की जाती है।

दुश्मन की उपरोक्त कार्यनीति का मुकाबला करने के लिए हम सही कार्यनीति नहीं अपना पाये हैं। नवम्बर 2005 से, खास कर फरवरी 2006 से दुश्मन की 'कार्ययोजना' के दौरान हमें सबसे भारी नुकसान उठाने पड़े। इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन क्रमशः उतार की स्थिति में गया जिसकी परिएति अन्ततः अस्थाई तौर पर सामयिक पराजय के रूप में सामने आयी। अस्थाई तौर पर इस सामयिक पराजय के निम्न कारण रहे हैं:- पहले, दुश्मन के सम्भावित हमले के समय और पैमाने के बारे में हमारे पास कोई सही आकलन नहीं रहा। वार्ता के दौरान कुछ सैनिक तैयारियाँ अवश्य कर ली थीं। परन्तु दिसम्बर 2004 तक हमारी ये तैयारियाँ अभी पूरी नहीं हो सकी थीं। दिसम्बर 2004 में जब युद्ध-विराम का दौर समाप्त हो गया, तो हमने सोचा कि शायद दुश्मन अभी दो महीनों तक, अर्थात् फरवरी 2006 तक गम्भीर हमले नहीं करेगा। परिणामस्वरूप हम दुश्मन के नृशंस आक्रमण का सामना करने की अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सके। एक यही वजह थी कि जनवरी की

शुरुआत में ही जब दुश्मन ने अपना भारी हमला शुरू कर दिया, तो प्रारम्भ में हमें गम्भीर नुकसान उठाना पड़ा। फौरन हमने दुश्मन के इस आक्रमण का मुकाबला करना शुरू किया, पर लम्बे समय से चली आ रही हमारी कमजोरियों के चलते हम कारगर प्रतिरोध नहीं खड़ा कर सके। दूसरे, हम विभिन्न तौर-तरीकों से योजनाबद्ध कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए अपनी शक्तियों को टिकाये रखने के लिए समूची पार्टी को प्रेरित नहीं कर पाये। तीसरे, जब परिस्थिति स्पष्ट रूप से हमारे प्रतिकूल रही, तब हमने पीछे हटने की कार्यनीति नहीं अपनायी। इससे दीर्घकालीन लोकयुद्ध और उसके ठोस अमल की गहरी समझदारी की कमी दिखायी देती है। इसके बजाय जब दुश्मन हमारा खात्मा करने के इरादे से हमारे पॉकेटों को घेर रहा था, तो हमने एक कदम पीछे हटने के बजाय प्रतिरोध तेज करने और लगातार जारी रखने की योजना बनाना कायम रखा। चौथे, बढ़ते दमन के साथ हमें अपने छापामार दस्ते मैदानी क्षेत्रों से हटाने पड़े। हमने मैदानी क्षेत्रों में संघर्ष और संगठन के वैकल्पिक रूप अपनाने का प्रयास किया, कुछ नतीजे हासिल भी किये। परन्तु दुश्मन के भारी दमन के सामने ये रूप नाकाफी थे। पाँचवें, हमने शुरुआती दौर में संघर्ष के क्षेत्र के विस्तार के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचा था। जिससे हमारी शक्तियों की दाँवपेंच संचालित करने की क्षमता पर गम्भीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारे इलाके, खास कर एपी में, काफी सिकुड़ चुके थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि युद्ध को तेज करने के हमारे प्रयास इसलिए वांछित नतीजे हासिल नहीं कर सके कि पिछले कई वर्षों से जनता की सक्रिय भागीदारी धीरे-धीरे घटती चली गयी थी। व्यापक जन समर्थन के बावजूद हम जनता को अपने सांगठनिक दायरे में लाने में असफल रहे थे। हम बार-बार जनता की शिरकत के बारे में योजना बनाते रहे, पर दुश्मन के बढ़ते दमन के कारण उसके आक्रमण के पैमाने के अनुरूप जनता की शिरकत बढ़ाना मुश्किल होता गया। इसके अलावा दुश्मन की बहुआयामी रणनीति, अर्थात् सुधार, प्रलोभन, मनोवैज्ञानिक युद्ध तथा अन्य विविध उपायों के साथ-साथ नृशंस दमन का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई उपयुक्त योजना नहीं थी। कुल मिलाकर सुदृढ़ जन आधार के अभाव का हमारे प्रतिरोध के पैमाने और गुणवत्ता पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप हमारा युद्ध अपनी पीएलजीए और दुश्मन के बीच का युद्ध बन कर रह गया। समुचित कार्यनीति अपनाने और नुकसान को रोकने में इस विफलता के लिए सीसी, पीबी, सीआरबी और एपी के तीनों जोनों का प्रभारी नेतृत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आज हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एपी की परिस्थिति समग्रता में अस्थाई तौर पर सामयिक पराजय की स्थिति तक पहुँच चुकी है। इस भारी दमन के बीच व्यवस्थित कार्ययोजना, श्रमसाध्य प्रयासों और सृजनात्मक कार्यपद्धति अपनाकर हम उपरोक्त खामियों

को दूर करके, सुदृढ़ जनाधार का निर्माण करके और जन युद्ध में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाकर एपी में दुबारा पहलकदमी हासिल कर सकते हैं। एपी के तीनों जानों में प्रत्येक जोन की विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप कार्यनीति अपनायी जानी चाहिए।

डीके में हम जनता की क्रान्तिकारी सत्ता के निकायों का निर्माण करने तथा छापामार आधारों को कायम करने में, युद्ध में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करने में, बड़ी संख्या में मिलिशिया का निर्माण करने में और अनेक कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों को सफलतापूर्वक चलाने में ब्रेकथ्रू हासिल कर पाये हैं। आज हमारा क्रान्तिकारी युद्ध प्रतिक्रान्तिकारी युद्ध और हमारे आन्दोलन पर प्रदेश के प्रशासनिक तन्त्र, सलवा जुडुम, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा पुलिस बलों की साझी शक्तियों की ओर से समन्वित हमले का सामना कर रहा है। जब मुखबिरों का जाल तैयार करने के दुश्मन के प्रयास सफल नहीं हुए, तो उसने *''सब कुछ मार डालो, जला डालो, लूट लो''* की नीति अपनाते हुए गाँव के गाँव नष्ट करने की रणनीति का सहारा लिया, जिसके तहत उसने सलवा जुडुम के आतंकवादी संगठन का प्रयोग कर जनता पर हमला किया और पुलिस बलों को तेजी के साथ दूरस्थ भीतरी क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए हेलिकॉप्टरों का प्रयोग शुरू किया। जून 2005 से दुश्मन के आक्रमणकारी अभियान का मुख्य रूप गाँव के गाँव साफ कर देने तथा राहत प्रदान करने के नाम पर लोगों को बन्दी शिविरों तक पहुँचाने के इरादे से तथाकथित सलवा जुडुम अभियान, अर्थात् मछली को मारने के लिए पानी को ही बहा देने की नीति रहा है। दुश्मन ने आदिवासियों के एक हिस्से को हमारे आन्दोलन के खिलाफ खडा करने और कोया तथा मुरिया जनजातियों के बीच खाई पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। हजारों की तादाद में स्थानीय आदिवासी एसपीओ बनने के लिए बाध्य किये गये हैं और उन्हें हमारे आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा किया गया है। पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों के साथ चल रहे ये गिरोह हमारे मजबूत गाँवों की जनता की हत्या करने तथा यातना देने के क्रूरतम तरीके अपनाकर जनता को हमारे विरुद्ध प्रतिक्रान्तिकारी अभियान में शामिल होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। पुलिस-अर्द्धसैनिक शिविरों को करीब-करीब स्थापित करके हमारी पार्टी, पीएलजीए तथा अन्य क्रान्तिकारी शक्तियों को ध्वस्त करने के इरादे से चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा (कारपेट सुरक्षा) व्यवस्था कायम की गयी है। तेजी के साथ पक्की सड़कें बनायी जा रही हैं और संचार का तानाबाना विकसित किया जा रहा है। दुश्मन की किलेबन्दी मजबूत की जा रही है। साप्ताहिक हाट को जबरन बन्द किये जाने के कारण स्थानीय आदिवासियों को बेशुमार आर्थिक किल्लतों और भयंकर दबाव झेलना पड़ रहा है। सलवा जुडुम अभियान को शुरू करने के बाद एसपीओ की व्यवस्था के साथ-साथ एक व्यापक गुप्तचर तानाबाना निर्मित किया गया है। केन्द्र

तथा छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार और निजी सशस्त्र गिरोहों द्वारा छेड़े गये इस सफाया अभियान (मॉपिंग-अप ऑपरेशन) में हमने 250 से अधिक लोग खो दिये हैं।

प्रतिक्रियावादी शक्तियों तथा दुश्मन के बलों पर लगाम लगाने के मामले में हमारी खामियाँ रही हैं। हम समय पर परिस्थिति का आकलन नहीं कर पाये और गाँव से भाग खड़े होकर आदिवासियों को हमारे खिलाफ संगठित करने वाले मुखबिरों तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ तुरत-फुरत कार्रवाई नहीं कर सके। सड़क के किनारे के गाँवों में काम की उपेक्षा किये जाने के कारण हम सलवा जुडुम के गिरोहों को काबू में नहीं रख पाये। शुरुआत में जब दुश्मन ने सलवा जुडुम अभियान शुरू किया, तो हम उसकी योजना की गहराई का आकलन नहीं कर सके। हमारे आन्दोलन की एक अन्य प्रमुख कमजोरी जनता के विभिन्न तबकों के बीच हमारी कोई खास उपस्थिति का न होना और शहरी क्षेत्रों में कमजोर आधार रही है।

बीजे में नवगठित भाकपा (माओवादी) के फैसले के मुताबिक पूर्ववर्ती एमसीसीआई की बिहार-झारखण्ड-बंगाल स्पेशल एरिया कमेटी और पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की बिहार-झारखण्ड संयुक्त प्रादेशिक कमेटी का विलय करके बीजे सैक का गठन किया गया। बीजे सैक के गठन के बाद डेढ़ साल के अन्तराल में निचले स्तरों पर विलय प्रक्रिया पूरी की गयी। एकीकरण में अभी भी कुछ समस्याएँ होने के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि इतने थोड़े समय में हमने एकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बीजे सैक के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। क्योंकि यही क्षेत्र दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों के बीच सर्वाधिक खूनी टकराव का क्षेत्र रहा है जिसे भारतीय क्रान्ति के इतिहास में काले अध्याय के रूप में चिह्नित किया गया है। बीजे सैक के मातहत 80 प्रतिशत क्षेत्र को छापामार जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। केन्द्रीय कमेटी की योजना को लागू करने के लिए बीजे सैक में आधार क्षेत्रों के निर्माण के फौरी लक्ष्य को हासिल करने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया के रूप में छापामार जोन के भीतर छापामार आधारों का निर्माण करने के लिए कुछ इलाके चुने गये हैं। दुश्मन की आक्रमणकारी मुहिम का मुकाबला करने के लिए अनेक प्रत्याक्रमण कार्यक्रम चलाये गये और गिरिडीह शस्त्रागार रेड तथा जहानाबाद जेलब्रेक ऑपरेशन जैसी कुछ ऐतिहासिक कार्रवाइयाँ भी की गयीं।

बीजे में दुश्मन ने अपने गुप्तचर तन्त्र में सुधार करते हुए, गुप्तचर तानेबाने को विकसित करते हुए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करते हुए, हमारे क्रान्तिकारी जन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए और बड़े पैमाने पर तथा पड़ोसी प्रदेशों के साथ तालमेल करते हुए कॉम्बिंग

ऑपरेशन चलाकर अपनी आक्रमणकारी मुहिम तेज कर दी है। कुछ हद तक पुलिस थानों की किलेबन्दी की गयी है। गिरफ्तार साथियों की फर्जी मुठभेड़ बढ़ रही हैं और ये आम विशेषता बनती जा रही हैं। यहाँ वाहनों में पुलिस बलों को लाने-ले जाने को बहुत हद तक कम कर दिया गया है और हमें पैदल चलने वाले दुश्मन से निपटने की जवाबी कार्यनीति अपनानी पड़ रही है। बीजे में दुश्मन द्वारा अपनायी जाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यनीति है, निजी लम्पट गिरोहों को संगठित करना और *सेन्दरा* के नाम पर हमारी शक्तियों पर हमला करना। अनेक गाँवों में पुलिस ने हमारे आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए ''ग्राम सुरक्षा समिति'' बनायी है। जनता के एक हिस्से को दूसरे से लड़ाने के लिए प्रतिक्रियावादी वर्ग गम्भीरता से प्रयास कर रहे हैं। लगभग पूरा का पूरा पुलिस बल हमारे दमन में लगा हुआ है, सीआरपीएफ की कई बटालियनें तैनात की गयी हैं और आवश्यकता पड़ने पर सेना को भी उतारने के लिए तैयार रखा गया है। हमारे खिलाफ हेलिकॉप्टरों का प्रयोग करने के लिए हेलिपैड तैयार कर दिये गये हैं। दुश्मन की देशव्यापी रणनीतिक योजना के अन्तर्गत लॉग रेंज पेट्रोलिंग (एलआरपी) का संचालन, हमारे रणनीतिक बिन्दुओं तथा मजबूत गढ़ों पर संकेन्द्रण, राजकीय तन्त्र के विभागों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और ऐसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

इधर राज्य की योजना और सक्रिय सहयोग से इलाके के पतित, भ्रष्ट व गद्दार तत्वों ने खुद को टीपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के रूप में संगठित कर लिया है। वे पुलिस की खुली दलाली कर रहे हैं और बीच-बीच में हम पर हमले भी कर रहे हैं। हमने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ राजनीतिक और सैनिक योजना भी बनायी है तथा उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हमारी शक्तियों, अर्थात् गाँव स्तर पर जन संगठनों, मिलिशिया आदि का सुदृढ़ीकरण कमजोर है। पार्टी, पीएलजीए तथा जन संगठनों में शिक्षण, प्रशिक्षण देकर और स्वतन्त्र जिम्मेदारियाँ सौंपकर हमारे नेतृत्व की गुणवत्ता को अधिक विकसित करने की जरूरत है। पार्टी में गैर-सर्वहारा रुझानों को दूर करने के लिए शुद्धिकरण अभियान चलाने की भी निहायत फौरी जरूरत है। हमने बीजे सैक की दूसरी बैठक में ही संगठन के अन्दर गैर-सर्वहारा प्रवृत्तियों व रुझानों की मजबूत स्थिति को चिह्नित किया था। शुद्धिकरण अभियान चलाने हेतु विभिन्न विजातीय व पतनशील मूल्यों को चिह्नित भी किया गया था, पर हम इस शुद्धिकरण अभियान को सुचारू रूप से चला नहीं सके हैं। अतः इन खामियों को दूर करके हम निश्चित तौर पर बीजे में युद्ध को सघन बनाने के साथ ही व्यापक इलाकों में फैला भी सकते हैं। हमने

आधार क्षेत्र के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित छापामार आधारों के निर्माण हेतु क्षेत्रों का चयन किया है और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें चिह्नित भी किया है। इस सन्दर्भ में हमने कुछ सांगठनिक बदलाव भी किये हैं। यदि हम सही परिप्रेक्ष्य तथा सटीक व ठोस योजना एवं कार्यक्रम अपनायें, तो प्रस्तावित क्षेत्रों में जल्दी ही क्रान्तिकारी जन कमेटी बनाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। हमने सन् 2007 के पूर्वार्द्ध तक उन्नत स्तर के सैनिक फारमेशन (संरचनाएँ) गठित करने का लक्ष्य भी घोषित किया था। लेकिन निचले स्तरों की पार्टी संगठन के विलय की लम्बी प्रक्रिया को पूरा करने और बुनियादी दस्तावेजों पर कक्षाएँ संगठित करने में व्यस्त रहने के कारण हम इस कार्यभार को पूरा करने पर उचित ध्यान नहीं दे पाये हैं। हम प्रस्तावित जीबी क्षेत्रों में अधिक उन्नत स्तर के संगठनों का विकास करने और सघन बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने में भी विफल रहे। इन सभी को बीजे सैक क्षेत्र की मुख्य कमजोरी समझा जाना चाहिए।

हमें बीजे की अपार सम्भावनाओं को ध्यान में रखना होगा और मौजूदा जन युद्ध में गुणात्मक छलांग लगाने के लिए इनका प्रयोग करने की व्यवस्थित योजना तैयार करनी होगी।

छत्तीसगढ़ में भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद विलय प्रक्रिया सम्पन्न हो गयी। प्रदेश सांगठनिक कमेटी (एससी), छत्तीसगढ़ गठित की गयी। सांगठनिक कार्यभारों को पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान राज्य की ओर से बड़े पैमाने पर दमन-अभियान शुरू किया गया है। हमने इस राजकीय दमन के खिलाफ अनेकों टीसीओसी चलाये। पुलिस शिविरों पर रेड तथा एम्बुशों में कुछ सफल रूप से संचालित किये गये। लेकिन कई कार्रवाइयाँ असफल भी हुईं। कुल मिलाकर हम दुश्मन की आक्रमणकारी मुहिम को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। इसी दौरान महिला संगठन की ओर से 8 मार्च को केन्द्रित करते हुए छोटे-छोटे किन्तु अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

दुश्मन के निरन्तर आक्रमणों के दौरान कई कामरेड शहीद हुए। एससी से भीम (प्राण), श्रवण; जोनल कमेटी से अवधेश तथा श्याम बिहारी; सबजोनल कमेटी से सागर तथा नारायण और पीएलजीए के अनेक कमाण्डर तथा कामरेड शहीद हुए हैं। सीसी तथा एससी के कामरेड गिरफ्तार हो गये। इस राजकीय दमन का वहाँ के संगठन पर गहरा असर पड़ा है। फलस्वरूप राज्य सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका।

छापामार युद्ध को विकसित करने के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। तदनुरूप हमने इन

सम्भावनाओं को तलाशने के लिए योजना तैयार की और कार्यक्रम दिये।

पश्चिम बंगाल में विलय के बाद हमने बीजेओ में छापामार जोन की तैयारियों पर संकेन्द्रण का कार्यभार लिया और उसे पूरा किया। अगस्त 2006 में आयोजित प्रदेश के सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कुछ कमजोरियों के बावजूद बीजेओ छापामार जोन बन चुका है। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में और झारखण्ड के दो सीमावर्ती जिलों में पिछले दो वर्षों में जन संघर्ष और जन प्रतिरोध बढ़ चले हैं। भारी राजकीय दमन के बीच जनता हमारी पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न संघर्षों में गोलबन्द होने लगी है। इसी के तहत 'बन्द' संघर्ष का एक रूप बन गया है। बेलपहाड़ी क्षेत्र में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नवम्बर-दिसम्बर में हुआ जन प्रतिरोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नादिया, मुर्शिदाबाद, हुगली और अन्य जिलों में भी निरन्तर दमन के बीच जनता जन संघर्षों में गोलबन्द हो रही है। मैदानी इलाकों में छापामार क्षेत्रों का निर्माण करने के दृष्टिकोण से हमें एक तरफ सशस्त्र संघर्ष को तेज करना होगा, तो दूसरी तरफ एक ठोस योजना के मुताबिक संघर्ष के क्षेत्रों का विस्तार करने पर बल देना होगा। हमारे जन संगठनों ने सिंगूर में किसानों से किये गये भूमि अधिग्रहण और टाटा मोटर्स को सौंपे जाने के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय हिस्सेदारी की। पश्चिम बंगाल जन संघर्षों तथा जन प्रतिरोध के विकास के जरिये पार्टी-सेना को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

महाराष्ट्र में भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद पार्टी की ओर नयी शक्तियाँ आकर्षित हो रही हैं। सुदृढ़ीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं और इसी प्रक्रिया में हमारा काम नये केन्द्रों में विकसित हो रहा है। उत्तर गड़चिरोली-गोन्दिया डिविजन में जन संघर्ष, फौजी प्रतिरोध और भर्ती बढ़ी है। लेकिन जन मिलिशिया को विकसित करने में, व्यापक जन आन्दोलन विकसित करने में और नेतृत्वकारी शक्तियों को मजबूत करने में कमजोरियाँ अवरोध बन रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तीन प्रदेशों के पुलिस बल संयुक्त रूप से हमारी शक्तियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण चला रहे हैं। लेकिन जनता का व्यापक प्रतिरोध भी हो रहा है।

शहरों में हमारा काम मुख्यत: मजदूर वर्ग के बीच है। इसके अलावा हम छात्रों में भी कामों की शुरुआत (ब्रेकथ्रू) कर सके हैं। इसी के साथ साझे मोर्चे के संघर्ष एवं गतिविधियाँ भी चल रही हैं। इस तरीके से हमने संयुक्त मोर्चों के जरिये साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों का पर्दाफाश, हिन्दू फासीवाद तथा जातिगत उत्पीड़न का पर्दाफाश किया है। सांस्कृतिक मोर्चे और महिला मोर्चे के कार्यों को विकसित करने की कोशिशें की जा रही हैं। व्यापक जन

आन्दोलनों का निर्माण करने, जुझारूपन बढ़ाने और पार्टी कमेटियों को मजबूत करने में अभी कमजोरी बनी हुई है। उत्तर गड़चिरोली-गोन्दिया के आन्दोलन और शहरी क्षेत्रों के आन्दोलन को एक-दूसरे के साथ मिलाने में भी कमजोरी रही है।

उपरोक्त कमजोरियों को दूर करते हुए आने वाले समय में मुख्य कार्यभार 'विदर्भ परिप्रेक्ष्य' के साथ छापामार युद्ध को सघन बनाना और विस्तारित करना है। साथ ही हमें मजदूर वर्ग के आन्दोलन तथा व्यापक जन संघर्षों को विकसित करना होगा और उपरोक्त कार्यभारों की पूर्ति के लिए पार्टी नेतृत्व विकसित करना होगा।

3यू में विलय के पूर्व एमसीसीआई की सीसी द्वारा नेपाल की सीमा से लगे उत्तर भारत के तीन राज्यों – उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड के एक विशेष इलाके को लेकर एक स्पेशल एरिया कमेटी का गठन किया गया था। यह क्षेत्र गंगा नदी के उत्तरी भाग में पड़ता है। विलय के बाद इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया तथा जोनल, सबजोनल एवं अन्य कमेटियों को भी पुनर्गठित किया गया। 23 जून 2005 के मधुबन के ऐतिहासिक बहुविध रेड की कार्रवाई नवगठित पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में लड़ी गयी एक महत्वपूर्ण घटना रही। इसने पूरे उत्तर भारत में लोकयुद्ध फैलाने की चेतना पैदा की तथा शासक वर्गों को आतंकित किया। हालांकि इसमें हमारे पीएलजीए के वीर योद्धाओं तथा जोन, सबजोन के कई नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं समेत 6 साथियों को भी खोना पड़ा। उसके बाद भी चरम प्रतिक्रियावादी केन्द्रीय मन्त्री रामविलास पासवान के भाई के रंगमहल को डायनामाईट से उड़ाना, जन्दाहा बैंक कब्जे की कार्रवाई (जो असफल रही) राजनीतिक व सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ रहीं। इन सारी कार्रवाइयों से सामन्तवाद के गढ़ रहे उत्तर बिहार में कृषि क्रान्तिकारी युद्ध को विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति तैयार हुई है।

दुश्मन द्वारा निरन्तर जारी घेराव-दमन मुहिम में कामरेड रवि शहीद हुए तथा भारी संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और हमें गम्भीर संगठनात्मक नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर भी हम सम्मेलनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से जोन/रिजनल कमेटियों व सैक को व्यवस्थित करने में सक्षम हुए हैं। भारी संख्या में पार्टी-सदस्य रहने के बावजूद सांगठनिक सुदृढ़ीकरण का काम अच्छी तरह नहीं किया जा सका है। अतः सेलों, एरिया कमेटियों तथा सबजोनल कमेटियों को गठित-पुनर्गठित तथा व्यवस्थित करने, जन मिलिशिया शक्तियों को संगठनात्मक रूप देने तथा उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित व हथियारबन्द

करने, एलजीएस की संख्या व गुणवत्ता का विकास करते हुए प्लाटूनों का गठन एवं केकेसी सहित विभिन्न स्तरों पर अन्यान्य जन संगठनों का निर्माण करने तथा भूमि आन्दोलन व उत्तर बिहार की मुख्य समस्या बाढ़-सुखाढ़ व जल जमाव के मुद्दे पर जन आन्दोलन को व्यापक रूप से खड़ा करने का काम तात्कालिक कार्यभार बन गया है। जमीन के सवाल पर सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलन व अन्यान्य मुद्दों पर क्रान्तिकारी जन आन्दोलन का सैक के समग्र क्षेत्र में विस्तार भी फौरी कार्यभार बन गया है। इस प्रकार मजबूत जनाधार पर कृषि क्रान्तिकारी छापामार युद्ध को अधिक उन्नत स्तर पर विकसित करते हुए जीबी एरिया के लिए निर्धारित इलाके में काम को ठोस करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य कार्यभार हमारे सामने है। साथ ही आर्थिक स्वावलम्बन हासिल करना भी हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यभार है।

हरियाणा खेतिहर समाज की प्रधानता वाला उत्तर भारत का एक छोटा प्रदेश है। विलय के बाद कुछ अच्छा विकास हुआ है। भर्ती में फिलहाल 35 प्रतिशत दलित, 21.4 प्रतिशत पिछड़ी जातियाँ और 29 प्रतिशत महिला कामरेड हैं। पीआर कामरेडों में 20 प्रतिशत महिलाएँ हैं। नेतृत्व में भी अच्छी-खासी संख्या दलित पृष्ठभूमि से है। संघर्ष और संगठन के रूपों के बारे में ज्यादा स्पष्टता हासिल हुई है और हमने उसे लागू करना भी शुरू किया है। अब हम भूमि-वर्ग संघर्ष के बारे में अधिक स्पष्ट हुए हैं। किसी अवसर पर हम प्रतिक्रियावादी सामन्ती शक्तियों के खिलाफ सशस्त्र टकराव कर चुके हैं। जिससे हमने तथाकथित हरित क्रान्ति के क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष का प्रारम्भिक अनुभव हासिल कर लिया है। पार्टी कतारें भूमिगत कार्यप्रणाली के प्रति अधिक गम्भीर हुई हैं।

इस रूपान्तर में कुछ कामरेडों में कानूनवाद का रुझान एक अवरोध बना है। सांगठनिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके चर्चा करने के एक अन्य रुझान ने कामरेडों के बीच में विभ्रम पैदा किये।

हमारी कार्यनीति में परिवर्तन के चलते दुश्मन भी सजग हो उठा है। वह माओवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए आईआरबी की 9 बटालियनें तैयार कर रहा है। एक विशेष गुप्तचर इकाई तैयार की गयी है। 2005 में कई साथी गिरफ्तार हुए, फर्जी मुकदमे लगाये गये। आज हरियाणा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। उपरोक्त विकास के साथ-साथ कानून से इतर, भूमिगत गतिविधियाँ अब कानूनी, खुली गतिविधियों का स्थान ले रही हैं। इससे नयी चुनौतियाँ सामने आयी हैं। नयी परिस्थिति के साथ कुछ कामरेड खुद को न ढाल पाते हुए निष्क्रिय हो गये हैं। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। लेकिन नयी भर्ती भी

हो रही है। पिछले दो सालों में 100 गाँवों में ठोस योजना के साथ संगठन विकसित किया गया है।

2006 के सम्मेलन के कार्यभार इस प्रकार हैं:- (1) अधिक एलओएस का निर्माण कर वर्तमान क्षेत्र को सटे हुए विस्तृत (बवदजपहनवने) क्षेत्र के रूप में विकसित करते हुए कृषि कार्यक्रम के आधार पर वर्ग संघर्ष विकसित करना और (2) परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में छापामार जोन के निर्माण की अधिक तैयारी करना।

उड़ीसा में विलय के बाद प्रदेश सांगठनिक कमेटी गठित की गयी। दो इलाकों को छापामार जोन के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। इस अन्तराल में संघर्ष के दौरान 9 कामरेडों ने अपने प्राण त्याग दिये। जिनमें दो जोनल कमेटी सदस्य भी थे। इसीलिए निर्धारित समय में लक्ष्यों को हासिल करना सम्भव नहीं हुआ। फिर भी कलिंगनगर में और कुछ अन्य कस्बों में कामों का विस्तार हुआ है। सलवा जुडूम और कामरेडों की गिरफ्तारी के खिलाफ जन कार्यक्रम किये गये। विस्थापन एवं अन्य मुद्दों पर जन आन्दोलन भी किये गये।

पंजाब में विलय प्रक्रिया सम्पन्न की गयी और प्रादेशिक कमेटी गठित हुई। इसके तहत .... जोनल कमेटियाँ और कुछ इलाकाई कमेटियाँ कार्य कर रही हैं। इसी के साथ कुछ शक्तियों को परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में भेजा गया है। किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के बीच काम हो रहा है। देहाती क्षेत्र में कुछ जुझारू जन संघर्ष भी हो रहे हैं। पंजाब के इतिहास को देखते हुए पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी प्रदेशों में भी क्रान्तिकारी आन्दोलनों तथा सशस्त्र संघर्ष की उज्ज्वल सम्भावना है।

असम में उल्फा के नेतृत्व में राष्ट्रीयता आन्दोलन और उत्तर-पूर्व में आम तौर पर संवेदनशील परिस्थिति के चलते वहाँ का दमनकारी तन्त्र बहुत ही विकसित है और लगातार सजग रहता है। यहाँ शुरू से ही अधिकतम गोपनीयता के साथ काम करना और जन मिलिशिया तथा नियमित दस्तों के निर्माण के साथ-साथ पार्टी संगठनों को मजबूत करने, उन्हें सुदृढ़ करने और विभिन्न जन समस्याओं को केन्द्रित कर जन प्रतिरोध संघर्ष खड़ा करने पर ध्यान केन्द्रित करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अन्य मुद्दों के अलावा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित मुद्दों पर जनता की बडे पैमाने पर राजनीतिक गोलबन्दी पर ध्यान केन्द्रित करना भी बहुत जरूरी है। हम जनाधार का निर्माण करने और मुद्दों पर जनता को गोलबन्द करने का प्रयास करते रहे हैं। पिछले दो सालों में हमने अपने कामों का विस्तार करते हुए

विशुद्ध जनजाति के लोगों के अलावा गैर–जनजातीय जनता के बीच भी काम बढ़ाया है। हमारे कार्यभार:- विभिन्न स्तरों पर पार्टी कमेटियों को सुदृढ़ करना, जनता के साथ घुलना–मिलना और विभिन्न रूपों में उन्हें संगठित करना, प्रदेश में जनता के ज्वलन्त मुद्दों पर जन आन्दोलन का निर्माण करने की पहल करना और व्यापक आधार वाले संयुक्त मोर्चे को खड़ा करने का पूरा प्रयास करना, आत्मनिर्णय के संघर्ष के समर्थन में एकजुटता आन्दोलन संगठित करना, राजकीय दमन के खिलाफ जन प्रतिरोध संघर्षों का निर्माण करना और पहल करना, साम्प्रदायिकीकरण तथा नस्ल–आधारित टकराव के खिलाफ मंच विकसित करना, जमीन के अधिकारों एवं जंगल के अधिकारों पर जन आन्दोलन खड़ा करना और चाय बगान मजदूरों तथा तेल रिफायनरियों में संगठनों का निर्माण करना।

केरल में अगस्त में केरलम का पहला सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में एसओसी का चुनाव हुआ। सम्मेलन में आन्दोलन की समस्याओं तथा पार्टी में विजातीय वर्ग रुझानों की समीक्षा की गयी। सम्मेलन ने एसओसी से लेकर सेल स्तर तक शुद्धिकरण अभियान का आह्वान किया। एसओसी की पहली बैठक में गम्भीर समीक्षा की गयी और आन्दोलन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं को चिह्नित किया गया। साथ ही हर स्तर पर विचारधारात्मक–राजनीतिक शिक्षा चलाने का फैसला भी किया गया।

अभी हम केरलम के 14 जिलों में से 9 में काम कर रहे हैं। हम मजदूरों, आदिवासियों, छात्रों, युवाओं, दलितों, सांस्कृतिक मोर्चों आदि में काम कर रहे हैं।

हमारी मुख्य कमजोरियाँ:- जैसा कि सम्मेलन और पहली एसओसी बैठक ने सही समीक्षा की है, एसओसी से लेकर जन संगठनों तक मुख्य समस्या राजनीतिक शिक्षा और सुदृढ़ीकरण की है। जनता पर संशोधनवादी पार्टियों के मजबूत प्रभाव और तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक सभी मार्क्सवादी–लेनिनवादी ग्रुपों की कानूनवादी कायशैली के चलते पीआर कामरेडों का विकास पार्टी के सामने गम्भीर चुनौती है। सुसंगतता और पलकदमी रखनेवाली टीम विकसित करने के मामले में पार्टी गम्भीर कमी का सामना कर रही है।

हमारे फौरी कार्यभार:- (1) एसओसी से लेकर शुद्धिकरण अभियान चलाना, (2) एसओसी, संगठनकर्ता, एसी से लेकर सेल स्तर पर सुदृढ़ीकरण करना, (3) अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति तैयार करने के लिए जन आन्दोलन का निर्माण करना, जुझारू जन संघर्ष चलाना और विभिन्न प्रकार के जन संगठनों का निर्माण करना (4) गुप्त कार्यप्रणाली की समुचित पद्धति विकसित करना और (6) सामाजिक जाँच–पड़ताल करना।

कर्नाटक में (पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की) पिछली काँग्रेस के फैसले के मुताबिक हमने कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में काम शुरू किया। वहाँ काम शुरू करने के बाद दक्षिणपन्थी अवसरवादी राजनीति सामने आयी। इसने हाथ में लिये गये नये–नये कार्यभारों तथा आन्दोलन के विकास में ढेरों अवरोध खड़े किये।

रणनीतिक क्षेत्र में आन्दोलन अभी कमजोर है। हमारा जनाधार भी अभी बहुत मजबूत नहीं है। क्षेत्र में तथा सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने के मामले में एससी की ओर से गम्भीर कमी है। बावजूद इसके कि जनता जमींदारों तथा वन विभाग के खिलाफ संघर्षों के रूप में संगठित है, इसे शान्तिपूर्ण आन्दोलन के रूप में विकसित करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में कार्यप्रणाली, सुदृढ़ीकरण के अभाव और वर्ग संघर्ष की दिशा न होने की समस्या पहले से चली आ रही है। अब जब से एक खासा बड़ा हिस्सा फूटपरस्तों के साथ शामिल हुआ है, कमजोरी बढ़ गयी है। इसीलिए अब पार्टी के सामने शहरी आन्दोलन का दोबारा निर्माण करने की गम्भीर चुनौती खड़ी है।

प्रदेश सम्मेलन ने आधार क्षेत्र का निर्माण करने के परिप्रेक्ष्य के साथ छापामार जोन के निर्माण की दिशा में परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्यभार तय किया। इसके लिए सम्मेलन ने परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में पार्टी, मिलिशिया, पीएलजीए, जन संगठन और शहरी क्षेत्रों में पार्टी, जन संगठनों, कवर संगठनों तथा संयुक्त मोर्चों का निर्माण करने का कार्यभार तय किया। इसने शहर के आन्दोलन का निर्माण देहात के आन्दोलन के पूरक के रूप में करने का कार्यभार तय किया।

भाकपा (माओवादी) के जन्म के बाद यहाँ के प्रदेश सचिव समेत 5 कामरेड शहीद हुए हैं।

तामिलनाडु में आन्दोलन गुणात्मक छलांग नहीं लगा पाया और सन् 2000 में आयोजित 5वें प्रदेश सम्मेलन के समय तक ठहराव में पहुँचा। 9वीं काँग्रेस के बाद शुद्धिकरण अभियान चलाने और वर्ग संघर्ष तथा सशस्त्र संघर्ष विकसित करने का फैसला किया गया। लेकिन जब शुद्धिकरण अभियान आखिरी चरण में पहुँच चुका था, तो नवम्बर 2002 में सैनिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने में हुई गम्भीर गलतियों के चलते पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

इस नुकसान के बाद एसडब्ल्यूआरबी के मार्गदर्शन में नयी कार्यनीति अपनायी गयी। देहात के काम से अस्थाई तौर पर हटने और अपनी आत्मगत शक्तियों को विकसित करने

के लिए शहरी क्षेत्रों पर संकेन्द्रित होने व फिर से देहाती काम की शुरुआत करने का फैसला किया गया। इन फैसलों को लागू करने के लिए अपनायी गयी कार्यनीति और प्रयासों से नये सिरे से काम चल पड़ा है। कुछेक मोर्चों पर नयी भर्ती और विकास ने हमारी स्थिति को सुधारा है।

पिछले डेढ़ साल से रणनीतिक क्षेत्र में फिर से वर्ग संघर्ष तथा सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए तैयारी का काम अभी चल रहा है। रणनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक, सैनिक तथा सांगठनिक तैयारी की योजना लागू की जा रही है।

पूर्ववर्ती पीपुल्स वार की 9वीं काँग्रेस में चिह्नित किये गये गलत रुझानों के अलावा ठहराव तथा छलांग न लगा पाने (ब्रेकथ्रू न कर पाने) के लिए मुख्य कारण निम्नवत रहे:- एससी में सामूहिक सोच तथा सामूहिक कार्यप्रणाली की कमी और नेतृत्वकारी कमेटी के रूप में उसका विकसित न हो पाना; गलत कार्यशैली (करीबी से मार्गदर्शन न देना और स्वत:स्फूर्तता) और अवश्य ही समूची पार्टी में राजनीतिक स्तर का कम होना।

जुलाई 2006 में आयोजित छठे प्रदेश सम्मेलन ने तामिलनाडू में ब्रेकथ्रू हासिल करने के लिए निम्न कार्यभार सामने रखे हैं:- छापामार जोन विकसित करने के फौरी लक्ष्य के साथ वर्ग संघर्ष तथा छापामार युद्ध विकसित करना, पार्टी की पहल से राजनीतिक मोर्चा गठित करना और इसे जनता के बीच स्थापित करना, शहरी योजना के तहत चिह्नित क्षेत्रों में मजदूर वर्ग के बीच हमारे कार्यों को स्थापित करना, शुद्धिकरण के कार्य को जारी रखना और खास तौर पर पार्टी के राजनीतिक तथा विचारधारात्मक स्तर को विकसित करना।

निष्कर्ष

सशस्त्र कृषि क्रान्ति को सारवस्तु बनाते हुए नक्सलबाड़ी के विद्रोह के उभर आने के समय से हमारे देश में शुरू हुए दीर्घकालीन लोकयुद्ध ने पिछले तीन दशकों से हमारी पार्टी द्वारा लागू की जा रही माओवादी राजनीतिक-सामरिक रणनीति तथा कार्यनीति के सही होने को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया है। इस लम्बे दौर में सशस्त्र क्रान्तिकारी युद्ध के दौरान हमारी यह रणनीति तथा कार्यनीति अधिक समृद्ध हुई है।

दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को लागू करते हुए हम आधार क्षेत्रों के निर्माण के परिप्रेक्ष्य के साथ अनेक छापामार जोनों का निर्माण कर सके हैं। पीएलजीए के रूप में जन सेना अस्तित्व में आयी है। देहातों के कुछ पॉकेटों में हम जनता की क्रान्तिकारी सत्ता के

निकायों की स्थापना कर सके हैं। हमसे कई गुना मजबूत दुश्मन का मुकाबला करते हुए हमने अनेक कार्यनीतिक जीतें हासिल की हैं। इससे हमें अपने छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध के उन्नत चरण में पहुँचाने में मदद मिली है।

पिछले दो सालों से हमारी एकीकृत पार्टी ने दोनों पूर्ववर्ती पार्टियों की क्रान्तिकारी विरासत को आगे बढ़ाया है, रणनीतिक क्षेत्रों पर संकेन्द्रित करने की हमारी पार्टी लाइन को लागू करते हुए आधार क्षेत्रों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य के साथ लाल प्रतिरोध क्षेत्र तथा छापामार जोनों का निर्माण किया है और छापामार आधारों (जीबी) की स्थापना की है। हमने छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए को पीएलए में और छापामार जोन को आधार क्षेत्रों में रूपान्तरित करने के दृढ़ निश्चिय के साथ मौजूदा जन युद्ध को तेज करने का प्रयास किया है। भारी नुकसान झेलते हुए भी हमने कुछ जीतें हासिल की हैं। कुछ गम्भीर नुकसान उठाने के बावजूद छापामार युद्ध को अधिक उन्नत स्तर तक विकसित करने की बड़ी सम्भावनाएँ मौजूद हैं। हमें अपनी उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी होगी, विफलताओं से सबक लेने होंगे और वस्तुगत परिस्थिति तथा अपनी आत्मगत क्षमताओं के अनुरूप ठोस कार्यभार निर्धारित करने होंगे।

आज देश-विदेश की शानदार परिस्थिति और नक्सलबाड़ी के विद्रोह के उभर आने के बाद से हमारे नेतृत्व में चल रहे मौजूदा सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध के लम्बे इतिहास के साथ-साथ पिछले दो वर्षों से हमारे जन युद्ध की जीतों के सकारात्मक प्रभाव की पृष्ठभूमि में क्रान्तिकारी युद्ध में गुणात्मक छलांग लगाने की बड़ी सम्भावना है। हमें जन युद्ध को आगे बढ़ाते हुए चार वर्गों के संश्रय का निर्माण करने के लिए साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद तथा सामन्तवाद के खिलाफ सभी शक्तियों को गोलबन्द करने के कार्यभार पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमें बुनियादी वर्गों के बीच से असंख्य युवाओं को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और पीएलजीए को पीएलए में रूपान्तरित करने के लिए जुट जाना होगा। हमें अपनी कार्यनीति को सृजनात्मक रूप से लागू करते हुए और दुश्मन के बलों के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण की कार्रवाइयाँ संचालित करते हुए दुश्मन के अनवरत आक्रमणों, मॉपिंग-अप ऑपरेशनों (सफाया अभियान), घेराबन्दी-दमन अभियानों तथा विभिन्न प्रतिक्रान्तिकारी अभियानों को शिकस्त देनी होगी। हमें छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करते हुए तथा जनता की क्रान्तिकारी सत्ता के निकायों की स्थापना करते हुए अपने रणनीतिक क्षेत्रों में छापामार जोनों को आधार क्षेत्र में रूपान्तरित करना होगा; हमें समूचे देहाती क्षेत्र में नये-नये छापामार जोन तथा लाल प्रतिरोध क्षेत्र विकसित करने होंगे

और छापामार युद्ध को फैला देना होगा। इस तरह हमें क्रान्ति का एक उफान खड़ा कर देना होगा। अपने फौरी कार्यभारों को लागू करते हुए हमें रणनीतिक दृढ़ता तथा कार्यनीतिक लचीलापन दिखाना होगा। नेतृत्व के सचेत प्रयासों के जरिये हमें प्रतिकूल कारकों को अनुकूल कारक में रूपान्तरित करने में जुट जाना होगा। हमें दुश्मन को कार्यनीतिक रूप से असली बाघ और रणनीतिक रूप से कागजी बाघ के रूप में लेते हुए अपनी कार्यनीति को विकसित करना होगा। इस प्रकार हमें देश भर में तीन जादुई हथियारों – पार्टी, सेना तथा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने और इन्हें मजबूती देने में जुट जाना होगा।

दूसरे विश्व युद्ध के दौर के बाद साम्राज्यवाद आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। दुनिया के सभी बुनियादी अन्तरविरोध अधिक तीखे होते जा रहे हैं। साम्राज्यवादियों तथा प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा शोषण, उत्पीड़न तथा लूट के खिलाफ जन आन्दोलन, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और क्रान्तिकारी आन्दोलन उमड़ आ रहे हैं। आइये, देश के मौजूदा जन युद्ध में महान छलांग लगाने के लिए इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठायें। इस प्रकार भारतीय क्रान्ति को नये जनवादी समाज की स्थापना की ओर कदम बढ़ाने के लिए और समाजवाद तथा साम्यवाद हासिल करने के लिए आगे बढ़ते चलें।

पार्टी का प्रधान और केन्द्रीय कार्यभार

पार्टी के सामने हमारी क्रान्ति के तीन हथियारों को मजबूत करते हुए प्रधान और केन्द्रीय कार्यभार हमारे रणनीतिक क्षेत्रों में आधार क्षेत्र स्थापित करने के लिए छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध की गुणात्मक रूप से उन्नत मंजिल तक पहुँचाने तथा पीएलजीए को पीएलए में रूपान्तरित करने, अन्य छापामार जोनों में छापामार युद्ध को तेज करने, परिप्रेक्ष्य क्षेत्रों में लाल प्रतिरोध क्षेत्र विकसित करने और इन क्षेत्रों में छापामार जोन के निर्माण के लिए तैयारियाँ पूरी करने का है। उपरोक्त प्रधान और केन्द्रीय कार्यभार को पूा करने के लिए हमें निम्न राजनीतिक, सामरिक तथा संयुक्त मोर्चे के कार्यभार सूत्रबद्ध करने होंगे :–

राजनीतिक कार्यभार

1. देश भर में ज्वाइण्ट टास्क फोर्स तथा ज्वाइण्ट ऑपरेशनल कमान के नेतृत्व में केन्द्र तथा प्रदेश सरकारों की बहुआयामी फासीवादी सशस्त्र आक्रमणकारी मुहिम को ध्वस्त करें; दुश्मन की प्रतिक्रियावादी एलआईसी रणनीति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने पर ध्यान दें और उसका मुकाबला करने के लिए उपयुक्त तौर–तरीके

व कार्यनीति अपनायें; वर्ग दिशा तथा जन दिशा पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए और पीएलजीए की शक्तियों को कारगर रूप से गोलबन्द करते हुए केन्द्र तथा प्रदेश के बलों और राज्य द्वारा प्रायोजित सलवा जुडूम, सेन्दरा, कोबरा तथा भाड़े के अन्य निजी सशस्त्र गिरोहों के प्रतिक्रान्तिकारी हमले का डटकर मुकाबला करें! छापामार जोनों तथा सशस्त्र संघर्ष के अन्य जोनों में दुश्मन के बलों का थोड़ा-थोड़ा करके सफाया करने के लिए कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों का संचालन करें!

2. एओबी में छापामार युद्ध को सघन बनायें और दुश्मन की क्रूर आक्रमणकारी मुहिम को परास्त करने तथा युद्ध में पहलकदमी दुबारा हासिल करने के लिए तमाम शक्तियों को गोलबन्द करें! हमारी पार्टी को सुदृढ़ करें, पीएलजीए को मजबूत करें, राजनीतिक सत्ता के हमारे निकायों का विस्तार करें! इस छापामार जोन को आधार क्षेत्र में रूपान्तरित करने में सहयोग के तौर पर व्यापक आधार वाले जन मोर्चों का निर्माण करें और हमारी समूची आत्मगत शक्तियों को बढ़ायें तथा सशस्त्र संघर्ष के हमारे क्षेत्र का विस्तार करें!

3. एपी तथा एनटी में आन्दोलन को टिकाये रखने और पुनर्जीवित करने पर ध्यान केन्द्रित करें। जहाँ तक सम्भव हो, दुश्मन का योजनाबद्ध तरीके से प्रतिरोध करते हुए उसकी मौजूदा नृशंस चौतरफा आक्रमणकारी मुहिम से अपनी शक्तियों को बचाने पर ध्यान दें। जनता के साथ सम्पर्कों को फिर से स्थापित करें और राजनीतिक गोलबन्दी तथा सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करें और हमारी आत्मगत शक्तियों को बढ़ायें। जोनों में हर कहीं संगठन की गुप्त कार्यपद्धति का सख्ती से पालन करें।

4. बीजेओ में वर्ग दुश्मन तथा प्रतिक्रियावादी वर्गों पर हमले करते हुए और छापामार युद्ध को जहाँ तक सम्भव हो, विकसित करते हुए अपनी आत्मगत शक्तियों को संचित करें।

5. 3यू, उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में कृषि क्रान्तिकारी युद्ध को विकसित करें। वर्ग दुश्मनों एवं राज्य पर हमले जारी रखते हुए मजबूत जनाधार का निर्माण करें तथा संगठन को सुदृढ़ करें। छापामार जोनों को विकसित करने के लिए तैयारियाँ पूरी करें।

6. अन्य प्रदेशों तथा परिप्रेक्ष्य क्षेत्रों में अपनी शक्तियों को संकेन्द्रित करें, उन्हें हथियारों से लैस करें तथा सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी संघर्षों को तेज करें और छापामार जोन

का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ तैयारियों को पूरा करें। मजबूत साम्राज्यवाद–विरोधी, सामन्तवाद–विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद–विरोधी संघर्षों को खड़ा करें।

7. एक विशेष रणनीतिक कार्यभार के रूप में समयबद्ध कार्यक्रम के साथ छापामार युद्ध के मुख्य जोनों के बीच के रणनीतिक क्षेत्रों को जोड़ दें।

8. सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के बीच समुचित सन्तुलन के साथ छापामार युद्ध को नये–नये प्रदेशों तथा क्षेत्रों में विस्तार करने की दिशा अपनायें।

9. जनाधार को विकसित करें, गहराई दें और व्यापक करें।

10. समूची पार्टी में विचारधारात्मक, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करें। पार्टी के सभी स्तरों पर गैर–सर्वहारा प्रवृत्तियों को दुरुस्त करने के लिए संघर्ष तेज करें।

11. दुश्मन की दुष्प्रचार मुहिम के खिलाफ क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रचार अभियान तेज करें।

गौजी कार्यभार

1. दीर्घकालीन लोकयुध्द के माओवादी उसूलों के साथ ही अन्य क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रीयता संघर्षों का अध्ययन करें और अपनी ठोस स्थितियों में इस पर सृजनात्मक रूप से अमल करें।

2. प्रत्येक छापामार जोन में छापामार युध्द को चलायमान युद्ध में और पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने के लिए कमीशनों और कमानों को स्थापित तथा सुदृढ़ करें।

3. दुश्मन की आक्रमणकारी मुहिम को शिकस्त देने के लिए युद्ध स्तर पर अपनी शक्तियों को विकसित करें और अपनी मारक क्षमता को विकसित करें।

4. पीएलजीए को पीएलए में रूपान्तरित करने के लिए गुप्तचर, आपूर्ति, संचार, प्रशिक्षण, उत्पादन इत्यादि सहायक विभागों को स्थापित करें।

5. डीके और बीजे में ऊँचे स्तर की संरचनाओं (फारमेशनों) को गठित करने के लक्ष्य के साथ व्यापक पैमाने पर कम्पनियों को पीएलए की प्राथमिक इकाई के तौर पर विकसित करें।

6. व्यापक पैमाने पर मिलिशिया का निर्माण करें और उन्हें हथियारों से लैस तथा प्रशिक्षित करें।

संयुक्त मोर्चे के कार्यभार

1. रणनीतिक और कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चों को मजबूत करें।
2. मुख्य जोनों में जन युद्ध को आगे बढ़ाते हुए चार वर्गों के संश्रय के रूप में संयुक्त मोर्चा विकसित करें और स्थानीय से लेकर जोन के स्तर तक आरपीसी स्थापित करें व मजबूत करें।
3. विस्थापन और इससे जुड़े विकास के साम्राज्यवादी ढ़र्रे के खिलाफ व्यापकतम सम्भव संयुक्त मोर्चा विकसित करें।
4. केन्द्र तथा प्रदेश सरकारों में आसीन देशद्रोही शासक वर्गीय पार्टियों द्वारा लागू की जा रही साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का विरोध करने वाली सभी शक्तियों के साथ एकताबद्ध हों।
5. कश्मीर, असम, नागालैण्ड, मणिपुर और उत्तर-पूर्व के अन्य हिस्सों में चल रहे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के सशस्त्र संघर्षों के साथ दीर्घकालीन लोकयुद्ध का तालमेल करें।
6. हिन्दू फासीवाद के खिलाफ अल्पसंख्यकों के, विशेष कर मुसलमानों के व्यापक मोर्चे का निर्माण करें।
7. जातिगत उत्पीड़न के सभी रूपों के विरुद्ध दलितों को संगठित करें।
8. महिलाओं को पितृसत्ता और सामन्ती/साम्राज्यवादी उत्पीड़न के सभी रूपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गोलबन्द करें।
9. भारतीय शासक वर्गों द्वारा तमाम क्षेत्रों में चलाये जा रहे फासीवादी दमन के खिलाफ व्यापक जनता को जुझारू संघर्षों में गोलबन्द करें और समस्त निरंकुश कानूनों के विरुद्ध अडिग संघर्ष करें।

सांगठनिक कार्यभार

1. पार्टी का विचारधारात्मक, राजनीतिक, सांगठनिक रूप से बोल्शेविकीकरण करें, विचारों तथा कार्यों की एकता तैयार करें और फौलादी अनुशासन के साथ एक आवाज़ के रूप में जुट जायें।

2. पार्टी कमेटियों को पहलकदमी लेने वाली, स्वावलम्बी कमेटी बनायें और अपने क्षेत्र विशेष के आन्दोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनायें।

3. पीआर के स्थिर केन्द्रक और अंशकालिकों की इकाइयों के व्यापक तानेबाने वाली मजबूत भूमिगत पार्टी का निर्माण करें। दुश्मन के हमलों की सूरत में अभेद्य रहने वाले गुप्त ढाँचे एवं तन्त्र का निर्माण करें। पार्टी से सभी विजातीय रुझानों का उन्मूलन करते हुए बोल्शेविकीकरण करें। पार्टी की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पार्टी सदस्यता तथा पीआर की संख्या बढ़ाने वाले भर्ती अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करें। बुनियादी वर्गों से पार्टी कार्यकर्ताओं को भर्ती करने और मजदूर वर्ग, गरीब तथा भूमिहीन किसानों तथा आदिवासियों, महिलाओं, मुसलमानों एवं दलितों समेत विशेष सामाजिक समूहों के बीच के पार्टी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत करने पर विशेष बल दें।

4. जनवादी केन्द्रीयता के ढाँचे के भीतर सभी कमेटियों को सृजनात्मक तथा सजीव तरीके से राजनीतिक एवं सामरिक कार्यनीति विकसित करनी होगी, मात्र ऊपरी कमेटियों के निर्देशों पर निर्भर न रहकर अपनी पहलकदमी का प्रयोग करना होगा।

शहरी कार्यभार

1. शहरी कार्य में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपनी शक्तियों तथा नेतृत्व को समयबद्ध कार्यक्रम के साथ तैनात करें।

2. शहरी क्षेत्रों में मुख्यत: मजदूर वर्ग पर संकेन्द्रित करते हुए वर्ग संघर्षों को विकसित करें। शहरी क्षेत्रों में गुप्त तानेबाने का विकास करें और खास तौर पर कोर क्षेत्र में मजदूरों के सशक्त आन्दोलन का निर्माण करें।

3. छात्रों एवं युवाओं के ऐसे व्यापक आन्दोलन का निर्माण करें जो पार्टी के लिए बड़े भर्ती केन्द्र का काम करें।

4. जन युद्ध की ओर उन्मुख मजबूत शहरी क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्माण करें।

***